

विश्व की प्रमुख शासन-प्रणालियाँ

(MAJOR GOVERNMENTS OF THE WORLD)

(इंग्लैण्ड, अमेरिका, सोवियत रुस तथा स्विटजरलैण्ड)
(ENGLAND U S A U S S R & SWITZERLAND)

ADVANCE COPY
Mean to Consideration
NOT FOR SALE

लेखक
आर एल सिंह,
एम ए (राजनीति) एम ए (इतिहास)
एल एल बी, एल टी, आर ई एस
अध्यक्ष राजनीतिशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर (राज०)

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
पुस्तक प्रकाशक, आगरा-3

प्रकाशक

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल
पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता,
हॉस्पिटल रोड, आगरा-3

प्रथम संस्करण 1974

मूल्य पन्द्रह रुपये मात्र

मुद्रक

हरीहर प्रेस

मोतीकटरा आगरा-3

(हरी कम्पोजिंग हाउस द्वारा कम्पोज)

दो शब्द

सविधान सावजनिक हितों की पूर्ति है। यह साध्य भी है और साधन भी। सविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। शक्तियों में सन्तुलन तथा शक्तियों की सीमाएँ सविधान द्वारा निश्चित की जाती हैं। सविधान सामाजिक गतिशीलता का द्योतक होता है। वह सामाजिक प्रगति का मानक होता है। वह सामाजिक परिवर्तनों का दायक है। सविधान जन भावनाओं का मूर्तरूप है। यह एक शासन की पद्धति है। सविधानों का विवेकपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन सविधान की प्रकृति एवं उसकी स्वस्थ परम्परा को समझने के लिए अपेक्षित है।

राष्ट्र भाषा में इस विषय पर अल्प पुस्तकें भी लिखी गई हैं और यह पुस्तक भी उसी दिशा में एक क्षुद्र प्रयास है। इसमें सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग करके विषय की जटिलता को कम करके उसे हृदयग्राही बनाने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी वर्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर पुस्तक की रचना की गई है। विषय सामग्री को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान पुस्तक में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस तथा स्विट्जरलैण्ड आदि देशों के सविधानों का उल्लेख किया गया है। विविध सविधानों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना लेखक का प्रमुख ध्येय रहा है।

मैं उन समस्त लेखकों के प्रति आभारी हूँ जिनकी पुस्तकों से विविध उद्धरण वर्तमान पुस्तक में लिए गये हैं। पुस्तक की सफलता उन विद्यार्थियों के हाथों में ही निहित है जिनके लिए यह लिखी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक के सफल एवं स्वस्थ प्रकाशन के लिए मैं मैसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के स्वामी श्री पी० एन० अग्रवाल के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में अकथनीय शक्ति प्रकट की है। पुनः मैं एक बार पुस्तक की सफलता का ध्येय विद्यार्थी वर्ग के हाथों में छोड़ता हूँ। लेखक उन विद्वानों के प्रति भी आभारी रहेगा जो समय समय पर पुस्तक को और अधिक उत्तम बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेगे। मुझे पूर्ण आशा है कि विद्यार्थी वर्ग वर्तमान रचना का उपयोगी पाकर उसका हृदय से स्वागत कर सकेंगे।

रक्षाबन्धन सन् 1974

गांधी नगर
फतहपुर रोड,
सीकर

—रामलखनसिंह

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

प्रथम खण्ड ब्रिटिश संविधान (BRITISH CONSTITUTION)

- 1 ब्रिटिश संविधान का विकास एवं स्वरूप (Nature and Development) 1—29
[राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचार तथा संविधान, सर्व धार्मिक सिद्धांत, ब्रिटिश संविधान के विकास की शक्त, संवैधानिक द्वाद तथा पुनर्निर्माण, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ, ब्रिटिश संविधान के निर्माणक तत्व, संविधान के अभिसमय (Conventions of the Constitution), अभिसमयों के प्रकार, कानून तथा अभिसमय, अभिसमयों के पीछे स्वीकृति ।]
- 2 राजा तथा राजमुकुट (King and the Crown) 30—53
[राजा और राजमुकुट में अंतर तथा उसका महत्व, काउन की शक्तियाँ, काउन की शक्तियों के स्रोत । सम्राट के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ—विशेषाधिकारों की समीक्षा, सम्राट का स्थान—राजा कभी कोई गलती नहीं करता राजा राज्य करता है, शासन नहीं । राजतन्त्र का औचित्य (Justification of Monarchy)—ऐतिहासिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण, राजा के व्यक्तिगत कार्य अथवा उपयोगितावादी तक, सामाजिक कारण ।]
- 3 मंत्रिमण्डल (Cabinet) 54—83
[परिचय, प्रौढी परिपद के कार्य, मंत्रिमण्डल तथा मंत्रिपरिषद में अंतर, मंत्रिमण्डल के विविध स्वरूप, मंत्रिमण्डल का गठन, मंत्रिमण्डल का महत्व, मंत्रिमण्डलीय पद्धति के सिद्धांत, मंत्रिमण्डल के कार्य, मंत्रिमण्डल का अधिनायकत्व, मंत्रिमण्डल की महत्ता के कारण, प्रधानमंत्री (Prime Minister), प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कार्य ।]
- 4 ब्रिटिश संसद—साउथ सभा (House of the Lords) 84—98
[लाउ सभा का संगठन, लाउ सभा के कार्य, लाउ सभा के विपक्ष में तक । लाउ सभा की उपयोगिता—1911 के संसदीय विधेयक की प्रमुख बातें, 1949 का संसदीय विधेयक, लाउ सभा को सुधारने की योजनाएँ—ब्राइस कमिटी की रिपोर्ट, लायड जॉन योजना, क्लैरेण्डन योजना, सैलिसबरी योजना, सबदलीय सम्मेलन, 1949 के सुझाव, अन्य सुझाव ।]

5 ब्रिटिश ससद—लोकसभा (House of Commons)

99-134

[लोकसभा का संगठन—निर्वाचन प्रणाली के दोष, निर्वाचन पद्धति में प्रस्तावित सुधार सदस्यों की उन्मुक्तियाँ, ससदीय अधिवेशन, लोकसभा का अध्यक्ष । अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य, राजा का विरोधी दल—महत्त्व, विपक्ष का संगठन—लोक सभा के कार्य और कर्तव्य, विधायी प्रक्रिया, विधेयको के प्रकार—सावजनिक विधेयक विषयक प्रक्रिया, व्यक्तिगत विधेयको के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया, वित्त विधेयक विषयक प्रतिक्रिया, अस्थायी आदेश, ब्रिटिश ससद में समिति व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की समितियों की तुलना, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन—प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के कारण, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन की आलोचना, प्रत्याधिकृत सविधान के विरुद्ध सुरक्षाएँ, ससद की शक्ति का ह्रास (Decline of Parliament), विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र, सदन का विघटन, दलीय अनुशासन की कठोरता, लोकसदन की प्रक्रिया, प्रत्याधिकृत व्यवस्थापन, वित्तीय नियंत्रण में ह्रास, सदन में सदस्यों की स्वतंत्रता की कमी, लोकमत की प्रबलता ।]

6 ब्रिटिश न्याय व्यवस्था (British Judicial System) 135-148

[ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताएँ—डायरी का विवेचन, विधि के शासन का अपवाद, इंग्लैण्ड में कानून के प्रकार, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का संगठन, प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का मूलमार्ग ।]

7 राजनीतिक दल (Political Parties) 149-162

[ब्रिटिश राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएँ, प्रमुख राजनीतिक दल—अनुदारवादी दल, नीतियाँ तथा संगठन, श्रमिक दल, कामगार तथा संगठन, उदार दल, नीति एवं कार्यक्रम संगठन ।]

8 ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें (Local Governments in Britain) 163-173

[इंग्लैण्ड में वर्तमान स्थानीय व्यवस्था—काउण्टी परिषद, बाउण्टी बोरो, तथा नान काउण्टी बोरो नगर जिला परिषद, ग्रामीण जिले, पैरिश, लंदन का स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण, केन्द्रीय नियंत्रण का स्वरूप ।]

9 प्रशासकीय सेवाएँ (The Civil Services) 174-180

[प्रशासकीय षण, निष्पादक षण, लिपिक षण । सिविल आयोग—यथा ससद मंत्रियों के हाथों में तथा मंत्री स्थायी राजकीय पदाधिकारियों के हाथों में यत्र है मंत्रिमण्डल स्थायी कर्मचारियों के हाथों में यत्रवत है ।]

द्वितीय पृष्ठ

अमेरिकी—सविधान

(THE CONSTITUTION OF U S A)

1 अमेरिकी सविधान की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of American Constitution) 181-211

[अमेरिकी शासन पद्धति का महत्त्व, सार्वजनिक विचारों की

रीतियाँ—ग्यायिक व्याख्याएँ, प्रशाकीय नियम, सर्वैधानिक सशोधन, सर्वैधानिक अभिसमय । अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ—सशोधन की प्रक्रिया, सशोधन प्रक्रिया की आलोचना, अमेरिकी पद्धति अथवा एव संतुलन के सिद्धांत पर अवलम्बित है, सघात्मक व्यवस्था की स्थापना, राष्ट्रीय सरकार की सर्वोच्चता तथा इसकी शक्तियों के बढ़ने के कारण ।]

- 2 अमेरिकी कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल) (American Executive—President, Vice President and the Cabinet) 212-256

[राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएँ—वैतन भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ, उम्तियाँ पदच्युति, पदाधिकार उत्तराधिकार । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली की आलोचना, राष्ट्रपति के कृत्य एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ—कांग्रेस के अधिवेशनों पर नियंत्रण, संदेश भेजने की शक्ति, विधायी क्षेत्र का नेतृत्व, निषेधाधिकार, संविधान के अतिरिक्त राष्ट्रपति के विधायी क्षेत्र में प्रभाव के साधन । अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति—राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण । अमेरिका के राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट तथा प्रधानमंत्री से तुलना । संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री । उपराष्ट्रपति—निर्वाचन एवं योग्यताएँ उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति पद की आलोचना एवं उपयोगिता । राष्ट्रपति का मंत्रिमण्डल—मंत्रिमण्डल की रचना, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल, कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डल, अमेरिकी मंत्रिमण्डल तथा ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की तुलना ।]

- 3 राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—सीनेट (National Legislature—Senate) 257-268

[सीनेट का संगठन—कार्यकाल, योग्यताएँ निर्वाचन, वैतन तथा उम्तियाँ पदाधिकारी, भाषण की स्वतंत्रता । सीनेट के अधिकार तथा कृत्य—कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ यायिक शक्तियाँ, सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण, सीनेट का मूल्यांकन । सीनेट तथा लॉर्ड्स समा—एक तुलना ।]

- 4 राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—प्रतिनिधि सदन (National Legislature—House of Representative) 269-290

[प्रतिनिधि सदन का संगठन—निर्वाचन प्रणाली, अहताएँ, कार्यकाल, उम्तियाँ अधिवेशन । प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी—स्पीकर—कांग्रेस की शक्तियाँ, प्रतिनिधि सभा की दुबलताएँ, विधायी प्रक्रिया—प्रस्तुतिकरण अथवा प्रथम वाचन, समिति व्यवस्था । ब्रिटिश सदन तथा अमेरिकी कांग्रेस—तुलना, अमेरिकी विधायी प्रक्रिया के प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द—लॉबीयिंग (Lobbying), जैरीमेंडरिंग (Gerrymandering), प्लोर लीडर, पीक बैरल तथा लोग रोलिंग (Log Rolling) । अमेरिकी कांग्रेस की कुछ दुबलताएँ ।]

अध्याय

पृष्ठ संख्या

- 5 अमेरिका की न्याय व्यवस्था (Judicial Organization of USA) 291-300
 [संघीय न्यायपालिका का संगठन, उच्चतम न्यायालय—उच्चतम न्यायालय या क्षेत्राधिकार, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुननिरीक्षण की आलोचना।]
- 6 अमेरिकी राजनीतिक दल (American Political Parties) 301-311
 [राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, राजनीतिक दलों का संगठन, अमेरिकी दल पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ तथा ब्रिटिश दल प्रणाली से तुलना।]
- 7 राज्य सरकारें (State Governments) 312-316
 [राज्य का प्रशासकीय संगठन—राज्यपाल, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य की व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के अधिकार राज्य, की न्यायपालिका।]

तृतीय खण्ड सोवियत रूस का संविधान

(CONSTITUTION OF U S S R)

- 1 रूसी संविधान का सामान्य परिचय तथा उसकी प्रमुख विशेषताएँ (General Introduction and the Features of the Constitution of U S S R) 317-335
 [परिचयात्मक, सन् 1918 का संविधान, सन् 1924 का संविधान, सन् 1936 का संविधान, सोवियत संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य—मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ, सोवियत संघ में नागरिकों के कर्तव्य—मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन, आलोचना।]
- 2 सोवियत संघात्मक व्यवस्था (Soviet Federalism) 336-347
 [परिचयात्मक, सोवियत संघ में संघात्मक तत्त्व, सोवियत संघ की विशिष्टताएँ, सोवियत संघवाद का मूल्यांकन, सोवियत संघ की अमेरिकी संघ से तुलना, सोवियत संघवाद तथा स्विस् संघवाद—तुलना।]
- 3 संघीय सरकार—सर्वोच्च सोवियत, प्रेसीडियम, मन्त्रिपरिषद् तथा न्याय व्यवस्था (Federal Government Supreme Soviet, Presidium, Council of Ministers and Judiciary) 348-379
 [सोवियत शासन व्यवस्था का रेखाचित्र, सर्वोच्च सोवियत—सरचना, अवधि, उम्तियाँ, अधिवेशन, पदाधिकारों वापस अथवा प्रत्याह्वान की पद्धति, सर्वोच्च सोवियत की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ, सर्वोच्च सोवियत की शक्तियाँ दोनों सदनों का सम्बन्ध। सर्वोच्च सोवियत का मूल्यांकन क्या सर्वोच्च सोवियत राजकीय सत्ता का सर्वोच्च अंग है? सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम—संगठन तथा कार्यकाल, अध्यक्ष, प्रेसीडियम की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, प्रेसीडियम की कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, प्रेसीडियम की वास्तविक स्थिति। मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का संगठन, मन्त्रिपरिषद् का

अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद् की प्रमुख विशेषताएँ, मन्त्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ, मन्त्रियों का उत्तरदायित्व । मन्त्रिपरिषद् की वास्तविक स्थिति वह कहाँ तक ससदीय है ? सोवियत याय व्यवस्था—सोवियत याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ, याय व्यवस्था के सगठन का रेखाचित्र, सोवियत संघ का सर्वोच्च पायालय, सर्वोच्च पायालय के अधिकार एवं कर्तव्य, उच्चतम पायालय की स्थिति । सोवियत संघ का प्रोक्युरेटर जनरल ।]

- 4 साम्यवादी दल तथा सोवियत रूस में लोकतन्त्र (The Communist Party and Democracy in Soviet Union) 380-396

[परिचयात्मक, साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताएँ, साम्यवादी दल का सगठन—साम्यवादी दल के सगठन का रेखाचित्र, साम्यवादी दल का स्थान । तथा सोवियत संविधान जनतन्त्रात्मक है—लोकतन्त्र के पक्ष में तक, विपक्ष में तक, निष्कर्ष ।]

- 5 लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा संघीय इकाइयों का शासन (Democratic Centralism and Administration of Federating Units) 397-405

[परिचयात्मक, लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा नौकरशाही के द्रवाद में अन्तर—व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद, सोवियत संघीय व्यवस्था में, साम्यवादी दल में लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद, सोवियतों में लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद । संघीय इकाइयों का शासन—संघीय गणराज्य की शासन व्यवस्था, संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम, संघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषद्, स्वायत्त गणराज्यों का शासन, स्वायत्त प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों का शासन, स्थानीय स्वशासन प्रांतों की सोवियतें, जिले का प्रशासन, नगरों का शासन, ग्रामों की सोवियत, क्षेत्र ।]

चतुर्थ खण्ड

स्विटजरलैण्ड की शासन व्यवस्था

(THE CONSTITUTION OF SWITZERLAND)

- 1 स्विटजरलैण्ड के संविधान की सामान्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (General and Historical Background of The Swiss Constitution) 407-428

[परिचयात्मक, राजनैतिक विचार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आधुनिक स्विटजरलैण्ड का जन्म, स्विटजरलैण्ड के संविधान की विशेषताएँ, स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन, स्विस संशोधन प्रक्रिया की अमेरिकी संशोधन प्रक्रिया से तुलना । स्विटजरलैण्ड की संघ व्यवस्था—स्विस संविधान में संघात्मकता के तत्त्व, स्विस संविधान में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति । निष्कर्ष, अमेरिकी तथा स्विस संघ व्यवस्था की तुलना ।]

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

2 सघीय कार्यपालिका (Swiss Federal Executive)

429-445

[परिचयात्मक, सघीय परिषद वा सभठन, सदस्यता, योग्यताएँ एवं कार्यकाल, वेतन एवं उम्तिर्या, अधिवेशन सघीय परिषद के पदाधिकारी, अध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य, प्रशासकीय विभाग, सघीय परिषद के कार्य, सघीय परिषद तथा विधानमण्डल, सवधानिक दृष्टिकोण, वास्तविक स्थिति, सघीय परिषद के प्रभावी होने के कारण । सघीय कार्यपालिका की प्रकृति—यह ससदात्मक नहीं है, यह अध्यक्षतात्मक भी नहीं है यह प्रेसीडियम भी नहीं है, तब यह क्या है, सघीय कार्यपालिका की विशेषताएँ ।]

3 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

446-464

[परिचयात्मक, प्रत्यक्ष व्यवस्थापन—लोकमत सग्रह का अर्थ, लोकमत सग्रह के गुण, लोकमत सग्रह के अवगुण, उपक्रम—उपक्रम के गुण, उपक्रम के अवगुण प्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान के गुण, अवगुण, प्रत्यक्ष प्रजासत्त के गुण और दोष, स्थानीय सभाएँ, स्विटजरलण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की सफलता के कारण ।]

4 स्विस सघीय न्यायाधिकरण तथा राजनीतिक दल (Swiss Federal Tribunal and Political Parties)

465-474

[परिचयात्मक, सघीय न्यायाधिकरण की रचना—वेतन सचिवालय तथा विभाग आदि, सघीय न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, स्विस न्यायाधिकरण तथा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना । स्विटजरलण्ड में दल पद्धति—स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताएँ प्रमुख राजनीतिक दल स्विटजरलण्ड में दल व्यवस्था की बुलता के कारण ।]

5 सघीय विधानपालिका (Swiss Federal Legislature)

475-488

[परिचयात्मक, राष्ट्रीय परिषद—सभठन निर्वाचन पद्धति कार्यकाल पदाधिकारी । राज्य परिषद—सभठन, विशेषाधिकार एवं उम्तिर्या, अधिवेशन मणपूति तथा वेतन । सघीय सभा की शक्तियाँ—सघीय सभा की स्थिति, सघीय सभा में विधिनिर्माण की प्रक्रिया—दोनों सदनों के मध्य सम्बन्ध स्विस राज्य परिषद की अमेरिकी सीनेट तथा इंगलण्ड की राज्य सभा से तुलना, स्विस राज्य परिषद तथा अमेरिकी सीनेट ।]

6 कंटनों की शासन व्यवस्था (The Govt of Cantons)

489-492

[कंटनों का राजनीतिक ढाँचा—कंटनों की व्यवस्थापिकाएँ कंटनों की कार्यपालिका कंटनल न्यायपालिका, प्रदेशों तथा नमूनों का शासन ।]

प्रथम खण्ड
ब्रिटिश संविधान

- ब्रिटिश संविधान का विकास एवं स्वरूप
- राजा तथा राजमुकुट
- मंत्रिमण्डल
- ब्रिटिश संसद—लॉर्डसभा
- ब्रिटिश संसद—लोकसभा
- ब्रिटिश न्याय व्यवस्था
- राजनीतिक दल
- ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें
- प्रशासकीय सेवाएँ

UNITED KINGDOM



ब्रिटिश संविधान का विकास एवं स्वरूप

[Nature & Development of British Constitution]

"Constitution is the autobiography of a power relationship" —Finer

"In England the Constitution there is no such thing" —Alexis de Tocqueville

सम्भवतः विश्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन संविधान इंग्लैंड का संविधान है, जिसका अमरीकी दृष्टिकोण से अस्तित्व नहीं है तथा संविधान की आग्ल परिभाषा के अनुसार उसका पूर्ण अस्तित्व है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन एवं द्विसदनात्मक संसदीय पद्धति आदि उसके ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुदाय हैं जिनका विश्व संवदा ऋणी रहेगा। प्राचीनता एवं मौलिकता उसने दो महत्वपूर्ण आधार हैं। ब्रिटिश संविधान अपने प्रकार का ऐसा एक ही संविधान है जो राजतन्त्र के होत हुए भी उत्कृष्ट लोकतन्त्रीय अभीष्टताओं से पूर्णतः युक्त है। निरंकुश राजतन्त्र से लेकर लोकतन्त्र के उत्तुंग शिखर तक का मार्ग इतनी सावधानी एवं दृढ़ता से निर्मित हुआ है कि संघर्ष एवं नाशियों के थपड़ उसकी गति का हिला नहीं सके।

ब्रिटिश संविधान के विश्व-यापी प्रभाव की सराहना करते हुए मुनरो (Munro) ने कहा है कि प्रकार वणमाला के विकास में पूर्व और कानून के विकास में रोम का हाथ है उसी प्रकार राजनीतिक संगठनों के अभ्युदय के लिए मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन उत्तरदायी है।" (Civilized man has drawn his religious inspiration from the East his alphabets from Egypt, his algebra from Moors his sculpture from Greeks and his laws from Rome but for his political organization he owes mostly to English models) जो दश किसी भी रूप में ब्रिटेन से सम्बंधित रहे उनके संविधानों पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परलक्षित होता है। फ्रांस, भारत, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया आदि के संविधान इस तथ्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अमरीका तथा रूस की शासन प्रणालियाँ अपनी शासकीय पद्धति की पृथक् विशेषताओं एवं उद्देश्यों को रखकर भी पूर्णतः ब्रिटिश संविधान के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकीं। यह निर्विवाद सत्य है कि ब्रिटिश संविधान के आधारभूत तत्वों का परिचय प्राप्त कर बिना विश्व के अधिकांश संविधानों का समझना कठिन है। इसी कारण ब्रिटिश संविधान का संविधानों का पितामह (Father of the Constitutions) तथा ब्रिटिश संसद का संसदों की जननी (Mother of Parliaments) कहा गया है। मुनरो (Munro) ने यह सत्य ही कहा है कि

“अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा भाषियों के नेतृत्व में सभ्य विश्व के बड़े भाग का जनतन्त्रीकरण राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्पष्ट सत्य है।” हम भारतीयों के लिए तो ब्रिटिश संविधान का और भी अधिक महत्व है। भारतीय संविधान के प्रत्येक अंग पर संसदीय प्रणाली की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

वस्तुतः ब्रिटिश संविधान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है। हम उसे जन-स्वातंत्र्य का रक्षक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रेरक कह सकते हैं। ब्रिटिश संविधान स्वतंत्रता तथा प्रगति का एक अनुपम प्रतीक है। यह इंग्लिश प्रतिभा एवं दूरदर्शिता का परिचायक है। संविधानों के जिन लाक्षणिक गुणाएँ उनके आधारभूत सिद्धांतों को इंगलैण्ड ने बल प्रदान किया है वह चिरस्मरणीय रहेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मैकेजी किम ने ब्रिटिश संविधान के प्रति अपनी वृत्तज्ञता की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा है, “इस अंग्रेजी संविधान को हम प्यार करते हैं वह इंगलैण्ड के निवासियों की उत्कृष्टतम प्रतिभा की सर्वोच्च सफलता को प्रस्तुत करता है। किसी ने इस कभी देखा नहीं, न किसी ने पर्याप्त रूप में कभी वर्णन किया है तथापि जब भी स्वतंत्रता अथवा अधिकार पर कोई आघात आती दिखाई देती है तब इसने अस्तित्व का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि यह जुलूम तथा अधम के विरुद्ध शताब्दियों तक संघर्ष करने के परिणामस्वरूप बना है और इसमें स्वतंत्रता की आत्मा का समावेश है।” संसदीय प्रणाली का यह अप्रदूत परम्पराएँ एवं विवेक के कलेवर में अपनी गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता के गुणों को संजोये, संघर्षों की झल्लाओं के मध्य में भी अपने मूल प्रवाह को बनाये हुए है। व्यवस्था के प्रसून इतनी कलात्मकता के साथ उसमें पिरोये गये हैं कि हम उसने लिखित स्वरूप का अभाव ही अनुभव नहीं होता।

राजनीतिक पृष्ठभूमि (Political Background)

इंगलैण्ड यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 93,371 वर्ग मील है। यह अमरीका के तीसरे तथा रूस के अस्सीवें भाग के बराबर है। इसमें लंदन, वेल्स, स्कॉटलैण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड सम्मिलित है। इसके चारों ओर समुद्र है जो इसकी सुरक्षात्मक शक्ति का सदैव सहयोगी रहा है। 20 मील लम्बा इंग्लिश चैनल इसे यूरोपीय महाद्वीप से पृथक् करता है। नात्सी जर्मनी के भयानक आक्रमणों से इसने सदैव इंगलैण्ड की सुरक्षा की है। कृषि योग्य भूमि अधिक नहीं है। लोहे तथा कोयले की खानें यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर विविध जातियों के लोग निवास करते हैं। ये सदैव मिलजुल कर रहे हैं और ब्रिटेन की इस जातीय एकरूपता का प्रभाव उसके संविधान पर स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होता है। यह विभिन्न भाषाएँ तथा संस्कृतियाँ वाला देश नहीं है।

इसने छोटे आकार में एकात्मक प्रणाली का सफल बनाया है। नागरिकरण तथा औद्योगिकरण में भी इसने सहयोग प्राप्त हुआ है। समुद्र-तट के लाभ के फलस्वरूप व्यापार में इसे आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। घम के क्षेत्र में

अवश्य ही विविधता है। अधिकांश लोग प्रास्टस्टण्ट धर्म के अनुयायी हैं। प्रो० वारकर का ऐसा विचार है कि ब्रिटन में धार्मिक सहिष्णुता बहुत कुछ सीमा में समदीय लोक तन्त्र का आधार रही है। ब्रिटन की वाणिज्यवादी प्रवृत्ति ने विदेशी व्यापार का जन्म दिया तथा वहाँ के निवासियों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का बीज-वपन किया। विदेशों की खोज तथा व्यापार की वृद्धि उसके नाविकों की आदत से बन गयी है।

ब्रिटेन का पारिवारिक जीवन अधिक कठोर तथा संगठित नहीं है। पारिवारिक गिनिलता ने राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया है। नामन शासकों से ज्येष्ठत्व के सिद्धांत को बल मिला। इसी वग का संवैधानिक विकास में भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा, क्योंकि इस वग के सदस्यों ने जन प्रतिनिधि के रूप में लोक सभा में बैठना स्वीकार किया था। लोक सभा इसी कारण सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा बन गयी। सरकार को वहाँ के देशवासी एक ट्रस्ट के रूप में स्वीकार करते हैं।

इतिहास वर्तमान का निष्कर्ष तथा भविष्य का निर्माता है। ब्रिटेन में लोकतन्त्र का आविर्भाव किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बरन् अत्यन्त व्यर्थ स्थित एवं विकासवादी आधार पर उसकी उत्पत्ति हुई है। राजतन्त्र में कुलीनतन्त्र तथा कुलीन वग को ही राजतन्त्र के अवतरण का श्रेय जाता है। आज लोकतन्त्र की जिन परम्पराओं का ब्रिटिश भूमि पर स्वागत करते हैं वे कुलीन वग के ही अनुदाय के रूप में हैं। कुलीनतन्त्र में समय की भाग के साथ अपने का परिवर्तित कर लोकतन्त्र से तादात्म्य स्थापित कर अपने को उसी गग में आत्मसात कर लिया है। लाड सभा इस तथ्य की परिचायक है कि ब्रिटेनवासियों का अपनी पुरातन संस्थाओं में कितना प्रगाढ़ विश्वास है और वहाँ का एक हजार वर्ष का अटूट संवैधानिक विकास इसका प्रमाण है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं पर पश्चिम का पूरा प्रभाव है। ब्रिटेन के समाज में तीन वग हैं—पूँजीपति, श्रमिक तथा नौकरीपेशा एवं छोटे छोटे दुकानदार आदि।

राजनीतिक विचार तथा संविधान (Political Ideas & the Constitution)

रूढ़िवाद (Conservatism)—नूतनता को शक की दृष्टि से देखने वाली आगल जाति पर रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव अत्यधिक है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे परिवर्तन विरोधी हैं बरन् वे परिवर्तन ऐसा चाहते हैं जिससे प्राचीन संस्थाओं की सुरक्षा सुलभ हो सके। रूढ़िवादी वक्ता (Burke) के दर्शन से प्रभावित होकर इंग्लैंडवासियों को 19वीं शताब्दी में प्रजातन्त्र तथा औद्योगिकीकरण की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने मानसिक सन्तुलन का बनाये रखकर जनता ने समझौतावादी नीति का अनुसरण किया तथा प्राचीन संस्थाओं एवं परम्पराओं को स्वीकार करते हुए नूतनता का स्वागत किया। समस्त ब्रिटिश संविधान प्राचीनता तथा नूतनता के मध्य समझौते का परिणाम है। ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के साथ-साथ रूढ़िवाद का विकास और अधिक हुआ। साम्राज्यवाद रूढ़िवादी नीति की एक विशेषता मानी जाती है।

उदारतावाद (Liberalism)—रूढ़िवादी दर्शन के प्रभाव के साथ-साथ ब्रिटिश संविधान के विकास पर उदारवादी विचारधारा का भी प्रभाव कम नहीं

रहा। इंग्लैण्ड में उदारवादी परम्परा के जनक जॉन लॉक (Locke) ने सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों का शक्ति प्रदान कर इस बात पर बल दिया कि सरकार को एक सीमित परिधि में ही कार्य करना चाहिए और सीमित अधिकार क्षेत्र के माध्यम से वह व्यक्ति को अधिक म अधिक स्वतंत्र बना सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दृष्टि से उसने शक्तियाँ के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। लॉक इंग्लैण्ड में उदारतावाद का मगीहा बन गया। उसके परचात उदारवाद की परिपाटी को आगे ले जाने का थय जरमी बेथम तथा उनके शिष्य जे एम मिल की है। उपयोगितावादी इन दाशनिवा न उदारवादी विचार को भौतिक सुख के साथ बद्ध करके राज्य क कार्यक्षेत्र का सीमित कर दिया तथा इस बात पर बल दिया कि राज्य को वह सब कुछ करना चाहिए जिससे अधिराश व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके। व्यक्तियों क सुख के लिए राज्य का प्रत्येक कार्य बध है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रवत्ता एडम स्मिथ ने भी इसी विचारधारा को आग बढ़ाया और इन सब का प्रभाव ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में है।

(3) समाजवाद (Socialism)—समाजवादी विचारधारा के प्रभाव से इंग्लैण्ड भी मुक्त नहीं रह सका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह समस्या उठ खड़ी हुई कि क्या परिवर्तन नायिक सुधारों के द्वारा आया अथवा राजनीतिक? दोनों ही पक्षा के समर्थक थे। जो राजनीतिक क्षेत्र में सुधार लाने के पक्ष में थे उनके भी दो समूह थे—क्रांतिकारी तथा संवैधानिक। काल मार्क्स के दर्शन से प्रभावित व्यक्ति जन-माधारण के लिए क्रांतिकारी पद्धति का समर्थन करते थे। इसके विपरीत, संविधानवादियों ने, जो लोकतंत्रीय माध्यम से परिवर्तन लाने के पक्ष में थे, इंग्लैण्ड में फबियन समाज (Fabian Society) की स्थापना की और फबियनवाद की प्रगति हुई। 1900 में प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित कुछ ममुदायों ने एक नूतन संगठन को जन्म दिया जो श्रमिक दल (Labour Party) कहलाता है, जिसके प्रभाव से विविध प्रकार के परिवर्तन एवं राष्ट्रीयकरण की योजनाएँ कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रारम्भ की गयी हैं।

संवैधानिक सिद्धान्त

(Constitutional Principles)

(1) ससदीय सर्वोच्चता (Supremacy of the Parliament)—यह ब्रिटिश संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है। राष्ट्र की बधानिक सत्ता का निवास ससद में माना गया है। ससद को ही देश की सर्वोच्च शक्तियाँ का आधार माना गया है। डी लॉम का कहना सही है कि ससद चाहे ता सब कुछ कर सकती है केवल नारी को पुरुष तथा पुरुष को नारी नहीं बना सकती। नायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की अनुपस्थिति ने उसकी सत्ता का विकास और अधिक किया है। इस सिद्धांत का व्यापक रूप से वर्णन अत्यन्त किया जायगा। ससदीय शक्ति पर सीमाएँ आरोपित नहीं की जा सकती।

(2) शक्तियों का सामंजस्य (Fusion of Powers)—अमरीका का संविधान शक्तियों के पृथक्करण पर अवलम्बित है और इंग्लैण्ड का संविधान शक्तियों के सामंजस्य पर आधारित है। विधान मण्डल तथा कार्यपालिका शक्तियाँ एक दूसरे के साथ गुथी हैं। कार्यपालिका को अपने अस्तित्व के लिए विधान मण्डल पर आश्रित रहना

पड़ता है। विधान मण्डल द्वारा अविश्वास प्रदर्शित करने की स्थिति में वायपालिका को त्याग पत्र प्रस्तुत करने को विवश किया जा सकता है। यह संसदीय लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धांत है जिसका विस्तृत विवेचन अग्रतः किया जायगा।

(3) राजा तथा ताज (King & Crown)—ब्रिटिश संविधान की तृतीय आधारशिला राजा तथा क्राउन का अंतर है। राजा एक व्यक्ति है तथा क्राउन एक संस्था जिसका कि वह भौतिक प्रतीक है। राजा व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं है किंतु संस्थागत राजा ही समस्त कानून तथा शक्तियों का स्रोत है। राजा की समस्त शक्तियाँ क्राउन रूपी संस्था को हस्तांतरित हो गयी हैं जो कि राज्य, संसद, मंत्रिमण्डल तथा अन्य पदाधिकारियों का सामूहिक नाम है।

(4) विधि का शासन (Rule of Law)—ब्रिटिश संविधान की एक और महत्वपूर्ण आधारशिला विधि का शासन है जिसके अर्थ हैं कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं चाहे वह साधारण व्यक्ति है अथवा शासकीय कर्मचारी। विधिवेत्ता डायसी (Dicey) ने इसका व्यापक विवेचन प्रस्तुत किया है। इसका मूलोद्देश्य यह है कि शासन किसी भी पदाधिकारी को 'याय के समक्ष विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

ब्रिटिश संविधान के विकास की झलक

(Glances of the Historical Development)

(1) राजतंत्र का विकास (Development of Monarchy)—इंग्लिश संविधान के विकास का प्रमुख श्रेय एंग्लो सैक्सन सभ्यता को जाता है। इनके दो महत्वपूर्ण अनुदाय हैं—राजतंत्र तथा स्थानीय स्वशासन। वशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था के स्थान पर राजा का निर्वाचन बुद्धिमानों की सभा द्वारा सम्पन्न किया जाता था। इस सभा के द्वारा कभी सर्वोच्च 'वायपालिका के कार्यों का भी सम्पादन होता था। इस समय के राजतंत्र की वस्तुतः यह विशेषता रही कि वह अधिनायकतंत्र का रूप न ले सका तथा एन्सन (Anson) का यह कथन सही है कि 'राजा ने कभी भी सिद्धांत में बिना सलाहकारों के परामर्श के कोई कार्य नहीं किया है।' बुद्धिमानों की इस परिपक्वता में वर्तमान मंत्रिमण्डल के स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। स्वायत्त संस्थाओं के उद्भव को इस युग का महत्वपूर्ण अनुदाय ही कहा जायगा। ब्लैकस्टोन ने ठीक ही कहा है कि 'इंग्लैंड की स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है।'

1066 ई० की नामन विजय के साथ ब्रिटिश संविधान के विकास का एक नूतन अध्याय आरम्भ होता है। नामन शासकों के दो मौलिक लक्ष्य थे—शक्तिशाली शासन की स्थापना तथा देशवासियों को पक्ष में करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से सैक्सन शासकों को दुबला बनाया गया तथा केन्द्रीय शासन को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन को संस्थाओं को अशक्तिशाली बनाया गया। नामन शासकों ने चर्च को भी शासकीय नियंत्रण में लिया। विलियम तथा उसके पश्चात् हेनरी द्वितीय ने पादरियों एवं भूमिपतियों को दबाकर राजकीय व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया तथा स्थानीय 'याय की परम्परा डालकर सामान्य कानून की संस्था को जन्म दिया। अतः राजनीतिक दृष्टि से इस युग की वैधानिक एवं शासकीय उपलब्धियाँ अत्यन्त महत्व की रही।

समय एवं आवश्यकताओं के साथ राजा के कार्यों में विकास हुआ और उसे

परामशदात्री सभाओं की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी। इसके फलस्वरूप दो परामशदात्री समितियों का आविर्भाव हुआ— Great Council तथा Little Council or Curia Regis। वरिष्ठ परामशदात्री समिति में अल, नाइट तथा आर्कबिशप के अतिरिक्त प्रधान भूमिपति भी हुआ करते थे और इस समिति की वष में तीन चार बैठकें होना साधारण बात थी। शासकीय नियन्त्रण, नीति निर्धारण, उच्च न्याय व्यवस्था एवं कानूनों के निर्माण एवं सशोधन आदि में ये राजा की सहायता करती थी। लघु परामशदात्री समिति की सदस्यता राज परिवार चैम्बरलेन, चांसलर आदि के मध्य वितरित थी। इसे वरिष्ठ समिति का आन्तरिक वृत्त (Inner Circle) कहा जाता था और इनके कार्यों का अवसर उस समय आता था जबकि वरिष्ठ समिति का अधिवेशन सुलभ न हो पाता था। वरिष्ठ समिति का सहयोग गम्भीर एवं असाधारण महत्व के ही मामलों में प्राप्त किया जाता था। अधिकांश दैनिक आवश्यकता विषयक कार्यों में सम्बन्ध में लघु परामश समिति की सलाह ही ली जाती थी। राजा इन परामशदात्री समितियों के परामश को मानने के लिए बाध्य नहीं था। किन्तु इन सत्स्थाओं का महत्व इस कारण है कि इनके स्वरूप से इंग्लैण्ड की अधिकांश वर्तमान राजनीतिक सत्स्थाओं का विकास हुआ और वर्तमान इंग्लैण्ड इस महत्वपूर्ण अनुदाय के लिए नामम शासका का सदैव ऋणी रहेगा।

ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण कड़ी मैग्नाकार्टा (Magna Carta) (1215) का घोषणा पत्र भी है। इस विश्वव्यापी महत्व के घोषणा पत्र के सम्बन्ध में विशप स्टव्स (Stubs) ने सत्य ही कहा है कि “ब्रिटिश संविधान का सम्पूर्ण इतिहास इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र की एक व्यवस्था मात्र है।” इसकी आवश्यकता का रहस्य हेनरी द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना था। इसे ब्रिटिश स्वतन्त्रता का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। यद्यपि इस घोषणा पत्र में बरन बग का स्वायत्त निहित था किन्तु सर्वप्रधानिक विकास अपनी गति के उस मोड़ पर पहुँच चुका था जहाँ पर जनता को यह निश्चय करना था कि क्या वह राजा का स्वेच्छा चारी शासन अथवा विधि का शासन स्वीकार करे। अल ऑफ चयम ने मैग्नाकार्टा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वह ब्रिटिश संविधान का बाइबिल है। हमारी समझ में तो सम्भवतः इंग्लैण्ड में उन्मूलकी विचारधारा का सूत्रपात ही इस घोषणा पत्र से हुआ हो। इस घोषणा पत्र ने सदैव वहाँ के निवासियों की सुरक्षा की है।

(2) संसद का उदय एवं निर्माण (Rise and Growth of British Parliament)—मैग्नाकार्टा पर हस्ताक्षर करने के उपरांत 1213 में उसने प्रत्येक काउण्टी से चार विद्वान आमंत्रित करके वृहत् सभा का आयोजन किया। 1254 में इसी प्रकार की एक सभा हेनरी तृतीय ने बुलायी थी। 1274 में हेनरी तृतीय के उत्तराधिकारी एडवर्ड प्रथम ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। बैस्टमिनिस्टर का प्रथम विधान 1275 में स्वीकार किया गया। इसी प्रकार 1276 में बरन के विजयी नेता माण्टफोर्ड साइमन डी ने सामन्तों एवं पादरियों तथा काउण्टी के प्रतिनिधियों की बैठकें बुलायी जिसने राजनीतिक क्षेत्रों में एक शक्तिशाली परिवर्तन को जन्म दिया। माण्टफोर्ड को इसी कारण वर्तमान लोक सभा का जनक कहा जाता है। 1295 में एडवर्ड प्रथम ने संसद की प्रथम बैठक आमंत्रित की जिसमें 400 प्रतिनिधियों ने

भाग लिया। इसे इतिहास में आदर्श सदन (Model Parliament) कहा गया है। इसमें नगरों के भी प्रतिनिधि थे। यह ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के स्थायी अंग के रूप में कार्य करने लगी। इंग्लैंड का कोई नगर ऐसा नहीं था जिसे इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को वैसे तो वर्तमान युग की उपलब्धि कहा जाता है किंतु उसकी नींव आदर्श सदन के समय से पड़ चुकी थी। 1338 में सप्तवर्षीय युद्ध कई महत्वपूर्ण सुधारों को अपने में समेट कर उत्पन्न हुआ। पादरियों तथा बैरन (Priests & Barons) ने बाद विवाद के लिए पृथक् रूप में बैठना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप वर्तमान हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords) की नींव पड़ी। नगरों तथा कस्बों के प्रतिनिधि पृथक् पृथक् सदनों में बैठकर राजकाज में रत हो गये। 1330 के पश्चात् यह निश्चित कर दिया गया कि प्रति वर्ष सदन का अधिवेशन आमन्त्रित किया जाय। 1362 में इस नियम की पुनरावृत्ति की गयी। एडवर्ड तृतीय के शासन काल के उत्तरार्द्ध में सदन के निम्न सदन कॉमन्स सभा (House of Commons) ने तीन महत्वपूर्ण अधिकार ले लिये जिससे लॉर्ड सभा का महत्व एवं स्तर उत्तरोत्तर कम होने लगा। ये अधिकार थे—कानून निर्माण के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, सदन की सम्मति के बिना प्रत्येक कर अवध है, निम्न सदन को शासकीय व्ययों में सशोधन एवं उनकी आलोचना करने का अधिकार है। धन की आवश्यकता के कारण राजा को ये नियन्त्रण स्वीकार करने पड़े। एडवर्ड प्रथम ने भी कहा था कि सावजनिक समस्याओं पर सब की स्वीकृति ली जाय।

संवैधानिक द्वन्द्व तथा पुनर्निर्माण (Constitutional Conflict & Reconstruction)

ट्यूडर युग तथा निरंकुशता—‘गुलाबों के युद्ध’ के पश्चात् महत्वपूर्ण बंधानिक परिवर्तन हुआ। बैरन्स के योर्किश्ट तथा लेक्वास्टर दो भागों में विभाजित हो जाने से उनकी शक्ति क्षीण हो गयी और राजा उनके अधिकार से मुक्त होने लगा। जनता की आर्थिक दशा भी शोचनीय थी। ऐसी परिस्थितियों में जनता ने हेनरी सप्तम को शासन के और अधिक अधिकार प्रदान किये। परिस्थितियों का लाभ उठाकर हेनरी सप्तम तथा अष्टम ने अपनी शक्तियों का प्रयोग निरंकुश रूप में किया। Court of Star Chamber and the Court of High Commission द्वारा बैरनों की शक्तियों को कुचल दिया गया। इन शासकों ने बड़ी ही होशियारी से सदन में अपने चाहु-कारों को भरवा दिया और उन्होंने कर लगान तथा धन को मनमाने ढंग से प्रयोग करने की पूरी पूरी छूट शासकों को प्रदान कर दी। रानी एन बोलीन के साथ विवाह करने के प्रश्न को लेकर हेनरी अष्टम ने पोप के साथ समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर लिये और एक शक्तिपक धार्मिक संगठन को अपने निर्देशन में जन्म दिया। रानी एलिजाबेथ ने बड़ी ही कूटनीति से काम लिया और जनभावना को दबाये रखा। प्रोटेस्टेंटों तथा कैथोलिकों के मध्य धार्मिक सन्तुलन उत्पन्न करके एलिजाबेथ स्वयं चर्च की मुखिया बन गयी। इस समय नूतन खोजों के फलस्वरूप कई व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा तथा जन सम्पन्नता आयी। जनजायति की वलामय

रश्मियाँ बिगड़ने के लिए आतुर हो उठी। किंतु य शासन अपनी रूढ़ीनि में इस प्रगति को दबाने रहे।

स्टुअर्ट-काल में धार्मिक प्रगति—स्टुअर्ट-वंश का प्रथम शासक जेम्स प्रथम था। इस ईसाई विश्व में सबसे अधिक विद्वान् चर्चक पड़ा गया है। इसने राज्य के देवी अधिकारों का व्यापक विवेचन अपनी पुस्तक '*Laws of Free Monarchies*' में किया है। 1611 से लेकर 1614 तक उसने बिना मगद के शासन किया। 1621 में तीसरी बार समद का आमन्त्रित किया गया। अनुरोध होने के कारण समद को पुनः भंग कर दिया गया। 1624 में चौथी बार पार्लियामेंट का अधिवेशन आमन्त्रित किया गया। इस बार समद की शक्ति एवं सम्मान बढ़ा गया कि उसकी बहुत-सी बातें मान ली गयीं। 1626 में जेम्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। वह भी अपने पिता की भाँति देवी अधिकारों में विश्वास करता था। धनाभाव से विवश होकर 1626 में उसने दूसरी पार्लियामेंट आमन्त्रित की किंतु वर्धिषम के प्रश्न को लेकर झगड़ा हो जाने की स्थिति में यह भंग कर दी गयी। 1628 में पुनः समद का अधिवेशन आमन्त्रित किया गया। 1628 में ही Bill of Rights का निर्माण हुआ जिसमें चार बातें रखी गयीं—अवैध कर वसूली को रोकना, राज्य में मांगल कानून पर राज स्वैच्छाचारी रूप से बाराबास पर रोक तथा सब धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की रक्षा। चार्ल्स प्रथम तथा समद में संपन्न इस स्थिति को पहुँच गया कि चार्ल्स का वध कर दिया गया और इंग्लैंड में 1649 से लेकर 1660 तक कामनवैलथ का शासन रहा जिसमें रज्ज पार्लियामेंट रही। 1659 में 'हेवियस कार्पस अधिनियम' की रचना की गयी।

1660 में इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय को पुनः मनारूढ़ होने के लिए आमन्त्रित किया गया। उसी के समय वेबल मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया तथा Earl of Danby पर मुकुटमा चलाकर यह प्रतिस्थापित किया गया कि अशुद्ध सावजनिक नीतियों के लिए राजा के नाम पर समद क्षमादान नहीं कर सकती। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात् उसका पुत्र जेम्स द्वितीय (James II) इंग्लैंड का शासक बना। उसकी नीतियों से जनता में व्यापक असंतोष था। कैथोलिकों के प्रति उनकी सवेदनशील नीतियों ने जन असंतोष का प्रसार किया और उसे इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग जाने के लिए विवश होना पड़ा जहाँ उसने जैकोबाइट विद्रोह (Jacobite Revolt) को जन्म दिया। किंतु राजा के निष्पासन की इस घटना को 1689 की रक्तहीन राज्यशान्ति कहा जाता है। उसके पश्चात् इंग्लैंड की जनता ने विलियम तृतीय (William III Duke of Orange) तथा रानी मरी (Mary) को इंग्लैंड के सिंहासन पर आरूढ़ किया तथा उसी समय Bill of Rights स्वीकार करके राजा की शक्तियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित कर दिये। Act of Settlement द्वारा राजवंश के उत्तराधिकारियों की वंशावली को निश्चित कर दिया गया। राजा के कार्यों को भी सीमित कर दिया गया। यहाँ तक कि जॉन लॉक की विचारधारा से प्रभावित होकर शासन को परिचित करने के जनता के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड में वैधानिक राजतन्त्र की स्थापना हुई। चार्ल्स प्रथम के ही शासन काल में इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की नींव पड़ चुकी थी। जो राजा के पक्ष में थे तथा हाब्स के

'लैवियायान' एवं बोलिंगब्रुक की पुस्तक 'Patriot King' से प्रभावित थे वे Cavaliers' कहलाते थे और जो संसदीय अधिकारों की दुहाई देते थे उन्हें 'Round Heads' कहा जाता था। इन्हीं दलों के नाम हैनोवर वंश के शासकों के युग में चलकर टोरी और विंग (Tories & Whigh) हो गये और फिर आगे चलकर ये दल कंजर वेटिव (Conservatives) तथा लिबरल (Liberals) के नाम से विख्यात हुए। श्रमिक दल (Labour Party) बीसवीं शताब्दी की उत्पत्ति है।

हैनोवर वंश के शासकों के युग में धार्मिक प्रगति—पार्लियामेंट प्रणाली के विकास का श्रेय हैनोवर-वंश के प्रथम दो शासकों को जाता है। जॉर्ज प्रथम ने तो अंग्रेजी भाषा जानता था और न ही उसे इंग्लिश रीति रिवाजों के प्रति कोई लगाव था। इस कारण उसने मंत्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। उसके स्थान पर विंग नेता रॉबर्ट वालपोल (Robert Walpole) मंत्रिमण्डल की बैठकों में अध्यक्ष का पद ग्रहण करता था। यही से प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। जॉर्ज तृतीय ने संसदीय शक्तियों को कम करके एक बार पुनः इंग्लैण्ड में राजा की शक्तियों का विसर्जन करने की कोशिश की किन्तु अमरीकी स्वतन्त्रता संग्राम तथा विलियम पिट जैसे प्रबुद्ध प्रधानमंत्री के कारण वह सफल न हो सका। रानी विक्टोरिया के समय यह परम्परा चल पड़ी कि मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्य प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त किये जायेंगे। इस सिद्धांत का विकास भी इसी युग में हुआ कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा संसद को भंग कर दे। इसी युग में कामपालिका के विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित हो चुका था। इस युग की कुछ प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार की

- (1) 1832 का सुधार अधिनियम (Reform Act of 1832)।
- (2) 1867 का द्वितीय सुधार अधिनियम (Second Reform Act of 1867)।
- (3) 1884 का सुधार अधिनियम।
- (4) 1888 तथा 1894 के स्थानीय शासन सम्बंधी अधिनियम।
- (5) 1911 का संसदीय विधेयक जिसके द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियाँ कम हो गयीं।

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ

(Salient Features of the British Constitution)

संविधान सरकार का आधार होता है, राज्य और सरकार का नागरिकों से सम्बंध स्थापित करता है तथा विभिन्न शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित करता है। सामाजिक उत्थान के लिए राजनीतिक संस्थाओं का चित्र प्रस्तुत करना संविधान के मौलिक कृतव्याप्तियों में प्राथमिक महत्व का है। संविधान द्वारा ही शासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। संविधान ही राजकीय कार्यों का निर्देशक एवं संचालक होता है। ब्रिटिश संविधान के सम्बंध में विविध प्रकार की सदृशताएँ प्रस्तुत की जाती हैं। टामस पेन ने एक बार कहा था कि 'जहाँ संविधान तो प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत न किया जा सके वहाँ संविधान का अस्तित्व नहीं होता।' उसने आधुनिक अनुदारवाद के जन्मदाता बर्क (Burke) को चुनौती देते हुए कहा था कि "क्या वह महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं तो हम इस निष्कर्ष पर

पहुँचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व न बची था और न है, यद्यपि उस संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है।" जॉर्ज बर्नार्ड शॉ (George Bernard Shaw) ने एक बार कहा था कि "हमारा एक संविधान है किंतु कोई भी नहीं जानता कि यह क्या है, और न इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। हाँ, अमरीका का संविधान एक वास्तविक रूप में पढ़ा जाने योग्य लेख है। मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य समझा सकता हूँ।" ब्रिटिश संविधान के विषय में यह सदिग्धता इस कारण है कि उसका अधिकांश भाग अलिखित परम्पराओं के रूप में है। वह उस नदी की भाँति है जिसकी गति एक भाग एक सा नहीं रहता। वह उस भवन की भाँति है जिसमें समय समय पर विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता रहा है। इस सदिग्धता का दूसरा कारण संविधान की नम्यता है। संविधान में संशोधन करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दृष्टि से साधारण तथा संवैधानिक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसी कारण इंग्लैंड का संविधान विश्व का सबसे अधिक नम्य संविधान है। इसके अतिरिक्त इस भाँति का तृतीय महत्वपूर्ण कारण सम्भवतः यह रहा हो कि उसमें उच्च आधारभूत नियमों का अभाव है। विश्व के अन्य संविधानों को सर्वोच्चता का प्रतीक कहा जाता है, किन्तु इसके विपरीत इंग्लैंड में संप्रभुता का आगार ससद है। ससद स्वेच्छा से एक आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन कर लेती है। अतः उसमें उच्च एवं मौलिक नियमों का अभाव है जो संविधान के अस्तित्व का प्रबल रूप से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त में तो डी टॉक्विले (De Tocqueville) का यह कथन सही है कि "इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है" (In England the Constitution there is no such thing)। किन्तु व्यवहार में कहा पर संविधान है यद्यपि उसका स्वरूप विश्व के कुछ अन्य संविधानों की भाँति वणसकरीय है। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो अमरीकी संविधान की गणना भी वणसकर परिवार में ही होगी। यह सही है कि उसमें लिखित भाग का आधिक्य है, किन्तु बहुत से अलिखित भाग भी हैं। आग तथा जिक (Ogg & Zink) ने लिखा है कि "यह निश्चित है कि पेन तथा टॉक्विले के समय से काफी पहले इंग्लैंड में संविधान था—ऐसा संविधान जिसकी सत्ता के लिए ब्रिटिश जाति सचेत थी तथा इसके इतिहास पर गव्व करती है।" जहाँ तक संविधान की नम्यता का प्रश्न है वह संवैधानिक संशोधनों से इतना सम्बन्धित नहीं है जितना कि देशवासियों के चरित्र से। फाइनर (Finer) का यह कहना सही है कि इंग्लैंड का संविधान व्यवहार में साधारण विधि की अपेक्षा संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में अधिक कठोर है। अमरीकी नागरिक की अपेक्षा इंग्लैंड के नागरिक का चरित्र में हमें अधिक नम्यता एवं परिवर्तनशीलता उपलब्ध होती है। इस चरित्र सम्बन्धी लक्षण का प्रभाव उसकी राजनीतिक संस्थाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम संविधान के व्यापक अर्थों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें तो हम यह विश्वास हो जायगा कि वहाँ संविधान है। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः परिनियमों, प्रलेखों, पूर्व-दृष्टांतों, रूढ़ियों तथा सामान्य विधियों का अदभुत सम्मिलन है। वह गतिशील भी है। स्वाभाविक रूप से उसकी मूल संस्थाओं का विकास हुआ है। वह जन इच्छा के साथ

परिवर्तित होता रहा है। उसका निर्माण नहीं हुआ और न कभी ब्रिटन के दीर्घकालीन इतिहास में किसी विधाननिर्मात्री सभा ने इस दिशा में कोई प्रयत्न ही किया। इंग्लैण्ड के संविधान का निवास अतीत में है जिसने वर्तमान का निर्माण किया है। उसके ऊपर रोमन अथवा डेनिस होने का लेविल नहीं लगाया जा सकता। कभी भी संविधान के नियमों को प्रमवद्ध एवं व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास नहीं किया गया। वाटमी (Boutmy) के शब्दों में "उसने अपने संविधान के भिन्न भिन्न भागों को वही छोड़ दिया है, जहाँ इतिहास की लहरों ने उन्हें डाल दिया है। उन्होंने इस बात का प्रयास नहीं किया कि उन टुकड़ों का एक स्थान पर एकत्रीकरण करके उन्हें वर्गीकृत किया जाय अथवा उनके स्वरूप को संकुचित कर दिया जाय।" ब्रिटिश संविधान आकस्मिक एवं संयोगिक ही रहा है। प्रत्येक संवैधानिक परिवर्तन एक घटना एवं संयोग का परिणाम है। इसी कारण जॉन स्ट्रैची (Strachey) ने संविधान की प्रकृति के विषय में कहा है, "वह विवेक तथा संयोग का सन्तान है। (The child of wisdom and chance) इसलिए यह समझना हमारी भूल है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। वह है और संविधान की व्यापक व्याख्या के गन्ध में है। वह विकास में है, पूर्ण प्रलेख के रूप में नहीं। उसका स्रोत एक नहीं, अनेक है। वह संयोग एवं पूर्व कल्पित निश्चयों का आश्चर्यजनक मिश्रण है। मुनरो (Munro) के शब्दों में, "वह (संविधान) सत्थाओं एवं व्यवहारों का जटिल मिश्रण है, वह आज्ञापत्रों, परिनियमों, निषेधों, पूर्व-दृष्टांतों, प्रथाओं एवं निरुद्धियों की समष्टि है।" (It is a complex amalgamation of institutions principles and practices, it is a composite of characters and statutes of judicial decisions and common law) मुनरो के ही शब्दों में ब्रिटिश संविधान का इतिहास 'शांत परिवर्तन, मंद रूपांतर तथा अबोध विकास का इतिहास है।' अतः इंग्लैण्ड का संविधान राष्ट्रीय राजनीतिक परम्पराओं एवं वहाँ के नागरिकों की आदतों में है। अलिखित होना तो उसकी आंतरिक शक्ति का द्योतक है। विलियम पिट ने इंग्लैण्ड के संविधान को सराहना करते हुए कहा है कि "संविधान इस देश की कीर्ति है। लोकतन्त्र की ध्वस्तता से मुक्त तथा राजतन्त्र के आतंक से दूर इसकी प्रसन्नता इसके अंगों में निहित है।" (The constitution of this country is its glory Free from the destructions of democracy, and the tyranny of monarchy, its happiness is to be found in the mixture of parts) इंग्लैण्ड के संविधान के कई लक्षण हैं जिनका अनुकरण विश्व के बहुत से देशों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किया है।

(1) यह विकासवादी है (It is Evolutionary)—ब्रिटिश संविधान के लक्षणों में जो लक्षण सर्वप्रथम हमारे ध्यान को आकर्षित करता है वह है संविधान की विकासवादी प्रवृत्ति। संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन् वह एक दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। उसके विकास की तुलना हम उस नदी में कर सकते हैं जो मन्द गति से प्रवाहित होती हुई अपनी गति को झर-झर परिवर्तित कर लेती है और कभी-कभी झुरमुट के आचल में अपने का छिपा लेती है। हम ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे झरने से भी कर सकते हैं जिसमें उसके विभिन्न मालिकों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बर, गैराज तथा स्तम्भ आदि बना लिये हैं। (It is an

assembling structure to which successive owners have added wings and gables, porches and pillars, thus modifying it to suit their immediate wants or fashion of the time) समय समय पर जो आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न होती रही हैं उनके समाधान के फलस्वरूप संविधान का विस्तार हुआ है। यह अनायास तथा अचेतन अवस्था में आगे की ओर अग्रसर होता रहा है। यह पूर्ण रूप से अवसर एवं घटनाओं की उत्पत्ति है। राजतंत्र के प्रारम्भिक निरंकुश स्वरूप को देखकर कोई इस बात अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि वहाँ संसदीय पद्धति तथा उत्तरदायी प्रकार की कार्यपालिका की स्थापना भी सुलभ हो मनेगी। संविधान की विकासवादी प्रवृत्ति उसकी शक्ति है और इसी गुण ने उसे विश्व के अन्य संविधानों के लिए मार्गदर्शक एवं आधारभूत संविधान बना दिया है। मौलिकता एवं अवसरवादिता के मिश्रण से निमित्त यह अपने ही आकार एवं ढंग का भवन है। ओग (Ogg) के अनुसार "यह एक सचेत जीवधारी के समान है" (A living organism)।

(2) सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर (Gap between Theory & Practice)—ब्रिटिश संविधान के सम्बन्ध में विचार करने वाला व्यक्ति इस तथ्य में आश्चर्यचकित हो उठता है कि संविधान में सिद्धांततः वह सब कुछ नहीं है जो हम दिखाई देता है और वह सब कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता। इस सत्य का ब्रिटिश संविधान उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सत्य इतना गम्भीरत्व प्राप्त कर चुका है कि यह संसदीय पद्धति का एक नक्षण भी बन गया है। सिद्धांत में तो आज भी राजा समस्त राजकीय शक्तियों का स्रोत है और बिना उसकी आज्ञा के कोई भी कानून वैध नहीं है। यह सिद्धांत मतो सही है किंतु इसका व्यावहारिक पक्ष दुबल पड़ जाता है जबकि इसके साथ हमें यह भी सुनने तथा कहने को मिलता है कि राजा की शक्तियाँ अब उसकी नहीं हैं और इन शक्तियों का हस्तांतरण मन्त्रिमंडल राजा अर्थात् क्राउन को हो चुका है और राजा की इच्छा उसकी इच्छा नहीं है। बेजहॉट (Bagehot) का यह कहना सही है कि यदि दोनों सदन राजा की मर्यादा भी प्रस्ताव पारित कर दें तो उस पर भी राजा की हस्ताक्षर करने होंगे। राजा वस्तुतः मंत्रियों के चयन में कोई वास्तविक हस्तक्षेप नहीं करता। सिद्धांत में ब्रिटिश शासन निरंकुश राजतंत्र है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र है। राजा ही मसद के सत्रों को आहूत एवं उनका अवसान करता है और भग भी करता है किंतु मंत्रिमण्डल के परामर्श पर। सम्पूर्ण सार्वभौमिक शक्ति सम्राट में है किन्तु इन शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम पर अन्य पदाधिकारी प्रयोग में लाते हैं। सम्राट की निरंकुशता केवल सिद्धांत में ही है, व्यवहार में वह हमारे विलकुल विपरीत है। सम्राट की शक्ति मंत्रिमण्डल है, यहाँ तक कि विवाह आदि सम्बन्धी बात भी मंत्रिमण्डल द्वारा निश्चित की जाती है। ब्रिटेन की राजनीति में शक्ति के निरंतर राजा का स्थान केवल स्वर्ण शून्य (Golden Zero) जैसा है। सिद्धांत तथा व्यवहार के अंतर का स्पष्ट चित्रण ओग तथा जिक (Ogg & Zink) ने कहा है 'सभी शासनों में सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर पाया जाता है परंतु जिस प्रकार से यह ब्रिटिश संविधान का एक अंग बन गया है वह अन्यत्र नहीं है। There are plenty of contrasts between Theory & Practice in all govts But

in none do they form the very warp and woof of the system as in the British) सिद्धांत में नॉर्ड सभा उच्चतम 'नायपालिका' है किंतु इसमें केवल कानून के लॉड्स का भाग लेंते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत तथा व्यवहार के दृष्टान्त भरे पड़े हैं। सिद्धांततः प्रधानमंत्री का कार्य मुख्य नायपालिका को परामर्श देना है। किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। सिद्धांत तथा व्यवहार के इस अंतर को न समझ पाने के कारण फ्रांसीसी दार्शनिक मॉण्टेस्क्यू यह प्रतिपादित कर बैठे कि इंग्लैंड में शक्तियाँ का पृथक्करण है। वेजहाट के कथनानुसार "व्यावहारिक जीवन में वह (प्रेक्षक) उन समस्त बातों का देखेगा जो पुस्तक में नहीं हैं और सिद्धांतों के साहित्यिक प्रतिपादन की अनेक शालीनताएँ उसे कठोर व्यवहार में नहीं मिलेंगी।" सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर का वस्तुतः मूल कारण यह है कि एक तो इंग्लैंड के वैधानिक विकास में क्रमिकता पायी जाती है और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर 1688 की राजनीतिक क्रान्ति रूढ़िवादी प्रवृत्ति में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकी। वहाँ के शासन ने प्रगतिशील नीतियों को अपनाया है किंतु उसमें मन्द गति का रूढ़िवादी तत्व हमें उपलब्ध होता है। इंग्लैंडवासियों ने जीवन के कठोर संघर्ष के सामने भी रूढ़िवादी नीतियों का परित्याग नहीं किया है। इसी कारण वहाँ के राजनीतिक जीवन में सिद्धांत तथा व्यवहार का अदभुत मिश्रण पाया जाता है।

(3) यह एक परिवर्तनशील अथवा नम्य संविधान है (It is a Flexible Constitution)—ब्रिटिश संविधान की नम्यता पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मुनरो (Munro) ने कहा है कि 'ब्रिटिश संविधान कभी भी गतिविहीन एवं जड़वत् रूप में नहीं रहा। वह परिवर्तनशील, अक्रमबद्ध तथा एक सीमा तक अनिश्चित ही रहा है।' (The British Constitution has never been constrained in to stereotyped form. It has remained flexible, uncodified and to a degree indefinite) परिवर्तनशीलता उसका प्रमुख गुण है। इसके विपरीत, अमरीकी संविधान कठोरता का श्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ संवैधानिक तथा साधारण नियमों में व्यवधान किया जाता है। इंग्लैंड में संसदीय सावधानीयता की उपमिद्धि के फल स्वरूप संवैधानिक तथा साधारण नियमों में यह अंतर नहीं किया जाता। साधारण नियमों की ही भाँति संवैधानिक नियमों में परिवर्तन सुलभ हो जाता है। उनके लिए किसी भी प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। परिवर्तनशीलता का एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि संविधान समय के साथ चल सका है और व्यापक संघर्षात्मक एवं संरक्षणीय परिवर्तनों के समक्ष अस्वस्थ नहीं हुआ है। इसकी नम्यता दहता एवं शक्ति की घातक सिद्ध हुई है। नम्यता में रूढ़िवादिता समा सकती है और इसी कारण वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में लॉड्स सभा जैसा सामान्यवादी अवशेष पनपत हुआ दिखाई पड़ता है। 1836 में एडवर्ड अष्टम ने राजपद से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि मंत्रिमण्डल की स्वीकृति की अनुपस्थिति में वह इच्छानुसार सेडी गिम्पसन से विवाह नहीं कर पाया। उसका त्यागपत्र केवल आद्य घण्टे में ही मन्द द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार 1939 में प्रसादन नीति के अमर्षन विरोध के चमत्करण का समय के लिए अक्षम समझकर बर्तन दिया गया और राष्ट्रीय सरकार का गठन चर्चित

के नेतृत्व में किया गया। संसद की अवधि बढ़ा दी गयी। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं। निश्चय ही नम्यता गिरगिट का सा घम है जो परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल अपने को परिवर्तित कर लेता है। ब्राइस (Bryce) के अनुसार "संविधान के ढाँचे को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकतानुसार छोड़ा और मोड़ा जा सकता है।"

(4) यह एक एकात्मक संविधान है (It is a Unitary Constitution)—ब्रिटिश शासकीय संघटन भारत, अमेरिका तथा कनाडा आदि की भाँति सघातमय पद्धति वाले देशों में नहीं है। वहाँ शक्तियाँ का केन्द्र तथा प्रशासकीय इकाइयों के मध्य वितरण न होकर, उनका संसद के हाथों में केन्द्रोत्तरण है। संसद ही समस्त शक्तियों का एवमात्र जलाशय है और यही विभिन्न जलवाह्य शक्ति रूपी जल को प्राप्त करते हैं। संसद एक कुशल अभिव्यक्ति की भाँति इन विभिन्न शक्तिवाहकों के मध्य समुचित रूप से आवश्यकता के अनुपात में शक्तियों का वितरण करती है। संसदीय वानुनों के पुनः संशोधन की व्यवस्था नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंग्लैंड में विदेशित व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। वहाँ प्रशासकीय विवेकीकरण है किंतु अंतिम सत्ता का मूल आधार संसद अथवा केन्द्र है जिसकी इच्छा के विपरीत कोई भी स्थानीय संस्था शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। कटन का तात्पर्य यह है कि केन्द्र जिस रूप में भी चाहे शक्तियों को घटा एवं बढ़ा सकता है।

(5) यह संसदीय पद्धति वाला संविधान है (It is a Constitution with Parliamentary System)—ब्रिटेन का संविधान राजतन्त्रात्मक न होकर संसदात्मक प्रजातन्त्र है। संवैधानिक परम्पराओं में राजा का बसल एवं प्रतीक रूप में रखा है, वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमण्डल तथा संसद के हाथों में हस्तांतरित हो चुकी हैं। मंत्रिमण्डल, जो वास्तविक कार्यपालिका है राजा द्वारा नियुक्त होता पर भी विधायक मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। संसद द्वारा अधिनियम प्रारंभ करने पर कार्यपालिका को अपवाद ही के लिए बाध्य किया जा सकता है। मन्त्रीय शक्तिशाली एवं सभ्य का परिणाम है। कार्यपालिका द्वारा रंग रंग प्रस्तावों पर दृष्ट करन का तथा नीतियों का सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण माँगने का संसद को पूर्ण अधिकार है। संसदीय संसदीय शक्तिशाली लोक सभा (House of the Commons) की शक्तिशाली शक्ति है। संसदीय विधायक का पुनर्वाचनार्ह नहीं होता।

(6) अनिर्लिखित संविधान (An Unwritten Constitution)—विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित है और न ही पूर्ण रूप से अनिर्लिखित। जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित होता है उसे लिखित तथा जिसका अधिकांश भाग अनिर्लिखित होता है उसे अनिर्लिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। लिखित संविधान में भी अनिर्लिखित तत्व होते हैं और अभी प्रसार अनिर्लिखित में लिखित। लिखित संविधान मॉडेल तथा विश्व की उत्पत्ति है। उसे सभी भी लिखित बना कर लिखित संविधान निर्माता सभा का रूप नहीं दिया गया। संसद ही जनप्रतिष्ठान परम्परा पूर्वक संविधान तथा जो संविधान में लिखित है। सामान्य में लिखित संविधान के लिखित भाग का अन्तर्गत अधिनियम और अधिनियम संशोधन हैं। लिखित संविधान में भी लिखित भाग है—संविधान के अन्तर्गत अधिनियम और अधिनियम संशोधन और अधिनियम संशोधन

सैटिलमेण्ट, डरहम कमेटी रिपोर्ट, 1953 का रीजेंसी एक्ट, 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियम, आदि।

(7) विधि का शासन (Rule of Law)—डायसी (Dicey) के अनुसार इंग्लैण्ड में नागरिक स्वतंत्रता के बाहुल्य का रहस्य विधि का शासन है। स्वतंत्रताओं का अंजन सतत संघर्ष का परिणाम है। कोई भी संसदीय अधिनियम तथा संवैधानिक कानून विशिष्ट नागरिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं करता। जनाधिकार निर्धारण यंत्र की अनुपस्थिति में नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था विधि के शासन का ही अनुदाय कहा जायगा। कानून के समक्ष समानता तथा बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी को अधिक समय तक कारागृह में रखने पर प्रतिबंध इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। विधि के शासन ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। विधि के शासन में विधि को एकरूपीय, सार्वभौमिक एवं सर्वोच्च माना जाता है। फ्रांस की भांति न तो वहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय हैं और न ही दो प्रकार के कानून। कानून सब के लिए एक है चाहे वह 10 डार्जनिंग स्ट्रीट में रहने वाला प्रधानमंत्री है अथवा गली में भीख मांगने वाला भिक्षुक।

(8) सीमित रूप में शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers in a Limited Sense)—इसमें सन्देह नहीं कि फ्रांसीसी लेखक मॉण्टेस्क्यू का इंग्लैण्ड के विषय में यह प्रतिपादन अत्यंत भ्रामक था कि वहाँ की व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। रैम्जे म्योर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि अमरीकी संविधान का आधार शक्तियों का पृथक्करण है तो हमारे संविधान का आधार शक्तियों का समन्वय है। उत्तरदायी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण का निषेध है। यदि किसी भी दिशा में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है तो वह न्यायिक क्षेत्र में। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के हेतुक्षेत्र से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार वहाँ शक्तियों का पृथक्करण सीमित रूप में पाया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ संविधान में परोक्ष रूप में अवरोध एवं सन्तुलन (Checks & Balances) की पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। संसद द्वारा पारित नियम उस समय तक कानून नहीं बन सकते जब तक कि उन पर संसद की स्वीकृति नहीं हो जाती, यद्यपि यह एक औपचारिकता मात्र है। इसी प्रकार बिना संसदीय विश्वास प्राप्त किये कार्यपालिका अपनी नीतियों का सफल सम्पादन नहीं कर सकती। मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार का कोई भी अंग वहाँ पूर्ण रूप से निरपेक्ष बनने का साहस नहीं कर सकता। यही इस व्यवस्था का लक्ष्य भी है।

(9) संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary Sovereignty)—डी लोमे (De Lolme) ने कहा था कि 'ब्रिटिश संसद पुरुष की स्त्री और स्त्री की पुरुष बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकने में समर्थ है।' एडवर्ड कूज के अनुसार "संसद की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार इतना व्यापक बन गया है कि उसे सीमाओं में बद्ध नहीं किया जा सकता।" डायसी (Dicey) के शब्दों में "कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है।" (The sovereignty of Parliament from a legal point of view is the dominant charac-

teristic of our political institutions) क्विंटिन हूग (Quintin Hoog) ने कहा है कि समद जो चाट कर सकती है और मनुष्यद्वारा बनाए गए कानून द्वारा जा परिणाम उपलब्ध है उसे प्राप्त कर सकती है। अतः इंग्लैंड में समद की सत्ता निर्विघ्न, असीमित एवं सर्वोपरि है। जिना मसदीय स्वीडन के समस्त शासकीय समस्याएँ व्यक्त हैं। समद ही समस्त राजकीय शक्तियों का स्रोत है। न्यायपालिका समद द्वारा स्वीकृत कानून का अवैध घोषित नहीं कर सकती। न्यायपालिका पूर्ण रूप में समद के प्रति उत्तरदायी है। यह मसदीय सर्वोच्चता का केवल मर्यादित मूल्यांकन है। व्यवहार में मसदीय सर्वोच्चता वास्तविक नहीं है। अतः वस्तुतः हम यह कहते हैं कि लोक सभा पाय नहीं करती बल्कि मन्त्रिमण्डल की इच्छा को पजीम करती है। मसदीय शक्तियाँ म ह्रास हुआ है और वे शक्तियाँ अतः वस्तुतः मन्त्रिमण्डल की ही शक्तियाँ हैं।

मसदीय सावभौमिकता पर नियन्त्रण (Limitations of the Sovereignty of Parliament)—सिद्धांत में यह सही है कि इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जिस मसद न बना सके या किसी कानून में परिवर्तन न कर सके, इंग्लैंड में सबैधानिक तथा साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है। मसदीय सावभौमिकता का बड़ा ही विशद विवेचन डायसी ने किया है किंतु व्यवहार में मसदीय सावभौमिकता का अर्थ कोई अस्तित्व नहीं है। मसद की सावभौमिकता पर निम्नलिखित प्रतिबंध हैं

(1) मसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नतिकता के विरुद्ध हो।

(2) मसद सम्राट के परमाधिकारों का नहीं बदल सकती। वह उन पर नियन्त्रण भी स्थापित नहीं कर सकती।

(3) मसद अपने से पहली मसद द्वारा बनाये गये कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। किंतु इस भावना का भी खण्डन हो चुका है। 1800 में मसद ने Act of Union स्वीकार किया था जिसे अंतिम रूप से 1912 में समाप्त कर दिया गया।

(4) मसद व्यावहारिक रूप से जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती।

(5) मसद कानून बनाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं कर सकती।

(6) सामाजिक तथा राजनीतिक परम्पराओं में परिवर्तन नहीं कर सकती।

(7) मसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। वे उसकी शक्ति से बाहर हैं। West Rand Gold Mining Co. v. The King में इसी आशय का निर्णय किया गया था।

अतः आज मसदीय संप्रभुता का अर्थ मन्त्रिमण्डल की संप्रभुता से है। मसदीय संप्रभुता केवल कानूनी है व्यावहारिक नहीं।

(10) सबैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy)—ब्रिटिश संविधान में सबैधानिकता एवं राजतंत्र का अद्वितीय मिश्रण पाया जाता है। इन दोनों का संयोग सामांय रूप में असंगतिपूर्ण है किंतु विकासवादी प्रवृत्ति ने इसे सम्भव बना दिया है। संविधान मर्यादा एवं सीमाओं का प्रतीक है और राजतंत्र निरंकुशता का सूचक है। किंतु ब्रिटिश संविधान की सौहार्दपूर्ण विकासवादी प्रवृत्ति ने इन्हें साथ-साथ

ब्रिटिश संविधान के निर्माणक तत्व (Sources of the British Constitution)

संविधान के निर्माणक तत्वों का अर्थ है वे स्रोत जिनके द्वारा ब्रिटिश संविधान की प्रकृति के सम्बन्ध में हमें पता चलता है। ये वे निर्माणक तत्व हैं जिन्होंने संविधान को उसका आधुनिक स्वरूप प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया है। ये स्रोत वस्तुतः संविधान के अवयवी भाग तथा उसके मौलिक आधार हैं। इनसे हम ब्रिटिश संविधान के स्वभाव को समझने में पर्याप्त सहयोग मिलता है। ये अवयवी भाग इस प्रकार हैं

(1) **संवैधानिक समझौते (Constitutional Compromises)**—ये संवैधानिक समझौते सफ्ट के समय राजा तथा प्रजा के मध्य हुए। राजा स्वच्छाचारी होकर जनता पर करारोपण तथा शासन करना चाहते थे और जनता अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सचेष्ट थी। दोनों पक्षों में समझौते हुए जिनके माध्यम से राजा के अधिकारों की सीमाएँ तथा जनता के अधिकारों का क्षेत्र सन्तुलित होता अथवा बढ़ता रहा। इनके द्वारा लोकतन्त्र का बटवृक्ष बढ़ता ही चला गया। जनता ने कठोर संधर्ष के उपरान्त अपने स्वत्वों को छीना और जनतन्त्र को व्यावहारिक रूप दिया। ये समस्त समझौते एक समय पर नहीं हुए। इनमें से कुछ प्रमुख समझौतों के नाम इस प्रकार हैं

(क) 1215 का **मग्नाकार्टा** (यह प्रथम आनापत्र नागरिक स्वतन्त्रता को उद्घोषित करने वाला था जब राजा जॉन ने जनता से भयभीत होकर इस पर अपनी सहमति दी)।

(ख) 1628 का **प्रायनापत्र (Petition of Rights)**—अकारण किसी व्यक्ति को बन्दी बनाने के राजा के अधिकार को खत्म किया गया तथा उसके कर लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया।

(ग) 1686 का **अधिकार पत्र (Bill of Rights)**—इसने लोकतन्त्र के प्रगति द्वार सदा के लिए खोल दिये।

(2) **संसदीय विधियाँ (Parliamentary Acts)**—संसदीय अधिनियम वस्तुतः वे अधिनियम हैं जो समय समय पर संसद द्वारा पारित किये जाते रहे हैं और जिनके द्वारा राजा की शक्ति उत्तरोत्तर नियन्त्रित होती रही है तथा नागरिक अधिकारों का विकास होता रहा है। इनके द्वारा केवल ब्रिटिश संविधान ही सजीव नहीं बना है बरन उसमें से सामन्तवादी तत्वों को भी खत्म किया गया है। ये अधिनियम इस प्रकार हैं

(1) 1679 का बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (**Habeas Corpus Act**), 1679)।

(2) 1701 का समझौते का अधिनियम (**Act of Settlement**)।

(3) 1707 का स्कॉटलैण्ड से संयोग का अधिनियम (**Act of Union with Scotland**)।

(4) आयरलैण्ड से संयोग का अधिनियम (**Act of Union with Ireland** 1800)।

(5) 1832 1867 तथा 1884 के सुधार अधिनियम।

(6) 1835 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट।

(7) 1872 का म्युनिसिपल चुनाव अधिनियम।

- (8) 1873, 1875, 1876 तथा 1894 का 'यायालय अधिनियम'।
- (9) 1888, 1894, 1929 तथा 1933 के स्थानीय शासन।
- (10) 1911 का संसदीय विधेयक।
- (11) 1918 तथा 1948 का जनमत प्रतिनिधित्व अधिनियम।
- (12) 1920 का आयरिश सरकार अधिनियम।
- (13) 1931 का वेस्टमिनिस्टर परिनियम (Statute of Westminster)।
- (14) 1936 का सिंहासन परित्याग अधिनियम (Abdication Act)।
- (15) 1937 का क्राउन एक्ट (Crown Act of 1937)।

(3) 'न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions)—डायसी (Dicey) ने ब्रिटिश संविधान को 'न्यायधीन' द्वारा निर्मित संविधान कहा है। समय समय पर कानून की उपस्थिति में विवेक का प्रयोग करते प्राकृतिक न्याय के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा जो नियम प्रसारित किये गये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो बात अमरीकी उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में सही है, वही ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था के विषय में भी कही जा सकती है। राजा के परमाधिकारों तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का विकास न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। इसी प्रकार का एक न्यायिक निर्णय Wilkes v. Wood में दिया गया था जिसमें यह निश्चय किया गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तलाशी अथवा गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता जिस लेखक का नाम पुस्तक पर न हो। हावेल के प्रसिद्ध निबन्ध में 'न्यायिक स्वतंत्रता की चर्चा व्यापक रूप से की गयी है। अतः डायसी का यह कथन सही है कि ब्रिटिश संविधान प्रचलित अर्थ में संसद के प्रतिनिधियों के प्रयत्नों का फल होने के स्थान पर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए न्यायालयों में लाये गये अभियोगों का परिणाम है।'।

(4) सामान्य विधि (Common Law)—मुनरो के कथनानुसार सामान्य विधि वह कानून है जिसका विकास परम्पराओं के माध्यम से हुआ है और जिसे समस्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है। 'न्यायिक निर्णयों में सबधानिक महत्व की बहुत-सी बातें अनायास ही हम उपलब्ध होती हैं। ये नियम अब इतने अचल हो गये हैं कि इनके उल्लंघन करने वाले को दण्ड अवश्य मिलता है। शताब्दियों के निरंतर प्रयोग के कारण सामान्य आचरण के नियम अनिवार्य-से बन गये हैं। वे इंग्लैण्डवासियों के जनजीवन में मिश्रित एवं आत्मसात् हो गये हैं। सामान्य कानून की स्थापना में पूर्व दृष्टान्तों का भी महत्व है। राजा ने अपने परमाधिकारों तथा संसद ने अपनी सर्वोच्चता सामान्य विधि से प्राप्त की। ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण का एवमाश्रय वहाँ की सामान्य विधि को है। ऑग (Ogg) के शब्दों में "सामान्य कानून अथवा विधि में वे सब रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ सम्मिलित हैं जिनका रूप शताब्दियों के प्रयोग के कारण अनिवार्य-सा हो गया है।" (Common Law consists of a vast body of legal percepts and usages which through the centuries have acquired binding and almost immutable character) कार्टर (M G Carter) ने भी सामान्य विधि को ब्रिटिश स्वतंत्रता का रक्षक माना है।

(5) कानूनी टीकाएँ (Legal Commentaries)—ब्रिटिश संविधान के स्वभाव तथा उसकी प्रगति के विविध स्तरों का परिचय हमें कानूनी टीकाओं के माध्यम

प्राप्त होता है। इन टीकाओं की रचना शास्त्रीय ढंग से की जाती है और इनके लेखक उच्चकोटि के विधिशास्त्री अथवा विधिवक्ता होते हैं। ये वैधानिक टीकाएँ तो सदैव कानून की श्रेयता में सहयोगी सिद्ध हुई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण टीकाएँ इस प्रकार हैं

- (1) एनसन (Anson) द्वारा रचित 'सविधान की विधि एवं लोकाचार', (Law & Custom of the Constitution)।
- (2) डायसी की 'सविधान की विधि (Law of the Constitution)।
- (3) मे (May) की 'संसदात्मक प्रथा' (Parliamentary Practise)।
- (4) सिडनी ला का 'इंग्लैण्ड का सविधान'।
- (5) वेजहॉट द्वारा रचित 'इंग्लैण्ड का सविधान'।

सविधान के अभिसमय

(Conventions of the Constitution)

मिल के अनुसार अभिसमय सविधान के अलिखित भाग हैं (Unwritten maxims of the Constitution)। ये ब्रिटिश जीवन में इस प्रकार मिश्रित हो गए हैं कि उन्हीं की शक्ति पर इंग्लैण्ड के सविधान का भव्य भवन टिका हुआ है। अभिसमय सविधान के सार हैं। उन्हें निष्ठापित कर देने से सविधान व्यर्थ एवं अव्यावहारिक हो जायगा। डायसी (Dicey) का यह कथन सही है कि ब्रिटिश सविधान अभिसमयों का सविधान है। अभिसमय सविधान के वे रीति रिवाज एवं परम्पराएँ हैं जो वहाँ के निवासियों की आदतों तथा उनके व्यवहार में अचेतन रूप में समा गये हैं। इसी कारण एनसन (Anson) ने अभिसमयों का सर्वैधानिक परम्पराएँ कहा है (Customs of the Constitution)। फाइनर (H. Finer) के शब्दों में "अभिसमय राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनिर्णयों, यायिक निर्णयों अथवा परम्पराओं के अंतर्गत नहीं हुई है।" (Conventions are rules of political behaviour not established in statutes judicial decision or Parliamentary custom) अभिसमयों के कारण ही ब्रिटिश सविधान इतना लचीला बन सका है। अभिसमय सविधान को गति प्रदान करने वाले भाग हैं। वे सविधान की विकासवादी प्रकृति के प्रतीक हैं। अभिसमयों के विषय में हम यह नहीं जानते कि वे कब और कहाँ से प्रारम्भ होते हैं। अभिसमयों के निम्नलिखित लक्षण हैं

(क) अभिसमयों का निर्माण संसदीय शक्ति द्वारा सम्पन्न नहीं होता।

(ख) कानून तथा यायालयों द्वारा उन्हें मान्यता न मिलने पर जन-समुदाय उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है।

(ग) सर्वैधानिक कानून न होने पर भी वे सर्वैधानिक कानूनों जैसी पवित्रता का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण इन्हें सविधान के मौखिक आधार कहा जाता है।

अभिसमयों का महत्व (Importance of Conventions)

(1) सविधान के निर्माण में योगदान (Facilitated the Growth of the Constitution)—ब्रिटिश सविधान के विकास में अभिसमयों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। इन्हीं के माध्यम से निरंकुश राज्यतंत्र को सर्वैधानिक राज्यतंत्र में बदला जा

सका। इन्हीं के सहयोग से ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का जनतन्त्राकरण हुआ। प्रधान-मंत्री का पद, क्राउन रूपी संस्था का विकास, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति, मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था की स्थापना आदि में अभिसमयों का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने संविधान को गति प्रदान की है।

(2) संविधान के क्रियान्वयन में योग (Helped the Execution of the Constitution)—संविधान को जन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का श्रेय अभिसमयों का है। ये जन शक्ति को नूतन दिशा दिखाते हैं तथा प्राचीन में हमारी आस्था दृढ़ करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये राजनीतिक उतार-चढ़ावों में मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। जेनिंग्स (Jennings) के कथनानुसार अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ाते हैं। वे कानूनों की निश्चितता एवं निरंतरता के बौद्धिक स्तम्भ प्रदान करते हैं। अभिसमयों के न होने पर संवैधानिक ढांचा लड़खड़ा जायगा। अभिसमयों के द्वारा ही कानूनी तथा राजनीतिक सप्रभु के मध्य ताल-मेल उत्पन्न होता है। कानूनी दृष्टि से राजा मन्त्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु अभिसमय राजा तथा मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक संपर्क को समाप्त करते हैं। अभिसमयों के अनुसार राजा मन्त्रिमण्डल द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट होने पर वह सत्तारूढ़ नहीं रह सकता, उसे त्याग पत्र देना ही होगा।

(3) ससदीय प्रणाली के संचालन में सहयोगी (Helpful in the Conduct of Parliamentary System)—बियर्ड के अनुसार अभिसमयों का वैसे तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी महत्व है किन्तु ससदीय प्रणाली में यह उससे भी अधिक है। ससदीय प्रणाली में सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर होता है। इस अंतर को खाई अभिसमयों द्वारा ही पूर की जा सकती है। ससदीय प्रणाली का यह सिद्धांत कि बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाय, केवल अभिसमय द्वारा ही सम्भव है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाममात्र का शासक होता है, यह अभिसमय द्वारा ही प्रमाणित हो सका है। वित्त विधेयक केवल प्रथम सदन में ही प्रस्तावित होना चाहिए तथा कानून बनने से पूर्व प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होने चाहिए, आदि ससदीय सिद्धांत अभिसमयों द्वारा ही सुलभ हो सके हैं। ब्रिटेन में अभिसमय द्वारा ही यह सम्भव है कि लॉर्ड सभा 'याय का सर्वोत्तम आगार' है किन्तु उस कार्य में केवल कानून के लॉर्ड ही भाग लेते हैं। जेनिंग्स के अनुसार समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल ये प्रशासन को जागरूक बनाते हैं और शासक वर्ग को उन परिवर्तित परिस्थितियों के संचालन के लिए योग्यता प्रदान करते हैं।

(4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा (Protect the Rights of Minorities)—प्रो० व्हीयर (Wheare) के अनुसार अभिसमय का एक महत्वपूर्ण कार्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा है। दोनों सदन के सम्बन्ध में अभिसमय तालमेल उत्पन्न करते हैं। व्यवस्थापिका का संगठन निश्चित होता है। डायसी (Dicey) के अनुसार अभिसमयों द्वारा संसद की विवेकीय शक्तियों का निर्धारण होता है। अतः अभिसमयों ने ब्रिटिश संविधान का गति एवं नैतिक बल प्रदान किया है।

(5) राष्ट्रमण्डल तथा जन-संप्रभुता को सफल बनाया है (They

Commonwealth and Popular Sovereignty Successful)—अभिसमयों ने एक जटिल महत्वपूर्ण राज्य राष्ट्रमण्डल को सफल बनाकर दिया है। ब्रिटिश राजा को साम्राज्यीय एकता का प्रतीक कहा जाता है। राष्ट्रकुल के सदस्यों की थोड़ा सम्राट के प्रति है—यह अभिसमय द्वारा ही सम्भव हो गया है। जेनिंग्स ने अभिसमयों का एक महत्वपूर्ण अनुदाय यह बताया है कि उनके द्वारा जन संप्रभुता सजग एवं सफल बन सकी है। जन प्रतिनिधित्व को वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो सका है।

अभिसमयों के प्रकार

(Kinds of Conventions)

1. व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के सम्बन्ध में (In Respect of Legislature and the Executive)

(1) मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का ससद की सदस्यता अनिवार्य है। इसके अभाव में अमुक व्यक्ति को मंत्री तो बनाया जा सकता है किन्तु उसे 6 माह की अवधि में स्वयं को ससद का सदस्य बनाना पड़ेगा।

(2) ससदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिसमय यह है कि कार्यपालिका विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहती है। इससे अभिप्राय यह है कि ससद द्वारा अविश्वाम व्यक्त करने की स्थिति में प्रधानमंत्री के समक्ष दो विकल्प होते हैं—प्रथम तो यह कि वह अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दे और दूसरा यह कि वह सम्राट से जटिल स्थिति में लोक सभा को भग करके नूतन निर्वाचन का आदेश दे। यदि पुनर्निर्वाचन के समय राष्ट्र प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन नहीं करता तो वह पुनर्निर्वाचन की भाग नहीं कर सकता।

(3) मन्त्रिमण्डल के मुख्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः मन्त्रिमण्डल का समग्रित स्वरूप है।

(4) लोक सभा का अध्यक्ष निरदलीय व्यक्ति होता है, उसका निर्वाचन केवल एक औपचारिकता है। वह जय तक चाहे अध्यक्ष रह सकता है।

(5) अवकाश ग्रहण करने पर उसे लोक सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है।

(6) लॉर्ड सभा जब अपीलनीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, उस समय समस्त मुख्य भाग नहीं लेते। केवल कानून के लॉर्ड (Law Lords) ही भाग लेते हैं।

(7) लोक सभा वित्त विधेयक पर तभी विचार करती है जबकि उसकी प्रस्तुति राज्य की ओर से मन्त्रिमण्डल द्वारा की गयी हो।

(8) लोक सभा मन्त्रिमण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में रखी गयी भाषा को घटा ता सकती है किन्तु उन्हें बदल नहीं सकती।

(9) कानून बनाने से पूर्व प्रत्येक विधेयक का तीन बार वाचन होना चाहिए।

(10) ब्रिटिश संविधान का एक अभिसमय यह भी है कि बहुमत दल के सदस्य का भाषण हो। चुनने के बाद विरोधी दल के सदस्य का भाषण होना चाहिए।

2. राजा के सम्बन्ध में (In Respect of King)

(1) राजा को अपने मंत्रियों के परामर्श पर आचरण करना चाहिए।

(2) निर्वाचन के उपरान्त राजा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के

लिए आमंत्रित करता है। उसके परामर्श पर ही वह अथ मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

(3) राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह वष में कम से कम एक बार वह संसद का अधिवेशन अवश्य आहूत करे।

(4) राजा मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता।

(5) यदि लॉर्ड सभा किसी विधेयक को स्वीकार न करके गतिरोध उत्पन्न करना चाहती है तो उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधेयक पारित कराया जाता है।

(6) संसद द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राजा को अनुमति प्रदान करनी होती है।

(7) राजा मन्त्रिमण्डल द्वारा आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई कार्य कर सकता है।

3 राष्ट्रमण्डल के सदस्य में (In Respect of Commonwealth)

(1) राजा के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्बन्ध में बात करते समय सम्बन्धित विभाग के मन्त्री से परामर्श करे।

(2) संसद किसी भी उपनिवेश के तन्ही कानून बनायेगी जबकि स्पष्ट रूप में उस उपनिवेश द्वारा अनुरोध किया गया हो और स्पष्ट अनुमति प्रदान की गयी हो।

इसके अतिरिक्त भी ब्रिटिश संविधान में अथ अभिसमय है, जैसे सामाजिक नियम बनाते समय उस वर्ग विशेष से परामर्श करना चाहिए तथा लोक सभा में समितियों के सदस्यों की संख्या सदन में विविध दलों की सदस्यता के अनुपात में होनी चाहिए, आदि। इसी प्रकार लोक सभा के अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद स्वयं उसका निर्णय कर सके।

कानून तथा अभिसमय (Law & Conventions)

जब संविधान के आकार तथा तात्कालिक विचारधारा में अंतर दिखाई देता है और उसकी पूर्ति कठिन हो जाती है, उस समय अभिसमयों का जन्म होता है। अभिसमय के माध्यम से अनुकूलता लायी जाती है। इसी के कारण तो इंग्लैंड के राज तन्त्रीय आकार में लोकतन्त्रीय व्यवस्था सफल हो सकी है। इसीलिए सम्राट, मन्त्रिमण्डल तथा संसद आदि के सम्बन्ध में विविध प्रकार के अभिसमय उत्पन्न हुए। कभी-कभी कानून की शून्यता के कारण भी अभिसमयों का जन्म होता है। यह बात वस्तुतः सही है कि यदि हम कानूनों तथा अभिसमयों को समानांतर रेखाओं की भाँति नहीं मान सकते तो उन्हें व शब्द भी नहीं कहा जा सकता जिनका प्रयोग हम एक-दूसरे के लिए कर सकें। यद्यपि अभिसमयों की पुष्टि में कानून जैसी शक्ति होती है किन्तु उन्हें कानून नहीं कहा जा सकता। डा० जेनिंस के शब्दों में "यद्यपि पहले अभिसमय कानून की ही नींव पर बनते हैं किन्तु जब वे स्थायी हो जाते हैं तो वे कानून के आधार बन जाते हैं।" (Though the conventions are built in the first instance on the foundations of Law, when once they have been established they tend to form the basis of Law) कानून तथा अभिसमयों के पारस्परिक भेद को निम्नवत् स्पष्ट किया जा सकता है

42314

06/11/2021

(क) निश्चितता के आधार पर (On the Basis of Positivity)—कानून निश्चित होते हैं उनके स्वरूप को स्वेच्छा से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनमें विविध व्याख्याएँ नहीं होती। उनके निर्माण की तिथि सद्धम, लक्ष्य तथा क्षम की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। अभिसमय के सम्बन्ध में यह सब कुछ कह सकता कठिन है कि उनकी उत्पत्ति कब तथा कैसे हुई और निश्चित रूप से उनका स्वरूप क्या है? उस दिशा में सापेक्षिक तत्त्व अधिक हैं। वस्तुपरक नहीं हैं। यह स्वाभाविक बात है कि जो वस्तु निश्चित है, वह स्पष्ट भी होगी। कानून स्पष्ट होते हैं किन्तु अभिसमय स्पष्ट नहीं होने, वे भ्रान्ति की घुघलिका में छिप रहते हैं।

(ख) निर्माण के आधार पर (On the Basis of Formulation)—कानून का निर्माण विधि निमात्री शक्ति द्वारा सम्पन्न होता है। इसी शक्ति के द्वारा वह लिखित रूप में निहित भी किया जाता है। कानून की शब्दावली भी सुनिश्चित एवं स्पष्ट होती है। किन्तु, इसके विपरीत, अभिसमयों का निर्माण नहीं होता बरन उनका विकास हुआ है जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। अभिसमय की तुलना एक वृक्ष से की जा सकती है जो धीरे धीरे बढ़ता है और कानून की तुलना एक भेज से कर सकते हैं जो शीघ्र बन जाती है। अभिसमय के लिए कोई विधान समिति नहीं बैठायी जाती। यह पता चलाना भी कभी-कभी कठिन हो जाता है कि कौन-सी प्रथा किस समय अभिसमय बन गयी।

(ग) स्वीकृति के आधार पर (On the Basis of Sanction)—अभिसमयों को 'यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। अभिसमय 'यायालया द्वारा अधिशासित नहीं किये जाते अभिसमयों के तोड़ने पर किसी भी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं की जाती। इसके विपरीत कानूनों को 'यायालय द्वारा क्रियावित किया जाता है तथा उन्हें 'यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। कानून के उल्लंघन करने पर शारीरिक दण्ड की व्यवस्था रहती है। अभिसमयों के पीछे अधिक से अधिक नतिक शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है। कानून का रूप शक्ति का होता है और अभिसमय का स्वेच्छा का। कानून की दृष्टि में 'अनिवार्य शब्द है और अभिसमय के साथ 'विकल्प' जुड़ा हुआ है। इसी कारण सम्भवतः अभिसमयों को राजनीतिक नतिकता के नियम मान कहा जाता है।

(घ) ज्ञान पहिचान के आधार पर (On the Basis of Acquaintance)—ज्ञान-पहिचान के आधार पर भी कानून तथा अभिसमयों में अंतर किया जाता है। कानून सविदित होता है और उसे सभी जानते हैं किन्तु अभिसमयों को बहुत-से लोग नहीं जानते। जेनिंग्स (Jennings) के शब्दों में 'परम्पराएँ विषय प्रश्न होते हैं जिन्हें वे ही जान सकते हैं जिनका उनसे सम्बन्ध है।' (Conventions are primarily technical questions They are known only to those whose business is to know them) अतः परम्पराओं की जानकारी जनसाधारण को नहीं होती।

किन्तु कानून तथा अभिसमयों के इस अंतर से हम यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अभिसमयों का कोई महत्व नहीं है। सत्य ही इनमें कोई गहरा अंतर नहीं है। बहुत से कानून अभिसमयों के आधार पर निर्मित हुए हैं जैसे 1937 का Ministers of the Crowns Act 1931 का Statute of Westminster।

जेनिंग्स के शब्दों में "कानून और परम्परा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। संविधान जनता की सहमति के साथ सम्बद्ध रहता है।" (The distinction between Law and Conventions is not really of fundamental importance. A constitution rests on acquiescence whether established by referendum or tacit approval.)

अभिसमयों के पीछे स्वीकृति (Sanction behind Conventions)

फाइनर ने परम्पराओं को राजनीतिक व्यवहार के नियम अथवा अलिखित सिद्धांत कहा है। (Conventions are rules or unwritten principles understanding or maxims of Political Behaviour) यह सही है कि स्वरूप की दृष्टि से अभिसमय तथा कानून में जनसाधारण के लिए कोई अंतर नहीं है किंतु जब दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं तब उनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्र परम्पराओं का स्वागत करता है और उनकी उपेक्षा को बर्दाश्त भी नहीं करता। यह स्वाभाविक प्रश्न है कि जब अभिसमयों के उल्लंघन करने पर भी कोई दण्ड नहीं दिया जाता तो जनता उनका पालन क्या करती है? यह अभिसमयों की दृष्टि में स्वीकृति कहलाती है। अतः परम्पराओं के पीछे निम्नलिखित स्वीकृतियाँ होती हैं

(1) 'न्यायिक कायबाही का भय (Fear of Judicial Punishment)'—प्रो० डायसी (Dicey) के अनुसार अभिसमयों की दृष्टि में 'न्यायिक कायबाही का भय' होता है। जब कभी भी परम्पराओं का उल्लंघन होता है तो निश्चय ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कानून का भी उल्लंघन होता है जिसके फलस्वरूप उल्लंघनकर्ता कानून की गिरफ्त में आ जाता है। अभिसमय कानून न होते हुए भी उनके इतने समीप तथा उनसे इतने एकरूप है कि दोनों को पृथक् करना लगभग असम्भव सा जान पड़ता है। स्वयं डायसी के शब्दों में 'परम्पराओं का पालन इस कारण किया जाता है कि इनका पालन न करने से व्यक्ति तुरंत ही कानून के शिकंजे में आ जाता है और वह न्यायालय से सघप में पड़ जाता है।' डायसी ने पुनः कहा है कि "राजनीतिशास्त्र की आचार संहिता के सिद्धांतों को चाहे महाभियोग के भय से स्थापित किया गया हो या जनमत ने प्रभावित किया हो किन्तु परम्पराओं की दृष्टि में यह शक्ति है कि इनको भंग करने वाले व्यक्ति तुरंत ही देश के नियमों तथा न्यायालयों के साथ सघप में आ जाते हैं।" डायसी इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि परम्पराओं के पीछे जनमत का तत्त्व निश्चित हो चुका है। डायसी ने अपने तर्कों की पुष्टि में कहा है कि यदि प्रति वर्ष कम से कम एक बार संसद का अधिवेशन आहूत नहीं किया जाता तो उससे केवल अभिसमय ही भंग नहीं होंगे, कई प्रकार की वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जायेंगी। वार्षिक बजट स्वीकार नहीं हो सकेगा, फलतः कमचारियाँ तथा सेना के सदस्यों को वेतन नहीं मिल सकेंगे। अनधिकृत करों के आधार पर सेना को रखना अवध होगा। प्रशासन बिखर जायगा। राजा मनमाने ढंग से शासन करने लगेगा। इस प्रकार लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जायगा।

किंतु डायसी द्वारा प्रस्तुत तर्क आंशिक रूप से सत्य ही माने जा सकते हैं,

पूरा सत्य नहीं। कानून तथा परम्पराएँ कदापि सहगामी नहीं हो सकते। अतः डायसी की यह मायता अशुद्ध है कि परम्पराएँ तथा कानून अयो-याधित हैं। ससद सप्रभु सत्ता सम्पन्न है और इस प्रकार कई वर्षों तक वे लिए बजट स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार प्रशासन के लिए कोई खतरा उत्पन्न होने का भय नहीं रहता।

दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे अभिसमय भी हैं जिनके अतिक्रमण से कानून भंग नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि प्रधानमंत्री लॉर्ड सभा में से नियुक्त किया जाय तथा स्पीकर (Speaker) निर्वाचित होने के पश्चात् अपने दस से त्यागपत्र न द तो उससे अभिसमय का उल्लंघन तो होता है किन्तु किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि अभिसमयों का पालन उनकी उपयोगिता के कारण होता है। 1868 में प्रधानमंत्री डिजरायली आम चुनावों में हारने के पश्चात् ससद में उपस्थित नहीं हुए और परम्परा को तोड़कर त्यागपत्र देकर चले गये। अतः जेनिंग्स (Jennings) का यह कहना सही है कि 'अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने ही लिए नहीं है, उनका अस्तित्व इसलिए भी है क्योंकि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं।'

(2) अभिसमयों की पुष्टि में जनमत की स्वीकृति है (Sanction of Public Opinion)—डायसी (Dicey) के ठीक विपरीत लवेल (Lowell) की मायता है कि अभिसमयों का पालन इसलिए होता है क्योंकि उनके पीछे जनमत की शक्ति है। कानून को तोड़कर तो सरकार कुछ समय तक रह सकती है किन्तु जनता की उपेक्षा कर लोकतन्त्रीय व्यवस्था में उसका टिकना एक जटिल प्रश्न है। अभिसमयों के प्रति जनता का हृदय में अगाध प्रेम रहता है। उनके प्रति जनता का निष्ठा इस सीमा तक है कि जनता उनके अपमान को सम्भवतः बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनमत के सन्दर्भ में यह तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि ब्रिटिश नागरिक स्वभाव से ही रुढ़िवादी होते हैं और उनकी श्रद्धा एवं निष्ठा की पात्र हैं वे समस्त सत्ताएँ जिन्हें हम पौराणिक कहते हैं। इसी श्रेणी में अभिसमय भी आते हैं। शासन बड़ी ही सतर्कता के साथ इन अभिसमयों के अनुपालन का ध्यान रखता है। सरकार इस तथ्य को भली भाँति समझती है कि अभिसमयों की उपेक्षा उनके पतन को सन्निकट ला सकती है। इसी कारण शासक वर्ग अभिसमयों की अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। स्वयं लवेल (Lowell) के शब्दों में 'अभिसमय एक विशेष खेल के नियम हैं। जो वर्ग इनसे सम्बन्धित है वह इन्हें पूणतया जानता है।' जेनिंग्स के अनुसार 'यह आशा-पालन व्यापक स्वीकृति पर आधारित है, किसी बल पर नहीं। यदि जनता उन्हें मानना चाहे तो कोई भी बल उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।' ऑग तथा जिंक (Ogg & Zink) के कथनानुसार 'अभिसमयों के पीछे वास्तविक सत्ता जनमत का बल है और इसका पालन इसलिए किया जाता है कि जनता की माँग है कि उनका पालन होना चाहिए। (The real sanction behind conventions is the force of the public opinion. Conventions are obeyed because the public opinion demands that they must be obeyed) अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि जनमत अभिसमयों की आत्मा है। जनता उनके अनुसरण की आन्तरिक अभिलाषा रखती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि डायसी की अपेक्षा लॉवेल का मत सत्यता के अधिक निकट है, किन्तु वह भी अभिसमयों के उपयोगिता पक्ष को विमुख कर देता है। जनमत की शक्ति चाहे अभिसमयों की दृष्टि में हो किन्तु उसे पूर्ण एवं एकमात्र आधार नहीं कहा जा सकता। अभिसमयों के सम्बन्ध में चर्चा करते समय लॉवेल यह भी भूल जाता है कि उनका पालन इस कारण से भी होता है क्योंकि वे स्थायी महत्व के होते हैं, केवल पौराणिक होना ही उन्हें स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी पुष्टि में सदैव व्याप्त रहने वाली उपयोगिता है। फाइनर (Finer) ने अपनी पुस्तक '*Major Govts of Modern Europe*' के पृष्ठ 60 पर कहा है कि अभिसमयों के पीछे स्वीकृति का आधार उनकी सदैव व्याप्त रहने वाली उपयोगिता है। (The compelling power of conventions comes from the public recognition of their lasting worth)

(3) अभिसमय संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल हैं (Conventions are in tune with Constitutional Principles)—लास्की (Lasky) के मतानुसार अभिसमयों का पालन इसलिए होता है क्योंकि उनकी अवस्थिति से ब्रिटिश लोकतंत्र को भय उत्पन्न नहीं हुआ। अभिसमयों ने लोकतंत्र तथा संवैधानिक सिद्धांतों को दृढ़ बनाया है, उनकी अपेक्षा नहीं की। आज हमें संसदीय लोकतंत्र का जो यह सिद्धांत दृष्टिगत होता है कि मंत्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री द्वारा होना चाहिए वह अभिसमयों के कारण ही हम बना पाये हैं। आज तृतीय यह परम्परा तोड़ना चाहता था किन्तु विलियम पिट जैसे योग्य प्रधानमंत्री के रहते हुए वह अपने इस दुर्दृश्य में सफल नहीं हो सका। उस समय से यह परम्परा पड़ गयी कि मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। इस प्रकार अभिसमयों के पालन से लोकतंत्रीय सिद्धांतों का हनन नहीं हुआ है बरन् वे स्थायी तथा व्यापक महत्व के बने हैं। इसी प्रकार यह परम्परा कि प्रधानमंत्री हाउस ऑफ़ काम्स का ही सदस्य होना चाहिए, सबदा लोकतंत्रीय अपेक्षाओं के अनुकूल है। लोकतंत्र में जिन संवैधानिक सिद्धांतों को हम स्थायी महत्व का समझते हैं अभिसमय उनके अनुकूल ही हैं। इनमें लोकतंत्र को गति एवं विश्वास प्राप्त हुआ है।

(4) संवैधानिक मतभेद (Uniformity in the Views of Political Parties on this Aspect)—लास्की (Lasky) के मतानुसार अभिसमयों के पालन में एक तत्व और भी निहित है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में देश के समस्त राजनीतिक दल लगभग एक विचारधारा एवं दृष्टिकोण के हैं। यदि इस प्रकार का मतभेद राजनीतिक दलों में उपलब्ध न होता तो अभिसमयों को देश की व्यवस्था में वह सम्मान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त है। वस्तुतः उनकी पवित्रता प्रश्न सूचक बन जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाशक वगैरे उन परम्पराओं का जीवित रखना ही चाहते हैं। राजतंत्रीय लोकतंत्र के पक्ष में सभी दल हैं।

(5) व्यावहारिक उपयोगिता (Practical Utility)—ऑग (Ogg) के मतानुसार "कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर परम्पराएँ माना मांस रूपी आवरण हैं। इनके द्वारा संवैधानिक कानून कायरूप में लाया जाता है और वे इससे विचारों के साथ मेल रखते हैं।" (They clothe the dry bones of law with flesh and

make the legal constitution work and keep it abreast of changing social needs and political ideas) जेनिंग्स (Jennings) ने एक स्थान पर लिखा है कि "सविधान स्वयं काय नहीं करता, वह मनुष्यों द्वारा त्रियावित किया जाता है। वह राष्ट्रीय सहयोग का साधन है और सहयोग की भावना उतनी ही आवश्यक है जितना कि उसका साधन। परम्पराएँ उस सहयोग के काय-साधन हेतु विस्तृत किये गये नियम हैं।" पुनः जेनिंग्स के ही शब्दों में "परम्पराएँ स्वयं के लिए जीवित नहीं रहती किन्तु उनकी उपयोगिता जीवित रहने का एक बहुत बड़ा कारण है।" (Conventions do not exist for their own sake, they exist because there are good reasons for it) न्यूमैन (Newman) ने कहा है कि संवैधानिक परम्पराओं की वैधता राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा निर्धारित होती है। (The validity of constitutional conventions will be determined by political realities) दीपगामी उपयोगिता ही सचमुच परम्पराओं की स्वीकृति का मूल आधार है। चाहे इस सम्मान में जनता की रुढ़िवादी प्रकृति का भी हाथ हो किन्तु उनकी व्यावहारिक उपयोगिता का महत्व कम नहीं है। यदि अभिसमयों में यह व्यावहारिक उपयोगिता न होती तो जनता द्वारा अभिसमयों का इस व्यापक स्तर पर सम्मान नहीं होता। आज तो वे जन जीवन के लोकतंत्रीय गाँव में इस प्रकार से घुल मिल गये हैं कि कोई भी उन्हें कष्ट नहीं मानता। यही कारण है कि ब्रिटेन में अभिसमयों का व्यापक रूप में पालन होता है।

Select References

- Finer *Major Goals of Modern Europe*
 Munro *Goals of Europe*
 Ogg & Zink *Modern Foreign Goals*
 Jennings *The British Constitution*
 Lasky *Parliamentary Goals in England*
 Sydney Low *The Goal of England*
 Keith *The British Constitution*
 Martin *The Magic of Monarchy*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- संवैधानिक अभिसमय का क्या अर्थ है? कुछ अभिसमयों का उल्लेख करके यह बतलाइए कि उनके द्वारा इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों के विकास में कैसे सहायता मिली।
 (What is a constitutional convention? Mention a few such conventions and show how they helped in the development of the constitution in England and the U S A)
- संवैधानिक अभिसमयों का ब्रिटेन के संविधान के कार्यचक्र में क्या महत्व है? उदाहरण देकर समझाइए।
 (What is the importance of constitutional conventions in the working of the British constitution? Explain with examples)
- इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की दृष्टि में रसत हुए संसदीय तथा अध्यक्षतात्मक पद्धति की कार्यपालिका का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
 (Explain the distinction between parliamentary and presidential

types of executives, keeping in view the constitutions of England and U S A)

- 4 ब्रिटिश संविधान की प्रकृति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए ।
(Critically examine the nature of the British Constitution)
- 5 "ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है ।" क्या यह कथन सही है ?
"The British Constitution does not exist " What justification is there for such a view ?)
- 6 "ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की सन्तान है ।" इस कथन का विश्लेषण करें ।
("The British Constitution is the child of wisdom and change ' Examine this statement)
- 7 ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का वर्णन करें ।
(Describe the sources of the British Constitution)
- 8 संविधान के अभिसमय से आप क्या समझते हैं ? संविधान के पीछे कौन कौन अनुशाक्तियाँ हैं ? उदाहरण सहित समझाएँ ।
(What is meant by conventions of the Constitution ? What are the main sanctions of the Constitution ? Illustrate your answer with examples)
- 9 "ब्रिटिश शासन पद्धति कानून पर आधारित होने पर भी संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित है ।" इस कथन की उदाहरण सहित विवेचना करें ।
('The British system of government though grounded in law, is largely dependent on constitutional conventions Discuss and illustrate)
- 10 "ब्रिटिश संविधान बुद्धि तथा संयोग की जात है ।' समीक्षा कीजिए ।
(The British Constitution is the child of wisdom and chance Examine)

2

राजा तथा राजमुकुट

[The King And The Crown]

"For all politics, in the end, is poetry —H. Finer

"राजा के पद आमतौर से बल प्रयोग से प्रारम्भ होते हैं जिसको समय घिस कर अधिकार बना देता है।" —ड्रायडन

"प्रत्येक थोड़ा राजमुकुट कांटो का मुकुट है और इस पृथ्वी तल पर सबका ऐसा रहेगा।" —कार्लायल

ग्लेडस्टन (Gladstone) ने एक बार कहा था कि "ब्रिटिश संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, किन्तु उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा तथा राजमुकुट का भेद है।" (There are many subtle distinctions in the vernacular of British Government and none so vital as the distinction between King and the Crown) इंग्लैंड का इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि 1688 तक राजा के निरपेक्ष अधिकार तथा उसकी सत्ता का निरपेक्ष रूप चलता रहा। राजा की आज्ञा ही कानून थी। राजकीय कार्यों में उसकी सत्ता जीवन एवं मृत्यु की व्याख्या से कम नहीं थी। समय की गति के साथ संसदीय संघर्ष तथा जन भावनाओं की व्यापक आकांक्षाओं के वेगमय प्रवाह के साथ राजा की शक्तियाँ क्षीण होने लगी और क्षीणता का क्रम इस सीमा तक बढ़ा कि आज राजा को निर्जीव खर की भाँति माना जाने लगा। राजतंत्र का जनतंत्रीकरण कर दिया गया है। राजा अब उतना प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नहीं रहा। राजा की शक्तियाँ काउन को हस्तांतरित हो चुकी हैं जिसका राजा केवल एक भीतिक प्रतीक के रूप में रह गया है। 'क्राउन' शब्द के अर्थ उस मुकुट से हैं जिसे शासक राज्यचिह्न के रूप में पहनता है और सिंहासन पर आरुढ़ होत समय शक्ति का यह प्रतीकचिह्न शीश पर धारण किया जाता है, किन्तु आज क्राउन का वह रूप नहीं है। अब वह एक संस्था है जिसमें संसद, मंत्रिमण्डल, राजा तथा प्रशासकीय तंत्र व अमर्निव पदाधिकारी तक सम्मिलित किये जा सकते हैं। क्राउन की शास्त्रिक व्याख्या करते हुए सिडनी लो (Sydney Low) ने कहा है कि "यह संविधानिक कामचलाऊ उपपत्ति है (Convenient working hypothesis)। क्राउन तो पहल भी था किन्तु उस समय उदात्त संस्थागत रूप नहीं था। धन्तुन उस समय राजा की शक्तियाँ भी इतनी विज्ञान एवं व्यापक थी कि किसी ने कभी इन दावा में आर राजन का दुस्माद नहीं किया। उस समय यह अन्तर

वैधानिक महत्व का भी नहीं था, इसी कारण उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। उस समय राजकीय शक्तियाँ राजा में ही केन्द्रीभूत थी, किन्तु आज वे क्राउन में हैं। 1774 में हाडविक ने इंग्लैण्ड के ताल्कालिक शासक जॉज द्वितीय से कहा था कि “श्रीमान आपके मन्त्रिगण सरकार के साधन मात्र हैं।” जॉज द्वितीय मुस्कराया तथा उसने उत्तर दिया, “इस देश में मन्त्रिगण ही वास्तविक राजा हैं।” जॉज द्वितीय का यह कथन आज सत्य है। मन्त्री राजा के अनुचर न होकर मालिक हैं। इंग्लैण्ड में जो वैधानिक सत्य (Legal truth) है, वह व्यावहारिक दृष्टि से राजनीतिक असत्य (Political untruth) होता है।

राजा और राजमुकुट में अन्तर तथा उसका महत्व

(Distinction between the King and the Crown and Its Importance)

समस्त शासकीय तन्त्र जिस राजा के नाम पर चलता है, वह केवल नाममात्र का है। व्यावहारिक रूप में राजा की शक्तियाँ एवं उसके विशेषाधिकारों का प्रयोग क्राउन नामक संस्था द्वारा होता है जिसका राजा भौतिक प्रतीक है। सम्राट की शक्तियाँ क्राउन को हस्तांतरित हो गयी हैं। सिद्धांत में राजा संसद तथा मन्त्रिमण्डल के परामर्श की उपेक्षा कर सकता है किन्तु व्यवहार में वह सोने के पिण्ड में बंद एक चिड़िया की भाँति है। बेजहॉट (Bagehot) का यह कहना यथार्थ है कि संसद एवं मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर राजा की हस्ताक्षर करने ही होने चाहिए वह उसकी मृत्यु का परवाना ही क्यों न हो। राजा तथा राजमुकुट का अन्तर सिद्धांत तथा व्यवहार के अन्तर का प्रतिनिधि है। सिद्धांत में राजा राजतन्त्र को बनाये हुए है यद्यपि उसका व्यावहारिक रूप लोकतन्त्रात्मक है। क्राउन वस्तुतः सावभौमिक शक्तियों का सामूहिक स्वरूप है। मुनरो (Munro) ने क्राउन के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि यह तो एक कृत्रिम ‘यामिक’ व्यक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होता।” (The crown is an artificial or juristic person, it is not carnate and it never dies) फाइनर (H. Finer) के अनुसार जब हम क्राउन की गतिविधियों की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा आशय जनता, संसद तथा मन्त्रिमण्डल से होता है। “राजनीतिक ऊर्जा के इन प्रभावशाली केन्द्रों के ऊपर क्राउन एक आभूषणात्मक टोपी मात्र है।” (The crown is the ornamental cap over all these effective centres of political energy) क्राउन शक्ति का प्रतीक है। एक कानूनी अपवाद है। ऐतिहासिक दृष्टि से क्राउन की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार राजा की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार हैं। प्रो० ए० सी० कपूर के शब्दों में “क्राउन राष्ट्र के वैधानिक भवन का मुख्य प्रस्तर है।” (The crown is the keystone of the constitutional structure) ब्रिटिश संविधान में यदि कोई विस्मयात्मक एवं बौद्धिक मनोरंजन का स्थल है तो वह केवल राजा तथा राजमुकुट का अन्तर है जिसे हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं

(1) राजा एक व्यक्ति है तथा क्राउन एक संस्था है (King is a person and Crown is an institution)—आज हम व्यक्तिगत राजा की चर्चा नहीं करते वरन् संस्थागत राजा के कार्यों को महत्व देते हैं। बहने का तात्पर्य यह है कि राजा व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं करता, वह केवल एक परम्परा का प्रतीक मात्र चिह्न

मान है। उसकी समस्त शक्तियाँ मैग्नाकार्टा के हस्ताक्षरों के उपरांत शन शन त्राउन रूपी सस्था को हस्तांतरित हो चुकी हैं जिसका वह स्वयं भी एक अप्रभावशाली अंग है। राजा का व्यक्तिगत रूप में कोई प्रभाव नहीं है। सस्थागत राजा ही वास्तविक शासक है। राजा केवल ध्वजमान है। उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। शक्तियाँ मंत्रिमण्डल के सदस्यों के पास हैं जो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। बेजहॉट का यह कहना ठीक था कि रानी विक्टोरिया सेना उत्पन्न करने से लेकर युद्ध की घोषणा, विदेशों से संधियाँ तथा करारोपण मंत्रियों को हटाने तक सब कुछ कर सकती थी किन्तु सस्थागत रूप में मंत्रिमण्डल तथा संसद के परामर्श पर। अतः राजा अब व्यक्ति विशेष न होकर एक सस्था के रूप में कार्य करता है। उस पद का महत्त्व त्राउन रूपी सस्था में ही निहित है।

(2) राजा अस्थायी है तथा राजमुकुट स्थायी (King is temporary and the Crown is permanent)—इस सम्बन्ध में ब्लैकस्टोन ने कहा था कि “हेनरी, एडवर्ड अथवा जॉर्ज मर सकते हैं लेकिन राजा कभी नहीं मरता।” (Henry Edward or George may die but king survives them all) ब्रिटेन की यह बहुचर्चित वचन कि “राजा मर चुका है, राजा चिरायु हो” (King is dead Long live the King) में हम यह वास्तविकता प्रतिध्वनित होती हुई दिखाई देती है कि राजा अब राजा के रूप में जीवित नहीं है, वरन् वह एक सस्था के रूप में जीवित है जो उसका स्थायी रूप है। राजा एक व्यक्ति के रूप में महत्त्वहीन एवं अस्थायी है किन्तु एक सस्था के रूप में जिसे हम त्राउन कहते हैं, वह सदा जीवित रहता है और वही उसका अमर रूप भी है। सस्था रूपी त्राउन कभी समाप्त नहीं होता। वह शाश्वत है और उसकी शक्तियाँ का स्वरूप निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। एक राजा की मृत्यु होने तथा उसके अपदस्थ होने की स्थिति में उसका दूसरा उत्तराधिकारी पद को ग्रहण कर लेता है। अतः पद स्थायी होता है और पदाधिकारी अस्थायी। राजा विशेष के मरने से त्राउन के स्वरूप एवं व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(3) राजा व्यक्तिगत है तथा राजमुकुट सामूहिक (King is individualistic and the Crown is collective)—राजा व्यक्तिगत है और त्राउन का स्वरूप सामूहिक है। त्राउन में संसद मंत्रिमण्डल, प्रशासकीय बंग और यहाँ तक कि हम जनता को सम्मिलित कर सकते हैं। किन्तु राजा एक व्यक्ति विशेष होता है। वेड तथा फिलिप्स के अनुसार राजमुकुट शब्द से शासन की सम्पूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। त्राउन वस्तुतः जन इच्छा का प्रतीक है और राजा केवल ध्वजमान तथा साज-सज्जा एवं परम्परा का प्रतीक मात्र है। ओग तथा जिंक (Ogg & Zink) के शब्दों में “राजमुकुट राज्य की सर्वोत्तम कार्यपालिका शक्ति है। उसमें सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न संसद तथा मंत्रिमण्डल सम्मिलित हैं। (Crown is the supreme executive authority in the state and it embodies a subtle combination of Sovereign Ministers and Parliament) राजनीय शक्ति का प्रयोग राजा स्वयं नहीं करता वरन् वह मंत्रियों की सलाह पर उन शक्तियों का प्रयोग करता है। हमी दृष्टि से प्रा० ए० सी बूपर ने त्राउन का ‘संवैधानिक महाराज का मुख्य प्रस्थान’ कहा है (The Crown is the

keystone of the country's constitutional structure)। मुनरो के शब्दों में 'राजमुकुट एक कृत्रिम एवं विधि व्यक्ति है, न यह शरीर धारणा करता है जोर न यह मरता है।' डब्ल्यू वी कैर ने 'European Govt and their Background' में कहा है, "कोई व्यक्ति राजमुकुट के लिए शुभकामना या उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता।"

(4) राजा का आधार पट्टक है (Kingship is based on Hereditary Principle)—राजा के निर्माण का आधार पैतृकता का सिद्धांत है जबकि क्राउन का आधार पैतृकता का सिद्धांत नहीं है। क्राउन के दो भाग—मंत्रिमण्डल तथा कॉमंस सभा—के सदस्य जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित होते हैं। क्राउन के इस अंग का आधार जनतंत्र है। अतः क्राउन उत्तराधिकार एवं निर्वाचन के सिद्धांतों का अद्भुत सम्मेलन है। क्राउन को अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग गये। लास्की (Lasky) के अनुसार "इंग्लैण्ड में राजतंत्र को प्रजातंत्र के हाथों बेच दिया गया है।"

क्राउन की शक्तियाँ (Powers of the Crown)

क्राउन की शक्तियों से हमारा आशय उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग ससद, राजा तथा मंत्रिमण्डल द्वारा होता है। इन्हीं शक्तियों के संयुक्त स्वरूप को क्राउन कहा जाता है। क्राउन एक ऐतिहासिक उपज है और इतिहास क काल में ही उसके महत्व को ढूँढा जा सकता है। ब्रिटिश क्राउन की सीमाएँ पूर्ण रूप से निश्चित नहीं की जा सकती। लॉवेल (Lowell) ने अपनी पुस्तक 'The Government of England' (पृष्ठ 26) में कहा है कि 'कानून की दृष्टि से क्राउन की शक्तियाँ बहुत विस्तृत हैं, ये बहुत से देशों के मुख्य शासकों की शक्तियों से अत्यधिक और लगभग उतनी ही विस्तृत हैं।' (All told the executive authority of the crown is in the eye of law, very wide, far wider than that of the chief magistrate in many countries) जो शक्तियाँ पहले राजा की थी वे सब अब क्राउन की हैं। क्राउन के पास वे सब शक्तियाँ हैं जो प्रशासन का सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अपेक्षित होती हैं। कीथ (Keith) के शब्दों में 'क्राउन उन शक्तियों का स्वामी है जो प्रशासन के संचालन हेतु आवश्यक होती हैं, राजकीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होती हैं तथा दूसरे देशों से सम्बंध स्थापित करने के लिए भी आवश्यक होती हैं।' क्राउन की शक्तियों की प्राप्ति में ससद तथा मंत्रिमण्डल की इच्छा निहित है। क्राउन वस्तुतः परम्पराओं की उत्पत्ति है उनके क्रिया-चक्र के पीछे परम्पराओं की शक्ति ही कार्य करती है। इससे पूर्व कि हम क्राउन की शक्तियों का विवरण दे सकें, उनकी शक्तियों के विविध स्रोतों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है।

क्राउन की शक्तियों के स्रोत

(Sources of the Powers of the Crown)

(1) परिनियम (Statutes)—क्राउन अथवा राजमुकुट की परिनियमित शक्तियाँ व शक्तियाँ हैं जो समय-समय ससदीय विधि द्वारा उसे प्रत्यापाजित होती रही हैं। ससदीय परिनियमों से प्राप्त शक्तियों का यह वह समूह है जिसके माध्यम से

विविध शासकीय विभागा तथा स्थानीय सरकारों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये वस्तुतः राजमुकुट की शक्तियों के उबरकर खात बन गये हैं। राजमुकुट की शक्तियाँ का स्वरूप इनके द्वारा व्यापक बना है और इन्हीं के सहयोग से उसकी शक्तियों का सही विश्लेषण भी सम्भव है। इन्हीं से सम्भवतः प्रशासन को प्रत्यायाजित विधायिकी शक्तियों का अधिकार मंत्रिमण्डल को मिला है।

(2) परमाधिकार (Prerogatives)—डायसी (Dicey) के अनुसार (यह) 'क्राउन की स्वच्छन्द एवं स्वाधीन शक्ति का अवशेष है जो कभी-कभी उसके हाथों में 'यायानुसार छोड़ दिया जाता है।' (The residue of discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the crown) इंग्लैण्ड में जनतन्त्र के विकास से पूर्व राजा की शक्तियों को विशेषाधिकार अथवा परमाधिकार की संज्ञा प्रदान की जाती थी। सामन्त युग से प्रारम्भ होकर 17वीं शताब्दी तक ये राजा की शक्ति के मुख्य आधार बने रहे। राजा तथा संसद के मध्य अधिकारों के सतत संघर्ष के परिणामस्वरूप संसद की विजय हुई तथा राजा के परमाधिकार छीन लिये गये। बहुत से परमाधिकार संसदीय विधेयकों द्वारा समाप्त कर दिये गये। ज्यों ज्यों इंग्लैण्ड में संसदीय लोकतन्त्र का विकास होता रहा, विशेषाधिकारों के महत्व एवं स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। कुछ परमाधिकार प्रयोग में न आने के कारण नष्ट हो गये। जो परमाधिकार स्वाधीन शक्ति के अवशेष के रूप में बचे रहे वे सब क्राउन को हस्तांतरित हो गये। विशेषाधिकार इतने अधिक तथा विविध प्रकार के हैं कि उन्हें सूचीबद्ध करना सरल नहीं है। संसद को आज़ूत करना युद्ध तथा तटस्थता की घोषणा करना संधियों का अनुसमर्थन सावजनिक नियुक्तियाँ राजस्वमचारियों की पदच्युति तथा अपराधियों को क्षमादान प्रदान करना आदि क्राउन के विशेषाधिकार हैं। ये कभी राजा की व्यक्तिगत शक्तियाँ हुआ करती थीं। जॉग तथा जिंक (Jogg & Zink) ने विशेषाधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा है कि "विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किये जाते अपितु नियमानुसार परिपाटियों, रीतिरिवाजों तथा 'यायिक' विधियों द्वारा प्राप्त होते हैं और उन समय भी वर्तमान रहते हैं जबकि संसद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि उनमें व्यवस्था से परिवर्तन कर सके।' प्रो० कीथ (Keith) ने परमाधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा उन मूलभूत शक्तियों का समूह कहा है जो शासन की स्थिरता, जन रक्षा तथा विधिशासक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनिवार्य हैं।

(3) परिमिश्रण एवं विशेषाधिकारों का मिश्रण (Mixture of Statutes and Prerogatives)—क्राउन की शक्तियाँ का यह तीसरा स्तम्भ है। इसमें कानून तथा परमाधिकारों का मिश्रण है। राजमुकुट के कुछ विशेषाधिकारों को गणन द्वारा विधायिक रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है। इन प्रकार कानून तथा विशेषाधिकार क्राउन की शक्तियों का एक मिश्रित स्तम्भ है।

क्राउन की शक्तियाँ (Powers of the Crown)

क्राउन की शक्तियाँ का यह मूलभूत स्तम्भ नहीं रहा। कभी-कभी होती रही हैं और कभी पड़ती हैं। वास्तविकता यह है कि 1215 में पहले आठ तर्ज उभरी

शक्तियों में विघटन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय जान पड़ती है। ससदीय विधेयकों ने अलबत्ता उसकी शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। यह कहना भी सही है और ब्रिटिश संविधान का विशेषाभास भी है कि प्रजातन्त्र के विवास के साथ क्राउन की शक्तियाँ में उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। आग तथा जिंक (Ogg & Zink) का यह कहना किसी हद तक बिल्कुल सही है कि “किसी भी समय क्राउन की शक्तियाँ इस स्वीचातानी से प्राप्त अधिकारों का कुछ योग है।” मैरियट (Marriot) ने ठीक ही कहा है कि “यदि राजा की शक्ति कम हुई है तो राजमुकुट की शक्ति बढ़ी है।” राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के साथ न केवल राजकीय कार्यों का क्षेत्र ही व्यापक बना है बरन् साथ में वायपालिका की शक्तियों में भी विकास हुआ है। क्राउन की विविध शक्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित शीपकों के अंतर्गत कर सकते हैं

1 अधिशासी अथवा कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

(अ) प्रशासनिक निर्देश (Administrative Directives)—वैधानिक नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का कार्य क्राउन का है। अधिशासन और निर्देशन उसकी दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। प्रशासकीय कार्यों पर नियन्त्रण तथा उनके सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित करने का कार्य क्राउन का है। महत्वपूर्ण राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति उसी की इच्छा से होती है। “यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य सावजनिक कम चारियों को पदच्युत करने का अधिकार भी क्राउन को है। कमचारियों के लिए कृतव्यपरायणता की सुविधाएँ एवं वातावरण उत्पन्न करने का कार्य क्राउन का है। वह सर्वोच्च सेनापति है। उसका कार्य स्थानीय प्रशासन पर नियन्त्रण एवं निर्देशन स्थापित करना है। इस दृष्टि से तो वास्तव में क्राउन की शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से भी आगे निकल जाती हैं।

(ब) बहिर्देशिक सम्बन्धों का संचालन (Conduct of Foreign Relations)—वैदेशिक नीतियों का संचालन तथा उनके सम्बन्ध में अनुदेशों का प्रसारण क्राउन का कार्य है युद्ध की घोषणा तथा शांति एवं संधि वार्ता क्राउन की शक्तियों में सम्मिलित हैं। विदेशों में राजदूतों को भेजकर तथा विदेशी दूतों का स्वागत करने दीर्घ सम्बन्धों की स्थापना करना क्राउन का कार्य है। यह उसका परमाधिकार भी है। असाधारण महत्व की संधियों के लिए ही ससदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। गोपनीय बहिर्देशिक शक्तियाँ ससदीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती। आग तथा जिंक (Ogg & Zink) के अनुसार “युद्ध की घोषणा तथा संधियाँ ऐसे की जाती हैं मानो उन्हें केवल राजा ही करता हो। ससद के पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है जिससे द्वारा वह युद्ध कर सबे अथवा उसका अंत करा सके।” (War is declared and peace made as if by the King alone but Parliament itself has no direct means of bringing about a war or bringing war to an end)

(स) उपनिवेश तथा राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी कार्य (Functions relating to Colonies & Commonwealth)—उपनिवेश तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्बन्ध में क्राउन ही अध्यक्ष है यद्यपि उसकी इस शक्ति का महत्व दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। राष्ट्रमण्डलीय देशों का तो वह केवल औपचारिक अध्यक्ष मात्र है

एक एक करके लगभग सभी उपनिवेश उनके हाथों से निश्चलर स्वतंत्र नीति का अनुसरण करने लगे हैं। किंतु फिर भी प्राउन कुछ राष्ट्रमण्डलीय देशों के मंत्रिमण्डलों के परामर्श पर मर्यादित शासकों की नियुक्ति करता है।

2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

(क) वीटो का अधिकार (Right of Veto)—प्राउन राष्ट्रीय विधानमण्डल का अभिन्न अंग है। प्राउन की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ ससद राजा (King in Parliament) में निहित हैं। जब कभी हम यह पढ़ने अथवा सुनते हैं कि अमुक विधेयक को सम्राट ने स्वीकार किया है तो उससे हमारा आशय केवल यह होता है कि ससद, मंत्रिमण्डल तथा राजा ने मयुक्त रूप में उस प्रस्ताव अथवा विधेयक को स्वीकार किया है। बिना सम्राट के हस्ताक्षरों के कोई भी कानून सविधि पुस्तिका (Statute Book) में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ससद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार केवल सम्राट को है, यद्यपि यह केवल औपचारिकता मात्र है। आजकल तो सम्राट स्वयं व्यक्तिगत रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं करता बल्कि यह कार्य अब एक कमीशन द्वारा सम्पन्न होता है।

(ख) विधेयकों की प्रस्तुति (Introduction of the Bills)—प्राउन की विधायिका पर ही ससद में विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। मंत्रियों को प्रस्तावित करने का यह अधिकार केवल इसलिये प्राप्त होता है क्योंकि राजमुकुट की ओर से उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) ससद के अधिवेशन आहूत करना (Convenes the Parliamentary Sessions)—ससद के माध्याह्न तथा अमाध्याह्न दोनों प्रकार के अधिवेशन प्राउन द्वारा बुलाये जाते हैं। ससद के उद्घाटन सम्राट द्वारा होता है तथा सम्बोधन भाषण मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है और यह केवल औपचारिकता मात्र है। ससदीय सत्र की शुरुआत तथा उसके अवसान का निश्चय भी प्राउन द्वारा किया जाता है। लोक सभा का स्थगन तथा विघटन भी उसी के द्वारा सम्पन्न होता है। लोक सभा के लिए आम निर्वाचन का निश्चय भी प्राउन द्वारा होता है, लॉर्ड सभा के सदस्य पीयस की नियुक्ति भी प्राउन के द्वारा होती है।

(घ) मरिपद आदेश (Orders in Council)—मरिपद आदेश को व्यवस्थापन की श्रेणी में रखा जाता है। विधानमण्डल अथवा ससद शासकीय नीतियों के सम्बन्ध में केवल व्यापक बातों की चर्चा करती है और उनके सम्बन्ध में अन्य सूक्ष्म बातों की पूर्ति प्राउन द्वारा की जाती है। शासकीय विभागों के ये प्रत्यापोजित नियम प्राउन द्वारा मरिपद आदेशों के रूप में प्रसारित किये जाते हैं। इन मरिपद आदेशों का महत्व कानून के सदृश ही होता है।

3 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

पहले कहा जाता था कि राजा का मदविवेक न्याय व्यवस्था में अनिवार्य हाथ है किंतु व्यवहार में यह मर्यादा से बहुत दूर है। ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका के आविर्भाव के पश्चात् इस उक्ति का कोई भूय नहीं रहा है। किंतु हमें यह नहीं भ्रम लेना चाहिए कि प्राउन के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायालय

पूर्ण रूप से क्राउन के अधिवार क्षेत्र से बाहर नहीं है। 'यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन द्वारा होती है और संसदीय सहमति के उपरांत उन्हें उनके पदों से पृथक् भी किया जाता है। ममस्त राजकीय अधिकारियों को क्राउन के ही नाम से दण्डित किया जाता है। उपनिवेशों से प्राप्त होने वाली 'यायिक अपीलों की सुनवाई क्राउन द्वारा प्रिवी-कोउंसिल की 'याय समिति के परामर्श से होती है। किंतु क्राउन को कोई नवीन 'यायालय स्थापित करने का अधिकार नहीं है। केवल यही नहीं, वह वर्तमान 'यायालय की वाय पद्धति में परिवर्तन भी नहीं कर सकता। 'यायाधीशों के वेतन, कार्यकाल, पदच्युत करने की विधि आदि क्राउन के क्षेत्राधिकार से बाहर रखी गयी है। क्राउन को क्षमादान (Pardon) का भी अधिकार है किंतु यह वाय गृह सचिव (Home Secretary) द्वारा ही किया जाता है। राजमुकुट के 'यायिक अधिकारों पर टिप्पणा करते हुए आग (Ogg) ने कहा है कि अतीत में जहां राजा के 'यायालयों में राजा का कानून लागू किया जाता था और राजा को 'यायिक निषेधों में हस्तक्षेप एवं परिवर्तन करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, उस दिशा में आज क्राउन का हस्तक्षेप नाममात्र का अथवा औपचारिकता मात्र का है, क्योंकि राजा का 'याय का ज्ञात कहा जाता है।

4 धार्मिक शक्तियाँ (Religious Powers)

एंग्लिकन तथा प्रेसविटेरियन चर्चों का नियंत्रण क्राउन द्वारा होता है। वह चर्च के अनुशासन के सम्बन्ध में सर्वोत्तम अधिकारी है। इंग्लैण्ड के स्थापित चर्च का वह अध्यक्ष है। सम्राट की इच्छा से ही चर्च आफ इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय सभा (National Assembly of the Church of England) के कार्यों का सम्पादन होता है। कैटरबरी तथा आर्कबिशपों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है। किंतु स्कॉटलैण्ड के स्थापित चर्च के सम्बन्ध में क्राउन की शक्तियाँ इतनी व्यापक नहीं हैं।

5 संरक्षण एवं सम्मान की शक्तियाँ (Fountain of Honour and Patronage)

सम्राट को ही सम्मान का स्रोत माना गया है। वह सावजनिक जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है तथा उन्हें विविध प्रकार की उपाधियों से अलंकृत करता है। वह संरक्षण भी प्रदान करता है।

राजमुकुट के परिप्रेक्ष्य में जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है उनका प्रयोग वस्तुतः मंत्रिमण्डल संसद तथा लोक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री करते हैं जिन्हें जन सम्प्रभु का विश्वास प्राप्त होता है। सम्भवतः राजा के व्यक्तिगत सेवकों को छोड़कर अन्य सब कर्मचारियों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होती है। मंत्रिमण संसद व प्रति उत्तरदायी होने हैं। इन्हीं मंत्रियों को यथायथ शक्तियों का उपभोक्ता कहा जाता है। समद शन शर्तें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शक्तियों का स्थानांतरण करती चली जाती है। राजा द्वारा कोई भी प्रसारित आदेश उस समय तक बध नहीं है जब तक कि मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य द्वारा वे प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिय जायें। राजा व्यक्तिगत रूप में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, उसके नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि राजा की इच्छा ही मंत्रिमण्डल की इच्छा है। अतः लोवेल (Lowell) का यह कथन सही है कि "लोकतन्त्र व विकास का

माथ काउन की शक्तियो मे वृद्धि हुई है ।" (The British Crown grows stronger as democracy spreads)

सम्राट के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया (Royal Privileges and Immunities)

- (1) सम्राट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।
- (2) सम्राट की कोई सम्पत्ति गोलाम अथवा कुन नहीं की जा सकती ।
- (3) उसके विरुद्ध कोई 'यायिक' कायवाही नहीं की जा सकती ।
- (4) व्यक्तिगत आचरण के लिए सम्राट पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

डायसी (Dicey) ने तो इस उन्मुक्ति को इतने अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में कहा है कि यदि राजा प्रधानमंत्री के गोली भी मार तो उस पर कानूनी कायवाही नहीं की जा सकती ।

(5) श्रृण के भुगतान न होने की स्थिति में भी उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

यद्यपि सम्राट का सम्पत्ति रखने, बेचने तथा प्राप्त करने का अधिकार है किन्तु उससे पर्याप्त आय न होने की वृद्धि में उसे संसद द्वारा अनुदान स्वीकृत करने की प्रथा चली पड़ी है । 'मिजिल लिस्ट' जोपक व अंतर्गत प्राप्त होने वाले वार्षिक अनुदान की आय लगभग 475,000 पौण्ड है । 1889 तक सम्राट के व्यक्तिगत उपभोग तथा सामाजिक कार्यों के लिए उसे जो धन की आवश्यकता होती थी उसे समुचित रूप में ही रखा जाता था किन्तु अब उस पृथक् किया जा रहा है । इंग्लैंड में उत्तराधिकार व नियम Act of Settlement 1701 के आधार पर ही अब सम्मिलित हैं । इसमें प्रमुख रूप से ज्येष्ठत्व के नियम का प्राथमिकता प्रदान की गयी है । स्त्रिया की तुलना में पुरुषों को श्रृष्ठता प्रदान की गयी है । बयोलिक मत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति शासक के पद पर आसीन नहीं हो सकता । केवल प्रोटेस्टेण्ट मत के अनुयायी ही इससे योग्य स्वीकार किया जाता है । अयोग्य अथवा अव्यक्त उत्तराधिकारी की स्थिति में रोजेंट अथवा परामशदाता की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था है ।

- (6) विधायक पर स्वीकृति देना अथवा न देना ।
- (7) मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार ।
- (8) पीपल (लॉड महा के सदस्य) बनाने का अधिकार ।

विशेषाधिकारों की समीक्षा (Royal Privileges Evaluated)—बहुत-सी प्रतिप्रधात्मक परम्पराओं के कारण सम्राट इन विशेषाधिकारों को उन्मुक्त रूप से प्रयोग में नहीं ला पाता । प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को है किन्तु वह बहुमत दल के नेता को उस पद के लिए आमंत्रित करने के लिए विवश है । 1894 में रानी विक्टोरिया ने लार्ड अमबरो को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करते समय स्वविवेक का प्रयोग किया था जबकि उस पद के लिए कई प्रत्याशी थे । इस सम्प्रदाय में एक घटना 1931 की है जिस राजमहल की क्रांति (Palace Revolution) कहा जाता है जबकि हैण्डरसन को बहुमत दल का नेता निर्वाचित हुए के पश्चात् भी उसके स्थान पर रैम्ज मैकडोनेल्ड को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया

गया। इसी प्रकार 1956 में साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने ईडन के त्यागपत्र के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के विषय में उसकी सलाह न लेकर दो वरिष्ठ राजनीतिज्ञों—चर्चिल तथा सैलिसबरी—से मन्त्रणा की और मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद के लिए आमन्त्रित किया। इससे एक परम्परा टूटी।

जहां तक लोक सभा को विघटित अथवा भंग करने के विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसमें भी दो अभिमत हैं। एक पक्ष यह है जो शासक को 'संरक्षण के सिद्धांत' (Theory of Guardianship) के आधार पर बिना प्रधानमंत्री की सलाह के भी इस अधिकार को देने के पक्ष में है। दूसरा पक्ष जो लोकतांत्रिक सिद्धान्त (Democratic Theory) का अनुयायी है, इस मत के विपक्ष में है और उसका विचार है कि सम्राट राष्ट्र की राजनीति में 'तटस्थ शक्ति' (Neutral Force) तभी रह सकता है जब सविध शक्तियों (Contingent powers) का प्रयोग न करे। 'राजा कभी गलती नहीं करता' का सिद्धांत तभी सायब सिद्ध हो सकता है और पूर्ण उत्तर दायित्व मंत्रियों पर डाला जा सकता है जबकि राजा राजनीति से ऊपर रहे। लास्की (Lasky) ने भी इसी पहलू पर बल दिया है कि राजा को तटस्थ भाव से कार्य करना चाहिए और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग मंत्रिमण्डल के परामर्श से करना चाहिए। 1784 के पश्चात् हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि लोक सभा को विघटित करने से सम्बंधित प्रधान मंत्री की सलाह को राजा ने स्वीकार न किया हो।

जहाँ तक मंत्रियों को पदच्युत करने के विशेषाधिकार का प्रश्न है कुछ इसे वास्तविक तथा कुछ अवास्तविक मानते हैं। जेनिंग्स का यह मत है कि राजा यदि इस तथ्य के सम्बंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाय कि मंत्रिमण्डल का काम-सभा में बहुमत नहीं रहा है तो वह उससे त्यागपत्र की मांग कर सकता है। 1783 में जॉर्ज प्रथम ने लाड नॉथ फॉक्स के मंत्रिमण्डल को इसी आधार पर पदच्युत किया था। लेकिन राजतंत्र के हित में जेनिंग्स यही परामर्श देता है कि राजा के लिए यही उचित है कि वह अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए राजी कर ले या प्रधानमंत्री से लोक सभा को विघटित कराने का प्रस्ताव रखवाये। प्रो० कीथ (A. B. Keith) ने राजा के इस विशेषाधिकार का समर्थन तो किया है किंतु साथ में यह भी कहा कि इसका प्रयोग गम्भीर परिस्थितियों में बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ होना चाहिए। साधारण तौर पर समझा यही जाता है कि राजा स्वेच्छा से इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वह जो कुछ करता है वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राजा प्रधानमंत्री से शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं कर सकता।

1852 में इंग्लैण्ड के लोकप्रिय प्रधानमंत्री डिजरेली ने यह मत प्रकट किया था कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने अथवा न करने का राजा का विशेषाधिकार वास्तविक है। किंतु 1707 से इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है और प्रयोग में न आने के कारण यह लगभग समाप्त हो गया है। इससे अतिरिक्त यह बात भी सही है कि राजा बिना अपने अस्तित्व को खतरे में डाले ऐसे संकट को आमंत्रित भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसके समक्ष दो ही विकल्प रहते हैं—प्रतिपक्षी दल के नेता को मंत्रिमण्डल बनाने का निमन्त्रण

तथा लोकसभा का विघटित करके नवीन आम निर्वाचन कराना। दोनों ही मांग दुर्गम हैं। मुनरा ने सही कहा है कि किसी भी मांग को अपनाते के अर्थ होंगे राज सिंहासन का परित्याग।

सम्राट का स्थान (Position of the King)

1688 के पश्चात् राजा की शक्तियाँ तथा उसके वास्तविक महत्व में उत्तरोत्तर क्षय होता रहा है। राजा के विशेषाधिकारों की ऊपर जो समीक्षा की गयी है उससे यह स्पष्ट है कि राजा की स्थिति वास्तविक नहीं होकर दशनीय है। राजा की शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर मंत्रिमण्डल तथा अन्य प्रशासकीय कमचारियों द्वारा होता है। राजा या वह महत्व नहीं रहा किन्तु पद की भव्यता अवश्य है। आज प्रायः सुनते हैं कि ब्रिटेन का राजा केवल निर्जीव खर की मोहर की भाँति है (Lifeless Rubber Stamp)। ब्रिटिश राजनीति में राजा “एक स्वर्ण शून्य के सदृश” है (A golden zero)। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनेर ने कहा है कि यह विशाल गगनचुम्बी तथा अभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। (It is vast sky filling figure of splendour with a political power vacuum)। सम्राट का पद आज ऐतिहासिक रह गया है। वह व्यवहार में अति क्षीण एवं दुर्बल है। ग्लडस्टोन के शब्दों में ‘राजा के राज सिंहासन पर आसीन होने के समय से उसके जीवित रहने तक कोई भी समय ऐसा नहीं होता जबकि कोई न कोई मंत्री उसके सावधानिक कार्यों के लिए सदन के प्रति उत्तरदायी न हो और राजा की शक्ति का ऐसा कोई प्रयोग सम्भव नहीं, जिसके लिए कोई मंत्री उत्तरदायी न हो। ब्रिटिश राजा के स्थान का मूल्यांकन करते हुए फिक्टन हेग ने कहा है कि ‘ब्रिटेन राजा रूपी अध्यक्ष के रूप में एक गणराज्य बन गया है। राजपद का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें निम्नलिखित उक्तियों पर कुछ व्यापक रूप से विचार करना होगा।

(1) राजा कोई गलती नहीं कर सकता (The King can do no wrong)—ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के इस सूत्र से कि राजा कोई गलती नहीं करता, सम्राट की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं—कानूनी तथा राजनीतिक। कानूनी दृष्टि से राजा कानून से ऊपर है। उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और यहाँ तक कि वह किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता उसे दोषी घोषित करने का कोई भी न्यायालय अधिकार नहीं रखता। पहले मंत्री परामर्श देते थे और राजा निर्णय लेता था किन्तु आज स्थिति भिन्न है। अब राजा परामर्श देता है और मंत्री निर्णय लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राजनीतिक घृति के लिए राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस कानूनी सूत्र का व्यापक विश्लेषण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं।

(क) राजा कानून से ऊपर है (King is above Law)—राजा के समस्त कार्य कानून की सीमाओं से परे हैं क्योंकि उसके शब्द उससे अवश्य होते हैं किन्तु उसके द्वारा किये हुए कार्य उसके नहीं होते। मित्रात में यह सही है कि

कानून राजा की इच्छा द्वारा बनाये जाते हैं किन्तु व्यवहार में स्थिति भिन्न है। लॉर्ड अरस्किन के शब्दों में “राजा कोई ऐसा अंतःकरण नहीं रख सकता जो उत्तरदायी नागरिकों की धरोहर नहीं है।” ब्रिटिश संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार राजा पर मुकदमा चलाया जा सके। कोई भी न्यायालय उसके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखता।

(ख) राजा दूसरों से भी गलत कार्य नहीं कर सकता (King cannot get wrong done by others)—यदि यह सही है कि राजा स्वयं गलती नहीं करता तो यह कहना भी उतना ही सत्य है कि राजा किसी अन्य व्यक्ति से भी त्रुटि नहीं कर सकता। राजा किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए भी अधिकृत नहीं कर सकता। सावजनिक दृष्टि से अपराध करने वाला मंत्री भी यह कहकर अपने को नहीं बचा सकता कि उसने जो भी कार्य किया है वह राजा की आज्ञा से। 1678 का डैनबी काण्ड (Danby's Case 1678) इस सत्य का स्पष्ट प्रमाण है। विदेश मंत्री अल आफ डैनबी ने मंत्रिमण्डल से परामर्श किये बगैर फ्रांस से एक गुप्त संधि कर ली थी किन्तु मसद ने उसके इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि उसने सम्राट के आदेश पर ऐसा किया, उस पर महाभियोग का दोष आरोपित किया। मसद का यह कहना था कि सम्राट कोई गलती नहीं करता, और इस कारण उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री अपने कृत्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हैं, वे त्रुटियों के लिए राजा की शरण नहीं ले सकते।

(ग) राजा की त्रुटि के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है (Minister's responsibility for the wrongs of the King)—इस लोकतित्ति का तीसरा पहलू यह है कि प्रथम तो राजा से त्रुटि की सम्भावना नहीं है और यदि वह गलती करता भी है तो उसके लिए मूल में वह व्यक्ति उत्तरदायी है जिसकी सलाह से उसने वह कार्य किया है। राजा की इच्छा स्वयं की इच्छा नहीं होती और उसने कानून भी उसके अपने नहीं होते। उसके प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रिमण्डल उत्तरदायी है। उसके द्वारा प्रसारित आदेश उस समय तक बध नहीं है जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कर दिया जाता। एक बार राजा चार्ल्स द्वितीय के एक दरबारी ने राजा के शयन शक्ति के द्वार पर लिख दिया—

“यहाँ सोते हैं सम्राट, हमारे सरताज
विश्वास नहीं करता है जिनकी बातों पर कोई
कभी कम अवली की बात नहीं करते हैं
और न करते हैं बुद्धिमानी की बात ही कोई।”

(Here lies a great and mighty king
Whose promise none relies on
Who never said a foolish thing
Nor ever did a wise one)

इसके प्रत्युत्तर में सम्राट ने यह व्यक्त किया कि यह सच है क्योंकि मेरे द्वारा कहे शब्दों में हैं किन्तु मेरे कार्य मंत्रियों के हाथ हैं।

लॉर्ड एस्विन्घम तथा ग्लेस्टोन दोनों के शब्दों से यह ध्वनि निकलती है कि

राजगद्दी पर बैठने से लेकर अंतिम समय तक कोई क्षण राजा के जीवन में ऐसा नहीं आता जबकि वह बिना मंत्रियों के परामर्श के कोई कार्य करे। यह बात अवश्य है कि ब्रिटिश संविधान की इस धारणा के फलस्वरूप राज्य कमचारियों में शिथिलता तथा वक्तव्यों के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वे यह जानते हैं कि मुकदमा उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में होगा और राजा की कोई शरण उन्हें प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस भावना के कारण कि राजा कोई गलती नहीं करता, नागरिक अधिकारों की भी हानि हुई है। 1947 के काउन एक्ट के अनुसार अब राज्य कमचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(2) राजा राज्य करता है, शासन नहीं (The King reigns but does not Govern)—इस उक्ति का आशय यह है कि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियाँ मर क्षीणता इस सीमा तक आ गयी हैं कि हम अब कहने लगे हैं कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं। वह महत्वपूर्ण होते हुए भी महत्वहीन है। उसकी विशाल शक्तियाँ की प्रहार सीमा नगण्य हैं। वह केवल ध्वजमात्र का शासक है। उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। 17वीं शताब्दी में तो राजा राज्य तथा शासन दोनों ही करता था किंतु जनतन्त्रीय भावनाओं के विकास के साथ वह केवल नाममात्र का रह गया है। फाइनेर (Finer) के शब्दों में, “यह विशाल गगन चुम्बी तथा वनस्पतिपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है।” (It is a vast sky filling figure of splendour with a political power vacuum inside) राजा की समस्त शक्तियों का प्रयोग अब राजमुकुट द्वारा होता है। व्यावहारिक रूप में राजा केवल आलंकारिक है। उत्तरदायी मंत्री ही राजा की समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन केवल राजा के नाम पर होता है। राजा राज्य तथा शासन दोनों का अध्यक्ष होते हुए भी महत्व में शून्य है। राजा नाममात्र का शासक होता है।

किंतु इस विवरण से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि राजा प्रशासन में पूर्ण रूप से अप्रभावशाली है। बजहॉट (Bagehot) के अनुसार राजा अब भी निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण कार्य करता है

(क) परामर्श देने का अधिकार (Right to be consulted)—राजा का यह मूल अधिकार है कि वह प्रशासकीय गतिविधियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना रखे। मंत्रिमण्डल क्या करता है अथवा सोचता है इसका विषय में जानकारी रखने का अधिकार राजा का है। राजा प्रत्येक महत्वपूर्ण निणय से अपने को परिचित रखता है। राजा को परामर्श देने का भी अधिकार है और यह मंत्रिमण्डल की इच्छा पर अवलम्बित है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार।

(ख) प्रोत्साहन देना (Right to Encourage)—प्रशासकीय कार्यों में कुशलता उत्पन्न करने तथा कमचारियों के मनोउत्साह में वृद्धि करने के लिए राजा मंत्रिमण्डल के सदस्यों का प्रोत्साहन भी कर सकता है। वह मंत्रियों का ध्यान विश्वव्यापी परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन के प्रति आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार से मंत्रिमण्डल का माहौल में अभिवृद्धि होती है।

(ग) चेतावनी देने का अधिकार (Right to Warn)—राजा का यह

अधिकार है कि वह मंत्रिमण्डल को भुमराह होने तथा राज्य में त्रुटिपूर्ण नीतियों को लागू करने से रोके। विचित्र प्रकार की समस्याओं के उत्पन्न होने पर वह साहसिक तथा सही दिशामुचक के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमण्डल राजा के द्वारा दिये हुए परामर्श का मानने हेतु बाध्य नहीं है। राजा वस्तुतः मंत्रिमण्डल का विरोध नहीं करता किंतु उसे सचेत रखता है तथा संकट के समय अपूर्व धैर्य का परिचय देता है। रानी विक्टोरिया से मंत्रिमण्डल डरते थे। 1909 में एडवर्ड सप्तम ने बजट के प्रश्न पर लाइ सभा की शक्तियों को कम कराया। 1911 का संसदीय विधेयक उसी के प्रयासों से स्वीकार हो सका। जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व से विश्व शांति में इंग्लैण्ड के महत्व को बढ़ाया। 1931 में मिले जुले मंत्रिमण्डल का निर्माण उसी के प्रयत्नों से सम्भव हो सका। 1910 में लोक सभा के तीसरी बार विघटन में उसका हाथ था। 1955 में जार्ज षष्ठम के प्रयास से बेनिन परराष्ट्र विभाग सँभाल सके।

विस्तृत इन अधिकारों के होते हुए भी सम्राट की शक्ति को श्रेष्ठतम नहीं स्वीकार किया जा सकता। यथाय यही है कि राजा शक्तिहीन है और वह केवल राज्य करता है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति शासन।

राजतन्त्र का औचित्य

(Justification of Monarchy)

ब्रिटिश संविधान के विषय में यह प्रश्न कम आवश्यक नहीं है कि संसदीय लोकतन्त्र की जड़भूमि तथा जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को जन्म देने वाली श्रेष्ठ भूमि राजतन्त्र की कुष्ठता से पीड़ित रहे। इंग्लैण्ड ही वस्तुतः विश्व का वह राष्ट्र है जहाँ लोकसभा तथा राजतन्त्र का पाणिग्रहण सुलभ हो सका है और जनतन्त्रीय वधू बड़ी सौम्यता से राजतन्त्र रूपी इष्ट की आराधना में तल्लीन जान पड़ती है। प्रेक्षकों की तो यह भावना है कि ज्यों ज्यों लोकतन्त्र प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राजतन्त्र की जड़ें और अधिक मजबूत होती जाती हैं। इंग्लैण्ड के नागरिक अब भी यही कामना करते हैं कि रानी चिरायु हो, और उसके स्वस्थ भविष्य की आकांक्षा रखने हैं। वैसे तो राजतन्त्र का तरकश मात्र ही भूखतापूर्ण विरोधाभास जान पड़ता है। एक लेखक के अनुसार "यह आवश्यक है कि इतना शक्तिहीन राजा भी क्यों बतमान है। (It is a curious dilemma that why such an unimportant monarch survives in this democratic age) यह सही है कि इंग्लैण्ड में राजतन्त्र की इतनी कटु आलोचनाएँ हुई हैं कि उसकी व्ययता का विरोध करना अब अनुचित जान पड़ता है। ब्रदलाउ (Bradlaugh) ने तो यहाँ तक कह डाला कि "राजा न तो योग्य है, न सम्भर न चितक और न श्रेष्ठ प्रशासक जो इस महान् देश के प्रशासन का संचालन कर सके।"

चम्बरलेन ने एक बार कहा था कि "गणराज्य आना चाहिए और जिस तेजी से हम आजकल विचार कर रहे हैं उस हिमाव से तो यह हमारे समय में ही आना चाहिए।" कुछ आलोचकों का ऐसा विचार है कि धन का जितना दुरुपयोग शक्तिहीन राजवंश के केवल आलंकारिक महत्व के लिए बनाय रखने में व्यक्त होता है वह असम्य गरीबों की समस्या के रहते हुए औचित्यपूर्ण नहीं जान पड़ता। प्रजातन्त्र का यह दिखावा हास्यास्पद-सा समता है। किंतु जेनिंग्स (Jennings) का

यह कथन कि 'जनतन्त्रीय सरकार केवल तक तथा ठोस नीतियों के आधार पर ही नहीं चलायी जा सकती, इसमें कुछ दिखावा भी होना चाहिए और वह शाही शान शोकेत के अलावा और कहीं नहीं है' अधिक सतोपजनक नहीं जान पड़ता। प्रो० लास्की (Lasky) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि राजतन्त्र की इतनी व्यापक प्रशंसा हुई है मानो राजतन्त्र प्रजातन्त्र के हाथों में बिक चुका है।" (Monarchy has been sold to Democracy)। चर्चिल (Churchill) ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए लिखा था, "अंग्रेजी राजतन्त्र हमारी जनता में गहराई से स्थापित और सबसे अधिक प्रिय है।" (is most deeply founded and dearly cherished by the whole association of our people) प्रो० आग (Ogg) के अनुसार "राजा संविधान का रहस्यात्मक भाग है जिसके बिना प्रतीत होता है कि मनुष्यों पर कठिनाता से ही शासन किया जा सकता है।' जोस ने राजा तथा प्रजा के सम्बन्ध का पिता पुत्र का सम्बन्ध बनाया है। प्रो० ऑग ने तो राजतन्त्र के महत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि बकिंघम राजभवन में राजा के होने से लोग अपनी नींदों पर शांति से सोते हैं।' (With the king in the Buckingham palace, people sleep more quietly in their beds) यह मान लेना हमारी भूल है कि राजतन्त्र का कोई महत्व नहीं है अथवा वह एक व्यर्थ की सस्था है। अमेरिकावासियों के लिए आज भी यह विस्मय का विषय बना हुआ है कि एक सस्था जो अपनी उपयोगिता को पूर्ण रूप से खो चुकी है, कैसे जीवित है। इंग्लैंड के निवासी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि राजतन्त्र को समाप्त करके वे किसी नवीन सस्था को जन्म देना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए है कि व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण सेवाएँ राजा द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। राजतन्त्र को बनाये रखने के औचित्य का समयन निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है

1. ऐतिहासिक कारण (Historical Reasons)

(क) राजपद का सराहनीय इतिहास (Glorious Past of the Kingship)—इंग्लैंड में राजतन्त्र लगभग 1150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 1649 से लेकर 1660 के 11 वर्ष की अवधि को छोड़कर जबकि क्रामबल की अध्यक्षता में गणतन्त्र रहा, इंग्लैंड के इतिहास में राजतन्त्र ही छाया रहा। राजतन्त्र का इतिहास इतना प्रभावशाली रहा है कि लोग उससे पथक करने मात्र की बात का अस्वभाविक समझते हैं। राजपद रूढ़िवादी स्वभाव के अनुपूरक है और ब्रिटिश ऐतिहासिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजवंश सदैव जनहित का रक्षक बनकर रहा है, उसका अतीत गौरव से युक्त है, ब्रिटिशों की दूरदर्शिता तथा व्यक्तित्व की श्रद्धा की छाप आज तक देशवासियों पर है, एडवर्ड सप्तम का हँसमुख स्वभाव, जॉर्ज प्रथम की जन भावना तथा वर्तमान साम्राज्ञी रानी एलिजाबेथ के व्यक्तित्व ने गहरा प्रभाव छोड़ा है। इंग्लैंड में राजतन्त्र देशवासियों की भावना से ओतप्रोत भूतनालोचन संपन्नताओं का इतिहास है।

(ख) राजतन्त्र का शांतिपूर्ण जनतन्त्रीकरण (Peaceful democratization of Kingship)—ब्रिटिश राजतन्त्र की लोकप्रियता का एक कारण यह भी रहा है कि उसने जनतन्त्र में बिना किसी अवरोध नहीं किया। राजतन्त्र जनतन्त्रीय

विकास का सहयोगी सिद्ध हुआ है। समय एवं आवश्यकता के साथ उसने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया है। ब्रिटेन में सुधार योजनाओं की सफलता में राजतन्त्र का सराहनीय सहयोग रहा है। जनतन्त्र के विकास के प्रति अनिर्वार्यता का दृष्टिकोण राजाओं ने अपनाये रखा, इनका व्यवहार कभी भी विचकहीन नहीं रहा। यह मानना मही है कि यदि ब्रिटिश राजाओं ने जनतन्त्रीय भावनाओं के आविर्भाव एवं विकास के प्रति रुस के जार तथा फ्रांस के बुअरबौन शासकों की भाँति रुख अपनाया होता तो उही की भाँति उसकी भी अत्येष्टि हो गयी होती। किन्तु वह आज भी जीवित है तथा लोकतन्त्र के विकास के साथ उसकी जड़े और अधिक शक्तिशाली बनी है। वह इस बात का प्रतीक है कि राजा कितना लोकप्रिय है और लोकतन्त्र के विकास में उसकी जो प्रभुता हुई है, उसका स्वर इतना एकरस रहा है कि कभी कभी उठने वाले विरोध ने स्वर उसमें सुनाई नहीं देते (Monarchy has been sold to democracy and so nearly has been its chorus of eulogy that rare voices of dissent have hardly been heard)

2 मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Reasons)

(क) रूढ़िवादी स्वभाव (Conservative Nature)—ब्रिटिश साहित्य तथा संस्थाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वहाँ जन माधारण का दृष्टिकोण कितना रूढ़िवादी है। उसे प्रत्येक उस वस्तु से प्यार है जो पुरातन है। ऐतिहासिक परम्पराओं से उहे इतना लगाव है कि एक कृषण की भाँति वह उहे धनायें रखना चाहते हैं। ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ वह अलिखित होत हुए भी शक्ति सम्पन्न है। वह ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। वे अस्थायी एवं अनुपयोगी बातों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तनों के समर्थन में नहीं हैं। उन्होंने निस्सन्देह राजपद का जनतन्त्रीकरण किया है और वह भी इस कलात्मक एवं सुन्दर ढंग से किया है कि राजतन्त्र का गौरव एवं उसकी गरिमा नष्ट न हो। उसके मूल स्वरूप पर आँच नहीं आने दी है। जनतन्त्रीकरण आत्मा का हुआ है किन्तु उसके स्वरूप में वही अतीत की आलम्बित्वता एवं शान शोक का तोर-तरीका रखा गया है जिसमें लोकतन्त्रीय विकास के साथ में ऐतिहासिक परम्पराओं की भी रक्षा होती रहे। इसमें पीराणिकता तथा आधुनिकता का एक सुन्दर एवं स्वस्थ सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। नयी बातों में शराब पुरानी है। इसमें यह स्पष्ट है कि राजतन्त्र की अजस्र प्रवृत्ति समय तथा प्रगति के अनुकूल अपने को मोड़ सकी है और आज राजतन्त्र वस्तुतः लोकतन्त्र का संरक्षक बन गया है। वह जन रूढ़िवादियों के अनुकूल है।

(ख) स्वाभाविक सम्मान (Natural Prestige)—ब्रिटिश सम्राट को जो सम्मान एवं आदर प्राप्त है वह अद्वितीय है। जो ज्ञान शोक एवं साज-मज्जा हमें रात-दिन में दृष्टिगत होती है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। ब्रिटिश निवासी बड़े ही हृष तथा उमाद के साथ राजा को गद्दी पर बैठते हैं। जेनिंग्स (Jennings) के अनुसार 'लाकृत-आत्मक शोभा निर्जिव तर्कों तथा नीरस नीतियों तक ही सीमित नहीं है। उममें कुछ रगिनी, कुछ तटक भटक होनी ही चाहिए और एसी स्पष्ट तटक भटक और वहाँ देखने को मिलेगी जसी कि शाही पाशाव में मिलती है।' विण्डसर राजभवन में निवास करने वाली रानी आज भी ब्रिटिश जनता के सम्मान

की केन्द्र है। स्वर्णिमविद्या के देशों में भी राजतन्त्र है किन्तु उन्हें वह प्रतिष्ठा एवं शान प्राप्त नहीं है जो ब्रिटिश राजतन्त्र को प्राप्त है। इस प्रकार का वैभव एवं सम्मान गणतन्त्र में राष्ट्राध्यक्ष को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता।

(ग) सुरक्षा का प्रतीक (Symbol of Safety)—ब्रिटिश नागरिकों में एक मनोवैज्ञानिक भावना यह बाय बरती है कि राजतन्त्र की अनुपस्थिति में उनके सामाजिक व राजनीतिक जीवन में अप्रणता आ जायेगी। जनता अपने हितों को राजा के हाथों में अधिक सुरक्षित समझती है। उन्हें सम्राट पर इतना अगाध विश्वास है कि उसे लोकतन्त्रीय भावनाओं का जनक मान बैठे हैं। महारानी विक्टोरिया अपने शासन के उत्तराधिकारी के रूप में जन जननी कहलाती थी। "रानी विक्टोरिया को नयी पीढ़ी जर्मन राजकुमार की अभियानिनी पत्नी के रूप में न देखकर राष्ट्रीय इतिहास राष्ट्रीय कीर्ति, राष्ट्रीय समृद्धि तथा साम्राज्य के स्वर्णिम युग का साकार प्रतीक मानती थी। कट्टर टोरी विचारधारा की समयक, समाजवादी विचारधारा के प्रवेश से सशक्त तथा उदारवादी दल को विध्वंसकारी समझने वाली विक्टोरिया के प्रति जन मानस में इतनी श्रद्धा थी। हर्बर्ट मोरीसन (Herbert Morrison) के शब्दों में, "वास्तव में राजा एक व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत करता है जो जनता की भावनाओं को उन वैधानिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है जिन्हें न देखा जा सकता है और न ही सुना जा सकता है।"

3 राजनीतिक कारण (Political Reasons)

(क) इंग्लैंड और अधिक लोकतन्त्रात्मक नहीं बन सकेगा (England will not be more democratic)—इंग्लैंड में राजतन्त्र का लोकतन्त्रात्मक स्वरूप शांतिपूर्ण ढंग से विकसित हुआ है। राजतन्त्रीय परम्पराओं के पोषक आज लोकतन्त्र के भी रक्षक बन गये हैं। राजतन्त्र ने किसी भी रूप में साक भावना तथा जनतन्त्रीय विचारों की प्रगति का अपमान करके उन्हें अवरुद्ध नहीं किया है। यह बात भी सत्य है कि राजतन्त्र को समाप्त करके इंग्लैंड और अधिक लोकतन्त्रीय नहीं बन सकेगा। राजतन्त्र को समाप्त करके उसके स्थान पर गणतन्त्र को अपनाना होगा और राजा के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति पद की शक्तियों का वही स्वरूप रखा जाता है जो अमेरिका में है तो वह सदन की शक्तियों का कम करके ही सम्भव है और वह व्यवस्था सदीय लोकतन्त्र के अनुकूल सिद्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ से सम्पन्न न करके पहले फ्रांस जैसे षष्ठमात्र राष्ट्रपति के रूप में रखा जाय तो वर्तमान तथा उभ भविष्य में कोई अंतर नहीं होगा और ब्रिटिश जनता उत्तराधिकारी राजा को उस शौर शरान तथा राजनीतिक असाह्य की अपेक्षा अधिक पसन्द करेगी। इससे अतिरिक्त थोड़े से लाभ के लिए परम्परागत संस्थाओं को समाप्त करना विवेकपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। रेनॉल्ड ने उचित ही कहा है राजा लोक इच्छा का विरोध करके उसके अनुसार राज्य इसलिए नहीं करता कि लोकतन्त्र उसके अधीन हो गया है बल्कि इसलिए करता है कि राजतन्त्र का औचित्य प्रिय बन गया है। (It is not democracy that has become subservient but because monarchy has become reasonable at the king reigns not in defiance but in conformity to the popular will.)

(ख) राजनीतिक निष्पक्षता (Political Neutrality)—ब्रिटिश राजतन्त्र के औचित्य के सम्बन्ध में यह तर्क दिया जाता है कि राजा दलीय राजनीति से ऊपर है। वह राजनीति में निष्पक्ष है और ससदीय लोकतन्त्र को सफलता के लक्ष्य तक ले जाने के लिए ऐसा ही व्यक्ति उपयोगी भी हो सकता है। यदि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति है, तो वह चाहे कितनी ही निष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ कार्य क्यों न करे वह पूर्ण रूप से अपने दलगत सम्बन्धों का विस्मरण नहीं कर सकता और यदि वह करना भी चाहे तो उसके समर्थक उसे नहीं करने देंगे। राजनीतिक शांति नहीं रह सकेगी। पैतृक आधार पर अवलम्बित होने के कारण राजा सदा निष्पक्षता का व्यवहार करता है और हर कदम विश्वासपूर्वक उठाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जल्दबाजी का व्यवहार नहीं करता। हर प्रस्ताव को तोलकर वह राष्ट्रीय भावना का अंदाज तथा दृष्टिकोण जानने की कोशिश करता है। वह भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, अपन व्यक्तिगत प्रभाव का लाभ उठाकर द्वन्द्वपरक परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयत्न करता है। जेनिंग्स (Jennings) के शब्दा में, “संविधान यह मानकर चलता है कि यदि राजा निष्पक्ष न हो तो भी कम से कम व्यवहार तो ऐसा करना ही होगा, मानो वह निष्पक्ष हो।” अर्न ऑफ बैलफोर (Balfour) ने राजा को “राष्ट्रीय इतिहास का जीवित प्रतिनिधि” माना है (Living representative of our National History)। पुन बैलफोर के ही शब्दा में “वह (राजा) न तो किसी दल का नेता है और न वह किसी वर्ग का प्रतिनिधि। वह राष्ट्र का प्रमुख है। वह प्रत्येक का राजा है।” (He is not a leader of a party nor the representative of a class. He is the chief of the nation. He is everybody's king.)

किंतु हमें कुछ स्थल ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जिनके सहयोग से हम यह कह सकते हैं कि यह समझना हमारी भूल होगी कि ब्रिटिश सम्राट ने सदैव निष्पक्षता का रत्न बनाये रखा। रानी विक्टोरिया ही इसका एक उदाहरण हो सकती हैं। एडवर्ड प्रथम की सहानुभूति सदैव टोरी दल के साथ रही, उदारवादी मंत्रियों से प्रायः उनका मतभेद रहता था। विदेश नीति में हस्तक्षेप को वे अपन परमाधिकारों के अनुकूल समझती थीं। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ को कम करने के विधेयक पर जाज पंजम लिबरल प्रधानमंत्री को यह आश्वासन नहीं दे सके कि वे लाइ सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधेयक को पारित करावेंगे। इसके लिए दो बार निर्वाचन हुआ और अंत में राजा को जन इच्छा के सम्मुख झुकना पड़ा। इसी प्रकार आयरलैंड के प्रश्न पर टोरी दल के साथ राजा की सहानुभूति रही। यह युद्ध की घमकी टोरी दल से प्रभावित सैनिक अफसरों ने दी। 1931 का पैलम पंड्यत्र प्रसिद्ध है जिसमें रमजे मैकडोनाल्ड को राष्ट्रीय सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वह सदन के किसी भी दल का प्रधान नहीं था। यह ससदीय परम्पराओं के मुख पर जोरदार थपड़ था। राष्ट्रीय सरकार टोरी सरकार का ही दूसरा रूप था। एथोनी ईडन के त्यागपत्र के पश्चात् ग्यातिहीन तथा अभिजात कुलीन डगलस ह्यूम को महारानी एलिजाबेथ ने प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया तथा बटसर जस मुयोग्य व्यक्ति को छोड़ दिया गया। उसे यह मान लेना सही नहीं है कि राजा सदा निष्पक्ष रहता है।

4 राजा के व्यक्तिगत कार्य जयवा उपयोगितावादो तक (Personal Works of the King or Utilitarian Arguments)

(क) वस्तुतः राजा द्वारा कुछ ऐसे कार्यों का सम्पादन होता है जो अथ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इन व्यक्तिगत कार्यों का राजनीतिक महत्व है और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

(1) लाइ चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति।

(2) परिपद आदेशों (Executive orders) को पारित करना।

(3) सकट के समय सर्वदलीय सम्मेलन आमंत्रित करता। इस प्रकार का एक सम्मेलन वैधानिक सकट को टालने के लिए 1914 में जाज पचम न आमंत्रित किया था।

(4) प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment of Prime minister)। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीमा तक संसदीय परम्पराओं से उसके हाथ बँधे हुए हैं किंतु फिर भी वह अपने व्यक्तिगत से कई ऐसे कार्य करा सकता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सहायक हो सकते हैं। 1931 में सम्राट के ही कारण टोरी दल की सहायता से रैमजे मैकडोनाल्ड किसी भी दल के प्रतिनिधि न होने पर भी राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री बने।

(5) मंत्रियों को अपदस्थ करना तथा लोक सभा का विघटन (Dissolution of the House)—यह शक्ति आदर्श में अधिक तथा यथार्थ में कम है। 1873 के पश्चात् इस शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। रानी विक्टोरिया इस बात में रुचि रखती थी कि किसे मंत्री रखा जाय और किसे नहीं।

(6) संरक्षण तथा उपाधि वितरण (Patronage & Fountain of Honour)—सत्य ही औपचारिक रूप में मंत्रिमण्डल के गठन से लेकर पुला आदि के उद्घाटन तक के कार्य सम्राट का करने पड़ते हैं। उपाधियों का नियम यद्यपि मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है किंतु सूची में राजा परिवर्तन कर सकता है।

(7) संसदीय अधिवेशनों को आहूत करने का उत्तरदायित्व—जब एक सरकार प्रस्थान करती है तो दूसरी सरकार के आने तक राजा शासन संचालन करता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

(ख) सम्राट आलोचक, परामशदाता तथा मित्र के रूप में (King as a Critic Adviser and Friend)—1867 में महारानी विक्टोरिया की वैधानिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए वेजहार्ट ने लिखा था शासन के शोभनीय अंग के रूप में रानी की उपस्थिति में अनेक लाभ हैं। उसके अभाव में अंग्रेजी सरकार असफल और विनष्ट हो जायगी। यहो तक जाज भी रानी एलिजाबेथ के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। सम्राट का प्रयोग ब्रिटेन का शासन वगैरह तीन रूपों में करता है—(1) प्रचार के उपकरण के रूप में (2) शासन के दैनिक कार्यों के रूप में (3) निहित स्वार्थों द्वारा एक सुरक्षित हथियार के रूप में। प्रचार के उपकरण के रूप में राजतंत्र का प्रयोग आवश्यकताओं समाचारपत्र टेलीविजन चर्च तथा राजनीतिक दल वही ही तत्परता के साथ करते हैं। जाज पचम (George V)

मुवराज के रूप में भारत पधार उस समय उन्होंने अपने पिता को एक पत्र में

लिखा था, "हमारी कलकत्ता यात्रा राजनीतिक दृष्टि से बड़ी सफल रही। यह यात्रा बड़ी ही सामयिक थी क्योंकि बंगाल के विभाजन के कारण यहाँ वातावरण बड़ा उत्तजित था और सरकार के प्रति जनता में बड़ा रोष था।" स्वयं राजकीय वैभव का यही लक्ष्य है। ब्रिटिश समाचार पत्र 'टाइम्स' ने 11 जुलाई, 1952 के अंक में लिखा था, "शाही महलों, शाही जुलूसों, शाही दावतों और अतिथि सत्कार को समाप्त करने से मामूली बचत अवश्य होगी लेकिन लोगों की जिदगी में इससे रूखापन अवश्य आ जायगा।" शापित अमिकों को सन्तुष्ट करने के लिए भी राजवश का प्रयोग किया जाता है। मजदूरों के मुहल्लों तथा बस्तियों में रानी का जाकर ह्राथ मिलाना बड़ा महत्व रखता है। 1926 में मजदूरों की हड़ताल के दमन के फलस्वरूप उत्तेजना की स्थिति का शांत करने के लिए सम्राट का प्रयोग किया गया। "महारानी की कुपालु आखें सभी का दुख दब देखने तथा बाटने के लिए आतुर रहती हैं।" एक मित्र के ही रूप में राजा मंत्रिमण्डल को चेतावनी भी देता है। वह शासन की आलोचना नहीं करता किन्तु यह अवश्य बता देता है कि सही मार्ग क्या है और गलत कार्यों के भावी परिणामों के विषय में वह चेतावनी भी दे देता है। सम्राट इस चेतावनी देने के अधिकार का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करता है, इसका जनता पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण राजा को शासन का रूफरी अथवा निरीक्षक कहना अमत्य नहीं है। मंत्रिमण्डल की कार्यवाहियाँ के विषय में प्रधानमंत्री सम्राट को सूचित रखता है। कार्यवली (Agenda), ज्ञापन (Memorandum), विवरण पुस्तिका (Proceeding Book), समस्त प्रेषण पत्र (daily despatches) तथा संसदीय प्रतिवेदन (Parliamentary Reports) आदि के विषय में उसे पूर्ण सूचना रहती है। इन्हें पढ़ने का उसे अवसर मिलता है।

(ग) सम्राट एक् मध्यस्थ के रूप में (King as a Mediator)—राजनीतिक मतभेदों को दूर करने में राजवश का विशेष योग रहा है। राजा की निष्पक्षता के कारण सवत्र उसकी मन्त्रणा का सम्मान होता है, अपनी प्रतिष्ठा तथा व्यक्तित्व का प्रयोग सम्राट विरोधों की पचण्डता को कम करने के लिए करता है। 1871 में महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड रसेल से आप्रह किया था कि वह राजनीतिक उद्यत-पुथल को अलबामा (Alabama) प्रश्न के माध्यम से जम द। 1881 में विक्टोरिया ने आयरिश प्रश्न को सुलझाने की कोशिश की। 1916 में सम्राट द्वारा लॉर्ड एस्विबथ तथा लॉर्ड जॉर्ज के झगडा को समाप्त करने के लिए जॉर्ज पञ्चम ने प्रयत्न किये, 1861 में रानी विक्टोरिया के प्रयत्ना से ही ट्रेंट एफेयर के सम्बन्ध में इंग्लण्ड तथा अमेरिका में युद्ध होने से बचा। एडवर्ड सप्तम ने इंग्लैण्ड को अय देशों से पूर्णतः पृथक् होने से बचाया। उन्हीं के कारण रूस तथा इंग्लैण्ड के मध्य एक समशीता सम्भव हो सका। 1931 में सरकार बनाने में सम्राट ने रैम्जे मैकडोमल्ल्ड की सहायता की। जेकब न ठीक ही कहा है कि 'एक राजा जिसके पास समस्त बातों की सूचना है यदि योग्य व्यक्ति है तो वह अप्रतिद्वंद्वी रूप में राजनीतिक अनुभव का आधार बन जाता है।' (A king who is fully informed of affairs becomes in course of time if he is an able man, an unrivalled storehouse of political experience)

(घ) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्राट का महत्व (Importance of King in International Sphere)—अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सम्राट के व्यक्तित्व एवं पद की विशेष महत्ता है। वह न केवल परेलू नीतियों को ही प्रभावित नहीं करता बरन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1840 में महारानी विक्टोरिया के व्यक्तिगत प्रभाव एवं प्रयासों से इंग्लैंड तथा फ्रांस में युद्ध टल गया। 1861 में उसी के प्रयासों के फलस्वरूप इंग्लैंड तथा अमेरिका में युद्ध हात हात बचा। 1869 में उसने आयरिश प्रश्न के सम्बन्ध में मध्यस्थता की। एडवर्ड सप्तम ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 1904 तथा 1907 में रूस से मत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए। उन्हीं विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर एक पत्र-व्यवहार द्वारा इंग्लैंड की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। आइरिश होम रूल विधेयक पर राजा ने बड़ी शक्ति का परिचय दिया।

इसके अतिरिक्त राजा का महत्व राष्ट्रमण्डलीय देशों के सन्दर्भ में भी कम नहीं है। राजा ही राष्ट्रमण्डल को जोड़ने वाली कड़ी है। सम्राट साम्राज्यीय एकाता का प्रतीक है। चर्चिल (ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री) के शब्दों में, “सम्राट एक रहस्यमय कड़ी है जिसने हमारे पीछे बंधे हुए किन्तु दुर्बल के साथ जुड़े हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों, जातियों तथा राज्यों को मिला रखा है।” (He is the mysterious link indeed I may say the magic link, which united our loosely bound but strongly interwoven Commonwealth of Nations, states and races) लास्की के शब्दों में, “सम्राट राष्ट्रमण्डल का भौतिक आधार है।” राष्ट्रमण्डलीय देशों के सदस्य ब्रिटेन के संविधान के प्रति नहीं बरन् वहाँ के सम्राट के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। वही एक सूत्र में बाँधने वाला अनुपम बन्धन है। 1939 में एडवर्ड सप्तम ने कनाडा स्पेन, फ्रांस आदि देशों का भ्रमण किया। वर्तमान रानी एलिजाबेथ द्वितीय की राष्ट्रमण्डलीय देशों की यात्रा से इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा सहारा मिला है, अतः अंतर्राष्ट्रीय विश्व में भी सम्राट का महत्व एवं अनुदायक कम नहीं है। विदेशों से सौहार्दमय सम्बन्धों की सृष्टि में राजा का बड़ा हाथ होता है। बाल्डविन (Baldwin) ने ठीक ही कहा है कि “सम्राट ही हमारा अवशिष्ट साम्राज्य की एकमात्र कड़ी है।” (The last link of the Empire that is left)

5 सामाजिक कारण (Social Reasons)

इंग्लैंड में राजवंश के औचित्य का सामाजिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सिडनी लो के शब्दों में, ‘किसी भी समूह के साथ राजकीय शब्द जुड़ जाने से सफलता अवश्यम्भावी हो जाती है।’ 1939 में राजकुमारी एलिजाबेथ तथा मार्गरेट में मायकाइन दैनिक रूप से घूमने के समय हेट पहनना बन्द कर दिया था। इसका प्रभाव हेटों की बिक्री पर हुआ तथा हेट विक्रेताओं ने महारानी से आग्रह किया कि वे अपनी पुत्रियाँ को पुनः हेट पहनाने का आदेश देकर उनकी रक्षा करें। फैनन, तथा साहित्य आदि में राजपरिवार के आदर्श का सख्त अनुकरण होता है।

इसीलिए सम्राट को सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग कहा जाता है। उदघाटन तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के पर्वों पर सम्राट को सुनने के अवसर जनता को मिलते हैं।

जेक्स (Jenks) ने ठीक ही कहा है कि एक संस्था को अपेक्षा एक व्यक्ति का समझना अधिक सरल है। इसमें सन्देह नहीं कि अनुभव से युक्त योग्य सम्राट जनसाधारण की भावनाओं का अर्थ किसी की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार प्रतिनिधित्व कर सकता है। लास्की के अनुसार राजतंत्र रूपी संस्था की सफलता आवश्यकतारूप में हुई है। सम्राट अविच्छिन्नता तथा स्थायित्व का प्रतीक है। राजतंत्र ने देश में क्रांतिकारी परिवर्तनों का होने से रोका है, किंतु इससे जनतंत्रीय भावनाओं का विकास अवरोध नहीं हुआ। बाकर ने राष्ट्रीय जीवन की तुलना जहाज से करते समय सम्राट को उसकी पेंदी तथा मस्तूल बताया है। पताका दिशा के अनुसार बदल जाती है किंतु अपना मूल स्थान नहीं छोड़ती तथा पेंदी का भार जहाज की गति एवं आवश्यकता के साथ इधर-उधर खिसक जाता है। अतः राजतंत्र का राजतंत्रीकरण तो हुआ है किंतु उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंग्लैंड में सम्राट का पद बहुत कुछ सीमाओं में संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप रहा है। संसदीय प्रणाली उसी समय सक्रिय रूप में कार्य कर सकती है जबकि राष्ट्राध्यक्ष ध्वज मात्र हो। राजतंत्र को हटाने का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह होगा कि इंग्लैंड का चर्च बिना प्रधान के रह जायेगा। लॉवेल (Lowell) ने ठीक ही कहा है कि “यदि राजा राज्य रूपी पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अति आवश्यक अंग है।” (If the king is no longer the motive power of the ship of the state, it is the spur on which the sail is bent and as such it is not only useful but an essential part of the vessel) मैरीसन के शब्दों में, ‘संसार में कोई भी राजपद इतना सुरक्षित तथा जनता द्वारा सम्मानित नहीं है जितना कि हमारा।’ ओग (Ogg) ने राजतंत्र का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि “यों तो राजपद के विषय में भविष्यवाणी करना कठिन है किंतु फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब तक ब्रिटिश सम्राट समय की गति को पहिचान कर उससे अनुकूल आचरण करता है, एक असमति नहीं बनता, स्टूअर्ट शासकों की भाँति पागलों के स्वप्न में नहीं रहता तथा जॉर्ज तृतीय की भाँति दशभक्त राजा (Patriot King) बनने की कोशिश नहीं करता उस समय तक राजतंत्र का झण्डा इंग्लैंड में सहस्रता रहेगा।’

Select References

- Jennings *The British Constitution*
 Bagehot *The English Constitution*
 Lowell *The Govt of England*
 Ogg & Zink *Modern Foreign Govt*
 Amos *The English Constitution*
 Finer *Govts of Greater European Countries*
 Muir *How Britain is Governed*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 'क्राउन' शब्द से आप क्या समझते हैं ? सम्राट् और क्राउन में क्या अन्तर है ?
(State briefly what do you understand by the term 'Crown' in the British Constitution and distinguish it from the King)
- 2 ब्रिटिश संविधान में क्राउन की स्थिति और कृत्या का वर्णन करें ।
(Examine the position and functions of the Crown in the British Constitution)
- 3 ब्रिटिश सम्राट् की स्थिति की विवेचना करें । सम्राट् पद के स्थायित्व का कारण बतायें ।
(Discuss the position of the monarch in the British constitution Why does monarchy survive ?)
- 4 "ब्रिटिश राजत्व राजनीतिक भ्रांति है ।" इस कथन की आलोचना कीजिए ।
'Monarchy in England is a political anachronism ' Examine the statement)
- 5 "सम्राट् राज्य करता है शासन नहीं ।" ब्रिटिश सम्राट् के प्रसंग में इस कथन की समीक्षा करें । इंग्लैण्ड में राजतन्त्र क्यों नहीं खत्म हो रहा है ?
"He reigns but does not govern " Explain this statement with regard to the monarchy of England Why is the kingship not abolished in England ?
- 6 "ब्रिटिश सम्राट् स्वर्णिमशून्य है ।" व्याख्या करें ।
(' The British king is a magnificent cipher ' Explain)
- 7 यदि सम्राट् राज्य पोत की चालक शक्ति नहीं है, तो वह उसका वह मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोत का अभिन्न अंग है इस कथन की विवेचना करें ।
(' If the crown is no longer the motive power of the ship of the state it is the spur on which the sail is bent and as such it is not only useful but an essential part of the vessel ' —Discuss)
- 8 "सम्राट् भूल नहीं कर सकता ।" इस कथन का अर्थ और महत्त्व बतलाइए ।
"The king can do no wrong ' Explain the meaning and implication of the statement)
- 9 राजत्व की उपयोगिता का वर्णन कीजिए ।
(Discuss the utility of monarchy in England)
- 10 ' ब्रिटिश संविधान की परिभाषा में अनेक सूक्ष्म अन्तर हैं परन्तु सम्राट् और क्राउन के अन्तर से अधिक महत्वपूर्ण अन्तर कोई नहीं । इस कथन की विवेचना करें ।
(There are many subtle distinctions in the vernacular of the British Constitution but none more vital than the distinction between the King and the Crown Explain)
- 11 सम्राट् और क्राउन में क्या अन्तर है ? क्राउन की शक्तियों का वर्णन कीजिए ।
(What is the distinction between the King and the Crown ? Describe the powers of the Crown)

- 12 इंग्लैण्ड में राजा और राजमुकुट का भेद स्पष्ट कीजिए तथा राजमुकुट के अधिकारों एवं कृतव्यों का पूर्ण विवेचन कीजिए ।
(Distinguish between the King and the Crown in England and carefully examine the powers and functions of the Crown)
- 13 इंग्लैण्ड में सम्राट् की व्यक्तिगत शक्तियाँ कमश राजमुकुट नामक संस्था के हाथों में आ गयी हैं ।” इस कथन के आधार पर सम्राट और क्राउन में अंतर बतलाइए ।
(Form an estimate of the position and powers of the King in the British Constitution)
- 14 ग्रेट ब्रिटेन का राजा “राज्य चरता है, शासन नहीं ।” इस कथन को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन के राजा की स्थिति समझाइए ।
(‘ The King of Great Britain rules but does not govern Explain the position of the British King keeping in view the statement)

3

मन्त्रिमण्डल

[Cabinet]

'No form of Government can survive that excludes the dictatorship when the life of the nation is at stake

"The Cabinet is the highest focus of comprehensive political view and leadership —H Finner

परिचय—मन्त्रिमण्डल सूदमन्कार विधानमण्डल है। यह चक्र के अतगत एक चक्र सदस्य है। मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक वायपालिका है। किन्तु मन्त्रिमण्डल की स्थिति की व्याख्या एवं उसके अस्तित्व का मूल्यांकन करने से पूर्व इस सदन में प्रीवी परिषद (Privy Council) के विषय में जान लेना आवश्यक है। वास्तव में 1937 से पूर्व मन्त्रिमण्डल का कोई कानूनी आधार नहीं था। मन्त्रिमण्डलीय पद्धति का उद्गम क्यूरिया रीजस (Curia Regis) से हुआ है जिसे छोटी परिषद भी कहा जाता है। इसी के समकक्ष एग्लो सैक्सन युग में बुद्धिमानों की परिषद हुआ करती थी जिसका प्रमुख वाय राजा का उसके बधानिक कार्यों में परामश प्रदान करना होता था। इसी परिषद का स्थान वृहत सभा (Magnum Counciliam) तथा क्यूरिया रीजस ने ले लिया था। कालांतर में क्यूरिया रीजस से ही प्रीवी परिषद का विकास हुआ। क्यूरिया रीजस ही प्रीवी परिषद तथा मन्त्रिमण्डल का विकासस्थल है।

प्रीवी परिषद ने सदस्यों की नियुक्ति अभिजात वर्ग के व्यक्तियों में से सम्राट द्वारा होती है। इस समय प्रीवी परिषद में लगभग 320 सदस्य हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल ने परामश पर होती है। परम्परानुसार कुशल राजनीतिज्ञ, मन्त्रियाँ साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार तथा अवकाश प्राप्त यायाधीशों को इसका सदस्य बनाया जाता है। इसके सदस्यों को 'महामाय (Right Honourable) की उपाधि प्राप्त होती है। इसके अधिवेशन के लिए गणपूर्ति की संख्या केवल 3 है। इसकी बैठक का स्थान वर्किंगम राजभवन है। इस केवल विशेष अवसर पर ही आमन्त्रित किया जाता है। इसकी वायराही बड़ी ही औपचारिक ढंग की होती है। सान् प्रमीडण्ट इसकी वायवाहिया व समय सभापति का पद ग्रहण करता है। यह सत्य मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है।

प्रीवी परिषद के वाय (Functions of Privy Council)

प्रीवी परिषद का निम्ननिमित्त वाय है

(1) मन्त्रिमण्डल ने नियमा का औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना।

(2) सपरिपद आदेशों तथा उद्धोपणाओं को परिपद की मुद्रा के अंतर्गत मुद्रित करना ।

(3) ऐसे चाटरो आदि को स्वीकार करना जिनका लक्ष्य वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक गवेषणा के लिए विश्वविद्यालय आदि के लिए आयोग आदि की नियुक्ति करना हो ।

(4) मन्त्रिमण्डल के सदस्यों तथा उच्च पदाधिकारियों को उनके पद की शपथ दिलाना ।

(5) आर्थिक एकीकरण के लिए उपायों पर विचार करना ।

(6) ब्रिटिश प्रसारण निगम की नीतियों का निर्धारण ।

(7) ग्राम्य समिति का संगठन करना, यही उपनिवेशों तथा स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के लिए सर्वोच्च 'यायालय' के रूप में कार्य करती है ।

(8) धर्मोपदेश तथा प्राइज 'यायालयों' द्वारा किये गये निणयों के विरुद्ध अपीलीय 'यायालय' का कार्य करना । किंतु यह सलाहकार समिति है, निणयात्मक नहीं ।

शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जिसे प्रीवी परिपद संस्थागत रूप में करती हो । वस्तुतः प्रीवी परिपद के निणय मन्त्रिमण्डल के ही निणयों के प्रतीक होते हैं । इसकी 'यायिक' समिति, व्यापार मण्डल, शिक्षा मण्डल आदि कई समितियाँ होती हैं । यह स्वशासी एवं नीति निर्धारक शक्ति नहीं है । अपने वर्तमान स्वरूप में प्रीवी परिपद अतीत के गौरव की प्रतीक मात्र है । आज इसकी कोई शक्ति नहीं है अपितु शक्ति की एक प्रतीक मात्र संस्था के रूप में यह अपने अस्तित्व को बनाये हुए है । प्रीवी परिपद से ही कैबिनेट प्रणाली का अभ्युदय हुआ है । इसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि इसे अपना परामशदाता स्वरूप खो देने के लिए विवश होना पड़ा । इसी समिति को कालांतर में 'कैबिनेट' शब्द से पुकारा जाने लगा । बेकन (Beacon) ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था । इस शब्द का प्रयोग चार्ल्स द्वितीय (Charles II) के समय में हुआ जबकि राजा ने पांच सदस्यीय समिति का संगठन अपने परामशदाताओं के रूप में किया । इसी को 'कैबाल' (Cabal) मन्त्रिमण्डल की संज्ञा दी गयी, क्योंकि इसके सदस्यों के नाम इन शब्दों से प्रारम्भ होते थे—Clifford, Ashley Buckingham Arlington, Landerdale । संसद इस समिति को शका की दृष्टि से देखती थी । किंतु स्टुअर्ट काल में संसदीय प्रणाली के निश्चित नियमों का विकास नहीं हो पाया था । मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राजा इस बात का ध्यान नहीं करता था कि उसे बहुमत भी प्राप्त है अथवा नहीं । संसद के पास मंत्री को पदच्युत करने का महाभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई यंत्र न था । मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था ।

वस्तुतः मन्त्रिमण्डलीय पद्धति का विकास विनियम तृतीय के बाद ही सम्भवना चाहिए । क्रामवेल के समय में जिन राजनीतिक दलों की नींव दृढ़ हो चुकी थी, उन्होंने विलियम तृतीय को विवश किया कि वह अपने परामशदाताओं का चयन एक ही राजनीतिक दल में से करे । फलतः 1696 में ह्विग जुंटा नामक मन्त्रिमण्डल का विकास हुआ । यही से इस सिद्धांत का सूत्रपात भी हुआ कि बहुमत दल का ही मन्त्रिमण्डल का निर्माण के लिए अभिमत किया जाय ।

किंतु मंत्रिमण्डलीय परम्परा का वास्तविक रूप में विकास हनोवर-युग के शासकों के युग में हुआ। इस युग की चमत्कारपूर्ण राज नीति—प्रधानमंत्री पद का आविर्भाव। इसका श्रेय था तात्कालिक शासक जाज प्रथम की आगल जीवन, भाषा तथा परम्पराओं में अरुचि तथा द्विग नता राबर्ट वालपोल की कार्यकुशलता एवं व्यक्तित्व का प्रभाव। राजा ने मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता का कार्य पूर्णतः वालपोल के ही हाथों में छोड़ दिया जिसने लगभग उन समस्त अधिकारों का प्रयोग किया जो प्रधानमंत्री पद के साथ आज जुड़े हुए हैं। बालपोल के सत्ताकाल में ही इस सिद्धांत का भी विकास हुआ कि सम्राट की प्रमदता के अतिरिक्त मूल रूप से मंत्रिमण्डल को अपने पद पर बने रहने के लिए लाक सदन का विश्वास तथा उसकी प्रसन्नता भी प्राप्त होनी चाहिए। उसी व समय में स्थापित 10, डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यालय आज भी प्रधानमंत्री का निवास स्थान बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक मंत्रिमण्डलात्मक पद्धति के अधिकांश लक्षणों की स्थापना हो चुकी थी। यह परम्परा भी निश्चित हो चुकी थी कि मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेंगे।

किंतु ससदीय व्यवस्था के विकासमय जीवन का एक अजीब तूफानी दौर जाज तृतीय व समय में आया जहां यह शक पड़ा होने लगा कि ससदीय स्वतंत्रता का महल कहीं सम्राट की महत्वाकांक्षाओं के तूफान के सामने ढहकर महज एक गवाय न रह जाय। सम्राट चाहता था कि मंत्रिमण्डल में विरोधी दल के सदस्यों को भी लिया जाय। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल से पूर्व ससदीय प्रणाली का कई नाजुक दौरों से गुजरना पड़ा। मंत्रिमण्डल के सदस्यों में कई बार फूट डालने की कोशिश की गयी लेकिन सफलता प्राप्त न हो सकी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस पद्धति का चित्र लगभग स्पष्ट हो चुका था। मंत्रिमण्डलीय पद्धति का सही अर्थों में विकास महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हुआ। उस समय डिजरायली, ग्लेडस्टोन तथा पामसटन जैसे योग्य प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में इस पद्धति ने आशातीत प्रगति की तथा अपनी शक्ति एवं लोकप्रियता प्राप्त की।

मंत्रिमण्डलीय पद्धति को आगे बढ़ाने में वर्तमान शताब्दी का अनुदाय भी वस्तुतः कम नहीं है। वर्तमान शताब्दी का महत्वपूर्ण अनुदाय है मिश्रित मंत्रिमण्डल की सम्भवना जबकि राष्ट्र में सबूट की स्थिति हो। दूसरा अनुदाय है मंत्रिमण्डल के सभ्यो की सभ्या में वृद्धि, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री पद के कानूनी पहलू की स्वीकृति, जो कार्य 1937 के 'Ministers of the Crowns Act' के तत्वावधान में सम्पन्न किया गया। वर्तमान शताब्दी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस दिशा में है कि प्रधानमंत्री सदैव लाक सदन में से होंगा। यह सिद्धान्त अब पूर्ण रूप में स्थायी बन गया है। अतः मंत्रिमण्डलीय शासन व्यवस्था आवश्यकता एवं आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण आविष्कार है।

मंत्रिमण्डल तथा मंत्रिपरिषद में अंतर (Difference between Cabinet & the Ministry)

ससदीय साकतंत्र के क्षेत्र में हम प्रायः मंत्रिमण्डल तथा 'मन्त्रालय' अथवा

‘मंत्रिपरिषद्’ शब्दों की चर्चा सुनते हैं और तत्सम रूपों में अवश्य उनका प्रयोग भी करते हैं। जिस प्रकार हम सचेतन रूप में राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं करते उसी प्रकार मंत्रिमण्डल तथा मंत्रिपरिषद् में मौलिक अंतर को भी विमुख कर देते हैं। सम्भवतः इसका कारण यह रहा हो कि ‘मंत्रिमण्डल’ शब्द का कोई वैधानिक पहलू नहीं है। हमारे संविधान में ही ‘मंत्रिपरिषद्’ शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हम इनका विश्लेषण करें तो हमें दोना व मध्य सगठन, कार्य तथा शक्ति आदि की दृष्टि से अनेक अंतर दृष्टिगत होते हैं।

1 सगठन की दृष्टि से (From the Organizational Point of View)—

(अ) मंत्रिपरिषद् एक व्यापक निकाय है और मंत्रिमण्डल सूत्राकार।

(ब) मंत्रिपरिषद् का निर्माण पहले होता है और मंत्रिमण्डल का बाद में।

(स) मंत्रिपरिषद् में तो सब प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जैसे मंत्री, उपमंत्री, राज्यमंत्री, ससदीय मन्त्रि तथा विना विभाग के मंत्री। किंतु इसके विपरीत, मंत्रिमण्डल में केवल वे ही व्योवृद्ध, अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो प्रधानमंत्री के अधिकतम निकट तथा विश्वासपात्र व्यक्ति होते हैं। इनकी अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विभाग रखे जाते हैं। इंग्लैण्ड में परम्परानुसार लॉर्ड चांसलर, चांसलर ऑफ़ दी एक्सचेन्जर, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, गृह मंत्री तथा फ़स्ट लाड ऑफ़ एडमिराल्टी तो आवश्यक रूप से इसके सदस्य रहते ही हैं। वस्तुतः मंत्रिमण्डल एक चक्र के मध्य चक्र है। इसी कारण रूमज्जे म्योर ने इसे मंत्रिपरिषद् का हृदय तथा शासन का परिचालक यंत्र कहा है।

(द) मंत्रिपरिषद् की सामूहिक बैठक मंत्रिमण्डल के सदस्य सभी नहीं होती। मंत्रिमण्डल की बैठकों में ऐसे मंत्रियों को भी आमंत्रित कर लिया जाता है, जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(य) मंत्रिपरिषद् एक सगठित इकाई नहीं है। इसके विपरीत, मंत्रिमण्डल एक सगठित तथा सामूहिक इकाई के रूप में अपने कार्यों का सम्पादन करता है। मंत्रिमण्डल के नियम सर्वसम्मति से होते हैं।

(फ) मंत्रिपरिषद् में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं

(1) विना विभाग के मंत्री (Ministers without Portfolios)—यह एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें अनुभव तथा व्यक्तिगत विशेष योग्यता के आधार पर ही मंत्रिमण्डल में रखा जाता है और उनका अनुभव तथा परामर्श का लाभ उठाया जाता है।

(2) विभाग सहित मंत्री (Ministers with Portfolios)—इस स्तर के सदस्य मंत्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। वे नीति निर्धारण में भाग लेते हैं तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

(3) मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री (Ministers of the Cabinet Rank)—यह वस्तुतः मंत्रिपरिषद् के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। वे मंत्रिमण्डल के वास्तविक सदस्य नहीं होते किंतु उन्हें मंत्रिमण्डल के सदस्यों के समान माना तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। वे विशेष नियंत्रण पर ही मंत्रिमण्डल की बैठक में भाग लेते हैं। एंग्लो के मंत्रिमण्डल में इस प्रकार के 15 मंत्री हैं।

(4) राज्य मंत्री (State Ministers)—इसकी विधिगत रूप से

तथा समदीय सचिव से कुछ ऊपर हानी है। मंत्री के साथ भार को कम करने की दृष्टि से इनकी नियुक्ति की जाती है।

(5) ससदीय सचिव (Parliamentary Secretaries)—इसकी नियुक्ति विभागीय अध्यक्ष की सहायता के लिए की जाती है। हर मंत्री के पास एक या दो ससदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय स्थायी सचिव नहीं हैं जो असीमित सवालों का बमबारी होता है।

(6) राजमहल के मंत्री (Ministers of the Palace)—इनमें महत्वपूर्ण हैं कापाध्यक्ष नियंत्रण तथा राजप्रासाद का प्रमुख बमबारी (Chamberlain)। इन अधिकारियों का भी राजनीतिक महत्व की दृष्टि से मंत्री-स्तर का ही समझा जाता है।

2 कार्य की दृष्टि से (From the point of view of Functions)—कार्य की दृष्टि से भी हम मन्त्रालय तथा मन्त्रिमण्डल में मध्य निम्नलिखित अंतरों को देख सकते हैं

(क) शासकीय नीतियों का निश्चय मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है, न कि मन्त्रिपरिषद् के द्वारा।

(ख) मन्त्रिमण्डल में केवल महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और उन्हीं के सम्बन्ध में नीतियों का निश्चय किया जाता है।

(ग) राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य मन्त्रिमण्डल का है, न कि मन्त्रिपरिषद् का। मन्त्रिपरिषद् अपने व्यापक रूप में परामर्श देने की स्थिति में नहीं होती।

मन्त्रिमण्डल के विविध स्वरूप

(Different Forms of the Cabinet)

साधारण मन्त्रिमण्डल को हम मन्त्रियों की पारी कह सकते हैं। इसे वास्तव में मन्त्रिपरिषद् की कार्यकारिणी कहना अत्युत्तिपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल के कई अन्य रूप भी होते हैं

(1) छाया मन्त्रिमण्डल (Shadow Cabinet)—ब्रिटेन में ससदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति छाया मन्त्रिमण्डल है। गैर सरकारी तौर पर विरोधी दल स्वयं को एक मन्त्रिमण्डल के रूप में संगठित रखता है। इसका कोई शासकीय महत्व नहीं होता बल्कि इससे केवल ब्रिटेन की समदीय व्यवस्था में विरोधी दल के महत्व का विकास हुआ है। इसके सदस्य विविध विभागों के अध्यक्षों की भांति कार्य एवं व्यवहार करते हैं। इसीलिए इसे छाया मन्त्रिमण्डल (Shadow Cabinet) कहा जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि राज्याध्यक्ष के पास एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहनी है और विरोधी दल का नेता सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है।

(2) संयुक्त मन्त्रिमण्डल (Joint Cabinet)—संयुक्त मन्त्रिमण्डलों का निर्माण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होता है। इस प्रकार के मन्त्रिमण्डल की रचना उस समय भी की जाती है जबकि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।

(3) युद्ध मन्त्रिमण्डल (War Cabinet)—इस प्रकार के मन्त्रिमण्डल का निर्माण युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण होता है। इंग्लैंड में 1918 तथा 1940 में इस प्रकार के मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ। इसमें मन्त्रिमण्डल के ही चार अथवा

पाँच व्यक्तियों को रख दिया जाता है जो विशेष रूप से युद्ध-सामग्री तथा उसकी अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। युद्ध की समाप्ति पर इस प्रकार के मंत्रिमण्डल समाप्त हो जाते हैं।

(4) आन्तरिक मंत्रिमण्डल (Inner Cabinet)—यह चक्र के अंदर लघुतम चक्र होता है। इसमें मंत्रिमण्डल के वे सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री के अत्यंत घनिष्ठ एवं विश्वासपात्र व्यक्ति होते हैं जिनकी संख्या चार या पाँच से अधिक नहीं होती। अत्यंत प्रशासकीय महत्व के निणय एवं नीतियों का सम्पादन प्रधानमंत्री द्वारा इसी के परामर्श पर किया जाता है। इसी कारण इसे आन्तरिक मंत्रिमण्डल कहा जाता है।

मंत्रिमण्डल का गठन

(Organization of the Cabinet)

यह हम पहले भी कह चुके हैं कि मंत्रिपरिषद् प्रीवी समिति नहीं यद्यपि औपचारिकता के रूप में उसके सदस्यों को इसका सदस्य बनाया जाता है। प्रीवी परिषद् का मंत्रिमण्डल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आम चुनावों के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सदन (House of Commons) में किस दल का नितना बहुमत है। जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता की रानी की ओर से सरकार अथवा मंत्रिमण्डल का गठन करने का निमन्त्रण दिया जाता है। यह व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।

इस सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री के चयन में रानी की व्यक्तिगत इच्छा अथवा पक्ष का कोई महत्व है? सम्भवतः इसका उत्तर नकारात्मक रूप में ही देना सही है। किंतु महारानी अपनी स्वच्छा का प्रयोग कबल उसी स्थिति में कर सकती है जबकि यह बात सिद्ध हो कि किस दल का बहुमत है। वह एक अच्छा अवसर मिलता है जबकि उसे स्वविवेक के प्रयोग का अवसर मिलता है। दूसरी स्थिति वह है जबकि बहुमत दल के पास संसदसभ्यता से स्वीकृत कोई नेता नहीं होता अथवा नेतृत्व के कई प्रतियोगी होते हैं। उनमें से रानी एक का व्यक्तिगत योग्यता तथा क्षमता के आधार पर नियुक्त कर देती है। एथोनी ईडन के त्याग पत्र देने के उपरान्त इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी जबकि नेता बनने के दो प्रत्याशी उत्पन्न हो गये थे—मकमिलन तथा बटलर। उस समय मकमिलन का ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक स्वविवेक निणय के अधिकार के प्रयोग करने का प्रश्न है, वह लगभग नहीं के बराबर है। सम्राट अल्पमत के व्यक्ति को इस पद पर आश्रित करके अपने अस्तित्व एवं निष्पक्षता के लिए मंतरा मोल नहीं ले सकता। बहुमत के अभाव में शासन का संचालन एवं स्थायित्व सम्भव नहीं हो सकेगा। मंत्रिमण्डल के निर्माण में सम्राट की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। सम्राट की शक्ति हम निम्नानुसार मर्यादित है। प्रधानमंत्री की इच्छा पर वस्तुतः कई व्यावहारिक प्रतिबंध हैं।

का मंत्री प्रस्तुत करत समय बन्द जाता व प्रतिनिधित्व का ध्यार रगता पड़ता है— भौगोलिक प्रतिनिधित्व अनुभव विगिष्टता तथा इन म म्मिनि का प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री को मंत्रियों की मंत्री म्मिनि करत समय इन म्ममम म्ममों का ध्यान रगता पड़ता है। मन्त्रिमण्डल व सन्ममों को ममद का सन्मम हाता आवश्यक है। यदि मन्त्रिमण्डल का कर्ट सन्मम म्मम का सन्मम नहीं है तो उम निपुति का निधि स छ माह की अवधि म ममद की सन्ममता गहम बग्ता अगमिा है, अग्मम उस अवध पद का त्याग करता पड़ता है। मन्त्रिमण्डल म सन्मम म्मिनि निवित्त नहीं है। मन्त्रिमण्डलीय पञ्चि का निर्वाह कागुत पर अवगमिा नहीं है। उत्तर काय म्ममलत लय निर्माण का आधार है परम्परा। दुगम प्राय 12 म सन्मम 24 व बीच म सन्मम हाता हैं। कागमा मन्त्रिमण्डल म 23 सन्मम है। तीन कोतत विभागीय अग्मम इनम म्मिमलित विप जायें दुगम विणय प्रधानमंत्री करता है। महत्वपूर्ण विभागा व लगमम सभी मन्त्री हाता सन्मम रहत हैं। जिन महत्वपूर्ण मंत्रियों को मन्त्रिमण्डल म प्राय सन्मिमलित विपा जाता है वे हैं—सॉट प्रीवी तील, अय मन्त्री रक्षा मन्त्री, प्रीवी कैसिल का अग्मम, सॉट चामसलर, व्यापार मन्त्री, उपविषम मन्त्री, राष्मण्डल सन्ममघी विपयो का मन्त्री, गृह मन्त्री, शिक्षा-मन्त्री, श्रम एव राष्ट्रीय सेवा मन्त्री आदि।

मन्त्रिमण्डल का महत्व (Importance of the Cabinet)

वास्तव इगलण्ड म पायपालिका का स्वरूप एव रय व सन्मम है। इसम महारानी का आसन है और राज-सन्मम के साथ उसकी सवारी निवत रही है। प्रधानमंत्री रय पर सारथी है। रय के लगमम 12 पहिये हैं, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। एव रय को सँकडा छोडे रीच रह हैं जो सन्मिम हैं। इगलण्ड व एक अय रूपव म महारानी की डोली का प्रधानमंत्री वित्त मन्त्री, सुरक्षा तथा विदेश मन्त्री वधो पर उठाये हुए चित्रित किये गये हैं। एव अय पत्रकार के अनुसार महारानी प्रधानमंत्री रूपी छोडे पर सवार है विन्तु उनके हाथ म लगमम नहीं है, फलत वे उमे रोक तथा इच्छानुकूल चला एव मोड नहीं सक्ती। पुचकारने से वह मानता नहीं है, छोडे का उसकी भीटी खाल पर कोई असर नहीं है। यदि महारानी थक जायें तो उससे उतर कर भी व थोड़ी देर विश्राम नहीं कर सक्ती। किन्तु थोडा भी बहुत समसदार है। महारानी को गिराता नहा है, वरन उनकी फटकार सह लेता है। उनके क्रोध पर उसे प्यार आता है। दुगम पथ तथा कैंटीली शाडिया म स महारानी को सुरक्षा के साथ निवाल ले जाता है। जब वह सवा-योग्य नहीं रहता तो महारानी उसे राजमहल म रखती हैं और नूतन छोडे अर्थात् प्रधानमंत्री की खोज करती हैं। इन तीनों रूपका स तीन बातें स्पष्ट होती हैं—महारानी, प्रधान-मन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल की सापेक्षिक स्थिति। इससे अन्तरम केबिनेट तथा ब्रिटिश कायपालिका व महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है।

संसदीय शासन प्रणाली म मन्त्रिमण्डल का प्रमुख स्थान होता है। इसे हम उसकी आधार शिला भी कह सकते हैं। वही उसकी निर्देशक शक्ति है। मन्त्रिमण्डल ही प्रशासन को एकरूपता प्रदान करता है। मन्त्रिमण्डल एक निगम की भांति है

जिसका नियंत्रण एवं निर्देशन मण्डल के हाथों में होता है। निर्देशन मण्डल की भाँति राज्य विषयक महत्वपूर्ण नीतियों की प्रतिस्थापना मंत्रिमण्डल के द्वारा की जाती है। ग्लेडस्टन के शब्दों में मंत्रिमण्डल आधुनिक युग का एक अद्भुत निर्माण है।" (The most curious formation of modern times) प्रो० वारर ने मंत्रिमण्डल को "नीति का चुम्बक" कहा है। लॉवेल (Lowell) ने मंत्रिमण्डल को 'राजनीतिक कृत्तमण्ड का मध्य प्रस्तर' (The keystone of the political arch) कहा है। रैम्से म्योर (Ramsay Muir) ने इसे "राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र" (Steering wheel of the ship of the state) कहा है। एमरी ने मंत्रिमण्डल को "सरकार का केन्द्रीय निर्देशक यंत्र" (The central directing instrument of Government) कहा है।

बजहॉट (Bagehot) ने मंत्रिमण्डल के समन्वयकारी रूप का विवेचन करते हुए उसकी परिभाषा इस प्रकार की है— 'यह एक हाइफन है जो जोड़ता है, तथा एक बन्धुआ है जो व्यवस्थापिका तथा वायपालिका भागों को जकड़ देता है। (A hyphen which joins a buckle, which binds the legislative and executive parts together) मरियट (Marriot) की दृष्टि में 'मंत्रिमण्डल वह घुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है।' (The pivot round which the whole political machinery revolves) जेनिंग्स के अनुसार 'मंत्रिमण्डल समस्त ब्रिटिश शासन प्रणाली का एकरूपता प्रदान करता है।' (The cabinet provides unity to the British system of Government) मंत्रिमण्डल शासन का प्रमुख संयोजक यंत्र है। मंत्रिमण्डल ही प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है। यही प्रशासन का केन्द्र तथा उमका जीवन है। ग्लेडस्टन के शब्दों में, 'यह एक सूर्य पिण्ड है जिसके चारों ओर अन्य पिण्ड घूमते हैं।' (It is the solar of orbit round which other bodies revolve) मंत्रिमण्डल ही प्रशासन को गति प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण यंत्र है। "मंत्रिमण्डल शासन-व्यवस्था का केन्द्रीय तथ्य तथा संविधान की प्रमुख आभा है।" (Central fact and chief glory of the constitution)

मंत्रिमण्डलीय पद्धति के सिद्धान्त (Principles of Cabinet System)

1. नाममात्र का कार्यपालिकाध्यक्ष (Titular Executive Head)

संसदीय प्रणाली की यह प्रथम आवश्यकता है कि वायपालिका का अध्यक्ष नाममात्र का होना चाहिए अर्थात् उसकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं हानी चाहिए। यदि राष्ट्राध्यक्ष की शक्तियाँ वास्तविक हैं तो संसदीय प्रणाली काय नहीं कर सकती। सिद्धान्त में तो समस्त शक्तियों का आगार सम्राट ही है परन्तु उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता बल्कि उसकी आर से इनका प्रयोग मंत्रिमण्डल अथवा संसदमय राजा अथवा क्राउन करता है। अब राजा मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता नहीं करता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की शक्ति केवल एक औपचारिकता मात्र है। यही कारण है कि कुशासन के लिए आलोचना सम्राट की नहीं होनी बल्कि सरकार की होती है क्योंकि शासकीय शक्तियों का वास्तविक प्रयोग उसी के द्वारा होता है।

2 मंत्रियों का चयन बहुमत दल में से होता है (Ministers are chosen from the parliamentary majority)

मंत्रिमण्डलीय पद्धति का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों का चयन प्रायः उस दल में से होता है जिस सगद में बहुमत प्राप्त हो। ससद की सदस्यता मंत्रिमण्डल के सदस्यता में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। इसी से विधानपालिका तथा वायपालिका एक दूसरे के साथ बढ किये जाते हैं। ससद की सदस्यता ही मंत्रिमण्डल का निर्देशन, नियन्त्रण तथा नन्तृत्व आदि के विविध अवसर प्रदान करती है। इंग्लैण्ड में मसनीय सदस्यता का अभिसमय है यद्यपि जनरल स्मट्स इसका अपवाद हैं जा 1916 में लेकर 1919 तक मुड मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे जबकि वे ससद के सदस्य नहीं थे। सर योसकवन 1922 23 में कृपि मन्त्री के रूप में ससदीय सदस्यता की अनुपस्थिति में भी कार्य करते रहे। 1935 से लेकर 1936 के प्रारम्भ तक रम्जे मकडोनल्ड तथा मैलकम मैकडोनल्ड बिना ससनीय सदस्यता के मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। किसी निश्चित अवधि के उपरान्त अब मंत्रिमण्डल की सदस्यता बिना ससदीय सदस्यता के सम्भव नहीं है। जब कभी भी मिले जुले मंत्रिमण्डलों का निर्माण होता है उस समय इस सिद्धांत का कि मन्त्री बहुमत दल में से नियोजित हैं, खण्डन भी हो जाता है।

3 प्रधानमन्त्री का नेतृत्व (Leadership of the Prime Minister)

प्रधानमन्त्री को मंत्रिमण्डल रूपी घृत्तरण्ड का मध्य प्रस्तर कहा गया है। वह मंत्रिमण्डल का केवल अध्यक्ष ही नहीं है, बरन् उसका निर्माता तथा जीवन है। प्रधानमन्त्री का त्यागपत्र मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र है। उसे मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में निर्देश नियन्त्रण तथा सघनन का पूरा अधिकार है। मंत्रियों की नियुक्ति यद्यपि परम्परागत रूप में राजा द्वारा होती है किन्तु वह केवल एक औपचारिकता मात्र ही है। प्रधानमन्त्री ही अपने माधियों का चयन करता है और वास्तव में वे उसी की इच्छानुसार अपने पदों पर आसीन भी रहते हैं। प्रधानमन्त्री स्वेच्छा से किसी भी रूप में मंत्रिमण्डल में परिवर्तन कर सकता है। 1931 में प्रधानमन्त्री रम्जे मकडोनल्ड ने अपने मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों से परामश किये बिना ही मंत्रिमण्डल का त्याग पत्र दे दिया था।

4 मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व (Ministerial Responsibility)

विश्व की ससदीय प्रणाली को इंग्लैण्ड का महत्वपूर्ण अनुदाय मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व की परम्परा है। मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व इस तथ्य का प्रतीक है कि वायपालिका विधानपालिका के अधीन है। विधानाङ्क का मन्त्रियाँ स प्रश्न पूछने तथा उनसे नीति सम्बन्धी स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार है। विधानमण्डल ही वास्तविक सप्रभु सत्ता का प्रतीक है। विधानमण्डल का अविश्वास मंत्रिमण्डल के अस्तित्व में बम्पन उत्पन्न कर सकता है। विधानमण्डल के प्रति यह उत्तरदायित्व वास्तव में लोक सदन अथवा हाउस आफ कॉमन्स के प्रति ही है। लॉड सभा के अविश्वास का मंत्रिमण्डल में ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह उत्तरदायित्व दोनों ही प्रकार का है—व्यक्तिगत तथा सामूहिक।

(क) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Responsibility)—अपने विभाग

के सम्बन्ध में पूरा उत्तरदायित्व सम्बाधित मन्त्री का ही है। अपने विभाग के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न तथा नीतियों का सदन के समक्ष स्पष्टीकरण मन्त्री को ही प्रस्तुत करना पड़ता है। वैसे तो दिन प्रति दिन मन्त्रिमण्डल का स्वरूप सामूहिक होता जा रहा है किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि इससे सम्बाधित मन्त्री का उत्तरदायित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इंग्लैण्ड के संवैधानिक विकास में ऐसे दृष्टांत हमें अब भी मिलते हैं जबकि विरोधी सदन के समक्ष मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा है। 1864 में श्री लोवी ने तथा 1866 में लाड वेस्टवरी ने सदन की अप्रसन्नता के समक्ष व्यक्तिगत त्यागपत्र दिए। 1936 में जे एच टामस को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया था क्योंकि बजट समय से पूर्व लोगों को पता लग गया था। इससे सरकार को घाटा हुआ। ऐसे ही आधार पर सर ह्यू डाल्टन की वित्त मन्त्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 1935 में विदेश मन्त्री सर स्म्युअल हार्बर को त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इटली इथियोपिया युद्ध के विषय में लोकसभा उनके प्रस्तावों की भत्सना करेगी।

(ख) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)—वस्तुतः मन्त्रिमण्डल का यह रूप अधिक महत्वपूर्ण है। इससे अतःगत इसे एक इकाई का रूप दिया जाता है। मन्त्रिमण्डल एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। इससे सदस्य एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। वे “जियेंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ” के सिद्धांत का व्यवहार में अनुकरण करते हैं। वे हर आपत्ति का मुकाबला सामूहिक रूप में करते हैं। अमुक मन्त्री का पतन केवल उसी का पतन नहीं है बरन वह पूरा मन्त्रिमण्डल का पतन है। मन्त्रिमण्डल में प्रायः एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। राजनीतिक प्रश्न पर उनका दृष्टिकोण लगभग एकसा होता है और यदि नहीं भी है तो बनाना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल के बाहर भी मन्त्री को उही नीतियों का अनुकरण करना होता है जिनके सम्बन्ध में पूर्व निर्णय हुआ चुका है। यदि कोई मन्त्री मन्त्रिमण्डल की नीतियों से सहमति स्थापित करने में अपन को असमर्थ पाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे हट जाना चाहिए। इसी प्रकार 1855 में लॉर्ड जान रसल ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। पील तथा अन्य तीन मन्त्रियों ने इस कारण त्यागपत्र दे दिया था कि वे उसके सुधार विधेयक से सहमति नहीं रखते थे। 1914 में लाड मार्ले तथा ब्रैम ने इसी आधार पर मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था कि युद्ध की घोषणा करने के निर्णय के विषय में उनकी सहमति नहीं थी। 1938 में इंग्लैण्ड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने चम्बरलेन मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि वे उसकी विदेश नीति से सहमत नहीं थे। मन्त्रिमण्डल में जिस समय निर्णय नहीं होता, उस समय तक, सहमति एवं असहमति दोनों का इजहार हो सकता है किन्तु एक निर्णय हो जाने के पश्चात् वह सबका अथवा पूरा मन्त्रिमण्डल का निर्णय है। जो मन्त्री उससे सहमति नहीं रखता उसने समक्ष केवल त्यागपत्र का विकल्प रह जाता है। समस्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य सदन में तथा सदन से बाहर निर्णीत नीतियों की रक्षा, पेरवी तथा अनुकरण करने के लिए नैतिक रूप से बद्धिबद्ध है। इसका उल्लंघन करने वालों से प्रधानमन्त्री त्यागपत्र मांग सकता है। 1922 में भारत मन्त्री लाड माटेयू का त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उन्होंने मन्त्रिमण्डल

अनुमति के बिना एक तार का प्रकाशन होने दिया जिसका सम्बन्ध व्यापक महत्वपूर्ण नीति से था।

5 गोपनीयता (Secrecy)

गोपनीयता मंत्रिमण्डल पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कानून तथा परम्परा दोनों के ही द्वारा इसे कायम रखा जाता है। मंत्री अपने पद की शपथ लेते समय गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। अत्यधिक प्रचार से मानसिक स्वतन्त्रता नष्ट होती है। गोपनीयता के अभाव में दलीय एकता को बनाय रखना कठिन प्रतीत होगा। प्रत्येक मंत्रिमण्डल के सदस्य से उसकी कायवाही को गोपनीय रखने की कोशिश की जाती है। इसके खुल जाने से सरकार का संचालन लगभग समाप्त एवं दुसाध्य हो जाता है। मंत्रिमण्डल की गोपनीय गतिविधियों का औपचारिक रूप में प्रकाशन नहीं होता। मंत्रिमण्डलीय कार्यों के सचिव को गोपनीयता सम्बन्धी विशेष हिदायत दी जाती है। मंत्रिमण्डल की कायवाही का बैठक के पश्चात् सील करके कण्ट्रोल रूम बंद कर दिया जाता है। अतः गोपनीयता इस पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। 1917 के पश्चात् अब मंत्रिमण्डल के निणयो का लेखा रखा जाने लगा है। कभी कभी इस आदेश का उल्लंघन भी हो सकता है किन्तु उस स्थिति में मंत्री विशेष को अपदस्थ होने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

मंत्रिमण्डल के विषय में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा। इसकी कई दृष्टियों से उपयोगिता भी है। मंत्रियों में परस्पर सहयोग की भावना बनी रहती है। वे परिवार के कमठ सदस्यों की भाँति कार्य करते हैं। मंत्रियों को व्यक्तिगत स्वाध में ऊपर उठने के लिए विवश होना पड़ता है। समस्त मंत्रिमण्डल एक इकाई के रूप में कार्य करता है तथा उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मंत्रिमण्डल सशक्त रूप में अपनी बात रखने में अपने का समय पा सकता है। ससद अथवा राजा को प्रदत्त परामर्श इतना मूल्यवान समझा जाता है कि उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं हो पाता। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना ही मंत्रियों में उस शक्ति को पैदा करती है जिससे वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में उपक्रम कर सकते हैं तथा अपने में आत्म विश्वास पा सकते हैं। किन्तु सामूहिक उत्तरदायित्व का अवगुण भी है कि इससे मंत्रियों में स्वतंत्र विचार रखने तथा उन्हें व्यक्त करने के गुण का नैतिक पक्ष दुबल पड़ जाता है और मंत्रिमण्डल अधिनायक के रूप में कार्य करने लगता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जो अधिक महत्वपूर्ण है क्षीण पड़ जाता है। व्यक्तिगत मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के आवरण में अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयत्न करने लगते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की इस ससदीय प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से वे मंत्री दब से रहते हैं जिनका व्यक्तित्व किसी कारण से शक्तिशाली नहीं बन पाता।

6 कार्य प्रणाली (Working)

साधारणतः ससदीय अधिवेशन के समय मंत्रिमण्डल की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मन्त्राह में दो बैठकें हो जाती हैं। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ायी भी जा सकती है। ससदीय अधिवेशन की अनुपस्थिति में मंत्रिमण्डल

की वृत्तों आवश्यकता पढ़ने पर ही आमंत्रित की जाती है। मन्त्रिमण्डल की अपनी स्थायी एवं अस्थायी समितियाँ होती हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं को इन्हीं की समर्पित कर दिया जाता है। इन समितियों के द्वारा अंतिम निर्णय भी लिये जाते हैं। अंतिम निर्णय की अनुपस्थिति में ये मन्त्रिमण्डल के समक्ष अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकती हैं। समितियाँ समस्या से सम्बद्ध मन्त्रियों को जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर सकती हैं। जो मन्त्री मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते वे इन समितियों की कार्यवाहियों में भाग तो ले ही सकते हैं किन्तु इसके साथ साथ वे इनके सदस्य भी बन सकते हैं। मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही गुप्त होती है। प्रत्येक मन्त्री उसकी गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मन्त्रिमण्डल के आदेश बिना उसका कोई मन्त्री कार्यवाही का जायजा बाहर नहीं दे सकता। यदि कोई मन्त्री अपने त्यागपत्र समर्पित करने के कारणों के विषय में सदन में वक्तव्य देना चाहता है तो उसे प्रधानमन्त्री की आज्ञा लेनी होती है।

मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियाँ का विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता केवल प्रमुख निर्णयों एवं तर्कों का ही विवेचन रखा जाता है। यह कार्य मन्त्रिमण्डल के सचिव द्वारा सम्पन्न होता है। मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों का प्रसारण तो होता है किन्तु बहुत ही संक्षेप में। मन्त्रिमण्डल के निर्णय बहुधा मजसमिति से ही होते हैं। ऐसा दृष्टिकोण उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है।

मन्त्रिमण्डल के कार्य

(Functions of the Cabinet)

काउन एक कार्यात्मक संस्था है जिसका यथायथ वास्तविक स्वरूप है मन्त्रिमण्डल। मन्त्रिमण्डल अपने ढंग का एक ही निकाय है। वर्तमान शताब्दी मन्त्रिमण्डल के प्रभुत्व की ही शताब्दी है। वही राष्ट्र का नेतृत्व करता है और जनजीवन की सुरक्षा का प्रतीक है। लोक सदन का नेतृत्व भी अब मन्त्रिमण्डल के द्वारा सम्पन्न होता है। शासकीय तंत्र सम्बन्धी 1918 के प्रतिवेदन में मन्त्रिमण्डल के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार मन्त्रिमण्डल के प्रमुख कार्य हैं—सावजनिक नीतियों का अंतिम निर्णय, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण राजकीय विभागों के मध्य तालमेल उत्पन्न करना तथा उनकी शक्तियों की सीमा निर्धारित करना। राज्य का कल्याणकारी स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासकीय हस्तक्षेप की आशा करता है जिसके फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल के कार्यों में आवश्यकता से अधिक विकास हुआ है। उसके कार्यों का विवेचन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं।

1. व्यवस्थापन विषयक कार्य (Legislative Functions)

यह कहना कि व्यवस्थापन में मन्त्रिमण्डल का कोई हाथ नहीं होता, यथायथ से दूर एक साहित्यिक कल्पना ही है। सचमुच मन्त्रिमण्डल ही वास्तव में विधानमण्डल है। उसके द्वारा ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं और उन्हीं के पारित होने की आशा भी रहती है। व्यक्तिगत विधेयक भी उसी की अनुकम्पा से पारित होने की आशा रखते हैं। मन्त्रिमण्डल ही कानूनों के लिए प्रस्ताव रखता है उन प्रस्तावों का प्रारूप रखता है और उन्हें लोक सदन द्वारा स्वीकृत कराने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता है। सम्भवतः इसी कारण हट जे ने इसे सूक्ष्माकार

विधान मण्डल कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापन सम्बन्धी नृत्व अब मंत्रिमण्डल के ही हाथों में आ गया है। इसके अतिरिक्त सदन के सत्रों को आहूत करने का परामर्श तथा सत्रावसान सम्बन्धी आदेश मंत्रिमण्डल द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। राजा का अभिभाषण भी मंत्रिमण्डल के द्वारा निश्चित तथा तैयार किया जाता है। आगामी सत्र के लिए व्यवस्थापन नीति का स्वरूप क्या होगा, इसका निश्चय भी मंत्रिमण्डल ही करता है। सावजनिक तथा व्यक्तिगत विधेयकों के विषय में वाद विवाद पर कितना समय लगाया जाय, इसका निश्चय भी सदन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। कहने का उद्देश्य यह है कि व्यवस्थापन पर मंत्रिमण्डल हावी रहता है, सदन तो उसकी इच्छा की स्वीकृति मात्र प्रदान करता है।

2 कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य (Executive Functions)

(क) नीति निर्धारण (Policy Determination)—मंत्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। राजा की समस्त शक्तियाँ का प्रयोग अब मंत्रिमण्डल ही करता है। राष्ट्रीय नीतियाँ वस्तुतः मंत्रिमण्डल की ही नीतियाँ होती हैं। नीतियाँ का निर्माण जनतन्त्रीय व्यवस्था में किसी एक स्तर पर नहीं होता। उसके निर्माण के विविध स्तर हैं और मंत्रिमण्डलीय स्तर उन सब में अधिक महत्वपूर्ण तथा अपनी अनुपम स्थिति के कारण सर्वोच्च शक्तिशाली है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण मंत्रिमण्डल करता है। सदन से केवल उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(ख) महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ (Important Appointments)—राज्य में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती हैं जो सेवा आयोगों की परिधि में नहीं आती। उदाहरण के लिए राजदूतों की नियुक्ति। इस प्रकार की नियुक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में राजा द्वारा की जाती हैं। राजा की स्वीकृति तो एक औपचारिकता मात्र है। वस्तुतः वे नियुक्तियाँ मंत्रिमण्डल के द्वारा ही की जाती हैं। पीयूषों का निर्माण तथा विविध प्रकार की उपाधियों का निश्चय भी मंत्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। विविध राष्ट्रीय आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति मंत्रिमण्डल द्वारा की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण (Supreme Control over National Executive)—कार्यपालिका का प्रमुख कर्तव्य है, विधान मण्डल द्वारा निश्चित की गयी नीतियों को अमली जामा पहनाना। इसी कारण से तो कार्यपालिका के इस वर्ग के सदस्य स्थायी कार्यपालिका के सदस्य कहलाते हैं। वे अपनी निष्पक्षता बनाये रखते हैं चाहे किसी दल की सरकार क्यों न हो। मंत्रिमण्डल का यह मूल उत्तरदायित्व है कि वह देख कि किस सीमा तक उन नीतियों का पालन विधान मण्डल की इच्छानुकूल हुआ है। इसी कारण प्रत्येक मंत्री की अध्यक्षता में एक अथवा एक से अधिक विभाग रखे जाते हैं। विभागों की स्वयं व्यवस्था का उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल पर है। मंत्रिमण्डल प्रशासन तथा व्यवस्थापन दोनों को नेतृत्व प्रदान करता है। प्रशासकीय विभागों की गतिविधियाँ सफरता तथा अमरफलताओं के विषय में सदन में मंत्रिमण्डल के सदस्यों को ही उत्तर देना होता है। नीतियों का स्पष्टीकरण उन्हीं के द्वारा होता है।

(घ) प्रमुख सचिवनकर्ता (Chief Co-ordinator)—समन्वय प्रशासन के

लिए जीवन है। प्रशासन के विविध क्षेत्रों के मध्य समन्वय उत्पन्न करके उसे बनाये रखना मन्त्रिमण्डल का महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यकुशलता के विकास, अंतरविभागीय सहयोग, नीतियों की द्विगुणनता को रोकने आदि के लिए समन्वय की अति आवश्यकता होती है। एक विभाग की नीति दूसरे विभाग की नीतियों के प्रतिद्वन्द्व हो सकती है। इस प्रतिद्वन्द्वता का दुष्प्रभाव प्रशासन पर होता है। इस स्थिति पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा सम्पन्न होता है। इसके अभाव में समस्त संगठन बिखर जायगा। सघन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो मन्त्रिमण्डल की विविध समितियों का गठन होता है। मन्त्रिमण्डल सचिवालय केवल मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों के लेखे जोखे को रखने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि शासन के विविध क्षेत्रों में समन्वय उत्पन्न करता है। प्रत्येक विभाग से सूचनाएँ प्राप्त करता है तथा विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं और गतिविधियों में ताल मेल उत्पन्न करके कार्यकुशलता के विकास के लिए यत्न करता है।

3 वित्त सम्बन्धी कार्य (Financial Functions)

देश की वित्त-व्यवस्था पर सदन का अधिकार रहता है किन्तु व्यवहार में उस अधिकार का प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा ही होता है। मन्त्रिमण्डल द्वारा ही आय तथा व्यय का व्यापक व्योरा तय किया जाता है। उसके निर्माण का उत्तरदायित्व वित्तमन्त्री के ही ऊपर रखा जाता है। बजट निर्माण में पूर्ण गापनीयता रखी जाती है। प्रस्तुत करने की तिथि के पाँच दिन पूर्व बजट मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मन्त्रिमण्डल यदि चाह तो उससे पूर्व भी बजट को अपन समक्ष प्रस्तुत करा सकता है। करो में परिवर्तन करने का अधिकार मन्त्रिमण्डल का है। मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन समद द्वारा किया जाता है। मन्त्रिमण्डल का भविष्य बहुत कुछ बजट की सफलता पर अवलम्बित रहता है।

मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व (मन्त्रिमण्डल तथा सदन)

(Dictatorship of the Cabinet)

मन्त्रिमण्डल के कार्यों तथा उसके स्वरूप का अवलोकन करने के उपरान्त यह सरलता से कहा जा सकता है कि जिस समय तक उसके पीछे बहुमत का समर्थन उपलब्ध है, वह सर्वसत्तात्मक एवं सर्वसत्ता-सम्पन्न शासकीय निकाय सिद्ध हो सकता है। यदि 19वीं शताब्दी मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व की शताब्दी थी तो वर्तमान शताब्दी मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व की शताब्दी है। मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अप्रत्याशित रूप से इतना विकास हुआ है कि उसने व्यवहार में एक 'अधिनायक' का सा रूप धारण कर लिया है। अब शासकीय जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो मन्त्रिमण्डल के प्रारम्भ एवं हस्तक्षेप क्षेत्र में बचा हुआ हो। आज सदन की स्थिति उच्चता एवं सर्वोपरिता की न होकर गौणता की है। ससदीय सावभौमिकता केवल सिद्धांत में रह गयी है व्यवहार में वह क्षीण एवं दुबल पड़ गयी है। इसी कारण सम्भवतः आज यह कहा जाने लगा है कि 'सदन का कार्य नियन्त्रण करना नहीं है बरन आलोचना करना है।' (The function of the Parliament is not to govern but to criticise) इसी प्रकार 'समद केवल मन्त्रिमण्डल की इच्छा को पजीवृत करने वाला एक निकाय मात्र है।' (Parliament is to register the will

of the cabinet) कहने का तात्पर्य यह है कि सदन ने मंत्रिमण्डल की शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। सदन का कार्य अब कार्य न करके केवल आलोचना करना मात्र रह गया है। आज सदन कोई बात प्रस्तावित नहीं करती वरन् मंत्रिमण्डल द्वारा रखे गये प्रस्तावों का अनुमोदन मात्र करती है। मंत्रिमण्डल तथा ससदीय सम्बन्ध के दो पहलू हैं—कानूनी तथा व्यावहारिक।

(1) कानूनी अथवा संवैधानिक पहलू (Constitutional Side)—इस दृष्टि से जिन विचारों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, वे हैं डायसी, रैम्जे म्योर तथा लाम्बी। डायसी मंत्रिमण्डल को सदन की सत्तायुक्त समिति मात्र मानता है जिस पर सदन का पूर्ण अधिकार एवं नियन्त्रण होना है। उसके अनुसार सदन के समक्ष इंग्लैण्ड में व्यवस्थापन कार्य करने वाला अथवा कोई निकाय नहीं है। साधारण एवं संवैधानिक दोनों प्रकार के कानूनों के निर्माण का एकमात्र अधिकार सदन का है। इस दिशा में उसे असीमित शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सदन द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार देश में किसी को नहीं है। कोई भी न्यायालय उसके कार्यों का सर्वेक्षण एवं नियन्त्रण का अधिकार नहीं रखता।

संविधान में सदन की स्थिति कार्यपालिका से उच्चतर है। ससदीय समर्थन की अनुपस्थिति में मंत्रिमण्डल को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मंत्रिमण्डल सदन की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकता। ससदीय नियन्त्रण कार्यपालिका को सीमित एवं मर्यादित रखना है। सदन प्रश्नों के द्वारा मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण स्थापित करती है। प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों से नीतियों का स्पष्टीकरण कराया जाता है। प्रश्नों का उत्तर न देने की स्थिति में कार्यपालिका के सम्मान को ठेस लगती है।

इससे अतिरिक्त समस्त मंत्रिमण्डल की नीतियों की आलोचना करके भी उससे ऊपर नियन्त्रण स्थापित करती है। वह मंत्रिमण्डल द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। मंत्रिमण्डल की नीतियों की अस्वीकृति उसके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। अस्वीकृति का अर्थ होता है अविश्वास।

मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण स्थापित करने के जो अथवा प्रभावशाली तरीके हैं उनमें हम बड़ीती प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव, निर्दा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को ले सकते हैं। इन माध्यमों के द्वारा भी सदन मंत्रिमण्डल पर सक्रिय नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो जाती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि सदन पूर्ण सत्तावान है और ससदीय अनुकम्पा के अभाव में मंत्रिमण्डल अपने पद पर आसीन नहीं रह सकता अर्थात् मंत्रिमण्डल को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ससदीय समर्थन को प्राप्त करना ही होगा।

(2) व्यावहारिक पहलू (Practical Side)—इस प्रश्न की व्यावहारिकता पर व्यापक रूप से विचार रैम्जे म्योर तथा लाम्बी ने किया है। व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त मंत्रिमण्डल के हाथ में बड़-पुनर्ती के गुण हैं। मंत्रिमण्डल की उपेक्षा करने का साहस सदन अब नहीं कर पाती। शासन के सीमा क्षेत्रों में मंत्रिमण्डल की स्थिति मजबूत होती है। व्यवस्था

य क्षेत्र में मासिक विधेयों का प्राप्ति मंत्रिमण्डल द्वारा ही संभव किया

जाता है। ससद तो केवल अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। किसी समय की यह वास्तविकता अब केवल एक औपचारिकता मात्र है। ससद भी अपने अस्तित्व को खतरे में डाले बिना विरोध एवं अस्वीकार करने का सरलता से साहस नहीं करती। ससद के सदस्य पुनः निर्वाचन से घबराते हैं।

कायपालिका क्षेत्र में भी मन्त्रिमण्डल की स्थिति उच्चतर है। शासकीय नीतियों का निर्धारण भी मन्त्रिमण्डल के द्वारा सम्पन्न होता है। ससदीय अधिवेशनों का निणय सत्रावसान आदि का निणय मन्त्रिमण्डल करता है। काय प्रणाली तथा विशेष सत्र में कार्यों का निणय भी मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। यदि सदन अविश्वास प्रदर्शित करके मन्त्रिमण्डल के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है तो मन्त्रिमण्डल भी अपने विघटन अधिकार द्वारा ससद के जीवन को कण्टमय बना सकता है। अतः मन्त्रिमण्डल पर ससदीय नियन्त्रण की बात सद्धान्तिक अधिक तथा व्यावहारिक कम है।

वित्तीय क्षेत्र में भी यद्यपि सद्धान्तिक दृष्टि से ससदीय शक्ति असीमित है, ससद ही वित्त विधेयको को स्वीकार अथवा अस्वीकार करती है किन्तु यह केवल एक औपचारिकता मात्र है। वस्तुतः यह काय मन्त्रिमण्डल द्वारा सम्पन्न होता है। मन्त्रिमण्डल ही बजट तैयार करता है, ससद में प्रस्तावित करता है तथा उसका निष्पादन करता है। ससद को वित्त विषयक अभियोगिकाओं की धनराशि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उसमें अलवृत्ता वह कमी अवश्य कर सकती है।

अतः ससदीय सावभौमिकता व्यवहार की दृष्टि से मिथ्या बात है। उसे सदन की एक समिति मात्र मानना एक भ्रान्ति है। वह ससद को विघटित कराने का एक शक्तिशाली अधिकार अपने पास रखती है। प्रशासकीय काय पर ससदीय नियन्त्रण की बात असत्य है। ससदीय आलोचना ग्राम मन्त्रिमण्डल को अपनी नीतियों में संशोधन करने के लिए बाध्य करने में असफल रहती है। प्रशासकीय विभागों की नियमित समीक्षा भी सुलभ नहीं हो पाती। सत्य तो यह है कि मन्त्रिमण्डल की शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण है तो वह केवल लाकमत् ही हो सकता है। उक्त विचारधारा का प्रबल समर्थन रम्से म्यूर (Ramsay Muir) द्वारा हुआ है। इसका विपरीत, लास्की (Lasky) मन्त्रिमण्डल को सत्तावान तो स्वीकार करता है किन्तु उसे अधिनायक के रूप में स्वीकार नहीं करता। मन्त्रिमण्डल को ससदीय आलोचनाओं में प्रति जागरूक रहना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण निरकुशता के आधार पर नहीं हो सकता।

मन्त्रिमण्डल की महत्ता के कारण (Causes of the Dictatorship of the Cabinet)

(1) दल प्रणाली (Party System)—इस दृष्टि से इंग्लैंड की स्थिति फ्रांस तथा भारत की अपेक्षा वही अच्छी है। इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में सदा दो दलों का प्रभुत्व बना रहा है। तृतीय दल तो नाममात्र का ही रहा है। इसी कारण वहाँ के राजनीतिक जीवन में स्थायित्व बना रहा है। फ्रांस में बहुत-से राजनीतिक दल हैं। मन्त्रिमण्डल बहुधा मिले जुले बनते थे और इसी कारण वहाँ मन्त्रिमण्डल का वह महत्त्व नहीं रहा। ब्रिटन की द्विदलीय पद्धति का वहाँ के

राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्व रहा है और वहाँ राजनीतिक स्थायित्व का मूल आधार बना रहा है। इसी कारण इंग्लैंड में बहुधा मंत्रिमण्डल स्थायी रहे हैं और फलतः राजनीतिक जीवन में भी स्थायित्व रहा है।

(2) दलीय अनुशासन (Party Discipline) लास्की (Lasky) के अनुसार स्वतंत्र सदस्यों का युग समाप्त हुआ और भविष्य में उससे पुनर्जीवित होने की कोई आशा दृष्टिगत नहीं होती (The day of independent member has gone and there is no prospect that it is likely to be reviewed) दलीय अनुशासन इतना कठोर एवं गम्भीर हो गया है कि जिना अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाले हुए कोई भी सदस्य दलीय आज्ञाभा की अवहेलना करने का साहस नहीं करता। दल से निष्कासन राजनीतिक आत्महत्या से कम नहीं है। निरदलीय सदस्य को कोई भी दल वजन नहीं देता। अंतरात्मा की पुकार का कोई मूल्य नहीं है उसके दिन समाप्त हुए। आज की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति भी मंत्रिमण्डल के बढ़ते हुए प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमण्डल इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है कि ससद सदस्यों से उसे अपनी नीतियों पर समर्थन प्राप्त होता रहेगा। कार्यक्रम तथा दलीय आदेश ससद सदस्यों के हाथ जकड़ देते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का ससदीय दल उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अपने को बद्ध समझता है जिनके सम्बन्ध में दलीय कार्यकारिणी न निश्चय कर लिया है। इस दलीय अनुशासन की कठोरता के कई कारण हैं।

(1) देश के छोड़पन तथा जनसंख्या की एकरसता के कारण दलीय संगठन उत्तरोत्तर कठोर बनता चला जा रहा है।

(2) निर्वाचित होने के लिए दल का सहारा लेना पड़ता है। मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है। 1950 में एक निरदलीय सदस्य चुना जा सका। विवरण होकर सदस्यों को एक न एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना पड़ता है।

(3) ससदीय जीवन के कार्य इतने व्यापक हो गये हैं कि उनकी पूर्ति के लिए बड़-एव निश्चित नीति आवश्यक है।

(4) मंत्रिमण्डल के बढ़ते हुए विकास एवं महत्व के कारण मंत्रिमण्डल को दल के लगभग सभी शीप नेताओं का समर्थन प्राप्त होता है।

(5) दल-व्यवस्था का स्वरूप व्यावसायिक हो गया है। उसके संगठन एवं कार्यक्रमों में सैनिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इन कारणों से दलीय अनुशासन अधिक कठोर बना है और अब उसका स्वरूप इतना भयानक बन गया है कि उसके उल्लंघन का कोई भी साहस नहीं करता।

(3) ससद को भंग कराने की शक्ति (Power to get the Parliament dissolved)—लास्की का यह कहना सही है कि सदन को भंग कराने के अधिकार से ससद के सदस्यों का रचनात्मक उत्साह कम हो जाता है। जब सदन को यह अधिकार है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करके मंत्रिमण्डल को हटा सके तो स्वाभाविक रूप से मंत्रिमण्डल को भी यह अधिकार उपलब्ध है कि वह सदन का भंग करा सके। मंत्रिमण्डल जब यह समझता है कि लोक सभा द्वारा उसकी

नीतिया का समयन नहीं हो रहा है और उसे मतदाता का समयन उपलब्ध है तो वह राजा से बहकर सदन को भग करा सकता है। सदन के भग होने पर नतन निर्वाचन के लिए आदेश प्रसारित किये जाते हैं और यदि मन्त्रिमण्डल का समयन प्राप्त हो जाता है तो वह अपने पद पर बना रहता है। मन्त्रिमण्डल का यह अधिकार इतना शक्तिशाली है कि सदन के सदस्यों को गरम रखता है और आलोचना के स्वर पर नियन्त्रण रखता है। कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि वह पुनः निर्वाचन में इतनी जल्दी उतरने का खतरा मोल ले तथा आर्थिक विपत्तियों में फँस जाय। उसे यह भी सम्भावना दिखाई नहीं देती कि वह पुनः मफन हो सकेगा। कुर्सी का मोह बहुत ही जबरदस्त होता है। भारतीय सदन के मध्यावधि निर्वाचनों ने इस तथ्य की सत्यता को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। लोक सदन बहुत ही विवशता की स्थिति में इस विघटन को स्वीकार करता है। मन्त्रिमण्डल की इस शक्ति का यह चूण सदन के सदस्यों को अपच नहीं होने देता। यह सदस्यों को ठीक रखता है और उनकी शान्तियों को दबाय रहता है।

(4) प्रशासकीय न्याय (Administrative Justice)—प्रशासकीय न्याय एक और दूसरी व्यवस्था है जिसके कारण मन्त्रिमण्डल का महत्व बढ़ गया है। सदन समय समय पर अपने कार्यपालिका विभागों अथवा मन्त्रालयों को विभागीय नियम करने के अधिकार देती रहती है जिससे मन्त्रिमण्डल का महत्व उत्तरात्तर बढ़ता जाता है। पहले इनके सम्बन्ध में नियम न्यायालयों द्वारा किये जाते थे। 1913 के यातायात अधिनियम के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में अस्वीकृति सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार यातायात मन्त्रालयों को दिया गया है। पेंशन अधिनियम (Old Age Pension Act) भी इसी प्रकार की एक व्यवस्था है। प्रशासकीय नियमों के विरुद्ध अपील नहीं होती। इससे मन्त्रिमण्डल के प्रभुत्व का विकास हुआ है।

(5) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)—सामूहिक उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल में एकता एवं सजातीयता की भावना उत्पन्न करता है। मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्यों के मध्य प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में यह अद्भुत सी एकता दृष्टिगत होती है कि 'मरेंगे तो एक साथ और रहेगे तो एक साथ।' प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल द्वारा नियम सामूहिक रूप में लिये जाते हैं। एक बार सामान्य नीति निश्चित हो जान पर मन्त्री उससे पथक होना का साहस नहीं करते। लोक सदन में यदि किसी मन्त्रालय विशेष की आलोचना होती है तो वह उस विभाग तक ही सीमित नहीं रहती, वह वास्तव में समस्त मन्त्रिमण्डल की ही आलोचना होती है। ऐसी स्थिति में सब एक हाँकर परिस्थिति का मुँहासला करते हैं। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल एक सगठित सहयोगात्मक टीम के रूप में कार्य करता है जिससे उसके महत्व में उत्तरोत्तर विकास होता चलता है। फ्रांस के मन्त्रिमण्डल इस महत्व की उपलब्धि से वंचित बने रहे क्योंकि उनमें इस प्रकार के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था।

(6) प्रत्यापोजित शक्तिया (Delegated Legislation)—दिन प्रतिदिन कानून का स्वरूप और अधिक जटिल होता जाता है। साधारण मानसिक स्तर के सदस्य उसका सही रूप में सर्वेक्षण नहीं कर पाते और न ही उनकी उनमें रचि रहती

है। इससे अतिरिक्त प्रत्येक वष मसद को मसदा की मध्या म विधेयक पारित करने पड़ते हैं। मसद ने पास समय का अभाव रहना है, विराम होकर उस अपनी शक्तियाँ का एक बहुत बड़ा भाग मंत्रिमण्डल को समर्पित करना पड़ता है। राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य से हटकर लोभित का बन गया है। अतः राज्य लोभित व सम्म में अपनी भूमिका का निर्वाह उस समय तक पूरी तरह से नहीं कर सकता जब तक कि वायपालिका को काय सम्पादन की ओर अधिव शक्तियाँ से सम्मानित न किया जाय। फलतः विधेयक स्परमात्मक रूप में मसद द्वारा स्वीकार किया जात है और उनसे सम्बन्ध में व्यापक बातों की पूर्ति मंत्रिमण्डल द्वारा की जाती है। इस प्रकार न केवल प्रशासन पर बरन बानूनी सेना में मंत्रिमण्डल का प्रभुत्व स्थापित होना चला जाता है।

(7) ससदीय जीवन की स्थिति (Conditions of Parliamentary Life)—ससदीय जीवन की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की हैं कि लोक सभा मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण स्थापित करने में अपने को सफल नहीं पाती। जब लोक सभा का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय सदस्यों को यह पता नहीं चलता कि उनके समोजक अर्थात् मंत्रिमण्डल के सदस्य क्या करत हैं तथा किससे बातचीत करते हैं। सिडनी लो (Sydney Low) के अनुसार लोक सदन के अधिकांश सदस्य तो मौज उड़ान में व्यस्त रहते हैं और उन सदस्यों की संख्या बहुत कम है जो सदन की कायवाही को गम्भीरता के साथ ग्रहण करते हैं। विवश होकर लोक सभा को मंत्रिमण्डल के आश्रित रहना ही पड़ता है। लोक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत होती है। वे सब प्रभावशाली रूप में काय नहीं कर सकते। इसके विपरीत, मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या कम होती है जो एक संगठित इकाई के रूप में अपने को प्रभावशाली बनाने में सफल हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि मंत्रिमण्डल केवल समयन के लिए अंतिम रूप में प्रस्तावा एवं विधेयका का प्रस्तुत करता है।

(8) आपात काल (Emergency Period)—प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में राष्ट्रीय आपत्तियाँ का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपाति काल में स्वाभाविक रूप से मंत्रिमण्डल की शक्तियों का विकास हो जाता है। मंत्रिमण्डल का नियन्त्रण बँठोर होने लगता है। सरकार के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। यह कहना सही है कि 'कोई भी सरकार अधिनायकत्व के बिना जीवित नहीं रह सकती जबकि राष्ट्र का जीवन खतर में हो।' (No form of government can survive that excludes dictatorship when the life of the nation is at stake) प्रथम विश्व युद्ध के समय लायड जॉज तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के समय सर चर्चिल लगभग अधिनायक हो बन गये थे।

(9) लॉर्ड सभा की अप्रभावशालीनता (Ineffectiveness of House of Lords)—मंत्रिमण्डल के अधिनायकत्व का एक कारण यह भी जान पड़ता है कि 1919 तथा 1949 के ससदीय विधेयका द्वारा उसकी शक्तियाँ नहीं के बराबर कर दी गयी हैं। अब मंत्रिमण्डल का मूल उत्तरदायित्व केवल लोक सभा के प्रति रह गया है जिससे ऊपर उसका स्वाभाविक रूप से नियन्त्रण बना रहता है। अब विधेयका

को रोकने की शक्ति लॉर्ड सभा में नहीं रही। लॉर्ड सभा की इस प्रभावहीनता का लाभ मन्त्रिमण्डल उठा लेता है।

(10) **संसदीय कार्यविधि (Parliamentary Procedure)**—मन्त्रिमण्डल के अधिनायकत्व का एक कारण संसद की कार्यविधि भी है। मदन के नियमों के कारण संसद के हाथ बँधे रहते हैं। सामान्य समापन (Simple closure), मुखबंद (Gullotine) तथा कंगारू समापन (Kangaroo closure) आदि के द्वारा मन्त्रिमण्डल संसद में वादविवादों का समाप्त करा सकता है अथवा उन्हें सीमित करा सकता है। इस के सदस्यों पर सचेतकों द्वारा पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है। इन संसदीय विधियों से मन्त्रिमण्डल संसद की शक्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो जाता है।

मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व की समीक्षा (Dictatorship of the cabinet evaluated)

यह सत्य है कि मन्त्रिमण्डल का स्वरूप एक अधिनायक का स्वरूप बन गया है। किन्तु हम इसे स्वेच्छाचारी नहीं कह सकते। मन्त्रिमण्डल अपनी शक्तियों का मनमाने रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। उसे भी कई प्रकार की मर्यादाओं एवं नियन्त्रणों का सामना करना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में एक ओर जहाँ उसके अधिनायकत्व की चर्चा करते हैं तो दूसरी ओर हमारा ध्यान बरबस उन मर्यादाओं एवं नियन्त्रणों की ओर भी आकर्षित होना अस्वाभाविक नहीं है जो उसके अधिनायकी के उद्भाव को नियन्त्रित किये रहते हैं।

प्रथमतः संसद की परम्पराएँ मन्त्रिमण्डल की शक्ति को नियन्त्रित रखती हैं। इसमें दो बातें नहीं कि शासन की कार्यविधि एवं उसके स्वरूप का निश्चय मन्त्रिमण्डल के अनुदेशों पर अवलम्बित रहता है किन्तु लाक मदन की परम्पराएँ उसे अपने बाहुपाश में जकड़े रहती हैं। लोक संसद के अध्यक्ष की स्थिति मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व से अप्रभावित रहती है। वह विधि निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करा सकता। संसदीय प्रथाएँ वस्तुतः ऐसे बहुत से अवसर प्रदान करती हैं जिनका विरोधी दल लाभ उठाकर शासकीय दल की कटु आलोचना करता रहता है।

दूसरी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल को प्रत्येक कदम पर अपने समर्थकों की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे दलीय नियन्त्रण कितना ही कठोर क्या न हो गया हो किन्तु मन्त्रिमण्डल जनभावना की उपेक्षा का साहस नहीं कर सकता। निर्वाचन की पेशाचिक आकृति सदैव सम्मुख बनी रहती है। जब दल के ही सदस्यों के व्यक्तिगत हित टकराते हैं तो मन्त्रिमण्डल की नींव हिलने लगती है। 1931 में प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वायत्तों के लेकर हैडरसन ने अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की तथा मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। 1935 में विदेश मंत्री सर सम्युअल होर को संधि की गुप्तता प्रकट होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। संसद ने उस त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था। मन्त्रिमण्डल को जागत की प्रवाह दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। शासकीय दल को सदैव यह ध्यान रखना पड़ता है कि जनता के समक्ष वे किस प्रकार अपना हिसाब चुकाने में सफल हो सकेंगे। 1904 में अशांति उत्तेजक विधेयक (Incite

ment to Disaffection Bill) में विशाल बहुमत के विपरीत भी शासकीय दल के जनमत को ग्रस्त रखने की दृष्टि से परिवर्तन करना पड़ा। मंत्रिमण्डल का अधिनायकत्व अविश्वास के डर तथा निर्वाचन की शकाबा से सीमित रहता है। इन भया से मंत्रिमण्डल अपने को मर्यादा में जकड़ कर रखना पसंद करता है। फाइनेर (Finer) के शब्दों में, “यह चुस्त, शक्तिशाली, विचारशील एवं उत्तरदायी नेतृत्व का जन्मदाता है।” इन समस्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रिमण्डल का स्वरूप चाहे कितना अधिनायकवादी क्यों न हो, किंतु वह स्वेच्छाचारी नहीं है।

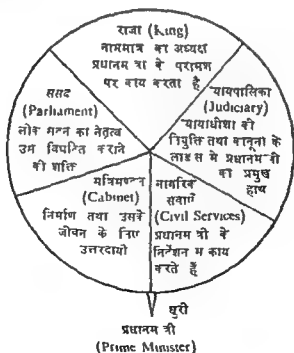
प्रधानमन्त्री (Prime Minister)

ग्लेडस्टन ने ठीक ही कहा था कि “कहीं पर भी इतने छोट पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है। यह वस्तुतः आश्चर्य की बात है कि 1937 से पूर्व बधानिक रूप में इतने महत्वपूर्ण पद का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ। आज भी परम्पराओं से ग्रस्त होकर इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कोप के प्रथम लॉर्ड (First Lord of the Treasury) के रूप में वेतन प्राप्त करता है। इंग्लैण्ड में अल्प राजनीतिक संस्थाओं की भांति यह पद भी निरुद्धि की उत्पत्ति है। राबर्ट वालपोल को इंग्लैण्ड का प्रथम प्रधानमन्त्री होने का श्रेय दिया जा सकता है। रॉबर्ट पील ने इस पद का निर्माण किया तथा पिछड़े जैसे प्रधानमन्त्रियों से उस पद को सम्मान दिलाया। ग्लेडस्टन, डिजरेली तथा पामस्टन जैसे प्रतिभासम्पन्न प्रधानमन्त्रियों की प्रबुद्धता का लाभ इस पद को प्राप्त हुआ। 1906 में सम्मानित नागरिकों की सूची में आकर बिशप के पश्चात् उसे चौथा स्थान प्राप्त था। अतः यह पद भी अल्प धिक ऐतिहासिक महत्व का है।

सैद्धांतिक रूप से वह किसी भी बधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, किंतु व्यावहारिक रूप में वह समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। लॉर्ड मोरले (Lord Morley) का यह कहना सरल नहीं है कि प्रधानमन्त्री बराबर के व्यक्तित्व में प्रथम है (Primus Inter Pares)। किंतु वह इससे अधिक है, अर्थात् चमकते हुए सितारों के मध्य चन्द्रमा है (Interstellas Lunas Minosos)। सम्राट तो औपचारिक रूप में एक राष्ट्राध्यक्ष है किन्तु व्यवहार में उसकी शक्तियाँ का प्रयोग प्रधानमन्त्री ही करता है। आपातकाल में तो उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वह विश्व के किसी भी अधिनायक से कम नहीं पड़ता। कार्टर (G M Carter) का यह कथन सत्य है कि “प्रधानमन्त्री संसार के अधिकतम निर्वाचित पदाधिकारियों में से एक है।” जेनिंग्स (Jennings) के अनुसार प्रधानमन्त्री “संविधान का मुख्य प्रस्तर” (Keystone of the Cabinet) है। लास्की ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक में प्रधान मन्त्री पद की सराहना करते हुए लिखा है कि “वह प्रधानमन्त्री के निर्माण का केन्द्र, उसके जीवन का केन्द्र तथा उसकी मृत्यु का आधार है।” (He is central to its formation, central to its life and central to its death) ग्रीव्स (Greaves) के शब्दों में ‘सरकार देश की स्वामी है और प्रधानमन्त्री सरकार का स्वामी है।’ (The Government is the master of the country and the Prime minister is the master of the Government)

प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में यह कहना सही है कि ममदीय समयन के विश्वास के आधार पर वह सब कुछ कर सकता है जो जर्मनी का शासक तथा अमेरिका का राष्ट्रपति करने में समर्थ नहीं है। राष्ट्र की समस्त प्रशासकीय शक्तियाँ प्रधानमंत्री में ही निहित हैं। इसी कारण से उसे शासन प्रणाली का केन्द्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री वास्तव में सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, आम चुनाव वस्तुतः प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन है। 'How Britain is Governed' में रमजे म्योर ने कहा है कि "मंत्रिमण्डल राज्य रूपी जलयान का चालक यंत्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है।" (The Cabinet is the steering wheel of the ship of the state and the Prime Minister is the steersman) किंतु वह स्वेच्छाचारी तथा निष्कुश नहीं है। वह अपनी सीमाओं में ही सम्पूर्ण है। प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार नहीं करता। विरोध करने वाले मंत्री का अपन राजनीतिक चरित्र से खलना पड़ता है। किंतु प्रधानमंत्री की स्थिति का रहस्य दल प्रणाली है। यदि दल उसका साथ छोड़ देता है तो उसके भाग्य का वही परिणाम होता है जो रमजे मक्डोनेल्ड का हुआ। व्यवहार में प्रधानमंत्री ही मुख्य कामपालिका है। किंतु पद का महत्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर अवलम्बित है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति विरोध होते हुए भी पद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में सफल हो सकता है।

प्रधानमंत्री का स्थान तथा उसका महत्व निम्न रेखाचित्र की सहायता से समझा जा सकता है



प्रधानमन्त्री की नियुक्ति (Choice of the Prime Minister)

प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राजा द्वारा होती है। अभिसमय के अनुसार राजा बहुमत दल का नेता का यह पद ग्रहण करने को आमन्त्रित करता है। आम निर्वाचनों के उपरांत लोक सभा (House of Commons) में प्रत्येक सदन की दलगत स्थिति स्पष्ट हो जाती है। द्विदलीय प्रणाली होने के कारण प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस सम्बन्ध में यह बात स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि क्या राजा बहुमत दल के नेता को आमन्त्रित न करके अपनी इच्छा से अन्य किसी व्यक्ति को इस पद पर आसीन करा सकता है? साधारण स्थिति में यह सम्भव नहीं है। केवल असाधारण स्थिति में प्रधानमन्त्री अपनी इच्छा को सक्रिय रूप से सबूत दे सकता है। प्रथम स्थिति वह है जबकि किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। दूसरी स्थिति वह है जबकि बहुमत दल के पास कोई स्वीकृत नेता न हो। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि नवतन्त्र के लिए सघर्ष हो। कई बार ऐसी स्थिति में पहले ही प्रधानमन्त्री को दल का नेता मान लेने की परम्परा है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति केवल एक औपचारिकता मात्र है। राजा के हाथ परम्पराओं से जकड़े हुए हैं।

1880 में महारानी विक्टोरिया को अपनी इच्छा का विपरीत भी ग्लेडस्टन को प्रधानमन्त्री नियुक्त करना पड़ा। राजा अपनी इच्छा का प्रयोग उस स्थिति में भी कर सकता है जबकि सरकार का स्वरूप मिश्रित रखना आवश्यक हो गया हो और दलों में मतभेद का अभाव हो। 1931 में रजिने मकडोनेल्ड का प्रधानमन्त्री बनना इसी सत्य का सूचक भी है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह बात भी सत्य है कि 1902 के पश्चात कोई भी प्रधानमन्त्री लॉर्ड सभा का नहीं रहा। लार्ड हैलीफक्स ने प्रधानमन्त्री पद के लिए अपने का इसी कारण अनुपयोगी माना कि वह लॉर्ड सभा का सदस्य था। कोई भी पीयर यह पद नहीं धारण कर सकता। 1963 में जब डेविड ह्यूम इस पद के प्रत्याशी थे तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि वे उस समय तक इस पद पर आसीन नहीं रह सकेंगे जब तक कि वे पीयर की उपाधि धारण किये रहेंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी समस्त उपाधियाँ को त्याग दिया और उपनिर्वाचन लड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में राजा का महत्व है तो अवश्य, किन्तु बहुत ही कम। 1965 के पश्चात तो यह प्रथा भी बदल सी हो गयी है कि अनुदारवादी दल के नेता के सम्बन्ध में अवकाश प्राप्त करने वाले प्रधानमन्त्री से परामर्श किया जाय।

प्रधानमन्त्री पद के लिए कोई वधानिक अहता नहीं है किन्तु फिर भी व्यवहार में उसके लिए कुछ गुणों का होना वस्तुतः अपेक्षित है। लोक सभा के सदस्य की अनिवार्यता उनमें से एक है। मुनरा के शब्दों में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री प्रायः कुलीन, सुशिक्षित तथा धनवान होते हैं। वे छोटी आयु में ही राजनीति में प्रवेश करते हैं और उसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं। 'छोटा पिट' (Pitt, the Younger) केवल 25 वर्ष की अवस्था में प्रधानमन्त्री बन गया था। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमन्त्री में सिने अभिनेताओं के समान जनता को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष कौतुक होना

चाहिए। पाइयो वाले वाल्डविन तथा सिगार वाले चर्चिल की भाँति उसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने राजनीतिक मित्रों के प्रति निष्ठा बनाये रखने के अतिरिक्त उसे कुशल वक्ता तथा भाषणा का आविष्कारक होना चाहिए। उसे ध्वनिविस्तारक यंत्र (Television) के समझ बोलने की कला भी आनी चाहिए। लास्की (Lasky) के अनुसार सामान्यतः प्रधानमंत्री में कुछ गुण अवश्य होने चाहिए जिनके बिना वह लोकमत को प्रभावित नहीं कर सकता है—ये हैं विवेक, कौशल, शासन करने की क्षमता, विश्वसनीय एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की पहिचान। प्रधानमंत्री पद का सफर लम्बा तथा दुःगम है। चर्चिल 1940 में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग दस पदों पर कार्य कर चुके थे। इसी प्रकार एन्थोनी ईडन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग नौ पदों पर कार्य कर चुके थे।

प्रधानमन्त्री के कार्य

(Functions of the Prime Minister)

वास्तव में प्रधानमंत्री ही राष्ट्र का वास्तविक अध्यक्ष होता है। बिना उसकी पूर्व-अनुमति तथा जानकारी के अथर्व विभागों में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। शासकीय व्यवस्था का वही प्रमुख संचालक है। बिना संसद की अनुमति के भी वह साधिका रूप में किसी भी बात के होने अथवा न होने का आश्वासन दे सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाता है

(1) मंत्रिमण्डल का गठन (Formation of the Cabinet)—इस पद पर आसीन होने के पश्चात् प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमण्डल के गठन हेतु अपने साधियों की सूची तैयार करके राजा की स्वीकृति हेतु भेजना होता है। राजा की स्वीकृति तो वस्तुतः एवं औपचारिकता मात्र है। प्रधानमंत्री भी मंत्रिमण्डल का निर्माण में वास्तव में पूर्णरूपेण स्वतंत्र नहीं है। उसे भी बहुत सावधानता से अपने साधियों की सूची तैयार करनी पड़ती है। विश्वास तथा व्यक्तिगत गुणों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल के गठन में जिन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, वे ये हैं—दलीय एकता, सन्धानिक अभिसमय राजनीतिक स्थिति, दल में स्थान, शर्तें एवं भौगोलिक स्थिति, धर्म आदि। कभी-कभी प्रधानमंत्री को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को मुह मागे विभाग भी समर्पित करने पड़ते हैं। सीजमवश भी प्रधानमंत्री को राजा के परामर्श पर ध्यान देना पड़ता है। 1890 में सॉड सलिसबरी (Salisbury) ने कहा था कि मंत्रिमण्डल का निर्माण करते समय यह एक अजायबघर-सा जान पड़ता है। (It is like the zoo at the feeding time) कभी कभी परिस्थितियों से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अमुक व्यक्ति को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित करना पड़ता है। मंत्रिमण्डल के निर्माण में भविष्य का ध्यान रखकर ऐसे नवयुवकों को भी सम्मिलित किया जाता है जो प्रशिक्षित होकर अपने परिपक्व अनुभवों का लाभ समाज एवं शासन को प्रदान कर सकें।

(2) मंत्रिमण्डल के कार्यों का संचालन (Conduct of Cabinet affairs)—

(अ) विभागों का वितरण—मंत्रिमण्डल के संचालन में सर्वाधिक महत्व का विभागों का वितरण है। किस मंत्री को कौनसा विभाग दिया जाय इसका

प्रधानमंत्री ही करता है। वह विभागों के निश्चय में स्वेच्छाचारी रूप से व्यवहार कर सकता है। यदि चाहे तो किसी को भी निर्विभागीय मंत्री भी रख सकता है। मंत्रियों की संख्या भी वही निश्चित करता है। एमरी (Amery) के अनुसार "मंत्रिमण्डल के निर्माण में जितनी निरकुशता प्रधानमंत्री को प्राप्त है उतनी दुनिया के बहुत कम तानाशाहों को प्राप्त है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत नियंत्रण को ठुकरा देने के अर्थ है सक्रिय राजनीति से निष्क्रमण। फिर दोबारा उस सदस्य के नाम पर विचार नहीं होता। प्रधानमंत्री वाल्डविन के प्रस्ताव को सर राबर्ट हान ने ठुकरा दिया था किंतु बाद में फिर किसी पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ऐसे सदस्यों के नामों पर भी विचार कर सकता है जो लोक-सभा के सदस्य तक नहीं हैं। यदि वह उन्हें मंत्रिमण्डल के लिए उपयोगी समझता है तो उन्हें उसमें सम्मिलित कर लेता है। 1924 में रैम्जे मकडोनाल्ड ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को मंत्रिपद पर आमंत्रित कर लिया था जबकि वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं थे। इसी प्रकार 1903 में जार्ज बलफोर ने मिलनर को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित किया जबकि वे अफ्रीका में थे। इस सम्बन्ध में उसके ऊपर न तो सदन और न ही कार्यपालिका दबाव डालती है।

(ब) प्रमुख सघनकर्ता (Chief Coordinator)—प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के विचाराएँ एवं कार्यों के मध्य समन्वय उत्पन्न करता है। पारस्परिक मतभेदों को दूर करना प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत आवश्यक होता है अथवा मंत्रिमण्डल सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता। वह विभिन्न दृष्टिकोणों वाले व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधता है। मंत्रिमण्डल में सहयोग उत्पन्न करके मंत्रीपूरा वातावरण एवं सौहार्द की सृष्टि करता है। प्रधानमंत्री ही पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, विविध मन्त्रालयों की नीतियों में समन्वय उत्पन्न करता है तथा मंत्रियों के विचारों में एकरूपता लाने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक मंत्री किसी नूतन कार्य को करने से पूर्व प्रधानमंत्री को विश्वास में लेता है। मंत्रिमण्डल में वादविवाद होते हैं किन्तु एक बार नीति निश्चित हो जाने पर कोई सदस्य बाहर जाकर उसके विरुद्ध नहीं बोलता।

(स) मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता (Chairmanship of the Cabinet)—प्रधानमंत्री ही मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है। उसी की अनुमति से बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। कार्यविधि पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। मंत्रिमण्डल के नियम मतदान द्वारा होते हैं परन्तु प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण निर्णायक होता है। वही मंत्रिमण्डल का प्रमुख परामर्शदाता है। मंत्रिमण्डल की बैठकों के समय स्थान तथा उनकी तिथि का निश्चय भी प्रधानमंत्री करता है। सफटवालीन बैठकों को भी आमंत्रित करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है।

(द) सहारकर्ता (Destroyer)—एक बार जहाँ हम प्रधानमंत्री का मंत्रिमण्डल का जीवन तथा उसकी गति कहते हैं तो दूसरी ओर वह मंत्रिमण्डल को समाप्त करने का भी अधिकार रखता है। उसकी इच्छा के विपरीत कोई भी सदस्य मंत्रिमण्डल का सदस्य बना रहे यह असम्भव है। प्रधानमंत्री तथा अन्य किसी सदस्य में सघर्ष होन की स्थिति में सदस्य को ही त्यागपत्र देना होगा, न कि प्रधानमंत्री को। विरोध व्यक्त करने वाले अथवा नीतियों से असहमति रखने वाले सदस्यों

से वह त्यागपत्र की माँग कर सकता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मंत्री को निम्नतम कर सबे विन्तु वह अपने मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन करके इस प्रकार के सदस्यों का निष्कासित कर सकता है। मंत्रियों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वे लोकहित में ही मन्त्रिपद पर आसीन रह सकेंगे। 1917 में लॉर्ड माटेयू, 1935 में सर सैम्युअल होर, 1956 में एयनी ईडन तथा 1963 में प्रोफेसर्स को एक न एक कारण से त्यागपत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री ही मन्त्रिमण्डल का मुख्य नियन्त्रक है।

किन्तु उपयुक्त वर्णन से हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री अधिनायक है तथा उसके साथियों की स्थिति अनुचरो जसी है। यह सही नहीं है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की स्थिति अमरीका के राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों जसी नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति सब की असहमति होने पर भी अपने विचारों को सही मान सकता है। वे उसके अनुचर हैं। इंग्लैंड में मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रधानमंत्री के अनुचर न होकर बराबर के सहयोगी हैं और साधारण स्थिति में उनके द्वारा दिये गये परामर्शों की अवहेलना प्रधानमंत्री सरलता से नहीं कर पाता। यथाथ तो यह है कि वे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले उत्तरदायी शक्ति सम्पन्न नेता होते हैं। हरमैन फाइनर (H. Finer) का अभिमत है कि 'यह मानना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कोई सीजर नहीं है और न ही उसका कोई कार्य ऐसा है जिसे चुनौती न दी जा सके। उसके विचार भी अनुत्तरीय नहीं हैं। उसकी सत्ता का एकमात्र आधार है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसका प्रतिद्वंद्वी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है।'

(3) दल का नेतृत्व (Leadership of the Party)—प्रधानमंत्री केवल सदन का ही नेतृत्व नहीं करता बल्कि दल का भी वह अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के उपरान्त वह सावजनिक महत्व प्राप्त कर लेता है। समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा टेलीविजन द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके भविष्य के साथ साथ दल के भविष्य का भी निणय होता है। सत्य ही आम चुनाव प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। मतदाता अप्रत्यक्ष रूप से यह निणय कर देते हैं कि देश का भावी प्रधानमंत्री कौन हो। 1857 का सामान्य मतदान इस बात का निणयक था कि क्या पामस्टन को प्रधानमंत्री बनाया जाय? 1880 में सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं को यह निणय करना था कि क्या वे लॉर्ड बेक्सफोर्ड को प्रधानमंत्री चाहते हैं अथवा ग्लेडस्टन को? द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर अनुदार दल के नेता श्री चर्चिल के चित्र स्थान स्थान पर लगाये गये जिनके नीचे लिखा था कि युद्ध का अधूरा कार्य पूरा करने दो। चर्चिल ने व्यक्तिगत रूप से अपील प्रसारित की थी। चर्चिल ने अपना स्वयं पोषणा पत्र प्रकाशित कराया जो 'मैं' शब्द से प्रारम्भ होता है। 1966 में विल्सन तथा हीथ के मध्य इसी प्रकार का मुकाबला हुआ था। इन सब बातों से प्रधानमंत्री राष्ट्र का भी प्रतीक बन जाता है। यह सही है कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति 10, डाउनिंग स्ट्रीट को जानता है। अन्य मंत्रियों की गतिविधियाँ की वह चिन्ता नहीं करता। जेनिंग्स (Jennings)

अनुसार "आम चुनाव साधारणतया प्रधानमंत्री का ही होता है। मतदाता किसी दल अथवा नीति को मत न देकर प्रधानमंत्री को मत देते हैं।"

(4) लोक सभा का नेतृत्व (Leadership of the House of Commons)—वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री ही लोक सभा का नेता होता है, उसके सदृश मंत्रिमण्डल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अथ किसी व्यक्ति को नहीं होता। शासकीय नीतियों के सदन में यदि कोई अधिकृत रूप से कह सकता है तो वह केवल प्रधानमंत्री है। महत्वपूर्ण घोषणाओं का दायित्व प्रधानमंत्री पर होता है। मंत्रिमण्डल की नीतियों को सदन में सुरक्षण प्रमुख रूप में उसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। वह वस्तुतः विधान-मण्डल का प्रमुख होता है। विधि निर्माण में उसका प्रमुख हाथ रहता है। बजट उसी के निरीक्षण में तैयार किया जाता है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्ष को उसका सहयोग प्राप्त होना आवश्यक होता है। सदन का पथ प्रदर्शन उसी के द्वारा होता है। सचेतक की सहायता से वह अपने दल के सदस्यों में शक्ति, गति एवं परस्पर सहयोग बनाये रखता है। सदन के कार्यक्रम निश्चय में उसका प्रमुख हाथ होता है। अध्यक्ष अपनी स्थिति के लिए भी संवैधानिक रूप में प्रधानमंत्री की अनुकम्पा पर निर्भर करता है। लोक सभा के विघटन का परामर्श प्रधानमंत्री राजा को किसी समय भी दे सकता है और आज तक यह परामर्श कभी ठुकराया नहीं गया। विघटन करने की शक्ति बड़ी ही प्रभावशाली शक्ति है जिसके माध्यम से सदस्यों में अनुशासनहीनता नहीं आती। सम्राट ने इसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया है।

(5) सम्राट और मंत्रिमण्डल के बीच की कड़ी (Link between King and the Cabinet)—प्रधानमंत्री सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता होता है। किसी भी परिस्थिति में वह सबसे पहले प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। सम्राट के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निष्पत्ति प्रधानमंत्री ही करता है। यहां तक कि सम्राट के व्यक्तिगत मामलों पर प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप रहता है। प्रधानमंत्री की उपेक्षा कर अब कोई मंत्री सम्राट से साक्षात्कार नहीं कर सकता। मंत्रिमण्डल की समस्त बायबाही एवं उसकी गतिविधियों के विषय में सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री ही देता है। सम्राट की विदेश यात्रा का कार्यक्रम तब प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री बाउंडविन ने सम्राट एडवर्ड अष्टम को श्रीमती मिम्स से विवाह करने की अनुमति नहीं दी। मंत्रिमण्डल के नीति सम्बन्धी निष्पत्ति की एक लिपिवद्ध प्रति वह सम्राट को भेजता है। प्रधानमंत्री द्वारा दी गयी सूचना को दोहराना मंत्रिमण्डल के किसी अन्य सदस्य के लिए आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के ही कारण राजतंत्र का जनतंत्रीकरण हो चुका है। सम्राट के अधिकारों का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री ही करता है।

(6) शासन का प्रमुख (Chief Executive)—शासन का वास्तविक प्रमुख सम्राट न होकर प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है

(1) सरक्षण एवं उपाधियाँ—प्रत्येक वर्ष अनन्त प्रकार की उपाधियाँ सम्राट द्वारा कीर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं, किन्तु वास्तविकता

यह है कि उपाधियों का नियम प्रधानमंत्री ही करते हैं यद्यपि इसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं ।

(11) नियुक्तियाँ—बड़े-बड़े एवं प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सम्राट द्वारा की जाती हैं । चायाधीश, राजदूत, विभागीय प्रमुख, उपनिवेशों के गवर्नर तथा स्थायी आयोगों आदि के सदस्य भी प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं । विभागीय मंत्रियों की सलाह के बावजूद भी अंतिम नियम प्रधानमंत्री का ही हाता है । सेवाओं पर वित्त मंत्रालय का नियम होता है और वित्त मंत्रालय पर प्रधानमंत्री का । लाइ सभा के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर होती है ।

(7) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि (Attends International Conferences)—विदेश विभाग चाह प्रधानमंत्री के हाथ में हो अथवा न हो किंतु विदेश नीति पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियम होता है । हम उसे विदेश नीति का आविष्कारक कह सकते हैं । विदेश मंत्रालय पर उसका पूर्ण नियम रहता है । विदेश नीति सम्बंधी महत्वपूर्ण घोषणाएँ उसी के द्वारा होती हैं । इस दिशा में उसके नियम अंतिम कह जा सकते हैं । अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी कभी-कभी भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है । लायड जाज नवसाई की संधि अथवा पैरिस सम्मेलन में भाग लिया था । म्यूनिख सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने भाग लिया था । रोडेशिया समस्या के सम्बन्ध में विल्सन का व्यक्तिगत रूप में स्मिथ से साक्षात्कार करना पड़ा । राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री भाग लेता है । हम प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कह सकते हैं ।

(8) आपातकालीन अधिकार (Emergency Powers)—आपात काल में स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होती है और प्रजातन्त्र में उसका स्वरूप एक संवैधानिक तानाशाह का बन जाता है । युद्ध आदि की विधिवत् घोषणा करने से पूर्व कोई भी कार्यपालिका सम्बंधी सैन्य कदम उठाने के लिए वह स्वतन्त्र है, कभी-कभी तो मन्त्रिमण्डल से भी परामर्श करने का समय नहीं मिलता । चर्चिल की शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसी भी हिटलर अथवा मुसोलिनी से कम नहीं थी । युद्ध के समय प्रधानमंत्री ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस पर हर पहलू से विचार कर सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि युद्धोत्तर काल में भी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कम नहीं रहती ।

अतः प्रधानमंत्री पद का सर्वेक्षण करने के उपरान्त यही कहा जा सकता है कि यह पद प्रतिष्ठा तथा महत्त्व से परिपूर्ण है किंतु बहुत कुछ उसका महत्त्व उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है । वह इसे जो भी रूप देना चाहे, दे सकता है । सम्भवतः उसकी विशेष स्थिति के ही कारण लॉरेल ने उसे मन्त्रिमण्डल रूपी महाराज की आधारशिला कहा है (Keystone of the Cabinet Arch) । मरियट के शब्दों में “प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक शासक है” (The political ruler of England) । ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का मूल्यांकन करते हुए फाइनेर (Finer H) ने कहा है कि “वह जीन पर दृढ़ता से अवस्थित है लेकिन वह मँजा हुआ सवार है । वह सुन्कने वाले टट्टू के साथक है या फौजों तथा घुड़दौड़ के

घोड़ों के लायक है, यह उस पर निभर करता है।" (He is firmly in the saddle, but whether he is a good rider or a stumbler, more worthy of a back than a charger or race horse depends on him) लास्की (Lasky) के अनुसार प्रधानमंत्री की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से कम तथा अधिक है। पुन लास्की (Lasky) के ही शब्दों में 'संसार में शायद ही अय किसी के पद को इतने अधिकार हैं जितने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का प्राप्त है।' एमरी के शब्दों में, "प्रधानमंत्री कप्तान तथा कणधार दोनों ही है।" (Prime Minister is in fact both captain and one man at the helm)

Suggested Readings

Bagehot *The English Constitution*
 Jennings *Cabinet Govt*
 Keith *British Cabinet System*
 Muir, R. *How Britain is Governed*
 Amrey L S *Thoughts on the Constitution*
 Lasky *Parliamentary Govt in En land*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमण्डल के संगठन, कृत्य तथा स्थिति का वर्णन कीजिए।
 (Explain the structure role and functions of the Cabinet in the British Constitution)
- 2 'ब्रिटिश मंत्रिमण्डल राजनीतिक वस्तुस्थिति का मध्य प्रस्तर है।' ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के अधिकार तथा महत्व के प्रसंग में इस कथन की विवेचना करें।
 ('The British Cabinet is the keystone of the political arch' Examine this statement in the light of the powers and importance of the Cabinet in England)
- 3 "ब्रिटिश मंत्रिमण्डल वह धरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है।" इस कथन की समीक्षा करें।
 ('Cabinet in Great Britain is the pivot round which the whole political machinery revolves Examine')
- 4 ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की सर्वव्यापकता के कारण बताये। किम सीमा तक मंत्रिमण्डल ने संसद की शक्तियाँ हस्तगत कर लियी हैं?
 (Account for the omnipotence of the British Cabinet To what extent it has usurped the powers of the Parliament)
- 5 क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ब्रिटिश कार्यपालिका बहुत ही शक्तिशाली है और विधानपालिका दुबल?
 (Do you agree with the view that the Executive in England is too strong and the legislature too weak?)
- 6 'वर्तमान युग में लोकसभा मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमण्डल ही लोकसभा पर नियंत्रण रखता है। इस विषय की व्याख्या करें तथा कारण बताये।

("Today it is not the House of Commons which controls the Cabinet but the Cabinet which controls the House ' Explain and account for this development)

- 7 क्या ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व है ? अपने प्रश्न के उत्तर में तर्क दीजिए ।

(Is there Cabinet dictatorship in Britain ? Give reasons in support of your answer)

- 8 ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कृत्या और स्थिति का वर्णन कीजिए । क्या उसे 'समान व्यक्तियों में प्रथम' कहा जाना उचित है ?

(Describe the powers, functions, and position of British Prime Minister Is he first among the equals)

- 9 ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार और स्थिति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए ।

(Compare and contrast the position and powers of the British Prime Minister with those of the President of the U S A)

- 10 "लोकसभा मन्त्रिमण्डल के नेतृत्व और निर्देशन में कार्य करती है । इस कथन की विवेचना करें ।"

(The House of Commons acts in accordance with cabinet's direction and leadership Examine the truth or otherwise of this statement)

- 11 सम्राट, मन्त्रिमण्डल और लोकसभा के साथ प्रधानमंत्री के सम्बन्ध का निरूपण करें ।

(Explain the relation of the British Prime Minister to the Sovereign the Cabinet and the House of Commons)

- 12 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार एवं स्थिति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए ।

(Compare and contrast the position and powers of the President of the U S A with those of the Prime Minister)

- 13 जॉन मोर्ले के अनुसार, ' प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की केन्द्रीय शिला है ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए एवं ग्रेट ब्रिटेन के शासन में प्रधानमंत्री के महत्व का वर्णन कीजिए ।

(' The Prime Minister is the keystone of the cabinet arch ' (John Morley) Explain the statement and clearly show the importance of the Prime Minister's office in the government of great Britain ')

- 14 ब्रिटिश कैबिनेट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि किस प्रकार यह राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है ।"

(Describe the main features of the British Cabinet and show how it is the keystone of the political arch)

ब्रिटिश ससद—लॉर्ड्स सभा [House of the Lords]

'The only institution in the world which was kept efficient by the persistent absenteeism of the great majority of its members —Lord Samuel
'England can never be ruined except by a parliament which is omnipotent' —Burlingame

लॉर्ड सभा सम्राट का द्वितीय सदन है। यह एक ऐतिहासिक सदन है। एडवर्ड प्रथम के समय से लॉर्ड सभा का विकास हुआ। ब्रिटिश संविधान की अंग सस्याओं की भाँति ब्रिटिश लॉर्ड सभा का जन्म भी अवसर एवं बुद्धि का परिणाम है। यह भी एक स्वविकसित संस्था है। आदर्श ससद के तीन भाग थे—कुलीन वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग तथा साधारण सदस्य। ज्ञान ज्ञान पहले दोनों वर्ग आत्मसात हो गये और साधारण सदस्य जिनकी संख्या अधिक थी और जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते थे, एक पक्क सदन के रूप में संगठित हो गये और वह सदन लोक सदन कहलाने लगा। आनुवंशिक (Hereditary) सिद्धांत का विकास भी इसी प्रकार हुआ कि कुलीन वर्ग के सदस्यों की मृत्यु के उपरांत उन पदों की पूर्ति के लिए सम्राट ने उनके पुत्रों को आमंत्रित करना प्रारम्भ कर दिया था। इसमें सन्देह नहीं कि 1832 के सुधार बिल तक वस्तुतः लॉर्ड सभा एक उच्च सदन था और 1911 तक उसकी सत्ता वास्तविक रूप धारण किये रही किन्तु इस तिथि के उपरांत लॉर्ड सभा केवल द्वितीय सदन रह गया है वरन् वह द्वितीय श्रेणी का भी सदन बन गया है। आज लोकतन्त्रीय व्यवस्था में कोई उसे प्रतिष्ठित एवं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और उसके प्रति विरोध इस सीमा तक बढ़ गया है कि यह ध्वनि सुनाई देने लगी है कि या तो उसमें सुधार किया जाय अथवा उसे समाप्त किया जाय। वह असामयिक एवं अप्रजातन्त्रीय बन चुका है। किन्तु वह ऐतिहासिक सदन है, सबसे पुराना है। इसे इंग्लैण्ड की शासन व्यवस्था में एक राजनीतिक अपवाद कहा जाता है। अतीत के इस गौरव को लोग तोड़ना नहीं चाहते वरन् मोड़ना चाहते हैं। श्रमिक दल के नेता लॉर्ड एटली ने भी 1947 में इससे महत्व को स्वीकार किया था।

लॉर्ड सभा का संगठन

(Organization of the House of the Lords)

इसके सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। 1948 में इसके सदस्यों

की संख्या 844 थी जो 1952 में घटकर 842 रह गयी और 1966 में बढ़कर 1029 तक पहुँच गयी। इससे यह स्पष्ट है कि इस संसदस्यो की संख्या घटती तथा बढ़ती रहती है। इसके सदस्यों को सात वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(1) राजवंश के सदस्य (Peers of Royal Blood)—यह लॉर्ड सभा का सबसे अधिक उदासीन वर्ग है। राजवंश से सम्बंधित पीयरो की संख्या कभी एक समय पर तीन अथवा चार से अधिक नहीं होती। यह लॉर्ड सभा के अधिवेशन में प्रायः भाग भी नहीं लेते हैं।

(2) वंशानुगत पीयर (Hereditary Peers)—ये लॉर्ड सभा में बहुसंख्यक वर्ग की सृष्टि करते हैं। इनकी संख्या 1966 में 853 थी। इस प्रकार के सदस्यों की पाँच श्रेणियाँ हैं—बैरन, ड्यूक, बिसकाउण्ट, मार्क्विस् तथा अर। इस व्यवस्था में एक पीयर के मर जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है और फलतः वह लॉर्ड सभा का भी सदस्य बन जाता है। अब इनकी नियुक्ति भी औपचारिक रूप में सम्राट द्वारा की जाती है। पहले स्त्रियों को लॉर्ड सभा की सदस्यता का अधिकार नहीं था किंतु अब यह अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया है।

(3) धार्मिक लॉर्ड्स (Lords Spiritual)—इन्हें पीयर नहीं कहा जाता बल्कि धर्मगुरु (Lords Spiritual) कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्यों की संख्या लगभग 26 होती है।

(4) स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर (Representative Peers of Scotland)—1707 के इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड अधिनियम के अंतर्गत स्कॉटलैंड को 16 पीयर भेजने का अधिकार दिया गया था। किंतु अब दिन प्रतिदिन उनके सदस्यों की संख्या भी काफी मात्रा में कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आ सकता है जबकि उसके सदस्यों की संख्या कम से कम हो जाय।

(5) आयरलैंड के प्रतिनिधि सदस्य (Representative Peers from Ireland)—1801 के अधिनियम के अंतर्गत आयरलैंड को 28 प्रतिनिधि पीयर भेजने का अधिकार दिया गया था। किंतु आयरलैंड की स्वतंत्रता के उपरान्त उनका मनोनयन लगभग बंद हो गया है। 1958 में केवल उसकी संख्या एक थी। 1961 में वह संख्या भी समाप्त हो गयी।

(6) आजीवन पीयर (Life Peers)—इनकी संख्या निश्चित नहीं है। 1958 में Life Peerage Act स्वीकार किया गया। इस अधिनियम का मूल लक्ष्य था इंग्लैंड के प्रतिष्ठित नेताओं की लॉर्ड सभा में नियुक्ति। आजीवन पीयरों को कोई वेतन नहीं मिलता। केवल उन्हें मान्यता मिलती है।

(7) विधि के लॉर्ड (Lords of Law)—इनकी संख्या लगभग 9 है। इनकी नियुक्ति जीवन भर के लिए की जाती है। 1876 के अधिनियम के अनुसार इनकी नियुक्ति विधि विशेषज्ञों तथा न्यायवेत्ताओं में से की जाती है। इन्हीं के द्वारा इंग्लैंड की सर्वोच्च न्यायशक्ति की रचना होती है।

अतः लॉर्ड सभा पंतुकाधिकार, नियुक्ति तथा निर्वाचन का अद्भुत समन्वय है। लॉर्ड सभा का कोई भी सदस्य नियुक्त होने की तिथि से 12 महीने के भीतर उसका परित्याग कर सकता है। जो पीयर बयस्क नहीं है वह 28 वर्ष की अवस्था

प्राप्त करने की तिथि में 12 माह के अन्दर सदस्यता का छोड़ सकता है। जो व्यक्ति पीयरजेज का परित्याग करते हैं उन्हें यह स्तर उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। जो रिजर्व्स इस अधिकार को पेंशनाधिकार पर प्राप्त करती हैं उन्हें भी लॉर्ड सभा की बैठका में भाग लेने का अधिकार होता है।

सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of the Members)

- (1) विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता।
- (2) संसदीय अधिवेशन के मध्य उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- (3) जनहित की बातें करने के लिए वे सीधे ही मंचाट के पास पहुँच सकते हैं।
- (4) लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह माँग करने का अधिकार है कि उनके मुकदमे लॉर्ड सभा के द्वारा ही सुने जायें।

निर्योग्यताएँ (Disabilities)

- (1) लॉर्ड सभा के सदस्य लोक सभा के निर्वाचनों में लड़े नहीं हो सकते।
- (2) उन्हें संसदीय निर्वाचनों में मतदाधिकार प्राप्त नहीं है।
- (3) वशानुगत लॉर्ड भी अपनी उपाधियाँ का परित्याग कर सकते हैं।
- (4) उन्हें लोक सभा के निर्वाचनों में लड़े होने का अधिकार है।

प्रक्रिया (Procedure)

संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन पृथक-पृथक स्थानों पर होते हैं। दोनों ही सदनों में सत्रों का प्रारम्भ एव अन्तमान एक साथ होता है। वे सप्ताह में चार दिन काम करते हैं, प्रत्येक दिन लगभग दो घण्टे। लॉर्ड सभा में उपस्थिति सदा क्षीण रहती है। विवादग्रस्त विधेयों को तब पर सदस्यों की उपस्थिति प्रायः 80 से 100 के मध्य रहती है। इसी कारण गणपूर्ति की संख्या 3 रखी गयी है। विधि पारित करने के लिए केवल 30 सदस्यों की संख्या रखी गयी है। भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। समिति व्यवस्था जटिल नहीं है, पूर्ण सदन के अतिरिक्त स्थायी एवं प्रवर समितियाँ भी होती हैं। वादविवाद का स्तर लोकसभा की अपेक्षा ऊँचा रहता है।

लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चान्सेलर (Lord Chancellor) होता है जो मंत्रिमण्डल का भी सदस्य होता है। वह विशिष्ट प्रकार का आसन जिस पर वह बैठता है, 'Woolsack' कहलाता है। लोकसभा के स्पीकर की तुलना में उसकी शक्तियाँ नगण्य हैं। यह सदन में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। वह वादविवादों को समयित भी करता है। लोक सदन की प्रथा के विपरीत वह वादविवाद में भी भाग ले सकता है किन्तु उस समय उसे अपना विशिष्ट आसन छोड़ना पड़ता है। लॉर्ड चान्सेलर के पास निर्णायक मत की भी व्यवस्था है।

लॉर्ड सभा के कार्य

(Functions of the House of the Lords)

(1) विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)—1911 से पूर्व लॉर्ड सभा की विधायी शक्तियाँ उतनी ही थी जितनी कि लोक सदन की, किन्तु इस तिथि के पश्चात् उसकी शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में नहीं के बराबर रह गयी हैं। वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, अधिक से अधिक उसे पारित करने में कुछ देर

अवश्य लगा सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किंतु अब लॉर्ड सभा की अनुमति के बिना भा उहे सम्राट की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए विधेयकों की स्वीकृति को टाल सकती है। 1949 के विधेयक के अनुसार यह अवधि घटकर केवल 1 वर्ष रह गयी है। अतः लॉर्ड सभा स्थायी रूप से किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष से अधिक नहीं रोक सकती। उसकी स्वीकृति के बिना भी वह विधि बन जायगा।

घन विधेयक अब केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। जिस समय तक लोक सभा की स्वीकृति उपलब्ध न हो, घन विधेयकों में लॉर्ड सभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि 1 माह की अवधि में घन विधेयक लॉर्ड सभा द्वारा स्वीकार नहीं कर लिये जाते तो बिना उसकी अनुमति के भी उह सम्राट के हस्ताक्षरों के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 1911 के विधेयक के अनुसार लोक सभा का अध्यक्ष यह नियम करता है कि अमुक विधेयक घन विधेयक है अथवा नहीं अर्थात् वित्तीय विधेयकों की दृष्टि से भी उसके अधिकार न के बराबर हैं।

(2) कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers)—लॉर्ड सभा के पास अब कोई कार्यकारी शक्ति 1911 के पश्चात् अवशिष्ट नहीं रह गयी है। इस दृष्टि से वह पूर्ण रूप में महत्वहीन बन चुका है। मंत्रिमण्डल को वह अपदस्थ नहीं कर सकती, अधिक से अधिक उसे प्रभावित कर सकती है। प्रश्न पूछकर तथा नीतिशास्त्र का स्पष्टीकरण करवाकर कार्यकारिणी पर वह अपना प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई अन्य शक्ति प्राप्त नहीं है।

(3) न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)—वस्तुतः 1936 के पश्चात् लॉर्ड सभा की न्यायिक शक्तियाँ में भारी कमी हुई है। उसका प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार लगभग नहीं के बराबर रह गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी लॉर्ड सभा के ममस्त सदस्य भाग नहीं लेते। उसमें कानून के लॉर्ड ही भाग लेते हैं जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं। कानून के ये लॉर्ड ही इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय की रचना करते हैं। लॉर्ड सभा को पहले अपने सदस्यों द्वारा किये गये अपराधों को सुनने तथा न्याय करने का अधिकार था किंतु अब उसकी यह शक्ति लगभग नहीं के बराबर रह गयी है।

लॉर्ड सभा के विपक्ष में एक

(Case against the House of Lords)

लॉर्ड सभा की शक्तियों का अवरोध करने से यह स्पष्ट है कि यह शक्तिहीन है और उत्तरोत्तर उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, यहाँ तक कि उसके बनावे रखने में भी लोगो को संदेह होने लगा है। जे आर क्लाइव्स के अनुसार 'लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता और यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर देना चाहिए।' (The House of Lords is an institution which cannot be reformed if it cannot be mended, it must be ended) लॉर्ड सभा का लोकतंत्र में अस्तित्व एक असंगति है। प्रो० ए सी कपूर का अभिमत है कि विश्व का शायद ही अन्य कोई सदन ऐसा

जिसकी इतनी आलोचना की जाती हो। इस प्रतिप्रियावादी मदन को समाप्त करने के लिए समय समय पर प्रयत्न होते रहे हैं किन्तु अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। कुछ आलोचक तो लॉर्ड सभा को बिलकुल ही समाप्त करने के पक्ष में हैं। लाउ सभा के विरुद्ध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं

(1) प्रतिप्रियावादी सस्था (Reactionary Institution)—लॉर्ड सभा के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह एक प्रतिप्रियावादी मन्त्र है। वह एक दल के अधीन सदन बनकर रह गया है उसे किसी भी दृष्टि से निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। प्राचीन बातों का पक्ष ग्रहण करना उसका एकमात्र उद्देश्य है। जब कभी भी अनुदारवादी दल का शासन होता है तो यह इज्जत के तरीके से कार्य करता है और जब श्रमिक दल की सरकार होती है तो यह ब्रेक का काम करता है। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लॉर्ड एटली ने ऐसे ही विचार प्रकट किये थे। लॉर्ड बतफोर (Balfour) ने भी लॉर्ड सभा के प्रयत्न का मूल उद्देश्य सदा कंजरवेटिव दल को सत्ताधारी रखना माना है। अनुमान है कि वर्तमान सदन में अनुदारवादी दल के सदस्यों की संख्या 600 से अधिक ही होगी। जेनिंग्स (Jennings) के अनुसार गत पचास वर्षों में अनुदारवादी दल का कोई भी विधेयक संशोधित नहीं किया गया यद्यपि ब्रिटेन में सुदृढ़ विरोधी दल का अभाव नहीं है। जी एम कार्टर ने भी ऐसे विचार प्रकट करते हुए कहा है कि "कॉमंस सभा में बहुमत में कोई भी हो, अनुदार दल का लॉर्ड सभा में स्पष्ट बहुमत रहता है।" (No matter which party is in majority in the House of the Commons the conservative party has an unchallenged mastery of the Upper House) लास्की (Lasky) के शब्दों में, 'किसी श्रमिक सरकार के विरुद्ध भारात करने की उसमें अब भी काफी सामर्थ्य है।' इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड सभा अनुदारवादी दल के हाथों में बिल्कुल चुकी है।

(2) अप्रजातान्त्रिक (Undemocratic)—लाउ सभा के विरुद्ध एक तर्क यह किया जाता है कि वह प्रजातन्त्र के लिए एक बलक से कम नहीं है। यह निर्वाचित सदन नहीं है। इसके संगठन का आधार उत्तराधिकार है। इसकी सदस्यता का आधार योग्यता नहीं है। वह इस दृष्टि से भी प्रजातन्त्र विरोधी है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उस पर 'व्यापारिक वर्ग का ही एकमात्र आधिपत्य बना रहता है। सिडनी तथा बर्ट्रिक वेब ने कहा है कि लॉर्ड सभा का निर्माण अपनी रचना से ही दूषित है। आगस्टाइन बिर्रेल (Birrell, A.) के शब्दों में "लॉर्ड सभा अपने अतिरिक्त किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। (House of Lords represents nobody, but itself) विज्ञान, कला तथा साहित्य आदि को इसमें बहुत कम स्थान मिलता है। इस प्रकार के सदन को लोकतन्त्र में बनाये रखना अजीब-सी बात है।

(3) धनिकों तथा निहित स्वार्थों का गढ़ (It is the Fortress of Wealth and Vested Interests)—रम्से म्योर (Ramsay Muir) ने लॉर्ड सभा की आलोचना करते हुए इसे धनिकों तथा निहित स्वार्थों का एकमात्र गढ़ कहा है (Common Fortress of Wealth)। राष्ट्रीय स्तर के समस्त उद्योगों के प्रबंध निदेशकों को इसमें स्थान दिया जाता है। इसमें बड़े लोगों का ही बोलबाला है।

सम्भवतः जैसा कार्टर (G M Carter) ने कहा है, 'लॉर्ड सभा धन एवं विशेषाधिकार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती अपितु वास्तव में वह तो स्वयं धन एवं विशेष अधिकारों का दुगुण है।' (The House of Lords is not merely a representative of wealth and privileges it is itself wealth and privilege.)

(4) क्षीण उपस्थिति (Thin Attendance)—सदन के सदस्यों में इसके कार्यों के प्रति उदासीनता बनी रहती है। यह इस तथ्य से प्रमाणित हो सकता है कि इसके अधिवेशनों में मामूली 30 अथवा 40 से अधिक सदस्य उपस्थित नहीं होते। जब कभी वाद विवाद सम्बन्धी कोई गम्भीर विषय प्रस्तुत होता है तो सदस्य संख्या अवश्य ही साधारणतः 200 से लेकर 300 तक रहती है। इसी उदासीनता के कारण इसकी गणपूर्ति की संख्या केवल 3 रही गई है। लाउड सभा के अधिकांश सदस्य तो ऐसे हैं जिन्हें वहाँ के कमचारी पहचानते भी नहीं हैं। 1893 में लाउड सभा के एक सदस्य से यह पूछे जाने पर कि क्या वास्तव में वह लाउड सभा का सदस्य है, उसने जा उत्तर दिया वह कम हास्यास्पद नहीं है—“क्या तुम सोचते हो कि यदि मैं पीयर न होता तो मैं इस वाहिदात जगह आता?” लॉर्ड सभा के सदस्य भारी संख्या में केवल तभी उपस्थित होते हैं जब उन्हें किसी प्रगतिशील विधेयक का विरोध करना होता है। एक बार एक व्यक्ति ने लॉर्ड सभा के बोखलेपन पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा था कि “मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं हूँ।” लॉर्ड सैम्युअल (Lord Samuel) के शब्दों में, ‘वह एक ऐसा सदन है जिसकी कार्यक्षमता इसके सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थिर रहती है।’ इससे स्पष्ट है कि लॉर्ड सभा के सदस्य पूर्णतः सदन की कार्यवाही के प्रति उदासीन बने रहते हैं।

(5) विधायी तथा कार्यकारी शक्तियाँ व्यर्थ (Legislative and Executive Powers are useless)—इन दोनों दृष्टियों से भी यदि हम विचार करें तो हमें लाउड सभा का अस्तित्व व्यर्थ एवं अनुपयोगी प्रतीत होता है, विधायी क्षेत्र में भी उसे कोई वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयकों के तो अस्वीकार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, साधारण श्रेणी के विधेयकों को वह केवल कुछ समय के लिए रोक अवश्य सकती है, इससे अतिरिक्त कामपालिका पर इसका कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है। लॉर्ड सभा को वस्तुतः मंत्रियों से प्रश्न पूछने तथा नीतियों को स्पष्ट कराने का अधिकार है किन्तु उसके अविश्वास अथवा स्वीकृति एवं अस्वीकृति का उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लॉर्ड सभा में प्रतिक्रियावाद का वैषम्य इस मात्रा में भरा हुआ है कि उससे प्रगतिशीलता भी अवरुद्ध जान पड़ती है। लास्की (Lasky) ने इसे अरक्षणीय असंगति (Indefensible Anachronism) कहकर पुकारा है।

(6) समाजवाद विरोधी संस्था (Anti Progressive)—लाउड सभा प्रगति के नाम पर असम्य कलक है। यह घूसखोरो, कुलीनों, जमाखोरो तथा मुनाफाखोरो का अड्डा है। यह प्रगतिशील विधेयकों का कभी भी स्वागत नहीं करती। इसका सम्पूर्ण इतिहास ही प्रगति विरोधी है। यह सामन्तो तथा पृथ्वीपतियों की संस्था है। इतना भयंकर प्रतिक्रियावादी सदन लोकतंत्र में आज भी बना हुआ है यह एक आश्चर्य की बात ही कही जायेगी। चम्बरलेन के शब्दों में, ‘लॉर्ड सभा ने जनता को उस समय तक रियायतें नहीं मिलने दी जब तक कि उसका सौंदर्य नष्ट नहीं हो गया। अधिकारों को

तो उस समय तक रोके रखा जब तक कि वह उलाहूत रूप में उससे छीने नहीं गये।" इसका अस्तित्व ही प्रतिप्रियावादी तत्वा पर टिका हुआ है। सारे प्रयत्नों के बावजूद अपेक्षित सुधार सम्भव नहीं हो सके हैं। 1917 के मसदीय विधेयक ने तो इसे परकेव कर महत्वहीन बना दिया है। जनता की भावनाओं को सम्मान देना तथा सम्मान करने में वह अपने को असफल पाती है। जेनिंग्स (Jennings) का यह कथन सही है कि वे जनता के दृष्टिकोण से सम्बद्ध नहीं होते। (They have not to trim their sails to the breeze of public opinion) ऐसे प्रतिक्रियावादी एवं महत्वहीन सदन को रखने से कोई लाभ नहीं है।

लॉर्ड सभा की उपयोगिता (Utility of the House of the Lords)

उपयुक्त विवरण से हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि लॉर्ड सभा का कोई मूल्य नहीं है और इंग्लैण्ड के राजनीतिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। लॉर्ड सभा में सशोधन करने के प्रयत्नों की तथा उसके उद्मूलन की असफलता इस सत्य का द्योतक है कि लॉर्ड सभा का अपना महत्व है और इसी कारण उसे वहाँ के राजनीतिक जीवन में से निष्कासित नहीं किया जा सका है। बेजहॉट का यह कहना सही है कि जिस समय तक हमारे पास आदर्श लोक सदन की व्यवस्था नहीं है जो सब दृष्टि से सम्पूर्ण हो उस समय तक द्वितीय सदन की आवश्यकता होगी और उस समय तक उसके उद्मूलन के औचित्य का कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति समझन नहीं कर सकता। बेजहॉट के ही शब्दों में 'क्याकि मनुष्यों की प्रकृति ऐसी है कि महान् गुणों का एक ही सदन में होना असम्भव है, अतः द्वितीय सदन की आवश्यकता है' उपयोगिता की दृष्टि से लॉर्ड सभा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(1) लोकतन्त्र की सुरक्षा (Safeguard of Democracy)—लॉर्ड सभा के पक्ष में यह सरलता से कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र को जीवित रखने तथा सशक्त रखने के लिए यह आवश्यक है। आलोचना लोकतन्त्र की सहचरी है। स्वतन्त्र विचार विनिमय एवं पर्यालोचन उसकी दो महत्वपूर्ण अहताएँ हैं। यह सभी सम्भव है जब उनकी व्यवस्था का माध्यम उपलब्ध हो। द्विसदनात्मक व्यवस्था अब लगभग लोकतन्त्र की आवश्यक परिस्थितियाँ में से एक है। जिन देशों ने उस व्यवस्था को त्यागा भी या उन्हें विवश हाकर इसे पुनः स्थापित करना पड़ा। ब्रिटेन जैसे देश के लिए तब बन्दुत यह और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि न तो वहाँ लिखित संविधान है और न रूस के संविधान की भाँति मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। वहाँ पर पुनरावलोकन की भी व्यवस्था नहीं है। इन परिस्थितियों में लॉर्ड सभा का रखना निस्सन्देह आवश्यक है। यदि लॉर्ड सभा को हटाया जाता है तो लोक सदन अधिक शक्तिशाली बनकर निरपेक्षा रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि लोक सभा अधिनायकत्व भी बन सकती है।

(2) विधि-निर्माण में सहायक (Helpful in Legislation)—लॉर्ड सभा को बनाये रखने के सन्दर्भ में एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत विधेयक (Private Bills) तथा अविवागात्मक विधेयकों को सबसे प्रथम लॉर्ड सभा में प्रस्तावित कर लोक सदन का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। इस बचे हुए समय का सदुप

योग करके लोक सभा लोकतन्त्र तथा राष्ट्र का और अधिक हित कर सकती है। इस समय लोक मदन में काम की ऐसी भीड़ रहती है कि विधेयको पर ठीक प्रकार से वाद-विवाद नहीं हो सकता। लोक सभा का कार्य बहुत ही जल्दबाजी में निपटाना पड़ता है। जनमत ठीक प्रकार से संगठित नहीं हो पाता। लोक सदन अपनी उपयोगिता तभी सिद्ध कर सकता है जबकि उस राजनीतिक प्रश्ना पर सोचने का तसल्ली से अवसर दिया जाय। लॉर्ड सभा को समाप्त करने से लोक सदन के कार्यों का बोझ और अधिक बढ़ जायगा और उसी अनुपात में उसकी असमर्थता एवं अकार्यकुशलता की अभिवृद्धि होती जायगी। मार्टिन लिण्डजे ने भी ऐसा ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस उन्मूलन से लोक सभा का कार्य दुगुना हो जायगा।

(3) योग्यता का आगार (Storehouse of Experience)—लॉर्ड सभा को बनाये रखने का एक कारण यह भी है कि उसके सन्स्य निर्वाचन द्वारा नहीं आते और मनोनयन में सबदा इस बात की गुंजाइश रहती है कि वयोवृद्ध समाजसेवी, वज्ञानिक, कुशल शिल्पी श्रेष्ठ कलाकारों एवं माहिर्यकारों की सेवाएँ राष्ट्रीय हित के सबद्धन के लिए अर्जित की जा सकें। तबे तपाय राजनीतिज्ञ जिनके कार्यों एवं विचारों को बड़े ही कौतूहलपूर्ण ढंग से हम सुनते अथवा देखते हैं, इस सदन में प्रवेश पाते हैं। बहुत समय तक लॉर्ड सभा न देश को डिजरायनी तथा पिट के स्तर के प्रधानमन्त्री देकर देश की अनुपम सेवा की है। लोक सभा तो लॉर्ड सभा की नसरी अथवा पोषणालय है। जीवन के यथाय तथा अनुभव से तपकर राजनीतिज्ञ लार्ड सभा में पहुँचते हैं। लॉर्ड सभा में बड़े बड़े उद्योगपति तथा व्यवसायी मिलते हैं जिनका विशिष्ट अनुभव राष्ट्र के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए फाइनर (H Finer) ने कहा है कि 'यह सावजनिक पर्यालोचन के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है। यह जनसेवक विशेषज्ञों का एक निकाय है जो पर्याप्त बुद्धि एवं ज्ञान से बोल सकते हैं।' (It remains one of the most distinguished forms of Public debate in the world for it has the right to discuss any phase of Legislation, policy of administration these constitute a body of public spirited experts and to talk with great intelligence and knowledge)

(4) लोक सदन की उत्तेजना पर रोक (Check on the hastiness of the House of the Commons)—ऑग तथा जिक (Ogg & Zink) के शब्दों में 'इंग्लैंड के इतिहास में किसी को भी यह बताने की आवश्यकता नहीं कि बहुत स अधिकतरों पर द्वितीय सदन ने राष्ट्र की इच्छा की व्याख्या प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक अच्छे प्रकार से की है और राजनीतिक स्थितियों को उससे अधिक अच्छी प्रकार से समझा है। कई बार इसा देश को जल्दबाजी तथा कम सोच विचार के कानूना से बचाया है।' लोक सदन में अनुभव एवं गाम्भीर्य का अभाव होता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्ना पर विचार करने के लिए जो दूरदर्शिता एवं परिपक्वता अपेक्षित है वह उनमें उपलब्ध नहीं होती। वह मिलती है लॉर्ड सभा के सदस्यों में। लॉर्ड सभा लोक सभा के उतावलेपन पर रोक लगा सकती है और यह नियन्त्रण प्रायः लाभप्रद सिद्ध होता है।

(5) ब्रिटिश जाति के स्वभावानुसूल (In line with British nature)—जिस प्रकार सं ब्रिटेनवासी राजतन्त्र को समाप्त नहीं कर सके और उसे

कहकर उसके आलोचकों की विरोधी ध्वनि को मँद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार लॉर्ड सभा ब्रिटिश अभिसमय एवं स्वभाव के अनुकूल एक ऐतिहासिक सदन है। केवल मूल अंतर यह है कि राजतन्त्र ने जन-भावना तथा समय के हिस को पहचाना है और उसी के अनुकूल अपने को ढाला है किंतु लाड सभा इस पहिचान से मुस्तसना रही है और एक दल के स्वामित्व में होने के कारण प्रगति का स्वागत करने में असमर्थ रही है। किंतु जिस प्रकार सुधारों के सम्मुख उसने समय समय पर समर्पण किया है उससे यह स्पष्ट है कि अब उसमें प्रगति के विरोध की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर कम होती जा रही है।

(6) व्यापक प्रतिनिधित्व (Wide Representative)—आग (Ogg) के शब्दों में, 'यहाँ पर उद्योग, वित्त विज्ञान साहित्य तथा धर्म आदि सबका प्रतिनिधित्व है। आध्यात्मिक बौद्धिक तथा मौलिक शक्तियाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। वशानुगत पीयरो को छोड़कर अन्य अधिकांश सदस्य वे होते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में राष्ट्र सेवा की है और लोक सभा के सदस्य के रूप में अनुभव की भट्टी में खूब अच्छी तरह तप चुके हैं। यदि वशानुगत सदस्य को नगण्य मान लें, जसा व्यवहार में है भी, तो लॉर्ड सभा द्वितीय सदन की स्वस्थ परम्पराओं के अपनाते हुए अपने दायित्वों की पूर्ति करने में सफल हो सकेगी। सम्मुख का यह कथन अयमय है कि 'अधिकांश सदस्यों की निरंतर अनुपस्थिति के कारण ही लॉर्ड सभा कुशल हो सकती है।' लॉर्ड सभा के पास समय का बाहुल्य रहता है। इसीलिए इसे 'आराम करने वाला सदन' की सजा दी जाती है।

1911 के संसदीय विधेयक की प्रमुख बातें (Main Provisions of the Parliamentary Act of 1911)

इस संसदीय विधेयक से पूर्व लॉर्ड सभा तथा कॉमन्स सभा दोनों की शक्तियाँ लगभग बराबर सी थीं। केवल अंतर यह था कि धन विधेयक लाड सभा में प्रस्तावित नहीं हो सकते थे। उसमें सशोधन करने का भी अधिकार लाड सभा को प्राप्त नहीं था, किंतु धन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार अवश्य ही उसे प्राप्त था। साधारण विधेयकों के विषय में उसके अधिकार पूर्णरूप से लोक सभा जैसे ही थे। 1909 में लॉर्ड्स ने लायड जाज के बजट को ही अस्वीकार कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया का परिणाम था 1911 का संसदीय विधेयक। इस संसदीय विधेयक की प्रमुख धाराएँ इस प्रकार की

(1) आर्थिक अथवा धन विधेयकों को कॉमन्स सभा से प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि में, यदि लॉर्ड सभा स्वीकार नहीं करती है तो वह अंतिम रूप से सभा के हस्ताक्षरों के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। लॉर्ड सभा यदि उसमें सशोधन भी करती है तो कॉमन्स सभा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उन्हें स्वीकार करे। बहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड सभा को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति धन विधेयकों के विषय में महत्वपूर्ण नहीं है।

(2) अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा। स्वीकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) यदि कोई सावजनिक विधेयक तीन बार लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकार

कर दिया गया हो और कॉमन्स सभा द्वारा बार-बार स्वीकार कर लिया गया हो और इसी बीच दो बप का समय व्यतीत हो गया हो तो वह विधेयक लॉर्ड सभा की स्वीकृति के बिना भी बानून बन जायगा। इससे लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सावजनिक विधेयकों के सम्बन्ध में कम हो गयी हैं।

(4) कॉमन्स सभा का कामकाज सात बप से घटाकर पाँच बप कर दिया गया।

इस प्रकार 1911 के संसदीय विधेयक ने ऐतिहासिक सदन के महत्व को कम करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम उठाया। यद्यपि लॉर्ड सभा का जनताधिकार तो नहीं हो सका, लेकिन उसकी शक्तियों में भारी गिरावट आयी। इन विधेयकों के सम्बन्ध में उसकी शक्तियाँ विलुप्त हो गईं। 1911 के विधेयक ने लॉर्ड सभा को बस साँस लेने भर की गुंजाइश छोड़ी थी। आगे चलकर वह भी समाप्त हो गयी।

1949 का संसदीय विधेयक (Parliamentary Act of 1949)

1934 में श्रमिक दल ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषित कर दिया था कि जब भी वे सत्तारूढ़ होंगे, वे लॉर्ड सभा के उन्मूलन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। 1945 में श्रमिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ। जब तक श्रमिक दल की राष्ट्रीयकरण की नीति का लॉर्ड सभा द्वारा अनुमोदन होता रहा, उस समय तक उसके उन्मूलन का प्रश्न नहीं उठा। किंतु जब इस्पात तथा लौह उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न उठा तो लॉर्ड सभा के विरोध की झलक मिलने लगी। यहाँ तक कि 1947 में लॉर्ड सभा के अधिवेशन समाप्त करने के बाद भी लॉर्ड सभा ने अपने मुद्दों को समाप्त करने के स्थान पर उसे चालू रखने की धापवा का और श्रमिक दल की राष्ट्रीयकरण की नीति पर बाद विवाद चलता रहा। जून 1948 में श्रमिक दल ने एक संसदीय विधेयक प्रस्तुत किया कि साधारण विधेयकों को गेजट की अवधि अधिक से अधिक एक बप हो। यह लॉर्ड सभा का स्वीकार नहीं था। फिर भी 1911 के विधेयक के अंतर्गत यह विधेयक अस्वीकार होने पर भी बानून बना और लॉर्ड सभा की देर लगाने की सीमा अधिक से अधिक एक बप निर्धारित कर दी गयी।

लॉर्ड सभा को सुधारने की योजनाएँ (Reform of the House of Lords)

लॉर्ड सभा के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा पूर्णतः एक अनावश्यक संस्था है। गहनतकह दृष्टि से यदि इसकी अनुपयोगिता प्रमाणित हो सके तो इसका उन्मूलन ही हीन रूप से हो गया होता। किन्तु गहनतकह दृष्टि से यह संस्था आज भी लॉर्ड सभा के जीवन में है तो इसका उन्मूलन हीन माना जायेगा। इसी कारण यह अनुभव किया गया कि लॉर्ड सभा को सुधारने तथा उसमें उन व्यक्तियों का प्रवेश करने के लिए जो लोकतन्त्र के सिद्धांतों पर लिये हुए हैं। इसी उद्देश्य के लिए लॉर्ड सभा के उन्मूलन के बजाय यह तो सभी अनुसूचित वर्गों के प्रतिनिधियों को लॉर्ड सभा में एव सुधार का एक उद्देश्य है।

संगठन, अधिकार एवं कतव्य मन्व धी बई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। प्रतिद्वीपीय सदन की अपक्षा लॉर्ड सभा को एक सहयोगी सदन के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका प्रतिश्रियावादी स्वरूप चिन्ता का विषय है किन्तु लॉर्ड सभा को सशोधित रूप प्रदान करना इतना सरल नहीं है। इसके माग में कई कठिनाइयाँ हैं—सबसे बड़ी कठिनाई तो जन साधारण की परम्परावादी प्रवृत्ति है जो अपनी पचीन सस्थाओं के उन्मूलन के पक्ष में नहीं जा पड़ती। नातिनारी स्थाव के प्रस्ताव रखने से पूर्व राजनीतिक दलों को इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी समस्या स्वयं राजनीतिक दलों के मतवैभिन्य की है। एक राजनीतिक दल इस बात का हामी है कि लॉर्ड सभा का जड़ से ही उन्मूलन किया जाय और विधि निर्माण के लिए लोक सभा ही काफी है। उदारवादी दल का दृष्टिकोण है कि इसमें सुधार तो होना चाहिए किन्तु इसे कमजोर ही रखा जाय। अनुदारवादी दल इसका सबसे बड़ा समर्थक है और उसका दृष्टिकोण यह है कि इसमें सुधार भले ही हो जायें किन्तु जिन शक्तियों को 1911 के समदीय विधेयक के अंतर्गत छीन लिया गया है उन्हें लौटा देना चाहिए। अतः इसके भाव, स्वरूप एवं स्थिति के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों में मतभेद है।

1869 में लॉर्ड सभा को सुधारने से सम्बन्धित प्रस्ताव लॉर्ड रसेल (Russell) ने रखा था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसी वर्ष ग्रे (Gray) का भी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। 1888 में लॉर्ड सैलिमबरी (Salisbury) ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका उद्देश्य अवांछित पीयरों को निष्कासित करके उनके स्थान पर 50 नये पीयरों की नियुक्ति का प्रश्न था। किन्तु इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया गया। 1909 में लैंसडाउन योजना (Lansdowne Plan) रखा गया। इसमें लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या 330 रखी गयी। इनमें से 100 प्रतिनिधि पीयरों में से तथा 100 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किये जायें, 125 सदस्य प्रादेशिक आधार पर लोक सभा द्वारा निर्वाचित किये जायें तथा शेष पाँच सदस्य विशेषों में से लिये जायें। यह योजना भी दुर्भाग्य से अस्वीकार कर दी गयी। इसके पश्चात् 1911 के समदीय आयोग में एक समिति नियुक्त करने की व्यवस्था थी जो उसमें सुधार के लिए योजना तैयार करे।

(1) ब्रायस कमिटी रिपोर्ट (Bryce Committee Report 1918)—1917 में लॉर्ड ब्रायस की अध्यक्षता में लॉर्ड सभा में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 1918 में समर्पित की। इसमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे

(अ) लॉर्ड सभा की संख्या घटाकर 327 कर दी जाय।

(ब) सदन के सदस्यों को दो भागों में बाँटा जाय। इनमें से 81 सदस्य पीयरों में से लोक सभा तथा लॉर्ड सभा की एक संयुक्त समिति द्वारा निर्वाचित किये जायें। शेष 246 सदस्यों के निर्वाचन के लिए लोक सभा का 13 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित किया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि भौगोलिक स्थिति के अनुकूल देश के प्रत्येक भाग को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

सदस्यों की पदावधि 12 वर्ष हो किंतु प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् $\frac{1}{3}$ सदस्यों को पद मुक्त कर दिया जाय।

किंतु ब्रायस समिति के इन उपयोगी प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया गया।

(2) लायर्ड जॉर्ज योजना, 1922 (Lloyd George Plan 1922)—(क) राजकुल, विधि तथा धार्मिक पीयर उसी रूप में बने रहें।

(ख) शेष सदस्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाय। इसमें तीन प्रकार के सदस्य हों—बाहर से निर्वाचित सदस्य, लॉर्ड समुदाय द्वारा अपने में से निर्वाचित सदस्य, तथा सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य।

(ग) निर्वाचित सदस्य 9 वर्ष की अवधि के लिए हों।

(घ) सदस्यों की कुल संख्या 350 हों।

यद्यपि यह योजना ब्रायस समिति का परिष्कारित रूप था किंतु इस भी अस्वीकार कर दिया गया।

(3) क्लरेण्डन योजना (Clarendon Plan)—1929 में लॉर्ड केव ने एक योजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य लॉर्ड सभा को शक्तिशाली बनाना था किंतु इसे भी अस्वीकार कर दिया गया और दिसम्बर में लॉर्ड क्लरेण्डन ने पुनः एक दूसरी योजना रखी जिसका उद्देश्य लॉर्ड सभा को प्रथम सदन का सहयोगी बनाना था। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं

(अ) 150 सदस्य कुल पीयरों की संख्या में से निर्वाचित होंगे।

(ब) 150 सदस्य सम्राट द्वारा प्रत्येक सदन की अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे।

(स) मनोनायन करते समय लोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति का ध्यान रखा जाता होगा। सम्राट को कुछ आजीवन पीयर बनाने का भी अधिकार दिया जाय।

किंतु यह योजना भी अस्वीकार कर दी गयी।

(4) सैलिसबरी योजना, 1932 (Salisbury Plan, 1932)—(अ) लॉर्ड सभा के कुल सदस्यों की संख्या 320 हो।

(ब) इनमें से 150 सदस्य पीयर वर्ग द्वारा 12 वर्ष के लिए निर्वाचित किये जायें।

(स) 150 सदस्य लोक सदन द्वारा निर्वाचित किये जायें।

(द) 20 सदस्य राजकुल, विधि तथा आध्यात्मिक पीयरों में से लिये जायें।

(5) सषदसीय सम्मेलन, 1949 के सुझाव (All Party Conference)—

(अ) पैंतृक सदस्यता समाप्त की जाय।

(ब) सषदसीय लॉर्डों की नियुक्ति व्यक्तिगत सावजनिक सेवा, प्रतिष्ठा एवं उपलब्धियाँ के आधार पर हो।

(स) विधि, राजकुल तथा आध्यात्मिक पीयरों को भी स्थान दिया जाय।

(द) पैंतृक लाइनों में से सषदसीय लॉर्डों की नियुक्ति का आधार योग्यता हो।

(य) लोक सभा के सदस्यों की ही भाँति लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन मिले।

(र) स्त्रियों को भी लॉर्ड सभा के सदस्य बनने की सुविधा दी जाय।

(ल) जो संसदीय ढाँचों की श्रेणी में न आ सकें उन्हें लोक सभा का सदस्य बनने तथा निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए।

किन्तु इस योजना का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ।

अन्य सुझाव (Other Suggestions)—31 अक्टूबर 1967 को भूमिक सरकार ने लॉर्ड सभा को सुधारने के लिए कुछ सुझाव रखे थे। उनमें से एक यह था कि लॉर्ड सभा की संख्या घटाकर 300 कर दी जाय। आग तथा जिंक (Ogg & Zink) ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक में इस सम्बन्ध में कुछ परामर्श दिये हैं।

(अ) केवल पीयर होना के कारण ही किसी को लॉर्ड सभा में बसने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

(ब) कुछ सदस्य आनुवंशिक पीयरों में से भी लिये जायें।

(स) विधि विशेषज्ञों तथा अन्य व्यापारिक व्यक्तियों को भी इसका सदस्य बनाया जाय।

(द) लॉर्ड सभा के सदस्यों का निर्वाचन लोक सभा के सदस्य प्रत्यक्ष आधार पर हो।

लास्की तथा फाइनर इन सुझावों से सहमत नहीं हैं क्योंकि लॉर्ड सभा सहयोगी सदन होने की अपेक्षा एक प्रतिद्वंद्वी सदन बन जायगा। रैम्से म्योर (Ram say Muir) ने लॉर्ड सभा को एक व्यावसायिक प्रतिनिधि सदन बनाने का सुझाव रखा है। प्रत्येक प्रमुख उद्योग को आनुपातिक प्रणाली के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय। किन्तु इससे लॉर्ड सभा का स्वरूप बहुत ही सकीन बन जायगा।

अतः लॉर्ड सभा में सुधार करने के लिए समय समय पर जो प्रस्ताव रख गये वे अस्वीकार कर दिये गये। सारी सुधार योजना अस्पष्ट तथा खिचड़ी सी जान पड़ती है। लोकतंत्र में पट्टक प्रतिनिधित्व के आधार का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। लॉर्ड सभा में सुधार करने का प्रश्न उसके विशेष राजनीतिक वातावरण के सन्दर्भ में विचाराय रखा जाय। सावजनिक दृष्टि से उसे अधिकाधिक उपयोगी बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसे अनुभवहीन दल तथा निष्पक्षों का सदन बनना चाहिए। सुधार इस दृष्टि से प्रस्तावित किये जायें जिनमें यह किसी भी दल का अड्डा न बन सके। इसका संगठन इसी रूप में होना चाहिए। सबसे पहले ता पट्टक अधिकार को समाप्त करना अति आवश्यक है। लॉर्ड सभा में लगभग 300 सदस्य ही रहें जायें, तभी यह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है। इनमें से कुछ सदस्य लोक सभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित किये जाय। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल भी लोक सभा के अन्य सदस्यों के कार्यकाल से सम्बद्ध होगा। कुछ सदस्य देश का सगठना हिता तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। प्रत्येक दो वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। लॉर्ड सभा का संवैधानिक स्तर ऊँचा रखने की दृष्टि से अवकाश प्राप्त

कुशल राजनीतिज्ञों, समाज सेवियों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि को भी स्थान मिलना चाहिए। घन विधेयक तथा मन्त्रिमण्डल पर नियंत्रण आदि को छोड़कर अन्य सभी बातों में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान रखने पर बल मिलना चाहिए। साधारण विधेयकों की स्वीकृति में यदि दोनों सदनों में मतभेद है तो उसे संयुक्त अधिवेशन तथा अन्य किसी तरीके से सुलझाना चाहिए। ग्रीन्ज ने एक सुझाव रखा है कि लोक सभा द्वारा निर्वाचन पद्धति का आधार क्या हो इसका निर्णय लोक सभा के अध्यक्ष के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इसमें दो मत नहीं हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार करने की आवश्यकता है।

18 जून, 1968 को लाइ सभा ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का जिक्र था कि सदस्य राज्य रोडेशिया के प्रति अपने प्रतिबन्धों को सख्त करें क्योंकि वहाँ स्मिथ सरकार ने काले व्यक्तियों की एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा करके उपेक्षा की थी। यह प्रस्ताव कॉमन्स सभा से स्वीकृत हो जाने के पश्चात् लॉर्ड सभा में गिर गया। तभी 20 जून, 1968 को प्रधानमन्त्री विल्सन ने घोषित किया था कि लॉर्ड सभा की शक्तियों में आमूल परिवर्तन करने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। 31 अक्टूबर 1968 को विल्सन सरकार ने इस आशय की घोषणा भी कर दी थी कि लॉर्ड सदन का पंतुक अधिकार समाप्त हो गया है। किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत लॉर्ड सभा में नहीं रहना चाहिए। सत्ताधारी दल को कामचलाऊ बहुमत मिलता रहे इतना ही काफी है। किंतु 1969 तक इस विधेयक पर कोई विचार नहीं हुआ है।

Suggested Readings

- Gordon *British Parliament*
Greaves *The British Constitution*
Fisher *Major European Governments*
Campbell *Parliament*
Jennings *Parliament*
Birch A II *Representative & Responsible Government*

ADVANCE COPY
Meant for Consideration
NOT FOR SALE

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 लॉर्ड सभा की रचना, कृत्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।
(Discuss the composition functions and powers of the House of Lords and critically examine its utility in the British constitutional system)
- 2 ब्रिटिश लॉर्ड सभा को वर्तमान युग में एक प्रभावी सदन कहना कहा तक उपयुक्त होगा ?
(How far can the British House of Lords be an effective second chamber to day ?)
- 3 "लॉर्ड सभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं अपितु शक्तिहीन सदन है।" इस कथन की विवेचना कीजिए।
(The House of Lords is not only a second but a secondary chamber " Discuss)

- 4 ब्रिटिश लाड सभा की अलोचप्रियता का वर्णन कीजिए। उसने सुधार के क्या प्रयत्न हुए हैं? अपना सुझाव दें।
(Account for the popular dissatisfaction against the House of Lords in England. What attempts have been made to reform it? Give your suggestions.)
- 5 'लॉर्ड सभा का या तो अंत होना चाहिए या सुधार।' इस बयन की समीक्षा कीजिए।
(The House of Lords should be either ended or amended. Comment upon this statement.)
- 6 "ब्रिटिश लाड सभा के अंत में नहीं, अपितु शक्तियों के दुरुपयोग में ही संकट है। इस कथन की विवेचना कीजिए।
(The danger to the British House of Lords lies in a trophy and not in assassination. Comment.)
- 7 'ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट की रचना, शक्तियों तथा स्थिति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए।
(Compare and contrast the composition, powers and position of the British House of Lords with those of the Senate of the U.S.A.)
- 8 इंग्लैंड और फ्रांस के उच्च सदनों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए।
(Compare and contrast the powers and functions of the upper Houses in England and France.)
- 9 इंग्लैंड की लॉर्ड सभा तथा सोवियत संघ की राष्ट्रीयतावा के अधिकारों एवं कार्यों की तुलना कीजिए।
(Compare the role and functions of the House of Lords in England with those of the Soviet of Nationalities in the U.S.S.R.)
- 10 जनतन्त्रात्मक ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के कार्यकरण का वर्णन कीजिए। उसने सुधार के सुझावों का उल्लेख कीजिए।
(What is the role of the House of Lords in a democratic Britain? Describe some of the salient proposals for reform.)
- 11 लॉर्ड सभा के संगठन, अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। लाड सभा के सुधार के लिए किये गये प्रस्तावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
(Describe the composition, powers and functions of the House of Lords. Briefly discuss the various proposals for the reform of this House.)

5

ब्रिटिश ससद—लोक सभा [House of the Commons]

"When a Minister Consults Parliament, he consults the House of the Commons, when the Queen dissolves Parliament she dissolves the House of the Commons A new Parliament is simply the new House of Commons"
—Robert Walpole

जब हम ससदीय सावभौमिकता की चर्चा करते हैं तो वह वस्तु लोक सभा की ही सावभौमिकता होती है। लोक सभा ही व्यावहारिक रूप में ब्रिटिश ससद है। जब सम्राट ससद का विघटन करता है तो वह लोक सभा का ही विघटन होता है। सिडनी लो (Sydney Low) के शब्दों में, ब्रिटिश लोक सभा ससार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सावजनिक सभा है, यह राजनीतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु है। प्राचीनता तथा परम्पराओं ने इसे प्रतिष्ठित सदन बनाकर एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। लोक सभा को विश्व ससदों की जननी कहा जाता है। राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व यही सदन करता है। जनमानस इसके अन्तर्गत एवं व्यवहार में समा गया है। लोक सभा लोकमत की अभिव्यक्ति का मूल स्रोत है। इसके माध्यम से सामाजिक मूल्य एवं राजनीतिक परिवर्तन जनता के समक्ष आते हैं। लोक सभा नवीन स्फूर्ति एवं उत्साह से युक्त व्यक्तियों की रणस्थली है। यह भावी राजनीतिज्ञों का प्रशिक्षण गार है। लोक सभा ने विभिन्न रूपों में देश की सेवा की है। भावी राजनीतिज्ञों के लिए स्थान खोजकर तथा उन्हें सावजनिक हित के साथ सम्मिलित करके लोक सभा ने बड़े बड़े वक्ता नीति निर्माता तथा प्रशासक उत्पन्न किये हैं।

लोक सभा का संगठन (Organization of the House of Commons)

1948 के प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार लोक सभा के सदस्यों की संख्या 640 से घटाकर 625 नियत कर दी गयी है। इसमें 507 प्रतिनिधि इंग्लैण्ड, 71 स्कॉटलैण्ड, 35 वेल्स तथा 12 उत्तरी आयरलैण्ड से निर्वाचित होते हैं। सम्पूर्ण देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है। मतदान का आधार वयस्क मताधिकार है। प्रत्येक उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार है जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जिसके पास कम से कम 10 पौण्ड वार्षिक का सकल अथवा सम्पत्ति

हो। लोक सदन के निर्वाचनों के लिए 'एक मत एक व्यक्ति' का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जिन लोगों का दिवाला निकल चुका है अथवा जो पागल हैं उन्हें इस अधिकार से वंचित किया गया है। एक व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान नहीं कर सकता। निर्वाचन के समय जिन लोगों ने गलत तरीकों का प्रयोग किया है और जिन्हें दण्ड भी मिल चुका हो उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं है। लाभदायक पद पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। पौधों को भी लोक सभा के निर्वाचना के लिए मताधिकार से वंचित रखा गया है।

कॉमंस सभा की निर्वाचन पद्धति का और अधिक स्पष्ट अध्ययन हम सीन शीपेंका के अंतर्गत कर सकते हैं—सदस्यों का मनोनयन, निर्वाचन प्रचार तथा मतदान की घोषणा। किसी भी क्षेत्र से पार्टी का टिकट देते समय राजनीतिक दल जिन बातों का सामांय रूप से ध्यान रखते हैं वे हैं—उम्मीदवार की लोकप्रियता, योग्यता, सावजनिक सेवाएँ, निर्वाचन व्यय को सहने की क्षमता। उम्मीदवार के लिए उस विशिष्ट क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। 1957 के 'कॉमंस अधिनियम' ने कुछ बग के लोगों पर चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबंध लगाया है—जैसे याय के पदों पर आसीन, असैनिक सेवाओं के स्थायी तथा अस्थायी सदस्य, नियमित सेवा के सदस्य, स्थानीय सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सावजनिक समितियों के सदस्य, राज्य द्वारा नियंत्रित अनेक समितियों के सदस्य आदि। एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं किंतु प्रत्येक को प्रतिभूति के रूप में 150 पौण्ड जमा कराना पड़ते हैं।

मनोनयन के उपरांत प्रत्येक राजनीतिक दल धुआधार प्रचार प्रारम्भ करता है। सभाएँ, आकाशवाणी छविगृह, समाचार पत्र तथा थ्येटर आदि सभी का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। प्रत्येक पक्ष अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक योजनाओं को मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करता है। निर्वाचन का समय प्रायः प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक रहता है। सेवारत कर्मचारियों को डाक द्वारा मत पत्र प्रेषित करने की सुविधा दी जाती है। 1918 के अधिनियम के उपरान्त सारे देश में निर्वाचन एक दिन होते हैं। पहले यह रिटनिंग अफसरों की इच्छा पर अवलम्बित था। 1950 के एक नियम के अनुसार एक उम्मीदवार काउंट्री के निर्वाचन के लिए 450 पौण्ड व्यय कर सकता था। किंतु सशोधित रूप में यह व्यय 160 पौण्ड, 330 पौण्ड 937 पौण्ड और 523 पौण्ड था।

मतदान समाप्त होने पर उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों के समक्ष मतगणना होती है। अब उम्मीदवारों की अपेक्षा जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसे अपेक्षाकृत मताधिक्य प्रणाली (Relative Majority System) कहा जाता है।

निर्वाचन प्रणाली के दोष (Criticism of Electoral System)

(1) निर्वाचित व्यक्ति सही प्रतिनिधि न हो (Elected person may not be the true representative)—ब्रिटेन की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली का एक

बड़ा दोष यह है कि निर्वाचित व्यक्ति, हो सकता है, अपने क्षेत्र का वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। निर्वाचित उम्मीदवार के प्रतिद्वंद्वियों के मत मिलाकर उसके द्वारा प्राप्त मतों से अधिक होते हैं। ऐसा अनेक बार होता है एक दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा

सन् 1922 के निर्वाचन से

उम्मीदवार का नाम	दल का नाम	मतों की संख्या
रीले बी	लेबर	8 821 निर्वाचित
हारवे टी ई	लिबरल	8,065
पीक, ओ	यूनियनिस्ट	6,744
क्षेत्र—हडसफील्ड		
माशाल	लिबरल	15,878 निर्वाचित
हडसन	लेबर	15,673
साइक्स	नेशनल लेबर	15,212
क्षेत्र—मेडरटोन		
ब्लेअर्स	यूनियनिस्ट	8 928 निर्वाचित
ब्लैक	नेशनल लिबरल	8,895
डाल्टन	लेबर	8 004

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि निर्वाचित उम्मीदवार के मत उसके प्रतिद्वंद्वियों के कुल मतों से अधिक नहीं हैं। फिर भी उसे घोषित किया जाता है। जिन्होंने उसके विरुद्ध मत दिये हैं उनका वस्तुतः वह प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह निर्वाचन की एक असंगति है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ दो उम्मीदवार खड़े होते हैं—एक संरक्षणवादी तथा दूसरा समाजवादी और दोनों में ही मतदाता का विश्वास नहीं होता, तो उसके पास केवल दो ही विकल्प होते हैं—या तो वह अपना मत त्याग दे अथवा उनमें से यह छांटे कि कम अहितकर कौन है। इस प्रकार उसकी पसंद सक्ती बन जाती है।

(2) राजनीतिक दलों को उनके कुल मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता (Parties do not secure seats in proportion of their votes obtained)—ब्रिटिश कॉमन्स सभा की निर्वाचन पद्धति का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि एक राजनीतिक दल को कॉमन्स सभा में उतने स्थान प्राप्त नहीं होते जितने कि उसके द्वारा प्राप्त मत संख्या के अनुपात में उसे प्राप्त होना चाहिए। इस प्रणाली से छोटे दलों की संख्या क्षीण हुई है। उनके मत कई निर्वाचन-क्षेत्रों में बिखरे होते हैं। इंग्लैंड की निर्वाचन-पद्धति से लोकमत दूषित हुआ है। तीन राजनीतिक दलों के होने से एक राजनीतिक दल सबसे अधिक मत ले जाय किन्तु उसे लोक सभा में एक भी स्थान प्राप्त न हो। 1923 के निर्वाचन में अनुदारवादी दल को कुल मतों के केवल 37% मत प्राप्त हुए और उसे 347 स्थान प्राप्त हुए जबकि सब विपक्षी दलों द्वारा प्राप्त स्थानों से 79 अधिक थे। उदाहरणार्थ—

दल का नाम	सन 1935 के निर्वाचन से	स्यानो की सख्या
	मतों की सख्या	
अनुदारवादी दल	10,496,000	35
उदारवादी	866,000	33
धर्मिक दल	34,000	7
नेशनल (सरकार)	9,700	5
लेबर	8,465,000	168
लिबरल	1 43,300	19
अन्य	302,000	8

दल का नाम	सन 1955 के निर्वाचन से	स्यान
	मतों का प्रतिशत	
अनुदारवादी दल	49 8%	345
मजदूर दल	46 3%	276
उदारवादी	27%	6

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दलों को प्रायः उनके द्वारा प्राप्त मतों की सख्या के अनुपात में स्यान प्राप्त नहीं होते और इसे हम 'यायसमत नहीं कह सकते। 1944 में उदारवादी दल को केवल 24 स्यान मिले जबकि उनके द्वारा प्राप्त मतों के आधार पर उन्हें 108 मत प्राप्त होने चाहिए थे।

(3) बहुसंख्यक मतदाता निर्वाचन से वंचित रहते हैं (Majority of votes are deprived of)—इससे कहने का तात्पर्य यह है कि 60 से लेकर 70% मत राष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित नहीं कर पाते या उन्हें उन सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ता है जिनसे सद्भातिक रूप से मतभेद होता है। निर्बिरोध निर्वाचना से बहुत से मतदाताओं के मत छिन जाते हैं। जो मत असफल उम्मीदवारों के पक्ष में डाले जाते हैं वे भी व्यर्थ चले जाते हैं। कभी कभी यह देखने में भी आता है कि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं होता और उनके मत व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि वे किसी के पक्ष में उनका प्रयोग नहीं करते। 1918 के निर्वाचना न इसे स्पष्ट कर दिया था।

(4) संसद का निर्वाचन संकुचित आधार पर होता है (Parliament is elected on narrow basis)—संसद के निर्वाचित सदस्यों का दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित होता है। निर्वाचित प्रतिनिधियाँ मं सकीर्ण स्थानीय भावनाएँ प्रायः उभरती रहती हैं। जिस संसद का वर्तमान प्रणाली के द्वारा निर्माण होता है उसे हम प्रत्येक दृष्टि से राष्ट्र का प्रतिनिधि सदन नहीं कह सकते। आक्स सविधानवादी रैन्जेम्योर के शब्दों में, "हमारी निर्वाचन-प्रणाली असोम मात्रा में अयायपूण, असंतोषजनक तथा आपत्तिजनक है यह प्रणाली आम चुनाव में राष्ट्रीय नियम का विवृत स्वरूप प्रस्तुत करती है। इससे अत्यन्त अयायपूण परिणामों की सृष्टि होती है। प्रत्येक निर्वाचन एक जुआ बन जाता है जिसका दलीय नेताओं पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है।" इसमें दो मत नहीं कि हम संसद को इस प्रणाली के माध्यम से राष्ट्र का आन्ध्र प्रतिनिधि संगठन नहीं बना पाते।

निर्वाचन पद्धति में प्रस्तावित सुधार (Proposed Reforms in the Electoral System)

(1) एकल मत हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System)—निर्वाचन अनुपाती पद्धति से कराये जायें जिसका माध्यम एकल मत प्रणाली हो। इस व्यवस्था में मत व्यर्थ नहीं जाते। संसद में विविध हितों एवं वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। किंतु इसे उपयोगी मानते हुए भी कुछ लेखक लागू करने को तैयार नहीं हैं। वे इसे दलीय बुराईयों से भी अधिक अहितकर मानते हैं।

(2) एकत्रमत तथा निबंधनीय मत प्रणाली (Cumulative Restrictive Vote System)—निबंधनीय पद्धति को अपनाये जाने की सिफारिश की जाती है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसंख्यक होते हैं। जिन्होंने प्रतिनिधि एक क्षेत्र से निर्वाचित होना होते हैं उससे कम मत देने का अधिकार एक मतदाता को दिया जाता है। इससे दो पक्ष वाली संसद की प्रणाली समाप्त हो जायगी। मतदाता को इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि वह चाहे तो अपने सारे मत एक उम्मीदवार के पक्ष में डाल दे या उन्हें वितरित कर दे। एकत्रमत पद्धति में मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्यों वाला वह निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें केवल यही छूट दी जाती है कि मतदाता अपने सारे मतों को एक ही उम्मीदवार के पक्ष में एकत्रित कर सकता है। इन प्रणालियों को अपनाने से एक ही हानि की सम्भावना है कि ब्रिटेन की द्विसदनीय व्यवस्था समाप्त हो जायगी।

इन सुधारों के अतिरिक्त हम यह भी नहीं कह सकते कि करोड़ों व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 630 सदस्य काफी हैं। विचार धाराओं के आधार पर भी तो निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण कठिन है जिसके अंतर्गत विविध विचारधारा के व्यक्ति रखे जा सकें। निर्वाचित होने के पश्चात् उम्मीदवार राष्ट्र का प्रतिनिधि हो जाता है।

अवधि (Duration)—लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 1911 से पूर्व यह अवधि पाँच वर्ष की हुआ करती थी, किंतु पाँच वर्ष से पूर्व भी उसका विघटन सम्भव है। सम्राट प्रधानमंत्री के आग्रह पर इस अवधि से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। संवत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता अनुभव होने पर इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रिटिश इतिहास में बहुत ही कम लोक सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष रहा है।

सदस्यता के लिए योग्यताएँ (Qualifications)—सामान्यतया कोई विशेष योग्यता की व्यवस्था कॉमन्स सभा की सदस्यता अर्जित करने के लिए निश्चित नहीं की गयी है। किंतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है

(1) किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से मतदाताओं की सूची में उसका नाम होना चाहिए।

(2) आयु नियमानुसार होना आवश्यक है।

(3) राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो।

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति लोक सभा के सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं माने जाते

- (1) जिनकी अवस्था नियमानुसूल नहीं है ।
- (2) विदेशी है, पागल है अथवा जो कभी भी कानून के अनुसार दण्डित किया जा चुका है ।
- (3) जो लॉर्ड सभा का सदस्य है ।
- (4) पादरी, मेयर तथा वाउंटियो के शेरिफ ।
- (5) राजकीय कर्मचारी ।
- (6) जो व्यक्ति सरकारी ठेको तथा सरकार द्वारा अन्य साधनों से लाभान्वित होते हैं ।

सदस्यता का परित्याग करना सरल नहीं है । किन्तु 1705 के स्थापन अधिनियम के अंतर्गत एक युक्ति खोज निकाली गयी है कि यदि कोई सदस्य राज मुकुट के अधीन सेवा की व्यवस्था कर ले तो उसे सदस्यता का परित्याग करने का अवसर उपलब्ध हो सकता है । चिल्ड्रेन हंडरेड (Children Hundred) का पत्र ऐसा है कि उसने लिए वेतन व्यवस्था तो है किन्तु उसके साथ सम्बद्ध कोई उत्तर दायित्व नहीं है । इस पद के लिए कोई भी आवेदन पत्र दे सकता है और परम्परा नुसार उसे इसके प्रतिकूल नियुक्त भी कर लिया जाता है । नियुक्ति की कार्यवाही होने पर लोक सदन का अध्यक्ष उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देता है । सदस्य घर बैठे ही त्याग पत्र भेज देत है और चिल्ड्रेन हंडरेड की व्यवस्था का सदस्य को लाभ मिल जाता है । इसी के सदृश एक और पद्धति नाथस्टैण्ड के मनर (Manner of the Northstand) है ।

सदस्यों की उन्मुक्तियाँ (Privileges)

(1) ससदीय अधिवेशन से 40 दिन पूर्व तथा अधिवेशन के 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता, केवल दीवानी मामलों में ।

(2) भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध रहती है । सदन में सदस्य के किसी भी शब्द पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती । किन्तु यदि वह भाषण का कोई अंश सदन से बाहर प्रकाशित करता अथवा बरवाता है तो उस स्थिति में उसे इस उन्मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

सदन के किसी भी सदस्य को किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में धन स्वीकार करने की अनुमति है । सदन में प्रस्तावित किसी भी विधेयक के समर्थन तथा विरोध के लिए धन स्वीकार करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और उसकी स्वीकृति सदन की मानहानि मानी जायगी । सदन की मानहानि करने पर ऐसे सदस्य को सजा देने की शक्ति सदन में निहित है । सदन की मानहानि के लिए सदन किसी भी कर्मचारी को दण्ड दे सकता है ।

ससदीय अधिवेशन (Parliamentary Sessions)

निर्वाचनों के पश्चात् दो सप्ताह की अवधि में नूतन सदन का अधिवेशन आमंत्रित कर लिया जाता है । गणपूर्ति की समस्या केवल 40 है । वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होते हैं । सप्ताह के प्रथम पाँच दिन सदन के अधिवेशन होते हैं ।

शनिवार तथा रविवार को अधिवेशन नहीं होते किंतु आवश्यकता होने पर यह भी सम्भव है। अधिवेशन वेस्टमिनिस्टर भवन में होते हैं। सामान्यतया अधिवेशन प्रतिदिन 2-30 अपराह्न से प्रारम्भ होकर रात्रि के 10 30 बजे तक चलते रहते हैं। केवल शुक्रवार को अधिवेशन 11-00 पूर्वाह्न से प्रारम्भ होकर अपराह्न 4 30 बजे तक चलता है। लोक सभा के पास काम की मात्रा इतनी अधिक हो गयी है कि उसे विवश होकर लम्बे लम्बे अधिवेशन करने पड़ते हैं। सदन की विभिन्न समितियों के अधिवेशन अपराह्न में ही हो जाते हैं। सदस्यों के लिए पूरे समय अधिवेशन में बैठना सम्भव नहीं हो पाता। कभी वे किसी समिति की बैठक में, कभी दल की बैठक में या कभी पुस्तकालय में चले जाते हैं। प्रायः उनका समय बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ अधिक शिगडता है जो 'हरा काड' दिखाकर उन्हें बाहर बुलवा लेते हैं और फिर अपने काम के लिए दबाव डालते हैं। प्रत्येक सदस्य को £ 1,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त होता है।

लोक सभा की कार्यवाही के विषय में कोई निश्चित नियम तो नहीं है, यह अधिकांशतः परम्पराओं पर निर्भर करती है। सदन की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष के द्वारा सम्पन्न होता है। सदन का अपमान करने वाले अथवा कार्यवाही में निरंतर बाधा डालने वाले सदस्यों को पहले निलम्बित किया जाता है तथा उनके सम्बन्ध में फिर सदन निश्चय करता है। सदन की कार्यवाही का मूल केन्द्र वाद विवाद रहता है। वाद विवाद के कुछ निश्चित नियम होते हैं। राजनीतिक दल पहले से ही किसी भी वाद विवाद के विषय में समय-विभाजन निश्चित कर लेते हैं किंतु कभी-कभी यह सम्भव नहीं हो पाता। तब वाद विवाद को किस प्रकार समाप्त किया जाय ? इस समापन (Closure) की कई विधियाँ हैं।

(1) साधारण समापन (Simple Closure)—लोक सभा का कोई भी सदस्य 100 अथवा सदस्यों के अनुसमयन से इस आशय का प्रस्ताव रख सकता है कि अमुक वाद विवाद को समाप्त करके मतदान ले लिया जाय। यदि अध्यक्ष को यह विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार का समर्थन प्रस्ताव को प्राप्त है और अल्प संख्यक दल के अधिकारों का उससे कोई हनन भी नहीं होता है, तो वह प्रस्ताव पर मतदान करा सकता है। इस प्रकार इस साधारण प्रक्रिया से वाद विवाद का अन्त हो जाता है।

(2) विभागगत अवरोधक (Closure by Compartment)—उपयुक्त समापन विधि में एक कभी भी कि प्रत्येक धारा के पश्चात् अवरोधक लाना पड़ता था। इस दोष के निवारणार्थ विभागगत अवरोधक की विधि निराली गयी है। इसके अनुसार अनेक धाराओं के समूह के लिए एक ही अवरोधक पर्याप्त समझकर प्रस्तावित करा लिया जाता है। बार-बार इस आशय के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, जब इस प्रकार का कोई समापन प्रस्ताव रखा जाता है कि 1824 तक की धाराओं पर होने वाले वाद विवाद का अन्त किया जाय तब यह विभागगत अवरोधक कहलाता है।

(3) कंगारू अवरोधक (Kangaroo Closure)—वाद विवाद पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने की यह अधिक लोकप्रिय विधि है। इसका प्रयोग सगोष्ठियों

के सम्बन्ध में किया जाता है। जब किसी विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से सशोधन आ जाते हैं तो उनमें से समय बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सशोधन छूट लिये जाते हैं और वाद-विवाद उन्हीं तक सीमित रखा जाता है। बीच में बहुत से सशोधनों को छोड़ दिया जाता है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसीलिए इसे वाद विवाद समापन की बगारू विधि कहा जाता है। सशोधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार लोक सभा के अध्यक्ष को होता है। यह अधिकार साधन एवं उपाय समिति के अध्यक्ष को भी प्राप्त होता है।

(4) गिलोटिन समापन (Gulliotine Closure)—गिलोटिन का प्रयोग शीघ्र काटने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के समय पर्याप्त मात्रा में हुआ। समापन की इस विधि के अंतर्गत विधेयक की प्रत्येक धारा के सम्बन्ध में होने वाले वाद विवाद का समय निश्चित कर लिया जाता है और समय पूरा होते ही उस धारा के सम्बन्ध में वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाता है चाहे उस पर पूर्ण रूप में विचार हुआ हो अथवा नहीं। इसी कारण समापन की इस विधि को गिलोटिन समापन कहा जाता है।

(5) समय सारणी समापन (Time Table Closure)—गिलोटिन पद्धति का एक सुंदर विकल्प समय सारणी समापन है। समापन की इस व्यवस्था के अंतर्गत विधेयक का प्रस्तावक स्वयं वाद विवाद का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि सदन इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक के सम्बन्ध में वाद विवाद का संचालन उसी ढंग से होता है और उतना ही समय दिया जाता है जितना कि समय सारणी में अंकित किया गया है।

(6) विभाजन अवरोधक (Closure by Division)—इस अवरोधक का प्रयोग विधेयक की प्रस्तावना के समय किया जाता है। विधेयक को प्रकाशनाय स्वीकार किया जाय अथवा न किया जाय इसका निर्णय सदन करता है। अध्यक्ष ध्वनि मतगणना से यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि पक्ष तथा विपक्ष में पलड़ा किसका भारी है। स्थिति स्पष्ट न होने पर वह सदन का विभाजन करा लेता है। वाद विवाद नियंत्रण की इस प्रणाली को अंत विभाजन द्वारा अवरोधक की प्रणाली कहते हैं।

लोक सभा का अध्यक्ष

(Speaker of the House of Commons)

गोडन ने अपनी पुस्तक 'Our Parliament' में लोक सभा के अध्यक्ष पद के महत्व पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि "लोक सभा के अध्यक्ष का पद विश्व के अत्यधिक प्रतिष्ठित उत्तरदायी एवं सम्मानजनक पदों में से एक है।" (The speakership of the House of the Commons is the most honourable, dignified and onerous offices in the world) लोक सभा के अध्यक्ष का पद एक ऐतिहासिक पद है जिसके आविर्भाव के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 1336 में थॉमस ह्यूरफोर्ड प्रमाणित एवं वैधानिक रूप में लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्पीकर का कार्य मूल रूप में समन्वय तथा परिभाजन है। आरम्भ से ही उसके पद की प्रवृत्ति कम बोलने की रही है। वह सदन का मूल प्रवक्ता होता है। वह लोक सभा का सदस्य होता है। सदन द्वारा उसका निर्वाचन सम्पन्न

होता है, यद्यपि वह अब परम्पराओं से बद्ध औपचारिकता मात्र है। वह सदन के वाद विवादों में सभापति पद ग्रहण करता है। इस पद का महत्व इसलिए भी है कि अध्यक्ष को निर्णायक के रूप में सदन में अधिष्ठित रूप से कहने का अधिकार होता है। बिना स्पीकर के सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। अध्यक्ष फिट्ज़रॉय (Fitzroy) की मृत्यु पर समस्त सदन उठ खड़ा हुआ और अधिवेशन उस समय तक पूरा आरम्भ नहीं हो सका जिस समय तक कि नये अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो गया, यद्यपि इंग्लैंड को युद्ध के बादल घेर हुए थे। स्पीकर के पद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इंग्लैंड का संविधान परम्पराओं पर अवलम्बित अलिखित संविधान है, जिसकी सफलता बहुत कुछ राजनीतिक दलों की नैतिकता तथा स्वशासन पर अवलम्बित है। स्पीकर को £ 10 000 वार्षिक वेतन मिलता है। यह कर रहित होता है। अवकाश प्राप्त करने पर स्पीकर को लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। वैंस्ट मिनिस्टर भवन में ही उसका निवास है। राष्ट्र में प्राथमिकता की दृष्टि से उसका नाम तुरन्त ही कैंटरबरी के आर्कबिशप के बाद तथा प्रधानमंत्री से पहले नहीं आता। अवकाश ग्रहण करने पर स्पीकर को पे शन के रूप में 400 पौण्ड मिलते हैं। स्पीकर अब सदन में प्रवेश करता है तो उसके अभिवादन के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसके संकेत पर अपने स्थान ग्रहण करते हैं। लोक सभा के हितों के संरक्षण का उस पर उत्तरदायित्व होता है। सर टॉमस मूर (Thomas More) को हनरी अष्टम के समय में राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर ठूसी से बांध दिया गया और उसे बहुत से कष्ट सहन पड़े। 'अध्यक्ष सम्राट तथा संसद के मध्य संधि की एक जोड़खी कड़ी है।' 18वीं शताब्दी तक वह प्रधानमंत्री पद के लिए अग्रिम कदम माना जाता रहा।

अध्यक्ष की निष्पक्षता (Impartiality of the Speaker)

ब्रिटिश लोक सभा के अध्यक्ष की निष्पक्षता सुविख्यात है। वह सदा ही दलीय भावना से ऊपर रहता है। अध्यक्ष विलफ्रेड वाउन ने एक बार कहा था कि "अध्यक्ष के रूप में मैं न तो सरकार का आदमी हूँ और न विरोधी दल का। मैं लोक सभा का आदमी हूँ और सबसे पहले पीछे बैठने वालों का।" रॉबर्ट ब्राइस (Bryce) के शब्दों में, "अध्यक्ष राजनीति से संसार से लेता है।" अध्यक्ष की निष्पक्षता की दृष्टि में रखकर ही प्रायः यह कहा जाता है 'एक बार अध्यक्ष, मरव अध्यक्ष' (Once a speaker always a speaker)। वह वास्तव में ब्रिटिश सम्राट से जोती हुई सावभौमिकता का प्रतीक है। अध्यक्ष की निष्पक्षता निम्नलिखित ऋष्या से प्रमाणित होती है

(1) लोक सभा का अध्यक्ष सम्पूर्ण संसदीय अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 1958 तक फ्रांस का स्पीकर नेबल एन सत्र के लिए निर्वाचित होता था, उसने अंत में उसकी योग्यताओं एवं कार्यक्षमताओं के आधार पर अगले सत्र के लिए पुनः नियुक्त किया जाता था। किन्तु अब फ्रांस ने भी इसी ब्रिटिश पद्धति को अपना लिया है।

(2) स्पीकर जिस समय तक चाहे अपने पद पर आसीन रह सकता है, यह परम्परा रही है। नवीन लोक सभा भी प्रायः पुराने स्पीकर का ही अनुमोदन करती

है। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि अध्यक्ष कितना निष्पक्ष रूप से व्यवहार करता है। ऑनस्लो (Onslow) 44 वर्ष तक लोन्स सभा के अध्यक्ष था रहे, दस सत्र लेकर पंद्रह वर्ष तक की अवधि के लिए स्पीकर बना रहना तो साधारण बात है पद की दीर्घावधि अथ सदस्यों की अपेक्षा एक शक्तिशाली स्थिति में रहती है।

(3) अध्यक्ष पद के लिए लोन्स सभा वैकल्पिक उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित कर सकती है किंतु 1839 से यह परम्परा रही है कि प्रमुख दल एकमत होकर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करते हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किया जा सके। वे प्रायः किसी पुराने मंत्री आदि का नाम प्रस्तावित नहीं करते जिससे सम्बन्ध में विवाद उठ सके हो।

(4) बहुधा जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर निर्वाचित होता रहता है वहाँ से परम्परानुसार अथ राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते। 1714 से लेकर अब तक बहुत ही कम ऐसे अवसर आय हैं जबकि स्पीकर के मुकाबले अथ राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हों। 1935 में श्रमिक दल ने इस परम्परा को तोड़ने का असफल प्रयत्न किया था।

(5) अध्यक्ष पद ग्रहण करने पर स्पीकर सब राजनीतिक दलों से अपने सम्बन्ध बिच्छेद कर लेता है। वह किसी राजनीतिक बलब सत्ता का सदस्य नहीं रहता। वह अपने शरीर पर किसी भी राजनीतिक दल का बोर्ड बिह्व धारण नहीं करता।

(6) अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है जैसे शायद ही कभी इसके प्रयोग की आवश्यकता हुई हो। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का स्वस्थ सन्तुलन इसके लिए उत्तरदायी है। यदि इसकी आवश्यकता भी पड़े तो स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग इस रूप में करता है जिससे शासन का परिवर्तन न हो।

(7) वह किसी भी वाद विवाद में भाग नहीं लेता।

(8) स्पीकर को यह आवश्यकता नहीं होती कि वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र को मुट्ठी में रखे। उसके पड़ोसी सदस्य उसके निर्वाचन-क्षेत्र की देखभाल रखते हैं।

(9) सदन के कार्य संचालन में भी वह पूर्ण निश्चित एवं निष्पक्ष भाव से कार्य करता है।

(10) 1917 के विधेयक ने धन विधेयकों के सम्बन्ध में उसके नियम को अंतिम माना है जो उसकी निष्पक्षता का प्रतीक है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कतव्य (Powers and Functions)

अध्यक्ष के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रमुख तथा प्रभावशाली। प्रमुख कार्य वे हैं जिनका सम्पादन वह नित्य प्रति के कार्यों हेतु सभापति के रूप में करता है। उदाहरण के लिए, वाद विवादों का संचालन एवं भाषणों का नियमन। प्रभावशाली कार्यों का सम्बन्ध सदन की सामान्य कार्यविधि से है। अध्यक्ष के काम निम्न प्रकार हैं

(1) नियमों की व्याख्या (Interpretation of Rules)—सदन में नियमों की व्याख्या अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उसका नियम अंतिम होता है। अन्य समान

अवसरो पर उसके निणयो को 'यायालयो के सदस्य बतौर नज़ीर प्रस्तुत किया जाता है। एक बार तो उत्पन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा दिये गये निणयो का अनुपालन होगा ही, चाहे बाद में सदन के प्रस्ताव द्वारा उसमें परिवर्तन ही क्यों न हो जाय।

(2) भाषणों की व्यवस्था (Arrangement of Speeches)—यह अध्यक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वाद विवाद का स्वरूप क्या होगा और उसमें कौन-से वक्ता भाग लेंगे, इसका निश्चय स्वीकार करता है। कौन-से वक्ता को भाषण में प्राथमिकता दी जाय, इसका निणय भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को सावधानी से ध्यान में रखे कि अल्पसंख्यक प्रति निधियों को 'यायिक अनुपात में भाषण करने का अधिकार मिला है अथवा नहीं। इससे वक्तृता का स्तर बहुत ऊँचा बन पड़ता है।

(3) सदन में सुव्यवस्था बनाये रखना (Maintenance of order in the House)—किसी भी संसदीय व्यवस्था का कुशल संचालन सदन की सुव्यवस्था पर अवलम्बित है। सदन में अनुशासन बनाये रखना अध्यक्ष का मूल उत्तरदायित्व है। इसके लिए उसे सदस्यों के व्यवहार असंसदीय भाषा तथा अप्रासंगिक बातों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जब सदन का कोई सदस्य उद्दण्डता का व्यवहार करता है अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करता है तब अध्यक्ष उस सदस्य को निष्कासन का आदेश देता है। यदि सदस्य इस पर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता तथा अध्यक्ष के आदेश की परवाह नहीं करता तो उस स्थिति में अध्यक्ष सारजेंट एट आम्स को उसे सदन से बाहर निकालने का आदेश देता है। अध्यक्ष अथवा अन्य किसी सदस्य के इस प्रस्ताव पर कि उस सदस्य को शेष संसदीय कार्यावधि के लिए निलम्बित कर दिया जाय, सदन विचार करता है। अध्यक्ष दुर्व्यवहार करने वाले सदस्य को पूर्ण एक मन्त्र के लिए निलम्बित कर सकता है। अतः सदन में व्यवस्था बनाये रखना अध्यक्ष का कर्तव्य है।

(4) वाद विवाद समापन का निणय (Decision to Wind up the Debate)—वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकता है। यह अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार। अध्यक्ष को इस दिशा में कोई भी निणय करने से पूर्व यह देखना पड़ता है कि सदन में अल्प संख्यकों को अपने विचार व्यक्त करने के पूर्ण अवसर प्राप्त हो चुके हैं अथवा नहीं। जब तक अध्यक्ष पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हो जाता वह आगे नहीं देता।

(5) प्रश्न अथवा सशोधन का चयन (Selection of Question or amendment)—प्रश्ना तथा सशोधनों के चयन के विषय में अध्यक्ष को पूर्ण स्वतन्त्रता है। किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से सशोधनों की प्रशस्ति की जाती है। वे सभी महत्वपूर्ण नहीं होते। समयावधि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष ही इस बात का निणय करता है कि कौन से सशोधनों को अधिक महत्वपूर्ण समझकर स्वीकार किया जाय। इसी प्रकार प्रश्ना का चयन भी अध्यक्ष के द्वारा होता है। सदन में बहुत-से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका निणय सदन का अध्यक्ष ही करता है।

कि कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है अथवा नहीं। अध्यक्ष का नियम व्यावहारिक रूप से गुणकारी सिद्ध हुआ है।

(6) सदन का प्रवक्ता (Advocate of the House)—सदन की गरिमा, सदस्यों के विशेषाधिकार, मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा बनाये रखने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। सदन के अधिवक्ता के रूप में वह सम्राट और उसके मध्य एक बड़ी के रूप में कार्य करता है। वित्त विधेयकों की लॉर्ड सभा में प्रस्तुति अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। सम्राट के पास निंदा अथवा धन्यवाद प्रस्ताव आदि उसी के द्वारा प्रेषित किये जाते हैं।

(7) धन विधेयकों का प्रमाणीकरण (Certification of Money Bills)—1911 के अन्तर्गत अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन-विधेयक है अथवा नहीं इसे अध्यक्ष प्रमाणित करता है। उसका नियम अंतिम होता है। किसी भी सावजनिक विधेयक के सम्बन्ध में तत्काल ही वाद विवाद हो इसका एकमात्र नियम अध्यक्ष पर है। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर स्वीकृति अध्यक्ष देता है।

अध्यक्ष ही इस बात का नियम करता है कि सदन की बैठक कब बुलाई जाय और उसका सत्रांत कब हो। इस विषय में वह प्रधानमंत्री का परामर्श लेता है। लोक सभा में कोई स्थान जब रिक्त हो जाता है तो उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष ही आपत्ति निकालता है। किसी भी सदस्य के गिरफ्तार होना की स्थिति में समावेश का प्रसारण अध्यक्ष करता है। जब कोई मंत्री सदन में पूछे गये प्रश्न के उत्तर को टालने की तथा सूचना न देने की कोशिश करता है और जिसे स्पीकर सावजनिक हित में समझता है, उसे निबलवाने के लिए वह मंत्री विशेष को बाध्य कर सकता है। किंतु उक्त शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष बहुत ही सावधानी के साथ करता है जिससे उसकी निष्पक्षता तथा पद की प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार की आघात न आने पाये। स्पीकर पद के लिए कोई विशेष शक्षणिक योग्यता तथा असामान्य बौद्धिक विलक्षणता की आवश्यकता नहीं है वरन् मध्यम श्रेणी के ही व्यक्ति प्रायः स्पीकर बनते रहे हैं। आवश्यकता है अपने काम में आस्था विश्वास तथा निष्पक्षता की। लॉर्ड रोजबरी (Rosbery) के इस कथन में एक चुभता हुआ सत्य है कि 'सब स्पीकर अच्छे स्पीकर बन जाते हैं' (All speakers become good speakers)। जब सदन एक समिति के रूप में एकत्रित होता है तो उस समय उसका अध्यक्ष पद स्पीकर ग्रहण नहीं करता। डॉ. जेनिंग्स (Jennings) के मत में स्पीकर जिस प्रतिष्ठा तथा शक्तियों को प्राप्त किये हुए होता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।

राजा का विरोधी दल (His Majesty's Opposition)

महत्व (Importance)

विरोधी दल सरकार का अति आवश्यक अंग है। ब्रिटन में उसे सरकारी भाष्यता देकर यह प्रयास किया गया है कि सरकार की स्वस्थ आलोचना हाती रहे जोकि लोकतन्त्र का मूल है। यही स्वशासन का आधार है। विरोधी दल सबदा वकल्पित होती है। इसका एकमात्र आशय यह है कि नियम में बहुमत के मत का ही

मूल्य होगा किंतु अल्पमत के पक्ष को भी सुना जाय। स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों में परस्पर सम्बन्ध बना रहे। लोकमत के निर्माण में विरोधी दलों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वे नयी दिशा व नय विचार देते हैं। सत्ताधारी दल को यथाथ में भाँकना चाहिए और यथाथ का निर्माण विरोधी पक्ष के सहयोग से होता है। विरोधी दल शासकीय नीतियों की आलोचना के द्वारा सरकार का उद्दिष्ट प्रकट करता है और उसे राष्ट्र के हित में उपयुक्त नीति अपनाने के लिए विवश करता है।

विपक्षी दल का उद्देश्य यह नहीं है कि रचनात्मक निर्माण से विमुख होकर ध्वसात्मक नीति का समर्थन करे। इसका उद्देश्य तो केवल आलोचना करना है, न कि गत्यवरोध उत्पन्न करना। जब सरकार किसी ऐसी नीति को लागू करती है जो कि राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं है तो उस समय विरोधी दल सत्ताधारी दल के कार्यों की आलोचना करके एक बहुत बड़ा काम करता है। यह आवश्यक नहीं है कि विरोधी दल सदा विरोध करता रहे। कभी कभी वह ऐसे सुझाव भी देता है जिनको स्वीकार करने में सत्ताधारी दल को कोई आपत्ति नहीं होती है। विरोधी दल सरकार की निरपेक्ष नीति पर एक बहुत बड़ा अकुश है। जब सरकार के विविध मंत्रालय अपने विभाग के सम्बन्ध में योजनाओं के लिए धन की माग करते हैं तो विरोधी दल को एक सुंदर अवसर मिलता है। वह सरकार की आलोचना करके उसे अपद्रव्य करने की कोशिश कर सकता है। विरोधी पक्ष के नेता को दो हजार पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है और अथ मंत्रियों की भाँति उसे सुविधाएँ भी दी जाती हैं। विरोधी दल का नेता ही वकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। जब लोक सभा किसी समारोह की विशेष औपचारिकता का निर्वाह करती है तो उस समय विरोधी दल का नेता प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होता है। ब्रिटेन में केवल दो ही राजनीतिक दल हैं। इसमें विरोधी दल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इंग्लण्ड में विरोधी दल इतना शक्तिशाली होता रहता है कि सरलता से उसकी उपेक्षा नहीं हो पाती। यह सही कहा गया है कि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी की अपेक्षा विरोधी दल के नेता को अधिक अच्छी प्रकार से जानता है।

विपक्ष का संगठन (Organization of the Opposition)

भासब दल की भाँति विपक्ष के पास भी अपने सचेतक (Whips) होते हैं। विपक्ष के पास भी छाया मंत्रिमण्डल होता है जिसमें विरोधी दल के नेता का स्थान सर्वोच्च होता है। इसके सन्सों के सुपुत्र पृथक् पृथक् कार्य होते हैं। विपक्षी दल इसी के कारण सत्ता ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। सदन की समितियों में पक्ष तथा विपक्ष दोनों को ही सदस्यता के अवसर प्रदान किये जाते हैं। छाया मंत्रिमण्डल को कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। यदि श्रमिक दल शक्तिशाली नहीं होता तो वह विपक्ष का निर्माण करता है। इसकी सप्ताह में कम से कम दो बैठकें होती हैं। इसकी सप्ताहिय कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचेतक तथा 12 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का प्रत्येक वर्ष पुनः निर्वाचन होता है। यह आशा की जाती है कि वही भावी प्रधानमंत्री होगा। कार्यकारिणी में 3 पीयर भी होते हैं।

जहाँ तक अनुदार दल का प्रश्न है उनके नेता की स्थिति बहुत ही अधिक

दड़ होती है। सामान्य निर्वाचनों में पराजित हो जाने पर भी यदि प्रधानमंत्री पुनः लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होकर आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह विरोधी दल का नेता बनता है। श्रमिक दल की भाँति प्रत्येक वृष उसका पुनः निर्वाचन नहीं होता। अपने छाया मंत्रिमण्डल के माधियों की चुनने के लिए वह स्वतंत्र है। वह चाहता एक उपनेता की भी नियुक्ति कर सकता है। चर्चिल ने एथानी ईडन को उपनेता बनाया था तथा मैकमिलन ने बटलर को।

विपक्ष के कार्य (Functions of the Opposition)

(1) आलोचना (Criticism)—विरोधी दल का यह प्रमुख कार्य है। जेनिंग्स के शब्दों में सदन आलोचना कर सकती है वह नियंत्रण नहीं कर सकती। "यदि सदन का प्रमुख कार्य आलोचना करना है तो विपक्ष उसका प्रमुख अंग है।" विपक्ष जनता की भावना को सत्तारूढ़ दल के समक्ष रखता है, मंत्रियों से प्रश्न करता है, तथा सरकारी कार्यों की त्रुटियाँ पर प्रकाश डालता है। लोकमत के निर्माण में इसका विशेष हाथ है। विपक्ष निर्भीकता के साथ कार्य करता है।

(2) शासन की बकल्पिक नीति का प्रचार (Alternative Government Policy)—विरोधी दल जनमत को अपने पक्ष में करने की सोचता है। सरकार की नीतियों की कमजोरियों को जनता के समक्ष रखता है, वर्तमान शासन को अयोग्य तथा असहनीय बताता है। सामंतीय नीति के विपरीत अपनी नीति रखता है। इस प्रकार जनता के सामने दो विकल्प सदा बने रहते हैं। 1945 के बाद अनुदारवादी दल की नीतियों का मतदाताओं ने समर्थन नहीं किया तथा चर्चिल शासन को अपदस्थ होना पड़ा। श्रमिक दल की नीतियाँ न उन्हीं अधिक प्रभावित किया। सदन में स्वयं का वाद विवाद निर्वाचन का अभ्यास है।

(3) शासकीय नीति को प्रभावित करता है (Influences administrative Policies)—सत्ताधारी दल विपक्ष की नज़र पर हाथ रखता है, विपक्ष की आलोचना का कम से कम मौका मिले इसका प्रयत्न करता है। यह बात नहीं है कि विपक्ष की आलोचना का सत्ताधारी दल पर कोई प्रभाव नहीं होता, विपक्ष की आलोचना के प्रकाश में सत्ताधारी दल विविध प्रकार के प्रशासकीय संशोधन कर लेता है। सत्ताधारी दल सदा इस बात के लिए सचेष्ट रहता है कि विपक्ष कहीं जनता पर हावी न हो जाय।

(4) लोकतंत्र की सुरक्षा (Safeguard of Democracy) विपक्ष जनता को दीक्षित तो करता ही है साथ ही जनता की कठिनाइयाँ को शासन के समक्ष रखता है और उनमें वाछनीय परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विपक्ष लोकतंत्र की एक महान् शक्ति है। लोकतंत्र आलोचना के आलोक में पनपता है, बौद्धिक विकास उसका लक्ष्य है। विपक्ष अधिनायकतंत्र पर अकुश है और उसका भयानक स्वरूप के विरुद्ध सुरक्षा भी। जेनिंग्स (Jennings) के शब्दों में, "जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायकतंत्र नहीं आ सकता। विपक्ष लोकतंत्र का कंलशियम है।

ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में हम उस आक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकते जो प्रायः राजनीतिक दलों के विरुद्ध लगाया जाना है कि वे विरोध केवल

विरोध के लिए ही करते हैं। वहाँ द्वितीय व्यवस्था होने के कारण सत्ताधारी दल कभी भी इस बात का विस्मरण नहीं करता कि विरोधी पक्ष तथा उसकी नीतियाँ वैकल्पिक नीतियों तथा सरकार का निर्माण कर सकती हैं। व्यवस्था पर विपक्षी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेन में बहुमत दल विरोधी दल को कभी कुचलने का प्रयत्न नहीं करता, स्पीकर के मनोनयन का विरोधी पक्ष सदा समर्थन करता है। लोक सभा के दोनों पक्ष इस बात को मिलकर तय करते हैं कि किस विषय पर विचार किया जाय अथवा नहीं। किसी राष्ट्रीय संकट अथवा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के उत्पन्न होने पर प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को अपने विश्वास में लेता है। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए 1945 में निर्वाचन परिणामी की घोषणा होने से पूर्व चर्चिल ने श्रमिक दल के नेता लॉर्ड एटली को पोर्ट्सडाम सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया था। राष्ट्रीय संकट के समय दोनों दल एक हो जाते हैं। 1939 में जोसेफ चैम्बरलेन के स्थान पर सर विंसटन चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। सदन में अत्यन्त इस बात का ध्यान रखता है कि विपक्ष के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अधिक सं अधिक समय मिलना चाहिए, विपक्षी दल के महत्व को प्रदर्शित करते हुए डा० जनिंग्स (Jennings) ने कहा है कि 'यह जानने के लिए कि अमुक जाति राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है अथवा नहीं, केवल यह जान लेना आवश्यक है कि वहाँ विपक्ष है अथवा नहीं।' ("To find whether a people is politically free, it is necessary only to ask if there is an opposition")

लोक सभा के कार्य और कर्तव्य

(Powers & Functions of the House of the Commons)

(1) व्यवस्थापन विधेयक (Legislative Powers)—कानून निर्माण की वास्तविक शक्ति लोक सभा में है, वैसे धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सब विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रकृति के विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं। साधारण श्रेणी के विधेयकों को लाइ सभा अधिक समय तक नहीं रोक सकती। वह अधिक से अधिक 1 वर्ष तक साधारण विधेयकों को रोक सकती है। सदन को जब हम वैधानिक सभ्य कहते हैं तो उससे हमारा आशय हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होता है। साधारण तथा संवैधानिक दोनों प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार लोक सभा को प्राप्त है। इसका व्यवस्थापन क्षेत्र अति व्यापक है। इसके द्वारा निर्मित नियमों के पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है इसमें कामन्स सभा का स्तर ऊँचा ही उठा है।

लोक सभा की व्यवस्थापन सम्बन्धी उपर्युक्त शक्तियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है उसमें सिद्धांत अधिक तथा यथार्थ कम है। व्यवस्थापन का सारा काम मंत्रिमण्डल करता है। महत्वपूर्ण सावजनिक मंत्रिमण्डल विधेयक मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रत्याधिकृत विधान के कारण लोक सभा की व्यवस्थापन शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, किन्तु मंत्रिमण्डल लोक सभा के ऊपर

तभी तब हाथी रह सकता है जब तक कि उसका बहुमत रहता है। व्यक्तिगत विधायक वही सफल हो सकता है जिन्हें मंत्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त हो।

(2) **बायपासिंग पर नियंत्रण (Control over Executive)**—मंत्रिमण्डल के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना लोक सभा का जटिल एवं प्रमुख कार्यों में से एक है। मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली का मूल है उत्तरदायी शासन। लोक सभा इस उत्तरदायित्व को कई माध्यमों से स्थापित करने में सफल हो जाती है। इनमें से एक साधन है प्रश्न पूछना। लोक सभा के सदस्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों से प्रश्न तथा पूरे प्रश्न पूछकर शासकीय नीति का स्पष्टीकरण कराते हैं। स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) रखकर सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार से लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव (Non Confidence Motion) के द्वारा बायपासिंग पर नियंत्रण स्थापित करती है उस त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है। निंदा प्रस्ताव द्वारा भी सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Call Attention Motion) द्वारा भी प्रशासकीय तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करती है।

(3) **वित्तीय अधिकार (Financial Powers)**—राष्ट्रीय वित्त पर लोक सभा का पूर्ण नियंत्रण है। वार्षिक आय तथा व्यय का बजट लोक सभा की स्वीकृति हेतु मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिना लोक सभा की स्वीकृति के कोई नवीन कर नहीं लगाया जा सकता तथा किसी व्ययमान को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक विभाग को धन विषयक अभियाचिकाओं को लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव का प्रयोग करने लोक सभा उस विभाग के जिया कलापी पर प्रकाश डालती है। पूरे भागों की स्वीकृति भी लोक सभा देती है। इससे अतिरिक्त वित्त विधेयक (Finance Bill) पर भी लोक सभा को अवसर प्राप्त होता है कि शासकीय नीतियों की आलोचना कर सके। लोक सभा व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सदन की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) यह देखती है कि धन स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यय हो रहा है अथवा नहीं। अतः राष्ट्रीय वित्त पर लोक सभा का पूर्ण नियंत्रण है।

(4) **जनता की शिकायतों को दूर करना (Removal of Public Grievances)**—आग तथा जिं क न लोक सभा को राष्ट्र का दर्पण कहा है। विरोधी पक्ष को जनता की स्वतंत्रता का रक्षक कहा गया है। लोक सभा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ जनता की शिकायतों की सुनवाई की जा सकती है। कामस सभा विचार विमर्श के द्वारा उन तरीकों को खोज निकालती है जिनसे जनता की शिकायतें दूर की जा सकें। जनता पर जो अत्याचार किये जाते हैं वे सब सदन में रखे जाते हैं। सरकार का ध्यान इन घटनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है। बर्क (Burke) के शब्दों में, लोक सभा की सामान्य भावना एवं सार यह है कि वह राष्ट्र की सच्ची आवाज है।

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

विश्व की अधिकांश व्यवस्थापिकाओं ने व्यवस्थापन प्रक्रिया के क्षेत्र में ब्रिटिश प्रणाली का ही अनुकरण किया है। विधि निर्माण संसद का प्रमुख कार्य है। विधि निर्माण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक में कार्यपालिका के अधिनायकत्व पर नियंत्रण है। जटिलता को विधि निर्माण प्रक्रिया का गुण नहीं कहा जा सकता। यह सरल होनी चाहिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया निश्चित करने से लोकमत को भी बल मिलता है। इसका रूप जितना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित होगा उतनी वह प्रभावशाली बन पड़ेगी। विधि निर्माण विशेष योग्यता का विषय है। विधायी प्रक्रिया पर संसद का सम्मान बहुत कुछ अवलम्बित है। ब्रिटेन में विधेयक निम्न प्रकार के होते हैं

(1) **सार्वजनिक विधेयक (Public Bill)**—सार्वजनिक प्रकार के विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से हो अथवा देश के अधिकांश भाग से हो। उदाहरण के लिए कर लगाने से सम्बन्धित विधेयक। सार्वजनिक विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं

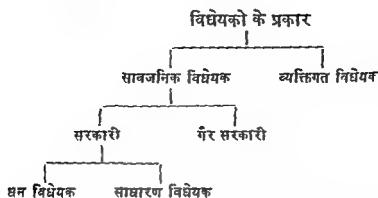
(क) **व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विधेयक (Private Members Bill)**—जब कि सार्वजनिक प्रकार का कोई विधेयक सरकार द्वारा न रखा जाकर सदन में किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब हम उसे निजी सदस्य द्वारा विधेयक कहते हैं। इस प्रकार के विधेयक बिना सरकार की सहायता के स्वीकृति की अंतिम मजिल तक नहीं पहुँच पाते। इनकी स्वीकार अथवा अस्वीकार होने की दशा में मंत्रिमण्डल की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता।

(ख) **सार्वजनिक विधेयक (Public Bill)**—जब सार्वजनिक विधेयक सरकार के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं और जिनकी सफलता अथवा असफलता पर सरकार का अस्तित्व अवलम्बित है उन्हें सही रूप में सार्वजनिक विधेयक कहा जाता है। वैसे तो अब सार्वजनिक विधेयकों के भी दो भाग हैं

(1) **धन विधेयक (Money Bill)**—ये वे सार्वजनिक प्रकार के विधेयक होते हैं जो व्यय से सम्बन्धित होते हैं और जो सदन ही मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य द्वारा रखे जाते हैं। वे केवल लोक सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसको प्रमाणित करने का एकमात्र अधिकार लोक सभा के अध्यक्ष को है।

(2) **साधारण विधेयक (Ordinary Bills)**—ये किसी भी सदन में मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

(2) **व्यक्तिगत विधेयक (Private Bill)**—व्यक्तिगत विधेयक सार्वजनिक विधेयकों के विपरीत निजी नगरपालिका अथवा किसी वग विशेष से सम्बन्धित होते हैं। किसी विशेष स्थान में सुधार लाने के लिए भी व्यक्तिगत विधेयक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत विधेयक का सम्बन्ध सार्वजनिक हित से नहीं होता। ऐसे विधेयक जिस समय तक सत्ताधारी दल का समर्थन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते उस समय तक हम उनके पारित होने की आशा नहीं करते।



व्यक्तिगत तथा सावजनिक विधेयको में अन्तर (Distinction between Public Bill and Private Bill)—(1) सावजनिक विधेयक व्यापक होते हैं, उनका सम्बन्ध अधिकांश क्षेत्र अथवा जनता से होता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत विधेयक संकुचित होते हैं और उनका सम्बन्ध भी अधिकांश जनता अथवा क्षेत्र से नहीं होता है।

(2) सावजनिक विधेयक में एक श्रेणी धन विधेयको की भी होती है और ऐसे विधेयक मंत्रिमण्डल द्वारा ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, व्यक्तिगत विधेयक धन विधेयक नहीं होते।

(3) सावजनिक विधेयक एक सुसंगठित प्रस्ताव के रूप में रखे जाते हैं और व्यक्तिगत विधेयक प्रायः पत्रों (Petitions) के रूप में।

(4) व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक (Private Members Bill) तथा व्यक्तिगत विधेयक (Private Bill) एक नहीं है। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक सावजनिक विधेयको की श्रेणी में आते हैं जबकि व्यक्तिगत विधेयक उस श्रेणी में नहीं आते।

(5) सावजनिक विधेयक यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर सरकार का भविष्य अवलम्बित रहता है किन्तु व्यक्तिगत विधेयक के सम्बन्ध में यह बात सही नहीं है।

(6) सावजनिक विधेयको की प्रक्रिया भी व्यक्तिगत विधेयकों से भिन्न होती है।

सावजनिक विधेयक विधेयक प्रक्रिया (Procedure on a Public Bill)

प्रथम सोपान (First Reading of the Bill)—विधेयक की प्रस्तुति (Introduction of the Bill) विधि निर्माण की प्रक्रिया में सबसे प्रथम सोपान विधेयक की प्रस्तुति है। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। विधेयको की प्रस्तुति से सम्बन्धित तीन तरीके हैं।

(क) साधारण प्रस्तुति (Ordinary Presentation)—फाइवर ने विधेयक की प्रस्तुति की इस विधि को सराहना की है इसका अन्तर्गत प्रस्तुतकर्ता को सदन के समक्ष विधेयक की प्रस्तुति में कोई भाषण नहीं करना पड़ता। प्रस्तावक उस बिल को जमा करा देता है। तत्पश्चात् वह स्वयं अथवा सदन का लिपिक उसके शीपक को पढ़कर सुना देता है। प्रत्यक्ष सदन की गाय जान लेता है कि उस विधेयक की स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। यदि सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो यह विधेयक का

प्रथम वाचन (First Reading) समझा जाता है। इसी के साथ उसे छपवाने की अनुमति भी मिल जाती है।

(ख) दस मिनट का नियम (Ten minutes rule)—महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विधेयको के सम्बन्ध में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावक तथा विपक्ष के एक सदस्य को विधेयक के उद्देश्य तथा श्रेय के विषय में बोलने को कहा जाता है। मन्त्रिमण्डल के छोटे समय में ही प्रकाश डालने के बाद सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अमुक विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय, स्वीकृत हो जाने पर विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त समझा जाता है।

(ग) लम्बे भाषण का नियम (Rule of Long Speech)—विधेयक की प्रस्तुति की इस विधि में काफी समय लगता है और इसीलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रस्तावक तथा विपक्ष के सदस्य लम्बे भाषण करते हैं। प्रस्तावक प्रशंसा करता है और आलोचक अवहेलना। एक पक्ष स्वीकार करने की बात कहता है, तो दूसरा पक्ष अस्वीकार करने की। स्वीकार होने पर विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त समझा जाता है।

द्वितीय वाचन (Second Reading of the Bill)—फाइनेर (Finer) ने ठीक ही कहा है कि द्वितीय वाचन विधेयक का परीक्षण होता है। विधेयक के जीवन में यह सबसे अधिक विस्मयोत्पादक महत्वपूर्ण एवं कष्टमय होता है। इस स्तर पर पक्ष तथा विपक्ष दोनों की ओर से विधेयक के उद्देश्य क्षेत्र एवं प्रभाव के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े भाषण होते हैं। विपक्षी दल को आलाचना का पूरा-पूरा अवसर मिलता है। वाद विवाद की तिथि पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। निश्चित तिथि को प्रस्तावक विधेयक के द्वितीय वाचन की अनुमति सदन से माँगता है। द्वितीय वाचन के समय विधेयक के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। यदि विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है तो मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वस्तुस्थिति को देखकर सरकार भी विधेयक को वापिस ले लेती है। 1936 में इसी प्रकार कायले की खाना के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक का विपक्ष के कठोर विरोध के कारण वापस ले लिया गया था। द्वितीय वाचन की समाप्ति के लिए प्रायः दो तरीके काम में लाये जाते हैं—पहली विधि यह है जब यह प्रस्ताव रख दिया जाता है कि विधेयक दोषपूर्ण है इस कारण उसे कानून न बनाया जाय। दूसरी विधि के अनुसार जब प्रस्तावक विधेयक को रखे कि उसका द्वितीय वाचन करा लिया जाय तब विरोधी पक्ष उसमें ऐसा कोई संशोधन रखे जिस पर सत्र के अन्त तक ही पूरा विचार न हो सके। उस स्थिति में विधेयक मर जाता है। यदि सरकार विधेयक को सत्ताधारी दल का समर्थन नहीं मिलता तो वे द्वितीय वाचन के ही समय समाप्त हो जाते हैं। यदि विधेयक द्वितीय वाचन पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे फिर समिति के पास भेजना तथा अन्य बातों की पूर्ति के लिए भेज दिया जाता है।

समिति स्तर (Committee Stage)—विधेयको का किसी न किसी समिति के पास भेजा जाता है। यदि वह वित्त विधेयक है तो सम्पूर्ण सदन की समिति के पास भेजा जाता है। अन्य श्रेणी के विधेयको को किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। विधेयको को कभी कभी किसी प्रवर अथवा विशिष्ट समिति

के पास भेजा जाता है। विधेयक के जीवन में समिति स्तर का महत्व भी कम नहीं होता। समिति में सदस्य के दोनो पक्षों के सदस्य होते हैं। वे बड़े ध्यान से विधेयक के अंग प्रत्यंग का अवलोकन करते हैं और आवश्यक सशोधन प्रस्तावित करते हैं। विधेयकों की उपयोगिता की दृष्टि से काट छांट भी करते हैं। बिल के शब्द शब्द पर विचार विमर्श किया जाता है। समिति में नियमों की कठोरता नहीं होती। कोई भी सदस्य अपने विचार कितने ही समय तक व्यक्त कर सकता है। लोक सभा का अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष नहीं होता। समिति विधेयक को सदन को लौटाते समय उसमें अपने सशोधन प्रस्तावित कर सकती है। यह सदन की इच्छा पर है कि वह उन्हें मान लें या नहीं। फाइनर (Finer) के शब्दों में, 'समिति में सरकार वास्तविक कार्य करने के लिए प्रस्तुत रहती है। सशोधनों को स्वीकार करके विधेयकों को अच्छा बनाती है।'

प्रतिवेदन स्तर (Report Stage)—प्रत्येक समिति अपने प्रतिवेदन के साथ विधेयक को पुनः सदन के पास लौटा देती है। इस प्रतिवेदन में सशोधन प्रस्तावित किये जा सकते हैं। प्रतिवेदन पर भी वाद विवाद होता है, किंतु सम्पूर्ण सदन समिति के पश्चात् यह स्तर केवल एक औपचारिकता मात्र है। यह सदन की इच्छा पर है कि प्रतिवेदन में प्रस्तुत सुझावों को वह स्वीकार कर लें या अस्वीकार। इस स्तर पर पहुँचने के पश्चात् विधेयक तृतीय वाचन के लिए तैयार हो जाता है। इस स्तर पर मतदान नहीं होता। विधेयक को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तृतीय वाचन (Third Reading of the Bill)—विधेयक के सिद्धांत, प्रभाव तथा क्षेत्र को लेकर द्वितीय वाचन के सदृश तृतीय वाचन पर भी वाद विवाद होता है किंतु कम विधेयक के सम्बन्ध में वाक्य प्रति वाक्य, शब्द प्रति शब्द विचार नहीं होता, वाद विवाद केवल विधेयक के व्यापक उद्देश्यों तक ही सीमित रहता है। विधेयक के लाभ तथा हानियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक के प्रत्येक भाग तथा अनुभाग को सदन की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। मतदान इसी स्तर पर होता है। तृतीय वाचन के सम्बन्ध में फाइनर (Finer) ने लिखा है कि 'इस द्वितीय वाचन की भाँति सम्पूर्ण विधेयक पर राजनीतिक विवाद होता है। यह एक राजनीतिक प्रदर्शन होता है'।

(The third reading like the second, a political debate on the whole Bill The third reading is a political mustering)

तृतीय वाचन के उपरान्त विधेयक द्वितीय सदन की स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। लॉर्ड सभा की स्वीकृति के पश्चात् विधेयक को राजा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है जो कि एक औपचारिकता मात्र है। यदि द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो वह पुनः विचाराय लोक सभा के पास भेज दिया जाता है। यदि लोक सभा उन सशोधनों को स्वीकार कर लेती है जो कि लॉर्ड सभा ने रगे हैं तो कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती। दिक्कत उस समय होती है जब लोक सभा सशोधनों को अस्वीकार कर दे तथा दोनों सदनों में गत्यावरोध उत्पन्न हो जाय इस गत्यावरोध को मिटाने के दो तरीके हैं—प्रथम यह कि दोनों सदनों में कुछ प्रतिनिधि लिए जाते हैं जो कि वहाँ की शब्दावली में प्रबंधक (Managers)

कहे जाते हैं, वे इस सधप को समाप्त कराने की कोशिश करते हैं। इनमे लोक सभा के सदस्यों की संख्या दुगुनी होती है। दूसरी विधि के अनुसार 1911 तथा 1949 के संसदीय विधेयकों की धाराओं का प्रयोग किया जाता है जिसके अनुसार लॉर्ड सभा में 1 वर्ष से अधिक विधेयकों को नहीं रोक जा सकता है। राजा की स्वीकृति मिल जाने पर विधेयक बिल बन जाता है और उसे सविधि पुस्तिका (Statute Book) में सम्मिलित कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत विधेयकों की सम्बन्ध में प्रतिक्रिया (Procedure on a Private Bill)

व्यक्तिगत विधेयकों की प्रकृति एवं स्वरूप के विषय में पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। वे सावजनिक विधेयकों से भिन्न होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से उनकी विधि निर्माण प्रक्रिया भी भिन्न होनी चाहिए। व्यक्तिगत विधेयक प्रायः स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में होते हैं और इनका लक्ष्य भी व्यापक नहीं होता। असावजनिक प्रकार के व्यक्तिगत विधेयक की प्रस्तुति किसी भी सदन में बाह्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत विधेयक प्राथना पत्रों के रूप में भेजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत विधेयक के संसद के साथ एक प्राथना पत्र (Petition) भी संलग्न होना चाहिए। प्राथना पत्र को प्रेषित करने से पूर्व उन व्यक्तियों को भी सूचित करना पड़ता है जिनके हित उससे प्रभावित होत हों। सूचना की एक प्रतिलिपि उस सरकारी विभाग का भेजनी पड़ती है जिससे कि वह सम्बन्धित है। जब यह कार्यवाही पूर्ण हो चुकती है उसके पश्चात् ही व्यक्तिगत विधेयक पर विचार किया जाता है। विधेयक की प्रस्तुति का शुल्क प्रार्थी को राजकोष में जमा कराना पड़ता है। इसके बाद व्यक्तिगत विधेयक की अग्य सोपाने आती है।

विधेयकों का परीक्षण (Examination of Petitions)—सर्वप्रथम विधेयक का परीक्षण होता है। उसके विविध पहलुओं पर विचार किया जाता है। विशेषतः इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक विधेयक नियमानुसार है अथवा नहीं। परीक्षक लोक सभा तथा लॉर्ड सभा से लिये जाते हैं। जब परीक्षक यह प्रमाणित कर देते हैं कि विधेयक नियमानुसार है तब उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित कर दिया जाता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन (First Reading) समझा जाता है।

द्वितीय वाचन (Second Reading)—इस स्तर पर विधेयक के उद्देश्यों पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है। यदि विधेयक निर्विरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे निर्विरोध विधेयकों की समिति (Committee of Unopposed Bills) के पास भेजा जाता है जो उसकी धाराओं पर विचार करके अपने प्रतिवेदन सहित वापस कर देती है। यदि विधेयक का विरोध हुआ है तो उसे व्यक्तिगत विधेयक समिति (Committee on Private Bills) के पास भेजा जाता है जो 'मायिक जांच' करके अपने प्रतिवेदन सहित विधेयक को वापस कर देती है। समितिवादी तथा प्रतिवादी की बातों को सुनती है। यदि समिति यह समझती है कि विधेयक अनुपयोगी है तो वह यही पर समाप्त हो जाता है। सदन के सभासद पहुँचने के बाद विधेयक का वाचन उसी रूप में होता है जिस रूप में कि अग्य विधेयकों का होता है। यदि विधेयक के पक्ष में समिति का प्रतिवेदन है तो वह प्रायः बिना वाद विवाद के ही सदन के द्वारा

स्वीकार कर लिया जाता है। समिति को वस्तुतः यह भी देखना पड़ता है कि विधेयक किसी सरकारी नीति के विरुद्ध तो नहीं है।

व्यक्तिगत विधेयकों के सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का अनुगमन किया जाता है वह कुछ भिन्न अवश्य है किन्तु उससे सदन का काफी समय बच जाता है। सदन उसके सम्बन्ध में तभी विचार करती है जब समिति व्यक्तिगत विधेयक के पक्ष में अपना प्रतिवेदन दे। अमेरिका तथा फ्रांस में विधेयकों में इस प्रकार का विभेद देखने को नहीं मिलता। और देशों में इसी कारण भरकारी विधेयकों में विधान मण्डल कम समय लगा पाते हैं और महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है। किन्तु इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मँहगी बहुत है। बकीला को बड़ी बड़ी फीसें देनी पड़ती हैं तथा गवाहों के बुलाने पर काफी पैसा व्यय होता है।

वित्त विधेयक विधेयक प्रक्रिया (Procedure over a Finance Bill)

जिस विधेयक का उद्देश्य कर लगाना तथा किसी वस्तुमान कर को समाप्त करना हो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। विभागों के द्वारा घनराशि के लिए जो अभियाचनाएँ रखी जाती हैं उन्हें कम करने का अधिकार तो सदन को प्राप्त है किन्तु उन्हें बढ़ाने का अधिकार उसे नहीं है। वित्त विधेयकों को प्रस्तावित करने के लिए सम्राट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। लोकसभा उन स्थितियों एवं साधना पर विचार करती है जिनके माध्यम से राजस्व प्राप्त हो सकता है। लोकसभा प्रत्येक विभाग द्वारा अनुमानों का परीक्षण करती है और यह निश्चय करती है कि प्रत्येक विभाग पर कितना व्यय होगा। लोकसभा यह देखती है कि धन का व्यय लोकसभा के आदेशानुसार हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार लोक सभा का आय तथा व्यय के ब्यौरे (Budget) पर पूर्ण अधिकार है। राजकोष पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण पूर्ण है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(1) लोकसभा में सम्राज्ञी की पूर्व अनुमति से विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किये जाते हैं। यह विधेयक का प्रथम वाचन होता है जबकि वह सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। बजट प्रस्तावित करने के लिये लोक सभा का बजट अधिवेशन होता है।

(2) दूसरे सेशन पर वित्त विधेयक के सिद्धांतों पर प्रभाव एवं क्षेत्र पर वाद विवाद होता है। यह उसका द्वितीय वाचन है। इसके पश्चात् धन विधेयक को समस्त सदन की समिति (Committee of the Whole House) को समर्पित कर दिया जाता है। समिति की विधेयक उसी समय समर्पित किया जाता है जबकि द्वितीय वाचन के स्तर पर उसके ऊपर पर्याप्त विचार ममाप्त हो चुकता है। जब सम्पूर्ण सदन की समिति विधेयक के व्यय पर विचार करती है, तो वह सम्पूर्ण समिति (Committee of Supply) कहलाती है। जब यह विधेयक के अंतर्गत धन की व्यवस्था के लिए साधनों पर विचार करती है, तो इसे साधन समिति (Committee of Ways and Means) कहा जाता है।

सावजनिक विधेयकों के सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी प्रक्रिया का प्रयोग धन विधेयक में भी किया जाता है अर्थात् उसका भी तृतीय

वाचन सावजनिक विधेयक की ही भांति किया जाता है। इसके पश्चात् वित्त विधेयक को लॉर्ड सभा के पास भेज दिया जाता है। लॉर्ड सभा उसे 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती। यह अवधि समाप्त होने पर घन विधेयक स्वतः ही वानून बन जाता है। रानी के हस्ताक्षर केवल एक औपचारिकता है। वित्त व्यवस्था भी अग्य विधेयक की भांति मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण में संगठित की जाती है। ब्रिटिश विधि निर्माण प्रक्रिया विश्व में आदर्श समझी जाती है।

अस्थायी आदेश (Provisional Orders)

व्यवस्थापन की जिन विधियों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें एक न एक दोष अवश्य है। इन दोषों की पूर्ति करने की दृष्टि से अस्थायी आदेशों की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत विधेयक ससद का काफी समय खा जाते हैं। सावजनिक विधेयकों में देर लगती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रार्थी अपनी कठिनाई से सम्बन्धित शासकीय विभाग को प्रार्थना पत्र समर्पित करता है। विभाग उसके सम्बन्ध में छान बीन करके तथा उससे प्रभावित होने वाले पक्षों की बात सुनने के पश्चात् निणय लेते हैं और प्रार्थना को यदि वे उचित मानते हैं तो उसके सम्बन्ध में प्रार्थी की कठिनाई को दूर करने के लिए अस्थायी आदेश प्रसारित करते हैं। इन अस्थायी आदेशों (Provisional Orders) से प्रार्थी को ससद की दीघगामी कामवाही का इतजार नहीं करना पड़ता। सावजनिक कार्यों के लिए भी इन आदेशों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात् जब बहुत से अस्थायी आदेश एकत्रित हो जाते हैं तो उन्हें एक प्रमाणित विधेयक (Confirmation Bill) के रूप में ससद के किसी एक सदन में प्रस्तावित करके प्रथम तथा द्वितीय वाचनों की कामवाही करने के उपरान्त किसी एक समिति को समर्पित कर दिया जाता है। समिति के प्रतिवेदन के आन के पश्चात् उसका तृतीय वाचन होता है और पारित होने के उपरान्त दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। बाद में वह सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करता है। अस्थायी आदेश 5 प्रकार के होते हैं

(1) कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनके लिए ससद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(2) कुछ आदेश आरम्भ से ही प्रभावी होते हैं किन्तु उन पर बाद में ससदीय स्वीकृति लेना आवश्यक होता है।

(3) कुछ आदेशों को 40 दिन की अवधि पूर्ण होने के अंदर ही अंदर ससद के समक्ष लाना आवश्यक होता है।

(4) कुछ आदेश उसी समय तक प्रभावी माने जाते हैं जब तक कि कोई बाहरी निकाय उन पर आपत्ति न करे।

(5) कुछ आदेश पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं और वे उस समय तक प्रभावी नहीं बनते जब तक कि उन्हें प्रमाणित विधेयक का अंग बनाकर उन पर ससदीय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

ब्रिटिश ससद में समिति व्यवस्था

(Committee System in British Parliament)

इंग्लैंड में समिति प्रणाली की व्यवस्था बहुत पुरानी है। 1882 में प्रथम

चार इनका समुचित रूप से संगठन किया गया था। वैसे इनका प्रारम्भ राजी एलिजाबेथ के समय में ही हो चुका था। आज तो उनका महत्व विधान मण्डलों के जीवन में इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक हो गया है कि कोई भी ससत्रीय व्यवस्था, चाहे वह कितनी ही स्वस्थ क्या न हो, इनकी अनुपस्थिति में जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने में सफल नहीं हो सकती। समितियाँ इस तथ्य की प्रतीक हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक काम हो। विधेयक का य सूक्ष्म परीक्षण ही नहीं करती बरन उसे उपयोगी बताती हैं। फाइनेर (Finer) के शब्दों में, "समिति व्यवस्था का मूल उद्देश्य अथ सस्याओं और अन्य समस्या के लिए कार्य हटाकर लोक सभा के कार्य भार की अधिकता को कम करना है।" आज के कानून निर्माण का कार्य अति प्रावधिकता के लिए हुए है जिसके लिए समितियाँ का रखना आवश्यक है। इससे न केवल समय की बचत होती है किन्तु साथ में स्वस्थ प्रकार की विधि का भी निर्माण होता है। इंग्लैण्ड में निम्नलिखित प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं।

(1) समस्त सदन की समिति (Committee of the Whole House)—इस समिति में सदन के समस्त सदस्य सम्मिलित रहते हैं। जब सदन समिति के रूप में कार्य करता है तो उसमें कुछ अंतर हो जाता है। समिति के रूप में जब सदन एकत्रित होता है तो अध्यक्ष अपना स्थान रिक्त कर देता है। समिति का अध्यक्ष उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। स्पीकर के पद का सम्मान बिहू मेज के नीचे रख दिया जाता है। कार्यवाही के नियम शिथिल हो जाते हैं। प्रस्तावों का अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं होती, सदस्याओं को बोलने की पूरी छूट मिल जाती है। उद्देश्यों के आधार पर सम्पूर्ण सदन की समिति के चार भाग किये जाते हैं। (1) सम्पूर्ण सदन की साधारण समिति (2) वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति, (3) स्पेल्स अथवा पूति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति, (4) अर्थोपाय (Means) की सम्पूर्ण सदन की समिति। जब सम्पूर्ण समिति की बैठक समाप्त हो जाती है, तब वह सदन की बैठक में परिवर्तित हो जाती है। स्पीकर पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। सम्पूर्ण सदन की समिति के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान रखने की है कि यह एक अस्थायी निकाम है जिसकी बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित की जा सकती है। सम्पूर्ण समिति की बैठकें बहुधा घन विधेयकों के सम्बन्ध में हुआ करती है।

(2) स्थायी समितियाँ (Standing Committees)—लोक सभा में इनकी संख्या पाँच है। साद सभा में केवल एक ही स्थायी समिति है। इंग्लैण्ड में इन समितियों को 'क', 'ख', 'ग' के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इन्हें विषय से सम्बद्ध किया जाता है, जैसे कृषि-समिति शिक्षा समिति आदि। साधारण विधेयक का जब द्वितीय वाचन हो चुकता है तो उसे अध्यक्ष द्वारा किसी न किसी स्थायी समिति के पास प्रेषित कर दिया जाता है। स्कॉटलैण्ड से सम्बन्धित मामलें स्कॉटिश समिति के पास भेज दिये जाते हैं। जिन विधेयकों में किसी नये सिद्धांत की उत्पत्ति होती हो वह किसी भी प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेज दिया जाता है। यदि विधेयक महत्वपूर्ण है तो उसे सम्पूर्ण सदन की समिति के पास भेजा जाता है। प्रत्येक स्थायी समिति में 30 से लेकर 50 तक सदस्य होते हैं। इनके अलावा प्रत्येक

Accounts Committee) (4) विशेषाधिकार समिति (The Committee on Privileges), प्रांकलन समिति (Estimate Committee), (6) परिनियत व्यवस्थापन समिति (The Committee on Statutory Instruments)।

(5) ध्यक्तित्व विधेयक समितियाँ (Committees on Private Bills)—इन समितियों का गठन केवल निजी विधेयकों पर विचार करने के लिए होता है। लोक सदन में इस प्रकार की समितियों की संख्या 4 है और लॉर्ड सभा में इसकी संख्या 1 है। इसके सदस्य चयन समिति द्वारा उस सूची में से लिये जाते हैं जोकि दोनों सदनों के सचिवों (Whips) द्वारा तैयार की जाती है। समिति का स्वरूप एक अर्द्धन्यायिक समिति (Semijudicial Committee) का होता है। किसी भी विधेयक पर विचार करने से पूर्व समिति के सदस्यों को यह घोषित करना पड़ता है कि अमुक विधेयक से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, अथवा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यह समिति उन सभी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा हितों को सुनती है जो किसी भी रूप में विधेयक से सम्बन्धित हैं। वादी तथा प्रतिवादियों की ओर से वकीलों को परवाी करने का अधिकार है, विधेयक के समस्त पहलुओं पर विचार करने समिति निष्पक्ष रूप से सदन को प्रतिवेदन समर्पित करती है जो सदन द्वारा स्वीकार कर ली जाती है।

(6) संयुक्त समिति (Joint Committee)—किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय का हल निकालने के लिए संयुक्त समिति की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 1933 में एक संयुक्त प्रचर समिति (Joint Select Committee) की व्यवस्था की गयी थी। इस समिति का अध्यक्ष लार्ड सभा का पीयर होता है। इस प्रकार की समितियों की रचना बहुत ही कम अवसरों पर इंग्लैण्ड के इतिहास में हुई है। इस समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है।

अतः इन समितियों को लघु विधान मण्डल की सहायता दी जाती है। इनका काम मुख्य तथा लोक सभा का काम गौण हो गया है। किन्तु फिर भी इनकी स्थिति अधीनस्थ संस्था की है। विधेयकों के सिद्धांतों के सम्बन्ध में ये कुछ नहीं करती। इनका काम तो केवल सुधार करना है। फाइनेर (Finer) के अनुसार “संशोधनों की सफाई करने के लिए ये नीचे काम करने वाली सहायक परिचारिकाएँ हैं।”

ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की समितियों की तुलना
(Comparison of the Committee System of Great Britain with that of U S A)

(1) इंग्लैण्ड में समितियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितनी अमेरिका में। इंग्लैण्ड में वे निष्पक्ष भाव से विधेयक पर विचार करती हैं तथा उस एक सगठित रूप प्रदान करके मन्त्रों को प्रतिक्रिया के रूप में वापस लौटा देती हैं। विधेयक में कोई आमूल-भूल त्रुटि पत्तरी परिवर्तन नहीं करती। इससे विपरीत अमेरिका में समितियाँ को लघुसंशोधन व विधान मण्डल की सहायता दी जाती है। वे त्रिम सीमा तक चाहें विधेयक में परिवर्तन कर सकती हैं यहाँ तक कि वे विधेयक का रूप एवं शीर्षक बदल कर उसे नया रूप प्रदान कर सकती हैं। सम्भवतः सभी-कभी विधेयक व प्रस्तावक का यह पहचानने में कठिनाई होती है कि क्या यह वही विधेयक है।

समितियाँ अमेरिका में विधेयक तक को समाप्त कर सकती हैं। वे निष्पक्ष नहीं होती। कानून को वास्तविक रूप में ही प्रदान करती हैं, यह कहना अनुचित नहीं है।

(2) इंग्लैंड में अधिक से अधिक 5 प्रकार की समितियाँ होती हैं जबकि अमेरिका में उनकी संख्या प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में 19 तथा 15 है।

(3) इंग्लैंड में स्थायी समितियाँ को क. ख. ग. घ. आदि शीपका से जाना जाता है। इसके विपरीत अमेरिका में उन्हें विषयगत रूप में जाना जाता है जैसे—शिक्षा समिति, विद्युत-समिति, कृषि समिति आदि। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में समितियों का गठन सामान्य उद्देश्यों के लिये हुए होता है और लोक सभा का अध्यक्ष कोई भी विधेयक किसी भी स्थायी समिति के पास भेज सकता है। किंतु अमेरिका में यह सम्भव नहीं है। वहाँ स्थायी समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिये हुए होता है और यह सम्भव नहीं कि शिक्षा सम्बंधी विधेयक को अन्य किसी समिति के पास भेज दिया जाय। वह शिक्षा समिति के पास प्रेषित किया जायगा।

(4) अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में समितियाँ विधेयकों में अधिक रुचि का प्रदर्शन करती हैं। इंग्लैंड में विधेयक को द्वितीय वाचन के उपरांत समिति के पास भेजा जाता है जब उसके सिद्धांतों के सम्बंध में पूर्णरूप से विचार हो चुकता है। समितियाँ आश्वस्त हो जाती हैं कि विधेयक स्वतः ही सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जायगा। किंतु अमेरिका में इसके विपरीत विधेयक समितियों के पास प्रथम वाचन के उपरांत भेजे जाते हैं जबकि उसके सामान्य उद्देश्य पर विचार पूर्ण नहीं हो चुकता। अतः समितियों को यह विश्वास नहीं होता कि विधेयकों को जो रूप वे देंगे वह स्वीकार कर लिया जायगा तथा विधेयक स्वीकार कर लिया जायगा।

(5) इंग्लैंड में समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोक सभा द्वारा गठित एक चयन समिति के द्वारा होती है। समितियों के अध्यक्ष पूर्णरूप में निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का सम्पादन करते हैं, किंतु अमेरिका में समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। किंतु व्यवहार में वे बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। वे निष्पक्ष भाव से कार्य नहीं कर पाते। वे दलीय आधार पर कार्य करते हैं।

(6) ब्रिटेन में समितियों के समक्ष गवाही देने की व्यवस्था नहीं है। साक्ष्यों की पूर्ति बहुमत तथा विपक्षीय दल के नेताओं द्वारा कर दी जाती है। इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत अमेरिका में यह व्यवस्था नहीं है और समितियों के समक्ष गवाही देने की आवश्यकता पड़ती है।

(7) ब्रिटेन में सरकारी, निजी सदस्य विधेयक तथा निजी विधेयक में अंतर किया जाता है। उनकी प्रक्रिया में भी भारी अंतर है। किंतु अमेरिका में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। वहाँ पर मंत्रिमण्डल के अभाव में सभी विधेयक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।

(8) इंग्लैंड में विधेयकों का नेतृत्व मंत्री करते हैं तथा इसके विपरीत अमेरिका में नायक समितियों के अध्यक्ष तथा नियम समिति (Committee of Rules) करती है।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन (Delegated Legislation)

लोक हितकारी राज्य के विकास के साथ साथ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन का भी उन्नी अनुपात में विकास हुआ है। सरकार को विविध प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और इस परिवर्तित स्वरूप की अपेक्षाओं का मुकाबला करने के लिए संसद को कानून निर्माण सम्बन्धी अपने अधिकार का एक बड़ा भाग विवश होकर शासकीय विभागों को देना पड़ता है। शासन की गति एवं गरिमा बनाय रखने के लिए और इसलिए कि वह समय के साथ अपने कदम मिलाकर चल सके, यह आवश्यक भी है कि शासकीय विभाग नियमों का सम्पादन कर उस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समय संसद का अधिवेशन भी उपलब्ध नहीं होता। आज का कानून भी दिन प्रतिदिन जटिल एवं प्रावधिक प्रकार का होता जा रहा है जो व्यापक ज्ञान की अपेक्षा करता है। जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता। संसद के पास काम का बोझ भी इतना रहता है कि चाह कर भी वह जनता की समस्त समस्याओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति करने में अपने को सफल नहीं पाती। और यह कार्यपालिका को करना पड़ता है। अतः प्रत्यायोजित व्यवस्थापन संसद द्वारा शासकीय विभागों को व्यवस्थापन सम्बन्धी दिये गये अधिकारों का प्रतिफल है। सरकारी विभाग जिन नियमों का निर्माण करते हैं उनका वही मूल्य होता है जो संसद द्वारा स्वीकृत कानूनों का।

डा० जैनिंग्स के शब्दों में, 'ज्यों ज्यों समूहवाद के विकास के कारण सरकारी शक्ति बढ़ती गयी त्यों त्यों प्रदत्त कानूनों की सहायता भी बढ़ती गयी है।' इंग्लैण्ड में 19वीं शताब्दी में प्रत्यायोजित व्यवस्थापन का विकास हुआ। 1870 के पश्चात् इसकी सहायता में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सबसे प्रथम प्रदत्त व्यवस्थापन स्थानीय स्वशासन तथा सावजनिक उपयोगिता के कानूनों तक सीमित था। 1906 के पश्चात् केन्द्रीय शक्ति का विकास और अधिक तेजी के साथ हुआ है और प्रशासकीय विभागों को जनता के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति के हेतु बहुत से नियम बनाने से सम्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 1932 में मंत्रियों की शक्ति समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "चाहे अच्छा हो या बुरा, पर इस परम्परा का विकास आवश्यक है। यह सर्वसामान्य कानून के क्षेत्र में हमारे सरकार सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन का स्वाभाविक प्रतिबिम्ब है, जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विचारों एवं वैज्ञानिक सोचों से हमारे जीवन की अवस्थाओं में आये हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है।'

इंग्लैण्ड में प्रदत्त व्यवस्थापन का सबसे अच्छा उदाहरण 1923 का रेटिंग तथा वेल्थ्युएशन एक्ट है। इसके अनुसार मंत्रियों को केवल आदेश जारी करने के अधिकार ही नहीं दिये गये बरन् प्रचलित प्रावधानों में भी परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1931 के आर्थिक सब्सिडी का सामना करने के लिए अनेक परिपक्व महित आदेश (Order in Council) प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। 1932 के ही नगर नियोजन अधिनियम (Town Planning Act) ने स्वास्थ्य मन्त्रालय को यह अधिकार दिया कि वह स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करके योजनाओं को लागू

करें। 1914 से लेकर 1916 तक ब्रिटिश क्राउन को युद्ध संचारण के लिए अनेक असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गयीं। 1931 में वित्त विभाग को विनिमय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सी शक्तियाँ दी गयीं। 1920 में सड़ककालीन शक्ति अधिनियम (Emergency Power Act) के द्वारा औद्योगिक झगड़ों के समय आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए सरकार को अनेकों शक्तियाँ प्रदान की गयीं। वर्तमान शताब्दी में तो प्रदत्त व्यवस्थापन की सराया कल्पना से भी परे पहुँच गयी है। 1890 में सरकारी विभागों द्वारा बनाये गये कानूनों की संख्या 168 थी। 1937 में यह बढ़कर 1500 हो गयी और 1945 में 1706 हो गयी। 1952 तक यह संख्या घट कर 706 रह गयी किंतु 1952 के बाद यह सराया फिर बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के कारण (Causes of Delegated Legislation)

(1) कल्याणकारी राज्य का उदय (Rise of Welfare State)—19वीं शताब्दी के पुलिस राज्य का स्थान अब लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है। राज्य का उद्देश्य अब केवल रक्षा करना मात्र नहीं रहा वरन् सत्रिय रुचि लेकर जन साधारण के स्तर का विकास करना हो गया है। इस कार्य का सम्पादन करने हेतु राज्य को अनेक नियम एवं उपनियमों की रचना करनी पड़ती है। संसद के पास कार्य का इतना आधिक्य है कि सबदा समय का अभाव रहता है। इसी कारण विधेयकों को वह रूपरेखात्मक स्वरूप में स्वीकार करके छोड़ देती है। शेष नियमों, उपनियमों एवं व्यापक कार्यों की पूर्ति शासकीय विभागों द्वारा होती है।

(2) कानूनों की प्रावधिकता में वृद्धि (Growth in the technicality of Legislation)—समाज की जटिलता के साथ कानून अब साधारण योग्यता वाले व्यक्तियों की वस्तु नहीं रहा। उसमें मूल्यांकन एवं प्रयोग के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। यह प्रावधिक योग्यता संसद के साधारण सदस्यों में नहीं पायी जाती। अतः संसद को विशेषज्ञों की सेवाओं पर स्वाभाविक रूप से निर्भर रहना पड़ता है। ये विशेषज्ञ हैं स्थायी कार्यपालिका के शासकीय कमचारी जो कानून की व्यावहारिक रूप से आँकते हैं।

(3) संसद के पास समयअभाव (Lack of time at the Disposal of Parliament)—संसद अब एक ही सत्र में इतने कानूनों पर विचार तथा उनका निर्माण करती है कि उसके पास सबदा समयअभाव बना रहता है। केवल विधि निर्माण ही नहीं वरन् इसके अतिरिक्त भी उसे अन्य कई प्रकार के विविध-कार्य करने पड़ते हैं जिससे उसे हमेशा ही अधिक समय की खोज करनी पड़ती है। इसी कारण विधेयकों के प्रारूप स्वयं तैयार नहीं करती। यह काम मंत्रिमण्डल करता है। संसद वास्तव में ही कार्यपालिका द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर अपनी स्वीकृति की छाप मात्र लगाती है।

(4) कानूनों के लागू करने में कठिनाई (Difficulty in implementing the Laws)—प्रदत्त व्यवस्थापन का औचित्य इस कारण से भी है कि कानूनों के आदेश तथा व्यवहार में अंतर हो सकता है। कानूनों को त्रिपाचित करने में वस्तुतः जो कठिनाइयाँ आती हैं साधारणतः हम उनका अनुमान नहीं लगा पाते, चाहे उनके निर्माण में कितनी ही होशियारी क्यों न दिखाई गई हो। संसद का अधिवेशन प्रत्येक समय नहीं

होता। इसी कारण विधायकों को स्पेरेमात्मक रूप में स्वीकार किया जाता है और उससे सम्बन्ध में उपनियमों तथा नियमों एवं अन्य बातों की पूर्ति का व्यापक काम कायपालिका के हाथों में छोड़ दिया जाता है।

(5) आपत्तिकात्मीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए (To meet an emergency)—सरकारनीन परिस्थितियों का उत्पन्न होना किसी भी राष्ट्र में कोई आवश्यकता की बात नहीं है। सरकाराल में वायपालिका की कई प्रकार के आदेश देने पड़ते हैं और उनमें से बहुत से गुप्त प्रचार के भी होते हैं। सदन का अधिवेशन तुरन्त आमन्त्रित करना कठिन हो सकता है। तात्कालिक परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से वायपालिका को सपरिषद आदेशों (Orders in Council) को प्रसारित करने का अधिकार दिया जाता है।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन की आलोचना (Criticism)

साड हीवट ने अपनी पुस्तक *New Despotism* में प्रत्याधिक व्यवस्थापन की बहुत आलोचना की है। उनमें ही शब्दों में सदन प्रदत्त व्यवस्थापन को न तो नियंत्रित कर सकती है और न ही इसकी जाँच कर सकती है। इसलिए यह सदन की पशुना पर बड़ा अतिक्रमण है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं

(1) इस बात का सदैव भय बना रहता है कि व्यवस्थापिका आवश्यकता से अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है।

(2) प्रत्याधिकृत शक्तियों से सम्पन्न पदाधिकारी केवल संगठित हितों का ध्यान रखते हैं तथा सावजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं।

(3) नियमों के सम्बन्ध में लोचनीयता घातक सिद्ध हो सकती है।

(4) नियमों के उचित प्रकाशन एवं प्रसार की व्यवस्था के अभाव में हो सकता है कि साधारण व्यक्ति उचित लाभ न उठा सके।

(5) नियम निर्माण करने वाले व्यक्ति उन बातों का ध्यान नहीं रखते जो राजनीतिक दृष्टि से भी उचित माने जाते हैं। कमचारी कई बार यह नहीं जान पाते कि जनता वास्तव में क्या चाहती है।

(6) यह बहुत कुछ सम्भव है कि नागरिक प्रशासकीय कमचारियों के आतंक के विरुद्ध अपने अधिकारों के सम्बन्ध में 'यायिक सुरक्षण' प्राप्त न कर पायें।

(7) इंग्लैण्ड में राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार परम्पराएँ हैं जिनसे इस बात की शका और भी बढ़ जाती है कि नागरिक अपने अधिकारों का 'यायिक सुरक्षण' सही रूप से प्राप्त न कर सकें।

(8) चाहे प्रत्याधिकृत व्यवस्थापन पर कितनी ही सीमाएँ क्यों न लगायी जायें किन्तु जब तक पुनः परीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होती उस समय तक सब व्यर्थ है।

प्रत्याधिकृत विधान के विरुद्ध सुरक्षाएँ (Safeguards against Delegated Legislation)

1929 में मंत्रियों के अधिकार से सम्बंधित जिस समिति की रचना की गयी थी उसने भी यह स्वीकार किया था कि प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति का

वायपालिका दुरुपयोग कर सकती है। उसने लिए सुरक्षात्मक रूप में समिति ने कई सुझाव भी दिये थे —

(1) प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाय।

(2) अधिकारियों की स्वविवेक शक्तियों की सीमाएँ निश्चित कर दी जायें जिससे वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें।

(3) प्रशासकीय विनियमों को समद की जानकारी के लिए भेजा जाय। 1944 में एक प्रवर समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रसारित आदेशों नियमों तथा उपनियमों का परीक्षण करके यह देखना था कि किस सीमा तक वे समदीय सावभौमिकता का उल्लंघन करते हैं। अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ इस कार्य का परीक्षण भी समिति को समर्पित किया गया था। हर्बर्ट मॉरीसन (Herbert Morrison) ने भी अपनी पुस्तक *Govt & Parliament* के पृष्ठ 151 पर लिखा है कि 'प्रत्याघिकृत व्यवस्थापन का सिद्धांत ठीक है, किंतु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि संसद उसकी सभी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखे।' (The principle of delegated Legislation is I think right but I must emphasise that is well for Parliament to keep a watchful and even jealous eye on it at all stages) प्रदत्त व्यवस्थापन पर नियंत्रण अत्यंत माध्यमों से भी रखा जा सकता है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

(1) सुनिश्चित सीमाएँ (Well defined Limits)—प्रदत्त व्यवस्थापन की सीमाएँ निश्चित होनी चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए।

(2) असाधारण कार्यों के लिए शक्तियों का प्रत्याधिकरण न किया जाय (Powers of extra ordinary nature should not be delegated)—उदाहरण के लिए करारोपण (Taxation) एक असाधारण कार्य है और उसके लिए शक्तियों का प्रत्याधिकरण सही नहीं माना जा सकता।

(3) संसदीय परीक्षण (Parliamentary Scrutiny)—लार्की (Lasky) के शब्दों में 'प्रत्याघिकृत व्यवस्थापन के विरुद्ध प्रतिवाद उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय उसे संसदीय परीक्षण के लिए समर्पित कर दिया जाता है।' (The protest against the delegated legislation collapses as soon as it is submitted to serious scrutiny) प्रत्याघिकृत व्यवस्थापन में यह शर्त लगायी जा सकती है कि बिना संसद की स्वीकृति के वह लागू न किया जाय। काम रोकों प्रस्तावों (Adjournment Motions) का प्रयोग भी प्रदत्त व्यवस्थापन पर कुछ हल्की सीमाएँ लगाने के लिए किया जाता है।

संसद की शक्ति का ह्रास (Decline of Parliament)

19वीं शताब्दी में इंगलैंड के स्यातिलव्ध विधिवेत्ता डाइसी (Dicey) ने संसदीय सावभौमिकता का अतिरंजन करते हुए लिखा था कि 'वह एक शिशु को प्रोढ़ घोषित कर सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही

कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मुकदमे में "यायाधीन बना सकती है," किंतु संसदीय संप्रभुता के सम्बन्ध में इसे सत्य नहीं मान सकते। वस्तुतः आज स्थिति यह है कि संसद की सत्ता क्षीण पड़ती जा रही है तथा मंत्रिमण्डल की शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। मंत्रिमण्डलीय रूपी नूतन संप्रभुता का उदय हो रहा है। मंत्रिमण्डल की सत्ता का हम नूतन अधिनायकत्व की सजा दे सकते हैं। रैम्से म्योर (Ramsay Muir) की शब्दावली में "मंत्रिमण्डल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है, उसकी कायबाहियाँ के शोरव को समाप्त कर दिया है और यह प्रतीत करा दिया है कि संसद का अस्तित्व सर्वगुणसम्पन्न एवं सर्वशक्तिमान नहीं है।" सत्य तो यह है कि संसद मंत्रिमण्डल के हाथों बिक चुकी है और सरकार की एक कठपुतली बनकर रह गयी है। कॉमन्स सभा ने अनेक बार अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति में असमर्थता प्रकट की है और कायभार के आधिक्य से उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गयी है। अब वह अयोग्यता से नियंत्रण एवं आधिपत्य बनाये रखने में अपने को असमर्थ पाती है। संसदीय सावभौमिकता अब केवल एक स्वप्न मात्र है। संसद की शक्तियाँ अब ह्रास के मार्ग पर हैं और इस ह्रास के कई कारण हैं—

विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र (Extensive Electoral Constituencies)—पहले निर्वाचन क्षेत्र छोटे हुआ करते थे। उम्मीदवार के लिए मतदाता से सम्पर्क स्थापित करना तथा अपने व्यक्तित्व की शक्ति का आधार पर निर्वाचन लड़ना अत्यंत सरल था, किंतु निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान विघातकार स्वरूप को देखते हुए अब यह सम्भव नहीं है कि कोई भी उम्मीदवार अपने सीमित साधनों से विजय प्राप्त कर सके। ब्रिटेन में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था तथा मतदाता में जागरूकता इतनी गहरी एवं व्यापक है कि निदलीय उम्मीदवार सफलता की आशा कर ही नहीं सकते। यह भी लगभग वही आवश्यकता है कि निदलीय उम्मीदवारों को किसी न किसी दल के साथ अपने को संलग्न करना पड़ता है। अथवा उसका कोई राजनीतिक महत्त्व स्थापित नहीं हो पाता। दल के साथ सम्बद्ध होने के पश्चात् उसे दलीय फठोर नियमों के नियंत्रण को स्वीकार करना पड़ता है। संसद में समस्त कार्यों का सम्पादन बहुमत दल की इच्छा द्वारा होता है। बहुमत दल की इच्छा वास्तव में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमण्डल की ही इच्छा है। संसद तो केवल मंत्रिमण्डल की इच्छा को पजीकृत करने वाला निकाय मात्र है।

सदन का विघटन (Dissolution of the House)—मंत्रिमण्डल के अधिनायकत्व का विकास तथा संसदीय शक्तियों की क्षीणता का यह एक विशेष कारण है। विरोधी दल भी उस सीमा तक विरोध करता है जहाँ प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देने के लिए विवश न होना पड़े। प्रधानमंत्री को सभाट को यह मन्त्रणा देने का अधिकार है कि सदन का विघटन किया जाय। विघटन की घमकी ही संसदीय सदस्य रूपा थोड़ी की त्तिहिनाहट को बंद करने के लिए काफी होती है। विरोधी दल ही क्या मताधारो दल व सदस्य भी फिर दोबारा निर्वाचन में अपनी सफलता के विषय में आश्वस्त नहीं होते।

(3) **दलीय अनुशासन की कठोरता (Rigidity of Party Discipline)**—संसद सदस्यों को सबसे अधिक चिंता अपने राजनीतिक भविष्य की रहती है। इस भविष्य के रक्षक तथा भक्षक हैं दल के सचेतक (Whips) जो स्वयं भी नेताओं के निर्देशन में कार्य करते हैं। दलीय अनुशासन इतना कठोर है कि सदस्य इधर उधर कान हिलाने का साहस ही नहीं करता। राजनीतिक लगाम सदस्य के अह को काबू में रखती है। दलीय आदेशों की अवहेलना के अर्थ हैं दल से निष्कासन जो एक जीवन सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न है।

क्रिस्टोफर होलिस (Christopher Hollis) के अनुसार 'सदस्य दलीय मशीन का आज्ञाकारी भक्त है' (The member is the most obedient servant of party machine)। उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण कोई महत्व नहीं रखता। गौडन (Strathearn Gordon) ने बड़ा ही तीखा व्यंग्य करते हुए कहा है कि संसद में स्वतन्त्र विचार एवं अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों का युग तो समाप्त हुआ। सदन पर राजनैतिक दलों का ऐसा अधिकार स्थापित हो गया है कि स्वतन्त्र विचार वाले व्यक्ति का तो वहाँ तक पहुँचना ही असम्भव सा हो गया है जो राजनैतिक नियम वस्तुतः सदन को लेने चाहिए वे उससे बाहर टूट यूनियन अथवा ब्रिटिश व्यापार संघ द्वारा लिये जाते हैं या वे प्रावधिक विशेषज्ञों द्वारा लिये जाते हैं जो राजनैतिक नेताओं पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो जाते हैं।

(4) **लोक सदन की प्रक्रिया (Procedure of the House of the Commons)**—लोक सदन का सामान्यतः सारा समय सरकारी विधेयकों की प्रगति एवं स्वीकृति में ही लग जाता है। निजी सदस्य द्वारा विधेयक (Private Members Bill) का तो मानो अब युग ही भाग रहा है। उसकी ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं जाता चाहे उसमें कितनी ही विशेषताएँ क्यों न हों। इसके अतिरिक्त निजी सदस्यों के बाद विवादों को समाप्त करने की भी कई विधियाँ बहुमत दल के पास सदन में रहती हैं। सदन का कार्यक्रम कहने को तो अध्यक्ष द्वारा तय होना है कि तु वास्तव में वह मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तय किया जाता है। फाइनेर (H. Finer) के शब्दों में, संसद के साधारण सदस्यवाद विवाद में बहुत ही कम योग दे पाते हैं क्योंकि उन्हें तो इसका विशेष प्रशिक्षण मिलता है और न ही उनका व्यवसाय ऐसा है कि वे इसके योग्य हों। उनके निर्वाचन क्षेत्र की कोई ऐसी विशेषता भी नहीं होती कि उसकी आवाज सुनी जाय।

(5) **प्रत्याधिकृत व्यवस्थापन (Delegated Legislation)**—संसद की क्षीणता का महत्वपूर्ण कारण प्रदत्त व्यवस्थापन भी है। विधेयक अस्थायी रूप में संसद द्वारा निर्मित किये जाते हैं और उनमें मासपत्रियों की पूर्ण प्रशासकीय विभागों द्वारा की जाती है। जिस समय तक कानूनों का सम्बन्ध हम प्रदत्त व्यवस्थापन के साथ नहीं जोड़ते उस समय तक वह अपूर्ण है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों के सम्बन्ध में नियम तथा उप नियमों की संरचना शासकीय विभागों द्वारा की जाती है। प्रदत्त व्यवस्थापन की मात्रा इतनी बढ़ गयी है कि इनके द्वारा नीकरशाही तथा ताल फीताशाही को बल मिला है और प्रशासन में दक्षिणानुमीपन आ गया है। हालत यह है कि संसद कानून कम बनाती है और सरकारी विभाग उससे कहीं अधिक।

1947 तक प्रदत्त बानूनों की संख्या लगभग 2916 तक पहुँच गयी थी। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था को नूतन निरंकुशतावाद कहा गया है। सिसिल टो० कार ने कहा है कि "कानूनों की पुस्तक उस समय तक आधार हो नहीं, अपितु भ्रमात्मक भी है, जब तक कि उसे उस प्रदत्त विधान के साथ मिलाकर न पढ़ा जाय जिसके द्वारा उसका बहुत कुछ विस्तार और संशोधन होता है।"

(6) वित्तीय नियन्त्रण में ह्रास (Decline of Financial Powers)—पहले वित्तीय व्यवस्था पर लोक सभा का पूर्ण नियन्त्रण था। इसी कारण उसका पूर्ण सम्मान भी था। किन्तु आज स्थिति बदली हुई है। यदि लोक सदन वित्तीय प्रस्तावों को अस्वीकार करता है तो प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास समझा जाता है और वह त्यागपत्र देने के लिये नैतिकरूप में बाध्य किया जा सकता है। इसके साथ प्रधानमन्त्री को भी सदन को सम्म्राट के द्वारा भंग कराने का भी अधिकार प्राप्त है जिससे सदन भयभीत रहता है। सदन को विवश होकर कार्यपालिका की इच्छा के समक्ष समर्पण कर देना पड़ता है। स्वीकृत धनराशि का प्रयोग उचित रूप में होना चाहिये, इस पर भी सदन का नियन्त्रण नाममात्र का है। राष्ट्रीय ऋण तथा संचित निधि पर सदन का नियन्त्रण नाम मात्र का भी नहीं है।

(7) सदन में सदस्यों की स्वतन्त्रता की कमी (Reduction of Freedom of Members in the House of the Commons)—पहले सदन में बड़े ही योग्य व्यक्ति निर्वाचित होकर आते थे। निर्वाचनों में भी व्यक्तिगत गुणों पर व्यापकरूप से बल दिया जाता था। निर्वाचित सदस्य भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार तथा मत का प्रयोग कर सकते थे। किन्तु अब यह सम्भव नहीं है। अब न वह विचार ही स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सकता है और न ही अपनी रुचि के अनुसार अपने मत का प्रयोग कर सकता है। इस सबका कारण है दलीय अनुशासन। इसी कारण अब योग्य व्यक्ति निर्वाचनों में भाग लेना तथा सदन में आना पसंद नहीं करते।

(8) लोकमत की प्रबलता (Public opinion has grown stronger)—लोक सभा की शक्तियों के ह्रास का एक कारण यह भी है कि लोकमत का प्रभाव उत्तरोत्तर सशक्त होता रहा है। मन्त्री ससदीय इच्छा की परवाह न करके लोकमत की अधिक शक्ति करते हैं। लोकमत के समक्ष झुकते हैं और उसी के प्रकाश में अपने आचरण का नियोजन करते हैं।

अतः हम यही कहेंगे कि सदन का ह्रास नहीं हुआ है अपितु उसका स्वरूप अवश्य बदल गया है। यह बात अवश्य है कि अब उसका कार्य हस्तक्षेप करना न होकर केवल नियन्त्रण करना है। प्रशासकीय ऋण पर नियन्त्रण रखने का कार्य वस्तुतः सदन सफलतापूर्वक ढंग से कर रही है। आज भी वित्त पर सदन का पूर्ण नियन्त्रण है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र और उसके लिए कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से अधिकाधिक शक्ति देनी होगी। यह सही है कि व्यवस्थापन का कार्य निजी सदस्यों के हाथों से निकलकर विभागों के हाथों में चला गया है। फिर भी निजी सदस्यों के हाथों में बाकी महत्वपूर्ण कार्य रहता है। शासन की आलोचना तथा व्यक्तिगत विधेयकों के प्रस्तावन में भी उनका विशेष हाथ रहता है। निजी सदस्य लोकमत को

प्रभावित करते हैं। यह सही है कि दलीय अनुशासन अत्यंत बठोर है किंतु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि संसद का कायपालिका पर कोई निष्पत्ति नहीं है। कायपालिका फिर भी संसदीय आलोचना तथा अवहेलना से भयभीत रहती है। संसद की उपयोगिता का मूल्यांकन हमें इस रूप में करना है कि क्या उसने प्रगति को रोका है अथवा उसे प्रोत्साहन दिया है।

लास्बी (Lasky) के शब्दों में 'आजकल आलोचक' निजी सदस्य की स्थिति के पतन पर आसू बहाना एक फैशन समझते हैं किंतु यह अप्रामाण्य व्यवस्था है। लॉर्ड कनेट (Lord Kennet) के अनुसार 'क्राउन पर नियंत्रण रखने की शक्ति अब बहुत पुरानी पड़ गयी है।' जनिन्ग्स के शब्दों में, 'अब राम भरोसे सिद्धांत अथवा शक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने के सिद्धांत का अंत हुआ। आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक प्रस्तुत करती है जिसे ग्लैंडस्टन तथा डिजरायली एक 'यादिक समाज' वादी बतलाते हैं और जिनसे बोर्डन तथा पील को ठस पहुँचती है।

Select Readings

- Ilbert *Parliament*
 Muir *How Britain is Governed*
 Taylor *House of Commons at work*
 Gordon *British Parliament*
 Carter *Govt. of Great Britain*
 Munro *Govts. of Europe*
 Finer *Theory & Practice of Modern Govts*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. ब्रिटिश लोक सभा की रचना, अधिकारों तथा कृत्यों का वर्णन कीजिए।
 (Describe the composition powers and functions of the House of Commons in England)
2. अमेरिकी तथा ब्रिटिश अधिसभों के अधिकारों, कृत्यों तथा स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या अधिसभा का निदलीय होना आवश्यक या उचित है?
 (Compare the position powers and functions of the speaker in the British House of Commons and the American House of representative Do you consider it necessary or desirable, that the Speaker should be a non party man?)
3. ब्रिटेन में प्रचलित विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और उसकी तुलना अमेरिकी प्रक्रिया से कीजिए।
 (Explain the procedure for the passing of laws in England and compare the same with that in the U S A)
4. सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकों में क्या अंतर है? लोक सभा में दूसरे के पारित करने में क्या अंतर है?
 (Distinguish between Public and Private bills and explain the procedure followed in respect of the latter in the House of Commons)
5. ब्रिटिश समिति पद्धति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा अमेरिकी पद्धति से इसकी तुलना कीजिए।
 (Critically examine the Committee system in England and compare it with that of America)

- 6 प्रदत्त विधायन से आप क्या समझते हैं ? इसके विकास के क्या कारण हैं ? इसके गुण और दोषों का वर्णन करें ।
(What is meant by 'Delegated Legislation' ? Account for its growth in Great Britain in modern times and discuss its merits and demerits)
- 7 "संसद का कार्य शासन करना नहीं, बल्कि आलोचना करना है ।" इस कथन की समीक्षा करें ।
('Function of Parliament is not to govern but to criticise' —Jennings Discuss)
- 8 "ब्रिटिश संसद अभी भी कार्यपालिका पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखती है ।" हम कथन की विवेचना करें ।
('The British Parliament still exercise effective control over the executive' Discuss)
- 9 'ब्रिटिश संसद की शक्ति तथा प्रतिष्ठा के ह्रास के कारण बताइए ।' क्या यह अपने कार्य सफलतापूर्वक कर रही है ?
(Account for the decline of prestige and authority of the British Parliament It is performing its duties successfully)
- 10 ब्रिटिश संसद तथा अमेरिकी कांग्रेस की समिति पद्धति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए ।
(Compare and Contrast the Committee System in British Parliament with that in the Congress of U S A)
- 11 अमेरिकी तथा ब्रिटिश अध्यक्ष के अधिकारों, कृत्यों एवं स्थितियों का तुलनात्मक वर्णन करें ।
(Compare and Contrast the position, powers and functions of the British Speaker with that of the U S A)
- 12 बिल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें । वह लोक सभा में कैसे प्रवेश होता है और कैसे पारित किया जाता है ?
(Describe the different types of bills How are they introduced and passed in the British House of Commons ?)

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था [British Judicial System]

"Justice is the end of Government It is the end
of civil society"

James Madison

यह सत्य है कि इंग्लैण्ड की सामान्य कानून व्यवस्था ने जितना विश्व की न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया है उतना सम्भवतः अन्य किसी प्रणाली ने नहीं किया। यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने रोमन विधि का अनुकरण अपनी न्यायिक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में किया है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैण्ड, भारत, लंका आदि देशों ने अपनी न्याय व्यवस्था को इंग्लैण्ड के सामान्य कानून पर आधारित किया है। इंग्लैण्ड में जिस राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ है और उसका जनतन्त्रीकरण हुआ है, ठीक उसी प्रकार वहाँ की न्याय व्यवस्था का भी विकास तथा जनतन्त्रीकरण हुआ है। नागरिक अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की जिस सुदृढ़ता के साथ रक्षा सामान्य कानून ने की है, वह इतिहास का एक रजत अध्याय है। वह उनका प्रेरक तथा प्रहरी रहा है। वह किसी शासक वर्ग का अथवा किसी वर्ग विशेष का कानून न होकर जनसाधारण का कानून है।

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था की विशेषताएँ

(Characteristics of British Judicial System)

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की लोकप्रियता के कई आधार हैं। उसकी अपनी कई विशेषताएँ हैं।

(1) न्यायिक स्वतन्त्रता (Judicial Independence)—ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण न्यायिक स्वतन्त्रता है। न्यायाधीश निष्पक्ष तथा निर्भीक होकर कार्य करते हैं। कार्यपालिका का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता। न्यायाधीश सदाचरण की अवधि में अपने पदों पर आसीन रहते हैं। वहाँ की न्याय-पालिका भ्रष्टाचार से मुक्त है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिलता है तथा साथ ही सेवा सुरक्षा भी उपलब्ध होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है और संसद के अनुरोध पर ही वे सम्राट द्वारा अपने पदों से हटाए जा सकते हैं।

(2) जुरी प्रणाली (Jury System)—इंग्लैण्ड की यह बहुत ही सफल व्यवस्थाओं में से एक है। इसमें गणमान्य नागरिक सम्मिलित किये जाते हैं जो अपनी निष्पक्षता के लिए लोकप्रिय होते हैं। छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े न्यायालय को छोड़कर अन्य सब न्यायालयों में जुरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। न्यायाधीश

of Law) — अलिखित सविधान होने का कारण इंग्लैण्ड में एक सामान्य सम्पूर्ण कानूनी संहिता की रचना सुलभ नहीं है। यहाँ की कानूनी व्यवस्था का आधार संसद के लगभग 300 सदस्यों द्वारा समय समय पर सविध कानून हैं या न्यायाधीशों के द्वारा लगभग तीस लाख समय समय पर प्रदत्त महत्वपूर्ण निणय हैं।

(9) न्यायिक कायदाहिया का गुप्त नहीं रखा जाता (Judicial Proceedings are not kept Secret) — न्यायाधीशों के निणय निष्पक्ष होते हैं। उन्हें गुप्त रखने की अवस्था गुप्त रूप में सुनने की आवश्यकता नहीं होती, निणय खुले रूप में सुनाये जाते हैं। उन्हें सुनने का जनता का अधिकार है। मुकदमे बढ़ कमरे में नहीं होते हैं और न ही निणय बढ़ कमरे में सुनाये जाते हैं।

(10) नि मुक्त कानूनी सहायता (Free Judicial Help) — 1949 के परामर्श तथा सहायता अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि वेल्स के उच्च न्यायालय, अपील न्यायालयों तथा सेशन एवं शेरिफ न्यायालयों के सदस्यों में जो लोग गरीब हैं, सर्वोपेक्षित नहीं कर सवत तथा मुकदमों के अधिक समय तक चलने की सम्भावना है, उन्हें मुक्त कानूनी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(11) सर्किट न्यायालयों की व्यवस्था (Arrangement of Circuit Courts) — आर्थिक दृष्टिनाइयों तथा आवागमन की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित ही समझा गया है कि कुछ मोबाइल न्यायालयों की व्यवस्था की जाय। इन्हीं को सर्किट न्यायालय कहा जाता है। ये बड़े बड़े न्यायालयों की शाखा के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें 'Court of Assizes' भी कहा जाता है। ये न्यायालय वर्ष में तीन बार अपने कोर्ट लगाते हैं। न्यायाधीश दूर दूर जाकर मुकदमों का निपटारा करते हैं।

(12) विधि का कानून (Rule of Law) — विधि का शासन ब्रिटिश सविधान की अनुपम देन है। इसका आशय यह है कि देश में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का शासन न होकर कानून का शासन है। कानून ही सावभौमिक है। कानून के समक्ष सब एक हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से उन्मुक्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिक, प्रधानमंत्री तथा चौकीदार पूजीपति तथा निधन में कानून की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। लाड होवट के शब्दों में, "विधि के शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता (The Supremacy or Dominance of Law)। कानून का उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा चाहे समाज में उसका कोई स्तर क्यों न हो। विधि का शासन नागरिक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है। विधि का शासन इस तथ्य का भी चोतक है कि इंग्लैण्ड में किसी वर्ग विशेष का शासन न होकर जनता का कानून का शासन है। अपराध स्थापित हुए बिना किसी भी व्यक्ति को दण्ड भोगने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। विधि का कानून प्रशासकीय कानून का उल्टा शब्द है। हीगन तथा पावेल (Hegan and Powell) के अनुसार, 'जो व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं वे अपनी इच्छानुगुण ही सब कुछ कर सकते, परंतु उन्हें अक्षरशः उन कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करना पड़ता है जिनका निर्माण संसद ने किया है।'

जुरी के निणय की अवहेलना नहीं कर सकता। वह उसका अभिमत मानने को बाध्य है।

(3) नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Safeguard of Civil Liberties)—नागरिकों की स्वतंत्रताएँ यायपालिका के हाथों में सुरक्षित रहती हैं। यद्यपि संविधान अलिखित है किंतु फिर भी नागरिकों की स्वतंत्रताएँ सामान्य कानून (Rule of Law) के द्वारा सुरक्षित हैं। स्वतंत्रता का हनन किसी शासक अथवा अधिकारी की इच्छा पर अवलम्बित नहीं है। इससे यह भी अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार बिना मुकदमा चलाये हिरासत में नहीं रखा जा सकता परम्पराओं के हाथों में बद्ध संविधान को स्थायित्व केवल यायपालिका से प्राप्त हो सका है।

(4) एकरूपता का अभाव (Lack of Uniformity)—यायिक सगठन में वस्तुतः एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इंग्लैण्ड तथा वेल्स के याय सगठन तांगभग एक से हैं किंतु इस प्रकार की एकरूपता उत्तरी आयरलैण्ड तथा स्कॉटलैण्ड के यायिक सगठनों में हम उपलब्ध नहीं होती। इंग्लैण्ड तथा वेल्स की पद्धतियों में जो व्यवधान था उसे तीन सप्ताह के सतत प्रयत्नों के पश्चात् समाप्त करना सम्भव हो सका है।

(5) शीघ्र निणय (Quick Decisions)—अमेरिका तथा भारत के सदृश वहाँ के यायालय निणयों में देर नहीं लगाते, निणय अति शीघ्रता के साथ होते हैं। आशिक रूप से इस सफलता का श्रेय यायाधीशों को कानूनी जटिलताओं से व्यक्तिगत रूप में निपटने की स्वतंत्रता के अधिकार को जाता है और आशिक रूप से यायिक प्रक्रिया की स्पष्टता तथा प्रभावशालीनता को जाता है। यायिक प्रक्रिया के निर्धारण का कार्य वहाँ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में विधि विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा किया जाता है।

(6) यायिक पुनरावलोकन का अभाव (Absence of Judicial Review)—इंग्लैण्ड में संविधान अलिखित है और वहाँ संसदीय सावधानीमयता है। संसद द्वारा निमित्त किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसी भी यायालय को नहीं है। इसके विपरीत भारत तथा अमेरिका में उच्चतम यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। इसी कारण यहाँ उच्चतम यायालय कभी कभी सहयोगी के स्थान पर प्रशासन के प्रतियोगी के रूप में कार्य करने लगता है। इंग्लैण्ड में इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

(7) प्रशासकीय यायालयों का अभाव (Lack of Administrative Courts)—पास तथा अन्य बहुत से देशों में दो ही प्रकार के कानून तथा दो ही प्रकार के यायालय हैं। इसी व्यवस्था को प्रशासकीय याय व्यवस्था कहते हैं। वहाँ जनता तथा प्रशासकीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने तथा सुनवाई करने के लिए पृथक्-पृथक् यायालय तथा कानून हैं। इंग्लैण्ड में यह व्यवस्था नहीं पायी जाती। वहाँ पर जन माधारेण तथा प्रशासकीय अधिकारियों के लिए न तो पृथक् यायालय ही हैं और न ही कानून सब सामान्य कानून के आधीन हैं।

(8) सम्पूर्ण कानूनी-संहिता का अभाव (Absence of Complete Code

of Law)—अलिखित सविधान होने के कारण इंग्लैण्ड में एक सामान्य सम्पूर्ण कानूनी संहिता की रचना सुलभ नहीं है। वहाँ को कानूनी व्यवस्था का आधार ससद के लगभग 300 सदस्यों द्वारा समय समय पर सविध कानून हैं या 'यायाधीशों' के द्वारा लगभग तीस लाख समय समय पर प्रदत्त महत्वपूर्ण निणय हैं।

(9) 'यायिक कार्यायाहियों को गुप्त नहीं रखा जाता (Judicial Proceedings are not kept Secret) — 'यायाधीशों के निणय निष्पक्ष होते हैं। उन्हें गुप्त रखने की अथवा गुप्त रूप से सुनने की आवश्यकता नहीं होती निणय खुले रूप में सुनाये जाते हैं। उन्हें सुनने का जनता का अधिकार है। मुकदमे बाद कमरे में नहीं होते हैं और न ही निणय बाद कमरे में सुनाये जाते हैं।

(10) नि मुक्त कानूनों सहायता (Free Judicial Help)—1949 के पराम्प तथा महायता अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि वेल्स के उच्च 'यायालय अपीलीय 'यायालयों तथा सेशन एवं शरिफ 'यायालयों के सदस्य में जो लोग गरीब हैं खर्चा बदाशत नहीं कर सकते तथा मुकदमे के अधिक समय तक चलन की सम्भावना है उन्हें मुक्त कानूनी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(11) सर्किट यायानयों की व्यवस्था (Arrangement of Circuit Courts)—आर्थिक कठिनाइयों तथा आवागमन की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित ही समझा गया है कि कुछ मोबाइल 'यायालयों की व्यवस्था की जाय। इन्हीं को सर्किट 'यायानय कहा जाता है। ये बड़े बड़े यायालयों की शाखा के रूप में कार्य करत हैं। इन्हें 'Court of Assizes' भी कहा जाता है। ये 'यायालय वष में तीन बार अपने कोर्ट लगाते हैं। 'यायाधीश दूर दूर जाकर मुकदमों का निपटारा करते हैं।

(12) विधि का कानून (Rule of Law)—विधि का शासन ब्रिटिश सविधान की अनुपम देन है। इसका आशय यह है कि देश में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का शासन न होकर कानून का शासन है कानून ही सावभौमिक है। कानून के समक्ष सब एक है। कोई भी व्यक्ति कानून से उन्मुक्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिक प्रधानमंत्री तथा चीफ़ीदार पूजीपति तथा निधन में कानून की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। लाइ हीवट के शब्दों में, "विधि के शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता" (The Supremacy or Dominance of Law)। कानून का उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा चाहे समाज में उसका कोई स्तर क्या न हो। विधि का शासन नागरिक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है। विधि का शासन इस तथ्य का भी चेतक है कि इंग्लैण्ड में किसी वय विशेष का शासन न होकर जनता का कानून का शासन है। अपराध स्थापित हुए बिना किसी भी व्यक्ति को दण्ड भोगने के लिए विवश नहीं किया जा सकता विधि का कानून प्रशासकीय कानून का उल्टा शब्द है। हीगन तथा पॉवेल (Hegan and Powell) के अनुसार, 'जो व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं व अपनी इच्छानुक्ल ही सब कुछ नहीं कर सकते, परंतु उन्हें अक्षरशः उन कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करना पड़ता है जिनका निर्माण ससद ने किया है।'।

जुरी के निणय की अवहेलना नहीं कर सकता। यह उसका अभिमान मानने को बाध्य है।

(3) नागरिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (Safeguard of Civil Liberties)—नागरिकों की स्वतन्त्रताएँ याचकालिका के हाथों में सुरक्षित रहनी हैं। यद्यपि संविधान अलिखित है किंतु फिर भी नागरिकों की स्वतन्त्रताएँ सामान्य कानून (Rule of Law) के द्वारा सुरक्षित हैं। स्वतन्त्रता का हनन किसी शासक अथवा अधिकारी की इच्छा पर अवलम्बित नहीं है। इससे यह भी अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार बिना मुकदमा चलाये हिरामत में नहीं रखा जा सकता, परम्पराओं के हाथों में बद्ध संविधान को स्थायित्व देकर याचकालिका से प्राप्त हो सका है।

(4) एकरूपता का अभाव (Lack of Uniformity)—याचक सगठन में वस्तुतः एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इंग्लैंड तथा वेल्स के 'याच सगठन' लगभग एक से हैं किंतु इस प्रकार की एकरूपता उत्तरी आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड के 'याचक सगठनों' में हमें उपलब्ध नहीं होती। इंग्लैंड तथा वेल्स की पद्धतियों में जो व्यवधान या उसे तीन चरणों के सतत प्रयत्नों के पश्चात् समाप्त करना सम्भव हो सका है।

(5) शीघ्र निणय (Quick Decisions)—अमेरिका तथा भारत के सर्वश्रेष्ठों ने याचालय निणयों में देर नहीं लगाते, निणय अति शीघ्रता के साथ होते हैं। आंशिक रूप से इस सफलता का श्रेय 'याचाधीशों' को कानूनी जटिलताओं से व्यक्तिगत रूप में निपटने की स्वतन्त्रता के अधिकार को जाता है और आंशिक रूप से याचक प्रक्रिया की स्पष्टता तथा प्रभावशालीनता को जाता है। 'याचक प्रक्रिया' के निर्धारण का कार्य वहाँ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा किया जाता है।

(6) 'याचक पुनरावलोकन' का अभाव (Absence of Judicial Review)—इंग्लैंड में संविधान अलिखित है और वहाँ संसदीय सावधानीमयता है। संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसी भी 'याचालय' को नहीं है। इसने विपरीत भारत तथा अमेरिका में उच्चतम याचालय को यह अधिकार प्राप्त है। इसी कारण वहाँ उच्चतम 'याचालय' कभी कभी सहयोगी के स्थान पर प्रशासन के प्रतियोगी के रूप में कार्य करने लगता है। इंग्लैंड में इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

(7) प्रशासकीय 'याचालयों' का अभाव (Lack of Administrative Courts)—फ्रांस तथा अन्य बहुत से देशों में दा ही प्रकार के कानून तथा दा ही प्रकार के 'याचालय' हैं। इसी व्यवस्था को प्रशासकीय 'याच व्यवस्था' कहते हैं। वहाँ जनता तथा प्रशासकीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने तथा सुनवाई करने के लिए पृथक् पृथक् 'याचालय' तथा कानून हैं। इंग्लैंड में यह व्यवस्था नहीं पायी जाती। वहाँ पर जन साधारण तथा प्रशासकीय अधिकारियों के लिए न तो पृथक् 'याचालय' ही हैं और न ही कानून सब सामान्य कानून के आधीन है।

(8) सम्पूर्ण कानूनी-संहिता का अभाव (Absence of Complete Code

of Law)—प्रलिखित सविधान होने के कारण इंग्लैंड में एक सामान्य सम्पूर्ण कानूनी संहिता की रचना सुलभ नहीं है। वहाँ की कानूनी व्यवस्था का आधार समस्त के लगभग 300 मदस्यों द्वारा समय समय पर सविध कानून हैं या 'यायाधीशों के द्वारा लगभग तीस लाख समय समय पर प्रदत्त महत्वपूर्ण निणय हैं।

(9) 'यायिक कायदाहियों को गुप्त नहीं रखा जाता (Judicial Proceedings are not kept Secret) — 'यायाधीशों ने निणय निष्पक्ष होते हैं। उन्हें गुप्त रखने की अवस्था गुप्त रूप में सुनने की आवश्यकता नहीं होती निणय खुले रूप में सुनाये जाते हैं। उन्हें सुनने का जनता का अधिकार है। मुकदमे बाद कमरे में नहीं होते हैं और न ही निणय बाद कमरे में सुनाये जाते हैं।

(10) नि शुल्क कानूनी सहायता (Free Judicial Help)—1949 के पराम्य तथा सहायता अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि वेल्स के उच्च यायालय अपीलीय 'यायालयों तथा सेशन एव शेरिफ 'यायालयों के सदस्य में जो लोग गरीब हैं, स्वर्चा वर्द्धित नहीं कर सकत तथा मुकदमे में अधिक समय तक चलन की सम्भावना है, उन्हें मुफ्त कानूनी अधिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(11) सर्किट यायालयों की व्यवस्था (Arrangement of Circuit Courts)—आर्थिक कठिनाइयों तथा आवागमन की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित ही समझा गया है कि कुछ मोबाइल 'यायालयों की व्यवस्था की जाय। इन्हीं को सर्किट 'यायालय कहा जाता है। ये बड़े बड़े 'यायालयों की शाखा के रूप में काम करते हैं। इन्हें 'Court of Assizes' भी कहा जाता है। ये यायालय वर्ष में तीन बार अपने कोर्ट लगाते हैं। 'यायाधीश दूर दूर जाकर मुकदमों का निपटारा करते हैं।

(12) विधि का कानून (Rule of Law)—विधि का शासन ब्रिटिश सविधान की अनुपम देन है। इसका आशय यह है कि देश में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का शासन न होकर कानून का शासन है कानून ही साधनौमिक है। कानून के समक्ष सब एव हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से उन्मुक्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिक प्रधानमंत्री तथा चौकीदार पूज्यपति तथा निधन में कानून की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। लाड हीवट के शब्दों में, 'विधि के शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता (The Supremacy or Dominance of Law)। कानून का उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा चाहे समाज में उसका कोई स्तर क्यों न हो। विधि का शासन नागरिक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है। विधि का शासन इस तथ्य का भी स्रोतक है कि इंग्लैंड में किसी वय विशेष का शासन न होकर जनता का कानून का शासन है। अपराध स्थापित हुए बिना किसी भी व्यक्ति को दण्ड भोगने के लिए विवश नहीं किया जा सकत। विधि वा कानून प्रशासकीय कानून का उल्टा शब्द है। हीगन तथा पावल (Hegan and Powell) के अनुसार जो व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं व अपनी इच्छानुक्त ही सब कुछ नहीं कर सकते, परंतु उन्हें अक्षरशः उन कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करना पडता है जिनका निर्माण संसद ने किया है।

(The persons who compose the government of the day cannot do just as they please but must exercise their powers strictly in accordance with the rules which parliament has laid down) इससे यह स्पष्ट होता है कि यह निरंकुश प्रवृत्ति वाले शासकों के ऊपर अंकुश है। यह ब्रिटिश परम्परा तथा स्वभाव के अनुरूप ही है। यह प्रशासकीय ढंग में और अधिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। विधि के शासन का सबसे अच्छा विवरण इंग्लिश विधियेता डायसी (Dicey) ने दिया है। इसका व्यापक विवेचन डायसी ने अपनी पुस्तक '*Law of the Constitutions*' में किया है।

डायसी का विवेचन (Dicey's Exposition)

डायसी ने विधि के शासन की व्यापक रूप में व्याख्या करते हुए उसके तीन भाग बताये हैं

(1) कानून की सर्वोच्चता (Supremacy of Law)—कानून की सर्वोच्चता से आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक दण्ड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके विरुद्ध कानूनी बायबाही न की जाय अपराध स्थापित न किया जाय तथा अपराधी को अपने बचाव का पूरा पूरा अवसर न दिया जाय। इससे यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता। कायपालिका अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकती, उसे पूरा रूप में कानून के अनुसार आचरण करना होगा। अन्य देशों में कायपालिका अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करके नागरिकों को आतंकित करती है, मनमाने ढंग से आचरण करके उनकी स्वतन्त्रता को खतरे में डालती है। दण्ड किसी 'यायालय द्वारा गुप्त रूप में देने की व्यवस्था नहीं है। अपराधों की सुनवाई खुले रूप में होती है। विशेष न्यायालयों की भी रचना नहीं की जाती। शारीरिक एवं आर्थिक रूप में एक व्यक्ति को दण्डित केवल उसी रूप में किया जा सकता है जब उसे साधारण 'यायालय द्वारा सामान्य कानून के अनुसार दण्ड दिया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दण्ड 'यायालय में प्रमाणित होने की ही स्थिति में ही दिया जा सकता है अन्यथा नहीं।

(2) कानून की समानता (Equality before Law)—डायसी के शब्दों में विधि के शासन से अभिप्राय है कि "कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, देश के सामान्य कानून से नियंत्रित होता है तथा सामान्य 'यायाधिकरण के अंतर्गत रहता है। जो बात एक आदमी के लिए कानून है वह समस्त नागरिकों के लिए कानून है।" व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से देश का कानून तथा उसके 'यायालय प्रभावित नहीं होते। कानून के समक्ष सबका स्तर समान है, चाहे कोई कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो उसका मूल्य कानून के समक्ष समान है। डायसी (Dicey) के शब्दों में "हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही तक या एक कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे काय के लिए जो कानून के अंतर्गत 'याय न हो, उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून तथा पृथक 'यायालय फ्रांस की भाँति इंग्लैण्ड में नहीं है। कानून से लाभ अथवा हानि की उपलब्धि सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। साधारण

कानून ही शासकीय कमचारियों के कार्यों के औचित्य तथा अनौचित्य को निश्चित करता है। 'याय' के समक्ष सब समान हैं।

(3) अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं बरन् 'यायिक' निणय हैं (Rights do not originate from the Constitution but from Judicial Decisions)—विधि के शासन का तीसरा अर्थ है कि जहाँ संविधान स्पष्ट नहीं है वहाँ 'यायालयों' के निणय ही अंतिम माने गये हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का निर्माण 'यायिक' निणयों का ही परिणाम मात्र है। डायसी के शब्दों में, "संविधान के सामान्य सिद्धांत उन 'यायिक' निणयों के परिणाम हैं, जिनमें यायालयों ने विशेष अभियोगों में नागरिकों के अधिकारों को निश्चित किया है।" देश का सामान्य कानून 'यायिक' निणयों का ही परिणाम है, संसद की सर्वोच्चता का भाव केवल इस लिए माना गया है कि वह कानूनों का निर्माण सामान्य कानून के अनुसार करती है, यही शासन का आधार भी है।

विधि के शासन का अपवाद (Exceptions to the Rule of Law)

इसमें सन्देह नहीं कि डायसी कानूनी निणय तथा संवैधानिक निणयों के समेले में उलझा हुआ दीख पड़ता जिसे वह अंत तक नहीं सुझा पाता। यह बात भी सही है कि जब उसने 1885 में अपनी पुस्तक की रचना की थी राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक नहीं था। वह व्यक्तिवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। किंतु 1915 तक राज्य के कार्यक्षेत्र की व्यापकता का इतना शीघ्रता के साथ विकास हुआ कि स्वयं डायसी ने यह अनुभव किया कि सपरिषद आदेशों (Orders in Councils) की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि विधि के शासन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। महायुद्धावधि में सरकार ने शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से किया था। विधि के शासन के सम्बंध में निम्नलिखित अपवाद हैं

(1) प्रत्याधिकृत व्यवस्थापन (Delegated Legislation)—संसद के पास न इतना समय है कि वह कानून की सूक्ष्मताओं का अवलोकन कर सके और न ही उसके पास इतना प्रावधिक ज्ञान है जो कानून की परिवर्द्धित जटिलताओं का सही सही विश्लेषण ही कर सके। विवशता की स्थिति में उसे अपनी शक्तियों का महत्वपूर्ण भाग—कानून निर्माण—कार्यपालिका को समर्पित करना पड़ता है। मंत्रीगण अपने स्थायी सचिवों के परामर्श से विभागीय नियमों एवं उपनियमों की रचना करते हैं और उस समय तक इन नियमों का कानून की भाँति मूल्य भी होता है जब तक कि वे अर्द्धध्वंसित नहीं कर दिये जाते। यह विधि के शासन पर करारी चोट है जिसने उसके महत्व को पददलित सा कर दिया है।

(2) प्रशासकीय 'याय' (Administrative Justice)—इंग्लैंड में बहुत से शासकीय विभागों को कानून बनाने तथा 'याय' करने तक के अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों से वे विभागीय विवादों का निपटारा करते हैं। प्रशासकीय अधिकारियों को कुछ परिस्थितियों में 'यायिक' अधिकार भी समर्पित किये गये हैं। उदाहरणार्थ, Factory Act, Trade Board Act, Public Health Act, Town and Country Planning Act आदि ऐसे संसदीय अधिनियम हैं जिन्होंने प्रशासकीय विभागों को 'यायिक' शक्तियों से सम्पन्न किया है। नागरिकों के हितों से सम्बंधित

ये जा निषेध करने हैं उनके विरुद्ध शक्ति नहीं की जा सकती। ये किसी विधिवाकानुनी प्रणिया का भी पालन नहीं करते। प्रसाधिन लोग को अपनी सपाई देने का भी कभी-कभी पून अवसर नहीं मिल पाता। इस प्रकार प्रशासकीय ध्याय विधि के शासन के माग म णर बहुत बड़ी बाधा है।

(3) ग्यायाधीशों के विशेषाधिकार (Privileges of the Judges)—इंगलैण्ड म ग्यायाधीशों को ग्यायिक सुरक्षा इस सीमा तक प्राप्ता है कि उनके विरुद्ध कोई कानूनी बायबाहो नहीं की जा सकती। यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र का अति कमण भी करते हैं तो भी उनके विरुद्ध कोई प्रशासकीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। गलत निणय देन पर भी ग्यायाधीशों क विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती।

(4) सरकारी अधिकारियों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ (Privileges and Immunities of Government Officials)—1947 के Crown's Proceeding Act क पारित होने के बाद भी प्रशासकीय अधिकारियों को कुछ अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ अब भी प्राप्त हैं। 1939 के अपोस्टीम प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई अधिकारी अवराध करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध किसी नागरिक द्वारा उस तिथि से 6 माह की अवधि में मुकदमा दायर करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यदि अधिकारी क विरुद्ध चलाया गया मुकदमा लारिज हो जाता है तो नागरिक को मुआवजे के रूप म एव बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है। सम्भवत यही कारण है कि सरकारी कमचारियों के विरुद्ध मुकदम दायर करने से लोग डरते हैं।

(5) विदेशियों को उन्मुक्तियाँ (Immunities to the Foreigners)—विधि के शासन के विरुद्ध यह एक बहुत बड़ा अवबाध है जो विदेशी नागरिक दूतावासों में निवास करते हैं अथवा जो अंतर्राष्ट्रीय भायता प्राप्त सत्वाओं के सदस्य हैं या जो अम दशा के अधिका राजदूत अथवा शासक हैं उन पर इंगलैण्ड के नियम लागू नहीं होते। वे अपने देश के कानून स निर्मात होते हैं। इस प्रकार वे इंगलैण्ड के कानून से उन्मुक्त रहते हैं।

(6) स्वविवेक शक्तियाँ (Discretionary Powers)—स्वेच्छा शक्तियों को किसी भी प्रशासकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। बिना इनके प्रयास के कामकुशलता उत्पन्न नहीं की जा सकती। इनका होना विधि के शासन के प्रतिवूल है। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड म गृह मन्त्रि किसी भी विदेशी को नागरिकता का प्रमाण पत्र देने से मना कर सकता है। किसी भी विदेशी को इ से बाहर जाने को कह सकता है यदि उसकी हरकतें बित हैं। कायपा भी बाहर जाने का पार पत्र अस्वीकार कर इस अस्वी भी ग्यायालय में अपील नहीं की जा स

(7) ट्रेड यूनियन, सशस्त्र सेना
Unions, Armed Forces and G
सदस्यों पर भी विधि का शासन लागू नहीं
कोई भी व्यक्ति कानूनी

किस्ता
uncil
अति
f

चलाने का हकदार नहीं है। इसी प्रकार सैनिक 'यायालयों' द्वारा सैनिक कानून के अनुसार दिये गये निणयो के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है। पादरियों पर चर्च सम्बन्धी कानून लागू होते हैं और डाक्टरों पर सामान्य चिकित्सा परिषद द्वारा बनाये गये कानून लागू होते हैं।

(8) अधिकारों की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत 'यायिक निणय नहीं हैं' (Rights do not Originate From Judicial Decisions Alone)—डायसी का यह विचार एक दम नुटिपूर्ण है कि नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का एकमात्र श्रेय 'यायिक निणयों' को है। यह एक पक्षीय विचार है। इंग्लैण्ड में जनता को बहुत से अधिकार संसद तथा सम्राट द्वारा समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। 1816 में हीबियस कॉर्पस एक्ट के द्वारा विधि शासन की इस आवश्यकता को मायता दी गयी कि बिना अपराध स्थापित किये किसी को सजा नहीं दी जा सकती। 1888 के लाइबल एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई। 1936 में पब्लिक ऑर्डर एक्ट के द्वारा सावजनिक बैठकों आदि के सम्प्रदाय में महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया गया।

अतः विधि का शासन एक खोखला आदर्शवादी सिद्धांत मात्र है। New Despotism' में लॉर्ड हीवर्ट (Hewart) ने प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना करते हुए कहा है कि 'इंग्लैण्ड की यह दोषपूर्ण प्रणाली किसी भी व्यक्ति, जनता अथवा पदाधिकारी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इंग्लैण्ड में कानून के शासन में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि इसमें कभी-कभी होने वाले अनियमित विकास ने विधि के शासन को पीछे धकेल दिया है।' किंतु इससे हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि इंग्लैण्ड में विधि का शासन नहीं है। इंग्लैण्ड में विधि का शासन है किन्तु उसका स्वरूप बदल गया है। उसका वस्तुतः वह स्वरूप नहीं रहा है जिसकी चर्चा डायसी ने की थी। आज तो उमका लक्ष्य केवल यह देखना मात्र रह गया है कि कायपालिका द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न हो तथा नागरिक अधिकारों की लोकात्मक पद्धति द्वारा सुरक्षा बनी रहे। किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से आतंकित न किया जाय। कानून के शासन का महत्व कम नहीं हुआ बरन् बढ़ता जा रहा है। वेड तथा फिलिप्स के शब्दों में "कानून के शासन से यह अभिप्राय है कि उसमें कायपालिका की निरंकुश शक्तियों का अभाव होगा, प्रत्याधिकृत व्यवस्थापन पर संसद का प्रभावशाली नियंत्रण होगा इसका उचित प्रकाशन होगा विशेष रूप से जब इसके द्वारा दण्ड की व्यवस्था की जाय। जब कायपालिका को स्वेच्छाचारी शक्तियाँ दी जाएं तो यह निर्धारित कर दिया जाय कि कायकारिणी उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करेगी।" इस प्रकार विधि के शासन का मूल्यार्जन इस नये रूप में किया जाना चाहिए न कि उस रूप में जिस रूप में डायसी ने इसकी व्याख्या की है।

इंग्लैण्ड में कानून के प्रकार (Kinds of English Law)

(1) सामान्य विधि (Common Law)—इंग्लैण्ड की कानूनी परम्परा में सामान्य विधि का स्थान सबसे अधिक पुराना है। यह लगभग 800 वर्ष पुराना है।

नामन शासकों की विजय से पूर्व इंग्लैण्ड में सामान्य व्यवस्था का अभाव था। कई प्रकार के कानून वतमान थे। पृथक् पृथक् क्षेत्रों में पृथक् पृथक् कानून थे। कानूनों का कोई व्यापक एवं संगठित आधार उपलब्ध नहीं था। न्यायालय स्थानीय परम्पराओं के अनुसार नियम किया करते थे देश के विविध भागों में स्वामाधिकार रूप से विभिन्न प्रकार के कानून थे। नामन तथा एंजिदिन शासक यह चाहते थे कि देश में सर्वत्र शासन व्यवस्था का रूप एक सा हो व पृथक्तावादी नहीं थे। वे इन बिखरे हुए भागों को मिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सामूहिक याय व्यवस्था का प्रयोग किया। धीरे धीरे स्थानीय प्रथाओं का भेद समाप्त होने लगा था। सम्पूर्ण देश में सामान्य यायिक सिद्धांतों के आधार पर एक सामूहिक व्यवस्था कायम हो गयी। सर्वप्रथम यायाधीशों ने परम्पराओं को अपने नियमों का आधार बनाया किन्तु धीरे धीरे एक निश्चित नियमावली का आविर्भाव हुआ। यही से सामान्य कानून का जन्म समझना चाहिए।

सामान्य कानून वस्तुतः वह कानून है जिसका निर्माण संसद तथा सम्राट ने नहीं किया है वरन् जो यायिक नियमों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है। समय समय पर इन्हें सहिताबद्ध करने की कोशिश भी की गई है। इस प्रकार की सहिता उनकी व्याख्या तो करती है किन्तु वह यह नहीं बतलाती कि वे कानून क्या हैं। यद्यपि कानून तथा याय के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है किन्तु फिर भी सामान्य कानून का महत्व आज व्यवस्था में आज तक बना हुआ है। सविदा नियम तथा सामाजिक अपराधों से सम्बन्धित नियम इसी पर अवलम्बित हैं। फौजदारी कानून भी बहुत कुछ सीमा में इसी पर आधारित हैं। सामान्य कानून का एक बहुत बड़ा भाग संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के रूप में आ गया है। सामान्य कानून के ही सदृश कुछ न्यायालयों का विकास हुआ जिन्हें अब एसाइज (Assizes) कहा जाता है और वे अब भ्रमणशील न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं। यह तो मानना ही होगा कि सामान्य कानून के मूल में ये प्रथाएँ हैं जिनके आधार पर यायाधीशों ने अपने नियम दिये हैं। ब्रिटिश जनता आज भी यायिक युग में इन कानूनों को सम्मान तथा श्रद्धा के रूप में देखती है। ब्लैकस्टोन (Blackstone) के शब्दों में "यह सब श्रेष्ठ जन्माधिकार और मानव का सर्वोत्तम उत्तराधिकार है।"

(2) याय भावना अथवा औचित्यपूर्ण नियम (Equity)—सामान्य कानून के आधार पर औचित्यपूर्ण कानून की नींव रखी गयी है। तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक सामान्य विधि की लोचशीलता में परिवर्तन आगया था। वह कठोर हो गया। समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल वह अपने को ढालने में सफल न हो सकी। अनकों कमियाँ उसमें आगयीं। यायाधीशों ने समझ ऐसे ऐसे मामले आते रहे जिनमें वह अनुपयुक्त प्रतीत होने लगा। याय की अस्पष्टता बढ़ती गयी। सामान्य कानून के अनुकूल नियम देना सम्भव न रहा। जनता के सदस्य असंतुष्ट होकर सम्राट तथा संसद के पास याय की माँग हेतु जाने लगे। लोभ अय्याम से पीड़ित थे। राजा ही उस समय कानून तथा याय का स्रोत था। इसी कारण उससे अनुरोध किया जाता था। जब इन याचिकाओं की संख्या बढ़ने लगी तो सम्राट के लिए इन्हें सुनना सम्भव नहीं रहा। स्वविवेक द्वारा नियम देना असम्भव हो गया। किसी

भी कानून की अनुपस्थिति में निम्न राजा प्राकृतिक न्याय तथा न्याय भावना के आधार पर कर दिया करता था। जब अपील की बढ़ती हुई सख्या के साथ राजा कदम मिलाकर नहीं चल सका तो उसने विवश होकर उह अपने चांसलर (Chancellor) के पास भेजना आरम्भ कर दिया। इसी से चांसरी न्यायालय (The Court of Chancery) का विकास हुआ। चांसलर को राजा की आत्मा का साधक कहा जाता था। इस चांसरी का स्वरूप न्यायालय का न होकर एक शासकीय विभाग का सा था। चांसरी न्यायभावना प्राकृतिक न्याय तथा सविवेक के आधार पर ही निम्न कर दिया करता था। इस प्रकार के कानून को औचित्यपूर्ण निम्न की समा दी गयी।

18वीं शताब्दी तक साम्यविधि के नियम पर्याप्त रूप में स्पष्ट हो चुके थे। 1873 के न्यायालय अधिनियम (Judicature Act) के अनुसार न्यायभावना तथा सामान्य कानून की पृथक्ता समाप्त कर दी गयी। पहले सामान्य कानून के अतगत पृथक्-पृथक् न्यायालयों की व्यवस्था थी। दोनों प्रकार के कानूनों—सामान्य तथा न्याय भावना—में बहुत एकरूपता सी जान पड़ती है। सामान्य कानून का आधार प्रार्थ है और न्याय भावना का आधार विवेक। इसकी पठि में यह भावना छिपी हुई है कि न्यायकाय केवल कानून के शुष्क आकार के अनुकूल ही नहीं चलना चाहिए किन्तु उसे उस कानून के अनुसार चलना चाहिए जो सामाजिक नैतिकता की कसौटी पर खरी उतर सके। दोनों ही प्रकार के कानून असहिताबद्ध (Uncodified) हैं। दोनों ही प्रकार के कानूनों का विकास न्यायाधीशों के निम्नों के परिणामानुसार हुआ है। फिर भी दोनों प्रकार के कानूनों में अंतर है। सामान्य कानून का विकास दौरा अथवा समरण करने वाले न्यायाधीशों के फलस्वरूप निम्नों के रूप में हुआ है। औचित्यपूर्ण कानून का विकास भी चांसरी न्यायाधीशों के निम्न के फलस्वरूप विकसित हुआ है। एक का विकास प्रार्थों के आधार पर हुआ है तो दूसरे का नैतिकता के आधार पर। औचित्यपूर्ण निम्न का सम्बन्ध फौजदारी कानून के नियमन से है। दोनों के सम्बन्ध में एक बात और भी स्पष्ट की गई है कि दोनों में सघर्ष की स्थिति में औचित्यपूर्ण निम्न का निम्न अंतिम होगा।

(3) सविध कानून (Statute Law)—सविध कानून को ससदीय कानून कहा जाता है। वास्तविक रूप में यही कानून है, और दो कानून विकसित प्रकार के हैं, किन्तु सविध कानून ही केवल निमित्त प्रकार का है। यही पक्के प्रकार का कानून है। ससद द्वारा स्वीकृत विधेयक सभा की स्वीकृति के उपरान्त कानून बन जाते हैं। वर्तमान समय में ससदीय प्रणाली के विकास के साथ सभा की स्वीकृति अथ केवल एक औपचारिकता मात्र है। ससदीय कानूनों के निर्माण की माँग लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का संगठन (Organization of British Judiciary)

ब्रिटेन में न्याय-व्यवस्था का संगठन 1873 के न्यायालय अधिनियम के अतगत किया गया था जिस 1925 में संशोधित रूप प्रदान किया गया। इंग्लैण्ड यद्यपि एकात्मक देश है किन्तु वहाँ हम न्याय व्यवस्था का मध्यम एकात्मक रूप दृष्टि गोचर नहीं होता। वेल्स तथा स्कोटलैण्ड की न्याय व्यवस्था में अंतर है। इंग्लैण्ड

में दो प्रकार के न्यायालय हैं—दीवानी तथा फौजदारी (Civil & Criminal Courts)। दीवानी न्यायालय नागरिकों के मामलों में, मर्यादा और सामान्य कानून के तहत कार्य करता है। फौजदारी न्यायालय अपराधों के मामलों में कार्य करता है जो कि राज्य की शक्ति के अंतर्गत हैं। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में हम अधिक देना का मिनट है किन्तु उर्जो-उर्जो हम ऊपर की ओर मिला है। यह अर्थ कम जाना जाता है। सभी मामलों का प्रकार के न्यायालय में मिला मिला यहाँ न्यायालय है। मध्यमम हम दीवानी न्यायालयों के तहत पर विचार करेंगे।

दीवानी न्यायालय (Civil Courts)—

(1) काउंटी न्यायालय (County Courts)—इन प्रकार के न्यायालयों में 400 कोर्ट हैं की संख्या के अधिकांशों की सुनवाई का सक्ती है। भूमि की पुनर्प्राप्ति के मुद्दों में इन न्यायालयों में आता है जहाँ भूमि की दर योग्य बीमन 100 पौण्ड से अधिक नहीं है। इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या इंग्लैंड तथा वेल्स में मिलाकर लगभग 500 है। इनमें 60 सर्किट कोर्टों में सगठित किया गया है। प्रत्येक सर्किट कोर्ट में एक न्यायाधीश होता है। इन न्यायालयों में सार्वजनिक न्यायाधीश होते हैं। वे दोरे करते रहते हैं। 7 वर्ष के अनुभव प्राप्त बैरिस्टर्स में से साइकल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इन न्यायालयों में मजान मालिकों और किरायेदारों के झगड़े तथा मजदूरों और मालिकों के झगड़े का भी निपटारा किया जाता है।

(2) सुप्रीम कोर्ट ऑफ जूडिसियर (Supreme Court of Judicature)—यह काउंटी न्यायालयों के ऊपर होता है इसमें भी दो भाग हैं—हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस (High Court of Justice) तथा कोर्ट ऑफ अपील (Court of Appeal)।

(क) हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस (High Court of Justice)—हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस तीन सम्भागों में बंटा है

(i) चांसरी—इसमें बहुधा व सामान्य आते हैं जो पहले औचित्यपूर्ण नियम के न्यायालयों में जाते थे।

(ii) किंग्स बेंच (Kings Bench)—इसमें सामान्य विधि से सम्बंधित मामले आते हैं।

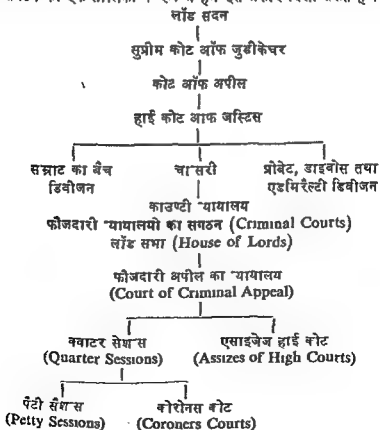
(iii) प्रोबेट डाइविजन तथा एडमिरल्टी डिबिजन (Probate Divorce and Admiralty Division)—प्रोबेट में इच्छा पत्र अथवा वसीयत से सम्बंधित मामले आते हैं। डाइविजन के न्यायालयों में विवाह विच्छेद से सम्बंधित मुद्दों में आते हैं। एडमिरल्टी न्यायालयों में नौकाधिकरण तथा जहाजों आदि के मामले आते हैं।

सम्राट की बेंच का अध्यक्ष लॉर्ड चीफ जस्टिस होता है। इसमें 24 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश माल के मुद्दों के साथ साथ फौजदारी के मुद्दों की भी सुनवाई करते हैं। चांसरी डिबिजन का अध्यक्ष लॉर्ड चांसर होता है। इसमें 7 न्यायाधीश होते हैं। चांसरी न्यायालय मृतकों की साक्षेदारी यास घरोहर तथा कर में सम्बंधित मुद्दों में सुनते हैं। प्रारम्भिक स्तर के न्यायालयों में न्यायाधीश जजों ही मुद्दों की सुनवाई करते हैं। अपील के मामले में 3 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। यदि

काउण्टी कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर का कोर्ट मामला हो तो उच्च न्यायालय के किसी भी विभाग में मुकद्दमे की सुनवाई हो सकती है।

(स) कोर्ट ऑफ अपील (Court of Appeal)—इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काउण्टी तथा उच्च न्यायालय के निणयो के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जाती है। यह सर्वोच्च न्यायालय का ही एक भाग है। इस न्यायालय का अध्यक्ष मास्टर ऑफ दि रोल्ल्स (Master of the Rolls) होता है। इस पदाधिकारी के सहयोग के लिए 8 जस्टिस ऑफ दी पीस (Justice of the Peace) होते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि अपीलें केवल विधि तथा तथ्य के प्रश्न पर होती हैं।

(4) सर्वोच्च न्यायालय (House of the Lords)—लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय है। कोर्ट ऑफ अपील के निणयो के विरुद्ध केवल लॉर्ड सभा में ही अपील की जा सकती है। सारा लॉर्ड सदन अपील नहीं सुनता। अपील केवल कानून के लॉर्डों द्वारा ही सुनी जाती है। कानून के इन लॉर्डों की संख्या 9 है। ये ही कानून की बैच का निर्माण करते हैं। जिस समय कानून के ये लॉर्ड न्यायालय के रूप में बैठते हैं उस समय अध्यक्ष पद लॉर्ड चांसलर ग्रहण करते हैं। लॉर्ड चांसलर मंत्रिमण्डल का भी सदस्य होता है। लॉर्ड सभा ही संयुक्त राज्य का उच्चतम दीवानी न्यायालय है। यह फौजदारी मामलों में भी उच्चतम न्यायालय का कार्य करता है। दीवानी न्यायालय के इस संगठन को एक तालिका के रूप में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं।



(1) जस्टिस ऑफ पीस का 'यायालय (Court of stipendiary Magistrates and Justice of peace)—फौजदारी अभियोगों की श्रेणी में यह इस समय सबसे छोटा 'यायालय है। प्रत्येक 'यायालय में 2 से लेकर 7 तक 'यायालय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन 'यायाधीशों को शांति 'यायाधीश भी कहा जाता है। नगरों में यह काय दण्डनायकों (Magistrates) द्वारा किया जाता है त्रिनकी नियुक्ति गृह सचिव द्वारा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'यायाधीश कानून के विशेषज्ञ नहीं होते, वे अनुभव की कलकों की सहायता से काय करते हैं और उनके पद भी अवैतनिक होते हैं। किंतु नगरों में ये पद वैतनिक होते हैं। शांति 'यायाधीशों की नियुक्ति साँड चांसलर द्वारा की जाती है। इन शांति 'यायाधीशों को 14 दिन तक का कारावास तथा 90 शिलिंग तक जुर्माने करने का अधिकार है।

(2) पेट्टी सेशंस का 'यायालय (Court of Petty Sessions)—ये 'यायालय ऐसे मुकद्दमों का फैसला करते हैं जिनमें जूरी की आवश्यकता नहीं होती। यातायात, चोरी, चोट तथा आक्रमण आदि के मामले इन 'यायालयों के सामने रखे जाते हैं। प्रत्येक 'यायालय में कम से कम 2 शांति 'यायाधीश होते हैं। इन 'यायालयों को 50 से लेकर 100 पौण्ड तक तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में 500 पौण्ड तक जुर्माने करने का अधिकार है। इन्हें 6 माह तक की तथा विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष तक की सजा देने का भी अधिकार है। यदि किसी मुकद्दमे में अपराधी को 3 माह से अधिक की सजा मिलने की सम्भावना हो तो उस परिस्थिति में मुकद्दमे का निणय एक जूरी के द्वारा होता है।

(3) कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस (Court of Quarter Sessions)—ऊपर जिन दो प्रकार के 'यायालयों का उल्लेख किया गया है उनके ऊपर कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस का 'यायालय होता है। इसे काउण्टी 'यायालय भी कहा जाता है। इसमें काउण्टी 'यायालयों के सारे शांति 'यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। ये ही अभियोगों की भी सुनवाई करते हैं। इन्हें कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस इसलिए कहा जाता है कि ये वर्ष में केवल मुकद्दमों को सुनते हैं। इस प्रकार के 'यायालयों को निम्न 'यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार है। ये बड़े फौजदारी मुकद्दमों में भी अपील सुनते हैं किंतु वे इतने गम्भीर प्रकार के नहीं होते चाहिए कि उन्हें कोर्ट ऑफ एसाइज में ले जाने की आवश्यकता पड़े। हत्याओं एवं देशद्रोहिता से सम्बंधित मुकद्दमों को सुनने का अधिकार इन्हें नहीं होता। इन 'यायालयों के 'यायाधीशों को रिकार्डर कहा जाता है। वे वैतनिक होते हैं। इनमें निणय करते समय जूरी का प्रयोग किया जाता है।

(4) कोर्ट ऑफ एसाइजेज (Court of Assizes)—इस प्रकार के 'यायालयों के समक्ष हत्या दण्डद्रोह डकैती तथा गम्भीर प्रकार के मुकद्दमों जाते हैं। इन 'यायालयों के 'यायाधीश वर्ष में तीन बार अपना 'यायालय लगाते हैं। सम्राट की जुडीशिपल बेंच के सदस्य इसमें भी मग्स्य होते हैं और दौरा करते हैं। वे एक काउण्टी से दूसरी काउण्टी में जाते हैं। इस प्रकार के 'यायालय को सेट्रल क्रिमिनल कोर्ट तथा साधारण भाषा में आल्ड बेली (Old Belly) कहा जाता है। दस्तुन एसाइजेज एक प्रकार से हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस की ही शाखाएँ हैं।

(5) फौजदारी अपील का न्यायालय (The Court of Criminal Appeal)—यह न्यायालय भी हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस की एक शाखा है। इसमें सामान्यतः न्यायाधीशों की संख्या तीन होती है। इसमें लाइ चीफ जस्टिस तथा सभा के न्यायाधीशों के सदस्य होते हैं। क्वाटर सेशन तथा एसडजेज के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध इसमें अपील सुनी जाती है। कानूनी प्रश्नों पर इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपील लायी जा सकती है। कानूनी प्रश्नों पर अपील तभी लायी जा सकती है जबकि महायायवादी यह प्रमाण पत्र दे दे कि अमुक कानूनी प्रश्न अपील करने योग्य है। कानूनी प्रश्नों से सम्बंधित अपील की संख्या सबदा कम रहती है।

(6) लाइ सदन (House of Lords)—जिस प्रकार दीवानी मुकद्दमों में यह सर्वोत्तम न्यायालय है उसी प्रकार फौजदारी मामलों में भी यह अंतिम न्यायालय है, इसमें कानून के लॉर्ड ही अपील सुनते हैं। निर्णय एवं सुनवाई के समय मारे सदस्य उपस्थित नहीं होते।

प्रीवी कौंसिल की न्याय समिति

(Judicial Committee of the Privy Council)

यह एक न्याय-समिति है जिसे घातक मामलों में उपनिवेशों तथा अधिराज्यों (Dominions) के उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यह अधिराज्यों की इच्छा पर है कि वे अपने उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भेजे अथवा नहीं। सम्राट की ओर से प्रीवी कौंसिल की न्याय समिति उन अपीलों को सुनती है। ऐसी अपील की संख्या बहुत कम होती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का कोई मुकद्दमा इसके पास नहीं भेजा गया है। इसे सम्राट को सलाह देने वाली समिति भी कहा जाता है। प्रीवी कौंसिल की न्याय समिति में लॉर्ड चांसलर, भूतपूर्व लाइ चांसलर लॉर्ड सदन के कानून के लॉर्डस तथा प्रसिद्ध विधिवेत्ता सम्मिलित किये जाते हैं। कुल मिलाकर उसमें 20 सदस्य होते हैं। कानून के लॉर्ड यहाँ पर प्रीवी कौंसिल के रूप में ही कार्य करते हैं। अधिकांश कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्रीवी कौंसिल के निर्णय सपरिपद आदेशों के रूप में लागू किये जाते हैं।

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का मूल्यांकन

(British Judicial System evaluated)

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था अपनी निष्पक्षता तथा प्रवीणता के लिए विश्वविख्यात है। न्यायालयों की कार्यप्रणाली बहुत ही गम्भीर है निम्न न्यायालयों तक की प्रतिष्ठा अमेरिका के उच्च न्यायालयों की अपेक्षा अधिक कही जाती है। जितना सुदूर, स्वस्थ तथा गम्भीर वातावरण वहाँ के न्यायालयों में हमें देखने को मिलता है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। न्यायाधीश एक पंच के रूप में कार्य करते हैं। वे अवैपण के रूप में कार्य नहीं करते अपराधी को प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। निर्णयों की शीघ्रता ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्य विधि सरल है। न्याय व्यवस्था प्रावधिक कम तथा व्यावहारिक अधिक है। वहाँ पर न्याय व्यवस्था कुछ अर्थों में असुविधाजनक केवल इसलिये है कि वहाँ के ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था है। विधि की समानता वहाँ का एक महत्वपूर्ण अनुदाय है।

अमेरिका की भाँति इंग्लैण्ड में भी वकीलों की फीस इतनी अधिक है कि जनता 'यायालयों में जाने का सुभमता से साहस नहीं करती। इसी कारण वहाँ की भेहगी 'याय व्यवस्था' की आलोचना करते हुए कभी-कभी यह कहा जाता है कि 'यायालय घनिकों के रक्षक हैं। यद्यपि गरीबों के लिए नि शुल्क 'याय की व्यवस्था की गयी है किंतु वह अभी सफल नहीं हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ गुप्त न्याय की व्यवस्था नहीं है और न ही विशेष 'यायालय स्थापित करने की परम्परा जान पड़ती है। अपनी निष्पक्षता तथा शीघ्र निणय करने की विशेषता के लिए यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ 'याय-व्यवस्था है।

References

Dicey *Law of Constitutions*

Jackson *Machinery of Justice in England*

James Phillips *Introduction in English Law*

Laski *Parliamentary Government in England Chapter VII*

Vardiez *Introduction to British Constitutional Law*

Wade & Phillips *Constitutional Law*

Jennings *Law of Constitution*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. ब्रिटिश 'याय व्यवस्था' की विशेषताओं का वर्णन करें।
(Point out the main features of Judicial system in England)
2. इंग्लैण्ड के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का संगठन कैसे होता है ?
(How is Judiciary organised in Civil and Criminal Courts in England)
3. 'विधि का शासन ब्रिटिश संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है।' इस कथन की व्याख्या करें।
('The Rule of Law is a distinctive characteristic of the English Constitution ' (Dicey) Explain)
4. विधि के शासन से आप क्या समझते हैं ? ब्रिटिश विधि के शासन और फ्रांसीसी कानून की तुलनात्मक विवेचना करें।
(What do you understand by the term Rule of Law Compare the Rule of Law in England with the Administrative Law in France)
5. 'कानून के राज्य' का क्या अर्थ है ? यह नागरिकों के अधिकारों को कहीं तक सुरक्षित रखता है ?
(What is meant by 'Rule of Law' ? How far it does not guarantee the rights of the people ?)

7

राजनीतिक दल (Political Parties)

"Without party System the State has no elasticity as true self determination"
—R M MacIver

राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र तथा प्रतिनिध्यात्मक प्रकार की शासन प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों की उपयोगिता अकथनीय है। राजनीतिक दलों का महत्व यहाँ तक बढ़ गया है कि हम सबसत्तावादी राष्ट्रों में दल तथा शासन के मध्य व्यवधान तक नहीं करते। लोकतन्त्र का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो वह राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। राज्य तथा जनता के हितों में समन्वय स्थापित करने वाला पुनः राजनीतिक दल है। यह लोकतन्त्र की संचालन शक्ति है।

राजनीतिक दलों को गुट नहीं कहा जा सकता क्योंकि गुट स्थायी नहीं होगा और न ही उनके सदस्यों में उद्देश्य की समानता पायी जाती है। राजनीतिक दल वस्तुतः व्यक्तियों की ऐसी समझदारी है जिसके सदस्य सामान्य लक्ष्यों की उपपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बक (Burke) के अनुसार "राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों। गणतन्त्रिक सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रीय हित का परिवर्द्धन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हुए हों। गेटेल (Gettell) के शब्दों में 'राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई की भाँति कार्य करते हैं और अपनी मतदान ईच्छा का प्रयोग करते हुए शासन को अपने नियंत्रण में रखने और अपने उद्देश्यों की कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं।' लास्की (Laskey) के शब्दों में 'राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक ही उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं।' ¹

न्यूमैन (Newman) ने राजनीतिक दलों को 'संयोजक, निर्देशक, संचालक' लोकतन्त्र की सफलता राजनीतिक दलों की उपस्थिति पर निर्भर है। दल का यह कहना सही है कि राजनीतिक दल एक ही उद्देश्य के लिए असांख्य नीतियों के कारण या तात्पर्य से एक ही दिशा में प्रशिक्षण राजनीतिक दलों की उपस्थिति है।

1 By a political party we mean a group of persons who act together as a political unit.

बड़ी सेवा आलोचना के माध्यम से करते हैं। वे हर प्रकार के दृष्टिकोण को आम जनता के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की सेवा इस रूप में करते हैं कि वे लोकमत की अभिव्यक्ति करते हैं, सावजनिक कल्याण की पेश-कश करते हैं और लोकहित की सही रूप में साधना करते हैं। लोकमत ही लोकतंत्र का जीवन है। जनता की गतिविधियों से सरकार को परिचित कराकर उसे एक नई दिशा दिखाते हैं। राजनीतिक दल सरकार तथा जनता के मध्य बड़ी काय करते हैं। जनता तथा शासन लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिये हैं। इन दोनों के मध्य धुरी का काय राजनीतिक दल करते हैं। ससदीय प्रणाली राजनीतिक दलों का एक रूप है। ससदीय लोकतंत्र तो राजनीतिक दलों के बिना असम्भव है। राजनीतिक दल वक्तविक सरकार की रचना करते हैं। राजनीतिक दलों की उपयोगिता केवल ससदीय प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। वरन् वे अभ्युत्थात्मक सरकार की सफलता के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही सत्ता को सँभालते हैं और शासन का संचालन करते हैं। सदस्यों को एक सूत्र में बाँधने तथा एक विचारधारा में विश्वास उत्पन्न करने की अनोखी सेवा राजनीतिक दल करते हैं। जन कल्याण के बहुत से काय राजनीतिक दलों द्वारा किये जाते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में एक बहुत बड़ा योग राजनीतिक दलों का है। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा करते हैं। राजनीतिक दलों के महत्व पर दृष्टिपात करते हुए ब्राइस (Bryce) ने कहा है, "राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। कोई भी बड़ा देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में व्यवस्था उत्पन्न करते हैं।"¹

इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति अनायास रूप में हुई है। राजनीतिक दल विकास के परिणाम हैं। स्टुअर्ट शासकों के साथ अधिकारों को लेकर ससद के साथ संघर्ष था। कुछ जो राजा के अधिकारों का समर्थन करते थे, वे कोवेलियर (Covalier) कहलाये और कुछ ससदीय अधिकारों को उच्चतर मानते थे वे राउण्ड हैड (Round Heads) कहलाये। 1688 की क्रांति के पश्चात् इन दलों के नाम व्हिग (Whigs) तथा टोरी (Tories) पड़ गये। व्हिग ससद के समर्थक थे तथा टोरी सम्राट के। व्हिग प्रधानमंत्री वालपोल के नेतृत्व में बहुत समय तक सत्तारूढ़ बने रहे। मंत्रिमण्डलीय शासन के विकास के द्वारा दलीय पद्धति को एक नवीन दिशा तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड की सामाजिक व्यवस्था में नूतन परिवर्तन हुए। टोरी चर्च तथा जमींदारों का समर्थन करते थे और व्हिग प्रगतिशील विचारों का। ये ही दल 1832 के उपरांत अनुदार दल (Conservative) तथा उदारवादी दल (Liberals) कहलाये। 19वीं शताब्दी इन दलों के मध्य संघर्ष की शताब्दी है। कभी अनुदारवादी दल तो कभी उदारवादी दल सत्ताधारी बनते रहे। 1835 में जो सुधार हुए उसका उदारवादी दल समर्थक था तथा अनुदार

1 Parties are inevitable. No free country has been without them. No one has shown how representative government could be worked without them. They bring order out of the chaos of a multitude of voters. —Bryce

वादी दल घोर विरोधी। 19वीं शताब्दी में अनुदार वादी दल का महत्वपूर्ण नेता डिजरेली था और उदारवादी दल का ग्लेडस्टोन।

बीसवीं शताब्दी के क्रांतिकारी परिवर्तनों तथा वामपंथी विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप एक नये दल का सूत्रपात हुआ और वह था श्रमिक दल (Labour Party)। समाजवाद का प्रभाव श्रमिक वर्ग को आकर्षित कर रहा था। मजदूर दल का जन्म 1906 से हुआ। 1910 से लेकर 1914 तक जितने भी प्रगतिशील विधेयक संसद में आये उन सबको इस दल का समर्थन प्राप्त रहा। 1923 तक उदारवादी दल की प्रतिष्ठा तथा संसद में उसके सदस्यों की संख्या कम होने लगी थी। मजदूर दल को पर्याप्त सफलता मिली। इसी वर्ष मंत्रिमण्डल को कई अहम और खतरनाक बातों का सामना करना पड़ा और नये आम चुनाव कराये गये। 1923 में मजदूर दल ने उदारवादियों के सहयोग से रैम्से मक डोनेल्ड के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। किंतु 1924 में इसका पतन हुआ। 1924 में नये चुनाव कराये गये और अनुदार दल शक्तिशाली बना जो 1929 तक शासन बनाये रहा। 1929 में मजदूर दल ने उदारवादी दल के सहयोग से पुनः जिस शासन का गठन किया वह 1931 के आर्थिक संकट को बर्दाश्त न कर सका और नये चुनाव कराये गये। 1931 से 1935 तक अनुदार दल ने प्रधानमंत्री बाल्डविन के नेतृत्व में अपना प्रभुत्व जमाये रखा। 1937 में चैम्बरलेन प्रधानमंत्री बने जिन्हें 1940 में सर विसटन चर्चिल के पक्ष में अपना पद त्याग करना पड़ा। युद्धावधि में चर्चिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। 1945 में युद्ध की समाप्ति पर प्रथम बार मजदूर दल को लोकसदन में 400 सीटें प्राप्त हुईं। 1950 तक मजदूर दल ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किये। 1951 के आम निर्वाचनों के पश्चात् उदार दल के सदस्यों की संख्या लोकसदन में नगण्य रह गयी। इस कारण ग्रेट ब्रिटेन में दो ही प्रमुख दल रह गये हैं—अनुदारवादी दल (Conservatives) तथा श्रमिक दल (Labour Party)। शेष छोटे छोटे दल हैं किंतु उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं है। 1955 से लेकर 1964 तक अनुदारवादियों का प्रभुत्व जमा रहा। 1964 के आम चुनावों में मजदूर दल को लोकसभा के 630 स्थानों में से 317 स्थान प्राप्त हुए तथा अनुदारवादी दल को 303 स्थान प्राप्त हुए। उदारवादी दल को केवल 9 स्थान प्राप्त हुए। 18 जून 1970 को इंग्लैण्ड में नये निर्वाचन हुए जिनके फलस्वरूप अनुदार दल विजयी हुआ।

गत कुछ वर्षों में आम चुनाव के पश्चात् दलों की स्थिति (लोक सदन)

वर्ष	अनुदारवादी दल	श्रमिक दल	उदारवादी दल	अन्य दल
1945	212	394	12	22
1950	298	315	9	3
1951	321	295	6	3
1955	346	277	6	1
1959	365	258	6	1
1964	304	310	19	0
1966	253	363	12	2

ब्रिटिश राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएँ

(Features of British Political Parties)

(1) द्विदलीय प्रणाली (Bi-Party System)—न्यूमैन (Newmann) के अनुसार 'ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना है जिसके निर्माण में एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र सहायक है।' द्विदलीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रभाव सरकार की स्थिरता है। राजनीतिक दलों के जन्म से ही ब्रिटेन में दो दलों की सदैव प्रधानता रही है। थमिक दल से पूर्व अनुदारवादी दल तथा उदारवादी दल की प्रमुखता थी और 1906 के बाद से उत्तरोत्तर थमिक दल की प्रगति हुई है और उदारवादी दल का ह्रास हुआ है। आज भी इनमें से दो ही राजनीतिक दलों की व्यवस्था एक प्रधानता है—अनुदारवादी दल तथा थमिक दल। द्विदलीय व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र को अधिक शक्तिशाली बनाये हुए है। जनाधिकारों की सुरक्षा भली प्रकार से होती है।

(2) केन्द्रीकरण (Centralization)—ब्रिटेन की दल प्रणाली में केन्द्रीकरण की भावना पायी जाती है। दलीय संगठन का स्वरूप एक पिरामिड की भाँति है। इसका आधार चौड़ा है तथा शिखर की ओर जाते जाते वह संकरा होता जाता है। दल की नीचे की शाखाएँ अपने से उच्चतर निकायों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आज्ञा का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर चलता है। केन्द्रीय नेता अपने संसद सदस्यों तथा स्थानीय नेताओं पर कठोर नियंत्रण रखते हैं।

(3) गतिविधियों में निरन्तरता (Continuity of Operations)—फाइनर (Finer, H) के शब्दों में, 'अंग्रेजी राजनीतिक दल आम निर्वाचनों के बीच सो नहीं जाते और सुस्ताने नहीं लगते। वे जनता को शिक्षा देने का कार्य निरन्तर बड़े उत्साह के साथ करते रहते हैं।' साहित्य तैयार करना, आम सभाएँ करना, शोध कार्य तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करने में राजनीतिक दल लगे रहते हैं। ब्रिटिश दलों की गतिविधियाँ सदैव चलती रहती हैं।

(4) मध्यमार्ग एवं समझौता (Moderation and Compromise)—ब्रिटिश राजनीतिक दल मध्यमार्गीय एवं समझौतावादी हैं। अनुदार दल पूर्णतः अनुदारवादी नहीं है, इसने भी कई बार सुधारवादी तथा प्रगतिशील कार्यक्रमों को अपनाया है। इसी प्रकार हम थमिक दल को भी कट्टर समाजवादी नहीं कह सकते। विल्सन सरकार ने कारखानों में मजदूरों को हड़ताल करने के अधिकार के प्रति अपनी सहमति प्रकट नहीं की। दोनों दलों ने संसद से बाहर तथा संसद के अंदर मध्यमार्गीय तथा समझौतावादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। वे एक-दूसरे की आलोचना तो करते हैं किन्तु वह ध्वसात्मक के स्थान पर सज्जात्मक होती है। दोनों ही राजनीतिक दल निरुद्धियों में विश्वास करते हैं। थमिक दल चाहते हुए भी राजतंत्र को समाप्त नहीं कर सका। उसने समय-समय पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे हैं किन्तु कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि वह इसे पूर्णतः समाप्त करना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि थमिक दल प्रगतिशील एवं समाजवादी होते हुए भी निरुद्धियों तथा पुरानी संस्थाओं को बनाये रखने के पक्ष में हैं। थोड़े-बहुत व्यापारी भी थमिक दल का समर्थन करते हैं। मध्य वर्ग के लोग कभी किसी दल

का तथा कभी किसी दल का समयन करते हैं। राजनीतिक दलों के व्यवहार में काफी लोचनीलता पायी जाती है। समय के तकाजे पर ये मिल जाते हैं। 1940 में चम्बरलेन को हटाकर चर्चिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन इसका एक अच्छा उदाहरण है।

(5) अनुशासन एवं साहचर्य—(Discipline & Cohabitation)—काटन तथा हज के शब्दों में, 'ब्रिटिश दल प्रणाली की मरलता और उमका अनुशासन अमेरिकावासियों के लिए प्रशंसा एवं ईर्ष्या का विषय है।'।

सचेतक ही सदस्यों को बताते हैं कि सदस्य को क्या बोलना है तथा किसके पक्ष में अपना मत देना है। दल का समयन दल को एक व्यक्ति का रूप दे देता है तथा उसे संगठित और अनुशासित बनाता है।

(6) नेता का महत्व (Importance of Leadership)—ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में नेता का महत्व बहुत अधिक है। नेता के माध्यम से राजनीतिक दल सामाजिक जीवन में अपने व्यक्तित्व की छाप लगाते हैं। वस्तुतः आम चुनाव में प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। जनसाधारण दल के नेता के व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों से अधिक प्रभावित होता है। दोनों बड़े राजनीतिक दलों में नेता को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।

(7) ससब सदस्यों पर नियंत्रण (Control on the Members of the Parliament)—इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों की एक और व्यवस्था यह रही है कि दल के सदस्यों पर दल का कठोर नियंत्रण रहता है। दलीय सहायता पर सदस्यों की निर्वाचन में सफलता सुरक्षित रहती है। दलीय नीतियों के विरोध का अर्थ है राजनीति से स यास। इंग्लैण्ड में स्वतंत्र अथवा निदलीय रूप से जीतने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ही कम रहती है। दल के नेता के व्यक्तित्व का इस दिशा में पर्याप्त महत्व होता है।

(8) वर्ग प्रकृति एवं सद्भातिक मतभेद (Class Character and Ideological Difference)—ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में वर्गगत भिन्नता पायी जाती है, अनुदार दल के हित बहुत कुछ सीमा तक उच्च वर्ग से बद्ध हैं। श्रमिक वर्ग बहुत कुछ सीमा में मजदूर वर्ग में सहयोग एवं समयन प्राप्त करता है। दोनों ही दल मध्यवर्ग के सहयोग के प्रत्यासी बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त उद्देश्य की दृष्टि से भी अनुदारवादी दल व्यक्तिवादी विचारधारा में विश्वास करते हुए स्वतंत्र व्यापार तथा उच्च वर्ग के हितों की संरक्षण में विश्वास करता है। इसके विपरीत श्रमिक दल समाजवाद, केन्द्रीकरण तथा एक राष्ट्रीयकृत अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करता है।

प्रमुख राजनीतिक दल (Main Political Parties)

अनुदारवादी दल (Conservatives)

नीतियाँ तथा संगठन—यह कहा जाता है कि 1880 में जॉन विल्सन प्राकर ने 'कन्जर्वेटिव' शब्द का प्रयोग किया था। जेनिंग्स के अनुसार जब 1832 का

1 The Simplicity and discipline of British Party System is an object of admiration and even to many Americans
—Carter & Hartz

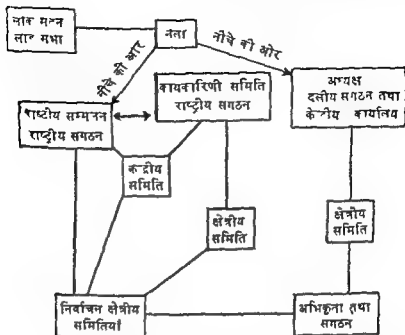
सुधार अधिनियम पारित हो गया और हिंस्र की विजय हुई तो टोरी दल ने अपना नाम बदल कर कंजरवेटिव रखा जिसका आशय था कि रक्षा की जाम। रक्षा का सम्बन्ध प्राचीन परम्पराओं तथा उच्च वर्ग के अधिकारों से है। टोरी दल सुधार विधेयक के विरुद्ध आवाज उग्रवाद का विरोध करके ही उठा सकता था। सुधारवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध पुरातन सत्ताओं एवं परम्पराओं में विश्वास करके आवाज उठाना उस समय से अनुदारवादी दल का मौलिक ध्येय बन गया। अनुदार दल का विश्वास निम्नलिखित नीतियों में है

- (1) प्राचीन परम्पराओं, सत्ताओं तथा विचारधारा में विश्वास।
- (2) पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद का समर्थन।
- (3) लार्ड सभा को शक्तिशाली बनाये रखने का समर्थन।
- (4) निजी सम्पत्ति, उद्योगों में निजी स्वामित्व का समर्थन।
- (5) राष्ट्रीय एकता का समर्थन।
- (6) समाजवाद का विरोध।
- (7) राष्ट्रीयकृत अथ-यवस्था के स्थान पर व्यक्तिवादी अथ व्यवस्था का समर्थन।
- (8) प्रत्यक्ष करों के लगाने का समर्थन।
- (9) जातीय श्रेष्ठता।
- (10) अन्तर्राष्ट्रवाद का विरोध।
- (11) दृढ़ विदेश नीति में विश्वास।
- (12) राजमुकुट तथा राजतन्त्र की अक्षुण्णता।

किन्तु इससे हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि अनुदारवादी दल परिवर्तन विरोधी, दकियानूसी तथा झगडालू प्रवृत्ति का है। वह परिवर्तन तो चाहता है किन्तु शर्तें शर्तें। 1947 के बाद से इस दल के दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिवर्तन आ रहा है। युवा वर्ग प्रगतिशीलता को लाने के लिये लालायित है। केंद्रीय नियोजन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। 1949 में अनुदारवादी दल ने अपनी पत्रिका Right Road for Britain में सार्वजनिक रोजगार की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को समर्थन प्रदान किया। 1951 के चुनाव घोषणा पत्र में राष्ट्रीय रक्षा को प्रथम तथा जनसाधारण के लिए आवास व्यवस्था को द्वितीय स्थान प्रदान किया। 1955 में स्वतंत्र उद्योग एवं स्वतंत्र व्यापार की अनुदारवादी दल ने प्रतिज्ञा की। आरम्भ में इस दल की सदस्यता केवल बड़े बड़े भू-स्वामियों तक सीमित थी किन्तु बाद में बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने भी इस दल की सदस्यता ग्रहण की। मध्यम वर्ग में कुछ ऐसे लोग भी जो कि अपने को पूँजीपतियों तथा धनाढ्यों के बराबर समझते थे इसके सदस्य बन गए। किन्तु निर्वाचन में मध्य वर्ग के सदस्यों के सहयोग की ओर अधिक प्रतीक्षा होती है। मध्यम वर्ग के समर्थन बिना अनुदार दल के लिए कोई निर्वाचन जीतना कठिन है। सिटनी तथा बर्क ने भी इस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है।

संगठन (Organization)

रूढ़िवादी दल (Conservative Party)



अनुदात्तावादी दल का केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, उसे नेशनल यूनियन ऑफ नॉन-जरवेडिब एण्ड यूनियनिस्ट एसोसिएशन कहा जाता है, इसमें एक सभापति, एक अध्यक्ष तथा तीन उपाध्यक्ष होते हैं। दो सचिव इससे पदाधिकारी होते हैं। वष में एक बार इसका अधिवेशन होता है, अधिवेशन में वर्तमान उपलब्धियों पर परिचर्चा के अतिरिक्त आगामी वष के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है, इस सम्मेलन में नेता भाग नहीं लेता। सम्मेलन के सदस्य मंत्रियों से अपनी नीति स्पष्ट करने को कह सकते हैं। वार्षिक अधिवेशन में केन्द्रीय कार्यालय के सदस्य, क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य, संगठनों के प्रमाणित एजेंट भाग लेते हैं। इस केन्द्रीय संगठन का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय मंजरीय सभा की स्थापना तथा सभी संगठनों की स्थापना करना है। यह केन्द्रीय कार्यालय से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखता है।

केन्द्रीय परिषद (Central Council)—इसे केन्द्रीय परिषद कहा जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः वष में एक बार इसका सम्मेलन अवश्य होता है। यह राष्ट्रीय सङ्गठन के पदाधिकारी का निर्वाचन करती है। राष्ट्रीय सङ्गठन के नियमों में संशोधन करती है। इसका अधिवेशन भी वष में एक बार होता है। केन्द्रीय परिषद में लगभग 2000 सदस्य हैं।

कामकारिणी समिति (Executive Committee)—इसमें लगभग 150 सदस्य होते हैं। दल में सम्मिलित सदस्य तथा दल की विभिन्न शाखाओं में अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। इस समिति की बैठक दो मास में एक बार अवश्य होती है। इसका एक सभापति होता है जिसका निर्वाचन उसके सदस्य स्वयं करते हैं।

इसके प्रमुख कार्य हैं—(1) राष्ट्रीय सगठन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नाम देना, (2) क्षेत्रीय सगठन की कार्यकारिणी द्वारा प्रेषित किसी विवाद पर निर्णय देना, (3) अथ परामशदात्री समितियों की स्थापना करना, (4) कार्यकारिणी द्वारा उठाये गये किसी प्रश्न पर विचार करना, (5) वार्षिक सम्मेलन तथा केन्द्रीय परिषद को अपनी गतिविधियों के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (6) केन्द्रीय परिषद की बैठकें जब न हो रही हों उस समय उसके कार्यों का सम्पादन करना ।

सामान्य उद्देश्य समिति (General Purpose Committee)—इसमें 56 सदस्य होते हैं । इसकी बैठक प्रत्येक माह होती है । केन्द्रीय परिषद तथा वार्षिक सम्मेलन की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करना, प्रांतीय परिषदों, क्षेत्रीय सगठनों और केन्द्रीय सघ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार करना तथा सगठन के सब साधारण एवं असाधारण कार्यों का सम्पादन करना इसके प्रमुख कार्यों में से हैं ।

केन्द्रीय कार्यालय (Central Office)—अनुदारवादी दल का केन्द्रीय कार्यालय लंदन में स्थित है । इसका एक प्रमुख सचालक होता है । यह दल के नेता के प्रति उत्तरदायी रहता है । दलीय सफलता में इसका महत्वपूर्ण अनुदाय रहता है । इसके प्रमुख कार्य हैं—(1) नवीन सगठनों की स्थापना, (2) नवीन सगठनों का माग निर्देशन करना, (3) दलीय कार्यक्रम का प्रचार, (4) दलीय साहित्य का सबत्र वितरण, (5) निर्वाचन के समय दलीय उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करना ।

संसदीय सगठन (Parliamentary Organization)—संसद के प्रत्येक सदन में दल का सगठन होता है । इस सगठन को परम्परानुसार 1922 की समिति बहकर पुकारा जाता है । इसका एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, दो सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष होता है । 12 और सदस्य दल द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो संसदीय सगठन की कार्यकारिणी कहलाते हैं । इसकी संस्था में एक बैठक अवश्य होता है जिसमें दल की नीतियों पर विचार किया जाता है । दल का सचेतक (Whip) सदस्यों को अनुशासन में रखता है । लॉर्ड सभा में दलीय सगठन इतना महत्वपूर्ण नहीं है । लॉर्ड सभा पर तो अनुदारवादी दल का प्रभुत्व स्थायी ही है ।

संसदीय सगठन के अतिरिक्त दलीय सगठन को 12 क्षेत्रों (Areas) में विभाजित किया गया है । इन क्षेत्रों का नियंत्रण एक समिति द्वारा किया जाता है, जिस प्रांतीय परिषद कहा जाता है । ये परिषदें निर्वाचन क्षेत्रों तथा सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करती हैं । अनुदारवादी दल के सगठन में सबसे निम्न स्तर पर क्षेत्रीय सगठन होता है । इसे निर्वाचन प्रांतीय सघ (Constituency Association) भी कहा जाता है । क्षेत्रीय सगठनों के अतिरिक्त दल में 1500 क्लब भी हैं । ये जनता से सम्पर्क रखते हैं और क्षेत्रीय सगठन के लिए अपना एक-एक प्रतिनिधि भेजते हैं ।

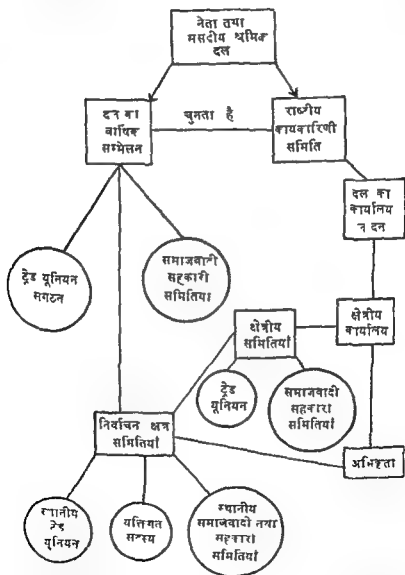
नेता (Leader)—अनुदारवादी दल में नेता का बड़ा महत्व है । केन्द्रीय कार्यालय उसी की अध्यक्षता में कार्य करता है । संसद में उम्मीदवारों का नियंत्रण में रहता है । सगठन की नीतियाँ नेता की इच्छा से निश्चित की जाती हैं । अनुदारवादी दल जब विपक्ष में होता है तो उसका नेता एक छाया मंत्रिमण्डल की स्थापना कर लेता है । राष्ट्रीय सगठन की सारी विचारियों को मानता है और उनका अध्यक्ष नहीं है । अनुदारवादी दल के नेता की स्थिति पर प्रधान मंत्री हुए चार्ल्स - टन न कहा

या कि अनुदारवादी दल का संगठन उसी समय तक जनतंत्रवादी है जब तक कि वह शिखर तक नहीं जाता। किंतु 1965 के पश्चात अनुदार दल ने भी अपने नेता के सम्बन्ध में निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया है। पहले वही नेता होता था जिसे सम्राट प्रधानमन्त्री पद के लिए आमन्त्रित कर लिया करता था।

श्रमिक दल—कार्यक्रम तथा संगठन

(Labour Party—Policy & Organization)

संगठन का रेखाचित्र



उपर्युक्त चित्र से श्रमिक दल का संगठन काफी स्पष्ट हो जाता है। इस दल की स्थापना 1906 में हुई। पहले इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति था। इस दल

ADVANCE COPY
Meant for Consideration
NOT FOR SALE

का यह विश्वास था कि उदारवादी तथा अनुदारवादी दल दोनों ही पुराने पड़ गये हैं और बेकार हो चुके हैं। इसकी स्थापना निम्नवर्ग की दशा सुधारने की दृष्टि से की गई थी। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी यह उग्र मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं रहा। श्रमिक दल उग्र आतंककारी विचारधारा का पोषक नहीं है। उसके आदर्श विश्व के अग्र राजनीतिक दल से काफी पृथक रहे। इमने ब्रिटिश परम्पराओं को बनाये रखा। वग-सघष में कभी भी अपनी आस्था प्रकट नहीं की। 1920 में इसके जो सदस्य मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे वे हताश होकर पृथक हो गये तथा साम्यवादी दल में सम्मिलित हो गये। साम्यवादी दल के इस सुझाव को इसने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह इसके साथ मिल जाय। यह दल 1922 के पश्चात् अधिक लोकप्रिय होने के कारण उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा है। 19 जून, 1970 से पूर्व इस दल का शासन था। यह इसी तथा चीनी प्रकार की रक्तप्लुत क्रान्तियों का खण्डन करता रहा है। इस दल की नीतियाँ इस प्रकार हैं —

(1) एक नवीन सामाजिक ढाँचे की रचना करना चाहता है। ऑग तथा जिक (Ogg & Zink) के अनुसार, श्रमिक दल ने “एक नई, विस्तृत, प्रत्यक्ष रूप में भयकर तथा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति को अपनाया है जो एक नवीन सामाजिक ढाँचा बनाने में विश्वास करती है।” श्रमिक दल प्रकृति से क्रान्तिकारी न होकर सुधारवादी है।

(2) निजी सम्पत्ति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व का समर्थन।

(3) आर्थिक क्षेत्र में खुले बाजार का विरोध।

(4) प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। 1945 में श्रमिक दल की सरकार ने लोहा, कोयले की खानें, इस्पात, यातायात, इधन व शक्ति, बँकों का राष्ट्रीयकरण आदि कई समाजवादी सार्वजनिक नियन्त्रण की योजनाओं का समर्थन किया।

(5) श्रमिक दल राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का 20% राष्ट्रीयकरण करना चाहता है तथा 80% व्यक्तिगत स्वामित्व के रखने के पक्ष में है किन्तु उस भाग का नियन्त्रण राजकीय नियोजन के अनुसार होना चाहिए।

(6) पूँजीवाद का विरोध, धन का वितरण वार्षिक आधार पर होना चाहिए, धन का एकीकरण छोटे ही व्यक्तियों के हाथों में नहीं होना चाहिए। यह पूँजीवादी ढाँचे को जनतन्त्रीय ढंग से परिवर्तित करने के पक्ष में है। बार्कर (Barker) के शब्दों में, श्रमिक दल यह चाहता है कि “ब्रिटेन समानता के नये युग में प्रवेश करे और इस प्रकार प्रवेश करे कि शरणगुल न हो। इस बात का भी प्रदर्शन न करे कि समानता का नये युग में पदापण समाजवादी तथा अन्य किसी व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है अपितु स्वेच्छा से काम हो। जिससे वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो जाये और वास्तव में समानता आ जाये।”

(7) श्रमिक दल यह चाहता है कि कृषि में म आयात क्षेत्र में इस प्रकार अकुल रह कि कृषकों के म = बड उनकी पदावार का निश्चिन्त मूल्य मिलेगा।

(8) श्रमिक दल समाज व लोच-वत्स

विन्तु उपाजन की यह पद्धति वह लोकतंत्रीय व्यवस्था में चाहता है। फाइनर (H Finer) के शब्दों में, 'श्रमिक दल 'दास कपीटल' की अपक्षा बाइबिल में अधिक विश्वास करता है।'

(9) साम्राज्यवाद का कटु विरोध, साम्राज्यवादी उपनिवेशों के सम्बन्ध में उसकी धारणा है कि उन्हें शीघ्रता से स्वशासी बना दिया जाय।

(10) श्रमिक दल विश्व समाजवादी सरकार में विश्वास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्वास करता है।

(11) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का समर्थन करता है।

(12) समाज के सीमित अधिकारों का समर्थन करता है।

(13) लाब सभा को अनुपयोगी समझता है और उसके उन्मूलन की बात कहता है।

(14) साम्राज्यवादका विरोध तथा समाजवादी कॉमनवैलथ का समर्थन करता है।

(15) अनुपाजित आय पर अधिक कर का समर्थन करता है।

(16) इंग्लैण्ड को यूरोपियन साम्राज्य बाजार में शामिल करना चाहता है।

मजदूर दल में अधिकांशतः वे व्यक्ति हैं जो मजदूर हैं। इसमें से भी अधिकांशतः मजदूर नगर के हैं। इसमें ट्रेड यूनियन सरकारी समितियाँ तथा विभिन्न समाजवादी संगठनों के सदस्य होते हैं। स्त्रियों की सदस्यता इसमें काफी है। जनसाधारण के मध्य यह दल काफी लोकप्रिय है। मध्यमवर्ग के ऐसे लोग जो पूँजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, इसके सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति भी इसके सदस्य हैं जिन्होंने जीवन में समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने का निश्चय कर लिया है।

संगठन (Organization)—मजदूर दल का संगठन संघीय स्वरूप का है। इसमें चार प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं

(1) ट्रेड यूनियन।

(2) समाजवादी सोसाइटियाँ—फरियन, श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा, समाजवादी वकीला एवं अध्यापकों की सभाएँ आदि।

(3) सहकारी संगठन।

(4) जनता के आम सदस्य।

श्रमिक दल सम्मेलन (Labour Party Conference)—यह श्रमिक दल का सर्वोच्च उपकरण है। समस्त इकाइयों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। 1000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि होता है। जहाँ 500 से अधिक महिला सदस्य होती हैं वहाँ एक महिला को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मजदूर दल के टिक्ट पर निर्वाचित संसद सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। अब इसमें 1000 से लेकर 1200 तक सदस्य होते हैं। इसका सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है। यह मजदूर दल की नीतियों का निर्माण करता है तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करता है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee)—इसमें 27 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य ट्रेड यूनियनों द्वारा मनानीय किये जाते हैं। समाजवादी सहकारी तथा अन्य व्यावसायिक संगठन एक एक सदस्य भेजते हैं।

का यह विश्वास था कि उदारवादी तथा अनुदारवादी दल दोनों ही पुराने पड़ गये हैं और बेकार हो चुके हैं। इसकी स्थापना निम्नवर्ग की दशा सुधारन की दृष्टि से की गई थी। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी यह उग्र माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं रहा। श्रमिक दल उग्र क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक नहीं है। उसके आदर्श विश्व के अग्र राजनीतिक दलों से काफी पृथक् रहे। इमने ब्रिटिश परम्पराओं को बनाये रखा। वर्ग संघर्ष में कभी भी अपनी आस्था प्रकट नहीं की। 1920 में इसने जो सदस्य माक्सवादी विचारधारा के समर्थक थे वे हताश होकर पृथक् हो गये तथा साम्यवादी दल में सम्मिलित हो गये। साम्यवादी दल के इस सुझाव को इसने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह इसके साथ मिल जाय। यह दल 1922 के पश्चात् अधिक लोकप्रिय होने के कारण उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा है। 19 जून 1970 से पूर्व इस दल का शासन था। यह रूसी तथा चीनी प्रकार की रक्तप्लुत क्रांतियों का खण्डन करता रहा है। इस दल की नीतियाँ इस प्रकार हैं —

(1) एक नवीन सामाजिक ढाँचे की रचना करना चाहता है। आग तथा जिंक (Ogg & Zink) के अनुसार श्रमिक दल ने “एक नई, विस्तृत, प्रत्यक्ष रूप में भ्रष्ट तथा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति को अपनाया है जो एक नवीन सामाजिक ढाँचा बनाने में विश्वास करती है।” श्रमिक दल प्रकृति से क्रांतिकारी न होकर सुधारवादी है।

(2) निजी सम्पत्ति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व का समर्थन।

(3) आर्थिक क्षेत्र में खुले बाजार का विरोध।

(4) प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। 1945 में श्रमिक दल की सरकार ने लोहा, कोयले की खानें, इस्पात यातायात ईंधन व शक्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि कई समाजवादी सांख्यिक नियंत्रण की योजनाओं का समर्थन किया।

(5) श्रमिक दल राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का 20% राष्ट्रीयकरण करना चाहता है तथा 80% व्यक्तिगत स्वामित्व के रखने के पक्ष में है, किंतु उस भाग का नियमन राजकीय नियोजन के अनुसार होना चाहिए।

(6) पूँजीवाद का विरोध, धन का वितरण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, धन का एकीकरण थोड़े ही व्यक्तियों के हाथों में नहीं होना चाहिए। यह पूँजीवादी ढाँचे को जनतन्त्र तंत्र से परिवर्तित करने के पक्ष में है। बार्कर (Barker) के शब्दों में, श्रमिक दल यह चाहता है कि ‘ब्रिटेन समानता के नये युग में प्रवेश करे और इस प्रकार प्रवेश करे कि शोरगुल न हो। इस बात का भी प्रदर्शन न करे कि समानता का नये युग में पदापण समाजवादी तथा अग्र किसी व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है अपितु स्वेच्छा से कार्य हो। जिससे वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो जाये और वास्तव में समानता आ जाये।’

(7) श्रमिक दल यह चाहता है कि कृषि के क्षेत्र में आयात तथा वितरण के क्षेत्र में इस प्रकार अकुश रहे कि कृषकों के मस्तिस्र में यह बठ जाय कि उन्हें उनकी पदावार का निश्चित मूल्य मिलेगा।

(8) श्रमिक दल समाज के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर दल देता है।

किंतु उपाजन की यह पद्धति वह लोकतंत्रीय व्यवस्था में चाहता है। फाइनर (H Finer) के शब्दों में, "श्रमिक दल 'दास कपोटल' की अपेक्षा बाइबिल में अधिक विश्वास करता है।"

(9) साम्राज्यवाद का कटु विरोध, साम्राज्यवादी उपनिवेशों के सम्बंध में उसकी धारणा है कि उन्हें शीघ्रता से स्वशासी बना दिया जाय।

(10) श्रमिक दल विश्व समाजवादी सरकार में विश्वास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्वास करता है।

(11) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

(12) सम्राट के सीमित अधिकारों का समर्थन करता है।

(13) साह सभा को अनुपयोगी समझता है और उसके उभूलन की बात कहता है।

(14) साम्राज्यवाद का विरोध तथा समाजवादी कॉमनवैलथ का समर्थन करता है।

(15) अनुपाजित आम पर अधिक कर का समर्थन करता है।

(16) इंग्लैण्ड को यूरोपियन साम्राज्य बाजार में शामिल करना चाहता है।

मजदूर दल में अधिकांशतः वे व्यक्ति हैं जो मजदूर हैं। इसमें से भी अधिकांशतः मजदूर नगर के हैं। इसमें ट्रेड यूनियन सरकारी समितियाँ तथा विभिन्न समाजवादी संगठनों के सदस्य होते हैं। स्त्रियों की सदस्यता इसमें काफी है। जनसाधारण के मध्य यह दल काफी लोकप्रिय है। मध्यमवर्ग के ऐसे लोग जो पूँजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, इसके सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति भी इसके सदस्य हैं जिन्होंने जीवन में समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने का निश्चय कर लिया है।

संगठन (Organization)—मजदूर दल का संगठन संघीय स्वरूप का है। इसमें चार प्रकार के तत्त्व सम्मिलित हैं

(1) ट्रेड यूनियन।

(2) समाजवादी सोसाइटियाँ—फवियन, श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा, समाजवादी वकीलों एवं अध्यापकों की सभाएँ आदि।

(3) सहकारी संगठन।

(4) जनता के आम सदस्य।

श्रमिक दल सम्मेलन (Labour Party Conference)—यह श्रमिक दल का सर्वोच्च उपकरण है। समस्त इकाइयों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। 1000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि होता है। जहाँ 500 से अधिक महिला सदस्य होती हैं वहाँ एक महिला को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मजदूर दल के टिकट पर निर्वाचन संसद सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। अब इसमें 1000 में लेकर 1200 तक सदस्य होते हैं। इसका सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है। यह मजदूर दल की नीतियों का निर्माण करता है तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करता है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee)—इसमें 27 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य ट्रेड यूनियनों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। समाजवादी सहकारी तथा अन्य ध्यावसायिक संगठन एक-एक सदस्य भेजते हैं।

5 महिलाएँ भी विभिन्न संगठनों द्वारा इसकी सदस्य बनायी जाती हैं। हरबट मोरीसन (Morison) के अनुसार, 'यह समिति सम्मेलन को सेविका है, पर तु सम्मेलन का नेतृत्व के लिए उसे किसी दिशा में चलना चाहिए, इसके लिए उसे परामर्श देना समिति का कर्तव्य है।' किसी भी सदस्य अथवा संगठन को निष्कासित करने का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को अधिकार है। इस समिति द्वारा जो नियम लिये जाते हैं उनका अनुमोदन सम्मेलन द्वारा किया जाता है। समिति अपनी उपसमितियाँ भी स्थापित करती है। ससदीय दल का नेता इसका नेता भी होता है। सम्मेलन द्वारा एक सचिव का भी निर्वाचन किया जाता है जो दल के विविध कार्यों का प्रभारी होता है।

ससदीय संगठन (Parliamentary Organization)—श्रमिक दल का भी अपना एक ससदीय संगठन होता है। यही संगठन हर वर्ष दल के नेता का भी चयन करता है। नेता को दलीय सम्मेलन तथा कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। नीति निर्धारण का कार्य अतः उसी का है। श्रमिक दल की एक विचित्र बात देखने में यह आती है कि जब वह सत्ताधारी होता है तो नेता का महत्व विरोध की अपेक्षा अधिक होता है। दल के कोषाध्यक्ष का दलीय सम्मेलन द्वारा निर्वाचन होता है। कार्यकारिणी समिति ही दलीय विवादों को तय करती है, सविधान की व्याख्या करती है, उम्मीदवारों का चयन करती है तथा दल की नयी शाखाएँ खोलती है।

उदार दल (Liberal Party)

इंग्लैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था में इस दल का महत्व अब उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। श्रमिक दल से पूर्व इसे प्रगतिशील दल माना जाता था। इस दल के पूर्वज ब्लिग कहलाते थे। 19वीं शताब्दी में इसके कई मन्त्रिमण्डल बने। सबसे पहला प्रधानमंत्री कहलाने जाता व्यक्ति बाल्फोर इसी दल से सम्बन्धित था। इसका नेता बहुत समय तक ग्लडस्टोन बना रहा। 1966 में इस दल को कॉमन्स सभा में केवल 12 स्थान प्राप्त हुए। 1970 के निर्वाचनों में इसकी सहाय नहीं के बराबर रह गयी। बैली (Baile) के अनुसार, "विगत तीन शताब्दियों में उदारवादी दल कई पहलुओं से गुजर चुका है। कभी यह घनिकों का दल रहा है तो कभी यह पददलितों का संरक्षक रहा है। कभी इसने शांति दल का और कभी कठोर प्रतिस्पर्धी प्रदर्शित करने वाले दल का रूप धारण किया है। कभी यह यदभाष्यमय नीति का समर्थक रहा है तो कभी आर्थिक नियोजन का पक्षपोषक। कभी यह साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है तो कभी इसने इंग्लैण्ड के छोटे देश का समर्थन किया है। साधारणतः यह सहिष्णुता का समर्थक रहा है किन्तु कुछ अवसरों में यह विवट असाहिष्णुता की ओर भी रहा है।'

नीति एवं कार्यक्रम (Policy & Programme)—यह दल मंदेव से मध्य मार्गों पर है। इसके निम्नलिखित मुख्य एवं नीतियाँ रही हैं

- (1) पंच तथा मजदूरों के विशेषाधिकारों का विरोध करना।
- (2) राजस्व तथा सौदे गमा के मरूपन नष्ट करना नहीं चाहता बल्कि उम्मीदवारों से जारी कर्मों करना चाहता है।

(3) बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ आर्थिक परिवर्तनों का समयन करता है।

(4) समाजवाद तथा राष्ट्रीयकृत औद्योगिक अथ व्यवस्था का यह दल समयन नहीं करता किंतु इसके साथ ही पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण का भी समयन नहीं करता।

(5) व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है तथा राज्य के अधिकार क्षेत्र को कम करने के पक्ष में है।

(6) मुक्त व्यापार का समयन करता है।

(7) राज्य द्वारा उद्योगों का नियमन चाहता है तथा मजदूरों को उद्योगों में सांभोवार बनाने के पक्ष में है।

(8) निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समयन करता है।

(9) यह दल इस सिद्धांत का समयन करता है कि भूमि पर उस व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार किया जाना चाहिए जो उसे जोनता है।

(10) कभी कभी इस दल ने यदभाष्य नीति का भी समयन किया है।

(11) विदेश नीति के सन्दर्भ में ब्रिटेन के अधीन देशों को अधिक से अधिक स्वशासन देने का इस दल ने समयन किया है।

उदारवादी दल में छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के मजदूर तथा धनिक कुपक आदि सम्मिलित हैं। सख्या तथा लोकप्रियता की दृष्टि से चाहे इस दल का महत्व कम हो गया हो किंतु बौद्धिक अनुदाय की कसौटी पर आज भी इसका महत्व कम नहीं है। इस समय इसे कुलीन वर्ग का ही समयन प्राप्त है। रॉस (Ross) के शब्दों में, "अत्यंत माध्यमिक स्थिति के कारण उदारवादी दल में ऐसी किसी स्थिति का अभाव है जो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके जो अत्यंत उग्ररूप से किसी एक पक्ष के समयन में या वर्गभावना के पक्ष में अधिक सचेत हैं।"

संगठन (Organization)—इसके राष्ट्रीय संगठन को राष्ट्रीय उदारवादी संघ (National Liberal Federation) कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है जिसे वार्षिक सम्मेलन भी कहा जाता है। यह दल के अधिकारियों को चुनता है तथा दलीय नीतियों का निर्धारण करता है। दल की निम्नतम स्तर की शाखा को निर्वाचन क्षेत्रीय संघ कहा जाता है। इन इकाइयों का कार्य अपना क्षेत्रों में दलीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रसार करना है। उदारवादी दल का भी अपना एक केन्द्रीय कार्यालय (Liberal Central Association) है। दलीय बोप पर केन्द्रीय कार्यालय का नियंत्रण नहीं है बल्कि क्षेत्रीय संगठनों का है।

अन्य दल (Other Parties)—इंग्लैंड में इन तीनों दलों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे दल भी हैं। इनमें विशेषकर साम्यवादी दल, फासिस्ट दल तथा स्वतंत्र धर्मिक दल की चर्चा की जा सकती है। साम्यवादी दल का महत्व लगभग नहीं के बराबर है। यह दल मार्क्स तथा लेनिन के सिद्धांतों में विश्वास करता है। यह दल राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का खण्डन करता है। चर्च के विशेषाधिकार का उन्मूलन करना चाहता है। इस दल की नीतियों पर रूसी साम्यवाद का विशेष प्रभाव है।

विश्व की अन्य समन्वय गणालियों की भांति ब्रिटेन में भी दल के दाय

हैं —संसद के अंदर तथा संसद के बाहर। संसदीय दल के तीन भाग होते हैं —दल के सदस्यों का पूरा समूह, समूह का नेता तथा दल का सचेतक (Whip)। दल यदि सत्ता में है तो नेता प्रधानमंत्री बनता है और विरोध में होने की स्थिति में विरोधी दल का नेता बनता है। निर्वाचन से पूर्व प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करता है। दलीय प्रचार केवल चुनाव के समय ही नहीं होता बल्कि सारे वर्ष चलता रहता है। दल अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए दलीय साहित्य का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक दल प्रचार के लिए अपना नवयुवक संगठन (Youth Organization) रखता है। अनुदार दल के पास Young Conservative Organization, उदार दल के पास The National League of Youth Liberals तथा श्रमिक दल के पास Labour League of Youth हैं। राजनीतिक दल विद्यालयों आदि में भी क्लबों तथा सघों का निर्माण करते हैं। प्रमुख नगरों में दल अपने राजनीतिक क्लब स्थापित करते हैं। अनुदार दल का The Prime Cross League श्रमिक दल का 'Fabian Society' तथा उदार दल का The National Reform Union आदि सहायक संगठनों के कुछ उदाहरण हैं। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली होने के कारण राजनीतिक दलों का महत्व अमेरिका की अपेक्षा कहीं अधिक है।

Select References

- Baile : *Political Parties & Party system of Britain*
 Laski : *Parliamentary Govt in England*
 McKenzie H. K. : *British Political Parties*
 Munro : *Govts of Europe*
 Neumann : *European and Comparative Govts*
 Bulmer : *The Party System in Great Britain*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 इंग्लैंड के प्रसंग में प्रजातान्त्रिक राज्य में राजनीतिक दलों के महत्व का वर्णन कीजिए।
 (Discuss the importance of political parties in a democratic state with special reference to England)
- 2 ब्रिटिश दल प्रथा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और अमेरिका तथा फ्रांस से उनकी तुलना करें।
 (Mention the main features of the British party system and compare them with those of America and France)
- 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के संगठन उद्देश्य तथा कार्यकरण की विधि का वर्णन कीजिए।
 (Describe the organisation, aims and methods of parties in England)
- 4 इंग्लैंड और फ्रांस की दल-पद्धतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करें।
 (Compare and contrast the working of the party system in England and France)

ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें

[Local Governments in Britain]

"We miss the essence of democracy if we think of it mainly as something practised by statesman in a distant capital"
—J A Corry

स्थानीय सरकारों के बिना लोकतंत्र अपूर्ण है। सभ्यता के विकास के साथ स्थानीय शासन की आवश्यकता और अधिक अनुभव होने लगी है। केन्द्र को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके बहुत सी शक्तियों को स्थानीय हित में हस्तांतरित करना पड़ा है। स्थानीय सरकारों को आज हम मानव व्यक्तित्व के अभिन्न रूप में देखते हैं। स्थानीय सरकारों की उत्पत्ति सरकार के किसी अधिनियम के द्वारा होती है। ये अद्वितीय सत्ताएँ राज्य के संरक्षण, निर्देशन एवं निरीक्षण में स्थानीय समस्याओं का समाधान करती हैं। कॉल जे० फ्रेड्रिक के अनुसार, स्वराज्य सरकार समाज की वह प्रशासकीय व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय हो।"

स्थानीय स्वशासन स्थानीय समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान है। शासकीय अधिकारों की विकेंद्रित व्यवस्था ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय सत्ताओं का निर्माण स्थानीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। वास्तविक लोकतंत्र की उपलब्धि स्थानीय स्वशासन है। मिल (J S Mill) का यह कहना सही है कि केन्द्रीय सरकार कुशलता, ईमानदारी एवं शीघ्रता के साथ बिना स्थानीय स्वशासन के जन हित का सम्पादन नहीं कर सकती। मोण्टेग्यू हैरिस के अनुसार स्थानीय स्वशासन की सत्ताएँ वृक्ष की शाखाओं की भाँति हैं जिनके बिना वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। फाइनेर (H Finer) के अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय स्वशासन सबसे अधिक उत्तम साधन है। यह विकेंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विरुद्ध सुरक्षा तथा चेनावनी है। लॉस्की (Lasky) के अनुसार 'कोई भी लोकतंत्र स्थानीय हित की उपेक्षा करके अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता।' हिक्स (Hicks) के अनुसार, 'आर्थिक विकास की अभिवृद्धि के लिए स्थानीय सरकारों की अधिक आवश्यकता है।' व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णत्व स्थानीय स्वशासन द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। नागरिकों में सामाजिक जागरूकता, बोद्धि-वता, निष्ठात्मकता एवं सामाजिकता का विकास स्थानीय सरकारों के द्वारा ही

अर्जित किया जा सकता है। ब्राइस (Bryce) ने इन्हें प्रजातन्त्र की पाठशाला कहा है। डी० टैक्यूवेल के अनुसार, “नागरिका की स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय की वास्तविक शक्ति है।”

स्थानीय स्वशासन का बड़ा महत्व स्वशासन में प्रशिक्षण है। यह भावी नेताओं की तैयारी है। यह प्राथमिक प्रशिक्षण है। कायकुशलता के दो महत्वपूर्ण उपकरणों—कृत-व्यपरायणता तथा कायकुशलता—की उत्पत्ति स्थानीय स्वशासन से होती है। लॉस्की (Lasky) तो जिले का प्रशासन स्थानीय सरकारों को समर्पित करने के पक्ष में है। स्थानीय सरकारों के कारण केन्द्र सरकार एक बड़े बोझ से बच जाती है। स्थानीय स्वशासन सामाजिक उन्नति का प्रभावपूर्ण साधन है। इसी के माध्यम से स्थानीय समस्याओं में सामाज्य चेतना का विकास होता है। ब्राइस (Bryce) के अनुसार, “स्थानीय समस्याएँ लोगों को न केवल दूसरों के लिए कार्य करना सिखाती हैं वरन् उनके लिए मिलकर कृत्य करना भी सिखाती हैं।” स्थानीय समस्याओं की एक महत्वपूर्ण देन जन सहयोग एवं नागरिक गुणों का निर्माण होता है। जितना अधिक जनसम्पर्क स्थानीय समस्याओं के माध्यम से उत्पन्न होता है उतना अर्थ किसी माध्यम से नहीं। सवेदना, मिश्रता, मद्भावना, विनम्रता, अध्यवसाय आदि नागरिक गुणों का विकास स्थानीय सरकारों के द्वारा बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न होता है। घण्टाचार की सम्भावनाएँ कुछ कम हो जाती हैं और नौकरशाही का दौर दौरा भी कम हो जाता है। अतः स्थानीय सरकारें शरीर की रक्तवाहक धमनियों के सदृश हैं।

इंग्लैण्ड में स्थानीय समस्याओं का इतिहास बहुत पुराना है। अर्थ समस्याओं के सदृश इनका भी विकास अनायास रूप में हुआ है। एंग्लो सैक्सन काल में शायर, हण्ड्रेड, उपनगर तथा बरो नामक स्थानीय समस्याएँ काफी स्वतन्त्र थीं और उनके ऊपर के द्रीय नियन्त्रण कम था। नामन युग में केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा बढ़ गयी थी। नामन काल में शायर काउण्टी उपनगर सामन्ती मेनर, बरो नगरपालिकाओं में परिवर्तित हो गयी थी तथा हण्ड्रेड समाप्त हो गये थे। उपनगर के स्थानों पर परिशों का विकास हुआ। नामन काल की तीन समस्याएँ—काउण्टी बरो तथा परिश उन्नीसवीं शताब्दी तक भी चलती रही। औद्योगिक क्रांति ने स्थानीय समस्याओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। 1835 के म्युनिमिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1888 के स्थानीय स्वशासन अधिनियम तथा 1894 के जिला परिश कॉंसिल एक्ट के द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था को पुनः संगठित किया गया, 1929 तथा 1933 में सप्तदीय अधिनियमों के द्वारा पुनः स्थानीय सरकारों को स्वस्थ रूप में संगठित किया गया।

1966 में था रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक राज्य आयोग की स्थापना की गयी थी जिसने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें इस बात की सिफारिश की गयी थी कि वर्तमान 1200 निर्वाचित परिषदों के स्थान पर 61 प्राधिकार (Authorities) उत्पन्न किये जायें जिन्हें 8 प्रांतों में संगठित किया जाय। इन 61 प्राधिकारों में अधीन अनेक स्थानीय सरकारें होंगी। आयोग के 11 सदस्यों में से 10 नई रिपोर्ट का समर्थन किया। ग्यारहवें ने अपनी पथक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस रिपोर्ट के

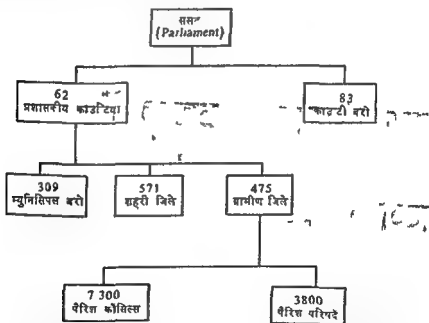
अनुसार स्थानीय शक्तियों में काफी विकास हुआ। पेट्रोल पर उत्पादन कर से होने वाली आमदनी स्थानीय सरकारों को समर्पित कर दी गयी। इसका लक्ष्य वित्तीय दृष्टि से स्थानीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना था।

इंग्लैण्ड में वर्तमान स्थानीय व्यवस्था (Present Set up of Local Bodies in England)

(1) काउन्टी परिषद (County Council)

सम्पूर्ण देश को काउन्टी बरों में विभाजित किया गया है। काउन्टी बरों का निर्माण 75,000 की जनसंख्या पर किया गया है। ये काउन्टियों से भिन्न हैं। काउन्टी बरों के बाढ़ शहरी जिले तथा ग्रामीण जिले होते हैं। ग्रामीण जिलों को पैरिशों में बाढ़ा गया है। एक ग्राम जिले (Rural District) के आधीन 20 से लेकर 30 पैरिश आते हैं। प्रत्येक इकाई का स्वशासन एवं निर्वाचित परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। इसको सविस्तार समझने से पूर्व उसे एक घाट के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है।

स्थानीय स्वशासन का स्वरूप



(1) काउन्टी (County)—यह स्थानीय प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके दो प्रकार हैं—(क) ऐतिहासिक काउन्टी, (ख) प्रशासकीय काउन्टी।

(क) ऐतिहासिक काउन्टी (Historic County)—कुल मिलाकर इनकी संख्या 52 है। ये प्राचीन शायस की प्रतिरूप हैं। इनके द्वारा प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन नहीं किया जाता। यायिक कार्यों के अतिरिक्त इनका महत्व कामन सभा के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में है। इनकी कोई परिषद नहीं होती। स्थानीय स्वशासन की

दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके तीन मुख्य अधिकारी होते हैं—लाइ जेफ्टनेण्ट, शेरिफ तथा शांति-यायाधीश (Justice of Peace)।

(ख) प्रशासकीय काउण्टी (Administrative County)—स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इनका महत्व है। इनकी स्थापना 1888 के सरकारी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी। इनकी संख्या लगभग 62 है। वृहत्तर लन्दन क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रशासकीय काउण्टी के प्रबन्ध के लिए काउण्टी कौंसिल की व्यवस्था की जाती है। परिषद का स्वरूप जनसंख्या के अनुरूप निश्चित किया जाता है। प्रत्येक परिषद में एक अध्यक्ष कुछ पापद तथा उपनगरपाल (Alderman) होते हैं। पापदों का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है जिसकी अवस्था 18 वर्ष है। उपनगरपाला (Aldermen) का निर्वाचन पापदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि कोई पापद इस पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है जिसके लिए पुनः निर्वाचन होता है। उपनगरपालों में से $\frac{1}{2}$ प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपनगरपालों की संस्था स्थायी सदन के प्रकार की है। काउण्टी कौंसिल की वर्ष में चार बैठक होती हैं किन्तु आवश्यकता पड़ने पर और अधिक बैठकें भी आमंत्रित की जा सकती हैं।

कार्य—काउण्टी परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- (1) जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध।
- (2) यातायात के स्थानीय साधनों का निर्माण।
- (3) प्रारम्भिक शिक्षा का विकास।
- (4) माप एवं तौल की व्यवस्था।
- (5) पुलिस का शांति एवं व्यवस्था के लिए प्रबन्ध।
- (6) चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था।
- (7) पशुओं की नस्ल तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- (8) अनायालय, पागलखाने तथा औद्योगिक शिक्षणालयों का प्रबन्ध।
- (9) शराब सम्बन्धी अनुज्ञप्तियों की व्यवस्था।
- (10) काउण्टी की इमारतों की देखभाल।
- (11) काउण्टी बजट की तयारी तथा उपनियमों का निर्माण।
- (12) नीचे स्तर की स्थानीय इकाइयों पर नियन्त्रण।
- (13) करारोपण।
- (14) महामारियों की रोकथाम आदि।

काउण्टी कौंसिल की अपनी कुछ समितियाँ भी होती हैं। इनमें से प्रमुख हैं—वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति, गृह निर्माण समिति, कृषि समिति, स्थानीय पेशन समिति, तथा शिक्षा समिति। प्रत्येक काउण्टी में 9-9 समितियाँ होती हैं।

2 काउण्टी बरो तथा नान काउण्टी बरो (County and Non County Borough)

सम्राट द्वारा प्रसारित सपरिषद आदेशों द्वारा एक अधिकार-पत्र के माध्यम से काउण्टी बरो की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या 75000

से अधिक् होती है। काउण्टी बरो के लिए प्राथना पत्र सम्राट को देना पड़ता है जिसका परीक्षण प्रीवी कौंसिल की एक समिति के द्वारा सम्पन्न होता है तथा उसका प्रवाशन लन्दन गजट में होता है। गजट में प्रकाशन होने के पश्चात् यदि उसका विरोध 1/20 करदाताओं के द्वारा किया जाता है तो उसे ससद के पास भेज दिया जाता है। ससदीय बहुमत के उपरांत उसे काउण्टी बरो में परिणत कर दिया जाता है। काउण्टी बरो के पास किसी भी प्रकार के प्रशासकीय अधिकार नहीं होते। काउण्टी बरो की संख्या इस समय 83 है। नॉन काउण्टी बरो (Non County Borough) काउण्टी के ही भाग होते हैं। उसी के आधीन रहकर कार्य करते हैं। इस समय इनकी संख्या लगभग 264 है। इस बरो की शक्तियाँ काउण्टी बरो से कम होती हैं। ठीक तो यह है कि जब किसी नॉन काउण्टी बरो की संख्या 75000 से अधिक हो जाती है तो उसे काउण्टी बरो का स्तर प्रदान कर दिया जाता है।

बरो का शासन प्रबंध एक परिपद के द्वारा सम्पन्न होता है। परिपद का आकार बरो की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किया जाता है। एक बरो की परिपद दूसरे से भिन्न होती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त बरो कौंसिल में परिपद तथा उपनगरपाल (Alderman) भी होते हैं। उपनगरपाल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। पापद मतदाताओं द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उपनगरपालों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन परिपद तथा उपनगरपाल मिलकर करते हैं। अध्यक्ष को महापौर (Mayor) कहा जाता है। उसका पद अवैतनिक होता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों को ही महापौर चुना जाता है। वह नगर के समारोहों के समय जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

काउण्टी बरो अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य, यातायात, निमाण, जल प्रदाय, विद्युत आवास आदि की व्यवस्था का प्रबंध करती है। लोक कल्याणकारी कार्यों में रत रहती है। अपनी साख (Credit) पर क्रेडिट से ऋण की व्यवस्था करती है। इसके अधिवेशन वर्ष में चार बार होते हैं। मेयर को किसी भी प्रकार का निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। साप्ताहिक तथा मासिक अधिवेशनों की भी व्यवस्था की गयी है। काउण्टी बरो की भी अपनी समितियाँ होती हैं जिन्हें अंतिम निणय के स्थान पर केवल सिफारिशें भेजने का ही अधिकार प्राप्त है। परिपद को उप नियम (Bye laws) बनाने का भी अधिकार है। इसके पास भी कई वैतनिक अधिकारी होते हैं।

3 नगर जिला परिषद (Urban District Council)

जब किसी काउण्टी की जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है और उसे व्यापक साधनों की आवश्यकता अनुभव होने लगती है तो उसे नगर जिले में परिवर्तित करके उसकी स्तरोन्नति कर दी जाती है। शहरी जिले की एक परिषद होती है। उस जिले के आधीन जितने पैरिश होते हैं वे इसमें एक-एक सदस्य भेजते हैं जो शहरी जिला परिषद का गठन करते हैं। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है किन्तु उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें उपनगरपाल (Alderman) नहीं होते। कौंसिल का अध्यक्ष सदस्यों में से अथवा सदस्यों से बाहर का भी हो सकता है। अध्यक्ष को शांति-यायाधीश के अधिकार भी प्राप्त होते हैं।

जिला परिषद के कार्य—(1) सड़क तथा भवन निर्माण।

(2) सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था ।

(3) गंदी बस्तियाँ को ठीक करना ।

(4) जल-प्रदाय की व्यवस्था ।

(5) वाचनालय, पुस्तकालय, पार्क, खेल तथा सावजनिक स्नानगृहों की व्यवस्था ।

जिन जिलों की संख्या 20,000 से अधिक है वहाँ परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों पर कुछ नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गयी है । कोषाध्यक्ष स्वास्थ्य निरीक्षक तथा स्वास्थ्य अधिकारी आदि का सहयोग लेता है ।

4 ग्रामीण जिले (Rural Districts)

इस समय इंग्लैंड में 470 ग्रामीण जिले हैं । इसके प्रबंध के लिए भी एक परिषद का गठन किया जाता है । इन समस्त सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए मतदाताओं द्वारा किया जाता है । $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रतिवर्ष पदों को रिक्त कर देते हैं । परिषद का एक अध्यक्ष होता है जिस शान्ति यायावरी के अधिकार भी प्रदान कर दिये जाते हैं । ये परिषद भी सफाई, रोडनी, जल, यातायात आदि का प्रबंध करती हैं । इन्हें भी कुछ वैतनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करनी होती है ।

5 पेरिश (Parishes)

इनकी संख्या लगभग 3,800 के है (पेरिश सभाएँ) । इसके विपरीत पेरिश परिषदों की संख्या 7,500 है पेरिश सभाएँ उन ग्रामों में पायी जाती हैं जहाँ पेरिश परिषदों का निर्माण नहीं हो सकता और जो बहुत छोटे हैं । पेरिश सभाओं की स्थापना केवल उन ग्रामों में की जाती है जिनकी जनसंख्या 300 से कम है । जहाँ जनसंख्या इससे अधिक है वहाँ पेरिश परिषदों की स्थापना की जाती है । यद्यपि पेरिश परिषदों के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में होती है किंतु फिर भी इनकी संख्या 5 से लेकर 15 सदस्यों तक रहती है । परिषदों का गठन तीन वर्ष के लिए होता है । इनकी शक्तियाँ साधारण होती हैं । पेरिश को कर लगाने का अधिकार है जो 1 पौंड पर 3 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके लेखाकनों का परीक्षण जिला लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है । कुछ पेरिश धार्मिक, कुछ भूमि कर तथा कुछ दावानी प्रकार के होते हैं । नगरीय पेरिशों को अब नगर जिला समितियों में मिला दिया गया है किंतु ग्रामीण पेरिश अब भी स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं ।

लन्दन का स्थानीय स्वशासन (Local Government of London)

ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानीय स्वशासन में लन्दन का महत्व सदैव से एक पृथक् इकाई के रूप में रहा है । इंग्लैंड की राजधानी होने के अतिरिक्त जनसंख्या तथा अब कई समस्याओं एवं गुणों के कारण लन्दन का नगर अपना पृथक् महत्व रखता है । यह शेष भाग से पृथक् समझा जाता रहा है । स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से लन्दन को तीन भागों में विभाजित किया गया है — (1) लन्दन नगर (City of London) (2) लन्दन काउण्टी (County of London), तथा (3) लन्दन मेट्रोपॉलिटन पुलिस (London Metropolitan Police) ।

1 लंदन नगर (City of London)

लंदन व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसका विकास सेल्टिक काल में हुआ था। यह व्यापारिक केंद्रों, प्रमण्डलों एवं बैंकों से भरा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि रात्रि को लंदन की आबादी काफी कम हो जाती है। लोग दिन में काम करने के बाद लौट जाते हैं। लंदन नगर के निवासी तथा कर-दाताओं को फ्रीमैन कहा जाता है। इसके स्थानीय प्रशासन में एक महापौर (Mayor) तथा अथ परिषदों का सहयोग मिलता है। ये परिषदें इस प्रकार हैं —

(1) कोर्ट ऑफ एल्डरमैन (Court of Aldermen)—इसमें एक मेयर तथा 26 उपनगरपालक होते हैं। इनका निर्वाचन लंदन के नागरिकों द्वारा होता है। इसकी बैठक वष में एक बार होती है। कोर्ट ऑफ एल्डरमैन द्वारा ही लॉर्ड मेयर का निर्वाचन होता है। लंदन का वास्तविक शासन 26 नगरपालक तथा 200 पापदों द्वारा सम्पन्न होता है। महापौर का पद बड़े महत्व का है। उस वास्तव में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। नगर की ओर से वह महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सम्मान देता है। कोर्ट ऑफ एल्डरमैन कॉमन कौंसिल की सहायता से जन स्वास्थ्य, जलपूर्ति, रोगनी, स्थानीय यातायात, भवन निर्माण आदि की व्यवस्था करता है, दलालों को लाइसेंस देना तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है।

(2) कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल (Court of Common Council)—यह वास्तविक कार्यपालिका है। इसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमैन के 26 सदस्य तथा 206 पापद होते हैं जिनका प्रति वष निर्वाचन होता है। इसे उपनियम बनाने का अधिकार होता है। अग्निरक्षा, नालियाँ, पानी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य सारे कार्यों का सम्पादन इस परिषद को करना पड़ता है। न्यायालय, पुलिस तथा पुलों का संरक्षण इसके अधिकार में रहते हैं।

(3) कोर्ट ऑफ कॉमन हाल (Court of Common Hall)—इसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमैन तथा नगर की प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं। कम्पनियों के प्रतिनिधि लिबररीमन कहलाते हैं। यह प्रत्येक वष एक शेरिफ (Sheriff) का निर्वाचन करता है।

इन तीनों परिषदों का अध्यक्ष साइ मेयर ही होता है। लॉर्ड मेयर को 10,000 पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है। नियुक्तियाँ तथा अन्य कार्य करना उसके अधिकारों की परिधि से बाहर है। वह तो केवल नगर का प्रतिनिधित्व करता है।

2 लंदन काउंटी (County of London)

लंदन काउंटी का क्षेत्रफल 117 वर्गमील है। इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है, यह भी एक प्रशासकीय काउंटी है। इसकी प्रबंध व्यवस्था का संचालन एक परिषद के द्वारा सम्पन्न होता है जिसमें 192 पापद तथा 20 उपनगरपाल होते हैं। उपनगरपाल पापदों द्वारा छ वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इनमें से प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं। उपनगरपाल तथा पापद समुक्त रूप से अपना एक मजिस्ट्रेट निर्वाचित करते हैं। पापद तथा एल्डरमैनों में केवल शिष्टाचार का ही अंतर है, वैसे अन्य किसी बात में कोई अंतर नहीं है। प्रशासन की स्वस्थता

- (2) सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था ।
- (3) गंदी वस्तियों को ठीक करना ।
- (4) जल प्रदाय की व्यवस्था ।
- (5) वाचनालय, पुस्तकालय, पार्क, खेल तथा सावजनिक स्नानगृहों की व्यवस्था ।

जिन जिलों की संख्या 20,000 से अधिक है वहाँ परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों पर कुछ नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गयी है । कोषाध्यक्ष स्वास्थ्य निरीक्षक तथा स्वास्थ्य अधिकारी आदि का सहयोग लेता है ।

4 ग्रामीण जिले (Rural Districts)

इस समय इंग्लैंड में 470 ग्रामीण जिले हैं । इसके प्रबंध के लिए भी एक परिषद का गठन किया जाता है । इन समस्त सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए मतदाताओं द्वारा किया जाता है । $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रतिवर्ष पदा को रिक्त कर देते हैं । परिषद का एक अध्यक्ष होता है जिसे शान्ति-न्यायाधीश के अधिकार भी प्रदान कर दिये जाते हैं । ये परिषद भी सफाई, रोशनी, जल, यातायात आदि का प्रबंध करती हैं । इन्हें भी कुछ वैतनिक अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करनी होती हैं ।

5 परिश (Parishes)

इनकी सराया लगभग 3,800 के है (पैरिश सभाएँ) । इसके विपरीत पैरिश परिषदों की संख्या 7,500 है । पैरिश सभाएँ उन ग्रामों में पायी जाती हैं जहाँ पैरिश परिषदों का निर्माण नहीं हो सकता और जो बहुत छोटे हैं । पैरिश सभाओं की स्थापना केवल उन ग्रामों में की जाती है जिनकी जनसंख्या 300 से कम है । जहाँ जनसंख्या इससे अधिक है वहाँ पैरिश परिषदों की स्थापना की जाती है । यद्यपि पैरिश परिषदों के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में होती है किन्तु फिर भी इनकी संख्या 5 से लेकर 15 सदस्यों तक रहती है । परिषदों का गठन तीन वर्ष के लिए होता है । इनकी शक्तियाँ साधारण होती हैं । पैरिश को कर लगाने का अधिकार है जो 1 पेंड पर 3 पेंस से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके लेखाकर्मों का परीक्षण जिला लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है । कुछ पैरिश धार्मिक, कुछ भूमि कर तथा कुछ दीवानी प्रकार के होते हैं । नगरीय पैरिशों को अब नगर जिला समितियों में मिला दिया गया है किन्तु ग्रामीण पैरिश अब भी स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं ।

लन्दन का स्थानीय स्वशासन (Local Government of London)

ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानीय स्वशासन में लन्दन का महत्व सद्वर्ष से एक पक्का इकाई के रूप में रहा है । इंग्लैंड की राजधानी होने के अतिरिक्त जनसंख्या तथा अन्य कई समस्याओं एवं मुद्दों के कारण लन्दन का नगर अपना पक्का महत्व रखता है । यह शेष भाग से पक्का समझा जाता रहा है । स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से लन्दन को तीन भागों में विभाजित किया गया है — (1) लन्दन नगर (City of London) (2) लन्दन काउण्टी (County of London), तथा (3) लन्दन मेट्रोपोलिटन पुलिस (London Metropolitan Police) ।

1 लन्दन नगर (City of London)

लन्दन व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसका विकास सेल्टिक काल में हुआ था। यह व्यापारिक केंद्रों में प्रमण्डलो एंव बैंका से भरा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि रात्रि को लन्दन की आबादी काफी कम हो जाती है। लोग दिन में काम करने के बाद लौट जाते हैं। लन्दन नगर के निवासी तथा कर-दाताओं को फ्रीमैन कहा जाता है। इसके स्थानीय प्रशासन में एक महापौर (Mayor) तथा अय परिषदों का सहयोग मिलता है। ये परिषदें इस प्रकार हैं —

(1) कोर्ट ऑफ एल्डरमैन (Court of Aldermen)—इसमें एक मेयर तथा 26 उपनगरपालक होते हैं। इनका निर्वाचन लन्दन के नागरिकों द्वारा होता है। इसकी बैठक वष में एक बार होती है। कोर्ट ऑफ एल्डरमैन द्वारा ही लॉर्ड मेयर का निर्वाचन होता है। लन्दन का वास्तविक शासन 26 नगरपालक तथा 200 पापदों द्वारा सम्पन्न होता है। महापौर का पद बड़े महत्त्व का है। उसे वास्तव में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। नगर की ओर से वह महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सम्मान देता है। कोर्ट ऑफ एल्डरमैन कामन कौंसिल की सहायता से जन स्वास्थ्य, जलपूर्ति, रोशनी, स्थानीय यातायात, भवन निर्माण आदि की व्यवस्था करता है, दलालों को लाइसेंस देना तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है।

(2) कोर्ट ऑफ कॉमन कौंसिल (Court of Common Council)—यह वास्तविक नगरपालिका है। इसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमैन के 26 सदस्य तथा 206 पापद होते हैं जिनका प्रति वष निर्वाचन होता है। इसे उपनियम बनाने का अधिकार होता है। अग्निरक्षा, नालियों, पानी तथा सावजनिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त अय सारे कार्यों का सम्पादन इस परिषद को करना पड़ता है। दायालय, पुलिस तथा पुला का संरक्षण इसके अधिकार में रहते हैं।

(3) कोर्ट ऑफ कॉमन हाल (Court of Common Hall)—इसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमैन तथा नगर की प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं। कम्पनियों के प्रतिनिधि लिबररीमैन कहलाते हैं। यह प्रत्येक वष एक शरिफ (Sheriff) का निर्वाचन करती है।

इन तीनों परिषदों का अध्यक्ष मॉड मेयर ही होता है। लॉर्ड मेयर को 10 000 पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है। नियुक्तियाँ तथा अय काय करना उसके अधिकारों की परिधि से बाहर है। वह तो केवल नगर का प्रतिनिधित्व करता है।

2 लन्दन काउंटी (County of London)

लन्दन काउंटी का क्षेत्रफल 117 वर्गमील है। इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है यह भी एक प्रशासकीय काउंटी है। इसकी प्रबंध व्यवस्था का संचालन एक परिषद के द्वारा सम्पन्न होता है जिसमें 192 पापद तथा 20 उपनगरपाल होते हैं। उपनगरपाल पापदों द्वारा छ वष के लिए निर्वाचित होते हैं। इनमें से $\frac{1}{3}$ प्रत्येक तीन वष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं। उपनगरपाल तथा पापद संयुक्त रूप से अपना एक संभाषन निर्वाचित करते हैं। पापद तथा एल्डरमनों में केवल शिष्टाचार का ही अंतर है, वैसे अय किसी बात में कोई अंतर नहीं है। प्रशासन की स्वस्थता

की दृष्टि से लंदन काउण्टी को 28 मेट्रोपोलिटन बरो में विभाजित कर दिया गया है। ये सब काउण्टी समिति के निर्देशन में कार्य करती हैं। प्रत्येक मेट्रोपोलिटन बरो की एक परिपद होती है जिसमें सभापति के अतिरिक्त पायपद तथा उपनगरपाल होते हैं। पायपद तीन वष के लिए तथा एल्डरमैन छ वष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक तीन वष के उपरान्त 1/2 एल्डरमैन रिटायर हो जाते हैं। इन बरो के द्वारा भी अन्य बरो की भांति ही कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

लंदन काउण्टी काउंसिल को जन-स्वास्थ्य, सफाई, पुल निर्माण, सड़कों, अग्निसुरक्षा, गृह निर्माण, शिक्षा, मेलो, ड्रामा मागों आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। 18 प्रकार की विविध समितियाँ इसके कार्यों का सम्पादन करती हैं। अधिकांश समितियाँ उपसमितियों की रचना भी करती हैं। परिपद की एक कार्यकारिणी समिति भी होती है जिसमें उपसमितियों के सभापति सम्मिलित किये जाते हैं। लंदन काउण्टी में 28 बरो हैं। लंदन काउण्टी परिपद को उपनियम बनाने के अधिकार भी हैं।

3 लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट (London Metropolitan Police District)

लंदन की पुलिस पृथक है। लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 1829 में रॉबर्ट पील के द्वारा हुई थी। इसका क्षेत्र लगभग 700 वर्ग मील है। यहाँ की योग्य पुलिस एक पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में कार्य करती है। लंदन काउण्टी के साथ कुछ और काउण्टियों को भी सम्मिलित किया गया है। पुलिस कमिश्नर की सहायता के लिए तीन और सहायक कमिश्नर भी होते हैं। पुलिस के जवानों की संख्या लगभग 20,000 है, वैसे प्रत्यक्ष रूप में इसका स्थानीय स्वशासन से बहुत समीप का सम्बन्ध है।

स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियन्त्रण (Central Control over Local Administration)

स्थानीय स्वशासनकीय समस्याएँ केन्द्र के साथ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार करने के लिए नहीं हैं, केन्द्रीय तथा स्थानीय इच्छाओं के मध्य विचार विरोध होने की स्थिति में स्वाभाविक रूप में केन्द्रीय इच्छा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किंतु स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय सस्था सही अर्थों में स्वशासकीय हो और उनके लिए जिस क्षेत्राधिकार का निश्चय किया जाता है वह एक अपवाद न होकर वस्तुतः यथार्थ हो। जनता को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाय। स्वशासन का अर्थ अराजकता तथा अव्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्वशासन का लक्ष्य यह कदापि नहीं है कि स्थानीय सस्थाओं पर कोई नियन्त्रण न रहता जाय और उन्हें केन्द्रीय व्यवस्था के साथ प्रतिद्वंद्विता करने के लिए छोड़ दिया जाय। इसके लिए उनके ऊपर किसी न किसी रूप में केन्द्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता है। केन्द्रीय नियन्त्रण और भी कई कारणों से आवश्यक है

(1) पर्याप्त धन (Inadequate Funds)—स्थानीय स्वशासन एक महँगी व्यवस्था है। उन्हें केन्द्र से धन प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से धन प्रदान करने वाली सस्था किसी न किसी रूप में नियन्त्रण रखने को इच्छुक रहेगी।

(2) सीमित अनुभव (Limited Experience)—स्थानीय सस्थाएँ अनुभव

की दृष्टि से अपरिपक्व होती है। उनका अनुभव सीमित होता है। केन्द्रीय नियन्त्रण के माध्यम से उन्हें विशेषज्ञों की सेवाओं के अतिरिक्त अनुभव तथा अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है।

(3) अशुद्ध नीतियों का प्रभाव (Effect of Wrong Policies)—स्थानीय सस्थाओं की सीमाएँ बहुत पास पास होती हैं। एक सस्था की अपनायी हुई अशुद्ध नीतियों का प्रभाव अल्प सस्थाओं पर भी पड़ता है। उसे रोकने के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता है।

(4) शक्ति-सम्पन्न स्वायत्त को रोकने के लिए भी केन्द्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ती है।

(5) सेवाओं का उच्च स्तर (High Standard of Services)—सेवाओं में स्तर ऊँचा बना रहे उनकी संचालन व्यवस्था सही रूप में स्थापित रहे, इसके लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। नियन्त्रण से असमानता कम होगी। सर मैकनाल्टी (Macnalty) ने कहा है, "स्थानीय सेवाओं के उचित निर्देशन, एकीकरण तथा समन्वय के लिए केन्द्रीय सत्ता के नियन्त्रण के किसी यन्त्र का होना परमावश्यक है, ऐसा न होने पर विभिन्न जिलों में इन सेवाओं का स्तर एवं प्रसार असमान रहेगा तथा यह कुल जनसंख्या के लिए अयायपूर्ण होगा।"

केन्द्रीय नियन्त्रण का स्वरूप (Forms of Parliamentary Control)

(1) विधायी नियन्त्रण (Legislative Control)—यदि हम ससदीय नियन्त्रण का विश्लेषण न करें तो हम सम्भवतः ऐसा अनुभव करते हैं कि स्वशासी सस्थाओं का शासन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वे यथायथ में जनता के प्रति ही उत्तरदायी हैं। मंत्रियों को स्थानीय सरकारों के विषय में हस्तक्षेप करने तथा उसके कमचारियों को पदच्युत करने का कोई अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप विकेंद्रवाद के विरुद्ध है। किंतु इससे देश की स्थानीय सस्थाओं के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं आ सकती। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। जब धन की पूर्ति ससद करती है तो उसके द्वारा नियन्त्रण होना अपेक्षित है। ससदीय नियन्त्रण निम्न लिखित रूपों में स्थापित किया गया है।

(1) मंत्रियों को विविध परिपत्रों (Circulars) के द्वारा स्थानीय सरकारों को परामर्श देने का अधिकार है।

(2) मंत्री व्यक्तिगत मामलों में भी स्थानीय सरकारों को परामर्श दे सकते हैं।

(3) आवास तथा स्थानीय सरकार का मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय अधिकारों के बीच सम्बन्धों की मुख्य कड़ी है।

(4) स्थानीय सरकारों को मायता ससदीय अधिनियम के द्वारा दी जाती है।

(5) किसी भी स्थानीय सस्था के स्तर में उन्नति ससदीय स्वीकृति के उपरांत ही की जा सकती है।

सही रूप में नियंत्रण कर सकते हैं कि स्थानीय निराया द्वारा किस सीमा तक उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है।

वस्तुतः केन्द्रीय सरकार का प्रमुख कार्य यह देखना है कि स्थानीय सरकारों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न हो। बानूनों के क्रिया-बन के लिए केन्द्र को स्वस्थ एवं प्रभावशाली ढंग में उठाने की आवश्यकता होती है। सरकार अपने निरीक्षक (Inspectors) तथा ऑडिटर (Auditors) रखती है जो स्थानीय निकायों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और उनके हिमाय विताय का परीक्षण करते हैं। केन्द्र सरकार ही इस बात का नियंत्रण करती है कि किस स्थानीय निकाय के कार्यों में वृद्धि की जाय और किसकी शक्तियाँ कम की जाय, किस नयी समस्या को उत्पन्न किया जाय और किसकी उन्नति की जाय। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थानीय निकाय केन्द्र की दास मात्र हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्णरूप से स्वतन्त्र हैं और जन-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पूर्णरूप से सचेष्ट रहते हैं। फाइनेर (Finer H) ने कहा है, केन्द्रीय सरकार अनावश्यक रूप से झगडातू बनकर नहीं रहती वह स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की स्वतन्त्रता का सम्मान करती है और अच्छा यही समझती है कि आवश्यकता के बिना वे अपनी स्वतन्त्रता का उचित प्रयोग कर सकें।¹ केन्द्र तभी हस्तक्षेप करता है जब ऐसा करना अतिआवश्यक हो।

Select References

- Finer *English Local Govt*
 Jackson W E *The machinery of Local Govt*
 Jennings *Principles of Local Govt*
 Mand *Local Govt in Modern England*
 Rohson *The Development of Local Govt*
 Clarke J J *Outline of Local Govt*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन की प्रमुख संस्थाओं की चर्चा कीजिए, तथा उनके निर्माण और कार्यों का वर्णन कीजिए।
 (Describe the main agencies of Local Govt in England and discuss their Composition and Functions)
- 2 इंग्लैण्ड में स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण की सीमाएं बताइए।
 (Describe the nature of control exercised by the Central Government on the working of Local Institutions in England)

1 The Central Govt is not meddlesome in respects the freedom of the local government bodies and would prefer to see this exercised properly without the need to intervene

(6) सामान्य नीतियों के लिए स्थानीय सरकारों के द्वीय विकास विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

(7) सरकार के विविध मंत्रालय के द्वीय तथा स्थानीय सरकारों के मध्य ताल मेल उत्पन्न करते हैं।

(8) स्थानीय समस्याओं को उतनी ही शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार है जितनी शक्तियाँ संसद ने उन्हें दी हुई हैं।

(9) स्थानीय सरकारों के क्षेत्र तथा कार्यों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। नवीन इकाइयों की स्थापना भी संसदीय नियमों द्वारा की जाती है।

(2) प्रशासकीय नियंत्रण (Administrative Control)—इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों पर केन्द्रीय नियंत्रण सरकार के विविध विभागों द्वारा स्थापित किया जाता है। फ्रांस में यह नियंत्रण एक विशेष विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है। ये विभाग हैं—स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, यातायात तथा कृषि आदि। ये विभाग अपने-अपने विषयों में सम्बन्धित निर्देश देते हैं तथा स्थानीय निकायों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। वे उन्हें आवश्यक सूचना दे सकते हैं। ये विभाग अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित स्थानीय निकायों के विषय में शिकायतें सुनते हैं और व्यक्तियों के परस्पर झगड़ों का निपटारा करते हैं। प्रशासकीय विभाग इस बात के लिए भी सचेष्ट रहते हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग न हो। ये विभाग न केवल निर्देश देते हैं बरन आवश्यक रूप से परामर्श भी देते हैं।

(3) वित्तीय नियंत्रण (Financial Control)—स्थानीय निकाय वास्तव में केन्द्रीय आर्थिक सहायता के सहारे ही जीवित रहते हैं। स्थानीय निकायों पर वित्तीय नियंत्रण निम्नलिखित तरीका से स्थापित किया जाता है।

(1) केन्द्र यह देखता है कि वित्त का प्रयोग उनके निर्देशानुसार हो रहा है अथवा नहीं।

(2) प्रशासकीय विभागों के निरीक्षक निरीक्षण करके स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

(3) केन्द्र अपने आडिटरों द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा रखे गये हिसाब किताब का परीक्षण कराता है।

(4) यदि धन का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया गया है, तो उसने सम्बन्ध में सरकार पहले निकाय से सुधार करने के लिए कहती है और बाद में सुविधानुसार उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में विचार करती है।

(5) केन्द्रीय अनुदान को संसद रोक सकती है अथवा उस बड़ा सकती है।

(6) स्थानीय निकाय उन योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्र अनुदान देने के लिए तैयार हो जाता है।

(4) न्यायिक नियंत्रण (Judicial Control)—स्थानीय निकायों के अनुचित कार्यों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ही इस बात का

सही रूप में नियंत्रण कर सकते हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा किस सीमा तक उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है।

वस्तुतः केन्द्रीय सरकार का प्रमुख कार्य यह देखना है कि स्थानीय सरकारों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न हो। वानूनी के क्रिया-दान के लिए केन्द्र को स्वस्थ एवं प्रभावशाली ढंग में उठाने की आवश्यकता होती है। सरकार अपने निरीक्षक (Inspectors) तथा आडिटर (Auditors) रखती है जो स्थानीय निकायों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और उनके हिसाब किताब का परीक्षण करते हैं। केन्द्र सरकार हो इस बात का नियंत्रण करती है कि किस स्थानीय निकाय के कार्यों में वृद्धि की जाय और किसकी शक्तियों में कमी, किस नयी सस्था को उत्पन्न किया जाय और किसकी उन्नति की जाय। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थानीय निकाय केन्द्र की दास मात्र हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं और जन कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पूर्णरूप से सचेष्ट रहते हैं। फाइनेर (Finer H) ने कहा है "केन्द्रीय सरकार अनावश्यक रूप से झगड़ालू बनकर नहीं रहती वह स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और अच्छा यही समझती है कि आवश्यकता के बिना वे अपनी स्वतंत्रता का उचित प्रयोग कर सकें।"¹ केन्द्र अभी हस्तक्षेप करता है जब ऐसा करना अतिआवश्यक हो।

Select References

- Finer *English Local Govt*
 Jackson W E *The machinery of Local Govt*
 Jennings *Principles of Local Govt*
 Mand *Local Govt in Modern England*
 Robson *The Development of Local Govt*
 Clarke J J *Outline of Local Govt*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन की प्रमुख सस्थाओं की चर्चा कीजिए, तथा उनके निर्माण और कार्यों का वर्णन कीजिए।
 (Describe the main agencies of Local Govt in England and discuss their Composition and Functions)
- 2 इंग्लैण्ड में स्थानीय सस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण की सीमाएं बताइए।
 (Describe the nature of control exercised by the Central Government on the working of Local Institutions in England)

1 The Central Govt is not meddlesome it respects the freedom of the local government bodies and would prefer to see this exercised properly without the need to intervene

प्रशासकीय सेवाएँ [The Civil Services]

"Ministers work is not to work but to get it worked"

—Bagehot

प्रशासन एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसका नियन्त्रण एवं संचालन केवल राजनीतिक कार्यपालिका के सहारे नहीं किया जा सकता। प्रशासन का वास्तविक उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभागों पर है जिसे हम स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive) कहते हैं जो मंत्रिमण्डल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसके अपने राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होते और यदि होते भी हैं तो वे उसकी सेवाओं में रहते हुए अभिव्यक्ति नहीं करते। मंत्री तो आते और जाते रहते हैं। उनके इस आवागमन का स्थायी कार्यपालिका की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशासकीय वर्ग स्वयं नियम नहीं करता अपितु मंत्रिमण्डल द्वारा किये गये नियमों को लागू करता है। प्रशासन के इस स्थायी पक्ष को हम नौकरशाही (Bureaucratic) वर्ग कहते हैं। काम दरअसल ये ही करते हैं। मंत्रिमण्डल की नीतियों तथा उनके नियमों को भी प्रभावित करते हैं किंतु वे इस क्षेत्र में सामने नहीं आते। ये सब कार्य मौलिक रूप से मंत्रिमण्डल के हैं। प्रशासकीय वर्ग विशेषज्ञों तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों का ऐसा वर्ग है जिन्हें विशेषकर इसी कार्य के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें सामान्य प्रशासन का विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सचमुच सरकार के हाथ, नाक, कान तथा पैर हैं।

आज का युग प्रगतिशीलता एवं समाजवादी विचारों का है। राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। इंग्लैंड ने भी 19वीं शताब्दी के पुलिस राज्य की विशिष्टताओं को जलेबत्तन कहकर राज्य के लोक कल्याणकारी (Welfare State) स्वरूप को अपनाया है। इससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों तथा उनके सचिवों पर आ पड़ी है। प्रशासन का कार्य केवल प्रशासन करना ही नहीं रहा है बरन् सक्रिय रूप में मावजनिक स्तर को ऊँचा उठाना सामाजिक उत्थान के विविध पहलुओं को संभालना एवं उनकी प्रगति में योग देना है। प्रशासक केवल प्रशासक ही नहीं है बल्कि वह समाज का सेवक तथा पथ प्रदर्शक भी है। लास्की (Lasky) ने ठीक ही कहा है कि 'एक निपेष्ठात्मक राज्य से सकारात्मक राज्य के बनने में सावजनिक काम इतना बढ़ गया है कि मंत्री विवश होकर केवल महत्वपूर्ण नीतियों के नियमों को छोड़कर शेष कार्य अपने प्रशासकों पर छोड़ देते हैं।' अमेरिकी सेवाओं के महत्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए फाइनर (H. Finer) ने कहा है कि 'सरकार का राजनीतिक पक्ष कितना भी सबल क्यों न हो, हमारी राजनीतिक भावनाएँ कितनी भी व्यापक क्यों न हो, हमारा नेतृत्व तथा कमाण्ड कितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो किंतु इन चीजों का प्रभाव उस समय तक नहीं होता जब तक

एक वग में ऐसे प्रशासकीय कर्मचारी उपलब्ध न हों जो इस शक्ति एवं बुद्धि के कोप को व्यक्तिगत मामलों में कार्यान्वित करने में कुशल हों।”

ब्रिटिश संसद की भाँति, ब्रिटिश असेनिक सेवा संगठन ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की असेनिक सेवाओं को प्रभावित किया है। ब्रिटेन में असेनिक सेवाओं का महत्व इतना व्यापक है कि मंत्रियों को स्थायी कर्मचारियों के हाथों में यह मात्र कहा जाता है इंग्लैंड की असेनिक सेवाओं को अमेरिका की दूषित लूट खसोट की प्रणाली से दूर रखने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया है। काय कुशलता एवं राजनीतिक कार्यों में निष्पक्षता—ब्रिटिश असेनिक सेवाओं के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। Report of the Committee on the Political Activities of Civil Servants, 1949 में लिखा है—“The political neutrality of the Civil Service is a fundamental feature of British democratic government and is essential for its efficient operations” मंत्रियों को अपने काय का बहुत कम ज्ञान होता है। उनका काय तो केवल नीति निर्धारित करना है। इन नीतियों को काय रूप में परिणत करने का काय स्थायी सेवाओं के कर्मचारियों का है। ब्रिटिश असेनिक सेवाओं को राजनीतिक संरक्षण से दूर रखा गया है। असेनिक सेवाओं में निष्पक्षता उत्पन्न करने के लिए ठोस प्रयत्न किये गये हैं। ब्रिटिश लोक सेवाओं को इतना आकर्षक बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उन्हें जीवन-वृत्त का स्थायी साधन स्वीकार करने में हिच-किचाहट अनुभव नहीं होती।

गैर-औद्योगिक असेनिक सेवाओं को इंग्लैंड में निम्नलिखित श्रेणियाँ में वर्गीकृत किया गया है

1 प्रशासकीय वग (Administrative Class)—इसे ब्रिटेन में समस्त सेवाओं का मूल केन्द्र माना जाता है। यह एक निर्देशक वग है। इस वग की मूल विशेषताएँ इस प्रकार हैं

(क) इस वग में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की आयु 22 तथा 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ख) स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही इसमें प्रवेश प्राप्त करने का समानाधिकार है।

(ग) उच्च कोटि के स्नातको में से कठिन प्रतियोगी परीक्षणों द्वारा चयन किया जाता है।

(घ) प्रत्याशियों में स्नातक स्तर की योग्यता होना अनिवार्य है।

(ङ) समग्र नीति निर्माण, नियंत्रण, सामान्य प्रशासन में निर्देशन तथा प्रशासकीय सुधार आदि कृत्यों में सम्मिलित हैं।

(च) इन सेवाओं में निम्नलिखित प्रकार के पदाधिकारी सम्मिलित किये जाते हैं राजकोष का स्थायी सदस्य, स्थायी सचिव, उपसचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव प्रधान सहायक सचिव।

(छ) इस वग के कर्मचारियों को प्रति सप्ताह लगभग 45½ घण्टे काय करना पड़ता है।

(ज) इस वग के कर्मचारियों को वय में 36 दिन की छुट्टियाँ दी जाती हैं। इनकी सरुवा दस वर्ष की सेवा के उपरान्त बढ़कर 48 दिन हो जाती है।

2 निष्पादक वग (Executive Class)—आयु 38 से लेकर 65 वर्ष तक।

शिक्षा माध्यमिक स्तर की योग्यता।

- कर्तव्य (1) निर्धारित नीति के वृत्त के अन्तर्गत दैनिक कार्यों का संचालन ।
 (2) पूर्ति सम्बन्धी कार्य ।
 (3) वित्त एवं लेखांकन कार्य ।
 (4) विशिष्टीकृत कार्य—करो का निर्धारण सामान्य प्रकार की विशेष योग्यता ।

मुख्य पदाधिकारी (1) बड़े संस्थानों के अध्यक्ष (2) प्रधान निष्पादन अधिकारी, (3) वरिष्ठ मुख्य निष्पादक अधिकारी, (4) मुख्य निष्पादक अधिकारी, (5) वरिष्ठ निष्पादक अधिकारी, (6) उच्च निष्पादक अधिकारी (7) निष्पादक अधिकारी ।

काम के घण्टे : प्रति सप्ताह—45½ (साधारण स्थिति में), प्रतिदिन—5½ ।
 अवकाश 36 दिन प्रति वर्ष 48 दिन (15 वर्ष की सेवा उपरान्त) ।

3 लिपिक वर्ग (Clerical Class)—आयु—16 से लेकर 17½ वर्ष तक के बीच ।

योग्यता—माध्यमिक स्तर की परीक्षा (यह हमारे यहाँ की इण्टर परीक्षा के स्तर तक की होती है) ।

कर्तव्य—(1) उच्च लिपिक अधिकारी कुछ संस्थानों में लिपिक कर्मचारी वर्ग के कार्यों की देखभाल करते हैं ।

(2) यह उनके द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षण का मुख्य भाग है ।

(3) वे उन सब कार्यों को सम्पन्न करते हैं जो लिपिक सहायकों को नहीं सौंपे जाते ।

(4) स्पष्ट अनुदेशों सामान्य प्रक्रिया, सुस्पष्ट विनियमों के अनुसार विशिष्ट मामलों का निपटारा करते हैं ।

(5) साधारण श्रेणी के लेखा, विवरण पत्रों आदि का सूक्ष्म परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण करते हैं ।

(6) विवरण पत्रों, निर्धारित फार्मों के लिए आर्डर तथा सामग्री तैयार करते हैं ।

(7) उस सामग्री का एकीकरण करते हैं जिसके आधार पर नियम करना सम्भव हो सके ।

(8) अभिलेखों का मार (Precis) तैयार करते हैं ।

पदाधिकारी—वर्तमान मुख्य विभागीय पदक्रम इस प्रकार हैं

(1) अतिरिक्त राजस्व अधिकारी ।

(2) श्रम मंत्रालय पदक्रम पण्डित अधिकारी ।

(3) सीमा शुल्क व उत्पादन कर विभागीय लिपिक अधिकारी ।

(4) उच्च लिपिक अधिकारी वर्ग ।

(5) लिपिक अधिकारी वर्ग ।

काम के घण्टे प्रतिदिन 5½ घण्टे तथा सप्ताह में 45½ घण्टे ।

अवकाश उच्च लिपिक अधिकारी—36 दिन लिपिक अधिकारी—24 दिन ।

4 लिपिक सहायक वर्ग (Clerical Assistant Class)—यह पूर्णतः प्रतियोगितात्मक वर्ग है इसके कर्मचारियों को 8 दिन का सशुल्क अवकाश दिया जाता है । किन्तु 5 वर्ष की सेवाओं के उपरान्त यह संख्या बढ़कर 21 भी हो सकती है ।

कतब्य—(1) युद्धकालीन सरल कार्यों का सम्पादन ।

(2) सरल अभिलेखों, आर्वाइवों तथा दस्तावेजों की तैयारी ।

(3) उनका सूक्ष्म परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ।

(4) सरल गणित के आँकड़े तैयार करना ।

(5) स्पष्ट अनुदेशों के अनुसार सरल पत्र व्यवहार करना ।

(6) रजिस्ट्री कार्य के साधारण फार्म तैयार करना ।

(7) कार्यालय यंत्रों का संचालन ।

इस वर्ग के कमचारियों के ये कार्य अवश्य हैं किंतु कोई कठोर सीमा नहीं है । इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उन्हें और भी कार्य सौंपे जा सकते हैं ।

5 मुद्रा लेखक वर्ग (Typist Class) ।

6 व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग ।

7 डाकघर अभिसाधक वर्ग (Post office Manipulative Class) ।

8 सवेशायाहक ।

9 डाकघर, इञ्जीनियरिंग तथा अन्य सम्बद्ध सेवा ।

सिविल सेवा आयोग (Civil Service Commission)

1855 में ब्रिटेन में असैनिक सेवाओं के लिए योग्य कमचारियों की खोज एवं भर्ती करने के लिए एक केन्द्रीय परीक्षक मण्डल (Central Board of Examiners) की स्थापना की गई थी । वर्तमान छ सदस्यीय सिविल सेवा आयोग इसी का विवर्धित रूप है । इनकी नियुक्ति फ़ाइन द्वारा होती है । दोष अनुभव सम्पन्न व्यक्तियों को ही इसका सदस्य नियुक्त किया जाता है, और सेवाओं में निष्पक्षता उत्पन्न करने तथा सदस्यों को राजनैतिक सरक्षण से मुक्त रखने के लिये उन्हें मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है । आयोग अपनी रिपोर्ट मंत्रिमण्डल को समर्पित न करके, प्रत्यक्ष रूप में महारानी को समर्पित करता है । सदस्य अपने कार्यों के लिए महारानी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । आयोग का सम्बन्ध कोष से है जो नियम निर्माण में भाग लेता है । सदस्यों को लगभग अर्ध-व्यापिक अधिकार प्राप्त हैं । सदस्यों को उनके पद से केवल उस स्थिति में मुक्त किया जा सकता है, जबकि संसद के दोनों सदन द्वारा महारानी से इस प्रकार की कोई प्राप्ति की जाय । ब्रिटेन में यह सत्य स्थापित हो चुका है कि लोक सेवा आयोग अपने कार्यों में एक निष्पक्ष भाव एवं स्वतंत्रता से कार्य करता है ।

अधिकांश असैनिक सेवाओं में प्रवेश खुली प्रतियोगिता द्वारा होता है । प्रतियोगिता सम्बन्धी नियमों का निर्माण आयोग तथा राजकोष द्वारा संयुक्त रूप में होता है । खुली प्रतियोगिता निम्न प्रकार से होती है

(क) लिखित परीक्षा ।

(ख) साक्षात्कार द्वारा ।

(ग) संयुक्त पद्धति द्वारा । व्यक्तित्व की परीक्षा साक्षात्कार द्वारा ज्ञानाजन की लिखित परीक्षा द्वारा । परीक्षाओं के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं

(1) परीक्षाएँ सामूहिक रूप में विविध सेवाओं के लिए एक ही परीक्षा केन्द्र पर ली जाती हैं ।

(2) परीक्षाओं का मूल उद्देश्य प्रत्याशियों की बौद्धिक क्षमता को मापना है ।

(3) परीक्षा के विषय शैक्षणिक होते हैं जिनके द्वारा प्रत्याशियों की विवरणात्मकता की जाँच करना होता है।

(4) तकनीकी प्रवार की परीक्षाओं की व्यवस्था व्यावसायिक प्रकार की सेवाओं के लिए होती है।

क्या ससब मंत्रियों के हाथों में तथा मंत्री स्थायी राजकीय पदाधिकारियों के हाथों में यंत्र है? (Is Parliament a Tool in the hands of the Cabinet and the Cabinet is a tool in the hands of Permanent officials)

इस प्रश्न के दो पहलू हैं—एक का सम्बन्ध ससद से है और दूसरे का सम्बन्ध स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों से है। इसका सम्बन्ध राम्से म्योर (Ramsay Muir) के इस कथन से भी है कि मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनप रही है (Bureaucracy thrives under the cloak of Ministerial Responsibility)। इस प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से भी है कि क्या मंत्रियों को विशेषज्ञ होना चाहिए (Should Ministers be experts)? इंग्लैण्ड के संविधान में विशेषज्ञों तथा अविशेषज्ञों का अनुपम सम्बन्ध है एक का सम्बन्ध लोकप्रियता से है और दूसरे का सम्बन्ध दक्षता से है। मंत्री विशेषज्ञ हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार इंग्लैण्ड का रक्षामंत्री एक दार्शनिक अथवा पत्रकार रहा। वित्त मंत्री ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि गणित में सदैव फेल होता रहा हो और जो ऑक्सफोर्ड तथा ईटन को पढ़ाई भूलकर दशमलव प्रणाली को समझने के लिए गणित के ट्यूशन की आवश्यकता अनुभव करता हो। एक वकील अथवा मंत्री हो सकता है। एक बार पार्लियामेंट उपनिवेश मंत्री थे तो उन्हें अपने विभाग के सचिव से बुलाकर यह समझने की आवश्यकता अनुभव हुई कि इंग्लैण्ड के ये उपनिवेश विश्व में कहाँ-कहाँ बिखरे पड़े हैं। सर एडवर्ड कार्सन ने एक बार कहा था कि 'इस पद पर मेरी योग्यता बस इतनी ही है कि मैं इस विषय में पूणत अज्ञानी हूँ।' एक बार इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने कहा था। 'मुझे सन्तुष्ट है कि आप (असैनिक कर्मचारी) हम लोगों के बिना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं किन्तु मुझे इस बात का विश्वास है कि हम लोगों के बिना विभाग का काम नहीं कर सकेंगे।' मंत्री यदि विशेषज्ञ न हों तो इसके कई लाभ हैं —

(1) शासन सुचारु रूप से चल सकेगा क्योंकि दो विशेषज्ञों में मतभेद होना कठिन होता है।

(2) मंत्री का काम निश्चयन एवं नियंत्रण है। यदि वह विशेषज्ञ है तो वह इन दोनों कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता।

(3) मायजनिश हिटोपादान विशेषज्ञता से सुलभ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो कि विशेषज्ञता में उपलब्ध नहीं हो सकता। विशेषज्ञ का दृष्टिकोण संकुचित होता है।

(4) राजनीतिक कार्यपालिका के सम्बन्ध आत और जान रहने हैं। उनसे लिए विनिष्ट अनुभव की आवश्यकता नहीं हो सकती।

(5) नेताओं के पास काइमों में नियामक मानने तथा अंगि फोड़ने का समय नहीं होता। यदि वे अपना समय इसमें लगावें तो वे ग्राह्यश्रितियों का निजि नहीं कर सकेंगे। इसी कारण यह कार्य स्थायी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है।

इसकी चर्चा का हम पक्ष भी यदि तमसन्धीय अजिनायकत्व के सम्बन्ध में कर रहे हैं कि समग्र विम प्रकाश तथा किम सीमा तक मंत्रिमण्डल के हाथों में एक

यत्र मात्र है। हम प्रायः सुनते और कहते भी हैं कि वर्तमान शताब्दी मंत्रिमण्डल की है। 'संसद का कार्य उपक्रम नहीं है कि तु आलोचना करना मात्र है।' लोक सदन केवल मंत्रिमण्डल की इच्छा को पजीकृत करने मात्र के लिए हैं। दलीय अनुशासन, संसद को विघटित कराने की शक्ति संसद के पास समयाभाव मंत्रिमण्डल की सजातीयता, प्रत्यायोजित विधान, सरक्षण की शक्ति आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से संसद के सदस्य मंत्रिमण्डल के हाथों में कठपुतली सी बने रहते हैं। संसद केवल मंत्रिमण्डल की इच्छा पर मोहर लगाने का कार्य करती है। संसद विघटन से घबराती है। इसी कारण वह मंत्रिमण्डल की बातों को कभी अस्वीकार करने का साहस नहीं करती। मंत्रिमण्डल पहले नियंत्रण करके अपनी नीतियों पर संसद का समर्थन बाद में प्राप्त करते रहते हैं। वास्तव में संसद स्वयं कुछ नहीं करती। मंत्रिमण्डल जिस प्रकार से भी उसे चलाना चाहता है, वह चलती है। मंत्रिमण्डल उसका नेतृत्व करता है। मंत्रिमण्डल स्थायी कमचारियों के हाथों में यत्रवत् है।

शासन का संचालन वास्तव में मंत्री नहीं करते। शासन का संचालन करने वाले तो स्थायी कमचारी ही हैं। एक के पास दृष्टिकोण है और दूसरे के पास अनुभव। मंत्री का दृष्टिकोण सामान्य होता है और प्रशासनिक का विशिष्ट। किंतु यह अनुभव हमारी भूल है। प्रशासन उस रूप में विशेषण नहीं है जिस रूप में कि डॉक्टर तथा वकील विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासकों के पास एक सामान्य दृष्टिकोण होता है और उन्हें विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें व्यापक अनुभव होता है। मंत्री आते और जाते रहते हैं। उनके इस आवासन का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। अविशेषज्ञ मंत्री का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता। विभागीय सचिव की सलाह एवं सूचनाओं के लिए मंत्री को उनके ऊपर अवलम्बित रहना पड़ता है। एक-दो अपवादों को छोड़ कर 99% मंत्री अविशेषज्ञ होते हैं और वे अपने सचिवों पर निर्भर रहते हैं। मंत्रियों की इस निर्भरता के कई कारण हैं।

(1) मंत्री अविशेषज्ञ होते हैं और लोक सेवाओं के कमचारी दक्ष एवं कार्य कुशल होते हैं।

(2) मंत्रियों का अधिकांश समय जन सम्पर्क तथा दलीय कार्यों में व्यय होता है।

(3) मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता।

(4) मंत्रियों को प्रशासकीय विभागों का अनुभव नहीं होता। उन्हें वास्तविक सूचना तक नहीं होती। उन्हें कानूनों का ज्ञान भी नहीं होता। यदि उनके अध्ययन में वह अपना समय लगाएँ, तो उसका अध्ययन पूर्ण करने तक उनके चलने का समय आ जाता है।

(5) विभागीय जटिलताओं को समझने तथा उन्हें सुलझाने का मंत्री के पास समय भी नहीं होता और न ही विशेष योग्यता।

(6) प्रत्यायोजित विधान के कारण भी उच्चतर सेवा के कमचारियों की शक्तियों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

इस कमचारियों की शक्ति इतनी बढ़ गयी है कि उन्हें वास्तविक शासन कहा जाता है। इनकी बाध्यकारी शक्तियों का विकास समाजवाद के विकास के माध्यम और अधिक हुआ है। आज वस्तुतः मंत्री नोकरशाही के हाथों में पड़े गया है। यह वह दलदल है जहाँ से घुस कर निरसन कठिन होता है। परोक्ष रूप से मंत्री जो कुछ भी चाहता अपना करता है वह सब स्थायी पदाधिकारियों के इशारों पर। सचिव जिस

रूप में भी उसे धुमाना चाहता है, धुमा सकता है। वह सचिव से हर प्रश्न पर परामर्श करता है। मंत्रिमण्डल की नीतियाँ वास्तव में स्थायी सेवा के कमचारियों की नीतियाँ हैं। मंत्री सदन में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तथा सूचनाएँ देते हैं यह सब परोक्षरूप में विभागीय सचिव द्वारा होता है। विभागीय सचिव तो स्थायी बंधू है जो अपने हरेक पति को वश में करना जाता है। वह जानती है कि किस अवसर पर किस पति से कैसे काम लिया जा सकता है। यहाँ तक देखा गया है कि सचिव ही मंत्रियों के अभिभाषण तक तैयार करते हैं। नौकरशाही का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि नागरिक स्वतंत्रताओं का स्वर्णिम आलोक ओझल होता हुआ जान पड़ता है। रैम्जे म्योर, हीवट तथा सी० के० एसन ने नौकरशाही की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए उसे खतरनाक कहा है।

किंतु इंग्लैंड में नौकरशाही का जो रूप है उसे सॉंस्की नौकरशाही ही नहीं मानता क्योंकि नौकरशाही से इंग्लैंड में नागरिकों की स्वतंत्रताएँ कम नहीं हुई हैं, जो कि उसका विशिष्ट गुण है। नौकरशाही वहाँ शासन पर छाई हुई नहीं है ब्रिटिश असैनिक सेवाएँ राज्य के मध्य राज्य नहीं हैं। ब्रिटिश असैनिक सेवाएँ बहुत कुछ सीमा तक नौकरशाही के परम्परागत दोषों से मुक्त रहती हैं। 'न्यूमन (Newmann) के शब्दों में "अधिनायकवाद या तानाशाही कहे जाने का कोई तथ्य युक्त कारण नहीं है।" इंग्लैंड में लोक सेवाओं तथा मंत्रियों के मध्य स्वस्थ सम्बन्ध है। राजनीतिक प्रभावों से मुक्त लोक सेवाएँ काफी सीमा तक निष्पक्ष हैं। मंत्रिमण्डल नीतियों का निर्धारण करता है और लोक सेवाएँ उन्हें निष्पादित करती हैं। लोक सेवक मंत्रियों की सलाह देते हैं। मंत्री भी काफी चौकन्ने रहते हैं तथा लोक सेवाओं के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। लोक सेवक भी कोई ऐसी सलाह नहीं देते जिससे उनकी तथा मंत्रियों की स्थिति सबटमय हो जाय। अतः इंग्लैंड में नौकरशाही का इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि उसका होना आलोचकों ने बनाया हुआ है।

Select Readings

Munro *Govt of Europe*
Ramsay Muir *How Britain is Governed*
Lasky *Parliamentary Govt in England*
Finer *Major Govts of Europe*

परीक्षापयोगी प्रश्न

- 1 "सम्राट की तरह ही स्थायी कमचारी बग भूल नहीं कर सकता। दोनों मंत्रियों के उत्तरदायित्व के आवरण में छिपे हुए हैं।" इस कथन की समीक्षा करें।

(The permanent official like the king can do no wrong. Both are shielded by the responsibility of the ministers. Examine the statement.)

- 2 "मंत्रियों के उत्तरदायित्व के आवरण में नौकरशाही का बोलबाला है।" इस कथन की समीक्षा करें।

(Bureaucracy thrives under the cloak of ministerial responsibility. Discuss.)

- 3 'ब्रिटिश संसद मंत्रियों के हाथ में और मंत्री स्थायी कमचारी बग के हाथ में पिरोने का सामान है। इस कथन की विवेचना करें।

(The British parliament is a tool in the hands of the ministers and the ministers are as tools in the hands of the permanent officials. Examine.)

द्वितीय खण्ड

अमेरिकी-संविधान

- अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख विशेषताएँ
- अमेरिकी कार्यपालिका (राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा मंत्रि-मण्डल)
- राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सीनेट
- राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—प्रतिनिधि सदन
- अमेरिका की न्याय व्यवस्था
- अमेरिकी राजनैतिक दल
- राज्य सरकारें

1

अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख विशेषताएँ

[Main Features of the American Constitution]

“अमेरिका का संविधान सब कुछ काट छाँट करों के बाव भी
विश्व के समस्त संविधानों में अछूट है।” —ग्राहम

‘In America, there is no king in his place there
in the constitution’ —Harold Stannard

विश्व के प्रमुख प्राचीन संविधानों में से अमेरिका का संविधान अपना महत्वपूर्ण स्थान आज भी बनाए हुए है। अमेरिकन महाद्वीप के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य स्थित है। बहुत लम्बे अरसे तक अमेरिका शेष विश्व की गतिविधियों से अपने को पृथक् रख सका। इसका मूल कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। अमेरिका प्रशांत तथा एटलाण्टिक महासागरों से घिरा हुआ उत्तर में कनाडा तथा ग्रीनलैण्ड के चरणा का आर्शियाद लेता हुआ दक्षिण में मक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। अपनी विचित्र भौगोलिक स्थिति के ही कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनरो के सिद्धांत पर चलकर अपने को शेष विश्व की राजनीति से अलग बनाये रखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का अपना विशिष्ट स्थान है। आज इसमें 50 राज्य हैं जो सघ की हकाइयाँ हैं और 30 लाख वर्गमील इसका क्षेत्रफल है। आकार में यह भारत से $2\frac{1}{2}$ गुना, फ्रांस से 26 गुना तथा इंग्लैण्ड से 25 गुना बड़ा है। किंतु साक्ष्यित रस के आध से कम क्षेत्र में है। प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल समान नहीं है। किंतु फिर भी उनकी क्षेत्रीय समानता को बनाये रखने का पूरा प्रयास सीनेट (Senate) के माध्यम से संविधान में किया गया है।

जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का स्थान चीन, भारत तथा रूस के बाद आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है। प्राकृतिक साधनों की ध्यान में रखते हुए यह जनसंख्या अधिक नहीं है। जनता की दशा सन्तोषजनक है। निम्न आर्थिक ढंग के लोग अल्प देशों के साधारण ढंग की अपेक्षा अधिक खुशहान हैं। जापान, भारत चीन व इंग्लैण्ड की अपेक्षा अमेरिका की समस्याएँ नगण्य हैं। जनता में चाहे वैदेशिक नीति की असफलता को लेकर द्वन्द्व हो जाय किंतु किसी भी सति का भय नहीं है। सम्भवतः यही कारण है कि संविधान के मौलिक की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई।

1

अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख विशेषताएँ

[Main Features of the American Constitution]

“अमेरिका का संविधान सब कुछ काट छाँट करने के बाद भी
विश्व के समस्त संविधानों में घण्ट है।” —ब्राइस
“In America, there is no king in his place there
is the constitution” —Harold Stannard

विश्व के प्रमुख प्राचीन संविधानों में से अमेरिका का संविधान अपना महत्वपूर्ण स्थान आज भी बनाए हुए है। अमेरिकन महाद्वीप के मध्य में समुक्त राज्य अमेरिका का राज्य स्थित है। बहुत लम्बे अरसे तक अमेरिका शेष विश्व की गतिविधियों से अपने को पथक रख सका। इसका मूल कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। अमेरिका प्रशांत तथा एटलाण्टिक महासागरों से घिरा हुआ उत्तर में कनाडा तथा ग्रीनलैंड के चरणों का आर्शवाह सेता हुआ दक्षिण में मक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। अपनी विचित्र भौगोलिक स्थिति के ही कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनरो के सिद्धांत पर चलकर अपने को शेष विश्व की राजनीति से अलग बनाये रखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का अपना विशिष्ट स्थान है। आज इसमें 50 राज्य हैं जो सघ की इकाइया हैं और 30 लाख वर्गमील इसका क्षेत्रफल है। आकार में यह भारत से 2½ गुना, फ्रांस से 26 गुना तथा इंग्लैंड से 25 गुना बड़ा है। किंतु सावित्र हस के आधे से कम क्षेत्र में है। प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल समान नहीं है। किंतु फिर भी उनकी क्षेत्रीय समानता को बनाये रखने का पूण प्रयास सीनेट (Senate) के माध्यम से संविधान में किया गया है।

जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का स्थान चीन, भारत तथा रूस के बाद आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड है। प्राकृतिक साधनों का ध्यान में रखते हुए यह जनसंख्या अधिक नहीं है। जनता की दशा सतोपजनक है। निम्न आर्थिक वग के लोग अ्य देशों के साधारण वग का अपेक्षा अधिक खुशहाल हैं। जापान, भारत चीन व इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका की समस्याएँ नगण्य हैं। जनता में चाहे वैदेशिक नीति की असफलता को लेकर द्वंद्व हो जाय किंतु किसी भी प्रकार की क्रांति का भय नहीं है। सम्भवत यही कारण है कि संविधान के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई।

अमेरिका भी रूस की भा
है। यहाँ विभिन्न प्रकार के घम
जाति के व्यक्ति अधिक संख्या में हैं
का भी निवास यहाँ पाया जाता है
कभी आपात पहुँचा है। श्वेत रंग वा
यात है। अमेरिका में प्रवेश पाने वाली
सांस्कृतिक परम्पराएँ लायी किन्तु भा
हुआ। अंग्रेजी भाषा की ही प्रधानता रही
किया गया। यहाँ विविध प्रकार के घम
भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण धार्मिक वि
हो सका है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि
है और वह प्रभावयुक्त भी है किन्तु जैसा कि ला
है। दबाव समूह (Pressure Groups) वहाँ
अण हैं। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व एवं संसदीय प्रणाली
अपने पक्ष का प्रभाव डालने के लिए अव्यव
समूह विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए रिश्व
तक सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में इस
500 गुट बतमान हैं जिनका यही पेशा है और जो किर
रहते हैं।

अमेरिका धनिकों का देश है किन्तु इससे यह अर्थ
गरीबी नहीं है। गरीब हैं किन्तु वे अर्थ बहुत से देशों के
हैं। शिक्षा पर अमेरिका में बहुत बल दिया जाता है और यह
होने वाले घम से आगे दूसरे नम्बर पर शिक्षा पर व्यय
संविधान पर व्यक्तिवादी विचारधारा की स्पष्ट छाप है जिसे बहु
पूर्वजों से परम्परा के रूप में लेकर आये। अमेरिकावासियों का प्र
कोण रहा है कि सरकार का अधिकार क्षेत्र सीमित होना चाहिए
में केवल निषिद्ध शक्ति ही रहनी चाहिए। शक्ति की वे उपेक्षा
की दृष्टि से देखते हैं। सम्भवतः इसी कारण स्थान स्थान पर हमें अर्थ
में शक्ति पर नियंत्रण दिखाई देता है। अमेरिकी विचारधारा पर
माटेस्व्यू की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। व्यक्ति व
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता में उनका आज भी विश्वास है। स
विषय में अमेरिकावासियों का जो दृष्टिकोण रहा है उसने उसे समाजवाद
पर पर अग्रसर होने से रोका है। किन्तु फिर भी अमेरिकी समाज के जीवन में
निर्माताओं की आशाओं के विपरीत राजकीय हस्तक्षेप बढ़ा है और आर्थिक जी
के सत्ताधन में वह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अमेरिकी समा
साम्यवादी विचारों की ध्वनि एवं गद्य मात्र से चौक उठता है। साम्यवादी दल वा
लगभग नगण्य है। साम्यवाद का विरोध अमेरिका का नैतिक वक्तव्य रहा है या
उसकी विदेश नीति का प्रमुख पहलू भी रहा है। किन्तु बतमान निवसन प्रशासन

परिवर्तन का चोंका अनुभव हो रहा है। चीन से अमेरिकी साठ गाँठ के परिवेश सामाजिक रूप से इस प्रकार की धारणा का बन जाना असम्भव नहीं है। मिक के शब्दों में, "शासक अमेरिकावासियों को इस तरीके से घेरे हुए हैं जैसी कि पूर्वजों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी।"

अमेरिकी शासन व्यवस्था जिस संविधान पर अवलम्बित है वह 1789 का है। इसके पृष्ठ में लगभग 193 वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है, वैसे संविधान इसकी अपेक्षा पुराने हैं किंतु लिखित संविधानों में यह सबसे अधिक है। यह सबसे अधिक पुराना अपरिवर्तित संविधान है। इतना कठोर संविधान तथा परिवर्तन के यपेड़े खाकर भी जीवित है, यह आश्चर्य की बात है। इससे वह श्रद्धा तथा सराहना का पात्र बन गया है। इसने न केवल नागरिक अधिकारों की तथा प्रतिशीलता को बनाये रखा है वरन् राष्ट्र की समृद्धशालीनता का विकास है। कठोर होते हुए भी शासन-पद्धति ने अपने को आवश्यकताओं के साथ है, यह कम गौरव की बात नहीं है। विकृत होकर भी अराजक एवं अत्या-न बनना संविधान की एक विशेषता रही है।" लिखित संविधान होते हुए भी राजमवादी रहा है, यह बात आश्चर्यजनक है। बंस तथा पैटसन के शब्दों में रिखा की जनवादी सरकार विगत दो शताब्दियों के विभिन्न प्रयोगों का है।

4 जुलाई, 1776 को ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश राज्यों ने उससे अपने मुक्त कराने की घोषणा कर दी थी। 1783 में ब्रिटिश संसद ने अमेरिका के उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया था। इन्हें प्रभुसत्ता सम्पन्न भी मान लिया था। 1779 तक केवल मेरीलैण्ड राज्य को छोड़कर अब उपनिवेश राज्यों ने की एक परिषद (Confederation) के रूप में संगठित कर लिया था। 1781 में मेरीलैण्ड की भी स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। परिषद के गठित होने सम्बन्ध जिस व्यवस्था को जन्म मिला वह शिथिल थी। कांग्रेस कार्यपालिका से बचित होने के कारण शिथिल एवं उपेक्षित थी। स्वतंत्रता संग्राम समाप्त पर लोगों के दिमाग में आक्रमण कम हो गया। यहाँ तक कि कुछ राज्यों ने अपने प्रतिनिधि तक भेजने बन्द कर दिये। कांग्रेस का स्तर घटकर एक परामर्श का रह गया। कांग्रेस राज्यों से सन की माँग तो कर सकती थी किंतु उसे नहीं कर सकती थी। ऋण लेकर चुकाने के लिए कांग्रेस राज्यों पर अवलम्बित शक्ति करने का अधिकार कांग्रेस का था किंतु उसके अनुसार आचरण करने का राज्यों का था। कांग्रेस के अधिकार तो बहुत व्यापक थे किंतु उसकी शक्तियाँ थीं। जैसा कि राष्ट्रपति विल्सन ने लिखा है "कांग्रेस में 'सम्मिलित' सयुक्त राज्य की। जैसा कि राष्ट्रपति विल्सन ने लिखा है। संधीय व्यवस्था में उप-मान सत्ता या कि यह सत्ताधारों का एक बार है। संधीय व्यवस्था की तीव्र राज्यों की कोई एकता प्रदान नहीं की गयी थी। संधीय व्यवस्था की मानना ऐसी थी कि उससे राज्यों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। सना के लिए बेद्व को राज्यों की रूपा पर अवलम्बित रहना पड़ता था। 76 की संधी व्यवस्था का शोचसामन बहुत ही गहरी मानने मान सगा। आदि-सन्धान उत्पन्न होने लगी। प्रत्येक राज्य अपने का एक पृथक् राष्ट्र समझता था।

बाह्य दशों से उठोने सम्पत्क स्थापित करने आरम्भ कर दिये । 9 राज्यो ने पृथक सेनाएँ संगठित की तथा कुछ राज्यो ने तो नौसेना तक का संगठन कर डाला । चारो ओर घोर असंतोष व ईर्ष्या के दशन होते थे ।

परिसंघ (Confederation) एक ताश का महल सिद्ध हुआ । गृह-युद्ध के काले वादल अमरीकी नभ मे मँडराने लगे थे । सविधान मे परिवर्तन की माँग को लेकर वातावरण मे उत्तेजना आ गयी थी । इस उत्तेजना का नेतृत्व प्रमुख रूप से तीन व्यक्तियों के द्वारा हुआ—वाशिंगटन, जेम्स मडीसन, तथा हैमिल्टन । वाशिंगटन ने आह्वान किया कि जब तक वे एक ऐसी केन्द्रीय मत्ता की स्थापना करने मे सफल नहीं हो जाते जो उतनी ही शक्तिशाली हो जितनी कि राज्यों की सरकारें तब तक देश की विनाश से नहीं बचाया जा सकता । अँग वाशिंगटन की इस समयागत माँग का इतना प्रभाव हुआ कि 1787 मे फिलाडेल्फिया के स्थान पर देश के विविध वर्गों के बौद्धिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन आमन्त्रित किया गया । इस सम्मेलन मे लगभग 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । राड द्वीप उस समय सम्मिलित नहीं हुआ था । फिलाडेल्फिया का सम्मेलन अपने मे अनुपम था । इसमे वाशिंगटन, मडीसन तथा जैफरसन के अतिरिक्त हैमिल्टन व जामिन, एडमण्ड रैल्डाल्फ, मोरिस तथा जेम्स विलसन आदि भी सम्मिलित थे । सम्भवत इतना सफल सम्मेलन कोई भी नहीं हुआ था । इस सम्मेलन ने देश की शासन व्यवस्था को ही बदल डाला । यह स्पष्ट हो गया था कि 1776 की सघीय व्यवस्था व्यर्थ एवं असफल सिद्ध हो चुकी है । सम्मेलन का सक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमे राज्यों की स्वायत्तता स्थापित रखते हुए एक शक्तिशाली केन्द्र की भी स्थापना की जा सके । यह सम्मेलन चार माह तक चला । 17 सितम्बर, 1787 को एक प्रलेख पर सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किये गये जिसके आधार पर सविधान के नये ढाँचे का रूप बना । नूतन सविधान मे एक व्यवस्था थी कि 13 मे से कम से कम 9 राज्यों के सम्मेलन पृथक् पृथक् रूप मे अपनी स्वीकृति प्रदान करें किन्तु दुर्भाग्य की बात यह रही कि उनमे से अधिकांश का उत्साह ठण्डा पड़ गया था और 1787 के अन्त तक केवल 3 राज्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की । नवीन सघीय व्यवस्था के विवाद को लेकर समस्त देश मे दो गुट बन गये—Federalists और Anti Federalists । एक दल सघीय व्यवस्था का घोर विरोधी था । दूसरा पक्ष जो सधवादी कहलाता था, यह चाहता था कि राज्यों को स्वशासी तो रखा जाय किन्तु एक शक्तिशाली केन्द्र की भी व्यवस्था रखी जाय । नये सविधान का लोगों द्वारा विरोध सम्भवत इस आधार पर भी किया गया कि उसमे अधिकार-पत्र (Bill of Rights) की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस विश्वास पर कि नये सविधान के लागू होते ही अधिकार पत्र की घोषणा कर दी जायगी, 4 मार्च, 1789 को नया सविधान लागू स्वीकार कर लिया गया । इस समय, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है अमेरिका मे 50 राज्य हैं और वहाँ के सविधान मे अब तक केवल 22 ही संशोधन सुलभ हो सके हैं । वहाँ का सविधान सदब से अमेरिका वासियों की श्रद्धा तथा सम्मान का विषय रहा है । ब्राइस (Bryce) ने शब्दों मे, “अमेरिका का सविधान समस्त बाट-छाँट के बाद भी समस्त सविधानों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी योजना अति सुन्दर है यह जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है,

यह सरल और संक्षिप्त है, इसकी भाषा शुद्ध है और इसमें सिद्धांतों की निश्चितता के साथ साथ विस्तृत विवेचना के लिए लचीलापन है।¹

अमेरिकी शासन-पद्धति का महत्व

(Importance of American Administrative System)

(1) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपनी पापकर्मवादी नीति का परित्याग कर चुका है। आज अमेरिका विश्व की दो महान् शक्तियों में से एक है। बहुत से देश ऐसा विश्वास करते हैं कि यदि साम्यवाद के प्रसार को रोकने की कोई देश जुरत कर सकता है, तो वह केवल अमेरिका ही है। आज अमेरिका की राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ से विश्व के अधिकांश देश प्रभावित रहते हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन विश्व के अनेक देशों द्वारा जितनी रुचि के साथ देखा जाता है उतना अन्य कोई स्थल नहीं। स्वाभाविक रूप से अमेरिकी संविधान का अध्ययन करने की दिशा में हमारी रुचि का विकास होता जाता है। सिडनी हेमन के शब्दों में "अमेरिकी राष्ट्रपति दृष्ट्यन्त में शक्ति उत्पादन करने वाली शक्ति है।"¹ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति मात्र रह गयी है। इससे अमेरिका की स्थिति स्पष्ट रूप से उभर कर हमारे समक्ष आ गयी है।

(2) अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे अधिक प्राचीन लिखित संविधान है। इसका अत्यधिक महत्व इस कारण भी है कि यह विश्व का प्राचीनतम तथा ऐसा संविधान है जिसमें लगभग नहीं के बराबर परिवर्तन हुए हैं। अन्य कोई ऐसा संविधान नहीं है जो इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी अप्रभावित एवं अपरिवर्तनीय रहा हो। फ्रांस की क्रांतियों ने उसके संविधान तथा शासन पद्धति को पर्याप्त रूप में परिवर्तित किया। टर्की, चीन, जापान तथा इटली में भी राजनीतिक विप्लवों ने वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को परिवर्तित किया है। ब्रिटेन में भी कई सुधार विधेयकों ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विशाल परिवर्तन किये। किन्तु अमेरिका के संविधान में इतने समय में नहीं के बराबर परिवर्तन हुए हैं। जब से अमेरिकन संविधान की संरचना हुई तब से लेकर अब तक देश का आकार तिगुना हो गया है और जनसंख्या भी 50 गुना बढ़ गयी है। आरम्भ में अमेरिका कृषि प्रधान देश था किन्तु अब वह औद्योगिक देशों का शीप है। इस औद्योगिकवाद का वहाँ के जन जीवन, विचारधारा तथा चरित्र पर व्यापक प्रभाव हुआ है। अमेरिकी गन्धता पूर्णतः शहरी बन गयी है। किन्तु इन परिवर्तनों का संविधान के स्थायित्व पर बहुत ही कम प्रभाव हुआ है।

(3) अमेरिकन संविधान के अध्ययन में हमारी जिज्ञासा इस कारण भी उद्दीप्त होती है कि अमेरिका न केवल चौथा महत्वपूर्ण लोकतन्त्रीय देश है किन्तु उसने इस परम्परागत विचार का भी खण्डन किया कि लोकतन्त्र एक छोटे देश में ही सफल हो सकता है, बड़े देश में नहीं। अमेरिका ने न केवल लोकतन्त्र को ही सफल बनाया है वरन् लोकतन्त्र को विश्व के लिए सुरक्षित बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है।

(4) अमेरिका ने शासन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण अनुदाय दिया है। सधवादी सिद्धांतों को आधुनिकता प्रदान की है। आधुनिक युग में अमेरिका ही वह प्रथम देश

है जिसने सघवाद को अपनाया और अरब देशों ने उसका अनुकरण किया है। यह सिद्धांत पहले भी शासन विज्ञान-वेत्ताओं को ज्ञात था कि तु उसे सक्रिय एवं व्यावहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय अमेरिका को है। यदि इंग्लैण्ड को संसदीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जा सकता है तो अमेरिका को भी संघात्मक व्यवस्था तथा अल्पक्षेत्रीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जा सकता है। अमेरिका को ही इस बात का श्रेय जाता है कि उसने विधि के शासन की प्रतियोगिता में 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के सिद्धांत को रखा। वह अनुदाय फ्रांस के प्रशासकीय कानून से भी कम नहीं है। भारत ने भी अमेरिका की कुछ राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण किया है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता आदि। एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हमें लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अमेरिका ही वस्तुतः विश्व का वह प्रथम देश है जिसने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का आधार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाया और जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाता था कि यह असम्भव है उसे अवरोध एवं संतुलन (Check & Balances) की प्रणाली द्वारा सफल बनाकर दिखाया। जल्दी-जल्दी परिवर्तन होना संविधान की कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है।

संवैधानिक विकास की रीतियाँ

(Process of Constitutional Development)

अमेरिका का संविधान केवल 1787 में निर्मित संविधान पर ही अवलम्बित नहीं है अपितु समय समय पर उसमें संवैधानिक संशोधन हुए हैं 'न्यायिक निर्णय' हुए हैं, प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियम बनाये गये हैं। परम्पराओं आदि ने उसके स्वरूप को निश्चित किया है, उसमें विकास किया है और भावी पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने संविधान का संक्षिप्त स्वरूप सम्भवतः इस कारण रखा कि वे इस बात में विश्वास करते थे कि उसका विकास समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार होना चाहिए। उन्होंने जान-बूझ कर संविधान को रूप रेखात्मक स्वरूप प्रदान करके ही नहीं छोड़ दिया है। बरन् विस्तार के लिए भी काफी गुंजाइश छोड़ दी है। अमेरिकी संविधान के विकास में जो तत्व सहयोगी सिद्ध हुए हैं वे इस प्रकार हैं —

(1) 'न्यायिक व्याख्याएँ' (Judicial Interpretations)—जस्टिस होम्स ने एक बार कहा था कि 'न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उन्हें ही बनाना चाहिए।' (Judges do and must legislate)। 'न्यायिक निर्णयों' का संविधान में इतना महत्व है कि बिना उनसे संविधान यदि मर नहीं जाता तो कम से कम सँभड़ा अवश्य हो जाता है। 'न्यायिक निर्णयों' के द्वारा संविधान का केवल शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई बरन् उसे व्यापकता तथा समयानुसृतता भी प्राप्त हुई है। संविधान की बहुत सी कमियों को दूर करने में 'न्यायिक निर्णयों' का विशेष महत्व है। संविधान में 'निहित शक्तियों' के सिद्धांत (Doctrine of Implied Powers) तथा 'जन्मजात शक्तियों' के सिद्धांत (Doctrine of Inherent Powers) की प्रस्तुति 'न्यायिक निर्णयों' का ही परिणाम है। संविधान में प्रयुक्त 'वाणिज्य' शब्द की लगभग 100 व्याख्याएँ समय-समय पर उच्चतम न्यायालय ने प्रदान कीं। संविधान कानून के विकास में 'न्यायिक निर्णयों' का

महत्वपूर्ण योग है। 'यायिक निणयो ने संविधान की शुष्क हड्डियों को मांस प्रदान किया है। राष्ट्रपति की शक्तियों में आशातीत वृद्धि का श्रेय उच्चतम 'यायालय को है। कांग्रेस की शक्तियों में भी विकास 'यायिक निणयो के द्वारा हुआ है। उच्चतम 'यायालय ने संविधान की सदिग्धता का उन्मूलन तथा स्थान स्थान पर नई शब्दावली का प्रयोग करके उसे नये अर्थ प्रदान करने की चेष्टा की है। 'यायिक व्याख्याओं के महत्व को स्वीकार करते हुए जस्टिस ह्यूग्स (Hughes) ने कहा था कि 'हम संविधान के अंतर्गत हैं परंतु संविधान वह है जिसे 'यायाधीश संविधान कहते हैं।'¹ मुनरो (Munro) के शब्दों में, "प्रत्येक सोमवार को सर्वोच्च 'यायालय के निणयो की घोषणा होती है, तब संविधान में परिवर्तन होता रहता है।"²

(2) प्रशासकीय निणय (Administrative Decisions)—मुनरो (Munro) ने प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियमों तथा उपनियमों को 'संविधानरूपी मुख्य तने की शाखाएँ कहा है।"³ 'यायिक निणय ही संविधान को गति एवं व्यापकता प्रदान करने में पर्याप्त नहीं होते वरन् प्रशासकीय निणयों का भी उस दिशा में अनुदाय कम सराहनीय नहीं है। ऐसे बहुत से नियमों तथा उपनियमों की रचना प्रशासकीय विभाग करते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता। दैनिक कृत्यों का निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के नियमों का निर्माण कार्यपालिका को करना पड़ता है। फ्रांस में तो इस प्रकार के नियमों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुलभ है। ब्रिटेन में भी संविधान के विकास में प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) का अनुदाय महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अमेरिका में कांग्रेस बहुत से कानूनों की केवल रूपरेखा ही तैयार करती है और उसके सम्बन्ध में शेष बातों की पूर्ति प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्पन्न की जाती है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल का उल्लेख नहीं है कि तु वाशिंगटन ने सलाहकार परिषद का रूप निर्धारित किया जो कालांतर में अमेरिका की एक स्थायी संस्था बन गयी है। आज भी यद्यपि राष्ट्रपति को अमेरिका में युद्ध घोषित करने का अधिकार नहीं है किंतु वह ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य उत्पन्न कर सकता है जिसके अंतर्गत स्वीकृति देने के अतिरिक्त कांग्रेस के पाम अर्थ कोई विकल्प नहीं रहता। इन प्रशासकीय निणयों का महत्व उसी समय होता है जबकि 'यायालय उन्हें स्वीकार करलें, इस दिशा में स्वीकृति केवल परम्परा मात्र है। इस प्रकार प्रशासकीय निणयों का अपना महत्व है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

(3) संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment)—इसमें संदेह नहीं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और वह एल्प पवत की चढ़ाई से कम नहीं है, किंतु संविधान के विकास में संवैधानिक संशोधनों का अपना महत्व है। उनके द्वारा ही संविधान समय के साथ बदल मिलान योग्य बना है। स्त्रियों के लिए मनाधिकार की व्यवस्था, सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की

1 We are under the constitution but the constitution is what the judges say it
2 One might almost say that it (constitution) undergoes some change every Monday when the supreme court lays down its decisions
3 The twigs on the branch which have sprung from the main trunk which is the Constitution

व्यवस्था, दास प्रथा का उन्मूलन, नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र आदि की व्यवस्था समय-समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों के द्वारा ही की गयी है।

(4) संवैधानिक अभिसमय (Constitutional Conventions)—विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखित है और न अनिश्चित। लिखित संविधानों में भी बहुत से अलिखित अंग पाये जाते हैं। प्रत्येक संविधान में भावी परिस्थितियों का अपा में समेट लेने की क्षमता हर लिखित संविधान में छोड़ी जाती है। ब्रिटिश संविधान में तो अभिसमयों का प्रमुख स्थान है। ब्रिटिश संविधान परम्पराओं पर आधारित संविधान है। किंतु उनका महत्व अमेरिका के संविधान में भी कम नहीं है। यह कहा जाता है कि अमेरिकन संविधान में भी उतने अभिसमय पाये जाते हैं जितने कि इंग्लैंड के संविधान में पाये जाते हैं। इस सत्य को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है

(1) अमेरिका का राष्ट्रपति तृतीय बार निर्वाचन में खड़ा नहीं होता। यह अभिसमय तब से पड़ा जब वहाँ प्रथम राष्ट्रपति जाज वाशिंगटन ने तृतीय बार निर्वाचन लड़ने से इन्कार कर दिया था। केवल राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सफ़ाई के कारण इसका खण्डन हुआ जबकि वे चौथी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। किंतु बाद में 22वें संशोधन द्वारा इसे संविधान का एक अंग बना दिया गया।

(2) यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को संविधान में अप्रत्यक्ष रखा गया है, किंतु परम्पराओं ने उसे दलीय प्रभाव से युक्त लगभग प्रत्यक्ष ही बना दिया है।

(3) अमेरिका के संविधान में किसी भी स्थल पर मंत्रिमण्डल की व्यवस्था नहीं है किंतु प्रशासकीय विभागों ने उसे परामशदात्री समिति का रूप देकर संविधान का व्यावहारिक रूप में एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है।

(4) अमेरिकी संविधान की एक परम्परा यह भी है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में जिन नियुक्तियों को करता है, उनके सम्बन्ध में वह उस राज्य के सीनेटर्स से पहले ही परामश कर लेता है। इसे सीनेटोरियल कर्टसी (Senatorial Courtesy) कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो बहुधा उनके द्वारा की गयी नियुक्तियों को सीनेट का समर्थन प्राप्त नहीं होता।

(5) संविधान में कहीं पर भी दल प्रणाली का उल्लेख नहीं है किंतु वहाँ जितने निर्वाचन होते हैं वे सब दल प्रणाली के आधार पर होते हैं।

(6) प्रथा के कारण ही अमेरिकन राष्ट्रपति प्रत्येक सप्ताह प्रेस प्रतिनिधियों से भेंट करता है।

(7) संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य उसी क्षेत्र के रहने वाले हों जहाँ से वे अमुक प्रतिनिधि निर्वाचन में खड़ा होता है। यह अनिवार्यता केवल परम्परागत है।

(8) अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वित्त विधेयक प्रतिनिधि मंडल में ही प्रस्तावित होना चाहिए, यह आवश्यकता केवल परम्परागत है।

(9) संचालन समिति, प्लोर लीडर तथा काकस (Cacus) का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। वे सब भी परम्परागत हैं।

(10) यह केवल परम्परागत है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में राष्ट्र की स्थिति पर अपना स देश प्रस्तुत करता है। शासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रपति कांग्रेस से यह अनुरोध करता है कि उसकी नीतियों को सफल बनाने के लिए वह आवश्यक कानूनों का निर्माण करे।

(11) संविधान कहीं पर भी इस बात का निषेध नहीं करता कि राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशनों को सम्बोधित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ऐसा किया करते थे। किन्तु उसके बाद से यह परम्परा सी बन गयी है कि अब राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशनों को सम्बोधित नहीं करता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में भी परम्पराओं का समावेश है जो उसके अतिरिक्त भाग भी हैं। इंग्लैण्ड के संविधान में तो इनका विशिष्ट महत्व है। संविधान ही परम्पराओं पर अवलम्बित है। अमेरिका में परम्पराओं का इतना व्यापक महत्व नहीं है जितना कि इंग्लैण्ड में। इंग्लैण्ड में कानून तोड़ने पर तो सक्षिप्त दण्ड मिलता है किन्तु परम्पराओं को तोड़ने से अनमत्त उबल पड़ता है तथा सरकार के अस्तित्व के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अभिसमयों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक बार जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि 'सरकार के वास्तविक चरित्र का निश्चय करने में समय एवं स्वभाव कम से कम उतना ही आवश्यक है जितना कि मानव सत्ताओं के लिए।'¹ मुनरो (Munro) के शब्दों में, "इस प्रकार लिखित संविधान के ऊपर एक पिरामिड के समान अमेरिका में राजनीतिक परम्पराओं तथा रीति रिवाजों की स्थापना की गयी है जिनका आधार न तो कानूनों में और न ही यायिक निणयों में पाया जाता है किन्तु वे दीर्घायु की बातों का परिणाम हैं।" ड्रूमन ने '*Politics and Government of United States*' के पृष्ठ 109 पर रीति रिवाजों तथा संवैधानिक अनुदाय के विषय में कहा है कि, 'अमेरिका की शासन प्रणाली तथा संविधान में विकास और परिवर्तन केवल सशोधनों, यायिक निणयों तथा व्यवस्थापन निर्माण द्वारा तो नहीं हुआ है। अनेक महत्वपूर्ण नियम प्रशासकीय प्रथाओं द्वारा बने हैं और इतने लम्बे समय तक उनका पालन किया जाता रहा है कि उन्होंने प्रशासन के अभिसमयों का रूप धारण कर लिया है।'

अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ

(Salient Features of the American Constitution)

(1) लिखित तथा संक्षिप्त संविधान (Written and Brief Constitution)—सम्भवतः लिखित संविधानों में अमेरिका का संविधान सबसे अधिक पुराना संविधान है। किन्तु साथ में यह विश्व का सबसे अधिक संक्षिप्त संविधान भी है। इसमें अंतर्गत केवल 7 अनुच्छेद हैं और 25 संशोधन हैं। ये संशोधन 181 वर्षों में हुए हैं। अमेरिकी संविधान को आध धष्टे में पढ़ा जा सकता है। संविधान में केवल

1 Time and Habit are at least as necessary to the true character of government as of other human institutions

शासकीय संगठन की महत्वपूर्ण बातों का रूपरेखात्मक रूप से विवरण प्रस्तुत किया गया है। शेष बातें व्यवहार तथा भविष्य के लिए छोड़ दी गयी हैं। इतने बड़े देश का इतना छोटा संविधान अजीब सी बात है। इसका बहुत कुछ सम्बन्ध अमेरिकी चरित्र चिन्ताधारा तथा भौतिकवादी प्रवृत्ति से है। इसकी तुलना में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 400 पृष्ठ हैं। हर बात को विस्तारपूर्वक ढंग से कहा गया है। मोवियन रूप के संविधान में केवल 146 अनुच्छेद हैं। आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 धाराएँ हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। चीन के संविधान में 106 तथा इटली के संविधान में 157 अनुच्छेद हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे अधिक छोटा संविधान है। अमेरिकी संविधान के संक्षिप्त स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ब्रोगन (Brogan) ने कहा है कि 'अमेरिकी संविधान केवल एक ठोका मात्र है जिसे राजनीतिक दलों के विकास, परम्पराओं, राष्ट्रीय आयातों तथा आर्थिक विकास ने जीवन प्रदान किया है। अमेरिकी संविधान की संक्षिप्तता के कई प्रभाव हुए हैं

- (1) कानून तथा परम्पराएँ दोनों ही संवैधानिक ढाँचे का निर्माण करती हैं।
- (2) संविधान कई बातों की व्यवस्था के बारे में मौन है।
- (3) संविधान का महत्व बढ़ गया है संविधान की संक्षिप्तता के ही कारण निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास हुआ है। संक्षिप्तता के कारण ही अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में लूट खसोट की प्रणाली का उदय हुआ है।
- (4) संविधान की संक्षिप्तता का एक प्रभाव यह हुआ है कि उसने द्वारा संविधान में स्थायित्व की वृद्धि हुई है और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ है।

निर्मित संविधान (Enacted Constitution)—विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्णतः विकसित है और न पूर्णतः निर्मित। दोनों ही प्रकार के तत्त्व प्रत्येक संविधान में पाये जाते हैं निर्मित संविधान वस्तुतः वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हुआ हो और विकसित प्रकार के संविधान आवश्यकता एवं परम्पराओं के आधार पर बनते हैं, उनके निर्माण के लिए किसी विशेष परिपक्व अवस्था सभा के संगठन की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका का संविधान यो तो निर्मित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है किन्तु उसमें भी विकासशील तत्त्व कम नहीं हैं। इसके विपरीत, ब्रिटेन के संविधान में विकासशीलता का तत्त्व बहुत अधिक है। वह परम्पराओं एवं आवश्यकताओं के सहारे अनायास रूप में आगे बढ़ा है अमेरिकी संविधान निर्मित होते हुए भी विकासशील तत्वों से युक्त है।

(3) कठोर संविधान (Rigid Constitution)—अमेरिका का संविधान स्वभाव से कठोर अथवा अनम्य है, कठोर संविधान वे संविधान होते हैं, जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष आयोजन एवं प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संविधान में अनम्यता की मात्रा एक ही हो, यह आवश्यक नहीं है कठोरता की

मात्रा में अंतर रह सकता है, भारत का संविधान लिखित एवं कठोर होते हुए भी इतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना हिमालय की चढ़ाई चढ़ने के समान है, यही कारण है कि 180 वर्ष के पश्चात् भी संविधान में केवल 25 संशोधन सफल हो सके हैं, किंतु कुछ संविधानवादी तो अमेरिकी संविधान को नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकार का मानते हैं और उनका ऐसा विश्वास है कि स्वस्थ संविधान में नम्यता तथा अनम्यता दोनों का ही योग होना चाहिए और यह गुण अमेरिकी संविधान में मौजूद है। आग तथा रे के शब्दों में, "वस्तुतः अब हमारे पास संविधान है, कल दूसरा होगा और परसा अन्य संविधान होगा, कोई भी संविधान किसी समय में नागरिकों, विधि निर्माताओं प्रशासकों तथा 'यायाधीशों की देन है यह उस विचार की अवस्था में है जो विचार के साथ बदला जा सकता है, हम लोग निश्चित रूप से सुगमतापूर्वक अपने विचार में परिवर्तन लाते हैं।"¹

अमेरिका में संशोधन करने वाले तथा व्यवस्थापन करने वाले निकायों में काफी अंतर है, यह अंतर ब्रिटेन में नहीं है, वहाँ पर व्यवस्थापन तथा संशोधन एक ही निकाय कर लेता है, अमेरिका में संशोधन करने की पद्धति बहुत जटिल है, सी० एफ० स्ट्रॉंग के मतानुसार "अमेरिका का संविधान संसार भर में सबसे अधिक अनम्य एवं दुष्परिवर्तनशील है। इस अनम्यता का मूल कारण इसका सघीय रूप है।" 6 जुलाई, 1965 के बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।

संशोधन की प्रक्रिया (Process of Amendment)

अमेरिकी संविधान की धारा 5 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अमेरिकी संविधान में संशोधन दो प्रकार से हो सकता है

(1) कांग्रेस के द्वारा—संविधान में संशोधन कांग्रेस स्वयं ही कर सकती है, इसके लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में स्वीकृति के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव केवल उसी दिशा में बंध माना जायगा जबकि उसे 3/4 राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, यह स्वीकृति राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ प्रदान करती हैं।

(2) राज्यों के द्वारा—अमेरिकी संविधान सभ की इकाइयों (राज्यों) को भी संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में यह अधिकार सभ की इकाइयों को प्राप्त नहीं है। सभ की 3/4 व्यवस्थापिकाएँ कांग्रेस से संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव कर सकती है। कांग्रेस इस आशय का प्रस्ताव आने पर राज्यों का एक सम्मेलन आमंत्रित करती है यदि राज्यों के इस प्रकार के आमंत्रित किये हुए सम्मेलन में 3/4 सदस्य उसकी पुष्टि कर देते हैं तो वह बंध मान लिया जाता है।

¹ For actual Constitution at any given time is what citizens and law makers administrators and judges think it is it is in a sense a state of mind and can be changed by Changing our mind Certainly we change our mind with remarkable facility

सशोधन सम्बन्धी कुछ जटिल प्रश्न (Some Complicated Questions regarding the Process of Amendment)

अमेरिकी संविधान में अंकित सशोधन प्रक्रिया अस्पष्ट है और उसमें कई प्रकार की शकाओं का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है, सशोधन विषयक निम्न लिखित जटिलताएँ हमारे समक्ष आती हैं

(1) बहुमत सम्बन्धी—संविधान में केवल इतना कहा गया है कि सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा $\frac{2}{3}$ बहुमत से स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु इससे दोनो ही अर्थ लगाए जा सकते हैं—कांग्रेस की कुल संख्या का दो तिहाई बहुमत अथवा कांग्रेस में प्रस्ताव पारित होते समय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत किंतु इस अस्पष्टता का निवारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने *Missouri P R Co Vs Kan* (1919) के प्रसिद्ध विवाद में यह निर्णय दिया था कि $\frac{2}{3}$ बहुमत का अभिप्राय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत से है।

(2) अनुसमर्थन सम्बन्धी—सशोधन प्रक्रिया से सम्बंधित एक और जटिल प्रश्न यह है कि यदि राज्य विधान मण्डल ने किसी प्रस्ताव का अनुसमर्थन कर दिया है तो क्या बाद में उसे इस अनुसमर्थन करने का अधिकार है अथवा नहीं? उच्चतम न्यायालय ने *Coleman Vs Miller* (1939) के विवाद में इस जटिलता का निराकरण किया था कि राज्य अपने द्वारा प्रदत्त स्वीकृति को वापिस लेने का अधिकारी नहीं है, किंतु ऐसा राज्य बाद में भी स्वीकृति एवं अपना अनुसमर्थन प्रेषित कर सकता है जिससे पहले इन्कार कर दिया हो।

(3) सीमावधि सम्बन्धी—इस विषय में एक और जटिल प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वीकृति न देकर चुप्पी साध सकता है? 1789 तथा 1810 के सशोधनों के सम्बन्ध में यही हुआ, ये प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये गये थे किंतु उनके ऊपर अनुसमर्थन नहीं मिला, राज्य चुप्पी साधे रहे। उच्चतम न्यायालय ने इस कठिनाई के सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि जिन प्रस्तावों को राज्यों का $\frac{2}{3}$ बहुमत प्राप्त नहीं होता वे संविधान के अंग नहीं बन सकते, किंतु इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रकार के सशोधन के सम्बन्ध में स्वीकृति की सीमा 7 वर्ष निश्चित कर दी गई है, जो प्रस्ताव इस अवधि में अनुसमर्थन हेतु $\frac{2}{3}$ राज्यों की व्यवस्थापिकाओं का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे रद्द समझे जायेंगे।

(4) निषेधाधिकार सम्बन्धी—संविधान में सशोधन सम्बन्धी एक और अस्पष्टता की ओर हमारा ध्यान जाता है। वह यह है कि क्या राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को वीटो (Veto) करने का अधिकार है? इसी प्रकार क्या राज्य के गवर्नर को राजकीय व्यवस्थापिका द्वारा सशोधन विषयक अनुसमर्थन प्रस्ताव वीटो करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय ने इस दिशा में स्पष्ट करते हुए यह बताया कि सशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों को वीटो करने का अधिकार न राष्ट्रपति को है और न राज्य के गवर्नर को।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Amending Process)

(1) यह असोक्तसम्प्रीय है (It is undemocratic)—संविधान के विषय में जो संशोधन प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनमें प्रत्येक में एक नूतन प्रश्न छिपा रहता है। राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को उस दिशा में कोई आदेश मिला हुआ नहीं रहता। वे अपने मनमाने ढंग से अनुसमर्थन देते तथा मना करते हैं, जनता से कोई आदेश प्राप्त नहीं करते, इस प्रकार वे आशय का एक सम्मेलन 21वें संशोधन के समय तो आमन्त्रित किया गया था जिसके माध्यम से जनता की राय जानी गई थी किन्तु 22वें संशोधन पर फिर पुरानी परिपाटी को ही अपनाया गया। आलोचकों के अनुसार इस प्रकार संशोधन की प्रक्रिया को वास्तविक तथा लोक-सम्प्रीय नहीं माना जा सकता।

(2) बहुमत की उपेक्षा (Disregard of Majority)—अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया की एक दुर्बलता यह है कि इस व्यवस्था में राज्यों के बहुमत पर अधिक बल दिया गया है तथा मताधिकारियों के बहुमत की उपेक्षा की गयी है। अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं जिसका $\frac{2}{3}$ बहुमत होता है 38 राज्य। इसका अर्थ यह हुआ कि 13 राज्य संशोधन प्रस्ताव का यदि विरोध करते हैं तो उनका पक्ष सबल माना जायगा जबकि 37 राज्यों की स्वीकृति का महत्व नहीं है। यह न केवल लोकतन्त्र में बहुमत के सिद्धांत का हनन है बल्कि किसी भी न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता।

(3) अत्यधिक जटिलता (Excessive Rigidity)—लिखित संविधान में दुष्परिवर्तनशीलता की अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता किन्तु उसका आवश्यकता से अधिक होना संस्था के हित के लिए घातक है, अमेरिकी संविधान की कठोरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 180 वर्ष बाद भी केवल 25 संशोधन सफल हो सके हैं। संविधान का इस सीमा तक कठोर होना भी समाज के लिए हानिकारक है।

(4) अनुसमर्थन की विधि का अभाव (Absence of the Law of Ratification)—अमेरिकी संविधान में संशोधन की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत अनुसमर्थन सम्बन्धी किसी विधि का निर्धारण नहीं किया गया है। सम्भवतः यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय को 18, 20 तथा 21वें संशोधन के लिए अनुसमर्थन की सीमा निर्दिष्ट करनी पड़ी। जब संशोधन के लिए अनुसमर्थन की सीमा निर्धारित नहीं की जाती तो उसका उद्देश्य तथा आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 1924 में वास्तव्य विषयक जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया था उस पर अभी तक केवल 28 राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अमेरिकी संघ के एक राज्य ओहियो (Ohio) ने लगभग 80 वर्ष पश्चात् एक संशोधन प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। दसवें संशोधन को 1791 में प्रस्तावित किया गया था। उसे $\frac{3}{4}$ राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु शेष $\frac{1}{4}$ राज्यों में से कनेक्टिकट, ड्योरजिया तथा मेसाच्यूसेट्स राज्यों ने 1939 तक अपना समर्थन दिया।

अमेरिकी संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए कई बार प्रयत्न किये गये हैं किन्तु अभी तक उसमें पूर्णरूप से सुधार करना सम्भव नहीं

सशोधन सम्बन्धी कुछ जटिल प्रश्न (Some Complicated Questions regarding the Process of Amendment)

अमेरिकी संविधान में अंकित सशोधन प्रक्रिया अस्पष्ट है और उसमें कई प्रकार की शकाओं का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है, सशोधन विषयक निम्न लिखित जटिलताएँ हमारे समक्ष आती हैं

(1) बहुमत सम्बन्धी—संविधान में केवल इतना कहा गया है कि सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा $\frac{2}{3}$ बहुमत से स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु इससे दोनों ही अर्थ लगाये जा सकते हैं—कांग्रेस की कुल सख्या का दो तिहाई बहुमत अथवा कांग्रेस में प्रस्ताव पारित होत समय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत किंतु इस अस्पष्टता का निवारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने *Missouri P R Co Vs Kan* (1919) के प्रसिद्ध विवाद में यह निणय दिया था कि $\frac{2}{3}$ बहुमत का अभिप्राय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत से है।

(2) अनुसमयन सम्बन्धी—सशोधन प्रक्रिया से सम्बन्धित एक और जटिल प्रश्न यह है कि यदि राज्य विधान मण्डल ने किसी प्रस्ताव का अनुसमयन कर दिया है तो क्या बाद में उसे इस अनुसमयन करने का अधिकार है अथवा नहीं? उच्चतम न्यायालय ने *Coleman Vs Miller* (1939) के विवाद में इस जटिलता का निराकरण किया था कि राज्य अपने द्वारा प्रदत्त स्वीकृति को वापिस लेने का अधिकारी नहीं है, किंतु ऐसा राज्य बाद में भी स्वीकृति एवं अपना अनुसमयन प्रेषित कर सकता है जिससे पहले इ बार कर दिया हो।

(3) सीमावधि सम्बन्धी—इस विषय में एक और जटिल प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वीकृति न देकर चुप्पी साध सकता है? 1789 तथा 1810 के सशोधनों के सम्बन्ध में यही हुआ वे प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये गये थे, किंतु उनके ऊपर अनुसमयन नहीं मिला, राज्य चुप्पी साधे रहे। उच्चतम न्यायालय ने इस कठिनाई के सम्बन्ध में अपना निणय देते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि जिन प्रस्तावों को राज्यों का $\frac{2}{3}$ बहुमत प्राप्त नहीं होता वे संविधान के अंग नहीं बन सकते, किंतु इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रकार के सशोधन के सम्बन्ध में स्वीकृति की सीमा 7 वर्ष निश्चित कर दी गई है जो प्रस्ताव इस अवधि में अनुसमयन हेतु $\frac{2}{3}$ राज्यों की व्यवस्थापिकाओं का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे रद्द समझे जायेंगे।

(4) निषेधाधिकार सम्बन्धी—संविधान में सशोधन सम्बन्धी एक ओर अस्पष्टता की ओर हमारा ध्यान जाता है। वह यह है कि क्या राष्ट्रपति का कांग्रेस द्वारा स्वीकृत सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को वीटो (Veto) करने का अधिकार है? इसी प्रकार क्या राज्य व गवर्नर को राजकीय व्यवस्थापिका द्वारा सशोधन विषयक अनुसमयन प्रस्ताव वीटो करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय ने इस दिशा में स्पष्ट करत हुए यह बताया कि सशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों को वीटो करने का अधिकार न राष्ट्रपति को है और न राज्य के गवर्नर को।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Amending Process)

(1) यह अत्यंत त्रयी है (It is undemocratic)—संविधान के विषय में जो संशोधन प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनमें प्रत्येक में एक नूतन प्रश्न छिपा रहता है। राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को उस दिशा में कोई आदेश मिला हुआ नहीं रहता। वे अपने मनमाने ढंग से अनुसमर्थन देते तथा मना करते हैं, जनता से कोई आदेश प्राप्त नहीं करते, इस प्रकार के आशय का एक सम्मेलन 21वें संशोधन के समय तो आमन्त्रित किया गया था जिसके माध्यम से जनता की राय जानी गई थी किन्तु 22वें संशोधन पर फिर पुरानी परिपाटी को ही अपनाया गया। आलोचकों के अनुसार इस प्रकार संशोधन की प्रक्रिया को वास्तविक तथा लोक-तन्त्रीय नहीं माना जा सकता।

(2) बहुमत की उपेक्षा (Disregard of Majority)—अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया की एक दुर्बलता यह है कि इस व्यवस्था में राज्यों के बहुमत पर अधिक बल दिया गया है तथा अताधिकारियों के बहुमत की उपेक्षा की गयी है। अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं जिसका $\frac{2}{3}$ बहुमत होता है 38 राज्य। इसका अर्थ यह हुआ कि 13 राज्य संशोधन प्रस्ताव का यदि विरोध करते हैं तो उनका पक्ष सबल माना जायगा जबकि 37 राज्यों की स्वीकृति का महत्त्व नहीं है। यह न केवल लोकतन्त्र में बहुमत के सिद्धांत का हनन है बल्कि किसी भी 'यायिक दृष्टि' से उचित नहीं माना जा सकता।

(3) अत्यधिक जटिलता (Excessive Rigidity)—लिखित संविधान में दुष्परिवर्तनशीलता की अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता किन्तु उसका आवश्यकता से अधिक होना संस्था के हित के लिए घातक है, अमेरिकी संविधान की कठोरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 180 वर्ष बाद भी केवल 25 संशोधन सफल हो सके हैं। संविधान का इस सीमा तक कठोर होना भी समाज के लिए हानिकारक है।

(4) अनुसमर्थन की विधि का अभाव (Absence of the Law of Ratification)—अमेरिकी संविधान में संशोधन की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत अनुसमर्थन सम्बन्धी किसी विधि का निर्धारण नहीं किया गया है। सम्भवतः यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय को 18, 20 तथा 21वें संशोधन के लिए अनुसमर्थन की सीमा निश्चित करनी पड़ी। जब संशोधन के लिए अनुसमर्थन की सीमा निर्धारित नहीं की जाती तो उसका उद्देश्य तथा आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 1924 में बाल श्रम विषयक जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया था उस पर अभी तक केवल 28 राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अमेरिकी संघ के एक राज्य ओहियो (Ohio) ने लगभग 80 वर्ष पश्चात् एक संशोधन प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। दसवें संशोधन को 1791 में प्रस्तावित किया गया था। उसे $\frac{3}{4}$ राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु शेष $\frac{1}{4}$ राज्यों में से कनेक्टिकट, ज्योरजिया तथा मेसाच्यूसेट्स राज्यों ने 1939 तक अपना समर्थन दिया।

अमेरिकी संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए कई बार प्रयत्न किये गये हैं किन्तु अभी तक उसमें पूर्णरूप से सुधार करना सम्भव नहीं

हो सभा है। इसी कारण सभी सभी यह सुचारु दिया जाता है कि सशोधन प्रस्ताव की वापस द्वारा स्वीकृति हो काफी है तथा उससे पश्चात् राज्यों के 2/3 विधान मण्डलों की स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव बड़ा सुन्दर था किन्तु अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

(5) संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) — अमेरिकी संविधान की एक विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान को समस्त शक्तियों का स्रोत कहा गया है। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। वायपालिका को इससे बढ माना गया है। किसी राज्य के संविधान में कोई ऐसी बात न हो और न जोड़ी जा सकती है जो मूल संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार की किसी भी वायवाही को उसी सीमा तक अथवा माना जायगा।

(6) अध्यक्षीय सरकार की स्थापना (Establishment of Federal Form of Govt) — अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत वायपालिका विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी न होकर उसके समकक्ष होती है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष ध्वजमात्र नहीं होता। उसकी शक्ति वास्तविक होती है। उसका वायकाल निश्चित होता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति का वायकाल 4 वर्ष निश्चित है और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास तथा निंदा प्रस्तावों का उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता। राष्ट्रपति अपने सचिवों की सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। इस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षीय पद्धति की शासन-व्यवस्था स्थापित की गयी है। इसका आधार भी शक्तियों का पृथक्करण है।

(7) गणतन्त्र की स्थापना (Establishment of Republic) — अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष का पद पलुन नहीं रखा गया है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन का पद रखा गया है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यों में गणतन्त्रात्मक शासन के संरक्षण का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर रखा गया है।

(8) अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Indirect Democracy) — अमेरिकी संविधान के निर्माता अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र को इतने बड़े दश के लिए श्रेयकर मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने के द्वाय शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र का ही समावेश रखा तथा राज्य सरकारों के स्तर पर प्रस्तावाधिकार (Initiative) जनमत संग्रह (Referendum) तथा प्रत्याह्वान (Recall) की पद्धति की स्वीकृति दी।

(9) अधिकार पत्र (Bill of Rights) — 1779 के संवैधानिक प्रारूप में अधिकार पत्र का कोई स्थान नहीं था। राज्यों के विरोध करने पर संघवादियों ने इसे कांग्रेस की स्थापना होते ही संविधान में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया, तभी इन्हें 1791 में दस संशोधनों के रूप में संविधान का अंग बनाया गया। इन्हीं संशोधनों को सामूहिक रूप में अधिकार पत्र कहा जाता है। ये संशोधन इस प्रकार हैं

1 पहले संशोधन के द्वारा नागरिकों को धर्म भाषण प्रेस, एकत्रित होने

- आदि के सम्बन्ध में अपने कष्टों को निवारणार्थ याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया ।
- 2 दूसरे संशोधन से अमेरिकावासियों को शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया गया ।
- 3 शान्तिकाल में मकान मालिक की अनुमति बिना सैनिक कायबाही के लिए कोई भवन नहीं लिया जा सकता, यहाँ तक कि युद्धावधि में भी मालिक की अनुमति बिना सैनिकों को किसी मकान में नहीं ठहराया जा सकता ।
- 4 चौथे संशोधन के द्वारा घरों में सामान तथा कागजों के सम्बन्ध में तलाशी लेने तथा जब्त करने के विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनता को सुरक्षा प्रदान की गयी ।
- 5 पाँचवें संशोधन के द्वारा नागरिकों को जीवन सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में व्यापक सुरक्षाएँ प्रदान की गईं या Habeus Corpus Acts की व्यवस्था की गई तथा सम्पत्ति लेने पर उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की गई ।
- 6 छठवें संशोधन के द्वारा अपराधियों के लिए शीघ्र याच तथा जूरी (Jury) की व्यवस्था की गयी ।
- 7 सातवें संशोधन के द्वारा नागरिकों को 20 डालर से अधिक धनराशि वाले मामलों में जूरी प्रथा के प्रयोग को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी ।
- 8 जनता को न तो आवश्यकता से अधिक जुर्माना देना पड़ेगा और न अधिक जमानत ही देनी पड़ेगी । साथ ही निम्न एवं असाधारण दण्ड भी प्रदान नहीं किया जायगा ।
- 9 नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि नवीन अधिकार पत्र की घोषणा का यह आशय कदापि नहीं है कि उन्हें उनके वर्तमान अधिकारों के उपयोग से वंचित कर दिया जायगा ।
- 10 संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख न तो वे 'द्र के पक्ष में किया गया है और न राज्यों के पक्ष में ही किया गया है, वे सब शक्तियाँ राज्य सरकारों को ही प्राप्त होंगी । इस प्रकार अमेरिका के नागरिकों को व सब मौलिक अधिकार दिये गये हैं जो अन्य सभ्य देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं ।

(8) शक्तियों का पृथक्करण—अवरोध एवं संतुलन की प्रणाली (Separation of Powers (Checks and Balances)—18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी लेखक माटेस्व्यू के शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का यदि कहीं व्यावहारिक रूप हमें देखने को मिलता है तो वह है अमेरिका । लोक तथा माटेस्व्यू अमेरिकी संविधान की आत्मा में जाग उठे हैं । जेम्स मेडीसन ने एक बार कहा था कि 'हम निरंतर माटेस्व्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा लेते रहे हैं ।' प्रो० ऑग तथा जिक के अनुसार "अमेरिकी सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय सरकारें सम्मिलित हैं अन्य कोई विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ।

इसके साथ सन्तुलन एवं अवरोह की व्यवस्था सावधानी से सम्मिलित की गई है।" अमेरिका के संविधान-निर्माताओं में मेडिसन का नाम उल्लेखनीय है। उनका यह मत था कि एक ही व्यक्ति के हाथों में सरकार की तीनों शक्तियों को एकत्रित करना 'याय का गला घोटना' है। उही के शब्दों में, "विधानपालिका, कार्यपालिका तथा 'यायपालिका की सभी शक्तियों का एक ही हाथों में केन्द्रीयकरण करना अत्याचार की परिभाषा है, चाहे वह एक व्यक्ति हो, बड़े हो, या अधिक, धनानुगत हों, स्वतन्त्र नियुक्त हो अथवा निर्वाचित हों।" अमेरिकी उपनिवेशों के निवासी पहले से ही संक्षेप में इस सिद्धान्त तथा 'यायिक पुनरीक्षण से परिचित थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार की समस्त शक्तियाँ विधान मण्डल में केन्द्रित हो गई थीं जिससे लोगों के मन में विविध प्रकार की शकाएँ उठने लगी थी। 1787 में फ़िलाडेल्फिया सम्मेलन के समय भी लोगों को यह बात ध्यान में रही और संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा पूरा प्रयास किया कि शक्तियों का केन्द्रीयकरण एक व्यक्ति के हाथों में न हो सके। लिप्सन ने ठीक ही कहा है कि "अमेरिकी संविधान के निर्माण में इतिहास तथा दक्षन दोनों मिल गये हैं।"¹

अमेरिका के संविधान में सरकार की तीनों शक्तियों को पृथक्-पृथक् रखा गया है। क्लिबबोन तथा थॉम्पसन के प्रसिद्ध मुकदमे में उच्चतम 'यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह मुख्य गुण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा केन्द्र से सम्बंधित जो शक्तियाँ सरकार को दी गई हैं वे तीन विशाल भागों में बँटी हुई हैं—कार्यपालिका, विधानपालिका, तथा 'यायपालिका। मेसाच्यूसेट्स के संविधान में भी शक्तियों के पृथक्करण की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है। अमेरिकी संविधान की धारा 1 के अनुसार व्यवस्थापिका शक्ति कांग्रेस में केन्द्रित की गई है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और धारा 3 के अनुसार 'यायिक शक्ति का एकमात्र आगार उच्चतम 'यायालय को माना गया है। वर्जीनिया राज्य के संविधान में थॉमस जैफ़रसन ने लिखा था, 'एक ही हाथों में इन तीनों शक्तियों को एकत्रित करना निरंकुश शासन की परिभाषा है।" डॉ॰ हरमैन फ़ाइनर (H. Finer) का भी ऐसा ही विश्वास है कि अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण का विवेकपूर्ण तथा वृहत् प्रयास है। यह संविधान इस सिद्धान्त पर चलने वाला विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है।²

अमेरिकी पद्धति अवरोह एवं सन्तुलन
के सिद्धान्त पर अवलम्बित है।

(The American Constitution is based upon the
System of Checks and Balances)

अमेरिकी संविधान ने निर्माता यह भरी भोति जानते थे कि शासन के सुचारु रूप से संचालन के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त अपने निरपेक्ष रूप

1 "History therefore joined hands with Philosophy in writing a separation of powers into the federal Constitution —Lipson *The Great Issues of Politics* p. 280.

2 "Today it is the most important Policy Document in the world which operates upon that principle

में पर्याप्त नहीं है। जब तक कि सरकार के तीनों अंगों में परस्पर ताल मेल नहीं होगा, वे एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं होंगे और उस समय तक शासन में काय-कुशलता भी उत्पन्न नहीं की जा सकती। जेम्स मेडीसन (Madison) ने जो स्वयं अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक थे, स्वयं अपने समाचार-पत्र *Federalist* में एक स्थल पर यह स्वीकार किया था कि "शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का लक्ष्य यह कदापि नहीं है कि विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई भी सम्बन्ध ही न रहे। जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से सम्बद्ध न किये जायेंगे और इस तरीके से न मिला दिये जायेंगे कि एक का नियन्त्रण दूसरे पर स्थापित हो जाय, तब तक स्वतन्त्र सरकार की स्थापना कदापि सम्भव नहीं हो सकती।" शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अधिनायकतन्त्र के विरुद्ध सबसे बड़ी सुरक्षा है। किन्तु वह सरकार के विविध अंगों में उत्पन्न होने वाली निरपेक्षता तथा स्वेच्छाचारी व्यवहार को रोकने में असमर्थ है। इस सम्भावित दुर्गुण के प्रति भी अमेरिकी संविधान के जन्मजात सजग थे और उन्होंने इसके दोषों से मुक्त होने के लिए जिस सिद्धांत को जन्म दिया वह है सन्तुलन एवं अवरोह की प्रणाली (System of Checks & Balances)। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि सरकार के तीनों अंगों को इस प्रकार से संगठित किया जाय कि एक अंग की शक्तियाँ दूसरे अंग की शक्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करके दोनों के मध्य सन्तुलन स्थापित कर सकें और कोई भी अंग निरपेक्ष एवं स्वेच्छाचारी न बन सके। यह सिद्धांत भी कोई नया नहीं है बल्कि अरस्तू के समय से ही चला आ रहा है। पौलीबीयस तथा सिसरो ने इसका प्रतिपादन किया था। यह अमेरिकी संविधान में किस प्रकार सफलतापूर्वक काय करता है, यह हम सरलता से देख सकते हैं।

(क) कांग्रेस (विधान भण्डल) की शक्तियाँ किस प्रकार कार्यपालिका (राष्ट्रपति) की शक्तियों से नियन्त्रित होती हैं (How does the powers of the executive constitute a check on the powers of the Congress)—

(1) राष्ट्रपति को निषेधाधिकार (Veto) का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकते जब तक कि उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाती।

(2) यद्यपि राष्ट्रपति कांग्रेस की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता किन्तु वह 'संदेश' भेज सकता है जिस पर कांग्रेस को अग्य कार्य छोड़कर तुरन्त विचार करना पड़ता है।

(3) संविधान की दृष्टि से संधि करने तथा युद्ध घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को उसी समय है जबकि उसने विधान भण्डल की स्वीकृति प्राप्त करली हो किन्तु राष्ट्रपति ऐसी अवस्था अवश्य ही उत्पन्न कर सकता है जिसके अन्तर्गत उसकी इच्छा स्वीकार करने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही न रहे।

(4) राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। उससे पूर्व उसे नहीं हटाया जा सकता। उसे हटाने का एक ही तरीका है, महाभियोग की कार्यवाही, जो आज तक सफल नहीं हुई।

(5) वार्षिक बजट की वयारी राष्ट्रपति के निरीक्षण में सम्पन्न होती है।

(6) कांग्रेस के दोनों सदन में किसी विषय पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति को उतने समय तक उनकी कार्यवाहियों को स्थगित करने का अधिकार है जितने समय के लिए वह उचित समझे।

(7) राष्ट्रपति कांग्रेस के असाधारण अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। 1948 में राष्ट्रपति ट्रूमन ने उन सदस्य सदस्यों को वापस बुला भेजा जो मुश्किल से घर के द्वार तक ही पहुँच पाये होते।

(8) राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रकाशित करने का अधिकार है जिनका वस्तुतः वही मूल्य होता है जो विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून का।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र प्रत्येक रहते हुए भी उसे इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है कि वह कांग्रेस को स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश बनने से रोक सके।

(घ) राष्ट्रपति (कार्यपालिका) की शक्तियों पर नियन्त्रण (Check on the Powers of the President)—(1) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। सीनेट के अस्वीकार करने पर नियुक्तियाँ अवैध घोषित कर दी जाती हैं।

(2) राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है। पुष्टिकरण न होने की स्थिति में राष्ट्रपति संधि नहीं कर सकता। इसी कारण 1920 में राष्ट्रपति अमेरिका को राष्ट्र संधि का सदस्य नहीं बना सके। यही कारण है कि राष्ट्रपति सीनेट की वदेशिक सम्बन्ध समिति से निरंतर सम्बन्ध बनाये रखता है।

(3) राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से उसके पद से प्रत्येक किया जा सकता है।

(4) राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्थापन के क्षेत्र में जो वीटो का अधिकार प्राप्त है वह भी विफल बनाया जा सकता है, यदि वीटो किया हुआ विधेयक पुनः 2/3 के बहुमत से कांग्रेस स्वीकार कर ले।

(5) राष्ट्रपति तथा विधान मण्डल द्वारा किसी भी विधेयक को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है।

(6) राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल से पूर्व विधान मण्डल को भंग नहीं कर सकता।

(7) सीनेट को बहुत से प्रशासकीय कार्यों के सम्बन्ध में अपनी जाच-पड़ताल समिति (Investigation Committee) द्वारा जाँच कराने का अधिकार है।

(8) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर सकता है किंतु उन्हें हटा नहीं सकता।

(ग) न्यायपालिका की शक्तियों पर नियन्त्रण (Checks on the Powers of the Supreme Court)—अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। यह कहा जाता है कि संविधान वही है जो कि न्यायाधीश चाहते हैं। न्यायाधीश कार्यपालिका के अधीन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। संविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व भी उसी

के ऊपर है। संविधान के विकास में उच्चतम न्यायालय का विशेष महत्व है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय एक अधिनायक है। उसकी शक्ति पर भी कई प्रकार के नियंत्रण हैं।

(i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।

(ii) कांग्रेस महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से पथक कर सकती है।

(iii) कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते आदि घटा बढ़ा सकती है।

(iv) कांग्रेस क्षेत्रीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है।

(v) यदि सुप्रीम कोर्ट कोई अनुचित नियम दे देती है तो कांग्रेस उसमें संशोधन करने उसे उचित घोषित कर सकती है। 1857 में ड्रेडस्कॉट (Dredscot) के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को, कि यदि कोई दास दक्षिण से भागकर उत्तरी अमेरिका में आ जाता है तो उससे उसकी दासता का अंत नहीं होता, परिवर्तित करके तैरहूँ तथा पढ़हूँ संशोधन के द्वारा दासता को सम्पूर्ण अमेरिका में अवैध घोषित कर दिया था।

इस प्रकार अवरोध एवं संतुलन की प्रणाली शक्ति पृथक्करण से कुछ अधिक हितकारी होते हुए पूर्णरूप से संतुलन उत्पन्न करने में तथा राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधों को उत्पन्न करने में अधिक सफल सिद्ध नहीं हो सकी है। अब भी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में गतिरोध खूब देखने को मिलते हैं। सकटकालीन अवस्था एवं अवधि में कांग्रेस कुछ खामोशी अस्तित्व रख कर लेती है किंतु उसके समाप्त होते ही वह रण लाना शुरू कर देती है। 1943 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बहुत से प्रस्तावों को रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ने विरोधाधिकार (Veto) का प्रयोग किया तो उसे 2/3 बहुमत से रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति तथा कांग्रेस यदि दो भिन्न भिन्न दलों से सम्बन्धित हैं तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। राष्ट्रपति आइजनहावर को भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ी। वर्तमान राष्ट्रपति निक्सन रिपब्लिकन हैं और कांग्रेस में डेमोक्रेटिक दल का जोर है। इसी कारण दोनों में विदेशी आर्थिक सहायता के प्रश्न पर मतभेद नहीं हो पाता। राष्ट्रपति स्वयं सदन के समक्ष अपने को प्रस्तुत करके अपने दृष्टिकोण को लोकमत के प्रतिनिधियों के समक्ष नहीं रख सकता। इसी प्रकार बजट के सम्बन्ध में वह अपने दृष्टिकोण को समझाने में असफल रहता है। 1892 में Field Vs Clark के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह नियम दिया था कि कांग्रेस अपनी विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को नहीं दे सकती है। 1933 में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति की जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया था उन्हें उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। 1935 में भी उच्चतम न्यायालय ने National Industrial Act को केवल इस कारण से अवैध घोषित कर डाला क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को वैधानिक शक्तियाँ दे डाली हैं। किंतु अब पिछले कई वर्षों में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में कुछ नरमी आयी है और उसने प्रदत्त-व्यवस्थापन की परिपाटी को उचित मानना स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक दलों ने भी बहुत कुछ सीमा तक कार्यपालिका तथा विधान मण्डल की पारस्परिक कटुता को धोने में सहयोग दिया है।

(9) 'यायपालिका की सर्वोच्चता (Supremacy of the Judiciary)—सघात्मक व्यवस्था के अनुरूप यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका में भी रखी गयी है। उच्चतम यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। 1801 के प्रसिद्ध विवाद मारबरी बनाम मेडीसन में चीफ जस्टिस जान माशल ने कहा था कि संविधान सर्वोच्च कानून है और यदि उसके विरुद्ध विधानमण्डल द्वारा कोई कानून बनता है तो वह अवध घोषित कर दिया जायगा। इससे यायपालिका की सर्वोच्चता दृष्टिगत होती है।

(10) संविधान में महत्वपूर्ण बातों का लोप (Notable Omissions in the Constitutions)—अमेरिका के संविधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का लोप है कि सामान्यतः अन्य सभी संविधानों में पायी जाती हैं

(क) प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं है।

(ख) दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में भी उसके निवारण के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(ग) सघीय कर्मचारियों को उनके पद से किस प्रकार मुक्त किया जाय, इस प्रक्रिया का भी संविस्तार वर्णन नहीं है।

(घ) बैंक निगम, शिक्षा राजनैतिक दल, वज्रट, कृषि श्रम तथा उद्योग आदि महत्वपूर्ण विषयों का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। किंतु इन लोपों के विषय में खेद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस की व्यापक शक्तियों ने इनकी पूर्ति कर दी है। मुनरो के शब्दों में 'यदि संविधान में इस लचीली व्यवस्था का प्रबंध न होता तो गत 50 वर्षों में इसमें संशोधनों का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो जाता।'।

सघात्मक व्यवस्था की स्थापना (American Federal System)

डाइसी (Dicey) के अनुसार, 'सघात्मक राज्य एक राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राजकीय सरकारों में समन्वय उत्पन्न करना है। हैमिल्टन (Hamilton) के शब्दों में "सघात्मक शासन राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नये राज्य का निर्माण करता है।' 1787 के पूर्व अमेरिका एक परिसंघ था जिसमें प्रत्येक राज्य अपनी सावभौमिकता से लैस था। यह राज्यों का शिविल संघ था। किंतु इसके बाद बड़ा सघात्मक सरकार की स्थापना की गयी, राज्यों को अपनी संप्रभुता का परित्याग करना पड़ा, केन्द्रीय सरकार का आविर्भाव हुआ और ये संप्रभुताहीन राज्य संघ की इकाइयों के रूप में बने रहे। इस प्रकार अमेरिका में सघात्मक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया गया है। सघात्मक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ अमेरिकी संघ में पायी जाती हैं शक्तियों का वितरण (Division of Powers)

सघात्मक व्यवस्था में सरकारों के दो समूह होते हैं—केन्द्र तथा राज्य सरकारें। इन दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। अमेरिका में भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की शक्तियों का समर्पण केन्द्र सरकार को किया गया है तथा स्थानीय महत्व की शक्तियाँ राज्य

सरकारों को समर्पित की गई हैं। इस वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन शक्तियों का उल्लेख इन दोनों अनुसूचियों में नहीं किया गया है, वे शेष समस्त शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के उपभाग 8 के अंतर्गत उन शक्तियों का उल्लेख किया गया है जो केंद्र को प्राप्त हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं—(1) नगर लगाने तथा इनको प्राप्त करने का अधिकार, (2) ऋण चुकाने की शक्ति, (3) देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था, (4) विदेशों से व्यापार का नियमन, (5) अमेरिकी साख (Credit) पर ऋण लेना, (6) मुद्रा निर्माण, (7) माप तथा तोल के स्तर का निर्धारण (8) सेना की स्थापना एवं उसकी व्यवस्था, (9) जल सेना की स्थापना, (10) विदेशी मुद्रा के साथ अमेरिकी मुद्रा के मूल्य का अनुपात निश्चित करना, (11) नकली मुद्रा के लिए दण्ड की व्यवस्था, (12) समुद्री डाकूआ के विरुद्ध व्यवस्थापन का निर्माण (13) विज्ञान तथा कला की उन्नति, (14) उच्चतम न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों की स्थापना (15) अमेरिका के सामाजिक कल्याण के लिए विधि निर्माण करना (16) विदेश नीति एवं संधियाँ, (17) नये राज्यों को संध में सम्मिलित करना, (18) अमेरिका में विद्रोह आदि को दबाने के लिए मिलिशिया की रचना करना। इन समस्त विषयों के सम्बन्ध में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। इनमें राजकीय अधिकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

अमेरिका के संविधान में केवल सघीय सरकार की शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है राज्य सरकारों की शक्तियों का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। अतएव जिन शक्तियों का उल्लेख सघीय सरकार की शक्तियों में नहीं किया गया है, वे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं। मूनरो (Munro) के अनुसार, राज्यों को जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं—(1) स्थानीय करों की व्यवस्था (2) स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना, (3) राज्य की साख पर ऋण लेना, (4) शिक्षा की व्यवस्था, (5) अनुदान तथा दान, (6) सड़कें तथा यातायात, (7) निगमों की स्थापना (8) दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण, (9) सम्पत्ति एवं जीवन की सुरक्षा, (10) जन स्वास्थ्य तथा नतिक जीवन की सुरक्षा, (11) सघीय संविधान के सशोधन का अनुसमर्थन, (12) राजकीय संविधानों में सशोधन करना, (13) निर्वाचनों का संचालन।

शक्तियाँ जो राज्यों के प्रयोग के लिए नहीं हैं (Powers denied to the States)

(1) अमेरिकी संध के राज्यों को विदेशों से सम्पर्क एवं समझौता करने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य राजनीतिक प्रकार का समझौता केंद्र की अनुमति के बिना विदेशों से नहीं कर सकता। अभी तक केवल एक समझौता यूयाक राज्य ने एक पुल के सम्बन्ध में कनाडा से किया है। राज्य पारस्परिक विवादों का निपटारा करने के लिए समझौता कर सकते हैं।

(2) प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के अधीन है। अतः राज्यों को सेना खड़ी करने तथा किसी विदेशी राज्य के विपरीत युद्ध घोषित करने का अधिकार नहीं है। आतंक विद्रोह को दबाने के लिए राज्य मिलिशिया का गठन कर सकता है। यदि अमेरिकी संध के किसी राज्य पर आक्रमण हुआ हो और तुरंत

सहायता मिलने की आशा न हो तो वह उसी राज्य से युद्ध की घोषणा कर सकता है।

(3) कांग्रेस को ही अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन करने का अधिकार है। अंतर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकार बहुत सीमित हैं। इस दिशा में उनकी स्वतंत्रता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है।

(4) बिना कांग्रेस की अनुमति के राज्यों को निर्यात तथा आयात कर (Export & Import duties) लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। माल ले जाने वाले जहाजों पर भी राज्य कर नहीं लगा सकते।

(5) राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगा सकते जिससे केन्द्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।

(6) राज्य स्थित किसी भी केन्द्रीय सम्पत्ति पर राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है।

(7) राज्यों को नोट छापने तथा मुद्रा बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। अपने ऋणों को चुकाने में सोने तथा चांदी के सिक्के के अतिरिक्त अन्य किसी धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करेंगे।

(8) राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे अनुबंधों के पालन करने में कठिनाई उत्पन्न हो।

(9) अमेरिकी संघ के राज्यों को चौदहवें संशोधन का अभिप्राय ऐसे कानून बनाने का विचार करने से है जिससे नागरिकों की उन्मुक्तियाँ कम हो जाती हैं।

संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)

अमेरिकी संविधान की धारा 6 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। जो भी कानून संविधान के किसी भी नियम के विरुद्ध हो वह अवध माना जायगा।

(1) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)—उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था प्रत्येक संघ में पाई जाती है। भारत, रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सभी देशों की इसमें आस्था है। अमेरिकी संघ इन सबसे पुराना है। उच्चतम न्यायालय ही संविधान का संरक्षक है। उसकी सर्वोच्चता बनाये रखना, न्यायालय का कर्तव्य है। केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों, एवं राज्यों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है।

(2) दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)—संविधान के अनुच्छेद 4 के भाग 2 में स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता की चर्चा की गई है। प्रत्येक व्यक्ति केन्द्र का नागरिक होने के साथ ही अपने राज्य का भी नागरिक है जहाँ का वह निवासी है। दोनों ही भागों में उसे विशेष प्रकार की उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं।

(3) द्विसदनात्मक विधान मण्डल (Bicameral Legislature)—अमेरिका में विधानमण्डल की द्विसदनात्मक व्यवस्था है। छोटे एवं सौजन्य सदन को प्रतिनिधि सदन (House of Representative) तथा बरिष्ठ सदन को सीनेट (Senate) कहा जाता है। पहले सदन के गठन का आधार है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, बरिष्ठ

सदन का प्रयोग प्रादेशिक अखण्डता के लिये किया गया है। प्रत्येक छोटे-बड़े राज्य को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(4) राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता अनुल्लङ्घनीय है (Inviolability of the Territorial Integrity of the States)—अमेरिकी संध में प्रादेशिक अखण्डता को सुदृढ़ रूप में बनाये रखा गया है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 के भाग 3 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कांग्रेस नये राज्यों की स्वीकृति तो दे सकती है किंतु किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में नये राज्य की रचना स्वीकार नहीं कर सकती। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।

(5) राज्यों के निजी संविधान (States have their own Constitutions)—अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। संघीय संविधान में राज्यों के संविधान सम्मिलित नहीं हैं। संघीय संविधान में केवल संध सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं। संविधान में केवल इस बात का ध्यान किया गया है कि उन्हीं सीमाओं में प्रत्येक राज्य को अपने संविधान की रचना करनी चाहिए। केवल दो प्रतिबंध लगाये गये हैं—प्रथम, राज्यों के संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं होगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार के नियमों अथवा दायित्वों की अवहेलना होती हो। द्वितीय, यह है कि किसी भी राज्य को अपनी शासन व्यवस्था में गणतन्त्रीय स्वरूप को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने का अधिकार राज्य के विधान मण्डल अथवा उस राज्य की जनता को दिया गया है।

(6) राज्यपाल का निर्वाचन (Election of the Governor)—अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न होता है, परंतु भारत में वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। राजकीय विधान मण्डल उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर, उसे उसके पद से पृथक् कर सकता है।

संध की इकाइयाँ (Units of the Federation)—प्रारम्भ में अमेरिकी संध में केवल 13 राज्य थे किंतु अब 50 राज्य हैं। वे इस प्रकार हैं—अलाबामा, अलास्का, एरीजोना, आरनेसस कैलीफोर्निया, कोलोरेडो, कोनेक्टिकट, डेलीवेयर, फ्लोरिडा, जार्जिया, हवाई, इडाहो, इलीनॉय, इण्डियाना, इयोवा, कैन्सस, केन्टकी, लुईसियाना, मेन, मेरीलैण्ड, मैसाचुसैट्स, मिशिगन, मिनीसोटा, मिसि मिन्सोरी, मोन्टाना, नवरास्का, नेवदा, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क स्टेट, नॉर्थ कैरोलीना, नॉर्थ डकोटा, ओहियो, ओक्लाहोमा, ओरेगोन, पेनीसिलवेनिया, रहोड आईलैण्ड, दक्षिणी कैरोलीना, दक्षिणी डकोटा टेन्सी टक्सास, उताह, वरमोंट, वर्जीनिया, वाशिंगटन पश्चिमी वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, व्योमिंग। इनमें 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का का राज्य सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 586,400 वर्गमील है और सबसे कम क्षेत्रफल रहोड आईलैण्ड का है जो कि 1,214 वर्गमील है। किंतु सीनेट में सबको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

संध में नये राज्यों के प्रवेश की विधि (Method of Admission of New States in the Federation)

नये राज्य संध में प्रवेश कांग्रेस की अनुमति के उपरांत ही प्राप्त कर

हैं। इसके लिए प्रवेश के प्रत्याशी राज्य को कांग्रेस के पास एक आवेदन पत्र प्रेषित करना पड़ता है। यह याचिका राज्य के विधान मण्डल द्वारा भेजी जाती है। यदि कांग्रेस उस याचिका को स्वीकार कर लेती है तो उसे योग्य अधिनियम (Enabling Act) पारित करना पड़ता है। तत्पश्चात् उस राज्य के विधान मण्डल को संविधान बनाने के लिए प्रतिनिधि चुनने तथा सम्मेलन आमंत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। उस राज्य के मतदाताओं द्वारा उस संविधान को स्वीकार कर लेने के पश्चात् उसे केन्द्र सरकार के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है। कांग्रेस को अधिकार है कि वह संविधान को स्वीकार कर ले, अस्वीकार कर दे अथवा अपने कुछ संशोधनों सहित वापस भेज दे और यह प्रतिबद्ध लगा दे कि जब तक वे संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तब तक राज्य को प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यदि प्रवेश प्राप्त करने का प्रत्याशी राज्य इन सब बातों की पूर्ति कर देता है तो कांग्रेस के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा उस राज्य के प्रवेश को स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान की धारा 4 के भाग 3 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

राष्ट्रीय सरकार की सर्वोच्चता तथा इसकी शक्तियों के बढ़ने के कारण

(Supremacy of the National Government and the Causes of the Growth of its Powers)

राष्ट्रीय सरकार के भी राज्य सरकारों के प्रति अपने दायित्व हैं। राष्ट्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखे। किसी भी राज्य के क्षेत्र में ऐसे विस्फोटक तत्वों को शक्तिशाली नहीं बनने दे, जिससे कि उस राज्य में एक नये राज्य की सृष्टि हो। इसके अतिरिक्त संघ सरकार का यह भी कर्तव्य है कि राज्यों की सुरक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाये रखे। यदि संघ के किसी राज्य पर आक्रमण होता है तो संघ सरकार उसकी रक्षा के तुरन्त सैनिक कार्रवाही करने का अधिकार रखती है। वह उस राज्य की सरकार से विचार विमर्श आदि करने के लिए बद्ध नहीं है। यदि किसी राज्य में कोई आन्तरिक संघर्ष या झगडा होता है और उस राज्य का गवर्नर यदि केन्द्रीय सहायता के लिए माँग करता है तो वह उसे तुरन्त उपलब्ध की जाती है। वस्तुतः संघ सरकार यही प्रयास करती है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य के आन्तरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाय। किन्तु यदि संघ के किसी राज्य में आन्तरिक स्थिति विस्फोटक हो गई हो और राष्ट्रीय सम्पत्ति, नीति तथा सम्मान एवं दायित्वों को खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रीय सरकार उस राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है। 1959 में जनरल आइज़न हावर ने आरकेंस राज्य के लिटिल रोक (Little Rock) में सेना भेजी थी। 1962 में राष्ट्रपति कर्नेडी ने मिसिसिपी राज्य के ऑक्सफोर्ड में सेना भेजी थी और इसी प्रकार 1963 में अलबामा राज्य के टस्कलूसा में सेना भेजी थी। इन राज्यों में हिंसाओं को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में प्रवेश मिलने के कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी और यह भय उत्पन्न हो चला था कि कहीं गृहयुद्ध न हो जाय।

अमेरिका में संविधान के द्वारा राष्ट्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने का ध्येय कभी नहीं था। किंतु गृहयुद्ध व पश्चात राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। बीसवीं शताब्दी में तो कमाल ही हो गया है। संघीय सरकार के सशक्त होने से केन्द्र तथा संघ की इकाइयों के सम्बन्धों में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय सरकार की शक्तियाँ जिन कारणों से बढ़ी हैं वे इस प्रकार हैं—

(1) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन (Social & Economic Changes)—पहले अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था। सम्पूर्ण देश में छोट छोट गाँव थे और वे भी एक दूसरे से दूर दूर थे। लोगों की आवश्यकताएँ कम थी जो प्रायः राज्य के प्रयत्नों से पूर्ण हो जाती थी। किंतु बाद में अमेरिका औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ा। धीरे धीरे जनता गाँवों से हटकर नगरों की ओर आने लगी। नगरों का विकास तेजी से हुआ। जनता का ध्यान कृषि की अपेक्षा उद्योगों पर अधिक गया क्योंकि मशीनों की सहायता से उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। समाज में पूँजीपति वर्ग का उदय हुआ। लोगों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई, अमेरिका का प्रसार हुआ। अमेरिकी संघ में राज्य बढ़े और कुछ राज्यों को खरीदा भी गया। समाज दिन-प्रतिदिन जटिल होता गया। अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होने से अपनी कठिनाइयों एवं सुरक्षा के लिए राज्य संघ शासन की ओर देखने लगा। लोगों की निर्भरता राष्ट्रीय सरकार पर दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।

(2) अतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत तथा उच्चतम न्यायालय के नियम (Implied Powers and Decisions of Supreme Court)—अँग तथा रे के अनुसार “निहित शक्तियों को एक बलशाली तुलायंत्र मानकर, राष्ट्रीय नियंत्रण कानून द्वारा सदैव चढ़ती हुई ऊँचाई तक पहुँचाया गया है।” संविधान में हर बात को खोलकर नहीं कहा गया है। जहाँ पर सन्देह की जरा सी भी गुंजाइश होती है वहाँ सहायता के रूप में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या आ जाती है। उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार से की कि उससे कांग्रेस तथा राष्ट्रपति की शक्तियों में विकास हुआ। इन्हीं को निहित शक्तियाँ (Implied Powers) कहा जाता है। विल्सन का यह कहना सही है कि जब भी उच्चतम न्यायालय एक नया नियम देता है तो एक प्रकार से नये संविधान का जन्म होता है। मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने 1819 ईस्वी में मैकलान बनाम मेरीलैण्ड नामक प्रसिद्ध विवाद में निहित शक्ति के सिद्धांत का व्यापक प्रतिपादन किया था। जस्टिस ह्यूज (Hughes) ने कहा था कि “हम संविधान के अधीन हैं किंतु संविधान वह है जिस न्यायाधीश संविधान कहते हैं।” हैमिल्टन तथा उसके समर्थकों का ऐसा विश्वास था कि जिन शक्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता वे सब कांग्रेस के पास हैं। निहित शक्तियों के सिद्धांत से भी सरकार की शक्तियों का विकास हुआ है। निगम, बैंक, कृषि सैनिक तथा अन्य सावजनिक निर्माण के क्षेत्रों में केन्द्रीय शक्ति का विकास हुआ है।

(3) गृह युद्ध (Civil War)—1861 से लेकर 1865 तक हथियारों की मुक्ति को लेकर गृहयुद्ध हुआ। इसमें मुक्ति का समर्थन करने वाले उत्तरी राज्यों की विजय हुई। दक्षिणी राज्यों की पराजय हुई किंतु उन राज्यों ने संघ को नहीं

छोड़ा। इससे राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों का विकास हुआ। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि सघ की सत्ता निश्चित एवं दृढ़ है।

(4) मताधिकार का विस्तार (Extension Franchise)—1868 में चौदहवें संशोधन द्वारा सभी नागरिकों को एक समान कानूनी सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया था। पंद्रहवें संशोधन (1870) के द्वारा नागरिकों के रंग जाति आदि भेदों को मताधिकार का आधार के रूप में अस्वीकार किया गया। 1920 में 19वें संशोधन से सभी स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। इसी कारण जनता का राज्यों की अपेक्षा कांग्रेस पर अधिक विश्वास जम गया।

(5) आय कर लगाने की शक्ति (Power to Levy Income Tax)—1913 से पूर्व कांग्रेस को आय कर लगाने की अनुमति नहीं थी। इसी वर्ष सोलहवें संशोधन द्वारा कांग्रेस को आय कर लगाने की अनुमति दे दी गई। इससे उसकी शक्तियों में विकास हुआ। 1964 में चौबीसवें संशोधन द्वारा राज्यों की निर्वाचन कर (Poll Tax) लगाने की अनुमति समाप्त कर दी गई। इसमें राज्यों की शक्ति क्षीण होती चली गई।

(6) राज्यों को अनुदान (Grants in aid to the States)—केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। यह अनुदान केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ शर्तों पर देती है। कांग्रेस यह चाहती है कि धन जिस कार्य के लिए दिया जाय वह उसी पर व्यय होना चाहिए। उस अनुदान को अब किसी विषय पर राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं किया जाय। राज्यों को केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदान के बराबर धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। राष्ट्रीय सरकार राज्य में एक ऐसे अभिकरण की स्थापना करती है जो वहाँ पर चलने वाले समस्त विकास कार्यों पर नियंत्रण रख सके, परीक्षण कर सके तथा केंद्र को उनके विषय में सूचित करती रहे। राष्ट्रीय सरकार योजनाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अपने हाथ में ही रखती है। उनके सम्बन्ध में 'यूनितम स्तर की स्थापना करती है। निर्धारित परिणामों के निरीक्षण का अधिकार अपने पास रखती है। आँग तथा रे के शब्दों में "जिन कार्यों के लिए राष्ट्रीय सरकार आर्थिक सहायता देती है उनमें राज्य राष्ट्रीय सरकार के एक प्रकार से छोटे प्रदेश ही हैं।"¹

(7) आर्थिक संकट तथा युद्ध (Wars & Economic Depression)—आर्थिक संकट तथा युद्ध के समय सम्पूर्ण राष्ट्र केंद्र की ओर देखता है। अमेरिका दो विश्व युद्धों में से होकर गुजरा। भोषण आर्थिक संकटों का उसे सामना करना पड़ा। प्रथम युद्ध के समय विल्सन ने नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने देश को नई दिशा तथा प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। आर्थिक संकट के समय राज्यों को केंद्र के सहयोग तथा भागदशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सघ शासन की शक्तियों से शासन के अधिकार बरस बढ़ जाते हैं।

¹ The states are to day for those programmes involving national financing largely administrative sub divisions of the national Government

(8) अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation)—संघ की शक्तियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था क्षीण हो गयी थी। मध्यपूर्व तथा दक्षिणी एशिया में एक वैकुंठ पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में अमेरिका की शक्ति का ऊपर उभर कर आना अस्वाभाविक नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में अवतरित हुए और दोनों के बीच शीत युद्ध के कारण बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए जाकि सुलभ नहीं पाये। अमेरिका पश्चिमी गुट का तथा रूस पूर्वी गुट का नेता बना। दोनों गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के काम में रत हैं। संसार में ये अपने-अपने प्रभाव को दृढ़ बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अमेरिका भी अपनी सैनिक शक्ति बनाये रखने के फेर में है।

(9) वैज्ञानिक खोजें (Scientific Discoveries)—अंतरिक्ष पर विजय तथा अणु शक्ति एवं आयुधों के निर्माण ने मानवीय समाज के सम्बन्धों में एक नया विश्वास तथा एक नये लक्ष्य को इंगित किया है। अंतरिक्ष खोज पर जो धन व्यय होता है उसे एकत्रित करने के लिए राज्य सरकारें सोच भी नहीं सकती। इसमें राष्ट्रीय सरकार ही सक्षम है। इन खोजों से स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

(10) राजनीतिक दल—अमेरिका में प्रमुख रूप से दो ही राजनीतिक दल हैं। उन्होंने ही केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों को सभाल रखा है। राजनीतिक दलों की स्थिति से ही राष्ट्रीय सरकार की स्थिति दृढ़ बनी है।

यद्यपि राष्ट्रीय सरकार को शक्तियाँ मर्यापित विकास हुआ है और उत्तरोत्तर होता जा रहा है किंतु उससे राज्यों का पृथक् व्यक्तित्व अप्रभावित रहा है। उनकी सत्ता का पृथक् रूप आज भी बना हुआ है। यह रूप उस समय तक बना रहेगा जब तक अमेरिकी सत्ता का वर्तमान रूप बना रहेगा। राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप की अभिवृद्धि के साथ-साथ राज्यों की शक्तियों में आशातीत विकास हुआ है। राष्ट्रीय सरकार के क्षेत्र के विकास के साथ-साथ राज्यों की सरकारों का क्षेत्र भी व्यापक बना है। राज्यों का अब भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता उपलब्ध है। अमेरिकी सरकार का रुख अब केन्द्रीकरण की ओर है। राष्ट्रीय सरकार की शक्तियाँ अब उतनी सीमित नहीं रही हैं जिसका अनुमान संविधान निर्माताओं ने किया था। राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों को अधिक से अधिक सीमित करने का प्रयत्न किया गया था। राज्य सरकारों की अपनी स्वायत्तता के विषय में उत्सुकता तथा केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में सन्तुष्टता की प्रवृत्ति ने एक अशक्तिशाली केन्द्र की संरचना की थी। किंतु आज राष्ट्रीय सरकार का अकल्पनीय अतिक्रमण राज्य सरकारों के क्षेत्र में हुआ है। संघीय सरकार का स्वरूप वस्तुतः राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप बन गया है।

वस्तुतः धन के विषय में आज राज्य केन्द्र पर इनने निर्भर हैं कि शक्तियाँ के पथकरण का अब कोई महत्व ही नहीं रहा है। ज्यों-ज्यों केन्द्र की सहायता का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है राज्य अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोत जा रहे हैं। सियोनाइ ने केंद्रीय नियंत्रण की इस अभिवृद्धि के विषय में कहा है कि 'जहाँ धन होता है

वहाँ शक्ति होती है और जहाँ इतने अधिक परिमाण में धन है वहाँ शक्ति भी बहुत अधिक होनी चाहिए। वित्तीय निर्भरता इस प्रकार की भी हो सकती है कि शक्ति का संवैधानिक विभाजन ही समाप्त हो जाय"।¹

राष्ट्रीय शक्तियों में जिस गति से विकास होता जा रहा है उसके विषय में लियोनाड ने कहा है कि 'भविष्य की चौथाई शताब्दी में राज्य केवल खोखले बन जायेंगे और मुख्यतः वे संघीय विभागों में ग्रामीण जिला के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने भरण-पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर करेंगे'।²

राज्य सरकारें अब केवल विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी संस्था मात्र ही रह गई हैं। रूसी एवं चीनी साम्यवाद के प्रसार का भय आज भी ह्वाइट हाउस प्रशासकों की नींद हराया कर चुका है। लियोनाड के शब्दों में, 'रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस है जो हमें केन्द्र की ओर धकेल रहा है'।³

किंतु उपर्युक्त विवरण से हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि राज्यों की स्वायत्तता का अध्याय समाप्त हो चुका है। मूनरो (Munro) के शब्दों में, "राज्य अब भी वे घुरी हैं जिनके आस पास अमेरिका का सम्पूर्ण राजनीतिक चक्र घूमता है"।⁴

Select References

- K C Wheare *Federal Govt*
 A W MacMohan *Federalism Mature and Emergent*
 Munro *Govt of U S A*
 E S Corwin *The Doctrine of Judicial Review*
 Brogan *The American Political System*
 Clark J P *The Rise of New Federalism*
 Garner *The Govt of U S A*
 Haskin *The American Govt To day*
 Ogg & Ray *Introduction to American Govt*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1 अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है ?

What is the process of Amendment in the constitution of USA

- 1 Where there is money there is power and where there is money on this scale there is substantial power. There can be a type of fiscal dependence which can erase the constitutional division of power —Leonard
- 2 In another quarter century the states may be left hollow shells operating primarily as field districts of federal departments and dependent upon the federal treasury for support —Leonard
- 3 The most obvious giant pushing us towards the centre is the Russian bear —Leonard
- 4 The states are still the Pivots around which the whole American Political System revolves —Munro

- 2 "अमेरिकी संविधान अवरोध एवं सन्तुलन (Checks and Balances) की पद्धति पर अवलम्बित है।" व्याख्या कीजिए।
- 3 अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 'अवरोध एवं सन्तुलन' के सिद्धांत का इस पर क्या प्रभाव है?

Analyse the main features of the American federal system and show how far they have been modified by the principle of checks and balances?

- 4 स्विटजरलैंड के संघ शासन की अमेरिकी संघ शासन से तुलना कीजिए और उनका भेद समझाइये।

Compare and contrast Swiss with the American federation

2

अमेरिकी कार्यपालिका

(राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल)

[American Executive]

(President, Vice President & Cabinet)

"President, has become the greatest ruler of the world"

—Ogg

"There is no foreign institution with which, in any basic sense it can be compared because basically there is no foreign institution"

—Lasky

राष्ट्रपति देश का संवैधानिक तथा वास्तविक अध्यक्ष है। उसके व्यक्तित्व में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के पद का अदभुत सामंजस्य है। इसका कारण वहाँ की शासन प्रणाली का स्वरूप है। यह कहना भी असत्य नहीं होगा कि ब्रिटेन के राजपद का सीमित एवं सशोषित स्वरूप ही राष्ट्रपति है। सास्की ने इसे विश्व के अधिशासी पदों में सबसे अधिक जटिल पद बताया है। प्रो० आग तथा रे (Prof Ogg and Ray) का यह परीक्षण है कि विश्व के तानाशाहों को छोड़कर अब कोई भी पद इतना अधिकार सम्पन्न नहीं है। ब्राइस (Bryce) के अनुसार यह विश्व का सबसे उच्चतम सर्वोच्च पद है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्नों से आसीन हो सकता है। संविधान के विकास के साथ साथ ही राष्ट्रपति पद का भी विकास हुआ है। वह ममस्त सघीय अधिकारों का केंद्र बन गया है। व्यक्तित्व के साथ साथ ही राष्ट्रपति के पद में भी परिवर्तन हुआ है। जहाँ कहीं भी संविधान की जा अभिवृद्धि हुई है वह उसी क्षमता का परिणाम है। ब्रोगन (Brogan) के शब्दों में राष्ट्रपति आज जनता का साक्षात् प्रतिरूप बन गया है (The Majesty of the People incarnate)।

आज राष्ट्रपति वह है जिसकी कल्पना सम्भवतः संविधान के निर्माता भी नहीं कर सके थे। संविधान के प्रमुखवेत्ताओं में इस प्रश्न को लेकर बौद्धिक संघर्ष हुआ कि संघ का राष्ट्रपति किसे बनाया जाय। जितने व्यक्ति थे उतने ही भिन्न भिन्न विचार थे। कोई भी सब सम्मति अथवा बहुसंमत विचार नहीं था। कुछ लोग राजाओं की वंश परम्परा को अपनाकर एकत्रीय शक्तिसम्पन्न शासन की स्थापना करना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने निरंकुश शासन के भय से तथा केंद्र में वापस की शक्ति दुबल होने के कारण प्रशासनाधिकारों की शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। इधर जनता भी इस बात से अनिच्छा थी कि राज्या के गवर्नर किमती स निणय

करते थे और कांग्रेस अपनी कायविधि में कितनी सुस्त थी। उन्होंने कायपालिका शक्ति का समपण एक ही व्यक्ति के हाथों में समर्पित करने का सुझाव भी दिया यद्यपि संविधान निर्माता एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति समपण के दुष्परिमाणों से भी परिचित थे किंतु फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति की एवम पद्धति का मांग प्रशस्त किया। इसीलिए संविधान में ही यह जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति को सभी प्रशासन-धिकार प्राप्त होंगे। यही कारण है कि कायपालिका के एकल स्वरूप को स्वीकार किया गया है।

अर्नेस्ट एस० ग्रिफिथ (E S Griffith) ने राष्ट्रपति के पद को अमेरिकी शासन की समस्त संस्थाओं में सबसे अधिक नाटकीय पद बताया है। (Most dramatic of all the institutions of American Government) मक्स वैलाफ के शब्दों में, "अमेरिका के राष्ट्रपति की यह अद्वितीय स्थिति इसीलिए है क्योंकि वह एक साथ ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी है और सरकार की शक्तियों का संचालन करता भी जोकि लोकतन्त्रात्मक संविधानों में एक विचित्र और असाधारण मिश्रण है। ऐसा मिश्रण संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त सत्तार के केवल उन्हीं देशों में मिलता है जो अमेरिकी आदर्श को अपनाते हैं।" सिडनी हेमन (Sidney Hayman) ने अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति पर गहन दृष्टि से विचार करते हुए कहा है कि "अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता तथा उसके महत्त्व में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और आज वह सघीय सत्ता का केन्द्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।"¹

कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तथा प्रशासकीय परिस्थितियों ने राष्ट्रपति के महत्त्व को इस सीमा तक बढ़ा दिया है कि वह केवल मुख्य प्रशासक ही नहीं अपितु मुख्य विधिवेत्ता भी बन गया है। शक्तियों का पृथक्करण होते हुए भी उसकी स्थिति सर्वोपरि है। राष्ट्रपति के विचार तथा उसकी गतिविधियों के प्रति आज विश्व जितना सजग तथा उत्सुक है उतना सम्भवतः कभी नहीं रहा।

डॉ० हर्मान फाइनर (Herman Finer) ने राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पद की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं—

(1) कृत्रिम किंतु विकसित कायपालिका—इसमें अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत ब्रिटेन की भांति परम्पराओं में नहीं है बरन संविधान है। संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका की स्थिति तथा निहित शक्तियों के सिद्धांत ने उसके स्वरूप में व्यापक रूप से परिवर्तन किया है।

(2) एकल कायपालिका (Singular Executive)—इसका अर्थ यह है कि वह भी कर चुके हैं। इससे हमारा आशय केवल यह है कि कायपालिका का स्वरूप ब्रिटेन की भांति सामूहिक उत्तरदायित्व का नहीं है। ये समस्त शक्तियाँ अकेले राष्ट्रपति के व्यक्तित्व में ही निहित हैं।

(3) प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election)—फाइनर (Finer) के अनुसार

1 The power and importance of the president have increased steadily and he is today the focus of federal authority and symbol of national unity

अमेरिकी कायपालिका की एक विशेषता प्रत्यक्ष निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद की जन कोलाहल एवं अव्यवस्था से दूर रखने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी आशका से एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा रखा गया है।

(4) कायपालिका से अधिक (More than the Executive)—कायपालिका शक्ति का एकमात्र निवास राष्ट्रपति में रखा गया है। नियंत्रण तथा सन्तुलन की पद्धति द्वारा इसकी पूर्ति की गयी है। राष्ट्रपति अपनी अपील सदेश तथा नियेष्टा अधिकार द्वारा व्यवस्थापन तथा न्यायपालिका को भी प्रभावित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की शक्तियों के कारण उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने को विवश होना पड़ता है।

(5) कायपालिका की विधानपालिका से पृथक्ता (Separation of Executive from Legislation)—इसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। यही सविधान का मूल सिद्धांत है। कायपालिका तथा व्यवस्थापिका को एक-दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को कांग्रेस के किसी भी सदन में स्थान नहीं दिया गया है। संसदीय कायपालिका में इन शक्तियों का हमें सामंजस्य उपलब्ध होता है।

(6) मरम्मत सुधार नहीं (Repairing and Reforming)—राष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति को एकदम असंतोषपूर्ण तथा निराशाजनक भी नहीं कहा जा सकता अतः उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसमें सुशोधन तथा मरम्मत करके इस योग्य बनाने की आवश्यकता है कि यह कांग्रेस की बीखलाहट का सामना सफलतापूर्वक कर सके। राष्ट्रपति पद की आज सबसे बड़ी समस्या कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व की है। राष्ट्रपति पद में इस प्रकार की बड़ता एवं सबलता उत्पन्न की जाय जिससे वह कांग्रेस को कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके।

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यतायें (Qualifications for Presidency)

अमेरिकी सविधान की धारा 2 भाग (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति पद से सम्बंधित योग्यताओं का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है—

- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो।
- (ii) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- (iii) वह अमेरिका का 14 वर्ष तक नागरिक रहा हो। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह एक साथ शाश्वत रूप से चौदह वर्ष तक रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्वाचन से पूर्व अमेरिका में उसकी रहने की कुल अवधि चौदह वर्ष पूर्ण हो गयी हो।

इन कानूनी बहताओं के अतिरिक्त राष्ट्रपति पद के लिए व्यवहार में प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा शक्तता की कुशलता का होना आवश्यक है। जो उम्मीदवार घनी जनसंख्या वाले राज्यों से सम्बंधित रहते हैं, वे ही निर्वाचन में विजयी होने की आशा करते हैं। राज्यों के राज्यपाल सेनापति राजदूत तथा पत्रकार आदि ही प्रायः राष्ट्रपति बनते रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि

उसे दोनों में से किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। निदलीय सदस्य कभी भी इस पद के लिए निर्वाचित होने का स्वप्न तक नहीं देख सकते। कुणलवक्ता जन-साधारण को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधायें (Pay, Allowances and other Amenities)—राष्ट्रपति के वेतन के विषय में संविधान कुछ नहीं कहता। वह केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसकी सेवाओं के लिए प्रतिवार मिलेगा। कांग्रेस ही राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं आदि का निश्चय करती है। इसमें भी समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। 1909 से लेकर 1949 तक राष्ट्रपति का वेतन 75000 डालर वार्षिक था। बाद में उसका वेतन में वृद्धि करके उसे 100,000 डालर वार्षिक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का 50 000 डालर व्यय भत्ता भी मिलता है। इस पर आय कर नहीं लगता। 1953 में आय कर रहित भत्तों की समाप्ति की गयी और विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसका वेतन 150,000 डालर निश्चित कर दिया गया। राष्ट्रपति की यात्रा सरकारी भोजी तथा हवाई हाउस के व्यय के लिए बजट में अलग व्यवस्था की गयी है। जनवरी 1969 से जब राष्ट्रपति ने पद संभाला, कांग्रेस ने राष्ट्रपति का वेतन 2 00,000 डालर वार्षिक निश्चित कर दिया है जोकि कर मुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राजकीय खर्चों पर विदेश यात्रा कर सकता है। व्यक्तिगत प्रयाण के लिए उसे कार, वायुयान तथा जलयान की भी सुविधा प्रदान की गई है।

उन्मुक्तियाँ (Immunities)—संविधान इनके विषय में मौन है, किंतु फिर भी परम्परानुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं

(i) उसे किसी भी अपराध के लिये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

(ii) उसे किसी भी 'यायालय में साक्षी अथवा प्रतिवादी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता।

(iii) उसके विरुद्ध परमादेश अथवा आदेश (Injunction) 'यायालय द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता।

(iv) राष्ट्रपति के ऊपर केवल महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग ही किया जा सकता है और उसी स्थिति में वह अपने को सीनेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

पदच्युति (Removal)—अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रणाली द्वारा पद से मुक्त करने की व्यवस्था है। रिश्वत, देशद्रोह तथा अन्य किसी गम्भीर प्रकार के अपराध में यदि राष्ट्रपति अंतरग्रस्त हो तो उसके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) के किसी एक अथवा कुछ सदस्यों द्वारा लगाये जा सकते हैं। इसके पश्चात् इन आरोपों को जाँच एवं 'यायिक समिति (Judicial Committee) के द्वारा कराई जाती है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप का सदन द्वारा आधार तैयार किया जाता है। आरोप तभी वैध होते हैं जब वे सदन के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिये जायें। तत्पश्चात् उसकी एक प्रति राष्ट्रपति को समर्पित की जाती

है। अंतिम निर्णय करने का अधिकार सीनेट के पास है। जब आरोपों के विषय में सीनेट को विचार कराया जाता है तो उस समय उसका अध्यक्ष पद उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रस्तुत करके अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है प्रतिनिधि सदन भी अपना एक एजेण्डा सीनेट के लिए नियुक्त करता है जो उसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यदि सीनेट 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग केवल एक बार राष्ट्रपति श्री जॉनसन के विरुद्ध 1867 में किया गया था और वह भी सीनेट में 1 मत कम होने के कारण सफल नहीं हो सका था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम तथा पूर्ण सावधानी के साथ किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि के विरुद्ध भी किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रपति को राष्ट्र के प्रति सजग एवं सजीव रखना है।

पदावधि (Tenure of the Office of President)—जब संविधान निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न आया कि राष्ट्रपति का वस्तुतः कार्यकाल क्या हो तो तीन सुझाव प्रस्तुत किये गये—(1) राष्ट्रपति का कार्यकाल बिना पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के 7 वर्ष रखा जाय। (2) कुछ लोगो का मत था कि राष्ट्रपति का पद जीवन पयः चलने वाला रखा जाय किन्तु इसकी स्वीकृति का तो प्रश्न ही नहीं था। (3) हैमिल्टन ने यह सुझाव रखा कि राष्ट्रपति की पदावधि केवल पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के साथ 4 वर्ष के लिए हो। पहले सुझाव का समर्थन राष्ट्रपति टाफ्ट (Taft) ने किया किन्तु पूर्ण वाद विवाद के पश्चात् तृतीय सुझाव ही समर्थन पा सका। पहले सुझाव का आधार था साहस एवं स्वतन्त्रता और दूसरे का जनता की इच्छा तथा चुनाव अवसरों को व्यापक बनाना।

अमेरिका का राष्ट्रपति तीसरी बार निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं होता। 1951 के 22वें संशोधन तक इसका आधार परम्परा ही रही। किन्तु इस संशोधन के बाद तो यह वैधानिक रूप से निश्चित कर दिया गया कि राष्ट्रपति तृतीय बार इस पद के निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं होगा। यह परम्परा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के समय से स्थापित हुई जिन्होंने तृतीय बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया था जबकि वे सरलता से निर्वाचन हो सकते थे। इस प्रयास का 150 वर्षों तक पालन हुआ। राष्ट्रपति थाफ्ट तथा ग्रियोडर रूजवेल्ट ने इस प्रयास को तोड़ने का असफल प्रयास किया। किन्तु राष्ट्रपति फ्रैन्कलिन डी० रूजवेल्ट (F D Roosevelt) केवल तृतीय बार ही नहीं बल्कि 1944 में युद्ध की विभीषिका के कारण चौथी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। किन्तु बाद में तो 22वें संशोधन से दो बार भी पदावधि निश्चित हो कर दी गयी। जो इस व्यवस्था के पक्ष में थे उनका कहना था कि राष्ट्रपति इस विधि से कभी भी निरंकुश बनने का साहस नहीं कर सकता।

उत्तराधिकार (Succession)—अमेरिकी संविधान की धारा 2 के भाग 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अयोग्य हो जाने की स्थिति में उत्तरा-

धिकार के रूप में उपराष्ट्रपति उसके पद के भार एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा, और वह उस समय तक उस पर पद बना रहेगा जिस समय तक कि राष्ट्रपति उस अयोग्यता से मुक्त नहीं हो जाय। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उपराष्ट्रपति पूर्ण रूप से राष्ट्रपति बन जायगा अथवा केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 1841 में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। 1886 में कांग्रेस के एक अधिनियम के अनुसार यह भी निश्चय कर दिया गया कि उपराष्ट्रपति के पश्चात् राज्य मंत्री (Home Secretary) को राष्ट्रपति पद सम्भालने का अधिकार होगा। 1947 में पुनः कांग्रेस ने राष्ट्रपति के उत्तराधिकार हेतु एक अधिनियम स्वीकार किया जिसमें राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को शेष अवधि के लिये राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया गया। यह भी व्यवस्था की गयी कि यदि किसी कारण से इस पद के लिये उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो सके तो प्रथम गवर्नर प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष को दिया जायगा और उसके पश्चात् मीनेट के अस्थायी अध्यक्ष, राज्य सचिव तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य (वित्त तथा युद्ध मंत्रियों) को यह पद उपलब्ध हो सकेगा।

किंतु 1965 में संविधान के 25वें संशोधन में राष्ट्रपति की नियोग्यता की स्थिति का विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया गया है। 10 फरवरी 1967 में इस संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जाता है उसरी मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो शेष काल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जायगा। संशोधन के दूसरे भाग में एक महत्वपूर्ण बात यह कहो गयी है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने पर अपने द्वारा रिक्त किये गये पद के लिये एक व्यक्ति का मनोनीत (Nominate) करेगा जिसकी पुष्टि दोना सदन के संयुक्त अधिवेशन द्वारा होनी चाहिए। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का पद 16 बार रिक्त रहा। 1963 में राष्ट्रपति कर्नेडी की हत्या के फलस्वरूप लिण्डन जॉन्सन राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति का पद पुनः रिक्त हो गया। उस समय यह अनुमान किया गया कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त रखना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है और तभी संविधान में 25वें संशोधन का प्रवेश सम्पन्न हुआ। अमेरिका में ऐसी स्थिति 5 बार उत्पन्न हो चुकी है जबकि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने में असमर्थता प्रकट की। 1881 में राष्ट्रपति गेफोर्ड पर गोली चलाई गयी थी। 1919 में राष्ट्रपति विल्सन का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का स्वास्थ्य भी चिंताजनक बन गया था। राष्ट्रपति आईजन हावर को भी स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतें बनी रहनी थीं। उस नियोग्यता की स्थिति में उस समय तक उपराष्ट्रपति या मीनेट अथवा प्रतिनिधि सदन का स्पीकर राष्ट्रपति के पुनः स्वस्थ होने तक कार्यभार सम्भालता रहा है। कांग्रेस को सूचना मिलने पर 21 दिन के अंदर 2/3 बहुमत से इस व्यवस्था पर निर्णय करना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President and Vice President)

संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं में इस बात पर व्यापक वाद विवाद हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति का स्वरूप कैसा हो? इस सुझाव

को अस्वीकार कर दिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति व द्वारा सम्पन्न हो क्योंकि इस व्यवस्था में हुल्नटजाजी एवं राजनीतिज्ञ अमरम के मध्य माध्य व्यक्ति के निर्वाचित होने की सम्भावनाएँ कम थी। दूसरा मुद्दा यह रहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस व द्वारा हो किया जाय। यद्यपि इस मुद्दाव को विस्तृत समयन उपलब्ध था किन्तु शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के सिद्ध होने के कारण इसे रद्द कर लिया गया। यदि ऐसा होता तो राष्ट्रपति विधान मण्डल के नियंत्रण से मुक्त नहीं रह सकता था। उन परिस्थितियों एवं विक्ल्ओं में यही उचित समझा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल (Electoral College) के द्वारा सम्पन्न हो जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों का मध्य भाग है और जिसे श्रेयस्वर भी माना जाता है। इस निर्वाचक मण्डल में उतने ही सदस्य होंगे जितने सदस्य कि अमेरिकी कांग्रेस में हैं। इस समय कांग्रेस में कुल सदस्यों की संख्या 535 है। (100 सीनेट के एवं 435 प्रतिनिधि सभ के सदस्य) किन्तु संविधान के 23वें संशोधन के द्वारा कोलम्बिया जिले को तीन प्रतिनिधि निर्वाचक मण्डल के लिए निर्वाचित करने का अधिकार द दिया गया है यद्यपि यह राज्य नहीं है। इस कारण निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की संख्या 538 हो गयी है।

राष्ट्रपति का पद एक महत्वाकांक्षी का पद है। राजनीतिक दलों के अम्युदप ने सन 1800 के पश्चात इस प्रतिष्ठित पद के निर्वाचन को लगभग प्रत्यक्ष ही बना दिया है। राजनीतिक दलों ने संविधान निर्माताओं की यह कल्पना निराधार सिद्ध कर दी है कि राष्ट्रपति शोरगुल से दूर रहे। लास्की (Lasky) ने इस सम्बन्ध में कहा है कि "संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनायी थी, उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था। परन्तु उनकी भाशाभा में से इससे अधिक और कोई भाशा भग नहीं हुई है।" राष्ट्रपति के निर्वाचन के पाँच चरण हैं—

(1) उम्मीदवार का नामांकन (Nomination of Candidate)

प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन (National Convention) आमन्त्रित करता है, जोकि एक ऐसे हॉल में होता है जिसमें कम से कम 15000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकें। सम्मेलन में प्रेम प्रतिनिधि टीकाकार तथा रेडियो रिपोटरो को उचित स्थान प्रदान किया जाता है। वातावरण में काफी उत्तेजना रहती है और जोशिले भाषण भी दिय जाते हैं। कभी-कभी बाजों के बजने से इतना कोलाहल उत्पन्न हो जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार का चयन करना कठिन हो जाता है। उम्मीदवारों का चयन दल के प्रमुख नेताओं में सोदेबाजी के आधार पर होता है। क्योंकि वे भी ऐसे उम्मीदवारों को छाटते हैं जिन्हें प्रतिनिधियों का बहुमत उपलब्ध हो सके। संविधान में इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि इसका कोई वर्णन तक नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम का प्रस्तावक तथा समयक जोशिले भाषण देता है। इसके पश्चात दल के प्रत्याशी को निर्वाचित करने के लिए मतदान होता है। मतदान में यदि कोई नियमित प्रतिनिधि (Regular Delegate) नहीं हो तो उसके स्थान पर वैकल्पिक प्रतिनिधि (Alternative Delegate) भाग लेता है। जिस उम्मीदवार को दल का प्रत्यापी घोषित किया जाता है उसके पक्ष में स्पष्ट बहुमत होता चाहिए।

जिस समय तक यह बहुमत उपलब्ध नहीं होता उस समय तक बार बार मतदान चलता रहता है। प्रत्येक बार कम मत प्राप्त करने वाले सदस्य का नाम उम्मीदवारों की तालिका में से निष्कासित कर दिया जाता है। कभी-कभी तो इसमें कई दिन भी लग जाते हैं। 1880 में राष्ट्रपति गैरफोल्ड (Garfield) का नाम 36 बार मतदान के पश्चात् ही घोषित हो पाया। 1912 में राष्ट्रपति विल्सन का नाम 46 बार मतदान करने के पश्चात् ही घोषित किया जा सका। 1924 में राष्ट्रपति पद के लिये जॉन हेविड का नाम घोषित करने के लिए 103 बार मतदान हुआ। 1952 में रिपब्लिकन दल ने राष्ट्रपति आइजन हावर को कई बार मतदान के उपरांत अपना प्रत्याशी घोषित किया।

उपराष्ट्रपति पद के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा इसी प्रकार होती है। इसके लिए बड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्रता से ही प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। वियड के शब्दा में, 'राष्ट्रपति का वास्तविक नियम विजयी दलों के राष्ट्रीय सम्मेलन तथा मतदान में उस दल के समर्थक मतदाताओं के समूह के हाथों में चला गया है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा व्यवस्थित विचारपूर्ण तथा गरिमामय पद्धति का स्थान विशाल लोकप्रिय प्रवर्तन में ले लिया है।' राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में या तो ह्वाइट हाउस में पुनः प्रवेश प्राप्त करने की योजनाओं में लगा रहता है या अपने उत्तराधिकारी के समर्थन में रत रहता है। इस निर्वाचन में बूटपालिश करने वाले से लेकर बड़े-बड़े स्तर का व्यक्ति भाग लेता है। इन सम्मेलनों में उम्मीदवारों का अत्यधिक घन व्यय होता है। ऑग तथा रे (Ogg and Ray) ने लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की तडक-मडक बड़ी ही अनूठी है। कठिनाई से ही नया राष्ट्रपति ह्वाइट हाउस में स्थिर हो पाता है। क्योंकि अगले निर्वाचन में शक्ति माप के लिये योजनाएँ बनना आरम्भ हो जाती हैं।'

(2) चुनाव अभियान (Election Campaign)

राष्ट्रीय सम्मेलन के समाप्त होने से पूर्व घोषित उम्मीदवार के पक्ष में एक समिति का गठन किया जाता है जोकि अपना एक अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष निर्वाचित करती है। इस समिति का प्रमुख कार्य घोषित उम्मीदवार के पक्ष में धुआँ धार प्रचार करना है। यह समिति अपनी शाखाएँ प्रत्येक राज्य में स्थापित करती है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में व्यय होने वाले धन पर सैद्धांतिक रूप से नियंत्रण तो होता है, किंतु उसका व्यावहारिक रूप अधिक बँडोर नहीं है। 1960 में राष्ट्रपति पद के लिए 1650 से लेकर 1750 डालर व्यय हुए। 1968 में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति निक्सन के निर्वाचन अभियान पर 1,20,00,000 डालर खर्च हुए जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में 8 करोड़ 40 लाख रुपये होता है। उम्मीदवार आवाशवाणी, टेलीविजन तथा यातायात सम्बन्धी अन्य साधनों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए करते हैं। अभी हाल ही के निश्चयानुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दो लाख डालर व्यय कर सकता है।

(3) निर्वाचक मण्डल की रचना (Formation of the Electoral College)

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल के द्वारा सम्पन्न होता है।

सदस्यों की संख्या कांग्रेस के सदस्यों के बराबर ही होती है किंतु कोलम्बिया जिले के तीन सदस्यों के आ जाने से संख्या 538 है। निर्वाचक मण्डल व सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सूची प्रणाली (List System) के आधार पर चुनाव वर्ष के नवम्बर माह में होता है। 15वें सत्राधन से हृथिया का भी मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। मतदाता किसी भी व्यक्तिगत उम्मीदवार को मत न देकर दल को मत देते हैं। जिस दल के निर्वाचक अधिक आ जाते हैं उसे अपनी विजय सामने नजर आने लगती है। निर्वाचकों को दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। जस्टिस जैकसन का यह कहना सही है कि निर्वाचक आने दल के आदेशानुसार ही मतदान करते हैं। वे स्वयं सोचने का विचार भी अपने सम्मुख नहीं लाते।" वस्तुतः निर्वाचक गण का निर्वाचन ही राष्ट्रपति का निर्वाचन है। उनके निर्वाचन में पर्याप्त उत्तेजना रहती है। ऑग तथा रे के शब्दों में 'निर्णय के चार पाँच महीने पूर्व से ही नामांकन के लिए कोलाहलपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलनों का युद्ध होता है। इससे पश्चात् थोड़ा-सा अवसर मिलता है और चक्रव्यूह की रचना होती है तथा दल में तयारी किया जाता है। धीरे धीरे दृश्य के पश्चात् नाटक आगे बढ़ता है। अन्त में चुनाव में 50 करोड़ से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग का निर्णय करते हैं। हजारों भाषण होते हैं, रीशनाई की बाढ़ आ जाती है और करोड़ों डालर खर्च हो जाते हैं।' इस सम्बन्ध में एक और बात यह देखने की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति निर्वाचक मण्डल का सदस्य नहीं बन सकता जो कि राज्य में भी किसी लाभ के पद पर है। अमेरिका की निर्वाचन प्रणाली की एक विचित्रता और भी है

यदि किसी राज्य से किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का बहुमत उपलब्ध हो जाता है तो उसे शेष निर्वाचकों के मत भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ—टक्सास के निर्वाचक मण्डल में 45 मत हैं। जो भी उम्मीदवार निर्वाचक मण्डल द्वारा दिये गये मते का बहुमत प्राप्त कर लेता वह शेष मतों का भी अधिकारी बन जाता है। अ, ब, स तीन उम्मीदवार हैं। अ को 15 व को 18 तथा स को 12 मत प्राप्त हुए। इस परम्परा के अनुसार 18 के अतिरिक्त अ तथा स के मत भी व को प्राप्त होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने निर्वाचन के सम्बन्ध में यह एक विचित्र परम्परा है। ऑग तथा रे के शब्दों में, 'लिखित मौलिक विधि को बिना स्पष्ट किये हुए काम रूप में संविधान में किस प्रकार परिवर्तन हाता जा रहा है इसका उदाहरण इससे उत्तम कहीं नहीं मिल सकता।'"

(4) निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President by the Electoral College)

निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने मत का प्रयाग दिसम्बर मास के दूसरे बुधवार को अपने-अपने राज्य की राजधानी में किया जाता है। इसी दिन वस्तुतः राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के भाग्य का निर्णय हो जाता है। मतदान केवल एक औपचारिकता है क्योंकि निर्वाचक गण दलीय प्रतिज्ञा से बद्ध होते हैं। प्रमाणीकरण

1 No better illustration can be found of how in the actual working constitution changes without a hand being laid on the written fundamental law

के पश्चात् मत पत्र सीनेट के अध्यक्ष के पास प्रेषित कर दिए जाते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में मतों की गणना सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यही विजयी होने वाले उम्मीदवार की घोषणा भी करता है। बीसवें संशोधन (1933) के अनुसार अब राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है जबकि वह पहले 4 मार्च को यह कार्य किया करता था। राष्ट्रपति की विजय के लिए 538 में से 270 मतों की आवश्यकता होती है।

यह भी सम्भव है कि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति में 12वें संशोधन (1804) के अनुसार अधिक मत प्राप्त करने वाले तीन उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि सदन (House of Representative) किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर लेता है। इस प्रकार से कभी कभी हम ऐसे प्रत्याशी को भी राष्ट्रपति देख सकते हैं जिसकी शेषमात्र भी आशा न हो। इस प्रथा को काले घोड़े (Dark Horses) कहा जाता है। इस मदभ में एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिनिधि सदन में मतदान करते समय प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है। अमुक राज्य के प्रतिनिधियों को आपस में यह निश्चय करना पड़ता है कि वे किमका समर्थन करेंगे। यदि उनमें यह समझौता न हो सके तो उस राज्य का मत रद्द माना जाता है। इसी प्रकार सीनेट (Senate) भी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर सकती है। ऐसे समय पर सीनेट की गणपूर्ति की सहायता उसके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होगी। इसमें प्रत्येक सीनेटर का एक ही मत होता है। जिस उम्मीदवार को सदस्यों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति बन जाता है।

राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली की आलोचना (Criticism of the System of Presidential Election)

(1) निर्वाचक मण्डल की उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है (It reduces the utility of Electoral College to the Minimum)—निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की वर्तमान व्यवस्था एवं परम्परा ने राष्ट्रपति के पद को अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष बना दिया है। निर्वाचक मण्डल की उपयोगिता ही समाप्त हो गई है। अब निर्वाचक मण्डल का गठन केवल एक औपचारिकता मात्र है। निर्वाचकों का निर्वाचन पूर्ण रूप से दलीय आधार पर होता है और उनके निर्वाचन होते ही यह पता सरलता से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन होगा। जनता में यह धारणा बनती जा रही है कि निर्वाचक मण्डल राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग है। इस सम्बन्ध में मूनरो ने लिखा है, “मूल योजना का हृदय प्रथम दस वर्षों में ही काटकर फेंक दिया गया था और उसके बाद कभी भी उस पुनः प्रतिस्थापित करने का अवसर नहीं आया।”¹

वस्तुतः राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल की स्थिति एक पोस्टमन जैसी है।

1 The heart of original plan was cut out within Ten years and never since has there been any serious attempt to restore it — Munro

अमेरिका में इस सस्या का स्तर इतना गिर गया है कि कोई इसकी बात नहीं सुनता। प्रो० ब्रोगन (Brogan) ने कहा है कि, '1820 के पश्चात किसी भी निर्वाचक मण्डल ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार मतदान में भाग नहीं लिया। समुक्त राज्य में इस सस्या को कोई महत्व नहीं दिया जाता।'

(2) निर्वाचन शांत वातावरण में सम्पन्न नहीं हो पाते (Presidential Elections are not held in a Calm Atmosphere)—सविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति पद के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुकरण केवल अव्यवस्था एवं जन कालाहल से बचने के लिए किया था। वह स्वप्न भग्न हो गया है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचकों के निर्वाचन में इतनी हल्लाबाली होती है कि जिसकी सीमा नहीं। विजय के लिए हर तरह के हथकण्डे अपनाये जाते हैं। निर्वाचन में शक्ति तोलने की योजनायें तयार की जाती हैं। निर्वाचन से पाँच महीने पूर्व ही राष्ट्रीय सम्मेलनों का अखाड़ा जमता है, चक्रव्यूह की रचना की जाती है। यह सब नाटकीय ढंग से होता है।

(3) निर्वाचन बहुत महंगा पड़ता है (Election is damn Expensive)—इस तथ्य का उल्लेख इस अध्याय में अत्यन्त भी किया जा चुका है। 1964 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दल का व्यय 1 करोड़ 70 लाख डालर से अधिक था तथा डेमोक्रेटिक दल का 1 करोड़ 5 लाख डालर था। 1968 में रिपब्लिकन दल का व्यय 1 करोड़ 20 लाख डालर था तथा डेमोक्रेटिक दल का खर्चा 1 करोड़ डालर हुआ। इस धन राशि को देखते हुए कोई साधारण आर्थिक स्थिति का व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का कभी विचार तक नहीं कर सकता।

(4) अल्पमत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता है (It Makes the Minority President)—अमेरिका में इस समय तक 11 राष्ट्रपति ऐसे बने हैं जिन्हें निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का तो बहुमत प्राप्त हुआ था किन्तु जिन्हें सार्वजनिक मतों का 50 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हुआ। 1860 में राष्ट्रपति लिंकन का ऐसा ही उदाहरण है जिन्हें लोकप्रिय मतों का 50 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं था। इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन को 1912 में अपने प्रतिद्वंद्वी थियोडोर रूजवेल्ट की अपेक्षा 20 लाख मत अधिक मिले किन्तु उन्हें लोकप्रिय मतों का केवल 42 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। 1876 में राष्ट्रपति हेज़ इसी प्रकार निर्वाचित हुए। 1888 में हैरीसन को भी यद्यपि क्लैवलण्ड से 1 लाख कम लोकप्रिय मत प्राप्त हुए किन्तु फिर भी विजयी हुए। 1960 में राष्ट्रपति कनेडी को भी लोकप्रिय मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। यद्यपि ऐसा होता तो कम है कि अल्पमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाय, किन्तु यह सम्भावना अवश्य रहनी है और बहुत से मामलों में यह सही भी उतरी है। इस व्यवस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व इकाई मत प्रणाली (Unit Vote System) पर है। इससे अनुसार यदि किसी राज्य से किसी राजनीतिक दल को लोकप्रिय मतों का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे उस राज्य के समस्त निर्वाचकों का मत ग्रहण करने का अधिकार मिल जाता है। एक दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जायगा। अमेरिका में निर्वाचकों का निर्वाचन अनुपाती प्रणाली के द्वार प्रसार सूची प्रणाली (List System) के आधार पर सम्पन्न होता है। ओहियो (Ohio) राज्य

से 25 निर्वाचक चुन जाने थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 1,500,001 मत डेमोक्रेटिक दल द्वारा प्रसारित सूची के पक्ष में आये तथा 15,00,000 मत रिपब्लिकन दल द्वारा रखी हुई सूची के पक्ष में पड़े। तो इस प्रकार डेमोक्रेटिक दल की विजय हुई और वह भी केवल 1 मत से। अब 25 के 25 निर्वाचकों के मत विभ्रम होने पर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पक्ष में गिन जायेंगे। इस प्रकार बड़े राज्यों में बहुत कम मत आने पर भी उम्मीदवार विजयी हो जाते हैं। यह व्यवस्था किसी दृष्टि से 'आयोचित नहीं कही जा सकती। इस प्रकार अल्पमत में होते हुए भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की सम्भावना बनी रहती है।

(5) कानूनी दायित्व का अभाव (Lack of Legal Guarantee)—यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचक मण्डल का एक सदस्य अपने दल के उम्मीदवार को ही अपना मत दे। इस प्रकार का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं है। परन्तु इस प्रकार का कानूनी दायित्व अमेरिका के दो राज्यों—कैलीफोर्निया तथा आरिगेन राज्यों—में पाया जाता है। 1948 से पूर्व स्थिति आमक नहीं थी क्योंकि ऐसे बहुत ही कम अवसर आये थे जबकि किसी पार्टी की ओर से निर्वाचित निर्वाचकगण ने अपना मत दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में दिया हो। किन्तु इसके पश्चात् अलबामा तथा टेनेसी राज्यों में ऐसे अवसर भी देखने को मिले जबकि निर्वाचकों ने अपने मत दूसरे दल के उम्मीदवारों को दिये। 1960 में निवसन सूची के आधार पर चुने हुए निर्वाचक ने अपना मत बियड के पक्ष में दिया। अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष यह विकट समस्या है।

(6) विशिष्ट व्यक्तियों के निर्वाचन में बाधा (Hinderance in the Election of Prominent Persons)—राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पद्धति का एक दोष यह भी है कि इसके अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो पाता। हस्ट, हैमिल्टन तथा माशल जैसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सेवायें प्राप्त नहीं हो सकीं। इसका मूल कारण है राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलनों की व्यवस्था। निर्वाचक गण भी स्वतन्त्रता पूर्वक मतदान नहीं कर पाते। यद्यपि रूजवेल्ट, वाशिंगटन तथा लिंकन जैसे विशिष्ट व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थ रहा है किन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है।

(7) पूर्व अनुभव का अभाव (Absence of Previous Experience)—इस दृष्टि से विचार करने पर प्रधानमन्त्री की स्थिति राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक अच्छी कही जा सकती है। प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बनने से पूर्व कई पदों का लाभ उठाये हुए रहता है। उसे प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो जाता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के अनुभव से वंचित रहता है। अनुभव को राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता।

राष्ट्रपति पद की इन आलोचनाओं के अतिरिक्त कभी कभी यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो सके तो वह उत्तम व्यवस्था होगी। निर्वाचकों का निर्वाचन समस्त राज्य के आधार पर न होकर क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा होना चाहिए।

यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रीय सम्मेलनों को आमंत्रित करने उनके द्वारा समयन की व्यवस्था का बत दिया जा सके तो यह मस्था और भी अधिक लोकप्रिय एवं ममस्पर्शी बन सकती है।

राष्ट्रपति के कृत्य एवं शक्तियाँ (Functions and Powers of the President)

टर्तोलोट (Turullot) ने *An Anatomy of American Politics* में लिखा है कि संविधान ने राष्ट्रपति के वर्तमान स्वरूप का उत्पन्न नहीं किया, किंतु यह सात राष्ट्रपतियों के साहस तथा उनकी दूरदर्शिता का परिचय है। प्रो० जे० पी० सूद ने कहा है कि "राष्ट्रपति विस्तारयुक्त शक्तियों का पद रहा है।"¹

यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति की शक्तियों का विकास क्रमबद्ध एवं निरंतर रूप में नहीं हुआ। उसकी शक्तियों में विकास अकस्मात् ही हुआ है। ऐसा समय भी रहा है जबकि उसकी शक्तियों में कोई विकास नहीं हुआ। राष्ट्रपति की शक्तियों का विकास निम्नलिखित श्रोतों से हुआ है—

(1) संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)—अमेरिकी संविधान की धारा 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियाँ का विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति के सैनिक अधिकारों के साथ-साथ उसके अन्य अधिकार जैसे—नियुक्ति क्षमादान आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान के ये दो शब्द कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का अधिकारी होगा, इतने शक्तिशाली सिद्ध होंगे, यह कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुनरो के शब्दों में, 'अब तक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयोग करता है।'²

(2) कांग्रेस के अधिनियम (Statutes of Congress)—राष्ट्रपति की शक्तियों के विकास में स्वविवेक नियमों का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो उसे कांग्रेस के अधिनियमों के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं। 1933 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मुद्रा परिवर्तन एवं स्थायित्व के विषय में कई महत्वपूर्ण नियमों पर स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार दिया। 1941 में उद्यार पट्टा अधिनियम (Lend Lease Act) के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने वाले देशों को सैनिक सामग्री उद्यार दे सकता है। अतः राष्ट्रपति की शक्तियों के विकास में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत अधिनियमों का भी विशेष हाथ है।

(3) परम्पराएँ (Traditions)—राष्ट्रपति की शक्तियों का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत परम्पराएँ हैं। परम्पराओं ने ही राष्ट्रपति को अमेरिकी जनमत का नतुत्व एवं अधिवक्ता बना दिया है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के समय में यह विचार

1 The Presidency has been an office of expanding power —J P Sood

2 When the founding fathers decreed that the executive power shall be vested in the President they did not realise that some day these minor words would serve to consolidate the largest amount of authority ever wielded by a man in democracy —Munro

बन पड़ा था कि राष्ट्रपति को एक नेता के रूप में भी सक्रिय रूप में अपने पद का प्रयोग करना चाहिए, शक्ति पृथक्करण के होते हुए भी आज राष्ट्रपति प्रमुख विधायक बन गया है। रूस तथा अमेरिका के विक्षिप्त सम्बन्धों के कारण राष्ट्रपति पद का महत्व काफी बढ़ गया है। राष्ट्रपति स्वयं ही प्रधानमन्त्री भी बन गया है, प्रोफसर रॉसिलर की रोसिलर (Rossiler) ने कहा गया है कि 'राष्ट्रपति वास्तव में अमेरिकी जनमत का निर्माता तथा प्रमुख प्रवक्ता है।'¹

यात्रिक एवं प्राविधिक प्रगति ने राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त मात्रा में विकास किया है। आज राष्ट्रपति की स्थिति यह है कि वह परम्परानुसार अपने में ही प्रधानमन्त्री पद से सम्बन्धित शक्तियों को समेटने में सफल हो गया है। वह जनता की आवाज बन गया है। सेनीटोरियस कर्टिसी की परम्परा में राष्ट्रपति की शक्तियों में विकास एवं नियन्त्रण हुआ है।

(4) 'यायिक निवचन (Judicial Interpretation)—अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जा व्यावहारिकता उत्पन्न हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है। न्यायालय ने समय समय पर सर्वोच्च न्यायाधीशों का विवेचन जिस रूप में किया है उससे राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। अनेक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय मौन है और उस दिशा में न्यायालयों के निर्णयों में उसकी सहायता की सीमा है। नियुक्तियों के सम्बन्ध में यह कड़ी पर नहीं कहा गया है कि उच्च पदाधिकारियों को पद मुक्त करने का अधिकार सीनेट का है अथवा राष्ट्रपति का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ही यह निवचन प्रस्तुत किया था कि यह अधिकार राष्ट्रपति का है।

राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में तीन प्रकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है—

(क) संवैधानिक सिद्धांत (Constitutional Theory)—राष्ट्रपति टाफ्ट (Taft) इस सिद्धांत का विशेष समर्थक था। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति के संवैधानिक एवं निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय से बाहर नहीं कर सकता। जिन शक्तियों का उल्लंघन किया जाय तो उनमें अधिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता।

(ख) नेतृत्व सिद्धांत (Stewardship Theory)—राष्ट्रपति प्रमुख प्रवक्ता राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट था। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति का नेता है और उस उन सम्पूर्ण कार्यों का प्रयोग कर सकता है जो कि जिनका सर्वोच्च न्यायालय में निषेध नहीं किया गया है।

(ग) विशेषाधिकार सिद्धांत (Privilege Theory)—इस सिद्धांत के मूल प्रवक्ता फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति का प्रयोग करते कई ऐसे नियम बन गए हैं जो कि राष्ट्रपति को प्रदान की जाती थी। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है।

1 He (President) is the best example of a leader in the United States

हो तो राष्ट्रपति कानूनों की परवाह किये बिना भी अपने सविवेक नियम का प्रयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति की अधिशायी शक्तियाँ (Executive Powers of the President)

राष्ट्रपति प्रमुख कार्यपालिका के रूप में निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है—

(1) कानूनों को लागू करना एवं व्यवस्था बनाये रखना (Enforcement of Laws and maintenance of order)—अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक तथा परिंरक्षक कहा गया है। राष्ट्र की सर्वोत्तम कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति अधिष्ठाता है। समस्त सघीय कानूनों एवं सघीय न्यायालयों के नियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर है। इस दिशा में उसे अनेकों सघीय कमचारियों से सहयोग प्राप्त होता है। किंतु राष्ट्रपति की व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति कांग्रेस के नियमों एवं अध्यादेशों पर निर्भर नहीं है। जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति यह समझता है कि व्यवस्था कायम करने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है, चाहे उस राज्य का राज्यपाल अथवा विधान मण्डल ऐसी कार्यवाही का अनुरोध करे अथवा न करे, राष्ट्रपति सन्निय कदम उठाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है। अब यह धारणा असत्य सिद्ध हो चुकी है कि राष्ट्रपति तभी कदम उठा सकता है जबकि उससे अनुरोध किया जाय। सन 1895 में री डेब्स विवाद (Case—Re Debs, 1895) में राष्ट्रपति की शक्ति का इस दृष्टि से स्पष्टीकरण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था, 'बहु राष्ट्र की समस्त शक्ति का देश के किसी भी भाग में या सारे देश में शांति बनाये रखने के लिए प्रयोग कर सकता है।' सन् 1894 में केन्द्र ने अंतर्राज्यीय डाक व्यवस्था एवं व्यापार को सुरक्षित रखने के आधार पर इलीनोइस (Illinois) राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी पुलिस कमचारियों की हड़ताल को भंग करने के लिये हस्तक्षेप किया। लिटिल रॉक (Little Rock) के सेंट्रल हाईस्कूल में हिंसाओं को प्रवेश दिलवाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना हेतु राज्य के राज्यपाल द्वारा सेना भेजने की स्थिति में केन्द्र की ओर से राष्ट्रपति आइजनहावर को सन् 1952 हस्तक्षेप में करना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों को मनवाने के लिये शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सन 1962 में मिसिसिपी राज्य के राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में हिंसाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जिसके लिये राष्ट्रपति कैनडी को शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अलबामा में भी सन् 1963 में इसी आधार पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा। सन् 1964 में देश के विभिन्न राज्यों में हुंसी विरोधी आन्दोलनों को दबाने के लिये राष्ट्रपति जॉनसन को शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अतः राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने का व्यावहारिक रूप में उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है।

(2) नियुक्ति का अधिकार (Power of Appointment)—अमेरिका में लगभग 23 लाख असैनिक कमचारी हैं जिनमें से 85% योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लगभग 25 000 कमचारियों की नियुक्ति होती है, किंतु व्यवहार में तो केवल 6000 कमचारियों की नियुक्ति करने का ही

अक्सर राष्ट्रपति को मिलता है, कुछ प्रत्यक्ष नियुक्तियाँ करने का अधिकार राष्ट्रपति को संविधान से ही मिला हुआ है। ऐसे पदों के विपरीत नियुक्तियाँ करने के अधिकार राष्ट्रपति को अधिक मिले हुए हैं जिनकी उत्पत्ति कांग्रेस करती है और जिनकी योग्यता का निश्चय भी कांग्रेस स्वयं करती है। लगभग 375 पद ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति के नियुक्ति-अधिकार को काफी स्वतंत्रता मिली हुई है, ये पद अधिकतर उसके व्यक्तिगत कमचारियों से सम्बंधित हैं। शेष पदों के लिये राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

बहुधा यह देखा गया है कि उच्च पदों की नियुक्तियों के सम्बंध में सीनेट अधिक बाधा उत्पन्न नहीं करती। राजदूत, वाणिज्य दूत सुप्रीम कोर्ट के 'यायाधीश' आदि इस श्रेणी में आते हैं। अन्य पदों के सम्बंध में परम्परानुसार राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटर्स को विश्वास में लेकर ही नियुक्तियाँ करता है। जहाँ नहीं भी राष्ट्रपति स्वीकृति लेने में भूल कर बैठता है वही पर उसे सीनेट की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी सीनेट ने उच्च पदों के लिये भी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया है। सन् 1925 में सीनेट ने राष्ट्रपति काल्विन कूलिज द्वारा मंत्री के रूप में चार्ल्स वारेन की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रपति जैक्सन ने इंग्लैण्ड में मार्टिन ब्यूरोन की राजदूत के रूप में नियुक्ति की थी, किंतु इसे सीनेट ने अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार 1930 में राष्ट्रपति हूवर को जान पाकर को 'यायाधीश' के पद से हटाना पड़ा क्योंकि सीनेट ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। इसके विपरीत अन्य छोटे पदों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपने दल की इच्छाओं को ध्यान में रखता है। सन् 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमेन ने भी इलीनोइस राज्य में जब जिला जजों की नियुक्ति की उसे भी सीनेट ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के सीनेटर्स से परामर्श नहीं किया था।

(3) पदच्युति करने की शक्ति (Power of Removal)—संविधान पदाधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता, महाभियोग के द्वारा ही पदाधिकारियों को पदच्युत करने की बात संविधान कहता है। क्या कमचारी के असम्य होने पर राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकता है इसके विषय में संविधान मौन है। सन् 1867 तक संविधान निर्माता जेम्स मीडिसन का यह सिद्धांत क्रियावित होता रहा कि राष्ट्रपति पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है किंतु राष्ट्रपति जों सन के साथ कटु सम्बंध होने के कारण कांग्रेस ने पदावधि अधिनियम (Tenure of Office Act) पारित कर दिया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पदच्युत आदेश की पुष्टि सीनेट के द्वारा होना आवश्यक कर दिया गया। किंतु इस सिद्धान्त को सन् 1926 में उस समय चुनौती का सामना करना पड़ा जब मेक्स बनाम यू० ए० के विवाद में सुप्रीमकोर्ट ने यह निणय लिया कि पदच्युत करने का प्रश्न राष्ट्रपति की शक्तियों से ही सम्बंधित है। मेक्स एक पोस्टमास्टर था जिसे सन् 1920 में राष्ट्रपति विल्सन ने सीनेट की अनुमति लिये बिना ही पद से मुक्त कर दिया था। मर्याद इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। यह निणय 1917 का है जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। सन् 1933 में एक बार पुनः पदच्युति का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समुक्ष आया जब राष्ट्रपति ह्यूवेल्ड ने विनियम २

हम्फ्री को सघीय व्यापार आयोग (Free Trade Commission) की सदस्यता से केवल इस आधार पर हटा दिया क्योंकि उनके राजनतिक विचारों से उनके विचार मेल नहीं खाते थे। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निणय लिया कि राष्ट्रपति केवल अक्षमता के आधार पर ही कमचारियों को पदच्युत कर सकता है और अन्य किसी आधार पर नहीं। अब कांग्रेस ने योग्यता सिद्धांत का प्रयोग एक स्वरूप काफ़ी व्यापक बना दिया है। राष्ट्रपति चाहे तो पदा को समाप्त कर सकता है तथा उससे सम्बंधित कमचारियों को हटा भी सकता है। सन् 1952 में राष्ट्रपति ट्रूमेन ने मजदूरी स्थिरता बोर्ड (Wage Stabilization Board) को समाप्त कर दिया और उसके समस्त कमचारियों को काय भुक्त कर दिया। परंतु कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पर आसोन कमचारियों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। कांग्रेस भी अपने द्वारा उत्पन्न निगमा एवं बोर्डों के कमचारियों की सेवाओं पर नियंत्रण लगा सकती है। लोक सेवा नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति पदाधिकारियों को हटा सकता है।

(4) प्रशासन का संचालन (Direction of Administration)—राष्ट्रपति मुख्य प्रशासक है। प्रशासकीय विभागों को आदेश देने का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह राष्ट्रपति उसी स्थिति में कर सकता है जब उसे प्रशासकीय संचालन का पूर्ण अधिकार हो। प्रशासकीय कार्य कुशलता एवं स्थायित्व के लिये राष्ट्रपति को अध्यादेश एवं अनुदेश जारी करने तथा नियम एवं उपनियम बनाने का अधिकार है। नियमों तथा उपनियमों के पालन हेतु राष्ट्रपति सेना का भी प्रयोग कर सकता है। सकट की स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकता है। उसे विभागों को पुनर्गठित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

(5) क्षमादान करने की शक्ति (Power to Grant Pardon)—अमेरिकी संविधान की धारा 2 में अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति कानून के विरुद्ध अपराध करने वालों को क्षमा कर सकता है अथवा दण्ड की मात्रा को कम कर सकता है। उस दण्ड को कुछ समय के लिये स्थगित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो दण्ड के स्वरूप को भी बदल सकता है। राष्ट्रपति को सामूहिक रूप में भी क्षमादान करने का अधिकार है, सन 1868 में राष्ट्रपति जॉनसन ने गृहयुद्ध की पृथकतावादी शक्तियों को सामूहिक रूप से क्षमा किया था।

(6) वदेशिक सम्बन्धों का संचालन (Direction and Conduct of Foreign Relations)—संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विदेशी नीति निर्धारण एवं वदेशिक सम्बन्धों के संचालन का अधिकार किसका है। इस अस्पष्टता का लाभ उठाकर यह अधिकार राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया है। सन् 1936 में कर्टिस राइट (Curtis Wright) के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निणय दिया था कि राष्ट्रपति ही वदेशिक सम्बन्धों का निर्देशन का मुख्य अधिकारता है। वदेशिक सम्बन्धों का संचालन करते समय राष्ट्रपति का सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति तथा प्रतिनिधि सदन की विदेश सम्बन्ध समिति के साथ तात्कालिक उत्पन्न करना पड़ता है। ये समितियाँ कभी-कभी रोड़ा अटक देती हैं। प्रत्येक दूरदर्शी राष्ट्रपति

इन समितियों से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जॉन माशल ने भी राष्ट्रपति को विदेश सम्बन्धों का प्रमुख अधिकारता कहा है।

विदेश-नीति एवं सम्बन्धों के संचालन में राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है—

राष्ट्रपति राजदूतों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, किन्तु इसके लिये उसे सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। किन्तु गुप्त दूतों के लिये उसे सीनेट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे दूतों का बतन राष्ट्रपति स्थायी कोष से दे सकता है। इसके विपरीत विदेशी राजदूतों को राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है, वे अपने प्रमाणपत्र राष्ट्रपति को ही समर्पित करते हैं।¹

विदेशी राष्ट्रों को राष्ट्रपति ही मायता देता है। सन् 1933 तक अमेरिका ने रूस को मायता प्रदान नहीं की थी। अमेरिका ने अभी कुछ समय पूर्व ही चीन को मायता दी है। उसकी मायता के बाद ही चीन समुक्त राष्ट्र संधि का सदस्य बन सका है। अमेरिका ने नवोदित राष्ट्र बंगला देश को भी काफी समय के पश्चात् मायता दी।

राष्ट्रपति को विदेशों से संधियाँ करने का अधिकार है किन्तु इसके लिये उसे कांग्रेस में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसी संधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन के बर्तर्हि संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। दूरदर्शी राष्ट्रपति संधियों के सम्बन्ध में दोनों दलों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति इस कठिनाई से बचने के लिये एक और उपाय करते हैं जिसे कायपालिका समझौते (Executive Agreements) कहा जाता है। इस प्रकार के कायपालिका समझौतों के लिये कांग्रेस की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। सन् 1901-1909 तक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डोमनीकन रिपब्लिकन तथा जापान के साथ इस प्रकार के समझौते किये थे। उत्तरी अमेरिका की किलेबंदी करने की व्यवस्था इसी प्रकार के समझौतों पर अवलम्बित है।

विदेश सम्बन्धों के संध में राष्ट्रपति को कांग्रेस को समाचार प्रेषित करने का अधिकार है। Doctrine of Isolation, मनरो सिद्धांत, टूमैन सिद्धांत तथा आइजनहायर सिद्धांत इसी प्रकार के संधों के परिणाम थे। अतः राष्ट्रपति विदेश नीति के सम्बन्ध में कांग्रेस को समाचार भेजता रहता है।

अतः राष्ट्रपति विदेश नीति का प्रमुख निर्माता है, वहीं उसके साध्य तथा साधनों की खोज करता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का भार भी राष्ट्रपति पर है। अभी हाल ही में बंगला देश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई कदम उठाये। क्यूबा के विरुद्ध अमेरिका ने जो कदम उठाये उसमें इस प्रकार के उद्देश्य निहित थे।

¹ भारत में जब गैलब्रेथ को राजदूत बनाया गया था उस समय सीनेट ने हिचकिचाहट प्रकट की थी।

हम्फ्री को सघीय व्यापार आयोग (Free Trade Commission) की सदस्यता से केवल इस आधार पर हटा दिया क्योंकि उनके राजनतिक विचारों से उनके विचार मेल नहीं खाते थे। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्पत्ति लिया कि राष्ट्रपति केवल क्षमता के आधार पर ही कमचारियों को पदच्युत कर सकता है और अब किसी आधार पर नहीं। अब कांग्रेस ने योग्यता सिद्धांत का प्रयोग एवं स्वरूप काफी व्यापक बना दिया है। राष्ट्रपति चाहे तो पदों को समाप्त कर सकता है तथा उससे सम्बंधित कमचारियों को हटा भी सकता है। सन 1952 में राष्ट्रपति ट्रूमेन ने मजदूरी स्थिरता बोर्ड (Wage Stabilization Board) को समाप्त कर दिया और उसके समस्त कमचारियों को काम मुक्त कर दिया। परंतु कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पर आसीन कमचारियों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। कांग्रेस भी अपने द्वारा उत्पन्न निगमा एवं बोर्डों के कमचारियों की सेवाओं पर नियंत्रण लगा सकती है। लोक सेवा नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति पदाधिकारियों को हटा सकता है।

(4) प्रशासन का संचालन (Direction of Administration)—राष्ट्रपति मुख्य प्रशासक है। प्रशासकीय विभागों को आदेश देने का उस पूरा अधिकार है। राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह राष्ट्रपति उसी स्थिति में कर सकता है जब उसे प्रशासकीय संचालन का पूरा अधिकार हो। प्रशासकीय कार्य कुशलता एवं स्थायित्व के लिये राष्ट्रपति को अध्यादेश एवं अनुदेश जारी करने तथा नियम एवं उपनियम बनाने का अधिकार है। नियमों तथा उपनियमों के पालन हेतु राष्ट्रपति सेना का भी प्रयोग कर सकता है। सफ़्ट की स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकता है। उसे विभागों को पुनर्गठित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

(5) क्षमादान करने की शक्ति (Power to Grant Pardon)—अमेरिकी संविधान की धारा 2 में अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति कानून के विरुद्ध अपराध करने वालों का क्षमा कर सकता है अथवा दण्ड की मात्रा को कम कर सकता है। उसे दण्ड को कुछ समय के लिये स्थगित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो दण्ड के स्वरूप को भी बदल सकता है, राष्ट्रपति को सामूहिक रूप में भी क्षमादान करने का अधिकार है, सन 1868 में राष्ट्रपति जॉन्सन ने गृहयुद्ध की पृथक्तावादी शक्तियों को सामूहिक रूप में क्षमा किया था।

(6) विदेशिक सम्बन्धों का संचालन (Direction and Conduct of Foreign Relations)—संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विदेशी नीति निर्धारण एवं विदेशिक सम्बन्धों के संचालन का अधिकार किसका है। इस अस्पष्टता का लाभ उठाकर यह अधिकार राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया है। सन 1936 में कर्टिस राइट (Curtis Wright) के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्पत्ति दिया था कि राष्ट्रपति ही विदेशिक सम्बन्धों के निर्देशन का मुख्य अधिकारता है। विदेशिक सम्बन्धों का संचालन करते समय राष्ट्रपति का मीनेट की विशेष सम्बन्ध समिति तथा प्रतिनिधि मंडल की विदेश सम्बन्ध समिति के साथ तालमेल उत्पन्न करना पड़ता है। ये समितियाँ कभी कभी रोड़ा बटका देती हैं। प्रत्येक दूरदर्शी राष्ट्रपति

इन समितियों से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जॉन माशल ने भी राष्ट्रपति को विदेश सम्बन्धों का प्रमुख अधिकृतता कहा है।

विदेश-नीति एवं सम्बन्धों के संचालन में राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है—

राष्ट्रपति राजदूतों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, किंतु इसके लिये उसे सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। किंतु गुप्त दूतों के लिये उसे सीनेट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे दूतों का वेतन राष्ट्रपति स्थायी कोष से दे सकता है। इसके विपरीत विदेशी राजदूतों का राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है, व अपने प्रमाणपत्र राष्ट्रपति को ही समर्पित करते हैं।¹

विदेशी राष्ट्रों को राष्ट्रपति ही मायता देता है। सन् 1933 तक अमेरिका ने रूस को मायता प्रदान नहीं की थी। अमेरिका ने अभी कुछ समय पूर्व ही चीन को मायता दी है। उसकी मायता के बाद ही चीन संयुक्त राष्ट्र सभा का सदस्य बन सका है। अमेरिका ने नवोदित राष्ट्र बंगला देश को भी काफी समय के पश्चात् मायता दी।

राष्ट्रपति को विदेशों से संधियाँ करने का अधिकार है किंतु इसके लिये उसे कांग्रेस में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसी संधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन के वर्साई संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। दूरदर्शी राष्ट्रपति संधियों के सम्बन्ध में दोनों दलों से समायन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति इस कठिनाई से बचने के लिये एक और उपाय करते हैं जिसे कायपालिका समझौते (Executive Agreements) कहा जाता है। इस प्रकार के कायपालिका समझौतों के लिये कांग्रेस की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। सन् 1901-1909 तक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डोमनीकन रिपब्लिकन तथा जापान के साथ इस प्रकार के समझौते किये थे। उत्तरी अमेरिका की क्लिबर्टी करने की व्यवस्था इसी प्रकार के समझौतों पर अवलम्बित है।

विदेश सम्बन्धों के सन्ध में राष्ट्रपति को कांग्रेस की समाचार प्रेषित करने का अधिकार है। Doctrine of Isolation, मनरो सिद्धांत, ट्रूमन सिद्धांत तथा आइज़नहावर सिद्धांत इसी प्रकार के सन्धों के परिणाम थे। अतः राष्ट्रपति विदेश नीति के सम्बन्ध में कांग्रेस की समाचार भेजता रहता है।

अतः राष्ट्रपति विदेश नीति का प्रमुख निर्माता है, वही उसके साध्य तथा साधनों की खोज करता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का भार भी राष्ट्रपति पर है। अभी हाल ही में बंगला देश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई कदम उठाये। क्यूबा के विरुद्ध अमेरिका ने जो कदम उठाये उसमें इस प्रकार के उद्देश्य निहित थे।

¹ भारत में जब गसट्रेथ को राजदूत बनाया गया था उस समय सीनेट ने हिचकिचाहट प्रकट की थी।

(7) सैनिक शक्ति (Military Power)—राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति है। यद्यपि राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने का अधिकार नहीं है, किंतु वह ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य ही उत्पन्न कर सकता है जिसके अंतर्गत युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त अब कोई विकल्प शेष न रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही स्वतंत्रता से करते रहे हैं। राष्ट्रपति पोक ने मैक्सिको में तथा मैककिलने ने स्पेन में युद्ध इसी रूप से आरम्भ किये। राष्ट्रपति ट्रूमेन ने साम्यवादियों की प्रगति को नियंत्रित करने के लिये दक्षिणी कोरिया में सेना भेज कर युद्ध स्वीकार करने के लिये कांग्रेस को विवश किया, राष्ट्रपति आइजनहावर, कैंनेडी तथा जॉन्सन ने वियतनाम युद्ध में इसी प्रकार अमेरिका को घस्त किये रखा। सन् 1970 में राष्ट्रपति निक्सन के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह बिना कांग्रेस की सहमति के अमेरिका को किसी भी युद्ध में नहीं उलझा सकेंगे।

युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियों में जितनी तेजी के साथ विकास होता है। वैसा शांति काल में हम देखने को नहीं मिलता। प्रधान सेनापति होने के कारण इसका निणय राष्ट्रपति ही करता है कि कब और कहाँ सैनिक दस्ते भिजवाये जाय। युद्ध काल में तो राष्ट्रपति सही अर्थों में राष्ट्र का नेतृत्व करता है। वह सवधानिक अधिनायक बन जाता है। कांग्रेस राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियों (Blanket Powers) के प्रयोग की अनुमति देकर उसे सविवेक निणय करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, वैसे तो उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों का सदैव ही समयन किया है किंतु पल हारबर घटना के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्धावधि में हवाई द्वीप में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा जो मासल लॉ लगाया गया था उसका समयन उसने नहीं किया था। राष्ट्रपति ट्रूमेन ने कोरिया युद्ध के मध्य इस्पात मिलों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों की हड़ताल का भय था, किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसका समयन नहीं किया और इसे कांग्रेस का अधिकार बताया।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

(Legislative Powers)

शक्तियों के पृथक्करण पर अवलम्बित होने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। किंतु वास्तविकता यह है कि वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति प्रमुख विधायक भी बन गया है। अब यह ठीक ही कहा गया है कि जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रपति का व्यवस्थापन में कोई हाथ नहीं होता वे वास्तविकता से हटकर कल्पना में वृहते हैं।¹ विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली है जितना कि कार्यपालिका क्षेत्र में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ निम्न लिखित हैं

1. कांग्रेस के अधिवेशनों पर नियंत्रण (Control over the Sessions of the Congress)

राष्ट्रपति इस बात का निश्चय करता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब बुलाया जाय। साधारण अधिवेशनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को असाधारण तथा विशेष दोनों

1 To say that President has no hand in legislation is to talk logic not fact

प्रकार के अधिवेशन आमंत्रित करने का अधिकार है। सन् 1933 के बीसवें सत्रोघन ने इस बात की सम्भावनाओं को कम कर दिया है क्योंकि जब ह्वाइट हाउस का नवीन अधिकारी राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है। शीतकालीन अधिवेशन के समाप्त होने पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। विशिष्ट अधिवेशन के लिये राष्ट्रपति ट्रूमेन ने कांग्रेस के सदस्यों को सन् 1948 में पुन बुला भेजा जबकि सदस्य कठिनाई से अपने घर पहुँच पाये थे। सन् 1934, 1935 तथा 1937 में विशेष विधायी कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस के अधिवेशन को बड़ा दिया था। कांग्रेस के अधिवेशनो को स्थगित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति का ही है, यद्यपि इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया।

2 सन्देश भेजने की शक्ति (Power to send Messages)

अमेरिकी संविधान की धारा दो के अंतर्गत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की गतिविधियों के विषय में कांग्रेस को सूचित करता रहे। परिस्थितियों का सामना करने के लिए वह कानूनी प्रावधानों की भी सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति सन्देश भेजकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कांग्रेस के समक्ष कर सकता है। सन्देश भेजना राष्ट्रपति की शक्ति नहीं अपितु कर्तव्य है, कि तु वर्तमान परिस्थितियों में यही उसकी शक्ति भी बन गया है। सन्देश कांग्रेस को प्रभावित करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। कांग्रेस के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में राष्ट्रपति सन्देश भेजता है जिसमें विविध महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की जाती है। प्रथम दो राष्ट्रपति—वाशिंगटन तथा जॉन एडम्स—स्वयं कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी समस्याएँ रखते थे किंतु इस प्रथा को तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफरसन ने समाप्त करके लिखित सन्देश की परम्परा को जन्म दिया। यह प्रथा सन् 1809 से लेकर सन 1913 तक चलती रही। सन 1913 में राष्ट्रपति विल्सन ने पुरातन प्रथा को प्रारम्भ करके कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ में स्वयं उपस्थित होकर अभिभाषण करने की प्रथा को प्रारम्भ किया, इसका समस्त राष्ट्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति कई बार कांग्रेस के नाम रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से भी सन्देश प्रसारित करता है, कई बार राष्ट्रपति इन लिखित सन्देशों के माध्यम से विषय अधिकारों की माँग करता है। सन् 1933 में बैंक संकट के समय राष्ट्रपति ने विशेष अधिकारों की माँग की थी तथा इसी प्रकार 1950 में भी ट्रूमेन ने विशेष अधिकारों की माँग की थी। सन् 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 'कायपालिका में सुधार करने के प्रस्तावों पर विशेषाधिकारों की माँग की थी। राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित प्रलेखों को अथ उच्चस्तरीय प्रलेखों की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। 'मुनरो सिद्धांत', विल्सन की चौदह सूत्री योजना (Fourteen Points) तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चार स्वतंत्रताओं (Four Freedoms) की रचना भी सन्देशों के ही रूप में हुई थी। जब भी कांग्रेस को ये सन्देश प्राप्त होते हैं तब सदन अथ कार्यवाहियों को स्थगित करके अपना सम्पूर्ण ध्यान इस ओर लगा देता है। मुनरो के शब्दों में ये सन्देश इंग्लैंड में राजा के अभिभाषण की तरह कोई भविष्यवाणी नहीं करते।¹

1 A President's annual Message is not like the speech from the throne in England accurate forecast of what will go on the statute book before the session ends

3 विधायी क्षेत्र का नेतृत्व (Legislative Leadership)

मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था व अभाव में व्यवस्थापन के लिए बहुत कुछ सीमा तक कांग्रेस को कार्यपालिका (राष्ट्रपति) पर व्यवस्थापकीय नेतृत्व के लिए निर्भर रहना पड़ता है। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखेगा। इसी आधार पर कई राष्ट्रपतियों ने विधायी क्षेत्र के नेतृत्व को ग्रहण करने की चेष्टा की है। विल्सन, रूजवेल्ट, हैरी, ट्रूमैन, कैंनेडी तथा जॉर्जन आदि ने भी विधायी क्षेत्र में नेता के रूप में व्यवहार किया। यह सच भी है क्योंकि अधिकतर महत्वपूर्ण विधेयक स्वयं राष्ट्रपति द्वारा अथवा उसके कमचारियों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। कांग्रेस कई रूप से उनमें सशोधन रखती है किंतु फिर भी उनमें कई बार गम्भीर कमियाँ रह जाती हैं जिनसे राष्ट्रपति की इच्छा स्पष्ट रूप से पलकती है।

4 निषेधाधिकार (Power of Veto)

संविधान की धारा 8 प्रावधान 7 के अन्तर्गत निषेधाधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार कर दे अथवा अपने सशोधनों सहित उस सदन के पास भिजवा दे जहाँ पर वह प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की यह शक्ति पूर्ण नहीं है वरन् वह केवल निलम्बनकारी निषेधाधिकार (Suspensory Veto) है। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत अथवा समोद्धित विधेयक यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में पृथक पृथक रूप में उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसके मूलरूप में पुनः स्वीकार कर लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की बिना अनुमति के भी कानून बन जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि हम समझते हैं।

इसके विपरीत राष्ट्रपति के पास पॉकेट निषेधाधिकार (Pocket Veto) की शक्ति भी है। जिस तिथि को राष्ट्रपति के पास कांग्रेस द्वारा स्वीकृत विधेयक आता है उससे 90 दिन की अवधि में राष्ट्रपति को या तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा उसे वापस करना चाहिए और यदि इन दोनों में से राष्ट्रपति किसी भी भाग को नहीं अपनाता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार समझा जाता है। "यवहार में यह देखा जाता है कि सत्र के अंतिम दिनों में विधेयकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। राष्ट्रपति उनमें से जिन विधेयकों से प्रसन्न नहीं रह पाता उन्हें इस प्रकार से रखता है कि वे सत्रांत तक स्वीकार न हो ऐसे विधेयकों का उस समय लिया जाता है जबकि सत्र के समाप्त होने में 90 दिन से कम समय रह जाता है। प्रत्येक वर्ष ऐसे बहुत से विधेयक समाप्त होते हैं। राष्ट्रपति की इस युक्ति को पॉकेट निषेधाधिकार (Pocket Veto) कहा जाता है किंतु इसका प्रयोग वह सावधानी एवं कुशलतापूर्वक करता है। सत्र के समाप्त होने पर जो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं होते वे गले हुए माने जाते हैं। राष्ट्रपति की यह निषेधाधिकार शक्ति समाप्त नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति जैक्सन (Jackson) से पूर्व राष्ट्रपति केवल उन विधेयकों को ही निषेधित (Veto) किया करता था जो कि संविधान के विरुद्ध हुआ करते थे। किन्तु राष्ट्रपति जैक्सन के पश्चात् राष्ट्रपति ऐसे

विधेयको को भी अस्वीकार कर देता है जोकि उसके विवेक के अनुकूल न हो। राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर राष्ट्रपति कैनेडी तक कुल मिलाकर 2,217 बार राष्ट्रपति द्वारा निपेधाधिकार शक्ति का प्रयोग हुआ है। इनमे से 1283 बार नियमित निपेधाधिकार तथा 934 बार पौकिट निपेधाधिकार का प्रयोग किया गया है। इनमे से केवल 72 निपेधाधिकार कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से अस्वीकार कर दिए गए। राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड ने 584 बार निपेधाधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 631 बार निपेधाधिकार का प्रयोग किया। इनमे से केवल 9 निपेधाधिकार कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किये गये। कुछ राष्ट्रपतियों के उदाहरण सख्या सहित, जिन्होंने निपेधाधिकार का प्रयोग किया, इस प्रकार हैं —

वाशिंगटन	2 बार	
जेम्स मीडोसन	7 बार	
जैक्सन	12 बार	
रण्डू जॉनसन	28 बार	
ग्राट	92 बार	
क्लीवलैण्ड	414 बार	पहली अवधि मे तथा 170 बार दूसरी अवधि मे
ग्रियोडर रूजवेल्ट	82 बार	
कलिज	72 बार	
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट	631 बार	
ट्रूमेन	250 बार	
आइजन हावर	181 बार	
कैनेडी	25 बार	
जॉनसन	21 बार	

इस प्रकार राष्ट्रपति का निपेधाधिकार अमर्यादित प्रकार का नहीं है। व्यवहार मे राष्ट्रपति जन भावना की ध्यान मे रखकर ही निपेधाधिकार के अधिकार का प्रयोग करता है। निपेधाधिकारो को बहुत सी बार कांग्रेस के द्वारा रद्द किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस भी इस दिशा मे सजग रहती है। निपेधाधिकार के अधिकार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मुनरो ने लिखा है कि "जिसे कायपालिका की आत्मरक्षा हेतु बनाया गया था वह राष्ट्र के कानून निर्माण प्राधिकरण के संचालन तथा भागदशन मे भी विकसित हो गया है। निपेधाधिकार की शक्ति के विषय मे आग तथा रे ने लिखा है कि निपेधाधिकार मे इतनी बढि हो गई है कि वह विधेयक को दोहराने की सामा य शक्ति धन गई है।"¹

हरमन फाइनर के शब्दो मे 'यह एक ऐसी शक्ति है जिसमे कोई व्यय नहीं होता, जिसका प्रयोग काफी सफलता के साथ किया जा सकता है और जिस पर कोई दण्ड नहीं है।'²

1 The veto power has been so expanded by usage as to become a general revising power applicable to all legislation —Ogg & Ray

2 Here is a power with no expenditure and which can be used with a fair prospect success and no punishment —H Finer

सविधान के अतिरिक्त राष्ट्रपति के विधायी क्षेत्र में प्रभाव के साधन (Extra constitutional Means to Influence Legislation)

(1) सरक्षण की शक्ति (Power of Patronage)—राष्ट्रपति टाफ्ट ने एक बार कहा था कि सरक्षण शक्ति से उसकी विधायी शक्तियाँ बढ गई हैं। सरक्षण शक्ति से राष्ट्रपति की शक्तियों में आशातीत विकास हुआ है। राष्ट्रपति के हाथों में बहुत सी नियुक्तियाँ रहती हैं। कांग्रेस के सदस्य उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वे राष्ट्रपति से साक्षात्कार करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विविध प्रकार के काय करा कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। सरक्षण शक्ति के माध्यम से ही बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति व्यवस्थापन को प्रभावित करता है। कायपालिका की एजेंसियों से कांग्रेस के सदस्य निरंतर सम्पर्क बनाये रखते हैं। सरक्षण अनुग्रह का एक प्रभावशाली साधन है। लूट खसोट प्रणाली का ज म इसी के द्वारा हुआ है।

(2) व्यक्तिगत सम्पर्क तथा अनुग्रह (Personal Contacts and Persuasion)—राष्ट्रपति अपने दल के कांग्रेसी सदस्यों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखता है। वह उन्हें प्रायः ह्वाइट हाउस में चाय अथवा भोजनों पर आमन्त्रित करता है। उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करता है उनके दृष्टिकोण को सुनने तथा समझने की कोशिश करता है, कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति के दृष्टिकोण को अग्रे सदस्यों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति समितियों (Committees) के सदस्यों से भी सम्पर्क स्थापित करता है और व्यवस्थापन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक विधेयक उस रूप में पारित होता है जिस रूप में कि राष्ट्रपति चाहता है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट जा सन कैंनेडी तथा नक्सन ने इस पद्धति का काफी प्रयोग किया है।

(3) निषेधाधिकार की धमकी (Threat of Veto)—निषेधाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति एक धमकी के रूप में कर सकता है। यदि विधेयक उस रूप में है जिससे राष्ट्रपति की इच्छाओं को आघात पहुँचता है अथवा वह इस रूप में नहीं है जैसा कि राष्ट्रपति चाहता है तो उसे अस्वीकार करने की धमकी राष्ट्रपति दे देता है। निषेधाधिकार की धमकी कांग्रेसजनों के कान खड़े कर देती है। वे चौकने होकर राष्ट्रपति की इच्छाओं पर पुन विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने सवप्रथम इस साधन का प्रयोग किया जोकि बहुत ही अनुकूल सिद्ध हुआ। राष्ट्रपति हैनरी ट्रूमेन ने इस साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया। उन्होंने 250 विधेयकों पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयोग किये हुए निषेधाधिकारों में से कांग्रेस ने केवल 12 को रद्द किया।

(4) राष्ट्रपति की लॉबी (Presidents Lobby)—व्यवस्थापन को प्रभावित करने में राष्ट्रपति ही अकेला नहीं है। उसे अग्रे साधनों से भी कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करने के अवसर मिलते हैं। वह प्रशासकी विभागीय अध्यक्षों व्योरो के निदेशकों एव आयोगों के आयुक्तों के माध्यम से विधायकों को अपने मत के अनुकूल लाने की चेष्टा करता है। इसी को राष्ट्रपति की लॉबी कहा जाता है।

(5) जनता का समर्थन प्राप्त करके (By Winning Public Support)—

कांग्रेस पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये राष्ट्रपति को जनता का समर्थन प्राप्त करना होता है। कांग्रेस भी जनमत की अवहेलना करने का साहस नहीं करती। दूरदर्शी राष्ट्रपति जनमत निर्माण के समस्त तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करते हैं। टेलीविजन, रेडियो प्रेस सम्मेलन एवं भाषण आदि सबका खुलकर प्रयोग किया जाता है। पियोडर रूजवेल्ट ने प्रेस सम्मेलनों का इस व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया कि ह्वाइट हाउस को धर्मोपदेशों का सबसे बड़ा आसन कहा जाने लगा। वाशिंगटन द्वारा सगठित अन्त-साप्ताहिक सम्मेलनों को सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति अपने को प्रभावशाली बनाये रखने के लिये जनता के दृष्टिकोण तथा विचारों को अपने पक्ष में करने के लिये उद्दीप्त रहता है। वह जनमत को उभारने की धमकी कांग्रेस को दे सकता है और कई बार ऐसा हुआ भी है और कांग्रेस को उसकी बात के समक्ष जनमत भय के कारण झुकना पड़ा है।

(6) दल का नेता (Leader of the Party)—राष्ट्रपति को दलगत स्थिति से ऊपर रखने हेतु संविधान निर्माताओं के प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अब पूर्णतः दलीय आधार पर होता है। दलीय नेतृत्व की दृष्टि से वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कम नहीं पड़ता। उसकी विधायी शक्ति किसी भी व्यावहारिक पहलू से कम नहीं कही जा सकती। दल के प्रतिष्ठित व्यक्ति ही उसके मंत्रिमण्डल का निर्माण करते हैं। दलीय नीति के लिये उसे अपने सहयोगियों पर स्वाभाविक रूप से अवलम्बित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय प्रेरणा एवं जन भावना का राष्ट्रपति प्रतिनिधि बन गया है। वह सर्वोच्च नेता तथा दल का प्रमुख निदेशक है। दलीय निर्वाचनों में उसका विशेष हाथ रहता है, संवत्कालीन स्थिति में तो राष्ट्रपति का स्तर बहुत ऊँचा उठ जाता है। यदि राष्ट्रपति कांग्रेस में बहुमत खो बैठता है तो उसे अनुरोधवादी, निषेधाधिकारवादी समझौतावादी तथा संरक्षणवादी बनना पड़ता है। राष्ट्रपति का दल यदि कांग्रेस में भी प्रभावशाली है तो उसकी स्थिति प्रधानमंत्री से भी अधिक सबल एवं सफल मानी जा सकती है। फिर भी दलीय अनुशासन की कठोरता के अभाव में उसकी स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं कही जा सकती, जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की। राइकर (Riker) ने कहा है कि “राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकार में मजबूत है, परंतु दल में कमजोर है। उसके विधान सम्बन्धी नेतृत्व के दो रूप हैं और इसलिये उसका यह नेतृत्व अबोध नहीं रहता, वह खण्डित हो जाता है।”¹

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers of the President)

अब राष्ट्रपति के सदृश राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध अपराध करने वालों को वह क्षमा कर सकता है, वह सामूहिक रूप में भी क्षमादान (Amnesty) प्रदान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है किन्तु राष्ट्रपति उन व्यक्तियों का समा नहीं कर सकता जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा दण्डित किया गया हो।

1 Strong in prerogative weak in party It is this dual nature of his legislative leadership that makes it so curiously intermittent
—Riker

सन् 1868 में राष्ट्रपति ने सामूहिक दामादान का परिचय दक्षिणी अमेरिका के उन व्यक्तियों को दामा करके दिया था जिन्होंने कि गृह युद्ध में भाग लिया था।

राष्ट्र का नेता (Leader of the Nation)

राष्ट्रपति केवल बायपालिका का ही नेता नहीं होता अपितु वह सम्पूर्ण राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करता है। उसकी नीतियाँ राष्ट्र की नीतियाँ हैं। राष्ट्रपति स्वयं ही नेता एवं प्रधानमन्त्री है। उसमें सम्राट तथा प्रधानमन्त्री दोनों के ही अधिकार पाये जाते हैं। प्रधानमन्त्री की भाँति वह विधियों की व्यवस्था का भी प्रमुख निर्माता है। उसने चारों ओर प्रेस प्रतिनिधियों एवं प्रतिवेदकों का जमघट लगा रहता है जो इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय रंगमंच का एकमात्र उन्मायक है। राष्ट्रपति सम्राट की भाँति राष्ट्रीय एकता का औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व भी करता है। वह अमेरिका की जनता से वही सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जोकि वहाँ एक सम्राट को प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसका सम्मान राष्ट्र की सम्पत्ति है जिसको निर्माता स्वयं जनता है। उसे राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित अनेकों प्रकार के काम करने पड़ते हैं। ग्राइस का यह कहना सत्य है कि 'राष्ट्रपति जनमत संग्रह करके कांग्रेस के दोनों सदनों से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है।'¹

राष्ट्रपति की सङ्कटकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers of the President)

अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की सङ्कटकालीन शक्तियों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं है, सम्भवतः संविधान निर्माताओं ने कभी उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं की। किन्तु सङ्कटकालीन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उसकी शक्तियों का विकास हो जाता है। कांग्रेस उसे अपना पूरा सहयोग देती है उच्चतम न्यायालय भी अधिक हस्तक्षेप नहीं करता। गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति लिंकन को परिस्थितियों से निपटने के लिये शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी पूरी छूट दी गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रपति विल्सन को कांग्रेस ने सन् 1918 तक इसी प्रकार की छूट दी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने ही ढंग से शक्तियों का प्रयोग किया। सन् 1942 में कांग्रेस के नाम अपने प्रेषित संदेशों में राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि कांग्रेस ने सङ्कटकालीन मूल्य नियन्त्रण (Emergency Price Control) के अनुसार मजदूरी तथा मूल्यों को स्थिर करने के उपायों पर स्वीकृति नहीं दी तो वह देश को आर्थिक सङ्कट तथा तबाही से नहीं बचा सकेगा। सन् 1950 में दक्षिणी कोरिया की रक्षा में राष्ट्रपति ट्रुमेन ने सेनाएं भेजी। सन् 1962 में क्यूबा से उत्पन्न परिस्थितियों के लिये राष्ट्रपति को समुद्री नाकेबंदी करनी पड़ी। भारत-पाक युद्ध के समय सन् 1971 में राष्ट्रपति निसन ने विश्व जनमत तथा भारत की मैत्री की अवहेलना करते हुए भी अपने सातवें समुद्री बेड़े को बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सहायता का प्रदर्शन करने तथा भारत-पाक युद्ध के अन्त में पाकिस्तान का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस तथा उ-वाव डालने के अ-य के अ-ए भी राष्ट्रपति अधिनायक से कम शक्तिशाली

¹ With public opinion behind him of the Congress

अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति (Position of the President of America)

सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति को चाहे इतना शक्तिशाली न बनाया गया हो किंतु व्यवहार में उसे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों में (प्रशासकों में) सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वह कायपालिकाध्यक्ष ही नहीं अपितु व्यवहार में वह प्रमुख विधिवेत्ता भी है। असाधारण परिस्थितियों में तो वह विश्व के किसी भी तानाशाह से कम नहीं है। वह स्वयं ही सम्राट एवं प्रधानमन्त्री है। किंतु वह हिटलर अथवा मुसोलिनी भी नहीं है। सीनेट तथा सुप्रीमकोर्ट का अकुशल इतना प्रबल है कि राष्ट्रपति निरपेक्ष शक्तियों का अधिष्ठाता नहीं बन सकता। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रदर्शन केवल संकट काल में ही कर सकता है और उसमें भी कांग्रेस का योग कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार हमें ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की शक्तियों का परिचय दोनों विश्व युद्धों के काय काल में प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार इन दो महायुद्धों में हमें राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है। गिरफ्तार का यह कहना सही है कि आज की विपन्न परिस्थितियों में जब तक राष्ट्रपति शक्तिशाली एवं निष्ठावान नहीं होंगे तब तक संविधान द्वारा राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। शांति काल में भी राष्ट्रपति राष्ट्र को कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति आज भी विश्व का महान व्यक्ति है। सिडनी साइमन के शब्दों में “अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिकी सैनिक कूटनीतिक तथा आर्थिक नीतियों के लिये आधारभूत नीतियों को प्रस्तावित करने के अतिरिक्त अन्य विविध कार्यों का भी सम्पादन करता है।”¹ लास्की के शब्दों में ‘अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख है।’² ब्राइस के शब्दों में “जनमत को अपने पक्ष में करके वह कांग्रेस के दोनों सदनों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है।”³ राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो, तब कोई अकेली शक्ति उसका मुकाबिला नहीं कर सकती, कई शक्तियों का संगठन भी उसे सरलता में नहीं हटा सकता।”

भोगन के विचार में संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति अपने काय काल के लिये सप्ताह के एकतन्त्री शासकों में से है, जिसके प्राधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, हाँ। उनमें बढि अवश्य है। सकती है।’ ऑग तथा रे के शब्दों में ‘यूरोप के तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका में राष्ट्रपति के मुकाबिले में किसी के पास भी इसनी शक्ति नहीं है और यह भी तब है जब कि संविधान ने उसके ऊपर पर्याप्त प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।”⁴ यह सत्य है कि अमेरिकी जनता द्वारा चार वर्ष के लिये

- 1 The American President does more than propose ground rules for American military, diplomatic and Economic policies —Sidney Hyman
- 2 American President is the head of the national life —Lasky
- 3 With opinion behind him he may prove stronger than both houses of the Congress —Bryce
- 4 Its occupant has become with the exception of certain of Europe's dictators the most powerful head of a Government known to one day —Ogg and Ray

एक बादशाह का निर्वाचन होता है। कुछ प्रतिबन्धों के साथ जनता उसके हाथों में निरपेक्ष शक्ति समर्पित कर देती है। पुनः ग्राइस के शब्दों में "जनता राष्ट्रपति के भाषणों को पढ़ती है कांग्रेस के अभिलेखों को नहीं, राष्ट्रपति का एक गौरवाचित व्यक्तित्व है वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर प्रकाश पुञ्ज पड़ता है।" ¹ ब्रोगन (Brogan) ने राष्ट्रपति की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए और भी आगे लिखा है कि "अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य ही नहीं करता है, इसके अतिरिक्त वह और भी बहुत से ऐसे काम करता है जोकि खिचाव उत्पन्न करने के मूल कारण होते हैं। उनमें राजा के प्रति उठने वाली भावनाएँ और श्रमिकों की तरह परिश्रम करने वाले एकात्मक प्रशासन के प्रधानमन्त्री का नेतृत्व होना भी है।" पुनः लास्की के शब्दों में "अमेरिका का राष्ट्रपति राजा से कम तथा अधिक दोनों ही है वह प्रधानमन्त्री से भी कम तथा अधिक दोनों ही है।"

अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति कुछ विचित्र ही है, मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि जिस ढंग से अमेरिका के कुछ राष्ट्रपतियों ने जनतन्त्रीय सीमाओं का उल्लंघन करके निरपेक्ष नीतियों का पालन किया है वह लोकतन्त्र के लिये अधिक आशावादा नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ—जन भावनाओं के सम्मान की उपेक्षा करके दक्षिणी विधतनाम तथा भारत उपमहाद्वीप में अमेरिका की जिस नीति का प्रतिस्थापन राष्ट्रपति निक्सन द्वारा हुआ वह लोकतन्त्र के लिये चेतावनी है। नियुक्ति तथा संरक्षण अधिकारों के कारण ही राष्ट्रपति शक्तिशाली बना है, परन्तु प्रशासन में कार्यकुशलता की दृष्टि से उसको स्वच्छ नहीं कहा जा सकता। यह भी सत्य ही है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि उनसे किसी समय भी संविधान को खतरा उभर हो सकता है तथा शक्ति प्रयत्नकरण का स्वप्न भी भग हो सकता है। आज सम्पूर्ण राष्ट्र ह्वाइट हाउस की ओर दृष्टि लगाए खड़ा रहता है। यद्यपि अमेरिका में दलीय अनुशासन इतना भयंकर नहीं है परन्तु जिस मात्रा में भी है उसने भी, उसके महत्व को प्रबल रूप में बढ़ावा दिया है।

राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण (Reasons for the Increase in Presidential Powers)

(1) व्यक्तित्व (Personality)—अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं भी अपनी शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। राष्ट्रपति निक्सन से पूर्व के राष्ट्रपतियों ने अपनी शक्तियों के सम्बन्ध में संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया था किन्तु उसके पश्चात् उनका दृष्टिकोण समय की माँग के साथ बदलता गया। राष्ट्रपति निक्सन ने स्वयं भी कांग्रेस को अपने नियन्त्रण में लेकर प्रशासन पर छाये रहने के लिए प्रयत्न किये। इसके पश्चात् तो रूजवेल्ट टाफ्ट, विल्सन जानसन, कनेडी तथा निक्सन आदि राष्ट्रपतियों ने इस पद के सम्मान को ऊँचा उठाने में अपना पूरा अनुदान प्रदान किया तथा सरकार के अग्र अंगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

(2) संकटकालीन परिस्थितियाँ (Emergencies)—अमेरिकी राष्ट्रपति की

1 The people read his speeches and do not read Congressional Records. It is a personality—a single figure on which fierce light beats —Bryce

शक्तियों में विकास का एक कारण राष्ट्रीय आपत्तियों का भी है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब भी राष्ट्र पर आपत्तियाँ आई हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में विकास उसी अनुपात में हुआ है राष्ट्रपतियों ने अपनी शक्तियों को निरपेक्ष रूप दिया है। सन् 1914-18 तक राष्ट्रपति विल्सन ने अपने ही ढंग से शक्तियों का प्रयोग किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय एक तानाशाह का सा परिचय दिया, राष्ट्रपति कनेडी ने ब्यूबा की समस्या से निपटने के लिए असंमित शक्ति का परिचय दिया। कोरिया, वियतनाम, मध्यपूर्व आदि की समस्याओं से निपटने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने अपने सिद्धांतों एवं नीतियों का प्रतिपादन किया। द्रूमैन तथा आइजनहावर सिद्धांत इसी के परिणाम हैं। शीत युद्ध की परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति के सश्र्वेक निणयों ने अधिकारों में व्यापक रूप से वृद्धि कर दी है।

(3) दल प्रथा का विकास (Rise of Party System)—अमेरिका में दल प्रथा के विकास के फलस्वरूप राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में सम बय स्थापित होना सम्भव हुआ है, यद्यपि वहाँ दलीय अनुशासन उतना उग्र नहीं है जितना कि वह ब्रिटेन में है। किंतु फिर भी उसके माध्यम से राष्ट्रपति अपने मूल के विधायकों से कांग्रेस में समर्थन प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार विधायी क्षेत्र में भी उसके प्रभाव में वृद्धि हुई है।

(4) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति (Election System of the President)—राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष हो गया है। प्रत्यक्ष होना से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। वह सही अर्थों में जननायक बन गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार उसे प्राप्त हो चुका है। कांग्रेस के उफान एवं विरोध की उग्रता को वह जनता से अपील तथा उसके सहयोग को संगठित करके शांत कर सकता है।

(5) सघीय कानून (Federal Laws)—यदि इसको हम प्रदत्त अथवा प्रत्यायोजित व्यवस्था कहें तो अधिक उचित होगा। समय समय पर राष्ट्रपति ने विविध समस्याओं से निपटने के लिए कांग्रेस से शक्तियाँ प्राप्त की हैं। सन् 1933 में आर्थिक मंदी को रोकने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति को विविध शक्तियाँ प्रदान की, सन् 1941 का Land Lease Act तथा सन् 1949 का Reorganization Act इसी प्रकार के उदाहरण हैं।

(6) निश्चिष्टता (Usages)—राष्ट्रपति की शक्तियों के विकास में परम्पराओं का भी अनुदाय है। राष्ट्रपति सैनीटोरियल कटसी का प्रयोग करके बहुत सी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सीनेट की निश्चरता से बच जाता है। इसी प्रकार वह अपने दल की कार्यकारिणी के चेयरमैन की नियुक्ति करके दल पर प्रभावी बना रहता है। अनौपचारिक रूप से अपने निवास पर कांग्रेस के सदस्यों को चाय अथवा भोजन पर आमंत्रित करके महत्वपूर्ण समस्याओं को निपटा लेता है तथा एक नूतन दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है।

(7) राज्य का कल्याणकारी स्वरूप (Welfare State)—प्रगतिवादी युग के साथ-साथ अमेरिकी राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। उसका स्वरूप लोक-कल्याणकारी आदर्श से प्रभावित हुआ है। लोककल्याणकारी स्वरूप के कारण राष्ट्रपति

को विविध प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। इससे उसकी शक्तियाँ मे आशातीत बढ़ि हुई है।

(8) सरक्षण (Patronage)—हम राष्ट्रपति के सरक्षण अधिकार का वर्णन इसी अध्याय में अग्रिम भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष हजारों नियुक्तियाँ करनी पड़ती हैं जिनके माध्यम से वह राष्ट्र के विविध दृष्टिकोणों को समुचित करके अपने पक्ष में ले लेता है। इसी के माध्यम से वह कांग्रेस में भी सदस्यों के ऊपर भी प्रभावशाली बना रहता है।

(9) संवैधानिक महत्व के निर्णय (Decisions of Constitutional Importance)—राष्ट्रपति की शक्तियाँ व विकास में 'पायपालिका' के निर्णयों एवं व्याख्याओं का बहुत बड़ा महत्व है। निहित अधिकारों के सिद्धांत द्वारा सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त मात्रा में विकास किया है। मन् 1926 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रपति को अपने पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार है, इसमें सीनेट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट तथा प्रधानमंत्री से तुलना
(Comparison of the President of U S A with the British King and the Prime Minister)

प्रो० एच० जे० लास्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट तथा राष्ट्रपति से तुलना करते हुए कहा है कि 'अमेरिकी राष्ट्रपति सम्राट से कम शक्तिशाली तथा अधिक शक्तिशाली दोनों ही है, वह प्रधानमंत्री से भी कम तथा अधिक दोनों ही है।'¹

यद्यपि दोनों ही राष्ट्रध्यक्ष हैं किंतु सबसेप्रथम हमें लास्की के कथन के इस भाग पर विचार करना होगा कि ब्रिटिश सम्राट की अपेक्षा राष्ट्रपति किन बातों में अधिक है और किन बातों में कम है अथवा उसकी स्थिति कमजोर है।

(1) अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की अपेक्षा किन बातों में अच्छी है ? (In what respect the American's President holds a Position of Superiority to British King)

(क) शक्तियों की वास्तविकता की दृष्टि से (Reality of Powers)—अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में सिद्धांत अथवा व्यवहार दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, वह अपनी शक्तियों का स्वयं अधिष्ठाता है और उनका वास्तविक रूप में प्रयोग भी करता है। उसकी शक्तियाँ केवल अलंकार मात्र ही नहीं हैं युद्ध तथा संधि के समय तो उसमें आशा एवं कल्पना से भी अधिक बढ़ि जा जाती है। राष्ट्रपति जक्सन के पश्चात् अमेरिका में जासन रूजवेल्ट व्नेडो टूमेन आदि राष्ट्रपतियों ने शक्ति का वास्तविक प्रयोग किया है। ब्रिटिश सम्राट सिद्धांत रूप में तो सब कुछ है अर्थात् 'पाय एवं विधि का स्रोत है किंतु व्यवहार में वह स्वर्ण शून्य अर्थात् केवल निर्जीव रबड़ की मोहर की भाँति है, (Goldenless & Lifeless Rubber

1 The American President is both more or less than the British King he is also both more or less than the Prime Minister —Lasky

Stamp) वह तो केवल शासन करता है नियंत्रण नहीं करता इसके विपरीत अमेरिका का राष्ट्रपति नियंत्रण करता है शासन नहीं करता, राजा की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल करता है।

(ख) राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से (From the Standpoint by National Leadership)—अमेरिका का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। किंतु व्यवहार में उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ही हो गया है। वह जनभावना का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रेस, टेलिविजन तथा रेडियो प्रसारण के द्वारा जनमन को अपने पक्ष में करता है काँग्रेस पर भी प्रभावी होने की कोशिश करता है। अपनी बात को राष्ट्र के समक्ष रखता है। किंतु इसके विपरीत इंग्लैंड का राजा राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता वह राष्ट्रीय भावना का भी प्रतीक नहीं है। वह तो केवल उत्तराधिकार नियम के आधार पर ही शक्ति प्राप्त करता है जोकि अथ एव निराधार ही है।

(ग) दलीय नेतृत्व की दृष्टि से (Leadership of the Party)—राष्ट्रपति राष्ट्र की राजनीति का सक्रिय अंग है। राष्ट्रीय राजनीति ह्वाइट हाउस के चारों ओर घूमकर लगाती रहती है। वह अपने दल का शक्तिशाली नेता होता है और अपने दल की राष्ट्रीय कायपालिका के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है और दल तथा शासन की नीतियों में सम उग्र उत्पन्न करता है। परंतु ब्रिटिश सम्राट यह सब कुछ नहीं करता, वह दलीय भावना से ऊपर है। क्योंकि वह दलगत राजनीति का संपासक नहीं होता है इसीलिए वह दलीय नेतृत्व भी नहीं करता है।

(घ) विधायी शक्तियों की दृष्टि से (Legislative Powers)—विधायी क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट से कहीं अधिक अच्छी है। राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार है और इस शक्ति का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बड़ी ही स्वच्छ दत्तापूर्वक किया है, जिसका वर्णन इसी अध्याय में अग्रज भी किया गया है, इसमें दो मत नहीं हैं कि राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार पूर्ण एवं निरपेक्ष प्रकार का नहीं है। किंतु समय आने पर राष्ट्रपति उसका प्रयोग इस रूप में अवश्य ही कर सकता है कि वह निषेधाधिकार सा ही जान पड़ता है। वस्तुतः सिद्धांत रूप में तो यह अधिकार ब्रिटेन के राजा को भी है किंतु वह इसका प्रयोग नहीं करता। रानी ऐन के पश्चात् किसी भी सम्राट ने इस निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

वास्तव में राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में भी नेतृत्व का कार्य करता है। यथाथ रूप में बहुत कुछ सीमा तक व्यवस्थापन उसकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। दल के सदस्य व्यवस्थापन के लिए उससे ही निर्देश लेते हैं और इस दिशा में राष्ट्रपति की लॉबी (Presidents Lobby) भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रपति विधायकों को आमंत्रित करके उनको अपना दृष्टिकोण समझाने तथा उसका प्रसार कराने का प्रयत्न करता है किंतु ऐसा करना ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों की परिधि से बाहर है। वह व्यवस्थापन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि यह सब मंत्रिमण्डल का ही कार्य है। राष्ट्रपति को संदेश (Messages) प्रेषित करने का भी अधिकार है परंतु इस प्रकार का कोई अधिकार सम्राट को

नहीं है। जब कभी भी आवश्यकता हो, राष्ट्रपति कांग्रेस के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकता है।

(द) मंत्रिमण्डल के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से (Relationship with the Cabinet)—मंत्रिमण्डल के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से भी राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमण्डल वास्तव में उसके व्यक्तिगत अनुचरों का एक समूह मात्र ही है मंत्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं और उसी की प्रसन्नता से ही अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए उनकी सलाह मानना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत बेजहोट (Bagehot) ने इंग्लैंड में मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में सम्राट के तीन अधिकार बताये हैं—सलाह देना, सलाह लेना तथा चेतावनी देना का अधिकार। यद्यपि मंत्रिमण्डल के सदस्य सम्राट द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वह नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है और उसी की इच्छा पर वे पदच्युत भी किये जाते हैं। अतएव सम्राट मंत्रिमण्डल की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिये विवश है। सामान्यतया वे वह परम्पराओं का तोड़कर बहुमत दल के नेता के अतिरिक्त अथवा किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए भी आमंत्रित नहीं कर सकता, अर्थात् मंत्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध सम्राट कुछ भी कर सकने में असमर्थ है।

(घ) संरक्षण की दृष्टि से (From the point of view of Patronage)—राष्ट्रपति द्वारा अनेको कमचारियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति को अपने समयको को अनुगृहीत करने के अवसर भी मिलते ही रहते हैं। इसके विपरीत इंग्लैंड में सम्राट स्वयं नियुक्तियाँ नहीं करता है अपितु उसके नाम से मंत्रिमण्डल तथा प्रधानमंत्री ही करते हैं। अतः स्पष्ट है कि उसे संरक्षण के अवसर भी नहीं मिलते।

(2) सम्राट से राष्ट्रपति किस प्रकार कम है (How he is less than the King)
इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिकन राष्ट्रपति का स्तर एवं स्वरूप एक वास्तविक एवं प्रभावशाली कार्यपालिका के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आता है किन्तु फिर भी कई बातों में वह ब्रिटिश सम्राट से कम भी है।

(क) गौरव एवं सम्मान की दृष्टि से (Grace and Popular Devotion)—ब्रिटिश सम्राट की पृष्ठभूमि में जो गौरव एवं सम्मान का भाव निहित है वह अमेरिकी राष्ट्रपति में हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इंग्लैंड की कहावत कभी नहीं कही जाती। इंग्लैंड में एक कहावत है कि इंग्लैंड में लोग अपने घरों में उस समय तक सुख की नीद सोते हैं जिस समय तक अकिंगडम प्रासाद में राजा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राष्ट्रीय समारोहों की अध्यक्षता करता है राजदूतों का स्वागत भी करता है किन्तु उसके पद के साथ वह गौरव एवं अतीत की परम्पराओं का भाव एवं सम्मान निहित नहीं जो कि सम्राट के साथ है। राजा को प्रत्येक व्यक्ति का राजा कहा जाता है (He is everybody's King)। जब शाही सवारी निकलती है तब लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उत्सुकता से इंतजार करते हैं। यह सब बातें अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नहीं होती हैं।

(ख) राष्ट्रपति पद का स्थायित्व (Permanence)—यद्यपि स्थायित्व की

दृष्टि से भी राष्ट्रपति कम शक्तिशाली नहीं है किन्तु वह केवल चार वर्ष के लिए ही निर्वाचित होता है और इन चार वर्षों के लिए उसका पद पर रहना निश्चित सा ही हो जाता है। उसे अवधि में उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसके पद से च्युत किया जा सकता है। किन्तु यह प्रतिबंध सम्राट के साथ नहीं रहता। उसके पद का आधार है वशानुक्रमण। उसे निर्वाचन नहीं लड़ना पड़ता। एक बार सम्राट बन जाने के उपरान्त वह जीवनपथ पर ही अपने पद पर रहता है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं हो जावे। उसे महाभियोग की कायवाही द्वारा हटाया नहीं जा सकता क्योंकि सम्राट कानून से ऊपर है।

(ग) मंत्रिमण्डल के साथ सम्बन्ध (Relationship with the Cabinet)—मंत्रिमण्डल के परामर्श पर राजा लोक सभा को भी भंग करके नये निर्वाचन करा सकता है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में भी प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग करता है। सम्राट के पास मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं—सूचित करने का अधिकार, अपने को सूचित रखने का अधिकार तथा चेतावनी देने का अधिकार, मंत्रिमण्डल तथा देश की राजनीतिक स्थिति में कभी कभी सघर्ष हो जाने पर सम्राट एक मध्यस्थ का भी कार्य करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह काम अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं करता। सम्राट दलीय व्यवस्था से ऊपर है जबकि राष्ट्रपति उसकी उत्पत्ति ही है।

(घ) संस्थागत दृष्टिकोण (Institutional point of view of Institution)—सम्राट के सम्बन्ध में कहा जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता। राजा मर चुका है राजा चिरायु हो। यह सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में नहीं होता है। शासन की त्रुटियों के लिए सम्राट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। उसके लिए शासन ही उत्तरदायी है। आलोचना मंत्रिमण्डल की होती है किन्तु अमेरिका में कुशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर है और उसके लिये आलोचना का एकमात्र पात्र भी वह ही है। सम्राट एक संस्था के रूप में कार्य करता है, अतः यहाँ पर हमारा अभिप्राय व्यक्तिगत राजा से नहीं अपितु संस्थागत राजा से है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री
(The President of U S A & The British Prime Minister)

प्रायः यह कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना यदि किसी कायपालिकाध्यक्ष से की जा सकती है तो वह केवल ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ही है। वैसे इन दोनों की शक्तियों के सम्बन्ध में भी लेखकों में मतभेद है। यदि ब्राइस (Bryce) ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद को विश्व का सर्वोच्च पद कहा है तो इसके विपरीत ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियों का महत्व प्रदर्शित करते हुए रम्से म्योर (Ramsay Muir) ने कहा है कि 'ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ इतनी विस्तृत एवं व्यापक हैं कि विश्व के किसी अन्य संवैधानिक शासक को उतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति को भी नहीं।' ऑग तथा रे (Ogg & Ray) के शब्दों में, 'यूरोप के तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली कायपालिका अधिकारी हो गया है।' लास्की के मतानुसार अमेरिका

का राष्ट्रपति सत्राट से कम तथा अधिक दोनों ही है, वह प्रधानमंत्री से भी कम तथा अधिक दोनों है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सही स्थिति के विषय में लेखकों में मतभेद नहीं है। कुछ ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिक शक्तिशाली मानते हैं और कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली बताते हैं। अतः सर्वप्रथम हमें यह अध्ययन करना है कि किन बातों में अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार अधिक शक्तिशाली है (How is he more Powerful)

(1) कायकाल (Tenure)—राष्ट्रपति का कायकाल निश्चित होता है और प्रधानमंत्री का अनिश्चित। राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और उससे पूर्व वह केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही अपने पद से पृथक् किया जा सकता है जोकि लगभग असम्भव सा ही है। प्रधानमंत्री का कायकाल दो तो पाँच वर्ष है किन्तु उसका कायकाल केवल लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर है। लोकसभा के विश्वास पत्र ही प्रधानमंत्री का अस्तित्व निर्भर रहता है।

(2) प्रशासन तथा राज्य की प्रधानता के दृष्टिकोण से (From the Point of view of Administration and Headship of the State)—इन दोनों ही दृष्टियों से अमेरिका का राष्ट्रपति उत्तम स्थिति में है क्योंकि उसके व्यक्तित्व में सत्राट तथा प्रधानमंत्री दोनों की ही शक्तियों का समावेश है। वह स्वयं का प्रधानमंत्री भी है। बेजहाट (Bagehot) ने सरकार के दो भाग बताये हैं—प्रतिष्ठित तथा प्रवीण। इंग्लैण्ड में पहले का अधिकारी सत्राट है जिसके द्वारा समस्त सौजन्यपूर्ण कार्यों का सम्बन्ध होता है। वास्तविक प्रशासन प्रधानमंत्री द्वारा ही सम्पादित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यक्तित्व में इन दोनों पदों का समावेश हो गया है।

(3) मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध की दृष्टि से (From the Point of Relationship with the Cabinet)—इस दृष्टि से भी अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहीं अधिक उच्च है। अमेरिकी राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का निर्माता एवं स्वामी है, परन्तु इसके विपरीत ब्रिटिश प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के मध्य प्रथम है वह मन्त्रिमण्डल को अपना दास नहीं बना सकता। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो मन्त्रिमण्डल के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। ब्रोगन (Brogan) के शब्दों में मन्त्रिमण्डल वही है जिसको राष्ट्रपति चाहता है वह उसका साधन मात्र है इसके सदस्यों को वह क्षण में बना सकता है तथा क्षण में मिटा सकता है। वास्तुतः प्रधानमंत्री की यह स्थिति नहीं है। उसे मन्त्रिमण्डल के गठन में भी कई दृष्टिकोणों का ध्यान रखते हुए ही विभागों का विभाजन करना होता है।

(4) समन्वयकारी कार्य (Conciliatory Functions)—दोनों ही को समन्वयकारी कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति की अपेक्षा कम है। प्रधानमंत्री अपने दल और विभिन्न हितों के मध्य समन्वय उत्पन्न करता है जबकि राष्ट्रपति विविध महत्वपूर्ण समुदायों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। अतः प्रधानमंत्री का क्षेत्र राष्ट्रपति की अपेक्षा सीमित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से किस प्रकार शक्तिसाली है (How is American President less than the Prime Minister)

(क) राजनतिक दलों के साथ सम्बन्ध (Relationship with the Political Parties)—इस दृष्टिकोण से प्रधानमन्त्री की स्थिति अधिक मजबूत है। अमेरिका में दलगत अनुशासन में वृद्धि हुई है किंतु वह उस स्तर को नहीं पहुँच पाया जिस रूप में कि वह ब्रिटेन में पाया जाता है। अमेरिका में दलीय संगठन अब भी शिथिल है। ब्रिटेन में आम चुनाव द्वारा प्रधानमन्त्री की ही खोज होती है। प्रधानमन्त्री दलीय राजनीति का केन्द्र है। वही उसका नेतृत्व करता है। दल के निणय अधिकांशतः प्रधानमन्त्री के निणय होते हैं। दल प्रधानमन्त्री का बहुमूल्य साधन है।

(ख) व्यवस्थापिका के दृष्टिकोण से (From the Point of view of Legislation)—इस सम्बन्ध में रम्से म्योर ने कहा है कि 'लोकसभा में जिस समय तक प्रधानमन्त्री का बहुमत है उस समय तक जो कुछ प्रधानमन्त्री कर सकता है उसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता।'¹ व्यवस्थापन के क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सदन को प्रभावित करके नियंत्रण में लाने का सर्वोत्तम माध्यम निषेधाधिकार है। किंतु राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार भी निरपेक्ष प्रकार का नहीं है। इसे भी 2/3 बहुमत द्वारा रद्द किया जा सकता है। किंतु इसकी अपेक्षा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली तथा बाध्यकारी हैं। वह संघाट को परामर्श कर लोकसभा का भंग करा सकता है, अतएव यह मंत्रिमण्डलीय अधिनायकत्व का मूल कारण माना जाता है। इस प्रकार की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। यदि राष्ट्रपति कांग्रेस पर दबाव डालने के लिये जनमत के विविध साधनों का प्रयोग कर सकता है तो प्रधानमन्त्री इससे बचकर ही इन साधनों के प्रयोग करने में समर्थ है। किसी भी विधेयक के प्रति प्रधानमन्त्री की उदासीनता वस्तुतः राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति से अधिक है। कांग्रेस में चाहे राष्ट्रपति के दल का बहुमत ही क्यों न हो किंतु उसे उसका स्वामी नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत प्रधानमन्त्री लोकसदन का नेतृत्व करता है और सदन सामान्यतः उस सबका अनुमोदन करता है, जो प्रधानमन्त्री चाहता है। प्रधानमन्त्री सदन की आत्मा है। हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास सरक्षण शक्ति (Power of Patronage) है किंतु प्रधानमन्त्री इस क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं अपितु अधिक ही है। विधायिका स्थिति भी जितनी प्रधानमन्त्री की सुदृढ़ है उतनी अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं है। लास्की के शब्दों में, 'अमेरिका के राष्ट्रपति को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की विधायिका स्थिति से अवश्य ही जलन होगी।'² काटर रन तथा

1 For so long as his party commands a majority in the House of the Commons he can do what no President can ever do
—Ramsay Muir

2 The President of U S A must envy the legislative position of a British Prime Minister

हज ने कहा है कि इस अर्थ में 'प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से ऊपर नियमात्मक लाभ है कि विधायिका सभा उसके नियंत्रण में है।'¹

(ग) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारों के दृष्टिकोण से (From the Point of View of Executive Powers)—यद्यपि हमारे मानस पर स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रभुत्व प्रभावित हो सकता है किन्तु प्रधानमंत्री भी इस दिशा में कम नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार है शक्तियों का पथवकरण और प्रधानमंत्री की शक्तियों का आधार है शक्तियों का समन्वय। बदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की अपेक्षा प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली है। वह अपनी नीति का पूर्ण अधिष्ठाता है। प्रधानमंत्री स्वयं का निर्णायक है। राष्ट्रपति की भांति प्रधानमंत्री को अपनी की हुई नियुक्तियों पर किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रशासकीय पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री की शक्ति राष्ट्रपति से कहीं अधिक है। कांग्रेस को समितियाँ राष्ट्रपति के दैनिक प्रशासकीय कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं किन्तु प्रधानमंत्री के साथ यह सम्भव नहीं है। समस्त राजनीति प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमती है यद्यपि उसकी शक्तियों का आधार परम्परा है। अमेरिकी राष्ट्रपति वह विशालकाय घोड़ा है जो केवल कांग्रेस पर ही सवारी कर सकता है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री उस घोड़े के समान है जो कद में छोटा अवश्य है किन्तु उसके भ्रमण के लिए विस्तृत मैदान उपलब्ध है, अतएव कार्यपालिका की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है।

(घ) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)—यदि हम इन दोनों की स्थिति का मूल्यांकन वित्तीय दृष्टि से भी करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि राष्ट्रपति की अपेक्षा प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक सुदृढ़ है। अमेरिका में बजट का निर्माण ब्यूरो ऑफ दी बजट (Bureau of the Budget) के द्वारा सम्पन्न होता है और इसी के निर्देशन द्वारा वह कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत भी किया जाता है। अतएव राष्ट्रपति को यह विश्वास नहीं हो पाता कि उसके द्वारा प्रस्तुत बजट को बिना किसी काट छाँट के स्वीकार कर ही लिया जायगा। प्रायः राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में कटौती होती है। इसके विपरीत इंग्लैण्ड में प्रधानमंत्री को टूजरी के प्रथम लॉर्ड के रूप में वेतन प्राप्त होता है। वित्त-विभाग द्वारा बजट का निर्माण होता है। लोक सभा प्रायः कटौती नहीं करती। यदि वह ऐसा करती है तो उसे मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास समझा जाता है और समस्त मंत्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ भी है। बजट के स्वास्थ्य के ऊपर मंत्रिमण्डल का स्वास्थ्य अवलम्बित है। अतः सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल एक होकर यह देखने की कोशिश करता है कि बजट उसी रूप में पारित होना चाहिए जिस रूप में कि वह रखा गया है। मंत्रिमण्डल स्वेच्छा से उसमें संशोधन स्वीकार कर सकता है।

(ङ) न्यायिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से (From the Point of View of Judicial Control)—अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर प्रबल नियंत्रण है। राष्ट्रपति

1 The decisive advantage which the Prime Minister has over the President is his control of the legislature —Rain & Hurz

द्वारा स्वीकृत विधेयको को कई बार उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया है। उदाहरणार्थ—राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने प्रस्ताव *New Deal* तथा कोरिया युद्ध के समय राष्ट्रपति ट्रूमेन द्वारा इस्पात के निजी कारखानों पर अधिकार करने की नीति का उच्चतम न्यायालय ने विरोध किया। किंतु इंग्लैण्ड में इस प्रकार का हस्तक्षेप एवं कटुतापूर्ण अनुभव सम्भव नहीं है। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री का पलड़ा राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक बजनी है।

हम अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट तथा प्रधानमंत्री के साथ तुलना करने के पश्चात् भी उनकी सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इस कठिनाई का मूल कारण है पद्धतियों का अंतर। राष्ट्रपति का सम्बन्ध अध्यक्षतात्मक पद्धति से है और प्रधानमंत्री का संसदीय से। अतः दोनों ही पद्धति लोकतन्त्र से सम्बद्ध होते हुए भी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। इसलिए इनकी सही स्थिति के विषय में व्यापक पमाने पर मतभेद है।

उपराष्ट्रपति (Vice President)

सविधान निर्माण के समय बंजामिन फ्रैंक्लिन (B Franklin) ने व्यंग्य में उपराष्ट्रपति पद की उपादेयता पर शर्का करते हुए कहा था कि उपराष्ट्रपति केवल व्यर्थ का महिमामय व्यक्ति (Superfluous Highness) मात्र होगा। पर्याप्त वाद विवाद एवं विचार विमर्श के उपरांत पद की अनावश्यकता का तर्क चल नहीं सका और इस पद को रखने का ही निश्चय किया गया। राष्ट्रपति द्वारा पद रिक्त कर देने अथवा दीर्घ अवकाश की स्थिति में उसके कतब्यों का निर्वहण करने का उत्तरदायित्व किसी न किसी पदाधिकारी पर डालना ही होया और वह उपराष्ट्रपति से अच्छा अथवा कोई पदाधिकारी नहीं हो सकेगा। सम्भवतः यही कारण है कि चाहने पर भी इस पद को समाप्त नहीं किया जा सका है। वर्तमान काल में तो इस पद का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अब देश के प्रशासन तथा वहाँ की राजनीति में उपराष्ट्रपति का सक्रिय अनुदाय है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पद के लिये प्रशिक्षण है। परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी है।

निर्वाचन एवं योग्यताएँ (Election & Qualifications)

सन् 1804 के 12वें संशोधन से पूर्व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पृथक् नहीं होता था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस उम्मीदवार को द्वितीय स्थान प्राप्त होता था उसे ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता था, किंतु एक बार 1800 में जैफरसन तथा बुर (Burr) को समान मत मिले और नियम प्रतिनिधि सदन को करना पड़ा। इसके पश्चात् 1804 में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की पृथक् व्यवस्था की गई। अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिये पृथक् पृथक् निर्वाचन होते हैं। निर्वाचक मण्डल के सदस्य दोनों पदों के लिए पृथक् पृथक् मतदान करते हैं। निर्वाचक मण्डल एक ही होता है। दोनों पदों के लिए योग्यताएँ भी समान ही हैं। जिसे निर्वाचक मण्डल का बहुमत प्राप्त होता है वही उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिये अग्रान्वित योग्यताएँ निश्चित की गई हैं—

- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका का ज मजान नागरिक होना चाहिए ।
- (ii) 35 वष की आयु पूण कर चुका हो ।
- (iii) वह 14 वष तक अमेरिका का निवासी रहा हो ।

उपराष्ट्रपति का प्रतिवष 35 000 डालर वेतन उपलब्ध होता है जोकि आयकर से मुक्त नहीं है । कि तु वेतन के अतिरिक्त उसे जो अन्य भत्ते मिलते हैं, उन पर आयकर नहीं देना पड़ता ।

उपराष्ट्रपति के काय (Functions of the Vice President)

उपराष्ट्रपति के काय दो प्रकार के हैं—

(i) जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र मृत्यु, निर्वोग्यता अथवा महाभियोग के फलस्वरूप रिक्त हो जाय ता उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है । इस प्रकार से अब तक 9 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं । 1841 में राष्ट्रपति हैरीसन की मृत्यु के परिणामस्वरूप जॉन टेलर (Taylor) ने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया । उन्होंने कायवाहक के रूप में नहीं अपितु पूण रूप में इस पद को ग्रहण करने की घोषणा की । तभी से यह परम्परा चली आ रही है कि उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति बनता है तो वह शेष अवधि के लिये ही बनता है न कि अल्प अवधि के लिए ही ।

(ii) उपराष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण काय सीनेट (कांग्रेस का वरिष्ठ सदन) की अध्यक्षता करना भी है यह काय बहुत कुछ सीमा तक वास्तविक की अपेक्षा औपचारिक ही है । उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता वरन् वह पदेन अध्यक्ष होता है । उसका कार्य सदन में अनुशासन बनाये रखना है । सदन में किसी विषय पर समान मत आने पर उसे निर्णायक मत के प्रयोग करने का भी अधिकार है । उसकी स्थिति प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष जसी नहीं है । वह दल का नेतृत्व नहीं करता ।

(iii) इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति की मेवाएँ मलाह लेने के लिए भी अजित की जा सकती हैं । सन 1912 में राष्ट्रपति कूलिज ने उपराष्ट्रपति को अपने भ्रमणमण्डलों की बैठकों में आमन्त्रित करना प्रारम्भ किया था किंतु यह प्रथा आगे नहीं चल सकी । राष्ट्रपति आइजनहावर ने उपराष्ट्रपति के महत्व में पर्याप्त वृद्धि की । उन्होंने उसे अन्य देशों में सद्भावना काय के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में भी भेजा । तात्कालिक उपराष्ट्रपति निक्सन ने कई देशों का भ्रमण करके तथा अमेरिकी दृष्टिकोण को समझाकर अंतर्राष्ट्रीय मद्भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की । वर्तमान राष्ट्रपति निक्सन (Nixon) ने भी 1970 में उपराष्ट्रपति एंग्लू को एशिया के 11 देशों में भेजकर अमेरिका के प्रति मद्भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया ।

उपराष्ट्रपति पद की आलोचना एवं उपयोगिता (Criticism and Utility of the Office of Vice President)

वास्तविकता यह है कि उपराष्ट्रपति का पद एक उपेक्षित तथा राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही कम महत्व का पद रहा है और यह अनुभव किया जाता रहा है कि राष्ट्रपति का वह सहयोगी बनकर ही काय करे तथा उसके द्वारा प्रशासकीय कार्य भी सम्पादित किये जाय जिससे राष्ट्रपति का बोझ भी कुछ हल्का हो सके । इसने विपरीत कुछ आलोचकों का अभिमत यह है कि यह एक स्वयं में ही व्यर्थ पद

है। फरगुसन तथा मकहैनरी के कथनानुसार “अमेरिका के इतिहास में उपराष्ट्रपति भूले बिसरे व्यक्ति ही होते हैं। यह पद बड़े महत्व का है फिर भी यह एक निम्नतर मजाक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।”¹

लास्वी के अनुसार—‘उपराष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का आकाश का डूबता हुआ तारा है।’²

उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलन भी ध्यान नहीं देते। प्रायः वे ऐसे व्यक्तियों को ही इस पद के लिए चुनते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहयोग दे सकें। अधिकतर उपराष्ट्रपति को ऐसी क्षत्र से लिया जाता है जहाँ पर राष्ट्रपति को कम मत मिलने की सम्भावना होती है। उपराष्ट्रपति सीनेट के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी योग्य व्यक्तियों को नहीं रखा जाता।

किन्तु इसने हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद का कोई महत्व ही नहीं है। उपराष्ट्रपतियों को 16 बार राष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ है और वे इस पद पर आने के पश्चात् पुनः भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ट्रूमैन, जानसन तथा टेलर आदि भी इसी प्रकार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रूजवेल्ट भी इसी प्रकार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और बिलिङ्ट स्याति भी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति कैनेडी के मरने के उपरांत यह समस्या उत्पन्न हुई थी कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत समय तक रिक्त ही रहेगा। अतः इस स्थिति के परिणामस्वरूप ही 25वाँ संशोधन पारित किया गया, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है जिसका अनुमोदन कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। अतः इस प्रावधान से अब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहने की सम्भावना नहीं है।

राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल (Cabinet of the President)

अमेरिका में मन्त्रिमण्डल का आधार निरुद्धियाँ हैं, सविधान नहीं, क्योंकि सविधान में तो केवल यही संकेत दिया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रशासकीय विभाग के अधिकारियों से लिखित रूप में सम्मति माँग सकता है। सविधान द्वारा मन्त्रिमण्डल का कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया गया है। सन् 1793 में प्रथम बार मन्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति वाशिंगटन के द्वारा सीनेट से परामर्श करने का प्रयोग सफल नहीं हुआ। रूडफोर्ड के मतानुसार—सन् 1907 से मन्त्रिमण्डल एक संस्था के रूप में अमेरिकी प्रशासकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। राष्ट्रपति जबसन ने प्रारम्भ में तो विभागीय अधिकारियों से परामर्श किया किन्तु बाद में उसकी बैठक ही बुलाना बंद कर दिया। राष्ट्रपति हार्डिंग (Harding) विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त अपने मित्रों तथा सहयोगियों

1 Vice Presidents are the forgotten men in American History The office is one of Importance and yet it is the butt of endless jokes

2 The Vice President has been little more than a faint wraith on the American political scene
—Ferguson & Mac Henry
—Lasky

से भी परामर्श करते थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तो विभिन्न अभिकरणों के अध्यक्षों को गठित करके एक 'सर्वोपरि मंत्रिमण्डल' की स्थापना की थी। वास्तविकता यह है कि इसका स्वरूप सर्वदा ही राष्ट्रपति की इच्छा के साथ-साथ परिवर्तित होता रहा है। राष्ट्रपति लिंकन (Lincoln) ने सात सदस्यों के विरोध करने पर कहा था कि ही का एक मत सात के विरुद्ध भी विजयी है। इससे अमेरिकी प्रशासकीय व्यवस्था में मंत्रिमण्डल की स्थिति का स्पष्ट आभास मिलता है।

मंत्रिमण्डल की रचना (Formulation of the Cabinet)—सविधान के अनुसार प्रशासकीय विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के परामर्श से की जाती है। परंतु वास्तव में नियुक्तियों का सम्बन्ध में सर्वोपरि इच्छा राष्ट्रपति की ही होती है। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि ब्रिटिश मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था की भाँति मंत्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनैतिक दल के समान दृष्टिकोण वाले हों। मंत्रिमण्डल का निर्माण करते समय राष्ट्रपति कुछ बातों का ध्यान रखता है। सर्वप्रथम वह उन व्यक्तियों को अपने मंत्रिमण्डल में सम्मिलित करता है जो उसके बहुत ही निकट होते हैं, तथा जिन्होंने उसे राष्ट्रपति पद दिलवाने में सहयोग दिया है। मंत्रिमण्डल का गठन करते समय दूसरी इस बात को भी दृष्टिगत रखा जाता है कि मंत्रिमण्डल में प्रदेशों तथा भाषाओं का प्रतिनिधित्व सुलभ हो सके। यूयार्क, पैन्सिल्वेनिया, केनिया तथा मैसाचुसेट्स आदि कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जिनको सदैव से ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कभी कभी देश के विभिन्न घमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल का गठन करते समय व्यक्तियों की योग्यता तथा कांग्रेस पर उनके प्रभाव का भी ध्यान रखता है। देश के अन्तर्गत वर्तमान आर्थिक हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है वास्तव में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमण्डल के गठन में पूर्णतः स्वतंत्र ही रहता है। क्योंकि प्रायः सीनेट उसके भाग में बाधक नहीं होती। राष्ट्रपति कूलिज (Coolidge) के द्वारा एटार्नीजनरल के पद पर बारेन की नियुक्ति को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया था। जोकि एक अपवाद ही है। वर्तमान मंत्रिमण्डल में निम्नलिखित पद हैं—

- (1) राज्य तथा विदेश सचिव (1789 में पद स्थापित किया गया)
- (2) कोष सचिव (1789)
- (3) प्रतिरक्षा सचिव (1947)
- (4) अटॉर्नी जनरल (1870)
- (5) पोस्ट मास्टर जनरल (1792)
- (6) गृह सचिव (1889)
- (7) कृषि सचिव (1889)
- (8) व्यापार सचिव (1903)
- (9) श्रम सचिव (1913)
- (10) स्वास्थ्य शिक्षा एवं कल्याण सचिव (1953)
- (11) भवन तथा शहरी विकास सचिव (1966)
- (12) यातायात सचिव तथा उपराष्ट्रपति इसके सदस्य हैं।

मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य को 35,000 डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अपने मंत्रिमण्डल के किसी भी सदस्य को उसके पद से हटाकर दे। मंत्रिमण्डल की बैठकें प्रति सप्ताह शुक्रवार को होती हैं। बैठकों में पर्याप्त औपचारिकता का व्यवहार किया जाता है। बैठकों की कार्यवाही को काफी गुप्त रखा जाता है। इससे निषेध की प्रक्रिया निषिद्ध नहीं होती, क्योंकि अतः राष्ट्रपति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अमेरिकी मंत्रिमण्डल द्वारा दो प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जाता है—

(1) प्रशासन विषयक—सचिव राष्ट्रपति के निर्देश एवं संरक्षण में अपने कार्यों का सम्पादन करते हैं। अपने विभाग के सम्बन्ध में प्रत्येक सचिव को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। राष्ट्रपति एक सम्बन्धकर्ता का कार्य करता है। सचिव ही विभागीय आदेशों को प्रसारित करता है तथा अपने विभाग पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। निम्नस्तर के अधिकारियों की नियुक्ति भी व्यवहार में सचिव द्वारा ही की जाती है।

(2) वस्तुतः मंत्रिमण्डल का प्रमुख कार्य मन्त्रणा देना है। अमेरिका में मंत्रिमण्डल के विकास का सम्भवतः यही कारण था। राष्ट्रपति ही इस बात का नियंत्रण करता है कि किस विषय पर मन्त्रणा होगी एवं उसका क्षेत्र तथा स्वरूप क्या होगा। विचार-विमर्श के विषय भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की बैठक से पहले स्वयं ही नियंत्रण कर सकता है और केवल औपचारिकता का निर्वाह करने हेतु उसकी सूचना मंत्रिमण्डल को देता है। मंत्रिमण्डल के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना भी राष्ट्रपति के ऊपर ही निभर है। राष्ट्रपति विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय अधिकारियों से भी परामर्श कर सकता है। मन्त्रणा का प्रमुख सहाय प्रशासकीय तन्त्र का नियंत्रण मात्र ही होता है।

राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल (President & the Cabinet)

राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसी नहीं है क्योंकि वह मंत्रिमण्डल के सदस्यों के मध्य प्रथम मात्र ही नहीं है अपितु राष्ट्रपति अपने मंत्रिमण्डल का निर्माता, अधिष्ठाता अर्थात् सभी कुछ है। वह जब चाहे मंत्रिमण्डल को भंग कर सकता है। किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। किसी भी नये पद को उत्पन्न कर सकता है और प्रचलित को समाप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में कोई भी उससे प्रश्न नहीं कर सकता। वह मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए विवश नहीं है। वह पूर्ण रूप में स्वामी है। ब्रोगन के शब्दों में, 'राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रधानों का शासक होता है।'¹

पुनः ब्रोगन के ही शब्दों में "अमेरिका में मंत्रिमण्डल वैसा ही होता है जैसा कि राष्ट्रपति उसे बनाना चाहता है। यह उसका औजार है। उसकी छोटी सी इच्छा उसे बना तथा बिगाड़ सकती है।'² वस्तुतः मंत्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के अनुचर हैं। मंत्रिमण्डल को राष्ट्रपति के परिवार की सजा (President Family) दी गई है। मंत्रिमण्डल की निम्नतम स्थिति के कारण ही उसे पाकशाला मंत्रिमण्डल

1 The President is the ruler of the heads of his departments

—Brogan

2 The cabinet is only what the President wants it to be. It is his tool and for its members a breath unmakes them as a breath has made

—Brogan

(Kitchen Cabinet) कहा जाता है। इसके सदस्य अपने पदों पर राष्ट्रपति की प्रसन्नता की अवधि तक ही बने रह सकते हैं। किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अमेरिकी शासन प्रणाली में मंत्रिमण्डल का कोई महत्व हो नहीं है। यद्यपि राष्ट्रपति बहुत कुछ अपने सचिवों के परामर्श पर ही कार्य करता है। सन् 1971 के भारत-पाक संघर्ष के उपरान्त जेक हेण्डरसन के द्वारा अमेरिका में कई प्रकार के विविध रहस्यों का उद्घाटन किया गया था जिनके अनुसार पाकिस्तान की नतिक एवं शस्त्रीय सहायता एवं गुप्त आशवासन देने में विदेश सचिव रोजस तथा किस्सिंगर की भूमिका महत्वपूर्ण है। वियतनाम-युद्ध में भी अमेरिकी नीति निर्धारण में मंत्रिमण्डल की विशेष भूमिका रही थी ऐसे विवादास्पद स्थल बहुत ही कम होते हैं जबकि राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा प्रदत्त परामर्श की उपेक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु फिर भी उनके अनिश्चित एवं अस्थायी अस्तित्व के कारण ही उन्हें राष्ट्रपति के हाथों की कठपुतली मात्र ही कहा जाता है।

कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डल (Congress & the Cabinet)

प्रत्यक्ष रूप से तो कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डल में शक्तियों के पृथक्करण के कारण कोई सम्बन्ध नहीं है। मंत्रिमण्डल के सदस्य ब्रिटिश राजनतिक व्यवस्था का भाँति विधान मण्डल के सदस्य नहीं होते और न ही वे किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। विधान-मण्डल का उनके ऊपर कोई सक्रिय नियंत्रण भी नहीं होता है। उसके अविश्वास प्रस्ताव का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मंत्रिमण्डल के सदस्यों को अपने कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यदि अप्रत्यक्ष रूप से रखे गये उनके प्रस्ताव अस्वीकार भी हो जाते हैं तो भी वे अप्रभावित ही रहते हैं। किंतु फिर भी इन दोनों में कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है और मंत्रिमण्डल पूर्ण रूप से कांग्रेस के अकुश से मुक्त नहीं है।

(क) मंत्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति होनी आवश्यक होती है यद्यपि यह औपचारिकता मात्र ही है।

(ख) विधान मण्डल विभागीय अध्ययनों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।

(ग) विभागों के सम्बन्ध में कांग्रेस निरीक्षण समितियों का भी गठन कर सकती है।

(घ) मंत्रिमण्डल के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से विधेयकों को प्रभावित करते हैं तथा सीनेट के बहुत ही निकट सम्पर्क में रहते हैं।

(च) कांग्रेस महाभियोग की पद्धति द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को उनके पद से पृथक् भी कर सकती है।

मंत्रिमण्डल की स्थिति का मूल्यांकन (Evaluation of the Position of the Cabinet)—वस्तुतः अमेरिका में मंत्रिमण्डल की स्थिति अधिक शक्तिशाली नहीं है। उसके सदस्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। सदस्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में दृष्टिकोण तथा लक्ष्य की एकता का विकास सुलभ नहीं हो सकता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यों का ही वितरण करता है किन्तु उत्तरदायित्वों का वितरण नहीं करता अतः उत्तरदायित्व

के अभाव में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्साह का क्षय हो जाता है। सदस्यों में उत्तरदायित्व के इस अभाव एवं आत्मनिभरता तथा स्वावलम्बन आदि नतिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। सदस्यों के पास काय विषयक स्वायत्तता तथा निष्पक्ष-त्मक स्वतन्त्रता भी नहीं रह पाती है अतः परामर्श का भी विशेष महत्व नहीं रहता। सदस्यों में किसी भी विषय के सम्बन्ध में गहराई के साथ सोचने का उत्साह नहीं रहता। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि सदस्य कांग्रेस के प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रमत्त रखने की बात कह डालते हैं, चाहे उनके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति कुपित हो क्यों न हो जाय। अमेरिका की मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था में एक खलने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस तथा कार्यकारिणी की नीतियों में सामंजस्य उत्पन्न करना कठिन हो जाता है। स्वस्थ व्यवस्थापन कार्यकारिणी के सहयोग पर ही अवलम्बित है जोकि शक्ति पृथक्करण के कारण सुलभ नहीं हो पाता। दोनों में ऐक्य उत्पन्न नहीं हो पाता। सम्भवतः इसी अभाव के कारण हमें प्रायः राष्ट्रपति तथा कांग्रेस की नीतियों में व्यापक अंतर का अनुभव होना है।

अमेरिकी मन्त्रिमण्डल तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तुलना (American & British Cabinet Compared)

लास्की के शब्दों में 'अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की कल्पना उस नमूने से कोई मेल नहीं खाती जिसे हम पुराने समय से योरोप की प्रतिनिधि सरकारों में देखने के अभ्यस्त हैं।' इसके अतिरिक्त दोनों ही देशों में मन्त्रिमण्डल का अभ्युदय परम्परा एवं प्रथाओं पर ही अवलम्बित है, अतः कोई साम्य उनमें दृष्टिगत नहीं होता। दोनों देशों का संवैधानिक आधार मूल रूप में ही पृथक् पृथक् है, अमेरिकी संविधान का आधार शक्तियों का पृथक्करण तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, जबकि इंग्लण्ड का आधार शक्तियों का सामंजस्य तथा संसदीय प्रणाली है। इसके अतिरिक्त भी दोनों देशों की मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्थाओं में भी कई दृष्टियों से भिन्नता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

(1) राजनैतिक सजातीयता (Political Oneness)—हमें ब्रिटिश संसद में जो राजनैतिक सजातीयता उपलब्ध होती है वह अमेरिकी मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था में परिलक्षित नहीं होती। इंग्लण्ड में मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रायः एक ही राजनैतिक दल के होते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं एक सदस्य का पतन भी समस्त मन्त्रिमण्डल के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न कर सकता है। वे एक-साथ ही मरते तथा जीते हैं। उनमें एक टीम की भावना होती है। उनके नियम भी सामूहिक रूप से ही होते हैं। जिनका दृष्टिकोण समान होता है तथा विचारार्थ भी एकता होती। जिनमें दलीय द्विधन की सर्वोपरि स्थान प्राप्त होना है। किन्तु यह सब कुछ अमेरिकी मन्त्रिमण्डल में नहीं होता। उसके सदस्य एक साथ मिलकर कार्य नहीं करते। उनमें विचार तथा दृष्टिकोण में एकरूपता नहीं होती। १७९९ नियमों का स्वरूप भी सामूहिक नहीं होता।

(2) मन्त्रिमण्डल की स्थिति (Status of the Cabinet)—हम मंत्रि म भी दोनों देशों (ब्रिटेन तथा अमेरिका) में पर्याप्त अंतर है। इंग्लण्ड में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में प्रथम है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति ।

का स्वामी है। मंत्रिमण्डल के निम्न प्रधानमन्त्री को मानना अनिवार्य है, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के निम्न को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमण्डल की स्थिति एक सलाहकार मात्र की है जिसकी सलाह मानना भी राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत इंग्लैंड में मंत्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है।

(3) मंत्रियों की नियुक्ति (Appointments of Ministers)—प्रायः इंग्लैंड में मंत्रिमण्डल में वही व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो दल के महत्वपूर्ण नेता होते हैं और जिन्होंने अपने कृत्या एवं विचारों से विधानमण्डल को प्रभावित किया हुआ होता है। वे जनता में भी प्रतिष्ठित रयतिलब्ध व्यक्ति होते हैं। किंतु अमेरिका में विविध हितों को संतुष्ट करने की दृष्टि से कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित करना पड़ता है जो निष्क्रिय हात हैं तथा जिनकी कोई लोकप्रियता भी नहीं होती। यहाँ पर तो लोग मंत्रिमण्डल की अपेक्षा सीनेट का सदस्य बनना पसन्द करते हैं। ह्याति एवं प्रतिभा की दृष्टि से भी अमेरिकी मंत्रिमण्डल ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की भाँति स्वस्थ मंच नहीं है।

(4) मंत्रियों की अवधि (Tenure of Ministers)—ब्रिटेन में मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य का निष्कासन एक असाधारण घटना ही कही जायगी। मन्त्री का त्यागपत्र से राजनैतिक क्षेत्रों में कौतूहलता एवं असमञ्जसता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कभी-कभी स्वयं मंत्रिमण्डल के लिए भी संकट उत्पन्न होने का भय रहता है। मन्त्री का निष्कासन सरल कार्य नहीं है। वास्तव में मन्त्री प्रधानमन्त्री की प्रसन्नतावधि में ही अपने पद पर आरुढ़ रहते हैं। अमेरिका में मंत्रिमण्डल के सदस्यों के निष्कासन को इतना महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ राष्ट्रपति एक इशारे से ही उन्हें अलग कर सकता है जिसकी कोई राजनैतिक प्रतिक्रिया भी नहीं होती।

(5) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)—इंग्लैंड में मंत्रिमण्डल संसद के प्रति सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में उत्तरदायी है। किसी भी मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समस्त मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव समझा जायगा। मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जा सकता है। प्रधानमन्त्री ही अन्त में मंत्रिमण्डल की रक्षा के लिए आता है। प्रधानमन्त्री का त्यागपत्र सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र होता है। किंतु अमेरिका में शक्ति-पृथक्करण के कारण यह सब कुछ सम्भव नहीं है। वहाँ मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप में न कार्य करता है और न विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी हो होता है।

Select References

- D W Brogan *The American Political System* Chapter II
 Hayman *The American President*
 Laski H J *The American Presidency*
 Ogg & Ray *Essentials of American Govt*
 Munro *The American Presidency*
 Wilson W *The President of U S A*
 Corwin *President's Office & Powers*
 Ferguson & Mc Henry *The American System of Govt*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 (अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्यवहार में यह कहाँ तक प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया है ?)
Explain the process of Presidential election in the U S A How far it has become direct election in practice ?
- 2 (संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कृत्यों का वर्णन करें।)
Summarise the powers and functions of the President of the U S A
- 3 ("अमेरिका का राष्ट्रपति नियन्त्रित शक्तियों और विशाल प्रभावों वाला निर्वाचित कार्यपालक है।" इस कथन की विवेचना करें।)
"The American President is a plebiscitary executive with limited powers but large potentialities Discuss
- 4 (उन विविध साधनों का वर्णन करें जिनके द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति विधिनिरमाण में प्रभाव डाल सकता है।)
Analyse and comment on the various ways in which the American President can influence legislation
- 5 (अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संवैधानिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध का वर्णन करें।)
Discuss the constitutional and political relations between the president and the congress in the U S A
- 6 ("संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति एक सम्राट से अधिक या कम है साथ ही एक प्रधान मंत्री से भी अधिक या कम है। उसके पद का जितना ही अध्ययन किया जाय उतनी विचित्रताएँ दिखाई पड़ती हैं।" समझाइये।)
"The President of the U S A is both more or less than a king he is also both more or less than a Prime Minister the more carefully his office is studied the more does its unique character appear" Elucidate —Laski
- 7 (अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति की तुलना इंग्लैंड के प्रधान मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति से कीजिए।)
Compare and contrast the powers and positions of the President of the U S A with those of Prime Minister of England and President of France (P U 1952 A 55 S, 56 A B U '57 A All U '55 Vikram U)
- 8 (संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट और प्रधान मंत्री के पद सम्मिलित हैं। इस कथन की विवेचना करें।)
The U S A President combines his person of the office of king and Prime Minister Discuss
- 9 (इस कथन की व्याख्या कीजिए कि "अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं प्रधान मंत्री है।")
The American President is his own Prime Minister Discuss
- 10 (अमेरिकी मंत्रिमण्डल के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करें।)

Discuss the composition powers and functions of the American Cabinet

- 11 (संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण करें।)

Compare the procedure of the president election in the U S A with that in the Indian union

- 12 (अमेरिकी मंत्रिमण्डल और सोवियत रूस के मंत्रिमण्डल की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।)

Compare and contrast the Cabinet in the United States of America with the Council of Ministers in the U S S R

- 13 (संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी शक्ति का प्रयोग करता है जितनी किसी भी प्रजातन्त्र में कोई नहीं करता। मुनरो का इस कथन को स्पष्ट करते हुए उसकी विश्लेषण कीजिए।)

The President of the U S A exercises "the largest amount of authority ever wielded by any man in democracy" (Munro, W B) Explain and elucidate

- 14 (सर हेनरी मेन का कथन था कि अमेरिका का राष्ट्रपति "शासन करता है, लेकिन राज्य नहीं करता है।" क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? कारण दीजिए।)

Sir Henry Maine asserted that the President of the U S A "governs but does not reign" Do you agree with this view Give reasons

3

राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—सीनेट [National Legislature Senate]

‘We pour Legislation into the senatorial saucer to cool it’
—George Washington
“The Senate of U S A is now the most powerful chamber in the world”
—Lindsay Rogers

अमेरिका में सम्पूर्ण राष्ट्र की विधायी शक्ति का एकमात्र आगार (Chamber) कांग्रेस है। इसका निर्माण दो सदनों के द्वारा होता है—सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन। इस व्यवस्था को द्विसदनात्मक प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के आदर्श एवं अनुभव से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने छोटे छोटे राज्यों के संरक्षण एवं समानाधिकार के प्रश्न को महत्त्व प्रदान करते हुए द्विसदनात्मक व्यवस्था को श्रेयस्कर समझा। इसके साथ ही प्रतिनिधि सदन को जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधि रूप प्रदान किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था से ही विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त धनिक वर्ग के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिये भी सीनेट का विकास हुआ। प्रतिनिधि सदन से उत्तरपायिया तथा सीनेट से दक्षिणपायियों की भावनाओं की संतुष्टि हुई। नैसे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था सघातमक व्यवस्था के अनुपूल ही है। अतः सीनेट का परिनिर्माण उच्च वर्ग के हितों की रक्षा हेतु एक राजनतिक पासा था।

इस संसद में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भाँति प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है। कांग्रेस की शक्तियों पर संविधान द्वारा परि-सीमन लगाया गया है। यह संघीय विषयों तक ही सीमित रहती है। इस सत्य को स्वीकार करने में किसी को भी संकोच नहीं हो सकता कि कांग्रेस ब्रिटिश संसद की अपेक्षा एक दुबल संस्था है। राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में कांग्रेस 2/3 बहुमत को जुटाकर ही विजय प्राप्त करने की आशा कर सकती है। वर्तमान युग कार्यपालिका के पक्ष में है जिसके फलस्वरूप ही नीकरशाही एवं साम्यवादी प्रवृत्ति व विकास के साथ ही कांग्रेस की शक्तियों का ह्रास हुआ है।

सीनेट का संगठन (Organization of Senate)

सीनेट के सदस्यों की संख्या आरम्भ में 26 थी जबकि अमेरिकी संघ में केवल 13 राज्य थे। प्रत्येक राज्य को दो प्रतिनिधि प्रेषित करने का अधिकार दिया गया था। इस समय इसके सदस्यों की संख्या 100 है क्योंकि अमेरिकी संघ में इस

समय 50 राज्य हो गये हैं। चाहे कोई राज्य नेवदा जैसी छोटी जनसंख्या वाला है और चाहे वह यूटाक जैसी बड़ी जनसंख्या वाला है, प्रत्येक को ही प्रतिनिधित्व की समानता प्रदान की गई है। यद्यपि यह पद्धति अजनतन्त्रीय ही है परन्तु अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 5 में ऐसी ही व्यवस्था है।

कायकाल—सीनेट भारतीय राज्य सभा की भांति एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं। एक सदस्य लगभग 6 वर्ष तक रहता है।

योग्यताएँ (Qualifications)—सीनेट की सदस्यता के लिये निम्नलिखित अहताएँ रखी गई हैं—

1 उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।

2 वह कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रहा हो।

3 जिस राज्य से वह उम्मीदवार है, वहाँ का वह नागरिक होना चाहिए।

उक्त अहताओं के अतिरिक्त भी व्यावहारिक दृष्टि से उसमें कुछ और गुणों का होना भी आवश्यक है। जैसे कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो तथा महत्वपूर्ण सावजनिक पदों पर रह चुका हो। उसे जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। बहुधा धनी तथा गणमान्य व्यक्ति ही इसके सदस्य हो पाते हैं।

निर्वाचन (Election)—सन् 1913 में पूर्व सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। उसके सदस्य राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा निर्वाचित होते थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के कारण सीनेट भ्रष्टाचार का आगार बन गया था। 27वें संशोधन के द्वारा सीनेट के निर्वाचन को भी प्रत्यक्ष रूप दिया गया जिसके फलस्वरूप प्रतिनिधियों का निर्वाचन आम मतदाताओं के द्वारा होने लगा। जब कभी भी सीनेट में किसी राज्य से सीनेटर का कोई पद रिक्त होता है तो उस स्थान के लिए निर्वाचन की व्यवस्था होने के समय तक अस्थायी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा कर दी जाती है।

वेतन तथा उन्मुक्तियाँ (Salary & Immunities)—सन् 1955 से सीनेट के सदस्य को भी प्रतिनिधि सदन की भांति ही 22,500 डॉलर प्रत्येक वर्ष प्राप्त होते हैं। सीनेट के अध्यक्ष को 30,000 डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है। आकस्मिक व्यय की भी व्यवस्था की गई है। सदस्यों को यातायात तथा डाक एवं तार की विविध सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यात्रा भत्ता 20 सेंट प्रति मील के हिसाब से मिलता है। प्रत्येक सदस्य को अपना एक निजी लिपिक रखने की भी सुविधा दी जाती है, जिसका वेतन राजकीय कोष से उपलब्ध होता है। सदस्यों को अधिवेशन काल में उसमें भाग लेने हेतु आते तथा जाते समय बंदी नहीं बनाया जा सकता, किन्तु देशद्रोहिता तथा शान्ति भंग करने के अपराधों के लिये उन्हें बंदी भी बनाया जा सकता है। सदन में सीनेटर द्वारा दिए वक्तव्य के आधार पर उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। परन्तु इन उन्मुक्तियों का दुर्व्यवहार करने पर उन्हें सदन से अनुशासनात्मक बाधवाही के फलस्वरूप निलम्बित किया जा सकता है।

पदाधिकारी (Officers of the senate)—अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पट्रेन (Ex officio) अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त सीनेट को एक अस्थायी

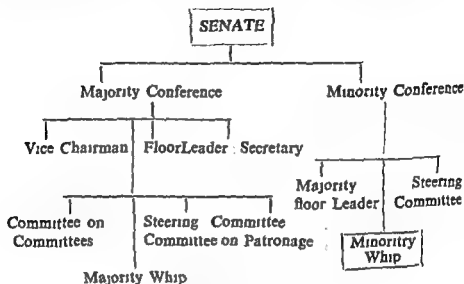
अध्यक्ष का भी निर्वाचित करना पड़ता है। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करता है उस समय वह उपराष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करता है। अध्यक्ष को सदन के वाद विवाद में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष सदन में समान मत आने पर अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग कर सकता है, सदन में पूर्णतः अनुशासन बनाये रखने का एकमात्र उत्तरदायित्व अध्यक्ष का ही है। अध्यक्ष के अतिरिक्त सदन में दल के सचेतक (Party Whip), सार्जेंट एट आम्स तथा लिपिक होते हैं।

कायविधि—सीनेट को स्वयं अपने नियम प्रतिपादित करने का अधिकार है। प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं। प्रत्येक विधेयक दो वाचनों के उपरांत ही समिति को भेजा जाता है। तीसरे वाचन के समय महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार सदन की पूर्ण समिति में ही होता है। सीनेट के खुले अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में होते हैं। सदन में दलीय अनुशासन का स्वरूप कठोर नहीं होता। किन्तु कभी कभी इसके अधिशायी अधिवेशन गुप्त रूप से भी होते हैं। सीनेट की कायवाही का अत्यन्त आकषक भाग भाषण की स्वतन्त्रता (Filbustering) है।

भाषण की स्वतन्त्रता—(Filbustering)—सन् 1917 से पूर्व सीनेट के सदस्यों की भाषण-स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। कोई भी सदस्य भाषण-स्वतन्त्रता का लाभ उठाकर सदन में कितने ही समय तक अभिभाषण कर सकता था। अभिभाषण की स्वतन्त्रता का प्रयोग किसी भी प्रगतिशील विधेयक का पूर्ण विरोध करने अथवा विधेयक की प्रगति को अवरोध करने के लिये बहुत अधिक किया गया, कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्वतन्त्रता का खुलकर दुरुपयोग हुआ है। विसर्कीसन का एक सीनेटर विल विधेयक में बाधा उत्पन्न करने की दृष्टि से लगभग 6 घण्टे से अधिक समय तक लगातार बोलता रहा। सन् 1908 में सीनेटर ला प्लाट 18 घण्टे तक बोलता रहा। सन् 1903 में एक सीनेटर कवि बाइरन की कविताओं का पाठ 22 घण्टे से भी अधिक समय तक करता रहा और उसने सदन को चेतावनी दी कि जिस समय तक विचाराधीन प्रस्ताव के कुछ अंश रह नहीं कर दिये जाते वह अपना पाठ बंद नहीं करेगा। सीनेट को व्याघात से बचने के लिए उसकी माँग को स्वीकार करना पड़ा। सन् 1917 में सीनेट ने यह नियम निर्धारित किया कि यदि सदन के 2/3 सदस्य किसी सीनेटर के अभिभाषण को नियंत्रित करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी सदस्य को एक घण्टे से अधिक अभिभाषण करने की अनुमति नहीं दी जायगी। परन्तु सामान्यतः इस नियम का प्रयोग कठोरता के साथ नहीं किया जाता। सर्वप्रथम 1919 में बार्सर्ड की संधि के सम्बन्ध में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया गया। सन् 1949 में सीनेट के इस नियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार अब सदन के सदस्य कायवाही होने से पूर्व ही संवसम्मति से यह निश्चित कर लेते हैं कि निश्चित एवं पूर्व निर्धारित समय से अधिक किसी सदस्य को नहीं बोलने दिया जायगा। वाद विवाद को नियंत्रित करने के लिये प्रस्ताव को 16 सदस्यों द्वारा लाया जाता है।

अभिभाषण की स्वतन्त्रता के दोनों पहलू हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रणाली

से सदन की कार्यवाही में व्याघात उत्पन्न होता है, इसका दूसरा तर्क यह भी है कि अल्पमत वाला दल इस प्रणाली का लाभ उठाकर ही बहुमत को अपनी बात स्वीकार करने को विवश कर सकता है, निम्नांकित रेखा चित्र के द्वारा सीनेट के संगठन की समझा जा सकता है।



सीनेट के अधिकार तथा कृत्य (Powers & Functions of the Senate)

1 कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers)

(अ) नियुक्तियों की पुष्टि (Confirmation of Appointments)—सविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया है जिससे अमेरिकी प्रशासकीय व्यवस्था में लूट खसोट (Spoil System) की प्रणाली को जन्म मिला। राष्ट्रपति का उच्चपदाधिकारियों तथा राजदूतों को नियुक्त करने का यह अधिकार सकारात्मक स्वरूप ही है। परन्तु इसके साथ ही राष्ट्रपति के इस अधिकार पर अवरोध एवं संतुलन की प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में यह नियन्त्रण भी लगा हुआ है कि नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा होनी चाहिए अथवा वे नियुक्तियाँ अवध घोषित हो जायगी। इसीलिए ही राष्ट्रपति अस्थायी नियुक्तियाँ करता है। सीनेट के द्वारा पुष्टि का यह अधिकार निषेधात्मक प्रकार का है। सीनेट पुष्टीकरण के अधिकार का प्रयोग उग्र रूप में उम्र समय और भी अधिक करती है जब कि राष्ट्रपति दूसरे दल का होता है। इसके लिए एक मात्र विधि सनीटोरियल शिष्टाचार (Senatorial Courtesy) की ही है।

इस सदन में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जब कि सीनेट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि नहीं हुई। सन 1925 में राष्ट्रपति कूलिज ने वारेन को महा अधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया किन्तु सीनेट ने उसकी पुष्टि नहीं की। इसी प्रकार जेम्स मैडोसन को सीनेट के विरोध के कारण विदेश सचिव के रूप में नैलिटन

को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। वर्तमान राष्ट्रपति निक्सन (Nixon) को भी सीनेट के द्वारा इस दिशा में एक झटका खग चुका है। निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए हैरल्ड क्रासवेल को यायाधीश नियुक्त कर दिया था किन्तु सीनेट ने उसे 45 के मुकाबिले 51 मत से अस्वीकार कर दिया। इस घटि का एक मात्र उपाय सनीटोरियल शिष्टाचार ही है। अब राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटस को विश्वास में ले लेता है जहाँ उसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है। फिर राष्ट्रपति का सीनेट में विरोध नहीं होता। अब राष्ट्रपति इस औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर पाता है तभी यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सन् 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इलीनोइस राज्य के लिए संघीय यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वहाँ के सीनेटर्स से परामर्श नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि में बाधा उत्पन्न हुई इसी कारण से सनीटोरियल शिष्टाचार का प्रयोग होता है।

(घ) संधियों की पुष्टि (Confirmation of Treaties)—नियुक्तियों की भाँति सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि का भी अधिकार है। अभी तक लगभग 300 संधियों को सीनेट ने अस्वीकार किया है। 173 को सशोधित किया है। राष्ट्रपति विल्सन सीनेट के विरोध के कारण अमेरिका को राष्ट्र संध का सदस्य नहीं बना सके, संधि का समयन 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। लास्की के शब्दों में “अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव रखने के नाते संसार की कोई विधान सभा सीनेट का मुकाबला नहीं कर सकती।” सीनेट में संधि-प्रस्ताव भेजने के उपरांत क्या होगा यह सदिग्ध ही रहता है। जॉन हे (John Hay) के शब्दों में, “सीनेट में जाने वाली संधि रंग भूमि में जाने वाले साड के सदृश ही है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा किन्तु एक बात निश्चित है कि वह रंग भूमि से कभी जीवित बाहर नहीं आयेगा।” अतः सीनेट वैदेशिक मामलों में एक निर्णायक के रूप में भाग लेती है। सीनेट के इस अकुश से बच निकलने का राष्ट्रपति के पास एक ही साधन है और वह है कार्यकारी समझौतों की कार्यकारी अनुमति (Executive Orders) जिसके द्वारा संधियों को यह रूप देकर सीनेट की पुष्टि का मामला टाला जा सकता है क्योंकि इनके लिए सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

विधायी क्षेत्र में सीनेट की स्थिति समानाधिकार की है, सम्पण की नहीं। कोई भी साधारण श्रेणी का विधेयक सीनेट में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन से स्वीकृत विधेयकों को जब तक सीनेट स्वीकार नहीं करती, उस समय तक वे कानून नहीं बन सकते। सीनेट को असहमति प्रकट करने के साथ ही अपने सलोघनों के साथ भी विधेयक को वापस करने का भी अधिकार है। असहमति की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन की व्यवस्था की जाती है किन्तु वहाँ पर बरिष्ठता तथा अनुभव का प्रभाव पड़ता है और अधिकतर विजयश्री सीनेट के ही हाथों में रहती है। भारत में राज्य सभा की गतिरोध उत्पन्न करने की नीति को लोकसभा पुनः विधेयक को स्वीकार करके विफल कर सकती है। प्राप्त में सीनेट किसी भी

विधेयक को रोक नहीं सकती। इंग्लैण्ड का हाउस ऑफ़ लाडस भी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक एक वष तक ही रोक सकता है। विधेयक के पुनः पुरस्थापित होने पर उसकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है।

किंतु वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सीनेट उसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है। कभी-कभी तो वह वित्त विधेयक के शीर्षक को छोड़कर उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित ही कर देती है। केवल प्रस्तावित करने की प्रक्रिया के अतिरिक्त दोनों सदनों की शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में समकक्ष हैं। फाइनेर (Finer) के शब्दों में, "सीनेट ने वित्तीय विधान में संशोधन करने के अधिकार का यह अर्थ लगाया है कि वह उनके पास भेजे गये बजट को नये सिरे से बनाने का अधिकार रखती है।" भारत में राज्य सभा 14 दिन से अधिक और इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ लाडस 1 माह से अधिक वित्त विधेयक को नहीं रोक सकती। अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार सीनेट ने टैरिफ सम्बन्धी वित्त विधेयक को 847 संशोधनों के सहित वापस कर दिया।

3. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

(क) महाभियोग की शक्ति (Power of Impeachment)—ब्राइस के अनुसार 'महाभियोग कांग्रेस के सम्प्रसारक का सबसे भारी शस्त्र है अतः भारी होने के कारण सामान्य स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।' राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राजनय के सदस्य तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग की जायबाही में सीनेट की भाग लेने का अधिकार है। व्यवस्था के अनुसार इन पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाये जाते हैं, जिनकी पुष्टि सदन के 2/3 बहुमत द्वारा होना अनिवार्य है। सीनेट एक न्यायालय के रूप में उन आरोपों की सुनवाई करती है। सीनेट को केवल निर्णय देने का अधिकार है। महाभियोग की जायबाही के समय अध्यक्ष का आसन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही ग्रहण करता है। सीनेट पदाधिकारियों के विवाद में फाँसी या जेल अथवा जुर्माने की सजा नहीं दे सकती। वह केवल कर्मचारी को अपदस्थ ही कर सकती है और भविष्य के लिए उसे राजकीय सेवाओं से निरस्त कर सकती है। अभी तक सीनेट ने समस्त 12 महाभियोग के मामले रखे गए जिनमें 9 मामले न्यायाधीशों के थे। इनमें से 4 को दण्डित भी किया गया।

(ख) अन्वेषण की शक्ति (Power of Investigation)—प्रो० हेरल्ड सामर्सी ने संविधान द्वारा प्रदत्त सीनेट की इस शक्ति को घट्ट एच अकाम्युमल कर्मचारियों की गतिविधियों पर सबसे अधिक प्रभावशाली माना है। सीनेट की यह शक्ति कार्यपालिका की केवल मर्यादित ही नहीं किये रहनी बल्कि उस उत्तरदायी भी बनाती है। सीनेट को प्रशासकीय अधिकारी तथा राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के विषय में भी छानबीन करके दण्ड देने का अधिकार है। सीनेट ने ही राष्ट्रपति ट्रुमैन के मंत्रिमण्डल के तीन सदस्यों के विरुद्ध आरोप की जाँच करके उन्हें हटाकर देने के लिए विवश किया था। सीनेट की अन्वेषण समिति ने 1930 में आर्चिब शर्म्स से सम्बंधित आर्चिब शर्म्स की गुप्त जाँच कराने का फैसला किया था। गोल्ले (Gollwey) ने अन्वेषण समिति की तुलना एक

वक्सूए से की है जोकि विधायिका को कायपालिका से बांध देता है। इंग्लैण्ड में जो वाय मन्त्रिमण्डल करता है अमेरिका में उस अभाव की पूर्ति अवेपण समिति द्वारा की जाती है। सीनेट की अवेपण समिति पदाधिकारियों की प्रावधान की स्थिति में रखती है।

अन्य शक्तियाँ (Miscellaneous Powers)—उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त भी सीनेट के द्वारा अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

1 सविधान में सशोधन करने हेतु भाग लेती है।

2 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए किए गए मतदान की गणना सीनेट ही करती है। यदि निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार की स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो सबसे अधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करता है।

(3) सच में नये राज्यों के प्रवेश की अनुमति देती है।

सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण (Causes of Strength of Senate)

सीनेट का आचरण सविधान निर्माताओं की आशाओं के अनुकूल ही रहा है। वस्तुतः वे यह चाहते थे कि सीनेट सविधान की रक्षा उसी रूप में करे जिस रूप में रीढ़ की हड्डी शरीर की रक्षा करती है और उसे साधे रहती है। सीनेट अपनी स्थिति के कारण राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सदन दोनों की आंखों में छटकती रहती है। वास्तव में यह कहना सही है कि राष्ट्रपति तथा सीनेट मिलकर बिना प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति के भी बहुत से काम कर सकते हैं, और सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन बिना राष्ट्रपति के भी बहुत से कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं किन्तु अमेरिकी सविधान में बिना सीनेट की अनुमति के राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सदन मिलकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रो० लिण्डसे रोबस ने सीनेट को आधुनिक राजनीति का महत्वपूर्ण आविष्कार (The most remarkable invention of modern politics) कहा है। सीनेट के सदस्य बनने की उत्कट इच्छा अमेरिकी नवयुवकों तक में पाई जाती है। यह उसकी विचित्र स्थिति का प्रतीक है। सात्स्की ने उसे व्यवस्थापन की स्वामिनी के रूप में देखा है।¹ सीनेट को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा गया है (Senate is the strongest Second Chamber of the World) सीनेट के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण हैं—

(1) प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election)—सीनेट के शक्तिशाली होने का एक कारण उसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन भी है। पहले उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय विधान मण्डलों द्वारा निर्वाचित होते थे। उस समय भी उसकी शक्तियाँ कम नहीं थी किन्तु प्रत्यक्ष निर्वाचन के पश्चात् उसके सम्मान में वृद्धि हुई है, स्तर में परिवर्तन हुआ है तथा वह लोक सप्रभुता के ओर अधिक निकट पहुँच गई है। जन-सम्पर्क और प्रतिनिधित्व के स्वरूप में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन ने उसके स्वरूप में हीनता के भाव को समाप्त किया है और उसकी स्थिति को और अधिक दृढ़ बनाया है।

(2) स्थायित्व (Permanence)—सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य आते तथा जाते रहते हैं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति 6 वर्ष तक उसका सदस्य बना रहता है। प्रतिनिधि सदन अस्थायी सदन है जिसका कार्य काल केवल दो वर्ष का है। सदस्य कोई अनुभव भी प्राप्त नहीं कर पाते कि अवकाश ग्रहण करने की साध्य लालिमा उन्हें आकर्षित करने लगती है। सामान्यतः एक व्यक्ति 6 से लेकर 18 वर्ष तक सीनेट का सदस्य रहता है। डॉ० स्मिथ 36 वर्ष तक सीनेट के सदस्य बन रहे। इस अवधि में सदस्य अनुभव में तप जाता है और अस्थायी एवं उथले विचारों के क्षुद्र प्रवाह से भी अप्रभावित रहता है। यही कारण है कि सीनेट में भाषणों का स्तर बहुत ऊँचा रहता है। सीनेट सबसे अधिक प्रभावशाली रंग मंच है। डॉ० टोक्यूविली (De Tocqueville) ने एक बार सही कहा था कि प्रतिनिधि सदन में प्रवेश करते ही गवार जन समूह के दर्शन होते हैं जिनमें कोई विवेकशील व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उससे थोड़ी ही दूर पर सीनेट के सदन में विख्यात राजनीतिक विवेकी तथा योद्धाओं के दर्शन होते हैं जिनमें बड़प्पन का माहा तथा अनुभव का गाम्भीर्य मंचलता हुई दिखाई देता है।

(3) संरचना एवं आकार (Structure & Size)—सीनेट का आकार उसकी लोकप्रियता एवं शक्तिशाली होने में अति सहायक है। सीनेट में 100 तथा प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण सीनेट के सदस्यों में पर्याप्त धनिष्ठता पायी जाती है। योग्य तथा होनहार व्यक्तियों के लिये छोटा आकार अच्छे अवसर प्रदान करता है। अतएव सदस्यों में रुचि धनी रहती है तथा संगठन की भावना भी व्यापक बन जाती है। प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व है।

(4) समकक्ष शक्तियाँ (Equal Powers)—केवल इस प्रतिबन्ध के अतिरिक्त कि वित्त विधेयक सीनेट में पुरस्थापित नहीं हो सकता अन्य सब शक्तियाँ समान ही हैं। साधारण विधेयकों के विषय में दोनों सदनों की शक्तियाँ में बराबरी भी अंतर नहीं है। वित्तीय शक्तियाँ भी सीनेट के बराबर हैं। वित्त विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर उन्हें वापस करने का उसे अधिकार है, असहमति की स्थिति में संयुक्त समिति की जो व्यवस्था है उसमें भी अपने अनुभव एवं सम्मान के आधार पर सीनेट का महत्व अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधि सदन किसी भी रूप में अपनी स्थिति को उच्चतर नहीं बता सकता।

(5) मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था का अभाव (Absence of Cabinet System)—अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इस कारण भी संसदीय लोकतन्त्र में प्रथम सदन शक्तिशाली बन जाता है क्योंकि उसमें मंत्रिमण्डल को अपदस्थ करने की क्षमता होती है। इस अभाव का साम स्पष्ट रूप से सीनेट को ही मिला है। अतः प्रतिनिधि सदन को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो इंग्लैंड में कॉमन सभा को है।

(6) विशेषाधिकार (Extraordinary Powers)—सीनेट का कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो साधारणतः विश्व के किसी भी द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं हैं। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करता है, उसे राष्ट्रपति

द्वारा सधियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सीनेट को पदाधिकारियों के आचरण के सम्बन्ध में अवेपण का भी अधिकार है। यह काम उसकी अवेपण समिति (Investigating Committee) द्वारा किया जाता है। सीनेट की इस शक्ति से अच्छे अच्छे तफिलसी तीसमारखाँओं के भूत भागते हैं। विश्व के किसी अन्य द्वितीय सदन को इतने निरपेक्ष रूप में ये शक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

(7) दलीय अनुशासन का अभाव (Absence of Party Control)—सीनेट में दलीय नियन्त्रण जैसी कोई वस्तु नहीं है। वैसे भी अमेरिका में दलीय अनुशासन शिथिल है और सीनेट में तो उसकी प्रतिष्ठाया मात्रा भी नहीं है। सीनेट के सदस्य किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं अतएव वे पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक राजनैतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं और स्वच्छन्द रूप से निर्णय लेते हैं। परन्तु प्रतिनिधि सदन में सदस्यों को इतनी छूट नहीं दी जाती। क्योंकि वहाँ सदस्यों को दलीय नीतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

(8) प्रक्रिया की सरलता (Procedural Flexibility)—सीनेट में काम-विधि की सरलता भी उसकी शक्ति के विविध स्तम्भों में से एक है। सदस्यों को अभिभाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है। सदस्य अपने विचारों को सशक्त रूप में रखने के लिये स्वतन्त्र हैं। एक ही सदस्य कई बार भी अपने विचार रख सकता है। यद्यपि 1917 में फिल्वुस्टरिंग की पद्धति पर रोक लगाई गई है किन्तु उसका प्रयोग बहुत ही कम होता है।

(9) भावार्थमय एकता (Solidarity)—सीनेट के सदस्यों में भाईचारे का भाव अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। वे एक दूसरे के अधिकारों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। सीनेट के सम्मान का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एवमत हो जाते हैं। यह भाईचारा प्रतिनिधि सदन के सदस्यों में देखने को नहीं मिलता। वे एक दूसरे के प्रति द्वेष तथा घृणा का भाव रखते हैं। सीनेट का मूल्यांकन (Evaluation of Senate)

इसमें दो मत नहीं हैं कि सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। सीनेट ने संविधान के सम्मान एवं उसकी भावना को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। राष्ट्रपति को स्वेच्छाचारी बनने से रोका है। उसमें उत्तम श्रेणी की भ्रातृत्व भावना पाई जाती है। सीनेट ने अमेरिका की विदेश नीति को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वह सदैव से ही गुस्सावर्षण का केन्द्र रही है। बीयर्ड ने ठीक ही कहा है कि “अपनी सीनेट कानूनी योग्यता के कारण राजनैतिक चाँव-पेच में यह प्रतिनिधि सदन से आगे है। यह सवमाय सत्य है कि सीनेट सरकार के अन्दर और राजनीति में प्रतिनिधि सभा पर छाई रहती है।” किन्तु इन गुणों के होते हुए भी सीनेट में जो कुछ कमियाँ हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

सीनेट वस्तुतः धनिकों का सदन बनकर रह गयी है जोकि सदैव पूँजीपतियों के हितों की ही रक्षा करती है। सीनेट के सदस्यों के लिये जो निर्वाचन व्यवस्था है वह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। बड़े तथा छोटे राज्यों की जनसंख्या की उपेक्षा करके

सब राज्यों की समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनुचित तथा लोकतन्त्रीय भावना के विरुद्ध है। उसकी सम्बद्ध शक्तियाँ संवैधानिक प्रतिरोध की प्रोत्साहन देती रहती हैं। सीनेट अपने विशेषाधिकारों के प्रति भी अनुचित रूप से भावुक रहती है। सम्भवतः राष्ट्रपति की नीतियों को झटका देना उसका नतिक उद्देश्य ही बन गया है। उसमें अभिभाषण की जो स्वतन्त्रता है उसे भी लोकतन्त्रीय पद्धति के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा जाता रहा है कि सीनेट जितना समय नष्ट करती है उतना समय विधान सभाओं बहुत ही कम नष्ट करती है। अतः हम यही कहेंगे कि इन कमियों के होते हुए भी सीनेट ने कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सर हेनरी मेन ने कहा है कि “अब से आधुनिक लोकतन्त्र का प्यार बढ़ा है, तब से जितनी समस्याओं का भी निर्माण हुआ है, उनमें यही एकमात्र पूर्णतः सफल समस्या रही है।”

सीनेट तथा लाड सभा—एक तुलना

(Senate & The House of The Lords a Comparison)

इन दोनों सदनों के मध्य यह समता है कि अपने-अपने देशों की सदन के ये द्वितीय सदन हैं और वित्त विधेयक की प्रस्तावना दोनों ही सदनों में नहीं की जा सकती किन्तु फिर भी इनमें परस्पर पर्याप्त भिन्नता है। यदि सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है तो लाड सभा विश्व का सबसे अधिक कम शक्तिशाली द्वितीय सदन ही नहीं बनूँ द्वितीय श्रेणी का सदन बनकर ही रह गया है। सन् 1911 के सप्तदीय विधेयक ने उसे परकेंच करके रख दिया है। सीनेट को जान बूझकर एक शक्तिशाली सदन के कार्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिये बनाया गया है। वास्तव में दोनों सदन ही पूँजीपति तथा धनिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही स्थापित किये गए हैं। इन दोनों सदनों की तुलना इन आधारों पर की जा सकती है—

1 उद्देश्य की दृष्टि से

(क) लाड सभा एक ऐतिहासिक सदन है जबकि इसके विपरीत सीनेट एक ऐतिहासिक सदन नहीं है। यदि लाड सभा का उद्देश्य सामन्तो तथा पूँजीपतियों के हितों की रक्षा करना है तो सीनेट भी पूँजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करती है।

(ख) एक ओर सीनेट की उत्पत्ति राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई है तो दूसरी ओर प्रतिनिधि सदन की जल्दबाजियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी की गई है परन्तु हाउस ऑफ लाडस इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता।

2 रचना की दृष्टि से

(क) लाड सभा में विविध प्रकार के सदस्य पाये जाते हैं। उसमें अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जिनका आधार वशानुगत है। सीनेट की सदस्यता का यह आधार नहीं है, न ही उसमें विविध प्रकार के सदस्य पाये जाते हैं।

(ख) हाउस ऑफ लाडस की सदस्यता एक प्रकार से उपाधि है। इसमें बानून तथा धर्म के लाडस भी होते हैं जोकि मनोनीत किये जाते हैं। सीनेट में मनोनयन की पद्धति नहीं अपनाई गई है। उसके समस्त सदस्य जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं।

(ग) हाउस ऑफ लॉर्डस् सदस्यता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वितीय सदन है। इसमें लगभग 900 सदस्य हैं। इसके विपरीत सीनेट में केवल 100 सदस्य होते हैं। अतः सीनेट आकार में भी बहुत ही छोटा सदन है।

(घ) हाउस ऑफ लॉर्डस् तथा सीनेट दोनों ही स्थायी सदन हैं किन्तु सीनेट इस दृष्टि से बहुत कुछ भिन्न है। उसमें प्रत्येक सदस्य कम से कम 6 वर्ष तक उसका सदस्य रहता ही है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् उसके $1/3$ सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।

3 अधिकारों की दृष्टि से

(क) लॉर्ड सभा विश्व का सबसे अधिक दुबल द्वितीय सदन है। किन्तु इसका विपरीत सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। सन् 1911 के सप्ततीय विधेयक के पश्चात् हाउस ऑफ लॉर्डस् की शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं। सीनेट की शक्तियों में उत्तरोत्तर विकास हुआ है।

(ख) अमेरिका में घन विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान ही हैं। लॉर्ड सभा के पास कोई प्रभावशाली वित्तीय शक्ति नहीं है। वह वित्त विधेयकों को एक माह से अधिक नहीं रोक सकती।

(ग) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा ही होती है, परन्तु लॉर्ड सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

(घ) अमेरिका में जो संधियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा होना आवश्यक है। सीनेट ने अनेकों बार ऐसी संधियाँ को अस्वीकार भी किया है। हाउस ऑफ लॉर्डस् को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

(ङ) इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल पर लॉर्ड सभा का कोई प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं है किन्तु सीनेट का राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रभावशाली नियन्त्रण है।

(च) अमेरिका में सीनेट को पदाधिकारियों, मन्त्रिमण्डल के सचिवों तथा यायावरीशा आदि के सम्बन्ध में भी अन्वेषण करने का अधिकार है। सीनेट के इस अधिकार से सब भयभीत रहते हैं। किन्तु यह अधिकार लॉर्ड सभा को प्राप्त नहीं है।

4 संवैधानिक महत्व की दृष्टि से

(क) लॉर्ड सभा की कोई संवैधानिक उपयोगिता नहीं है। यदि लॉर्ड सभा को समाप्त भी कर दिया जाय तो उसका संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु सीनेट को हटा देने पर अमेरिकी संविधान में अवरोह एवं सन्तुलन की व्यवस्था ध्वस्त हो जायगी।

(ख) लॉर्ड सभा एक बुराई मात्र है किन्तु सीनेट एक बुराई नहीं है। वह संघीय सरकार के लिए एक आवश्यकता है। सीनेट का प्रयोग संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व एवं प्रादेशिक एकता उत्पन्न करने के लिए किया गया है।

(ग) जब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित सन्ने वाले किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तब सीनेट निर्वाचनों में भी भाग लेती है किन्तु लॉर्ड सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

Selected Readings

- Carr *American Democracy in Theory & Practice*
 Finer *Theory & Practice of Modern Governments*
 Dimick & Dimock *American Govt in Action*
 Beard *American Govt & Politics*
 Munro *Govt of U S A*
 Bryce *Modern Democracies*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 अमेरिकी सीनेट के संगठन, अधिकार तथा कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
 (Critically examine the composition, powers and functions of the American Senate)
- 2 अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सीनेट के कार्यकरण का वर्णन करें। इसकी तुलना फ्रांस के सीनेट के साथ कैसे की जाती है ?
 (Discuss the role of the Senate in the constitutional system of the U S A. How does it compare with the Senate in France ?)
- 3 "अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है।" इस कथन की विवेचना करें।
 ("The American Senate is the most powerful second chamber in the world " Discuss)
- 4 अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के बीच के सम्बन्धों का वर्णन करें।
 (Examine critically the relation between the two Houses of the congress in the U S A)
- 5 अमेरिकी सीनेट के अधिकारों का वर्णन कीजिये।
 (Give an estimate of the powers of American Senate)
- 6 अमेरिकी सीनेट के कार्यों तथा शक्तियों की तुलना ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के कार्यों व शक्तियों से कीजिए और बताइये कि दोनों सदनों में कौन अधिक शक्तिशाली है और क्यों ?
 (Compare the powers and functions of the American Senate with these of the British Houses of lords and say which of the two is more powerful and why ?)
- 7 अमेरिकी सीनेट को विश्व में प्रयशक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है ?
 (Why is the American Senate considered the strongest second chamber in the world ?)
- 8 "सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है, लेकिन सार सभा की भाँति यह द्वितीय श्रेणी का सदन नहीं है।" समीक्षा कीजिये।
 ('The Senate is the second chamber at the Congress in the U S A but it is not a Secondary chamber as is the case with the British House of Lords')

राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—प्रतिनिधि सदन

[National Legislature—House of Representative]

"The House of Representative is the nature in miniature It is a mosaic of American Life" —Patterson
"The House of the Representative has gravely failed to fulfill the functions it might have been expected to perform"
 —Laski

प्रतिनिधि सदन का संगठन (Organization of the House)

प्रतिनिधि सदन अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है। यह यहाँ का लोकप्रिय सदन है। इसमें जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रारम्भ में इसके केवल 65 सदस्य होते थे परन्तु अब इसके 435 सदस्य होते हैं। इस सदन की सदस्य सख्या की अपेक्षा इंग्लण्ड में 630, भारतीय लोक-सभा में 520 तथा रूस की सर्वोच्च सोवियत में 682 सदस्य होते हैं।

निर्वाचन प्रणाली (Electoral System)

प्रतिनिधि सदन के लिए निर्वाचन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य का है। दस वार्षिक गणना के आधार पर सम्पूर्ण राज्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि सत्ताधारी दल विधायिकाओं (Constituencies) का परिशीलन इस प्रकार करता है कि उसके दल के सदस्य अधिक से अधिक सख्या में विजयी हो सकें। इस प्रणाली अथवा व्यवस्था को गैरी मण्डरिंग (Gerrymandering) कहा जाता है। अपने दल में भी कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य में इस प्रणाली का प्रयोग केवल प्रतिनिधि सदन के लिए ही नहीं किया जाता अपितु नगरीय तथा ग्रामीण नेतृत्व के लिए भी किया जाता है। गैरीमण्डरिंग अमेरिकी जीवन का सबसे अधिक दूषित तत्व है। यह लोकहित तथा जातिवाद का हनन है। क्षेत्रों को कभी कभी इतना विस्तृत कर दिया जाता है कि उसके परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष को अग्रिम हानि उठानी पड़ती है।

अमेरिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाममात्र का ही है। गौरी चमड़ी वाले मतदाताओं का वहाँ आज भी आधिपत्य बना हुआ है। महिलाओं को मताधिकार 1920 के पश्चात् ही प्राप्त हुआ है। दक्षिणी राज्यों में गौरे पदाधिकारी विविध प्रकार के प्रतिबंध लगाकर नौप्रोजनों को मताधिकार से भी वंचित करते हैं। प्रतिनिधि सदन की सम्मति प्राप्त करना तो प्रायः असम्भव ही है। गौरी

चमडी वालों ने नीगो नागरिकों को आतंकित करने के लिए कुन्-क्लक्स-क्लान (Ku KLUX KLAN) नामक संस्था का संगठन किया है। 'ग्राइमरी' की संस्था द्वारा नीगो नागरिकों का निर्वाचना से प्रायः बहिष्कार सा ही हो गया है। संविधान के 24वें संशोधन से मताधिकार कर समाप्त कर दिया गया है।

अमेरिका में निर्वाचन सापेक्षिक मतदान प्रणाली के माध्यम से होते हैं। इस प्रणाली के आधार पर निर्मित प्रतिनिधि सदन को राष्ट्र का उपयुक्त प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन की इस प्रणालि में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाया है। ये प्रत्येक प्रश्न पर क्षेत्रवाद के दृष्टिकोण से ही विचार करते हैं। सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

अर्हताएँ (Qualifications)

(1) प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

(2) उम्मीदवार कम से कम 7 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रहा हो।

(3) वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है।

उपर्युक्त योग्यताओं के अतिरिक्त सदस्यों में कुछ अन्य व्यावहारिक योग्यताओं का होना भी आवश्यक है। शासकीय पद पर आसीन रहते हुए कोई प्रतिनिधि सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। कोई भी सदस्य अपने सदस्यता काल में ऐसे सावजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जिससे कि वह पद पर रहते हुए अपनी सदस्यता का दुरुपयोग कर सके। अवाञ्छित रूप से निर्वाचित होने पर भी प्रतिनिधि सदन सीनेट की भाँति ही ऐसे सदस्यों को निष्कापित कर सकती है और उन्हें दण्डित भी कर सकती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका में भारत की तरह कोई निर्वाचन आयोग नहीं है। निर्वाचनों से सम्बन्धित विवादों का निणय भी 'मायालय' द्वारा नहीं होता अपितु उसका निणय भी सदन द्वारा ही किया जाता है। प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा सीनेट के सदस्य अधिक शालीन और विचारशील होते हैं। वास्तव में प्रतिनिधि सदन मध्यवर्गीय लोगों का सदन है। अतएव वे धन के लिए पूँजीपतियों के ही आश्रित रहते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि सदन भी पूँजीवादी वर्ग का ही प्रतिनिधि मात्र है।

कायकाल (Tenure)

प्रतिनिधि सदन का कायकाल केवल दो वर्ष का ही होता है। इसके विपरीत भारत, कनाडा तथा इंग्लैण्ड में निम्न सदन का कायकाल पाँच वर्ष का है। सम्भवतः इतनी सपु अवधि किसी अन्य लोक प्रिय सदन की नहीं होती। प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक सदस्य को 22,500 डालर वेतन प्राप्त होता है। विश्व का सर्वाधिक धन्यो सदन प्रतिनिधि सदन है। इसके सदस्यों को कई प्रकार के भत्तों भी दिए जाते हैं।

अमुक्तियाँ (Immunities)

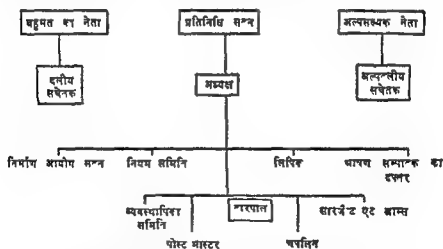
(i) सदन की आवश्यकियों में भाग लेने की स्वतंत्रता।

(ii) सदन में व्यक्त विचारों के लिये हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

(iii) इसके सदस्यों को अधिवेशन में आते जाते समय राजद्रोह के अपराध के अतिरिक्त अथ किसी अपराध के कारण बन्दी नहीं बनाया जा सकता ।

(iv) प्रतिनिधि सदन 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को उसके अनुचित आचरण के लिये बहिष्कृत कर सकता है ।

अधिवेशन (Sessions)—प्रतिनिधि सदन का वष में कम से कम एक बार अधिवेशन अवश्य होता है । प्रतिनिधि सदन के सकटकालीन अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किसी समय भी आहूत किए जा सकते हैं । वर्तमान समय में नव निर्वाचित सदन का अधिवेशन जनवरी तक अवश्य ही आहूत कर लिया जाता है, इससे पहले यह भाच में आहूत किया जाता था । पराजित प्रत्याशी भी विधि निर्माण हेतु इसके अधिवेशन में भाग लेते थे यद्यपि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अनुचित हो थी, इसीलिए ऐसे अधिवेशन को लगडी बत्तख (Lame Duck Session) का अधिवेशन कहा जाता था । यह प्रथा लोकतन्त्र के भी विरुद्ध थी । अतएव इस त्रुटि को दूर करने के लिये सन् 1923 में संविधान में बीसवा सशोधन किया गया और यह दोषपूर्ण व्यवस्था समाप्त कर दी गई । अब जनवरी तक ही नया सदन कार्य प्रारम्भ कर देता है । सन् 1946 के पश्चात् सदस्यों के लिये पेंशन व्यवस्था भी आरम्भ की गई है । प्रत्येक प्रतिनिधि को 17,500 डालर स्टेशनरी तथा लिपिक के वेतन के लिए भी मिलते हैं । प्रतिनिधि सदन में समय समय पर नियमों के विषय में जो भी निणय किए गये हैं, उन्हें 11 खण्डों में संगठित किया गया है । प्रतिनिधि सदन का संगठन इस मानचित्र से भली भाँति समझा जा सकता है—



प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी—स्पीकर

(Officers of House of Representative—Speaker)

स्पीकर प्रतिनिधि सदन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है । स्पीकर सदन का केवल अध्यक्ष ही नहीं होता, अपितु वह सदन में अपने दल का नेतृत्व भी स्वतन्त्र रूप से करता है । वह इंग्लैण्ड के स्पीकर के सदृश निष्पक्ष तथा राजनैतिक जीवन से सामास प्राप्त व्यक्ति नहीं होता । वह अपने दल के साथ सदन में प्रवेश

करता है और उसी के साथ ही पद त्याग करता है। अमेरिकी स्पीकर के सम्बन्ध में ब्रिटिश स्पीकर की वह उक्ति सुनाई नहीं देती है कि एक बार स्पीकर बनने के पश्चात् वह जब तक चाहें स्पीकर रह सकता है, इंग्लैण्ड में जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर निर्वाचन में खड़ा होता है वहाँ से विरोधी दल अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। परन्तु अमेरिकी स्पीकर के विषय में ऐसा नहीं होता है। वह बहुमत का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि होता है और उसी की शक्ति पर निर्वाचन में भी खड़ा होता है। अमेरिकी स्पीकर को इंग्लैण्ड के स्पीकर के समान सम्मान भी प्राप्त नहीं है।

एक समय था जबकि प्रतिनिधि सदन का स्पीकर अत्यन्त शक्तिशाली होता था यहाँ तक कि स्पीकर रीड (Thomas B Reed) को तो जार बहकर भी पुकारा जाता था। वह नियम समिति (Rules Committee) का अध्यक्ष होता था तथा मनमाने ढंग से अध्यय समितियों के निर्वाचन एवं नियुक्ति में भी हस्ति रखता था। बीयड का यह कहना सही है कि वह सदन का पूर्ण रूप से नेतृत्व करता है। सरकार के एक मूल्यवान् आन्तरिक अवयव के रूप में वह कार्य करता था। "वास्तव में स्पीकर उन थोड़े से प्रभावशाली नेताओं में से एक होता था जो सदन पर अपना अधिकार रखते थे।" किसी भी वाद विवाद पर अनुमति देना उसके हाथ में था। सदन में कोई विधेयक उसकी सहमति के बिना स्वीकृत होने का मयना तक नहीं देख सकता था। वही सदन की कार्यवाहियों का क्रम निर्धारित करता था। सदन में उसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी हो गयी थी। प्रो० आग के शब्दों में 'एक साधारण अध्यक्ष पद विकसित होकर एक शक्तिशाली तानाशाह का पद बन गया था, जिसके हाथ में सदन में किये जाने वाले कार्यों के जीवन का अधिकार था।'¹ परन्तु सन् 1910 का वर्ष स्पीकर के पद के लिए अत्यन्त ही अशुभ था। उस समय उसकी शक्तियों की तीव्र आलोचना हुई। स्पीकर को नियम समिति (Rules Committee) से भी वृत्त कर दिया गया। सन् 1911 में समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने की शक्ति भी स्पीकर को नहीं रही। उसकी तानाशाही का जनाजरा निवृत्त गया। परन्तु इन सब प्रतिबन्धों के होते हुए भी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अब भी पर्याप्त प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण है।

1 सदन का नेतृत्व (Leadership of the House)—सन् 1911 के पश्चात् भी सदन में वह अपने दल का नेतृत्व करता है। विधेयकों के पुरस्थापन में उसका विशेष हाथ होता है। सदन में अधिकांश नियम सम्बन्धी नियम वह अपने दल के हित में ही करता है। यद्यपि सदन का बहुमत स्पीकर द्वारा नियमों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों को परिवर्तित करा सकता है। परन्तु वास्तव में ऐसा बहुत कम ही होता है।

2 नियुक्ति का अधिकार—सदन में विशिष्ट तथा सम्मेलन समितियों का गठन स्पीकर ही करता है। यदि इन विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि जिस समिति को कौनसा विधेयक भेजा जायगा तो उसमें भी स्पीकर का नियम ही

1 A Simple chairmanship grew into a vital dictatorship carrying the power over life and death over almost everything that the house undertook to do

अंतिम समझा जाता है। वह आदेशों एवं सयुक्त प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करता है। स्पीकर को अन्य सदस्यों की भाँति भाषण करने का अधिकार है।

(3) अनुशासन का उत्तरदायित्व (Discipline in the House)—सदन में अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्पीकर का है। कौन सदस्य कब और कितने समय तक बोलेगा, इसका निणय भी स्पीकर ही करता है। भाषणों का क्रम स्पीकर ही निर्धारित करता है, सदन में अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाही करने का भी उसे अधिकार है। इसके लिये उसके पास सार्जेंट एट आम्स रहता है। यदि वह आवश्यक समझे तो दशक दीर्घाओं को भी खाली करा सकता है। मतगणना करके परिणाम को घोषित करना भी स्पीकर का ही कर्तव्य है। राष्ट्रपति से व्यवस्थापन के विषय में परामर्श करने के लिये वह ह्वाइट हाउस भी जाता है।

स्थिति (Position)—सन् 1911 का वष इंग्लैण्ड की साठ सभा के लिए तो हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ परन्तु प्रतिनिधि सदन के स्पीकर के लिए वह अशुभ ही रहा। किन्तु फिर भी अमेरिकी स्पीकर की स्थिति अब भी काफी अच्छी है। आँग सभा के का यह कहना सत्य है कि स्पीकर आज तक भी सदन में अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है।¹

उसके पास निर्णायक मत नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करता है। वह किसी अन्य सदस्य को भी अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मनातीत कर सकता है। फाइनर ने ठीक ही कहा है कि स्पीकर आज भी दलीय शक्ति का प्रतीक है। आज भी विभिन्न समितियों के गठन में उसका महत्वपूर्ण हाथ है। अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण स्पीकर थे—हैनरी क्ले विमर, कौलफावस, बिलेन, रैडाल, राइबर्न तथा रीड। बीयर्ड ने स्पीकर की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा था कि “अब नेतृत्व की शक्ति का सामुहिकरण हो चुका है यद्यपि इस समूह में अभी अध्यक्ष की प्रमुखता है।”

कांग्रेस की शक्तियाँ (Powers of the Congress)

1 विधायी शक्तियाँ—(Legislative Powers)—कांग्रेस के किसी भी सदन में कोई भी साधारण घेणी का विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु घन विधेयक केवल प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके विधायी अधिकार भी सीनेट के समकक्ष ही हैं। बिना प्रतिनिधि सदन की सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं जिस पर 2/3 बहुमत से स्वीकृति होनी आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा को ब्रिटिश सोवसभा जैसी अन्तिम निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है।

(3) अविधायी शक्तियाँ (Non Legislative Powers)

(1) जब किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेता है ऐसी अवस्था में प्रतिनिधि

सदन सबसे अधिक मत पाने वाले तीन उम्मीदवारों में से एक को निर्वाचित कर लेता है।

(2) निर्वाचन सम्बन्धी अनियमितताओं का निरीक्षण करने का अधिकार भी प्रतिनिधि सदन को है। यह अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अहताओं का सिद्धान्त लोकन भी स्वयं ही कर सकता है।

(3) राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करने से पूर्व सीनेट के साथ-साथ प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं हेतु व्यय होने वाले धन पर सीनेट के साथ-साथ प्रतिनिधि सदन भी विचार करता है। इस प्रकार वैदेशिक-नीति पर यह सदन नियन्त्रण स्थापित करता है।

(4) प्रतिनिधि सदन को अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी अधिकार है।

(5) यह सदन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के सम्बन्ध में महाभियोग की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। यद्यपि इस सदन को कमचारियों एवं सचिवों के आचरण के सम्बन्ध में शब्दों के अन्वेषण करने का अधिकार है परन्तु यह अधिकार सीनेट की अपेक्षा मग्न्य ही है।

(6) प्रतिनिधि सदन के पास आदेशात्मक एवं पयवेक्षणात्मक अधिकार भी हैं। इसे प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करने का भी अधिकार है, यह निकायों के कमचारियों एवं उनके अधिकारों तथा कृत्यों की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। उनके कार्यों का निरीक्षण करता है तथा उन्हें आवश्यक आदेश भी देता है।

प्रतिनिधि सभा की दुर्बलतायें

(Weaknesses of the House of Representative)

अब देशों में वास्तविक सत्ता निम्न सदन के हाथों में रहती है। भारत तथा इंग्लैण्ड में लोक सभाएँ ही वास्तविक रूप में सत्ताधारी हैं। परन्तु अमेरिका में स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ निम्न सदन दुर्बल तथा वरिष्ठ सदन आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट के व्यक्तित्व के मयक्ष प्रतिनिधि सदन बीना सा मालूम होता है। अमेरिकी संविधान के निर्माता चाहते थे कि प्रतिनिधि सदन ब्रिटिश लोक सभा का संशोधित संस्करण बने परन्तु उनकी आशायें धूमिल सिद्ध हुई। सास्की ने तो यहाँ तक कहा है कि 'प्रतिनिधि सभा उन कृत्यों के करने में जोकि उससे अपेक्षित हैं, बुरी तरह असफल रही है।' ¹ प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण निम्नलिखित हैं।

(1) कार्यपालिका पर नियन्त्रण का अभाव (Absence of Control on Executive) — अब देशों में निम्न सदन इस कारण से शक्तिशाली बन सके हैं क्योंकि कार्यपालिका पर उनका पूर्ण नियन्त्रण है। कार्यपालिका के प्रति उनका अविश्वास कार्यपालिका को अण्डस्थ कर सकता है, परन्तु अमेरिका में यह सम्भव नहीं हुआ है। वहाँ यदि कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ हैं भी तो वे केवल सीनेट की हैं। प्रतिनिधि सदन में उनका अभाव है।

1 The House of Representative in short have gravely failed to the functions, it might have expected to perform

(2) सीनेट की स्थिति (Position of The Senate)—संविधान स्वयं भी सीनेट को शक्तिशाली बनाना चाहता है। उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा गया है। सीनेट को राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश रखने के रूप में रखा गया है। अतएव प्रतिनिधि सदन की शक्ति पृष्ठभूमि में ही स्थित है। उसका व्यक्तित्व आच्छादित हो गया है। लागू पर प्रतिनिधि सदन का प्रभाव कम तथा सीनेट का अधिक है।

(3) अल्पावधि (Short Tenure)—प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल केवल 2 वर्ष है जबकि इंग्लैण्ड में लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। सदस्यों का आने की देर नहीं होती कि चलने की तयारी भी हो जाती है। सदस्य निर्वाचन में ही व्यस्त रहते हैं। दो वर्ष में सदन से प्रभावशाली होने की आशा भी नहीं की जा सकती।

(4) सदस्यों का स्तर (Standard of Members)—बहुत ही साधारण स्तर के व्यक्ति इसके सदस्य बनने की अभिलाषा रखते हैं। प्रबुद्ध एवं अनुभवी व्यक्ति सीनेट के ही सदस्य बनना चाहते हैं। इसके सदस्य मध्यम श्रेणी के होते हैं। वे विशेषज्ञ नहीं अपितु अनुभवशून्य होते हैं। वे अपने व्यक्तित्व द्वारा कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। उनमें सर्वोच्च दृष्टिकोण व्याप्त रहता है। सीनेट के सदस्यों के समान वे जीवन तथा देश के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं करते।

(5) विधायी शक्तियों की निष्फलता (Ineffectiveness of Legislative Powers)—जो कुछ भी विधायी शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन को मिली भी हैं, वे भी सीनेट की स्थिति के कारण अप्रभावी ही सिद्ध होती हैं। वस्तुतः इस सदन की स्थिति समर्पण तथा आधीनता की स्थिति है, संयुक्त समिति की व्यवस्था भी ऐसी है जिसमें सीनेट की इच्छा ही सर्वोपरि रहती है। केवल वित्त विधेयक की प्रस्तावना के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार इस सदन के सदस्य सीनेट को भी प्राप्त हैं। नियुक्ति, ३३ वेतन तथा सदस्यों के पुष्टीकरण में भी सीनेट की शक्ति इससे अधिक है। प्रतिनिधि सदन की स्थिति ग्लानता की ही है।

(6) आकार एवं कार्य विधि (Size & Procedure)—सीनेट आकार में अपेक्षाकृत छोटी होने के कारण अधिक प्रभावशाली है, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या यद्यपि ब्रिटिश लोक सभा तथा भारतीय लोक सभा से कम है, परंतु फिर भी वह दुबल है। सदन की समिति व्यवस्था ने प्रतिनिधि सदन के सम्मान को घटाया है क्योंकि जो कार्य समितियाँ कर सकती हैं वही कार्य सदन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि समितियाँ विधेयक के शीपक तब को परिवर्तित कर सकती हैं। यह कहना भी उचित है कि सदन तो समितियों के नियंत्रण पर मोहर मात्र लगाती है। प्रतिनिधि सदन के सदस्य स्वयं ही अपनी स्थिति से असंतुष्ट और दुखी रहते हैं।

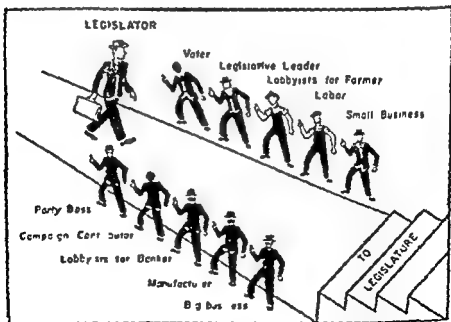
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

सर ए० हेल्प्स (A Helps) के अनुसार—“आप उन लोगों को मूख कह सकते हैं जो केवल चित्रों में ही सुंदरता देख सकते हैं। परंतु आप मानव पीढ़ियों की सूक्ष्मता और सदेहों के मूलरूप, जटिल तथा उलझे हुए विधान की सुंदरता का अनुमान नहीं लगा सकते।” मक्लीन के अनुसार ‘विधि एक ऐसा तंत्र है जो

मुस्कराते हुए ही आपको जेब काट लेता है और इसका उपयोग अध्यापक के लिये अधिक है, 'याय के लिए नहीं।' अमेरिकी विधि निर्माण की प्रक्रिया पर ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट है परन्तु उन्हें एक समान नहीं कहा जा सकता। इस अंतर का मूल कारण है प्रणालियों का अंतर। व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से विधायी प्रक्रिया का नेतृत्व नहीं कर पाती। साधारण श्रेणी का कोई भी विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अमेरिका में विधेयक को कानून बनने से पूर्व जिन सोपानों पर से अग्रसित होना पड़ता है, वे सोपान निम्न प्रकार हैं—

(1) प्रस्तुतिकरण अथवा प्रथम वाचन (Introduction or the First Reading of the Bill)—विधि निर्माण की प्रक्रिया में विधेयक की प्रथम स्थिति प्रस्तुति है। मंत्रिमण्डल के अभाव में विधेयक का स्वरूप सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत, कांग्रेस के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह समझना भी हमारी भूल होगी कि विधेयको की प्रस्तुति में राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों का कोई हाथ नहीं होता। परन्तु वास्तविकता यह है कि विधेयको के प्रारूप का निर्णय कांग्रेस के बाहर ही होता है और कांग्रेस के किसी सदस्य के नाम से ही वह प्रस्तावित किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगपति अपने हित में विधेयको को प्रस्तावित कराते हैं, अथवा कुछ अवाञ्छनीय विधेयको की प्रस्तुति को रोकते हैं। कांग्रेस के सदस्य तो केवल मध्यस्थ का ही काय करते हैं।

जैसा कि निम्नांकित चित्र से स्पष्ट है



उपरोक्त चित्र यह स्पष्ट करता है कि विधायक पर कितने प्रकार के दबाव पड़ते हैं। यदि गोलेंट में विधायक प्रस्तावित होना है तो बह्यस्त की मेज पर पड़

सदूक में विधेयक की प्रति प्रस्तावक डाल देता है। यदि विधेयक प्रतिनिधि सदन में प्रस्तावित होता है तो प्रस्तावक उसकी एक प्रति सिपिव की मेज पर रखे हुए सदूक (हूपर=Hooper) में डाल देता है। प्रस्तावक को तुरन्त ही विधेयक की क्रम सख्या मिल जाती है तथा विधेयक छपकर दूसरे दिन कांग्रेस के सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। विधेयक उस समय तक जीवित रहता है जब तक कि उस पर निर्णय नहीं हो जाता है। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है।

(2) समिति अवस्था (Committee Stage)—यह विधेयक के जीवन मरण की स्थिति होती है। विधेयक को उसी समिति के पास प्रेषित किया जाता है जिससे वह सम्बन्धित होता है। अमेरिका में समितियों का निर्माण विषयगत होता है। यदि अचानक ही यह विवाद उठ खड़ा होता है कि विधेयक किस समिति को समर्पित किया जाय तो उस समय अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है परन्तु उसके विरुद्ध सदन के समस्त अपील अवश्य की जा सकती है। यदि विधेयक सहानुभूति रखने वाली समिति के पास पहुँच जाता है तो उस पर ठीक प्रकार से विचार होता है और यदि वह विरोधी समिति के पास पहुँच जाता है तो उसे कक्ष में दफना दिया जाता है। ये समितियाँ विधेयक के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करती हैं, तथ्यों को एवजित करती हैं और उसके गहन अध्ययन के लिये उपसमितियों की रचना करती हैं। सभी कमी समितियाँ अपनी बैठकें गुप्त स्थानों पर भी करती हैं। विधेयक पर वे निर्णय लेते हैं। समिति के निर्णय का निम्नलिखित में से एक रूप हो सकता है—

(i) सम्बन्धित सदन में विधेयक को प्रस्तावित करने की सिफारिश कर सकती है।

(ii) वह यह भी सुझाव प्रस्तुत कर सकती है कि कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का प्रस्तावित किया जाय।

(iii) समिति विधेयक को समाप्त करके उसके स्थान पर नवीन विधेयक की रचना भी कर सकती है।

(iv) समिति विधेयक का मूलोच्छेदन भी कर सकती है और विरोधी सिफारिश के साथ उसे वापिस कर सकती है।

(v) समिति सदन से विधेयक को रद्द करने की सिफारिश भी कर सकती है।

(3) सूची स्तर (Calendar Stage)—ऐसा अनुमान है कि 90% विधेयकों के जीवन का अन्त समिति अवस्था पर ही हो जाता है। विधेयक पर समितियों का सर्वोच्च अधिकार होता है। वे विधेयक के शीघ्र तक में भी परिवर्तन कर सकती हैं। उपयोगी समझे जाने वाले विधेयक ही सदन को वापस लौटाये जाते हैं। सूचीकरण के स्तर पर विधेयक को विषय के अनुसार किन्हीं पाँच सूचिका में से एक में रखा जाता है।

1 सघ सूची (Union Calendar)—इसमें राजस्व, विनियोग तथा सावजनिक प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं।

2 सदन की सूची (House Calendar)—जिन सावजनिक विधेयको का सम्बन्ध वित्त से नहीं होता वे विधेयक इसके पास भेजे जाते हैं।

3 सम्पूर्ण सदन सूची (Calendar of the Whole House)—इसमें वे विधेयक रखे जाते हैं जिनका सम्बन्ध सावजनिक हित से न होकर किसी स्थानीय विषय से हो होता है।

4 सहमति सूची (Consent Calendar)—जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके सम्बन्ध में सहमति भी होती है वे इस सूची के पास भेजे जाते हैं।

5 विमुक्ति सूची (Discharge Calendar)—इस सूची के पास ऐसे विधेयक प्रेषित किये जाते हैं जिनको प्रस्तावक समिति के पास 30 दिन से अधिक रहने के कारण विमुक्त कराता है।

(vi) द्वितीय वाचन (Second Reading of the Bill)—प्रथम वाचन, समिति अवस्था तथा सूची स्तर के पश्चात् पूर्व निर्धारित तिथि पर विधेयक के ऊपर सदन में विधिवत विचार किया जाता है। परन्तु सदन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। स्पीकर अपने स्थान को त्याग देता है। अतः सदन, सम्पूर्ण सदन की समिति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House) विधेयक के उद्देश्यों पर व्यापक रूप से विचार करती है। सशोधन एवं सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। वक्ता को एक बार बोलने का अवसर अवश्य ही दिया जाता है। सदस्य विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका में विधेयक पर द्वितीय वाचन के समय ब्रिटिश लोक सभा के समान धुआँधार वाद विवाद नहीं होता। सदस्यों की भाषणों की जितनी छूट सीनेट में दी जाती है उतनी प्रतिनिधि सदन में नहीं दी जाती।

तृतीय वाचन (Third Reading)—विधेयक के जीवन का यह औपचारिक स्तर है। विधेयक की धाराओं एवं उप धाराओं के विषय में सूक्ष्म रूप से विचार नहीं किया जाता। यदि कोई सदस्य पूरे विधेयक के पढ़ने की माँग करता है तो उस दशा में विधेयक का केवल शीर्षक ही पढ़ा जाता है। विधेयक पर सदन का अंतिम निर्णय जाना जाता है। इसकी चार विधियाँ हैं—भौतिक मतदान, विभाजन, रोलकोल पद्धति तथा विद्युत के माध्यम द्वारा रोलकोल मतगणना में सदन का लिपिक सदस्यों के नाम बोलता जाता है तथा उनके नाम के सामने 'हाँ' अथवा 'नहीं' नोट करता जाता है वैसे तो आजकल यांत्रिक युग में विद्युत के उपकरणों के माध्यम से सदन का निर्णय प्राप्त कर लिया जाता है। कभी कभी अध्यक्षा मतगणना के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है जोकि गणक (Tellers) कहलाते हैं।

राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent by the President)—विधेयक के जीवन में राष्ट्रपति की स्वीकृति अन्तिम चरण होती है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसी भी विधि को अपना सकता है—

(i) विधेयक को स्वीकार कर ले।

(ii) विधेयक को पुनः विचार हेतु उस सदन को वापिस कर दे जहाँ पर वह प्रस्तावित किया गया था। यदि पुनः विचार में सदन विधेयक को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति की अनुमति का महत्व नहीं रहता।

(iii) वह तदस्य रह सकता है। उस स्थिति में विधेयक बिना उसके हस्ताक्षरों के भी कानून बन जाता है।

(iv) यदि 10 दिन की अवधि से पूर्व ही कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो रहा हो तो राष्ट्रपति शोधगामी निषेधाधिकार (Pocket Veto) का प्रयोग करके विधेयक के जीवन को समाप्त कर सकता है।

इसके पश्चात् कानूनों को सविधि पुस्तिका में अंकित कर दिया जाता है और राज्य सचिव उन्हें घोषित करता है।

अमेरिकी विधायी प्रक्रिया की ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया से तुलना (American & British Legislative Procedures Compared)

1 इंग्लैण्ड में सावजनिक तथा व्यक्तिगत विधेयकों में अंतर किया जाता है और उनकी प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। अमेरिका में यह अंतर नहीं होता है।

2 इंग्लैण्ड में अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं और वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तावित किये जाते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में मंत्रिमण्डल के अभाव में यह विधि सम्भव नहीं होती। व्यवहार में विधेयकों का प्रारूप सदन से बाहर ही निश्चित कर लिया जाता है तथा कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से उसे वहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है। अमेरिका में विधेयक की प्रस्तुति के विषय में इंग्लैण्ड के समान दस मिनट का नियम अथवा साधारण प्रस्तुति का नियम प्रयुक्त नहीं किया जाता है।

3 अमेरिका में सदन की सहमति प्राप्त करने के पूर्व ही विधेयक को छपवा लिया जाता है परन्तु इंग्लैण्ड में यह काम सदन की स्वीकृति के पश्चात् ही होता है।

4 ब्रिटेन में विधेयक की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन एक साथ होते हैं परन्तु अमेरिका में यह कार्य पृथक-पृथक होता है।

5 इंग्लैण्ड में विधेयक द्वितीय वाचन के पश्चात् ही सदन की किसी समिति के पास भेजा जाता है परन्तु अमेरिका में यह कार्य प्रथम वाचन के पश्चात् ही सम्पन्न हो जाता है।

6 इंग्लैण्ड में समितियाँ अमेरिकी सदन की समितियों के समान विधेयक के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विचार नहीं करती।

7 ब्रिटिश संसद की समितियाँ इसनी शक्तिशाली नहीं होती हैं, जितनी कि अमेरिकी समितियाँ। अमेरिकी समितियाँ 70% विधेयकों को तो चट ही कर जाती हैं और विधेयकों का पूर्णरूप से शव परीक्षण करती हैं। प्रत्यक्ष तथा गुप्त रूप से उस पर विचार करती हैं। विधेयक को कभी कभी नवीन सिरे से तयार करती हैं। उसमें संशोधन प्रस्तावित करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विधेयकों का सम्पूर्ण जीवन समितियों के हाथों में ही होता है। इंग्लैण्ड में समितियों को विधेयक को अस्वीकार करने अथवा अय इसी प्रकार के व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

8 इंग्लैण्ड में समितियों का गठन विषयगत नहीं होता, वहाँ समितियों की रचना आवश्यकतानुसार की जाती है, वे विषयगत नहीं होती। उनमें विशेषज्ञ भी रहे जाते हैं, जबकि अमेरिकी समितियों में विशेषज्ञ नहीं रहे जाते हैं।

9 इंग्लैण्ड में अमेरिका के समान कलैण्डर अवका सूची व्यवस्था नहीं पाई जाती है ।

10 तृतीय वाचन तो अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में लगभग समान ही है, उसमें केवल मत गणना की विधि का ही अंतर है ।

11 इंग्लैण्ड में सम्राट को निषेधाधिकार प्राप्त है, परंतु वह नाममात्र का ही है । प्रायः विधेयको को स्वीकृति मिल ही जाती है । सम्राट उसे रोक नहीं सकता । इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति का निषेधाधिकार वास्तविक है और इसका अनेको बार प्रयोग भी हुआ है ।

समिति व्यवस्था (Committee System)

अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली होने से समिति व्यवस्था का अनुठा महत्व है । मांजमण्डल के अभाव में सदन में नेतृत्व के अभाव की पूर्ति समितियों के द्वारा ही होती है । अमेरिका में विधि का एक बहुत बड़ा भाग समितियों का ही अनुदाय है । अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया में समिति का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है । यदि समिति में विधेयक को समर्थन मिल जाता है तो उसे चिन्ता की आवश्यकता नहीं होती है । यही उसका कठोर परीक्षण और प्रतीक्षा की घड़ी होती है । इसी कारण विल्सन ने उहें लघु विधान मण्डल कहा है ।' (Miniature Legislatures) स्पीकर रीड (Reed) ने इन समितियों का विधान मण्डल के हाथ, कान और तल कहा है । मुनरो (Munro) ने उनके महत्व को विधायी यन्त्र का तेल कह कर संबोधित किया है, जोकि उसे जलन नहीं देता । सदन की कार्यकुशलता समितियों की कार्यकुशलता पर ही अवलम्बित है । सीनेट की अपेक्षा प्रतिनिधि सदन में समितियों की संख्या बहुत अधिक है । कांग्रेस में निम्नलिखित समितियाँ पाई जाती हैं—

(1) स्थायी समितियाँ (Standing Committees)—अमेरिकी समिति व्यवस्था में इनका महत्व सबसे अधिक है । इंग्लैण्ड में स्थायी समितियों की संख्या अमेरिका की अपेक्षा अधिक है । सन् 1911 के पश्चात् इन समितियों का निर्माण स्पीकर के स्थान पर सदन द्वारा होता है, प्रत्येक समिति में 12 से 30 तक सदस्य होते हैं । कभी कभी कुछ समितियों की संख्या 50 तक भी हो जाती है । यद्यपि ये समितियों की रचना राजनैतिक दलीय आधार पर ही कर लेते हैं । सदन तो केवल ठप्पा मात्र लगाता है । समितियों के अध्यक्ष अनुभवी व्यक्ति होते हैं । वे प्रायः अपने दल के प्रमुख नेता होते हैं । सीनेट में स्थायी समितियों की संख्या 15 के लगभग होती है, जबकि प्रतिनिधि सदन में यह संख्या 19 होती है । इन समितियों का निर्माण विषयगत होता है जिनमें श्रृष्टि समिति, सैनिक समिति, अनुदान समिति, बैंक तथा मुद्रा समिति, शिक्षा व श्रम समिति, परराष्ट्र समिति, नियम निर्मात्री समिति, सैनिक कल्याण समिति आदि प्रमुख हैं ।

(2) प्रचर समितियाँ (Select Committees)—इस प्रकार की समितियों का गठन समय-समय पर विनिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से किया जाता है । उद्देश्य की पूर्ति होने पर ये समितियाँ समाप्त कर दी जाती हैं इनके सदस्यों की संख्या निश्चय नहीं होती ।

(3) **संयुक्त समितियाँ (Joint Committees)**—इन समितियों की रचना दोनों सदनों के मिले जुले सदस्यों द्वारा की जाती है। इनमें दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं। किसी ऐसे उद्देश्य के लिये इनकी रचना होती है जिसका सम्बन्ध दोनों सदनों से होता है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर ये समितियाँ समाप्त कर दी जाती हैं।

(4) **संचालन समितियाँ (Steering Committees)**—यह समिति ब्रिटिश समिति व्यवस्था में नहीं पाई जाती, वहाँ पर इसके कार्यों का संचालन मंत्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका में इस समिति का गठन बहुमत दल के सदस्यों में से ही होता है। उसका नेता ही इसका अध्यक्ष होता है। इस समिति का प्रमुख कार्य विधेयकों को विचार करके उन्हें सदन में प्रस्तुत करना और उन्हें पारित करना है। यह बहुमत दल की ओर से विधेयकों का कार्य संचालन करती है।

(5) **सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House)**—यह समिति ब्रिटेन में भी पाई जाती है। कुछ अन्तरो को छोड़कर अमेरिकी समिति व्यवस्था पर ब्रिटिश समिति व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट है। इस समिति में सदन के ही समस्त सदस्य होते हैं। इस समिति का प्रयोग वित्त विधेयकों तथा अन्य महत्वपूर्ण विवादास्पदों पर विचार करने के लिए किया जाता है। जब सदन पूरा सदन की समिति के रूप में कार्य करता है तो स्पीकर उसका अध्यक्ष नहीं रहता। समिति द्वारा निर्वाचित सदन का कोई सदस्य समिति का सभापतित्व करता है। अध्यक्ष की सत्ता का चिह्न मेज के नीचे रख दिया जाता है। समिति की गणनापूर्ति के लिए 100 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट भाषण के लिए दिये जाते हैं। इस समिति का प्रयोग सीनेट में बहुत कम होता है। इस समिति का प्रयोग संधियों आदि पर विचार करने के लिए किया जाता है। इसमें मतगणना या रिकार्ड नहीं रखा जाता। सम्पूर्ण सदन की समिति के नियमों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वे बाद में सदन के द्वारा भी अनुमोदित कर दिये जाएँ।

(6) **सम्मेलन समिति (Conference Committee)**—सम्मेलन समितियों की रचना तभी की जाती है जबकि कांग्रेस के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति नहीं हो पाती। साधारणतया, दोनों सदनों में से तीन-तीन सदस्य लिये जाते हैं। परन्तु कभी-कभी असाधारण प्रश्नों पर प्रत्येक सदन से 5 तक सदस्य लिये जाते हैं। वे अपने-अपने सदन से निर्देश लेते हैं और सदन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। हम इसे मेल-जोल समिति भी कह सकते हैं। ये पारस्परिक विवादों को सुलाने का प्रयत्न करती हैं। बहुधा यह देखा गया है कि इन समितियों में सीनेट के सदस्य अपने अनुभवपूर्ण व्यक्तित्व का लाभ उठाकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

(7) **नियम समिति (Committee on Rules)**—यह सदन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति होती है। यह सदन की स्थायी समितियों में से एक है। इसमें लगभग 12 सदस्य होते हैं। स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है। यह समिति नवीन सदन के प्रारम्भ में ही नियमों का निर्माण करती है। ये नियम सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। इस समिति में बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। ये नियमों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं जिससे कि उनके दल के कार्यक्रमों में

कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। यद्यपि अमेरिका में सदन की समितियाँ ही बहुत से विधेयकों का सम्पादन कर देती हैं परन्तु फिर भी इतने विधेयक बच जाते हैं कि उन सब पर विचार करना भी सदन के लिए सम्भव नहीं होता। उनमें से बहुत से विधेयक नियम समिति को प्रेषित किये जाते हैं। नियम समिति उनमें काट छांट करके पुनः प्रतिवेदन के रूप में सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती है जिससे सदन को उन पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। सदन की समिति ही इस बात का भी निणय करती है कि कौनसा विधेयक विचार विमर्श करने योग्य है। नियम समिति सदन तथा स्थायी समितियों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्यों का सम्पादन करती है। नियम समिति के पास व्यापक अधिकार होते हैं। यह सदन के नियमों में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है। यह विधेयकों में विलम्ब डाल सकती है। प्रायः इस समिति की बैठकें गुप्त रूप से होती हैं। सन् 1910 में सदन में स्पीकर कनन जोर्ड के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप सबसे पहला काम स्पीकर को नियम समिति से पदच्युत करना था। माशल डिमोक के शब्दों में नियम समिति वास्तविक शक्ति है।¹

प्रत्येक समिति के अध्यक्ष को पूर्वं काल में स्पीकर ही नियुक्त करता था परन्तु अब यह कार्य उसके हाथ में नहीं रहा है। अब अध्यक्षों की नियुक्ति बहुधा वरिष्ठता नियम के आधार पर ही होती है। समितियाँ अपने अध्यक्षों के कार्यों पर भी नियन्त्रण नहीं रख पाती हैं। अध्यक्ष निष्पक्षता की अपेक्षा अपने दल की नीतियों तथा उसके प्रस्तावों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। अमेरिकी समिति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक समिति तथा दूसरी समिति के कार्यों में विशेष अन्तर नहीं रखा गया है। अल्टमैन का यह कथन सही है कि 'विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति समितियों में पाई जाती है। इंग्लैण्ड की समिति व्यवस्थाओं की तुलना ब्रिटिश संविधान के अध्याय 'लोक सभा' के अन्तर्गत की जा चुकी है।

ब्रिटिश सदन तथा अमेरिकी कांग्रेस—तुलना

(British Parliament & American Congress—Comparison)

कांग्रेस तथा ब्रिटिश सदन की तुलना मनोरंजक है। कांग्रेस सचमुच ब्रिटिश सदन की पुत्री है, परन्तु पुत्री ने माता से अधिक उत्पत्ति कर ली है। दोनों ही अपने अपने देशों के प्रभावशाली विधान मण्डल हैं। दोनों ही द्विसदनात्मक हैं, परन्तु ब्रिटिश सदन का द्वितीय सदन ऐतिहासिक सदन है तथा कांग्रेस का द्वितीय सदन स्थायी सदन है, परन्तु ऐतिहासिक नहीं। हाउस ऑफ़ लाड्स की सदस्य संख्या की अपेक्षा अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या कम है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या भी ब्रिटिश लोक सभा के सदस्यों से कम है। हम और भी कई दृष्टियों से दोनों देशों के विधान मण्डलों की तुलना कर सकते हैं, जोकि इस प्रकार हैं

अमेरिका के समान ब्रिटिश सदन की समितियों को विधेयकों के सम्बन्ध में

व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे विधेयको के उद्देश्यों में परिवर्तन तथा उनकी समाप्ति नहीं कर सकतीं।

अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य पदाधिकारियों के आचरण के सम्बन्ध में इसे खोज करने का अधिकार है और इसके लिए खोज समितियों की स्थापना भी की जाती है, परन्तु ब्रिटिश सदन में यह व्यवस्था नहीं है।

इंग्लैण्ड में कायपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल के ऊपर सदन को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मन्त्रिमण्डल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। वह मन्त्रिमण्डल को अप हटाने भी कर सकती है। उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, परन्तु अमेरिका में यह अधिकार कांग्रेस को प्राप्त नहीं है। वहाँ कांग्रेस महाभियोग, नियुक्तियों को पुष्टि तथा संधियों पर स्वीकृति देकर ही अपना नियन्त्रण स्थापित करती है।

इंग्लैण्ड में सदन सविधान में सशोधन भी साधारण नियमों के समान ही कर लेती है किन्तु अमेरिका में यह सम्भव नहीं है। वहाँ पर सविधान में सशोधन करना अत्यन्त कठिन है।

इंग्लैण्ड में सदन अपने कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकती है जोकि अमेरिका में असम्भव ही है।

अमेरिका में कांग्रेस को महाभियोग की प्रक्रिया के प्रयोग करने तथा नवीन आयोगों की स्थापना करने का अधिकार भी प्राप्त है, परन्तु ये अधिकार इंग्लैण्ड की सदन को प्राप्त नहीं हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की अवस्था में, कांग्रेस को ही सबसे अधिक मत पाने वाले दो व्यक्तियों में से एक को निर्वाचित करने का अधिकार है, परन्तु ब्रिटिश सदन में यह सब कुछ सम्भव नहीं है।

इंग्लैण्ड में सदन द्वारा निमित्त विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है परन्तु अमेरिका में यह सम्भव है।

इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल सदन पर हावी रहता है जिसे हम मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व कहते हैं। सदन का कार्य अब केवल आलोचना करना मात्र ही रह गया है, नियन्त्रण नहीं। परन्तु अमेरिका में यह स्थिति नहीं है। वहाँ सिद्धांत तथा व्यवहार में कोई अंतर नहीं है और अवरोह एवं सतुलन की पद्धति के सन्दर्भ में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। वहाँ पर कायपालिका व्यवस्थापिका पर हावी नहीं रहती है।

इंग्लैण्ड में दलीय व्यवस्था की कठोरता के कारण ही सदन का महत्व कम होता जा रहा है। अमेरिका में दलीय व्यवस्था कठोर नहीं है, अतः वहाँ पर कांग्रेस में महत्व में वृद्धि होती जा रही है।

अमेरिका में दोनों सदनों की शक्तियों में समानता है, परन्तु संयुक्त समितियों में भी सीनेट अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर लेती है, परन्तु इसके विपरीत इंग्लैण्ड की सदन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर द्वितीय सदन न केवल द्वितीय सदन है वरन् वह द्वितीय श्रेणी का ही सदन रह गया है। उसकी सीनेट से कोई तुलना नहीं है।

अमेरिका में विधेयकों के निणय सदन से बाहर पहले ही कर लिये जाते हैं परंतु इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पहले विधेयक के प्रारूप पर पूर्ण रूप से विचार होता है।

अमेरिकी विधायी प्रक्रिया के प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द
लॉबीयिंग (Lobbying)

लॉबीयिंग व्यक्तिगत विधायकों तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापिका को प्रचार एवं प्रत्यक्ष सम्पर्क आदि से प्रभावित करने की एक पद्धति है। मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश सदन में इनका अस्तित्व नहीं है। लॉबीज को अमेरिकी राजनैतिक शब्दावली में उपांतिका सरकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में लॉबी उस मुख्य बरामदे को कहते हैं जोकि व्यवस्थापिका सभा के साथ सलग्न रहता है, जहाँ पर अवकाश के समय विधायक आकर बैठते हैं। जब कोई विधेयक कांग्रेस में प्रस्तुत किया जाता है उस समय विधेयक को अपने हित में स्वीकृत कराने अथवा अस्वीकृत कराने हेतु परस्पर विरोधी गुट अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों एवं हितों के रक्षाय विधायकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और अपने पक्ष के सम्बन्ध में विविध प्रकार से प्रभाव डालते हैं। वे विधायकों द्वारा विधेयकों में वाञ्छनीय संशोधन करवाने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रयत्नों को लॉबीयिंग कहा जाता है। ये लॉबीयिस्ट बड़े बड़े उद्योगों, संस्थानों (Firms), ट्रेड यूनियनों तथा बलबो आदि के अभिकर्ता (Agent) होते हैं, उन्हें पूँजीपतियों द्वारा नियमित रूप से वेतन मिलता है।

अमेरिका में लगभग 500 लॉबीज केवल वाशिंगटन में ही हैं। अमेरिका में जहाँ कहीं विधान मण्डल है वहाँ पर लॉबीज भी अवश्य ही पाई जाती हैं। कुछ विचारकों ने तो इन लॉबीज को विधानमण्डल के तृतीय सदन तक कहकर संबोधित किया है। लॉबीज कभी-कभी तो ऐसे विधेयकों का प्रारूप भी तैयार करती हैं जोकि उनके हित में हों। वे कभी-कभी निर्वाचन में अपने उम्मीदवार के रूप में उन व्यक्तियों को भी सहाय्य करती हैं जोकि उनकी नीतियों से सहमत होते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी वे अपनी नीतियों के विरोधी उम्मीदवार का विरोध भी करते हैं। अमेरिका में लॉबीज की उपयोगिता पर बल देने हुए माशल डिमोक तथा डिमोक ने कहा था कि 'लॉबीज उसी प्रकार से निश्चित हो गई है जिस प्रकार से मृत्यु एवं टैक्स¹ अमेरिका में उपांतिकावाद (Lobbyism) का प्रोत्साहन-दबाव समूह के विकास के कारण ही हुआ है। इसका एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि बड़े बड़े राजनैतिक दलों में समझौतावादी प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे दबाव समूहों (Pressure Groups) को प्रोत्साहन मिलता है। अमेरिका में दलीय राजनीति की अपेक्षा दबाव समूह राजनीति को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। जब राजनैतिक दल सावजनिक हित की बातें रखते हैं तो दबाव समूह यह सोचते हैं कि उनके हितों को बिना मात्रा में लाभ होगा। सरकार के कार्यों की मात्रा में इतनी वृद्धि हो गई है कि दबाव समूहों को अपने हितों को सुरक्षित रखने की बात बहनी पड़ती है। अतः

1 Lobbyes has come to be as certain as death and Taxes.

उपनिष्ठावाद वह प्रभाव है जोकि हितबद्ध समूह विधायकों पर विविध प्रकार से विधियों को अपने पक्ष में करवाने के लिए प्रभाव डालता है। इसके लिए इन दबाव समूहों को अवकाश प्राप्त सीनेटरो तथा अन्य उच्च प्रशासकीय पदाधिकारियों की सेवाओं को लेना पड़ता है। ये लॉबीज दबाव समूहों द्वारा ही बनाये रखी जाती हैं, उपनिष्ठावाद अनतिक्रम है परन्तु अवरोध नहीं है। इसमें वर्गीय हित की भावना है। चूँकि लोक सदन में भौगोलिक हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व उपलब्ध नहीं हो पाता है अतएव इससे विधुब्ध होकर ही दबाव समूहों का निर्माण को बल मिला है। अमेरिकन लॉबीज द्वारा जिन संगठनों का प्रतिनिधित्व प्रमुख रूप से किया जाता है वे इस प्रकार हैं अमेरिकन एसोशियसन आफ रेलवे एक्जीक्यूटिव फंडेशन ऑफ लेबर, नेशनल डेवीलियम एसोशियसन, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, तथा अमेरिकन लाइजन्स, इत्यादि।

अमेरिकन लॉबीज जिन साधनों का प्रयोग करती हैं वे इस प्रकार हैं

(1) व्यवस्थापिका के सदस्यों का विश्लेषण करना अर्थात् वे किस प्रकार के हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं उनको किस प्रकार अपने पक्ष में किया जा सकता है। कौन से सदस्य स्पष्ट एवं नैतिकतावादी हैं जिनको अपने पक्ष में नहीं बिचा जा सकता है और कौन से सदस्य सदिग्ध हैं।

(2) सदन के अध्यक्षों समितियों के अध्यक्षों एवं समितियों के सदस्यों आदि के निर्वाचनों में भाग लेना जिससे अधिक से अधिक संख्या में उनके सदस्य निर्वाचित हो सकें।

(3) विधेयकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निमित्त करना।

(4) विधायकों से उनके कार्यालयों में अवकाश सदन के प्रकोष्ठों में जाकर उनसे साक्षात्कार करना।

(5) विधायिका (Constituency) के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पत्राचार तथा सार एवं अन्य दूरभाषी यंत्रों द्वारा सदस्यों को प्रभावित करना।

(6) मित्रता एवं सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि करना और रात्रि का भोजन एवं अन्य पार्टियाँ आदि का आयोजन करना।

(7) प्रचार साधनों का प्रयोग करना।

जेरीमैण्डरिंग (Gerrymandering)

जेरीमैण्डरिंग की प्रथा बहुत पुरानी है। मसाचुसेट्स के राज्यपाल एलब्रिज-जेरी (Elbridge Cerry) के नाम से ही यह प्रथा प्रचलित हो गई है। उसने अपने राज्य को रिपब्लिकन दल का बहुमत बनाये रखने की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित किया कि वे क्षेत्र जहाँ डेमोक्रेटिक दल का बहुमत था बिखर गए और सन् 1812 में वे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके। जब डेमोक्रेटिक दल शक्तिशाली बनता है तो वह भी ऐसा ही करता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ही इस प्रकार से किया जाता है कि सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा विरोधी पक्ष का गढ़ टूट जाय। अमेरिका में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले विधायकों की संख्या, जनसंख्या के आधार पर कांग्रेस ही निर्धारित करती है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, परिसीमन, निर्माण तथा

निर्वाचन व्यवस्था एवं नियमों का निर्माण उस राज्य की सरकार ही करती है। क्षेत्रों की इस परिसीमन प्रणाली को जरी मैण्डरिंग कहते हैं। यह कहा जाता है कि राज्यपाल जरी ने इस व्यवस्था के अनुकूल एक नूतन निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्माण किया था वह सप के समान था, वहाँ पर एक चित्रकार ने आकर उसमें पक्ष, दाँत नाक आदि लगा दिए और कहा कि आप इसे सैलमैण्डर कहें, परन्तु एक सम्पादक ने उसका नाम बदलकर जैरीमैण्डर कर दिया। जैरीमैण्डर क सिद्धान्त की व्याख्या माशल डिमोक ने अपनी पुस्तक *American Govt in Action* में की है "किसी राज्य या नगर के मण्डलों को निर्मित करते समय अपनी पार्टी के समर्थित समस्त अथवा जितने भी अधिक से अधिक सम्भव हो सकें उतने अधिक जिलों को पक्षक करो। यदि आपके पास प्रत्येक जिले का नियन्त्रण करने के लिए पर्याप्त मत नहीं हैं तो अपने विरोधियों की शक्ति को कम से कम जिलों में स्थिर करो जिससे उन्हें कम से कम लाभ हो सके।"

किमी भी नैतिक दृष्टि से इस प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। कई बार इसको कानून के माध्यम से भी रोकने का प्रयास किया गया परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, परन्तु लोकमत इस प्रणाली के विपक्ष में है। अतएव यह निर्बल होता जा रहा है।

फ्लोर लीडर (Floor Leader)

अमेरिका में राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। इसीलिए वहाँ दोनों सदनो में दल का नेतृत्व फ्लोर लीडर के द्वारा होता है। फ्लोर लीडर बहुमत दल में भी होता है और अल्पसंख्यक दल में भी। सदन में बहुमत दल के फ्लोर लीडर अथवा सदनीय दल के नेता का स्थान, स्पीकर से द्वितीय स्थान पर होता है। उनकी शक्तियाँ पर्याप्त रूप से व्यापक होती हैं। सदनीय दल के नेता की नियुक्ति व्यवस्थापिका के राजनैतिक दलों के द्वारा की जाती है। इसे दलीय संगठन अथवा *Party Caucus* कहा जाता है। वह दल का प्रभावशाली व्यक्ति होता है। सदन में दलीय हितों के सरक्षण के हेतु उसकी नियुक्ति की जाती है। माशल डिमोक ने अपनी पुस्तक *American Govt in Action* में कहा है कि वास्तविक अर्थों में सफल सदनीय दल के नेता को ज्ञान, जात राजनीतिज्ञ होना चाहिए।¹ फ्लोर लीडर भावी गवर्नर राष्ट्रपति अथवा स्पीकर के पद के लिए भी सरलतापूर्वक आशावादी हो सकता है, वह केवल व्यवस्थापिका भवन तक ही सीमित नहीं रहता। जनसाधारण पर उसका व्यापक प्रभाव रहता है। भावी निर्वाचनों में कार्यकर्ता दलीय टिकट पाने के लिए उसकी ओर देख सकते हैं। फ्लोर लीडर में मधुर स्वभाव के साथ साथ ही स्वस्थ व्यक्तित्व के समस्त गुण व्याप्त होने चाहिए तथा उसमें निम्न की अद्भुत शक्ति का होना भी आवश्यक है।

वह भाषणों की व्यवस्था तथा अपने दल के वक्तव्यों का क्रम भी निर्धारित

1 'The Successful floor Leader must be a born politician in the best sense of the word
—Marshall Demoeck

करता है। वह अपने दल के सदस्यों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयत्न करता है। माथल डिमोब के शब्दों में 'वह निर्णायक तथा शांति सस्थापक दोनों ही है।'¹ वह केवल विरोधी पक्ष के अतिरिक्त सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। सदनीय दल का नेता वस्तुतः अपने दल का जनरल है और दल के सचेतक उसके कनल हैं। प्लोर लीडर सदन की विविध गतिविधियों के सम्बन्ध में दल के नेता को सूचित करता रहता है।

पौक बरल तथा लाग रोलिंग (Pork Barrel & Log Rolling)

पाक का आशय सूअर के मांस से है, बैरल से अभिप्राय है बेलनाकार पोला पात्र। दोनों शब्दों का सामूहिक अर्थ है सूअर के मांस से भरा हुआ ड्रम। गृह युद्ध से पूर्व अमेरिका में विद्यमान उसके दक्षिणी भाग में यह परम्परा थी कि वहाँ फसल काटने के बाय से निवृत्त होकर जमींदार उस ढोल को ताड़कर सूअर का मांस अपने मजदूरों में बाँटते थे। अमेरिका की व्यवस्थापिका में भी यह प्रथा पाई जाती है कि बजट से अतिरिक्त धन को विधायक अपने समयको में वितरित कराने का प्रयास करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो भावी निर्वाचना में उनके विजय की सम्भावनाएँ धूमिल पड़ जाती हैं। यह लूट खसोट पद्धति का ही एक रूप है। 'लॉग रोलिंग' भी एक पुरानी प्रथा का स्मृति चिह्न है। औपनिवेशिक काल में सीमाओं पर रहने वाले व्यक्ति लट्ठ लुढ़काने में एक दूसरे की सहायता करते थे। इसी प्रथा का प्रयोग व्यवस्थापिका में भी किया गया है। जब कोई सदस्य सावजनिक धन की माँग असावजनिक कार्यों के लिए करता है तो प्रयत्नों को वैधानिक रोग रोलिंग कहा जाता है। विधायकों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा विधायकों की सहायता भी लेनी पड़ती है। इस प्रकार के व्यवस्थापन को पौक बैरल लेजिशलेशन कहा जाता है। ये सबसे अधिन भ्रष्ट साधन हैं।

**अमेरिकी कांग्रेस की कुछ दुर्बलतायें
(Certain Weaknesses of the Congress)**

सन 1787 में अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने कांग्रेस को विविध प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न किया और यह आशा व्यक्त की कि वह विश्व को एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका के रूप में अपने स्वरूप को 'याय समत ठहरा सकेगी उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मायाधीशों के सम्बन्ध में महाभियोग की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया और इसके साथ ही वित्त पर पूर्ण अधिकार एवं संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति भी प्रदान की गई। किंतु कांग्रेस की कार्यवाही का जो स्वरूप रहा है और जिस प्रकार उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, वह केवल निराशा की बहानी मात्र ही है कांग्रेस की इस शोचनीय एवं दुर्बल स्थिति को उत्पन्न करने वाले कुछ कारण निम्नांकित हैं।

राष्ट्रीय हितों के प्रतिनिधित्व का अभाव (Absence of Representation of National interest)—कांग्रेस की निर्वाचन पद्धति इतनी दूषित है कि कांग्रेस

(How is the speaker of the House of Representatives selected ? Describe his powers and functions)

- 3 अमेरिका, भारत तथा इंग्लैण्ड के स्पीकर के अधिकारों, कृत्यों तथा स्थितियों का तुलनात्मक वर्णन करें ।

(Compare the position, powers and functions of the speakers in England, India and U S A)

- 4 यदि आपको अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनाया जाय, तो आप किस सदन की सदस्यता पसन्द करेंगे ?

(If you were offered a seat in the American Congress, would you chose the House of Representative or the Senate ? Give reasons for your answer)

5

अमेरिका की न्याय व्यवस्था [Judicial Organization of U S A]

"We are under a Constitution but the Constitution is what the Judges say it is" —Hughes

"The Supreme Court is the Constitution" —Frankfurter

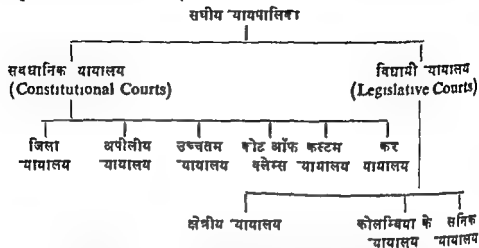
समात्मक व्यवस्था में अनिश्चितता एवं सदिग्धता का वातावरण उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है जिसका निराकरण एक स्वस्थ एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा सम्भव है। सभ की इकाइयों में विवाद होना बहुत कुछ स्वाभाविक है और उसके लिये एक निष्पक्ष न्यायिक की आवश्यकता होती है। इस कार्य का सफलता पूर्वक सम्पादन उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। सरकार के विविध अंगों में समन्वय तथा सामंजस्य बनाये रखने के लिए हमें एक ऐसी न्यायिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो शक्तियों को संतुलित रख सके तथा उनके विभाजन की सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए केवल निष्पक्ष न्यायपालिका ही उत्तरदायी है। अमेरिका में न्यायपालिका की स्वस्थ एवं निष्पक्ष व्यवस्था इसका प्रमाण है। फुल्लन तथा मैकहेनरी के अनुसार—“सभी संगठित समाजों के लिए न्यायालयों का होना आवश्यक है परन्तु शासन पद्धति एवं परम्पराओं का उनके स्वरूप पर प्रभाव होता है। इसी कारण हमें विविध देशों की न्यायपालिका संगठन में अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।” फ्रांस, सोवियत सभ तथा स्विट्जरलैण्ड के न्यायालयों में यह अंतर और भी अधिक देखने को मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के साथ तो न्यायपालिका एवं उसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। फ्रांस के शब्दों में, ‘न्यायपालिका की कार्यकुशलता के अतिरिक्त शासन की उत्तमता की अच्छी कसौटी और कोई नहीं है।’ स्वस्थ न्याय प्रगति का पथ प्रदर्शक है। फ्रांस के मतानुसार “अमेरिका की सरकार की किसी ओर विशेषता ने योरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा परिचर्चा प्रशंसा तथा गलतफहमी उत्पन्न नहीं की जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के उन कृतव्या और कार्यों ने उत्पन्न की है जिन्हें वह संविधान की रक्षा करते हुए प्रयुक्त करता है।”

संघीय न्यायपालिका का संगठन

(Organization of Federal Judiciary)

अमेरिकी संविधान की धारा तीन के अन्तर्गत अमेरिकी सभ की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में उच्चतम न्यायालय तथा इसी प्रकार के अन्य न्यायालयों

मे रखा गया है, जिनकी स्थापना समय समय पर कांग्रेस द्वारा सम्भव होती रहेगी। अमेरिकी याय सगठन की व्यवस्था को व्यापक रूप से निम्नांकित रेखाचित्र की सहायता से समझा जा सकता है—



व्यापक रूप से संघीय 'यायालयों को दो भागों में विभाजित किया गया है — संवैधानिक 'यायालय तथा विधायी 'यायालय। संवैधानिक 'यायालय वे 'यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान द्वारा की गई है और विधायी 'यायालय वे 'यायालय हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस के किसी अधिनियम के द्वारा हुई है। इनके क्षेत्राधिकार एवं स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। हम पहले संक्षेप में संवैधानिक 'यायालयों का उल्लेख करेंगे —

(1) जिला 'यायालय (District Courts)—ये संघीय 'यायपालिका के सगठन सोपान क्रम में सबसे छोटे प्रकार के 'यायालय होते हैं। कोलम्बिया जिले को सम्मिलित करके इस प्रकार के 87 'यायालय हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 जिला 'यायालय अवश्य होता है। बड़े राज्यों में एक से अधिक भी होते हैं। इनमें 1 से लेकर 24 तक 'यायाधीश होते हैं। कांग्रेस ही इस संख्या को निश्चित करती है। मुख्य 'यायाधीश इन्हें अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर सकता है। इनके पास काम बहुत होता है। ये प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 विवादों का निणय करते हैं। इन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं है। कानूनों को तोड़ने से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई इन्हीं 'यायालयों के द्वारा होती है। इन 'यायालयों के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में नौसेना, दिवालियापन पेटेंट राइट, डाकखाने तथा संघीय सरकार द्वारा रक्षित नागरिक अधिकारों के विवाद आते हैं।

(2) अपीलीय 'यायालय (Court of Appeals)—सन् 1911 से पूर्व इन्हें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स कहा जाता था। सम्पूर्ण अमेरिका में इस प्रकार के 11 'यायालय हैं जिनका सगठन क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। प्रत्येक 'यायालय में 3 से लेकर 9 तक 'यायाधीश होते हैं। इसमें निणय करने के लिए कम से कम 2 'यायाधीशों की आवश्यकता होती है। इन 'यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा होती है। इन 'यायालयों को किसी भी प्रकार का

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है। इन्हें केवल जिला 'यायालयों के निणयो के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इन 'यायालयों में प्रत्येक अभियुक्त को अपील करने का अधिकार है। उसके लिये उसे विशेष आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। इन 'यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।

(3) उच्चतम 'यायालय (Supreme Court)—उच्चतम 'यायालय देश का अंतिम अपीलीय 'यायालय है। इसकी स्थापना सन् 1789 के *The Judiciary Act* के द्वारा की गई थी। पहले इसका मुख्यालय न्यूयार्क में था, किंतु बाद में इसे वाशिंगटन में स्थानांतरित कर दिया गया तथा उस समय से इसका मुख्यालय वहीं पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का व्यापक वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जायगा।

(4) कोर्ट ऑफ क्लेम्स (Court of Claims)—इसकी स्थापना सन् 1855 में हुई थी और इसका प्रमुख कार्य सभ सरकार के विरुद्ध विवादों का निणय करना है। इसमें एक मुख्य 'यायाधिपति तथा 4 अन्य 'यायाधीश होते हैं। इन सबकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा सम्पन्न होती है। सदाचार बनाये रखने की अवधि में वे अपने पद पर रहते हैं। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में है।
विधायी 'यायालय (Legislative Courts)

(1) क्षेत्रीय 'यायालय (Territorial Courts)—इन सबकी स्थापना कांग्रेस के कानूनों के द्वारा हुई है। इस प्रकार के 'यायालय प्योरिटी रीको, वर्जीनिया द्वीप तथा पनामा नहरी प्रदेश में स्थित हैं। इन्हें जिला 'यायालय तथा अन्य स्थानीय 'यायालयों के अधिकार प्राप्त हैं। इन 'यायालयों में कार्य करने वाले 'यायाधीशों की कार्यवधि 4 वर्ष होती है।

(2) सैनिक अपीलीय 'यायालय (Military Courts of Appeals)—इसकी स्थापना सन् 1950 में हुई। इसमें 3 'यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा 15 वर्ष के लिये होती है। इसको कोई भी प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि किसी को निम्न सैनिक न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया हो तो यह सैनिक 'यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपील सुनता है। इसे उन विवादों के भी सुनने का अधिकार है जिनमें कोई जनरल अथवा एडमिरल अंतर्गस्त होता है। इस 'यायालय के निणय अंतिम होते हैं, परंतु उच्चतम 'यायालय विशेष रूप से अपील करने की अनुमति भी प्रदान कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Courts)

जब सवप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय इसमें एक मुख्य 'यायाधीश तथा पाँच अन्य 'यायाधीश थे। सन् 1807 में इनकी संख्या 7 कर दी गई। सन् 1837 में इनकी संख्या 9 कर दी गई। सन् 1863 में 10 तथा 1866 में पुनः 7 कर दी गई। परंतु सन् 1869 में इनकी संख्या 9 निश्चित कर दी गई। आजकल इसमें एक मुख्य 'यायाधीश तथा 8 अन्य 'यायाधीश हैं। 'यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भी प्रायः यही प्रयत्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति 'यायाधीश के पद पर की जाय जिस पर सीनेट की सहमति प्राप्त हो सके। क्योंकि सीनेट उसे अस्वीकृत भी कर सकती है।

9 अप्रैल 1970 में राष्ट्रपति निक्सन (Nixon) ने हेरल्ड फ़ासवाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर की थी जिसे सीनेट ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में फ़ासवाल एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति था जो प्रजातियता में विश्वास करता था, वैसे सीनेट ऐसा बहुत कम ही करती है। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में न्यायाधीशों के लिये भारत के समान अहतायें प्रतिपादित नहीं की गई हैं। न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निश्चित किया जाता है जिसकी उनकी कार्यवधि में कम नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश को 40,000 डॉलर तथा अन्य न्यायाधीशों को 35,000 डॉलर प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। भारत के सदृश अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु निश्चित नहीं है। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायाधीशों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने दिया जाता है। सदाचरण बनाये रखने तक वे अपने पद पर आसीन रहते हैं। यदि उन्होंने 10 वर्ष तक उस पद पर कार्य किया है तो उन्हें जीवन भर यह वेतन मिलता रहेगा।

यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है परन्तु वह अपनी स्वेच्छा से ही उनको पद से मुक्त नहीं कर सकता। वे कांग्रेस द्वारा महाभियोग (Impeachment) की पद्धति के माध्यम से ही सेवामुक्त किये जा सकते हैं। इसके लिए दोनों सदनों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस विषय पर सीनेट न्यायालय के रूप में कार्य करती है। यदि न्यायाधीश का अपराध प्रमाणित हो जाता है और न्यायाधीश को पदमुक्त करने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको सेवा मुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं। अभी तक अमेरिका में केवल 9 व्यक्तियों के विरुद्ध यह प्रक्रिया प्रयुक्त की गई है परन्तु केवल 4 के साथ ही यह सफल हो सकी है। सामान्यतः महाभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई विवाद अमुक न्यायाधीश पर नहीं चलाया जाता है परन्तु सैम्युल चेस (Samuel Chase) केवल इसके अपवाद मात्र हैं, जिनके ऊपर महाभियोग के पश्चात् भी एक अन्य विवाद चलाया गया परन्तु उन्हें भी सन 1805 में मुक्त कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन वाशिंगटन में ही होते हैं। इसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से प्रारम्भ होकर जून तक चलते रहते हैं। इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करता है जोकि उसका अधिष्ठायी अधिकारी है। उसी के द्वारा ही नियमों की घोषणा की जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी शक्तियाँ अधिक होती हैं अथवा उसके नियमों का अधिक महत्व होता है। नियम सामूहिक रूप से बहुमत द्वारा ही किये जाते हैं। गणपूर्ति के लिए 6 न्यायाधीशों की उपस्थिति पर्याप्त होती है। जो न्यायाधीश नियम से सहमत नहीं होता है उसके मत को भी लिखा जाता है। मुकदमों पर बहस एवं विचार सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार तक होता है। शनिवार को नियम हेतु न्यायाधीशों की बैठक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होती है। यह नियम सोमवार को मुख्य न्यायाधीश द्वारा घोषित किया जाता है। ये नियम जनता के हित के लिए समुक्त राज्य रिपोटर में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Supreme Court)—

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)—उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है जिसका उल्लेख अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस द्वारा अन्य न्यायालयों को भी ये अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं परंतु कांग्रेस उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम अथवा अधिक नहीं कर सकती। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में वे विषय सम्मिलित किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र रूप में हस्तक्षेप एवं निणय करने का अधिकार है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित विषय आते हैं

(क) संविधान, विधियों तथा संधियों से सम्बन्धित विवाद।

(ख) राजदूतों, वाणिज्य दूतों एवं राजनैतिक अधिकारियों से सम्बन्धित विवाद।

(ग) नाविक विवाद।

(घ) विभिन्न राज्यों के नागरिकों के मध्य विवाद।

(ङ) सघ राज्यों के पारस्परिक विवाद अथवा ऐसे विवाद जिनमें अमेरिका एक पक्ष के रूप में हो। संयुक्त राज्य के द्वारा किसी राज्य पर विवाद प्रतिरोपण भी इसी के क्षेत्र में आते हैं।

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)—उन विषयों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार की सूची में किया गया है अन्य सभी प्रकार के विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा अन्य निम्न सघीय न्यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह ऐसे विवादों को स्वयं विचारार्थ मगवा सकते हैं जिनमें किसी संवैधानिक व्यवस्था अथवा संधि का प्रश्न निहित हो। अपीलीय अधिकार का प्रयोग वस्तुतः उन्नीं स्थिति में होता है जबकि उच्च न्यायालय का निणय संविधान के किसी नियम के विरुद्ध होता है अथवा किसी राष्ट्रीय संधि का उसके द्वारा उच्छेदन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार पर यह परिसीमन भी लगाया हुआ है कि निम्न सघीय न्यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार केवल उस स्थिति में होगा जबकि उनके निणय इस तथ्य से सम्बन्धित होंगे कि कोई राजकीय नियम संविधान अथवा सघीय नियमों के विरुद्ध है। सन् 1936 के पश्चात् यह नियम बना दिया गया है कि क्षतिपूर्ति के ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार होगा जिनमें 3000 डालर की घनराशि का कोई विवाद अंतर्गस्त हो। फौजदारी के मामलों में उसे अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(3) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)—यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ने उसकी प्रतिष्ठा को आशा की उत्तम शिखर तक पहुँचाया है, संविधान की शक्ति एवं सामयिकता प्रदान करके सही अर्थ में संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत की प्रतिपादित

किया गया है और स्वयं अपने आपको संविधान का प्रेरक एव रक्षक बनाया गया है। इसी शक्ति के कारण उस विधानमण्डल के तृतीय सदन की सज़ा दी गई है। यद्यपि इस शक्ति का संवैधानिक औचित्य स्पष्ट नहीं है। परन्तु फिर भी प्रभुत विद्वान इस शक्ति को संविधान में निहित मानते हैं। यह सघातमक व्यवस्था तथा शक्ति पुष्टकरण के सिद्धांत के अनुकूल है। यदि यह शक्ति न हो तो सर्वोच्च न्यायालय अपने अस्तित्व को सायक मिट्ट नही कर सकता। इसी के माध्यम से वह एक कार्यपालिका की उद्दण्डता तथा दूसरी ओर कांग्रेस की उच्च खलता पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह तो दो धार वाला शस्त्र है, समय समय पर इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। 'यायिक पुनर्विलोकन में अभिप्राय यह है कि 'यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में यह अधिकार है कि वह विधान मण्डल तथा कार्यपालिका द्वारा स्वीकृत ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दे जोकि संविधान की किसी भी धारा अथवा उसकी मौलिकता का उल्लंघन करता हो। 'यायिक पुनर्विलोकन का यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही नहीं है। यह अधिकार राज्य के उच्च न्यायालयों को भी है कि वे राजकीय विधान मण्डलों द्वारा स्वीकृत कानूनों को अवैध घोषित कर दें। सम्भवतः इसी कारण ह्यूज ने कहा था कि "हम एक संविधान की छत्रछाया में निवास करते हैं और संविधान वह है जो 'यायाधीश कहते हैं।'¹ फ्रैंक फर्टर के शब्दों में तो सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है।² सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सका है। लास्की के शब्दों में यह सस्था (Judicial Review) इतनी सफल है कि किसी भी अन्य सस्था ने समुक्त राज्य अमेरिका के जीवन पर इससे अधिक प्रभाव नहीं डाला।"

वस्तुतः यायिक पुनर्विलोकन कार्यपालिका द्वारा इस तथ्य का निणय है कि विधानपालिका अथवा कार्यपालिका का व्यवस्थापन एवं अधिशायी आदेश संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं। उच्च न्यायालय भी यह देखते हैं कि राज्य विधान मण्डल तथा कार्यपालिका के किसी आदेश द्वारा सशरीर विधि अथवा सश्रि का उल्लंघन तो नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय इस बात का निणय करता है कि सरकार के अन्य दो अंगों ने अपनी शक्तियों का कहीं अतिउच्छेदन करके सामाजिक हित को विक्षिप्त तो नहीं किया। 'यायिक पुनर्विलोकन कार्यपालिका तथा विधान मण्डल के पट्टा के विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्यवाही है। यह दोहरी नियंत्रण व्यवस्था है। सन 1933 में कांग्रेस ने निराश होकर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रपति को विविध प्रकार की सविवेक निणय की शक्तियाँ प्रदान की थीं जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया।³ व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के इस प्रत्याधिकरण को अशुद्ध एवं नियमों तथा संवैधानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया गया है। सन् 1801 में सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को उद्दीप्त करने वाले

1 We are under a constitution and the constitution is what the Judges say it is — Hughes

2 Supreme court is the constitution

— Frankfurter

3 उदाहरणार्थ—Panama Refining Company Vs Ryon का विवाद।

दूरदर्शी, मुख्य "यायाधीश जॉन मार्शल (John Marshal) ने प्रसिद्ध विवाद *Marbury Vs Madison* में कहा था कि उच्चतम "यायालयों को कांग्रेस अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी ऐसे व्यवस्थापन को अवैध घोषित करने का अधिकार है जिससे संविधान की किसी धारा का उल्लंघन होता हो। इसी विवाद में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि संविधान एक लिखित प्रलेख है जो स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों को नियमित एवं सीमित करता है। उन्होंने इस सम्बंध में यह भी बताया था कि संविधान एक मौलिक कानून है तथा कांग्रेस के द्वारा पारित किये गये साधारण कानून से उच्चतर है। जॉन मार्शल ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जा शपथ "यायाधीश पदासीन होते हुए लेता है वह उसे इस बात के लिए विवश करती है कि वह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करके अशुद्ध व्यवस्थापन की दुर्गति को रोके। जॉन मार्शल के चिरस्मरणीय निणय पर टिप्पणी करते हुए फर्ग्युसन तथा मक हैनरी (Ferguson & Mc Henry) ने कहा है कि "यद्यपि उसकी युक्ति की आलोचना की जाती है और उसके तर्कों को गलत बताया जाता है, परन्तु फिर भी "यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिकन शासन प्रणाली का एक सुदृढ़ भाग बन गया है।"

"यायाधीशों ने वस्तुतः संविधान की भाषा तथा उसकी आत्मा की ही रक्षा नहीं की है अपितु शासकीय नीतियों को भी व्यापक मात्रा में प्रभावित किया है। सन् 1905 में लोचनर बनाम "यूयाक विवाद में उच्चतम यायालय ने उस प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया था जिसके द्वारा प्रतिदिन काम के घण्टों को सीमित कर दिया गया था। सन् 1918 में *Hammer Vs Dagenhart* में सर्वोच्च "यायालय ने कांग्रेस को उस कानून को अवैध घोषित किया था जिसमें बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित किया गया था। सन् 1922 के *Bailey Vs Drexel Furniture Co* के विवाद में उच्चतम "यायालय ने कांग्रेस के इस प्रयास को विफल कर दिया जिसका लक्ष्य बच्चों के श्रम का उन्मूलन करना था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सर्वोच्च "यायालय ने वहाँ के जन जीवन को विविध रूपों में देखा है और उसे प्रभावित भी किया है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहा गया है। फाइनर ने इसे उस सीमेन्ट की सजा दी है जिसने समस्त ढाँचे को जोड़ा हुआ है।¹

मुनरो के शब्दों में "अमेरिका के सर्वोच्च "यायालय की शक्ति इतनी अधिक है कि इतनी शक्ति का प्रयोग विश्व के अन्य किसी "यायालय ने बहुत ही कम किया है।" हैस्कन के शब्दों में, "यह अनेक बातों में अमेरिकी राजनैतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व में सबसे बड़ा "यायिक संगठन है।" "यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा उच्चतम "यायालय ने सदैव ही अमेरिकी विधानपालिका को आश्रित की स्थिति में रखा है।"²

1 It is the cement which has fixed the whole Federal Structure
2 It has kept the American Legislature permanently in a state of
he has naturally the ways of child

न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना (Criticism of Judicial Review)

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल अपने स्वत्वों की ही रक्षा की है, अपितु उसने सविधान की प्रभुता की रक्षा करते हुए नीकरशाही पर अक्रुश भी रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने गति एवं गरिमा प्रदान करके तथा राज्यों की प्रांतीयता को निरुत्साहित करके राष्ट्रीय एकता की रक्षा की है परंतु फिर भी कुछ न कुछ कारणों से विविध लेखकों द्वारा उसकी आलोचना भी की गई है।

(1) मौलिक कृत्यों की उपेक्षा (Disregard of Fundamental Duties)—

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के विरुद्ध एक तक यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की रुचि विवादास्पद एवं न्यायिक कार्यों में कम तथा राजनैतिक कार्यों में दिन प्रतिदिन की गति से अधिक बढ़ती जा रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निणय राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक नीतियों से अधिक प्रभावित रहते हैं। यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है। आज कांग्रेस सामान्य इच्छा को कानून का स्वरूप प्रदान कर उसे लागू करवाने में अपने को असमर्थ पाती है। कभी कभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपात एवं राजनैतिक दृष्टियों की दूषित चपेट में आकर ऐसे अमानवीय निणय तक दिये हैं जो नैतिकता के उच्च स्तर से गिरे हुए कहे जायेंगे। ड्रेडस्कॉट बनाम स्टेनफोर्ड (Dred Scot Vs Standford) के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दासता का समर्थन किया, जिसका परिणाम था गृहयुद्ध। तात्कालिक राष्ट्रपति लिंकन ने प्रत्यक्ष रूप से इसकी भर्त्सना की थी। सन् 1937 में रूजवेल्ट की नूतन आर्थिक नीति को भी अवैध घोषित किया गया जिससे आर्थिक संकट के भारों फँस जाने का पूरा-पूरा भय उत्पन्न हो गया था। अतः यह कहना गलत नहीं है कि लोकतंत्र तथा समय की आवश्यकताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय अपनी गति को मिलाकर नहीं चल सका है।

(2) निर्णयों में एकरूपता का अभाव (Absence of Uniformity in Decisions)—नेल्स ने कहा है कि "न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार परिवर्तनशील हैं जिस प्रकार नक्षत्री सिलक के रंग परिवर्तनशील होते हैं और वे राजनैतिक घूप के कारण शीघ्र बदल जाते हैं।" वस्तुतः न्यायपालिका की लोकप्रियता एवं उस पर विश्वास का आधार है निष्पक्षता जो अमेरिका में प्रायः सुलभ नहीं हो पाती। "न्यायाधीशों को सखीय राजनीति से ऊपर होना चाहिए तथा उन्हें समय की विचारधारा से अप्रभावित रहकर अपने को प्रश्न की विशुद्ध वैधता अथवा अवधता तक सीमित रखना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश अमेरिका में न्यायपालिका समय की विचारधारा तथा देश की दलगत राजनीति से प्रभावित रहती है और उनके निर्णयों पर उनकी कल्पित एवं सखीय विचारधारा का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। इसी कारण अमेरिका की न्यायपालिका में निर्णयों में एकरूपता का अभाव रहा है वे समय की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं। उनके निर्णय अनुचित रूप में कभी सभ के पक्ष में तो कभी राज्य के पक्ष में हुए हैं।

(3) सत्ताराम्य राज्य का विकास सम्भव नहीं हो पाता (Growth of positive State becomes Difficult)—सन् 1848 में अपनी अमेरिकी यात्रा के

पश्चात् फ्रैंच विचारक डी० टोब्यूवेली ने कहा था कि "यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे कि अमेरिकन कुलीनता कहीं पर निवास करता है तो मैं निःसंकोच यह कह सकता हूँ कि यह 'यायाधीशों में निवास करता है।" प्रत्येक प्रश्न चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, न्यायिक प्रश्न बन जाता है। 'यायाधीश प्रायः सम्पन्न परिवारों से सम्बन्धित व्यक्ति होते हैं जो प्रगति के नाम से ही भय खाते हैं। वे प्रगतिशील व्यवस्थापन का स्वागत करना तो दूर रहा उसे शमशान से जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं और उन्हीं के पक्ष पोषण में सजे रहते हैं। प्रगति में उनकी कोई रुचि नहीं होती। सविधान के नाम पर 'याय की समीक्षा एक दिखावा मात्र ही है।

(4) विधान मण्डलों का स्तर नीचे गिरा है (Prestige of Legislatures has Gone Down)—न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का एक अत्यन्त घातक परिणाम यह हुआ है कि विधान मण्डलों का सम्मान कम हुआ है और 'यायपालिका की हस्तक्षेप की नीति में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है। शताब्दी से प्रचलित आग्रह आरोपित करने के अधिनियम को सन् 1895 में इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि इससे व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार का हनन होता है। इसी प्रकार सन् 1905 में लोचनर बनाम 'यूयाक (Lochner Vs New York) के विवाद में 'यूयार्क राज्य के उस आदेश को अवैध घोषित कर दिया गया था जिसका उद्देश्य बेकरियों में काम करने वाले श्रमिकों के कार्य करने के समय को निश्चित करना था। वास्तविकता यह है कि निषेध बहुमत से होते हैं, अतएव उनमें एकरूपता बनी रहना कठिन ही है। वास्तव में लोकतन्त्र में विधानमण्डल का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, वही जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु 'यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को 'यायिक अधिनायकत्व (Judicial Dictatorship) की संज्ञा दी गई है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो विधानपालिका अपने कृतव्यों की पूर्ति में असफल हो जायगी और प्रगतिशील व्यवस्थापन के अभाव में लोकहितकारी राज्य का प्रासाद ध्वस्त हो जायगा। विधान मण्डल की आश्रित की स्थिति में रखने में भयंकर परिणामों के उत्पन्न होने की आशंका है।

यह भी सत्य ही है कि उच्चतम 'यायालय ने कभी कभी पुनर्निरीक्षण की शक्ति का दुरुपयोग किया है किन्तु इसका उपयोगी पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और सम्भवतः इसी कारणवश इतनी तीव्र आलोचना के होते हुए भी इसको समाप्त नहीं किया जा सका है। सन 1937 के पश्चात् सर्वोच्च 'यायालय के व्यवहार में उत्तरोत्तर उपयोगी परिवर्तन होता जा रहा है। इसने आर्थिक सुधार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कई अधिनियमों को अवैध घोषित नहीं किया। सन 1954 में एक ऐसे अधिनियम को सर्वोच्च 'यायालय ने अवैध घोषित किया जिसके अन्तर्गत स्कूलों में प्रजातीयता (Racial Basis) के आधार पर भेदपूर्ण व्यवहार किया जाता था। रेड कोड तथा ट्रूमैन का ऐसा विचार है कि बहुत से सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर सर्वोच्च 'यायालय ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए शासन को विवश किया है।

इसके अतिरिक्त आज अमेरिकी सविधान जो कुछ भी है वह सर्वोच्च 'यायालय

का महत्वपूर्ण अनुदाय ही है, इस सहयोग की अनुपस्थिति में संविधान को पोलियो (एक प्रकार का रोग) हो गया होता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं द्वारा संविधान को गति एवं जीवन प्रदान किया है। संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधान मण्डल तथा कायपालिका के मध्य सन्तुलन भी बनाये रखा है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों की सरकारों को नियंत्रण में रखा है। न्यायपालिका को जन श्रद्धा प्राप्त हुई है। फाइनर ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 'सर्वोच्च न्यायालय ने सीमेण्ट की तरह सारे संघीय ढाँचे को जोड़ रखा है।'¹

उच्चतम न्यायालय की प्रगति में जस्टिस मार्शल का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा है। यह विश्व की अमेरिका की मौलिक देन है। लास्की के शब्दों में, "अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय तथा उससे भी अधिक वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त है उतना संयुक्त राज्य के जीवन पर उसका प्रभाव भी है।"

Select Readings

- James Beck *Government of United States*
 C A Beard *American Govt and Politics*
 Brogan *The American Political System*
 Dimock *The American Government in Action*
 Ferguson and McHenry *The American system of Govt*
 Ogg & Zink *Modern Foreign Govts*
 Munro *The Govt of U S A*
 C G Hains *The American doctrine of Judicial Supremacy*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 'वास्तव में उच्चतम न्यायालय पुनरीक्षण की शक्ति द्वारा अमेरिका का तृतीय सदन बन गया है।' व्याख्या कीजिए।
 (Supreme Court by exercising the powers of Judicial Review has become in fact the Third Chamber in U S A —(Lasky), Discuss)
- 2 उच्चतम न्यायालय के सगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अमेरिका के राजनैतिक जीवन में इसका क्या महत्व है?
 (भागरा 1968, मेरठ 1970, सागर 1968)
- 3 उच्चतम न्यायालय को संविधान का रसक कहा गया है। क्या आप इस मत से सहमत हैं?

1 Supreme Court has been the Cement which has fixed the whole federal structure —Finer

अमेरिकी राजनैतिक दल

[American Political Parties]

"Ordinarily our parties are parties of Circumstances and not of principle —Amerson

Congress is disconnected with Executive but party organization brings the two together at times" —Finer

अमेरिकन दल पद्धति के विषय में मुनरो (Munro) ने कहा है कि "उन्होंने जिस शिला को अस्वीकार कर दिया था वही शिला शासन पद्धति का आधार बन गई है।"¹

अमेरिका के जनतन्त्रीय जीवन में आज उन राजनैतिक दलों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि हम उसे पृथक् कर ही नहीं सकते। शक्ति विभाजन के दोषों को कुछ सीमा तक दूर करने में राजनैतिक दलों का योग भी कम नहीं है। राजनैतिक दल शासन को जीवन तथा गति प्रदान करते हैं, यह बात भी सही है कि लोकतन्त्र में राजनैतिक दलों को सबसत्तावादी व्यवस्था की भाँति सर्वव्यापक अस्तित्व प्रदान नहीं किया जाता परन्तु वे अपने कार्यक्रम, दलीय नीतियों, राष्ट्रीय प्रश्नों पर आधारित दृष्टिकोण एवं अन्तर्राष्ट्रीय विचारों द्वारा लोकमत का निर्माण करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचन में सफलता प्राप्त करके शासन का निर्माण करते हैं और जनता के प्रति किये गये अपने वायदों की पूर्ति करते हैं। इससे विपरीत विरोधी दल अपनी आलोचना द्वारा जन शिक्षा का प्रसार करके सरकार के कृत्यों पर अकृश एवं नियन्त्रण रखते हैं।

अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने विदायी भाषण में कहा था कि 'दलगत विद्वेष में सभी के लिये नुराई तथा हानि छिपी हुई है। अतएव प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। दलगत विद्वेष से लोकप्रिय सत्स्थाएँ क्षीण होती हैं और प्रशासन में दुर्बलता आती है। यह दलीय भावना समय समय पर विद्रोह एवं दंगे का कारण बनती है।' जॉर्ज वाशिंगटन के उक्त विचारों से दलीय राजनीति अथवा व्यवस्था के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। अमेरिकी संविधान के निर्माता राजनैतिक दलों की उपेक्षा करते थे और सदीय व्यवस्था के लिये उसे

1 "The stone which the builders rejected has become the chief stone of the Corner —Munro

घातक समझते थे। वे नवजात लोकतंत्र के लिये दलीय व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। किन्तु जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसी समय निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध राजनैतिक दला का बीजव्ययन हो चुका था। संविधान निर्मात्री सभा का एक पक्ष ऐसा था जो शक्तिशाली संघ तथा राज्यों की अधीनस्थ स्थिति के पक्ष में था और इस प्रकार वह राज्यों की शक्ति द्वारा निमित्त सघातक व्यवस्था का विरोधी था। क्रमशः इसे संघवादी तथा एंटीफेडलिस्ट कहा जाता था। इसमें प्रथम गुट का नेता हैमिल्टन था तथा द्वितीय गुट का नेता जेफरसन था।

जॉज वाशिंगटन ने दोनों ही गुटों को अपने मंत्रिमण्डल में समायोजित करने का प्रयत्न किया। परन्तु हैमिल्टन के व्यवहार के फलस्वरूप जेफरसन के नेतृत्व में एक ऐसा गुट बन गया जिसके सदस्य रिपब्लिकन (Republicans) कहलाते थे। सरकार पर संघवादी गुट का ही प्रभुत्व बना रहा। द्वितीय राष्ट्रपति जॉर्ज एडम्स के समय (1798) में *Alien & Sedition Act* को लेकर संघवादियों में फूट पड़ गई और निर्वाचन में संघवादियों को करारी हानि खानी पड़ी। रिपब्लिकन गुट को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। अमेरिका के शासन पर सन् 1824 तक इसी गुट का प्रभुत्व बना रहा। जेफरसन के पश्चात् जेम्स मैडीसन तथा थुमरो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन् 1820 के लगभग संघवादी दल की ख्याति इस सीमा तक क्षीण हो चुकी थी कि इस वयं उसमें इतना साहस भी नहीं रहा था कि वह राष्ट्रपति पद के लिये अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सके। परन्तु रिपब्लिकन गुट भी दो भागों में विभाजित हो गया था—नेशनल रिपब्लिकन (National Republicans) तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन (Democratic Republicans)। प्रथम दल स्वभाव से उदारवादी तथा दूसरा दल अनुदारवादी था। राष्ट्रपति जेक्सन के नेतृत्व में अनुदारवादी दल सन् 1828 में विजयी हुआ और सन् 1840 तक यह दल शासकीय शक्ति को अपने अधिकार में किये रहा। दासता के प्रश्न को लेकर दोनों दल हिलकर रह गये। नेशनल रिपब्लिकन दल तो लगभग नष्ट ही हो गया। वर्तमान रिपब्लिकन दल का उदय उसी के खण्डहरों के अवशेषों पर ही हुआ है। सन् 1860 में लिंकन राष्ट्रपति बने तथा 1885 तक रिपब्लिकन दल का ही प्रभुत्व बना रहा। आर्थिक नीति के प्रश्न को लेकर दोनों दलों में अंतर था किन्तु हताश होकर डेमोक्रेटिक दल ने उस अंतर को भी समाप्त कर लिया।

सन् 1912 में दलीय व्यवस्था में एक और मोड़ आया। रिपब्लिकन दल के पारस्परिक विरोध के कारण डेमोक्रेटिक दल की सफलता मिली तथा विल्सन राष्ट्रपति बने। वे सन् 1920 में सीनेट के तीव्र विरोध के कारण अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने में असमर्थ रहे जिसके परिणामस्वरूप सावजनिक निर्वाचनों में उनके दल की बरारी हार हुई। रिपब्लिकन दल 20 वर्षों तक सत्ताधारी रहा। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवीन नीति (New Deal) का निर्धारण किया। सन् 1952 से लेकर 1960 तक यह दल पुनः अमेरिका के राजनैतिक जीवन पर प्रभुत्व शील रहा। सन् 1964 में कनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए परन्तु बाद में टेक्सास में उनकी हत्या कर दी गई। सन् 1964 में डेमोक्रेटिक दल के नेता के

रूप में जॉनसन राष्ट्रपति पद पर पुनः आसीन हुए। रिपब्लिकन प्रत्याशी गोल्डवाटर पराजित हो गए। सन 1968 में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन दल के टिकट पर विजयी हुए। अभी हाल में अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति भारी बहुमत से अपने डेमोक्रेटिक दल के प्रतिद्वंद्वी नेता मैकगवर्न को परास्त करके विजयी हुए हैं।

अमेरिका में दो बड़े राजनैतिक दलों के अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे राजनैतिक दल भी हैं, जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है। इनमें से कुछ प्रमुख दल निम्न प्रकार हैं

एंटी मेशन्स पार्टी (Anti Masons Party) अब यह समाप्त हो गई है।

प्रोहिबिशन पार्टी (Prohibition Party) इसका जन्म 1872 में हुआ।

प्यूपुलिस्ट पार्टी (Populist Party) इसका जन्म 1820 में हुआ।

प्रोग्रेसिव पार्टी (Progressive Party) इसका जन्म 1912 में हुआ।

सोशलिस्ट लेबर (Socialist Labour)।

सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (Socialist Democratic Party)।

कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसका जन्म फार्मर लेबर पार्टी (Farmer Labour Party) में परस्पर गुटबन्दी के कारण हुआ।

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर (American Federation of Labour)। तथा कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन (Congress of Industrial Organization) आदि इस प्रकार के अन्य श्रमिक समुदाय भी हैं।

कभी-कभी एक बड़ा ही तकसगत प्रश्न यह किया जाता है कि जब सविधान के निर्माता ही यह नहीं चाहते थे कि अमेरिका में राजनैतिक दलों का विकास हो तो फिर वे कौन से कारण थे जो उनके विकास के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। सम्भवतः, इसका प्रमुख कारण आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का मिश्रण ही रहा होगा। लोकप्रिय संप्रभुता को व्यावहारिक स्वरूप एवं सही नेतृत्व केवल राजनैतिक दलों से ही प्राप्त हो सकता है। राजनैतिक दल ही लोकमत को संगठित स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। अमेरिका जैसे घनाङ्ग देश में व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न पर भी आर्थिक हितों की दृष्टि से कई प्रकार के राजनैतिक समूह बन गये हैं। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों के विकास का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। सत्ताधारी तथा सत्ता से पृथक् व्यक्तियों में परस्पर द्वेष की भावना का विकास होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। यदि लोकतन्त्र को जीवित रखना है, तो उसे राजनैतिक दल रूपी ऑक्सोजन देना भी आवश्यक है। वर्तमान बौद्धिक प्रगति तथा प्रावधिक विकास ने राजनैतिक दलों के गठन को और भी अधिक सरल बना दिया है।

राजनैतिक दलों के कार्यक्रम

(Programme of Political Parties)

अमेरिकी गणतन्त्र का इतिहास इस तथ्य का चोक्त है कि वहाँ पर सदय ही दो राजनैतिक दलों का प्रभुत्व रहा है। तीसरे दल की माँग का राष्ट्र ने समर्थन नहीं दिया अमेरिका तथा इंग्लैंड दोनों ही देश ऐसे लोकतन्त्रीय उदाहरण हैं जहाँ

पर सदैव ही दो दलों का अस्तित्व रहा है। फ्रांस में सगभम 12 राजनैतिक दल हैं। इसका मूल कारण अनुभव है जिसको अमेरिकावासियों ने इंग्लैण्ड के राजनैतिक जीवन से प्राप्त किया है एक लेखक ने ठीक ही कहा है कि द्विदलीय व्यवस्था राजनैतिक परंपर्यता का चिह्न है।¹ इससे अतिरिक्त ब्रिटेन तथा अमेरिका में सोव राजनीति की खोल बूद के सदृश समझते हैं। वे पारी की दृष्टि से राजनीति को देखते हैं जब किसी पद को राजनैतिक दल प्राप्त करने की सोचता है तथा उसके लिए प्रयत्न भी करता है तो उसमें दो दलों की ही सम्भावना रह जाती है। अमेरिका के संविधान में तो राजनैतिक दलों के अस्तित्व में आने का मूल आधार ही संविधान निर्माण के समय भी सदस्यों का दो गुटों में विभाजित होना था—संघवादी तथा असंघवादी। इसके अतिरिक्त सोवतंत्र में जनमानस में भी ऐसी धारणा बन जाती है कि नवीन दल प्रभावशाली नहीं रह पायेगा, उसके पास अनुभवपूर्ण नेतृत्व नहीं होगा तथा उसके पास धन का भी अभाव रहेगा। इसी कारण से ही वे वर्तमान दलों को ही समर्थन प्रदान करते रहते हैं। प्रशासन द्विदलीय व्यवस्था में ही स्थायी रह सकता है। बहुदलीय व्यवस्था अनुनिर्मेयी अपवा तरंगी होती है। उनके विषय में कोई भी निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। एक सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र तथा शीघ्र कार्यपालिका के निर्वाचन की विधि ही ऐसी है जिसमें कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं समा पाती।

दोनों दलों के कार्यक्रमों में विशेष अंतर नहीं है। वे एकसे ही कार्यक्रमों का अनुमोदन करते हैं। इसी कारण ब्राइस ने कहा है कि “अमेरिकी राजनैतिक दल दो बोलतों के सदृश हैं जो खाली हैं परन्तु उन पर अंकित (Label) प्रथक प्रथक हैं।”² ब्रिड ने ठीक ही कहा है कि “दोनों दल भावनाओं एवं विचारों तथा इच्छाओं में बिल्कुल एक समान हैं तथा मतदाता खोलले शब्दों को मत देते हैं।”³ फाइनर का कथन भी उचित ही है कि “अमेरिका में केवल एक दल—‘रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल’ है जो कि स्वभाव एवं पदों की स्पर्शा के कारण ही दो भागों में विभाजित है। प्रो० जार्डन (Jordan) ने भी ठीक ही कहा है कि ‘सिद्धान्तों की दृष्टि से रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दोनों दलों में कोई मतभेद नहीं है। वे दोनों बधिया सूअरों के समान हैं जिनमें से एक मोटा है और उसके दोनों पर नाद में हैं दूसरा दुबला पतला व्याकुल पशु है जो स्वयं के लिए किसी स्थान की प्राप्ति करने लिए पूरा रूप से प्रयत्नशील रहा है। नाद अंतिम उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है।’ रिपब्लिकन दल के सिद्धांत इस प्रकार हैं

- 1 संघ के समस्त राज्यों के मध्य दृढ़ संगठन।
- 2 राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन।
- 3 साम्यवाद का विरोध।

1 Two party system is a sign of political maturity
 2 The American Parties are like two bottles each with different labels and both are empty —Bryce
 3 The two parties are substantially identical in their aspirations intentions and desires and the voters are reduced to phantoms voting for empty words —Beard

- 4 सैनिक शक्ति में विश्वास ।
- 5 उत्पादकों तथा श्रमिकों के हित का समर्थन ।
- 6 उद्योगों की राष्ट्रीयकृत व्यवस्था का विरोध ।
- 7 राष्ट्रवादी चीन का विरोध तथा राष्ट्र सघ में चीन की सदस्यता का

विरोध ।

डैमोक्रेटिक दल जिन सिद्धांतों का समर्थन करता है, वे इस प्रकार हैं

- 1 सघीय व्यवस्था का समर्थन ।
- 2 साम्यवाद का विरोध ।
- 3 एटलांटिक सघ का समर्थन ।
- 4 व्यक्तिगत उद्योगों का समर्थन ।
- 5 पिछड़े देशों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम का समर्थन ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों दलों के सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं है ।

राजनैतिक दलों का संगठन (Organization of Political Parties)

माशल एडमोक डिमोक (Dimock) ने ठीक ही कहा है कि “किसी भी राजनैतिक दल की शक्ति उसके दैनिक कार्यकर्ताओं में ही होती है और उनमें से कुछ ही व्यक्ति अधिक एवं राजनैतिक समस्याओं को सुलझाने में सफल हो पाते हैं ।” अमेरिका में राजनैतिक दलों के संगठन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) स्थायी संगठन (Permanant Organization)

(अ) स्थानीय संगठन (Local organization)—राजनैतिक दलों का संगठन एक पिरामिड के सदृश है । इसका आधार पर्याप्त व्यापक होता है । शीर्ष की ओर जाते समय स्थानीय संगठन का स्वरूप संकुचित होता जाता है । माशल डिमोक ने सही कहा है कि “अधिकांश राजनैतिक दलों की शक्ति का मूल आधार स्थानीय संगठन ही होते हैं ।” इस दृष्टि से सबसे निम्न संगठन विभागीय समितियों का है जिनकी संख्या लगभग 1 25 000 है, इन्हें प्रीसिक्ट्स (Precincts) कहा जाता है । डिमोक के अनुसार इनकी संख्या लगभग 1,20 000 है । प्रत्येक विभागीय संगठन में 100 से लेकर 500 तक मतदाता होते हैं । स्थानीय समितियों का नेतृत्व किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है । इसे विभागीय संगठन का कप्तान (Precinct Captain) कहा जाता है । वह समाजसेवी व्यक्ति होता है और वह उच्च समितियों एवं पदों के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देता है । इन स्थानीय विभागीय समितियों के अंतर्गत वाड समितियाँ तथा ग्राम समितियाँ (Ward & Village Committees) होती हैं । ये विभागीय संगठनों के कार्यों का समन्वय करती हैं । नगरों में नगर समितियाँ (City Committees) होती हैं ।

(ब) काउण्टी संगठन (County Organization)—नगर तथा ग्रामीण संगठनों को निर्देश प्रसारित करने के लिए काउण्टी समितियाँ होती हैं जिनकी संख्या लगभग 3 050 है । काउण्टी समिति स्तर पर नेतृत्व में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है ।

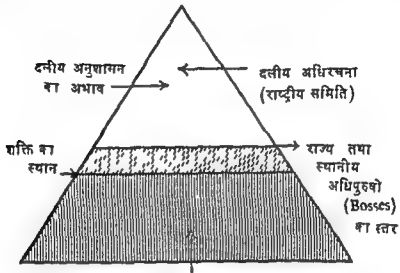
मतदाता काउण्टी के कार्यों में कम रुचि रखते हैं। वे केन्द्र तथा राजकीय समितियों से सम्बन्ध स्थापित करती हैं।

(स) राज्य संगठन (State Organization)—राष्ट्र स्तर का प्रत्येक राजनैतिक दल सघ के राज्यों में अपने संगठन रखता है। दलीय संगठन में राज्य संगठन शीपस्थ नहीं होते हुए भी पर्याप्त रूप से प्रभावशाली रहते हैं। काउण्टी, वार्ड तथा विभागीय संगठनों के प्रभावशाली नेता इनके सदस्य होते हैं, कम से कम राज्य स्तर की इन समितियों में 12 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन समिति का तो सदस्य होता ही है, परंतु इसके अतिरिक्त भी वह अति शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है।

(ख) राष्ट्रीय संगठन (National Organization)—दलीय संगठन के शीप पर राष्ट्रीय समिति का स्थान है। प्रत्येक राज्य इसमें दो सदस्य भेजता है—एक पुरुष और एक स्त्री सदस्य। राष्ट्रीय समिति में कोलम्बिया जिले तथा अन्य क्षेत्रों के भी सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय समिति में लगभग 100 सदस्य होते हैं। राज्यों में वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय समिति के लिए प्रतिनिधियों की छोट करते हैं। निर्वाचन के वर्ष में राष्ट्रीय समिति अपने अधिकांश अधिकार राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को प्रदान कर देती है। राष्ट्रीय समिति की एक कार्यकारिणी भी होती है जो निर्वाचनों में स्वयं भाग लेती है। राष्ट्रीय समिति की दो उपसमितियों (Congressional & Senatorial Committees) भी होती हैं। दलीय संगठन को फरगुसन तथा मैकहैनरी की पुस्तक से उद्धृत निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति	
राष्ट्रीय समिति	
कांग्रेस निर्वाचन अभियान समिति	सीनेटोरियल निर्वाचन अभियान समिति
51 राजकीय केन्द्रीय समितियाँ	
3050 काउण्टी केन्द्रीय समितियाँ	
नगर समितियाँ वाड समितियाँ	
1,20 000 विभागीय (प्रारम्भिक) समितियाँ।	

माशेल डिमोक (Dimock) ने अपनी पुस्तक *American Government in Action* में पृष्ठ 261 पर निम्नाविध रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। उससे माध्यम से अमेरिकी दलीय व्यवस्था में सत्ता एवं अनुशासन के विभिन्न स्तरों को समझने में सहायता मिल सकती है—



इस स्तर पर दलीय अनुशासन कठोर रहता है

अमेरिकी दल पद्धति की प्रमुख विशेषताएं तथा ब्रिटिश दल प्रणाली से तुलना

(Unique Features of American Party System & Comparison with English Party System)

(1) द्विदलीय पद्धति (Biparty System)—इंग्लैंड के अलावा ही अमेरिका में भी द्विदलीय पद्धति विद्यमान है। गिरफिपड के मतानुसार द्विदलीय पद्धति दार्शनिक देशों के निवासियों के स्वभाव के अनुकूल ही है। अर्नेस्टो ने द्विदलीय पद्धति ही क्यों पनप ली है इसके कारणों के सम्बन्ध में अपने ही एक लेख में लिखा है। पुनश्च अमेरिका में द्विदलीय पद्धति की व्यवस्था के कारण—जोर्जेजान्स, अनुभव-मूलक, आर्थिक तथा राजनैतिक है। यहाँ जटिलता का दबा के अतृप्त कान-पालिका की निर्वाचन प्रणाली ही इसके लिए उत्तरदायी है। सीमांत दल ने भी विकसित होने का प्रयत्न किया है परन्तु उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। दूसरे राजनैतिक दल को घनाभाव तथा मरणांशित करने में ही जनता ने इस स्तर पर स्वीकृति नहीं दी है। मैकग्रा ने यह भी कहा है कि 'गठबन्धन की प्रणाली तीसरे दल का हतोत्थित कर देती है, जिससे जनसंख्या में सुदृढ हो गई है।'

(2) नये-जुने सिद्धांतों का अभाव (Absence of Principles)—का कथन सरय है कि 'अमेरिकी दल अपने-अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं हैं।' फाइनर के अनुसार 'अमेरिकी दल अपने-अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं हैं।'

पद्धति की विशेषता है।" अमेरिकी दलों के कार्यक्रम भाषा में भिन्न हो सकते हैं किंतु विचारधारा में नहीं। दोनों दलों के सिद्धांत ऐसे नहीं हैं जिनके मध्य कोई विभाजन रेखा खींची जा सके। सन् 1940 के निर्वाचनों ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया था। जो बात डेमोक्रेटिक दल ने कही थी वही बात शब्दों के हेर-फेर से रिपब्लिकन दल ने भी कही थी। सन् 1968 में बाहु एच वैदेशिक नीति का जो उल्लेख राष्ट्रपति निक्सन तथा हम्फ्री के चुनाव घोषणा पत्रों में किया गया था उसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। जॉनसन के पश्चात् निक्सन तक ने भी परम्परागत वैदेशिक नीति का ही अनुसरण किया है।

(3) शिपिल संगठन (Loose Organization)—अमेरिका में दलीय संगठन इंग्लैण्ड तथा भारत के राजनैतिक दलों के सदृश कठोर नहीं है। वहाँ कोई भी दल सदस्यों की भर्ती नियमित रूप से नहीं करता। दल के सदस्यों के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वे किसी सामान्य सिद्धांत में ही विश्वास करते हों। सचमुच अमेरिका के दल ढीले ढाले विचारयुक्त व्यक्तियों के शिपिल समूह हैं। लास्की का यह कहना सही है कि "वे केवल निर्वाचन के समय ही राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय समस्याएँ ही हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि कांग्रेस के सदस्य दलीय नीति का समर्थन करें। यहाँ पर इंग्लैण्ड के सदृश दलीय सचेतक अथवा नेता का नियंत्रण सदस्यों के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं होता। अतः अमेरिका के राजनैतिक दलों में निःसंदेह दलगत अनुशासन एवं संगठनबद्धता का अभाव है।

(4) क्षेत्रवाद एवं वगवाद की अधिकता (Regionalism & Sectionalism)—अमेरिका के राजनैतिक दल विचारों के ओर पास नहीं अपितु व्यक्तियों के इद्द गिद घूमते हैं। फाइनर ने अमेरिकी दलों को क्षेत्रवाद तथा वगवाद से युक्त पाया है। उनमें स्थानीयता के साथ साथ ही स्वामित्व का भाव भी पाया जाता है। ब्रोगन ने ठीक ही कहा है कि "अमेरिकी दल समाज के विविध वर्गों के मध्य समझौते मात्र ही हैं। बस्तुतः उनकी स्थिति एक छोलदारी के सदृश है, जिसके नीचे सबके लिए स्थान है। रिपब्लिकन दल के उप्रवादी अथवा अनुदारवादी भी डेमोक्रेटिक दल के समान ही उप्रवादी तथा अनुदारवादी हैं।" ब्रोगन के ही शब्दों में "अमेरिकी राजनैतिक दलों के नाम ही इस प्रकार हैं कि जिनकी पृष्ठभूमि में सब प्रकार का प्रभावशाली लोकमत विद्यमान है। यदि एक दल क्षुप्त भी हो जाय तो उसकी कोई विचारधारा ऐसी नहीं है जो दूसरे दल में उपलब्ध नहीं हो सके।" व्यापक राष्ट्रीय प्रश्नों पर दोनों दलों के दृष्टिकोणों में समानता ही है। इन दोनों दलों को रिपब्लिकन कम डेमोक्रेटिक दल कहना ही अधिक सत्य होगा। ये राष्ट्रीय हित की अपेक्षा वग हित पर ही अधिक ध्यान देते हैं। इनमें केन्द्रीकरण का अभाव है।

(5) दल के प्रशासन का प्रभाव (Influence on Administration)—इंग्लैण्ड में प्रशासकीय कमचारियों को दलीय सदस्यता एवं हस्तक्षेप से पृथक् रखा गया है परन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्य न्यायापालिका अर्थात् राष्ट्रपति के पथक होते ही लगभग 3000 कमचारी त्यागपत्र देकर चल देते हैं। यह सच्चा तो 1883 के बाद की है। उससे पूर्व तो यह सच्चा बहुत ही अधिक थी। इसमें लोक सेवा आयोग तथा असनिश सेवा नियमों के निर्माण में भी कुछ अंतर पड़ा है।

अमेरिका में लूट ससोट प्रणाली ही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। वीयड के अनुसार "राष्ट्रपति द्वारा राजनैतिक आधार पर होने वाली नियुक्तियों का मूल्य कई करोड़ डॉलर अधिक है।" अमेरिकी राजनैतिक दलों में बहुत से लोगों का यह व्यवसाय ही है कि नये राष्ट्रपति के आते ही वे अपने सहयोगियों एवं पिछुआ के लिए पद उपाजित करने के लिए प्रतिद्वन्द्वतात्मक रूप से प्रयत्नशील हो जाते हैं। वहाँ प्रशासन पूर्ण रूप से दसबंदी के चंगुल में ग्रस्त है। दल के नेता भी दल के कार्यकर्ताओं से सामूहिक रूप में प्रत्येक वर्ष से सोदेबाजी करते हैं। इस प्रणाली को भ्रष्टाचार (Spoil System) प्रणाली कहा जाता है। राजनैतिक आधार पर जो कमचारी नियुक्त होते हैं उनसे निष्पक्षता एवं कार्यकुशलता की आशा करना ही भ्रष्टापूर्ण है। अवसरवादिता, भ्रष्टाचार तथा सोदेबाजी ने वहाँ का राजनैतिक जीवन को अर्सेनिक एवं अशुद्ध बना दिया है। भौतिक स्वार्थों के लिए आदर्शहीन सधपों को प्रोत्साहन मिला है। सी राइट मिस्स का कथन है कि "संयुक्त राज्य की अस्तित्व सरकार में वास्तविक नोकरशाही न तो कभी स्थापित हो चुकी है और न आज हो पाई जाती है।" राइट (Wright) के ही शब्दों में "अर्सेनिक सेवा का परिभाषा बदलते हुए राजनैतिक प्रशासन के साथ ही बदल सकता है। प्रतियोगिता पर आधारित नियुक्तियों के नियमों का उल्लंघन पूर्णतः नई समस्याओं की स्थापना के साथ ही किया जा सकता है।"

(6) दल के नेता का महत्व (Importance of Party Leader)—ब्रिटेन में दल के नेता की स्थिति पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है। वह दल का प्रमुख अधिकारता, निर्माता, वाक्ता तथा कणधार होता है और उसका विरोध किसी भी सदस्य के लिए हानिकारक हो सकता है यही तब कि राजनैतिक दृष्टि से उसकी राजनैतिक मृत्यु तक हो सकती है, परन्तु अमेरिका में यह सम्भव नहीं है। रोसो तथा स्टैकमैन का यह कथन सही है कि "राष्ट्रपति निर्वाचनों के मध्य राष्ट्रीय दल की एकता की एकमात्र बड़ी का काम करता है।" अमेरिका में एक नेता नहीं होता जिसके नेतृत्व में दल के अन्य सदस्य कार्य करते हों, इंग्लैण्ड में सार्वजनिक निर्वाचन में प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है किन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है।

अतः हम यही कहेंगे कि संविधान निर्माताओं ने जिस परंपरा की उपेक्षा की थी वही परंपरा अब आधार मिला बन गया है।¹ अमेरिकी राजनैतिक दलों में अनुशासन एवं संगठन सम्बन्धी कितने ही दोष क्यों न हों किन्तु लोकतन्त्र के सफल संचालन में उनसे महत्व को कम नहीं किया जा सकता। अमेरिका में लोकतन्त्र का गतिशीलता एवं सजीवता प्रदान की है। यदि सरकार एक बड़ी मशीन है तो राजनैतिक दल उसके एजिन हैं जोकि मशीन को चलाने वाली विद्युत् उत्पन्न करते हैं। दलों में संगठन के स्थान पर एककृपता स्थापित हो गई है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् दूरी से लेकर निश्चय तक आन्तरिक एवं बाह्य नीतियों के क्षेत्र में जिस प्रकार का व्यवहार एवं नीति का अनुसरण हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों

1 The stone which the builders of constitution rejected has become stoe of the Corner

दलो म केवल नाम का ही अंतर है, परन्तु विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि महत्वपूर्ण राजनैतिक नियम राजनैतिक दल ही करते हैं अथवा फौजी जनरल या पूँजीवादी वर्ग। इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि अमेरिका में पूँजीवादी सैनिकता का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि स्वयं लोकतंत्रीय दुर्ग की भित्तियाँ भी हिलने लगी हैं। सन 1964 में रिपब्लिकन दल की ओर से गोल्डवाटर का निर्वाचन अभियान पूँजीवादी सैनिक तंत्र द्वारा ही नियंत्रित था। गोल्डवाटर के पराजित होने पर भी वियतनाम के सम्बंध में अमेरिकी नीति को वही रूप मिला जब गोल्डवाटर के विजयी होने पर मिलता। राष्ट्रपति निक्सन ने अब अमेरिका में फासिस्टवादी सैनिक तंत्र को प्रोत्साहन दिया है। वह कभी भी पनप सकता है। यदि निक्सन पराजित भी हो जाते तो भी भारत के तथा पाकिस्तान के सवर्ष में अमेरिकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

अमेरिका में राष्ट्रीय सम्मेलनों का वातावरण सकस के समान रहता है। वक्ता का अभिभाषण वक्ता के अतिरिक्त अब कोई व्यक्ति नहीं सुनता। स्त्री तथा पुष्प दोनों ही कृत्ते बिस्त्रियों की आवाजें निकालते हैं और बिजली गायब हो जाने पर जो हालत सिनेमा में होती है, ठीक वैसी ही राष्ट्रीय सम्मेलन (National Convention) में देखने को मिलती है। उम्मीदवारों के समयक पूर्व निश्चित आधार पर मतदान करते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि अपने प्रिय क्षेत्रीय नेताओं को इस कारण से निर्वाचन में खड़ा कर देते हैं कि द्वितीय निर्वाचन (Second Ballot) होने पर उन्हें लोकप्रिय उम्मीदवारों से सीदेबाजी करने को मिल जाय। इस सीदेबाजी में कभी कभी ऐसे व्यक्ति को दल का उम्मीदवार निर्वाचित किया जाता है जिसकी कोई आशाही नहीं होती, यहाँ तक कि उसका सट्टा भी नहीं लगाया जाता है। घुड़दौड़ की शब्दावली में ऐसे प्रतिनिधियों को काले घोड़े (Dark Horses) कहा जाता है। कभी कभी घुड़दौड़ में ऐसे घोड़े भी विजयी हो जाते हैं जिनकी कोई आशा भी नहीं करता।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो सैनिक समझौते हुए हैं और शस्त्रीय एवं आर्थिक सहायता के रूप में शीतयुद्ध का दौर चला है उसके फलस्वरूप राजनैतिक दलों पर सेना के प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। फ्रैंडो जे० कुक का यह कथन सही है कि 'सेना ही अर्सेनिक प्रशासन रूपी घोड़े पर सवार होकर उसे बूट की ठोकर मारकर दौड़ा रही थी।' वाल्टर मिल्स (Walter Mills) के शब्दों में "जनता की दृष्टि में राज्य महत्वहीन हो गया था और ऐसे राष्ट्र में जहाँ असैनिक सत्ता की उन्मत्तता का सिद्धांत मात्र समझा जाता है, जनता तथा कांग्रेस राजनैतिक तथा असैनिक प्रशासकों की तुलना में सैनिक अधिकारियों के नियम तथा परामर्श को प्राथमिकता दे रही थी।" दोनों राजनैतिक दल एक मत होकर शस्त्राशस्त्रों के उत्पादन तथा सैनिक संगठन की स्थापना के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगे हैं। अमेरिकी समुक्त पूँजी से इन सेनाध्यक्षों का गठबन्धन है। लोकमत, दलीय संगठन कांग्रेस की समितियों, आयोगों तथा अन्य प्रशासकीय विभागों पर सैन्यीकरण का विशेष प्रभाव युद्धोत्तर काल की अमेरिकी राजनैतिक व्यवस्था की अद्भुत कड़ी है। अमेरिकी शासक वर्ग के ये तीन आधार स्वम्भ कह जा सकते हैं (1) उच्च सैनिक अधिकारी वर्ग (2) समुक्त पूँजी के मालिक (3) उच्चस्तर के राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक। सी० राइट मिल्स के शब्दों में

“न तो शासक वर्ग का सिद्धांत, न केवल प्रशासक राजनीतिज्ञों की निरंकुश शक्ति का उदय और न ही सैनिक गुट की तानाशाही का सिद्धांत ही अमेरिकी शासन प्रणाली की सतोषजनक व्याख्या कर सकता है। वर्तमान सत्ताधारी श्रेणी आर्थिक, सैनिक तथा राजनतिक शक्तियों के आकस्मिक सहयोग पर ही आश्रित है।”

Select References

- H Zink *American Govt & Politics*
 Carr & Berstien *American Democracy in Theory & Practice*
 H Finer *Theory & Practice of Modern Govts*
 Brogan *American Political System*
 Beard *American Govt & Politics*
 Munro *Govt of United States*

पाय सारणी आधुनिक संविधान ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 अमेरिकी तथा ब्रिटिश राजनतिक दलों की तुलना कीजिए ।
 [Compare and contrast the organization of Political parties in England & U S A]
- 2 ‘निर्माताओं ने जिस पत्थर की उपेक्षा की वही पत्थर आधार शिला बन गया है ।’ अमेरिकी राजनैतिक दलों के प्रसंग में इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
 [“The stone which the builders rejected has become the chief stone of the corner”—Discuss with reference to American Political Party System]

राज्य सरकार [State Governments]

“अमेरिका के राजनैतिक इतिहास में राज्यों के शासन विधान सबसे अधिक पुराने हैं।”

—ब्राइस

“राज्य अब भी वे घुरियाँ हैं जिनके चारों ओर अमेरिका का सम्पूर्ण राजनैतिक चक्र घूमता है।”

—मुनरो

‘In U S A State Governments are restricted only in the foreign affairs. Otherwise, they have a wide range of powers to exercise independently of federal Government’

—Laski

यह तो बहुत कुछ सीमा तक सही है कि संघीय सरकार के अधिकारों की अभिवृद्धि के साथ साथ ही राजकीय सरकारों के स्वत्वों में भी कमी आ गई है, परन्तु फिर भी उनका महत्व है और वे आज भी प्रशासकीय व्यवस्था की धुरी हैं। राष्ट्रपति तथा कांग्रेस दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए राज्यों की सरकारों पर ही अवलम्बित हैं। निर्वाचन की व्यवस्था केन्द्रीय न होकर राजकीय है। राज्यों की अनुमति के बिना संविधान में भी संशोधन नहीं हो सकता। प्रारम्भ में अमेरिका में 13 राज्य थे परन्तु आज उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। राज्यों के अपने अपने संविधान हैं। केवल प्रतिबन्ध यह है कि वे अपने संविधानों में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जोकि संघीय संविधान एक बानून का उल्लंघन करता हो। संघीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(i) राज्यों में परस्पर नैगोतिक असमानताएँ हैं, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी पर्याप्त अंतर है।

(ii) राज्यों के संविधान संघीय संविधान से भिन्न हैं। भारत में ऐसा नहीं है।

(iii) राज्यों के संविधान लिखित संविधान हैं।

(iv) संविधानों में अधिकारों के घोषणा-पत्र भी सम्मिलित हैं।

(v) प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका की द्विमंडलात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

(vi) राजकीय संविधान के निर्माण में जनता का प्रमुख हाथ है।

(vii) शक्ति विभाजन के सिद्धांत को सभी संविधानों में स्थान दिया गया है।

(viii) राज्यों में कार्यपालिका पर लोकप्रिय नियन्त्रण रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल (Governor) के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है।

(ix) राज्यों की शक्तियों को मौलिक कहा गया है और केन्द्र शासन की शक्तियों को प्रदत्त।

(x) राज्यों में प्रत्यक्ष जनतंत्र की व्यवस्था की गई है—जनमत संग्रह, आरम्भक, तथा प्रत्याह्वान।

(xi) प्रत्येक राज्य के सविधान में अध्यक्षतात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

(xii) सार्वजनिक मताधिकार को मायता प्रदान की गई है।

(xiii) सभी सविधानों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है।

(xiv) प्रत्येक राज्य में समान उद्देश्य वाले राजनैतिक दल पाये जाते हैं।

राज्य का प्रशासकीय संगठन

(Administrative Set up of State Government)

(1) राज्यपाल (Governor)

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित है, उसका राजकीय व्यवस्था में वही स्थान है जो कि केन्द्र में राष्ट्रपति का है। राज्यपाल का पद बड़े महत्व का होता है। प्रत्याशी भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के स्वप्न भी देख सकता है। राज्यपाल का पद बड़ी व्यस्तता का पद होता है। जनता से उसे पूर्णरूप से सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता होती है। राज्यपाल को डाक एवं पत्र व्यवहार का एक बड़ा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। राज्य स्तर के समारोहों पर राज्यपाल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। राज्यपाल को बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना पड़ता है।

योग्यताएँ (Qualifications)—(1) प्रत्याशी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए

(ii) सम्बन्धित राज्य में उसका निवास कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए,

(iii) वह समुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता चाहिए।

निर्वाचन (Election)—अमेरिका में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, जैसा कि भारतवर्ष में होता है। वहाँ राज्यपाल का निर्वाचन होता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन स्पष्ट बहुमत के आधार पर ही किया जाता है। एक ही व्यक्ति उसी पद के लिए दोबारा भी निर्वाचन में खड़ा हो सकता है।

पदावधि (Tenure)—सन् 1920 से पूर्व राज्यपाल की पदावधि 1 वर्ष हुआ करती थी किन्तु अब अमेरिकी संघ के लगभग 29 राज्यों में उसका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है। लगभग 21 राज्यों में उसकी पदावधि केवल 2 वर्ष है। कुछ राज्यों में राज्यपाल को पुनः निर्वाचन में खड़ा होने की अनुमति नहीं है।

राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से पृथक् कर सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जटिल होने के कारण उसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। सन् 1920 में माइताहामा राज्य में वाल्टन तथा जॉनसन दो राज्यपालों की महाभियोग की पद्धति द्वारा निष्कापित किया गया था। कुछ राज्यों में राज्यपाल को पद से पृथक् करने के लिए प्रत्याह्वान प्रणाली का भी

प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल उसका पद ग्रहण करता है और जहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है वहाँ पर यह पद राज्य सचिव के द्वारा ग्रहण किया जाता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ (Powers of the Governor)

(1) कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers)

(i) मुख्य प्रशासक के रूप में विधि निष्पादन एवं प्रशासकीय तंत्र के कार्य का निरीक्षण करना राज्यपाल का कर्तव्य है। वह प्रशासन का प्रमुख निर्देशक भी है।

(ii) राज्यपाल को उन पदों के लिए कमचारियों की नियुक्तियाँ करने का भी अधिकार है, जिनका वर्णन इस उद्देश्य से संविधान में किया गया है। कुछ पदों पर नियुक्ति का अधिकार उसे व्यवस्थापिका द्वारा भी मिला हुआ है, किंतु उसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी हैं। राज्यपाल विभागीय अध्यक्षों को नियुक्त नहीं कर सकता क्योंकि वे भी राज्यपाल के समान ही निर्वाचित होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को राजकीय सीनेट से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। उच्च पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, अतएव वह उन्हें कठोरता के साथ निर्देश भी नहीं दे सकता।

(ii) विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

(i) वह विधान मण्डल के लिए विशेष निर्वाचनों की व्यवस्था करता है।

(ii) राज्यपाल को विधान मण्डल के पास सन्देश भेजने का अधिकार है।

(iii) वह विधानमण्डल को आवश्यक विधियाँ स्वीकार करने की सिफारिश कर सकता है।

(iv) वह विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत विधियों के सम्बन्ध में नियमों एवं उपनियमों की रचना कर सकता है।

(v) वह व्यवस्थापिका का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है।

(vi) वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए व्यवस्थापिका के पास पुनः भेज सकता है।

(vii) राज्यपाल व्यवस्थापिका में अभिभाषण कर सकता है। वह जनता के पास तक अपना सदेश पहुँचा सकता है।

वित्तीय अधिकार (Financial Powers)

गत 30 वर्षों में राज्यपाल के वित्तीय अधिकारों में पर्याप्त विकास हुआ है। राज्यपाल के वित्तीय अधिकार निम्नलिखित हैं—

(i) राज्यपाल को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है।

(ii) उसे आय तथा व्यय के निरीक्षण करने का भी अधिकार है।

राज्यपाल राज्य की वित्तीय स्थिति में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रो० विलबट का भी यही विचार है कि "लगभग 2/3 राज्यों में राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ पर्याप्त व्यापक हैं।

न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

इस क्षेत्र में राज्यपाल को समाधान करने का अधिकार है जिसके अन्तर्गत वह नायिक नुटियों से जनता की रक्षा कर सके।

राज्य की व्यवस्थापिका (Legislature of a State)

अधिकांश राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन हैं। उच्च सदन को सवत्र सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन के नाम भिन्न-भिन्न हैं, कहीं पर निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन, वही पर सभा (Assembly) एवं वही पर प्रतिनिधि सभा (House of Delegates) कहा जाता है। सीनेट में राज्य की प्रत्येक काउण्टी से समान संख्या में सदस्य भेजे जाते हैं। निम्न सदन के सगठन का आधार राज्य की जनसंख्या होती है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है और निम्न सदन का केवल दो वर्ष। सीनेट का अध्यक्ष उपराज्यपाल होता है।

व्यवस्थापिका के अधिकार (Powers of the Legislature)

जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन बेतुल शासन को नहीं किया गया है वे समस्त अधिकार राजकीय व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ—

(i) राजकीय अनुसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है।

(ii) कर लगाने तथा कर समाप्त करने का अधिकार है।

(iii) सीनेट के विधेयकों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

(iv) घन विधेयक केवल निम्न सदन में ही प्रस्तावित हो सकता है।

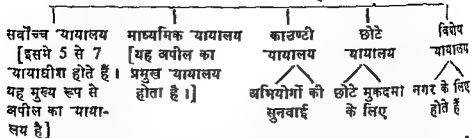
(v) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किए जाते हैं। वह उन्हें स्वीकार भी कर सकता है तथा पुन विचार के लिए वापिस भी कर सकता है। यदि विधेयक पुन सदन में 2/3 बहुमत द्वारा सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यपाल की अस्वीकृति अप्रभावी हो जाती है। यदि दोनों सदनों में विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद हो जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है।

(vi) व्यवस्थापिका को राज्यपाल तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के सम्बन्ध में महाभियोग की प्रक्रिया के प्रयोग करने का अधिकार है। व्यवस्थापिकाओं में समितियों का बहुत महत्व है। उनका अधिकांश कार्य उन्हीं के द्वारा सम्पन्न होता है।

राज्य की न्यायपालिका (Judiciary of a State)

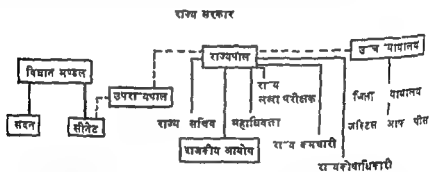
अमेरिका में दो प्रकार के न्यायालय हैं—संघीय तथा राजकीय। राजकीय संघीय न्यायालयों में दो बातों में भिन्नता है—(1) राजकीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल अमेरिकी संघ के 10 राज्यों के अतिरिक्त जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इन 10 राज्यों में उनकी नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा होती है। (2) प्रत्येक राज्य में न्याय पद्धति एक समान नहीं है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ राज्यों में व्यवस्थापिका की प्रार्थना पर ही राज्यपाल द्वारा न्यायाधीश पद से हटाने के लिए प्रत्याह्वान (Recall) की प्रणाली का प्रयोग होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। राज्य में काउण्टी तथा म्युनिसिपल न्यायालयों की भी स्थापना की गई है।

अमेरिकी राज्य में न्याय व्यवस्था इस प्रकार है :—



इस प्रकार सब सरकार के आदेश पर ही राजकीय सरकारों की रचना की गई है। इसमें ये भिन्नताएँ भी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सम्पूर्ण देश के लिये एक ही संविधान नहीं है। परन्तु केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, विश्ववाद तथा वैज्ञानिक आवेष्टनों के कारण उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है और उसी अनुपात में राज्यों की शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं।

अमेरिकी राज्यों के संगठन के निम्नांकित चित्र की सहायता से सरलतापूर्वक से समझा जा सकता है—



Select References

Munro *Govt of U S A*
 Finer *Theory & Practice of Modern Govt*
 Ogg & Roy *Modern Foreign Govts*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
 [Describe the system of Government in the States of U S A]

तृतीय खण्ड सोवियत रूस का संविधान

- इसी संविधान का सामान्य परिचय तथा उसकी प्रमुख विशेषताएँ
- सोवियत संघात्मक व्यवस्था
- संघीय सरकार (सर्वोच्च प्रेसोवियम मन्त्रिपरिषद तथा न्याय व्यवस्था)
- साम्यवादी बल तथा सोवियत रूस में लोकतन्त्र
- लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा संघीय इकाइयों का शासन ।

रूसी संविधान का सामान्य परिचय तथा उसकी प्रमुख विशेषताएँ

[General Introduction & the Characteristic Features
of the Constitution of U S S R]

"A perfect democracy is the most shameless thing
on the earth "

—Burke

"The main foundations of the Constitution of
U S S R are principles of Socialism It reflects them
It embodies them into law "

—J Stalin

परिचयात्मक

आकार का दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह भारत से 7 गुना बड़ा है, जापान से 100 गुना तथा अमेरिका से भी कई गुना बड़ा है। क्षेत्रफल 2,24,00,000 वर्ग किलोमीटर है। सन 1964 में इसकी जनसंख्या 234,000,000 थी। जनसंख्या की दृष्टि से चीन तथा भारत के पश्चात् इसका तीसरा स्थान है। इसकी भौतिक स्थिति की एक विचित्रता यह है कि इसकी गणना योरोप और एशिया दोनों ही में होती है। रूस में विविध राष्ट्रीय जातियों के लोग निवास करते हैं। रूस में लोहा, मिट्टी का तेल, ताँबा, सिंका ज़िंक, मैंगनेशियम आदि पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। रूस का 16 प्रतिशत भाग बर्फ से आच्छादित रहता है। 4% भाग उष्ण जलवायु वाला है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ एवं वेश धूपाएँ पाई जाती हैं।

चीन के उत्तर से पूर्व साम्यवादी देशों का नेतृत्व एकमात्र रूस के पास ही था और आज भी अधिकांश साम्यवादी राष्ट्र उसी के नेतृत्व की ओर देखते हैं। आज सोवियत रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है जिसके कारण उसने दृष्टिकोण के अनुसार विश्व राजनीति का नक्शा ही परिवर्तित हो सकता है। सोवियत संविधान में सचवाद, ससदात्मक व्यवस्था, सामूहिक राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा लोकतन्त्र सभी हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में उसके अर्थ दूसरे लगाने जाते हैं।

सोवियत रूस का संविधान भी अपने ढंग का एक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिणाम है। यह मानव के सिद्धांतों को लेनिनवादी दृष्टिकोण से क्रियावित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। समाजवाद की मौलिक मान्यताओं पर रूसी समाज को संगठित किया गया है। इसने द्वारा मानव इतिहास को एक नवीन परिवर्तन

नवीन दिशा उपलब्ध हुई। व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र की प्रतिक्रिया सोवियत आर्थिक व्यवस्था है। सोवियत रूस की शासन व्यवस्था अति जटिल है, वहाँ पर ऐच्छिक समुदायो का ज्ञान सा बिछा हुआ है। रूस एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। सोवियत जीवन व्यापक रूप में राज्य नियंत्रित है। इसीलिए रूसी समाज अति समन्वित समाज बन गया है। रूस आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक मूल्यों एवं विकास को महत्वपूर्ण मानता है। यह विश्व की परम्परागत सर्वैधानिक मान्यताओं के लिए एक चुनौती है। इस नूतन सर्वैधानिक परीक्षण को विश्व बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहा है।

साम्यवादी क्रांति से पूर्व रूस में जार (Czar) वंश के शासकों का राज्य था। उनके प्रयत्नों से ही रूस के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उनकी नीतियाँ साम्राज्यवादी थी। उन्होंने अपना प्रसार एशिया की ओर ही किया। जार वंश के शासक पीटर महान (1689-1725) ने रूस को योरोपियन सभ्यता के ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया। जारवंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय हुआ, उसने विविध प्रकार के सुधार करने का प्रयत्न किया। सन् 1865 के पश्चात् जार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और वह भी स्वभाव एवं नीति से प्रतिक्रियावादी बन गया। क्रांतिकारियों का उसने मृत्यु दण्ड दिया। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने प्रतिशोध की भावना का प्रदर्शन किया तथा अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। सन् 1890 में सैनिकों द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना हुई। सन् 1894 में निकोलस द्वितीय रूस का शासक बना और उसने सन् 1917 तक वहाँ का शासन किया। सन् 1905 में रूस जापान से संधि में परास्त हुआ जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। निकोलस के विरुद्ध कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए तथा सशस्त्र असंतोष भी हुआ क्योंकि इस हार के लिए निकोलस को ही दोषी ठहराया गया। इन विद्रोहों को तो दबा दिया गया किंतु उसे विवश होकर सन् 1906 में ड्यूमा (हसी सदन) को आमंत्रित करना पड़ा ड्यूमा में निर्वाचन की पद्धति ही इस प्रकार की रखी गई थी कि जिससे जमींदार वर्ग को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। जार इस सदन को शक्तिशाली नहीं रखना चाहता था, अतएव उस शीघ्र ही भंग कर दिया गया। परन्तु परिस्थितियों से विवश होकर द्वितीय बार भी ड्यूमा को पुनः आमंत्रित करना पड़ा, इसमें श्रमिकों एवं प्रगतिशील तत्वों का बहुमत हो गया जो कि जार तथा उसके जमींदार वर्ग के अनुयायियों पर सदन नहीं था। अतएव इसे पुनः भंग कर दिया गया। निर्वाचन पद्धति में संशोधन किया गया कि जिससे जमींदार वर्ग बहुमत न कर सके। सन् 1912 तक काम किया, जार ड्यूमा के लिए निर्वाचन हुए आधा सदन ने सन् 1912 तक काम किया, जार ड्यूमा के भी निर्वाचन की आलोचना की किंतु वे भंग करना पड़ा जिसने सन् 1917 तक काम किया।

जार्ज लॉस पर
उसे गुमरा
कारण से

ठहराया गया। सैनिकों के पास युद्ध का पूरा सामान नहीं था। विद्रोह को दबाने के लिए सेना का प्रयोग किया गया। पेट्रोग्रेड तथा अन्य स्थानों पर भयंकर प्रदर्शन किये गये। परंतु बाद में सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इकार कर दिया। 11 मार्च 1917 तक जनता के इस प्रदर्शन ने भीषण रूप धारण कर लिया। प्रिंस स्क्वोव की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी सरकार ने निकोलस से पदत्याग करने को कहा। निकोलस ने अपने भाई के पक्ष में पद त्याग दिया, किंतु उसने पद ग्रहण करने से इकार कर दिया। रूसी राज्य क्रांति सफल हुई तथा निकोलस तथा उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।

किंतु अस्थायी सरकार भी स्थायी शासन एवं शांति स्थापित करने में असफल रही। पुराने रूसी कलेंडर के अनुसार अक्टूबर तथा नये कलेंडर के अनुसार नवम्बर में लेनिन ट्राट्स्की के नेतृत्व में बोलशेविक अथवा साम्यवादी क्रांति हुई। लेनिन (V I Lenin) तथा उसके साथियों ने जमींदारों तथा पूँजीपतियों को समाप्त करने तथा उनकी सम्पत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने आदि का कार्यक्रम बनाया। संवैधानिक तरीकों को वे पहले ही ठुकरा चुके थे। मजदूरों ने अपनी संस्थाएँ स्थापित कर ली थीं जोकि सोवियत कहलाती थीं। 6 नवम्बर अथवा पुराने कलेंडर के अनुसार 24 अक्टूबर 1917 की रात्रि को लेनिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। अस्थायी सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली। 7 नवम्बर को साम्यवादियों ने अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अस्थायी सरकार में घनिष्ठ तथा पूँजीपति वर्ग के लोग थे। क्रांतिकारियों में मजदूरों के सर्वहारा वर्ग की विजय हुई। निकोलस के समस्त परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। सैनिक भी विश्व युद्ध से तंग आ चुके थे वे भी साम्यवादियों के साथ मिल गये। लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग ने सरकार की स्थापना की और इस प्रकार रूस की राज्य क्रांति सफल हुई।

सन् 1918 का संविधान (Constitution of 1918)

यह संविधान केवल संयुक्त सोवियत गणराज्य तक ही सीमित रहा। प्राकृतिक स्रोतों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा समाजवादी आदर्शों पर एक सरकार स्थापित की गई। इस संविधान में सोवियतों की एक कार्यस तथा एक केन्द्रीय कार्यपालिका समिति की स्थापना की गई थी। इसी समिति के आधीन एक लोक प्रत्यक्ष समिति (Council of Peoples Commissars) स्थापित की गई। संघीय सर्वोच्च न्यायालय (Union Supreme Court) की स्थापना की गई। पादरियों को मताधिकार से वंचित किया गया। चर्च को भंग कर दिया गया एवं पूँजीवादी तथा जमींदारी वर्ग को भी समाप्त किया गया।

सन् 1924 का संविधान (Constitution of 1924)

जैसा कि स्वाभाविक ही था रूस में राज्य क्रांति एवं सर्वहारा वर्ग की स्थापना आदि के पश्चात् ग्रहण्युद्ध प्रारम्भ हो गया विदेशी मेनाएँ विद्रोहियों को परास्त करने के लिए भेजी गई। लेनिन ने लाल सेना (Red Army) का संगठन किया और विदेशी सेनाओं को परास्त करके भगा दिया गया। बलोरोशिया तथा यूक्राइन

पर लाल सेनाओं ने अधिकार कर लिया था, लाल सेनाओं ने अजरबैजान, जार्जिया, बुखारा, तुर्किस्तान आदि प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया जोकि किसी समय निकोलस द्वितीय के अधिकार में थे। इस समय नवीन संविधान की आवश्यकता अनुभव होने लगी। सन् 1923 तक रूस का नवीन संविधान तैयार हो गया जिसे जनवरी 1924 में लागू किया गया। जिन प्रदेशों पर लाल सेनाओं द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई थी, उन्हें मिलाकर सोवियत समाजवादी गणराज्य (U.S.S.R.) की स्थापना हुई। विधायी शक्ति ऑल युनियन कांग्रेस ऑफ सोवियत (All Union Congress of Soviets) में निहित कर दी गई। इसके दो सदन रखे गये—सोवियत ऑफ दी यूनियन (Soviet of the Union) तथा सोवियत ऑफ नेशनलटीज (Soviet of Nationalities) इसके अतिरिक्त 27 सदस्यों की एक प्रेसीडियम (Presidium) की भी व्यवस्था की गई, जोकि संसद के अधिवेशनों की अनुपस्थिति में विधायी कार्यों का सम्पादन करती थी। संघ की कार्यकारिणी शक्ति का निवास प्यूपल्स कमिश्नर (Peoples Commissars) में रखा गया। उच्चतम न्यायालय तथा प्रोक््युरेटर की संस्थाएँ स्थापित की गईं। सन् 1924 में लेनिन एक महिला की गोली का शिकार हो गया। लेनिन के स्थान पर जोसफ स्टालिन बड़ा की साम्यवादी पार्टी का महा सचिव नियुक्त हुआ।

सन् 1936 का संविधान (Constitution of 1936)

माशाल स्टालिन ने कई पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन भी तीव्र गति से हुए। सोवियत अर्थव्यवस्था का समाजीकरण किया गया। 'बुर्जुआ वर्ग' का दमन किया गया। क्रांति का विरोध करने वाले तत्वों को निकाल बाहर किया गया। इन परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः एक नवीन संविधान की आवश्यकता अनुभव होने लगी। विधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष स्वयं स्टालिन नियुक्त हुए। उन्होंने नवीन संविधान का निर्माण किया यह नया संविधान स्टालिन संविधान के नाम से ही लोकप्रिय है। संविधान के मसविदे को प्रेसीडियम द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त उस पर 527 000 सावजनिक सभाओं में बहस की गई। जिसमें 154 000 सलाहें प्रस्तावित किये गये। इनमें से केवल 43 को ही स्वीकार किया गया। सन् 1947 के पश्चात् इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। सोवियत संघ के सवधानिक इतिहास में 1936 के संविधान का अपना बड़ा महत्त्व है। रूस की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए। जनवरी 1937 में इस संविधान को लागू कर दिया गया।

सोवियत संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(Characteristic Features of the Soviet Constitution)

(1) लिखित संविधान (Written Constitution)—हापर के अनुसार सोवियत संविधान क्रांति की उपज न होकर स्वयं एक निरंतर क्रांति है। संविधान उसी प्रकार से लिखित है जिस प्रकार से कि अमेरिका का संविधान। संविधान में 13 अध्याय तथा 146 धाराएँ हैं। भारत की अपेक्षा सोवियत संविधान बहुत छोटा है। वैसे विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्णरूप से लिखित है और न ही पूर्ण रूप से अलिखित। सोवियत संविधान में भी परम्पराओं के रूप संविधान के अलिखित भाग

हैं। संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है। ब्रिटिश संविधान के सदृश यह एक विकास का परिणाम नहीं है। रूसी संविधान एक सतत सघर्ष की सघर्षपूर्ण कहानी ही है।

(2) अनम्य संविधान (Rigid Constitution)—रूस के संविधान को नम्य कहा जाय अथवा अनम्य यह विवादास्पद ही है। सोवियत संविधान इंग्लैंड तथा यूजीतैण्ड के समान नम्य नहीं है क्योंकि संविधान की धारा 146 के अनुसार संविधान में संशोधन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। सघर्ष की इकाइयों से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सोवियत संविधान को अनम्य ही कहा जायगा। किंतु वह अमेरिका तथा भारत के सदृश अनम्य भी नहीं है। अधिक से अधिक हम यही कहेंगे कि सोवियत संविधान अनम्य होते हुए भी उसकी प्रवृत्ति पूर्णरूप से परिवर्तनशील है। सोवियत संविधान में इस परिवर्तनशीलता के कई कारण हैं—(1) एक दलीय शासन व्यवस्था। (2) राष्ट्र की सामाजिक प्रगति एवं उसके उद्देश्यों के लिए केवल एक साधन का प्रयोग। रूसवासियों की ऐसी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ ही संविधान को भी परिवर्तित होना चाहिए। (3) सन् 1918 से लेकर 1924 तक रूस में राजनैतिक अस्थायित्व, (4) रूस में मानव के दसनशास्त्र की एक व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। (5) संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव है।

(3) संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)—सिद्धांततः संविधान को राष्ट्रीय शक्ति का सर्वोच्च निकाय कहा गया है। गणराज्यों के संविधानों में परिवर्तन संविधान के अनुकूल होने चाहिए। सरकार के समस्त अंग संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। परंतु इस सिद्धांत का व्यावहारिक पक्ष संदिग्ध है। संविधान को शक्ति की उत्पत्ति कहा गया है और उसे जनता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व से मर्यादित होता है। देश के सर्वहारा अधिनायकत्व की ही टाउस्टर ने संविधान का मूल स्रोत कहा है। सर्वहारा वर्ग के अर्थ हैं साम्यवादी दल। अतएव संविधान का दलीय आवश्यकताओं के अनुकूल चलना आवश्यक है। व्यवहार में साम्यवादी दल की इच्छा ही सर्वोच्च है।

(4) संसदीय लोकतंत्र की स्थापना (Establishment of Parliamentary Democracy)—सर्वोत्तम सोवियत का सघर्ष की सर्वोच्च सत्ता का आगार कहा गया है। सन् 1936 के संविधान के अंतर्गत रूस में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। विशिष्की के शब्दों में 'सोवियत राज्य नये रूप का लोकतन्त्रात्मक राज्य है, इसका लोकतंत्र उच्च कोटि का है।' संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च सोवियत को ही है। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत (संसद) के प्रति उत्तरदायी है। अतः सोवियत संविधान में संसदीय प्रभुता की स्थापित किया गया है, परंतु व्यवहार में इसका चित्र दूसरा ही है। यह कहना संदिग्धपूर्ण है कि क्या वास्तव में कार्यपालिका वहाँ संसद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च सोवियत को साम्यवादी दल तथा कार्यपालिका के आदेशों

का सदैव ही पालन करना पड़ता है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन अल्पकालीन होते हैं तथा उनकी कार्यविधि प्रभावशाली नहीं होती, अतएव वह सदैव ही मन्त्रिपरिषद् तथा प्रेसीडियम के चंगुल में रहती है।

(5) सोवियत प्रणाली (Soviet System)—सोवियत मजदूरों की संस्था है। प्रत्येक गाँव, नगर गणराज्य एवं सेना आदि सभी में 'सोवियतें' हैं। इन्हें लोक तंत्र के लिए आवश्यक समझा गया है। लेनिन ने पूँजीवादी लोकतन्त्र को छोड़ता एवं दिखावा मात्र ही ब्रह्मा है क्योंकि जनता को हर पाँच वर्ष के पश्चात् दिखावा कराया जाता है। वास्तविक शक्ति अल्पसंख्यक पूँजीपतियों के हाथ में ही रहती है। वे सोवियत जनता तथा साम्यवादी दलों के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। प्रत्येक मजदूर राज्य के शासन में भाग लेता है। लेनिन (Lenin) के शब्दों में "सोवियत प्रणाली पूँजीवादी संसदीय प्रणाली से कई गुना अच्छी है क्योंकि इसमें सरकार का कार्य करने के लिए समस्त जनता स्वतन्त्र, व्यापक एवं अधिकतम उत्साह के साथ भाग लेती है।¹ कार्पे स्की ने इसे सर्वगुणकारी संस्था कहा है।

(6) संघात्मक व्यवस्था (Federal System)—संविधान की धारा 13 में रूस को एक संघ कहा गया है। यह गणराज्यों की स्वेच्छा से स्थापित हुआ है। संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य हैं, इन गणराज्यों को अपने अपने संविधान रखने का अधिकार है। रूस में भाषा तथा धर्म आदि की विविधताओं को संघात्मक व्यवस्था के माध्यम से एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया गया है। गणराज्यों के आधीन स्वायत्त गणराज्य हैं और उनके आधीन स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं तथा पुनः उनके आधीन राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। इनके संविधान लिखित तथा कठोर हैं। सोवियत संघ में केवल संघात्मक व्यवस्था का ही एक तत्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याता नहीं कहा गया है। रूस में केन्द्र अत्यधिक शक्तिशाली है।

(7) शक्ति प्रयत्नकरण को कोई स्थान प्राप्त नहीं है (No Place for the Separation of Powers)—साम्यवादी शक्तियों के प्रयत्नकरण के सिद्धांत को एक बुजुर्ग आ (पूँजीवादी) मिथ्यात कहते हैं। बिनिंस्की ने इसे ऐसा साधन कहा है जो कि कार्यपालिका को निरकुश तथा संसदीय सत्ता को कुण्ठित बनाता है। सोवियत संविधान शक्ति प्रयत्नकरण को कोई स्थान प्रदान नहीं करता। साम्यवादी इस सिद्धांत को स्वायत्त कहते हैं। फाइनेर (Finer) ने इसका कारण यह बताया है कि सोवियत नेता एकाधिकार चाहते थे जो इस पद्धति में सम्भव नहीं है। इसीलिए उन्होंने शक्तियों को मर्यादित करने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। जब मन्त्रिपरिषद् के सदस्य सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित होते हैं तो उसे शक्तियों के प्रयत्नकरण पर आधारित कहना उपहासार्थक है।

(8) समाजवाद की स्थापना करता है (It Establishes Socialism)—संविधान की धारा 1 के अंतर्गत रूस को समाजवादी गणराज्यों का संघ, मजदूर तथा

1 Soviet System is immensely superior to bourgeois parliamentarianism for drawing in the broadest and in most energetic manner all the masses in the work of the government —Lenin

कृषकों का समाजवादो राज्य कहा गया है। इन समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व सवहारा वग करता है। समाजवाद को सोवियत अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, उत्पादन के समस्त साधनों पर सामूहिक नियन्त्रण का वगन किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शोषण का निषेध किया गया है। सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित की जाती है। सोवियत अर्थ-व्यवस्था पर मावस तथा लेनिन के दशन का विशिष्ट प्रभाव है। साम्यवादी सूत्र है कि "जो काय नहीं करेगा, वह खायेगा भी नहीं।" दूसरा सूत्र है "प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता तथा योग्यता के अनुसार मिलेगा।" इस प्रकार उद्योगों की राष्ट्रीयकृत व्यवस्था होगी, अतः रूसी संविधान एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करता है।

(9) एकदलीय शासन व्यवस्था (One Party Rule)—सोवियत संविधान एकदलीय शासन व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत साम्यवादी दल को मायता दी गई है और उस श्रमिकों का अप्रदूत कहा गया है। यद्यपि संविधान में अन्य राजनैतिक दलों के उत्पन्न होने पर प्रतिबंध नहीं है, किंतु जैसा विलियम्स ने कहा है कि वे एक ही शत पर उत्पन्न हो सकते हैं कि एक जेल में रहे और दूसरा शक्ति में।¹ साम्यवादी एकदलीय व्यवस्था के पक्ष में एक ही तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था पूँजीवादी वग व्यवस्था की सूचक है। इसके साथ ही रूस में वग व्यवस्था भी नहीं है, अतएव वहाँ अन्य राजनैतिक दलों की भी आवश्यकता नहीं है। रूस ही वस्तुतः ऐसा देश है जो लोकतंत्र का नारा लगाकर, संविधान में एक दल को ही मायता प्रदान करता है।

(10) बहुल कार्यपालिका (Plural Executive)—सोवियत संविधान की धारा 48 के अंतर्गत कार्यपालिका का स्वरूप बहुल रखा गया है। हम इसे सामूहिक राष्ट्रपति भी कहते हैं। प्रेसीडियम के अध्यक्ष को ही रूस का राष्ट्रपति कहा जाता है। वही विदेशी दूतों का स्वागत करता है तथा राष्ट्रीय समारोहों की अध्यक्षता करता है। इसका स्वरूप कुछ कुछ स्विट्स सघीय कार्यपालिका से मिलता हुआ है। परंतु स्विटजरलैंड की सघीय कार्यपालिका शक्तियों एवं उनके स्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप तुलना करने पर प्रेसीडियम की शक्ति नगण्य ही है। यह रूस की अनीसी सस्था है जोकि सर्वोच्च सोवियत की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करती है।

(11) 'यायपालिका की विशिष्ट स्थिति (Conspicuous Position of Russian Judiciary)—रूसी यायपालिका की स्थिति विशिष्ट प्रकार की है, वह सरकार के अंग के रूप में ही कार्य करती है। वहाँ पर 'यायपालिका को स्वतंत्र तथा संविधान का संरक्षक नहीं कहा गया है। वहाँ उच्चतम 'यायालय को संविधान के व्याख्याता का पद भी प्रदान नहीं किया गया है। उसकी स्थिति अमेरिकी अथवा भारतीय उच्चतम 'यायालय जैसी नहीं है। रूस में 'यायपालिका का प्रमुख रूप इस दृष्टिकोण से ही मापना होगा कि उसे शक्ति के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों

1 One is in the power and another is in jail

को दण्डित करने वाला निषाया कहा गया है। 'यायपालिका का बाय समाजवादी विचारधारा को निश्चित एवं दृढ़ बनाना है। अतः उसकी स्थिति विशिष्ट प्रकार की है।

(12) जनमत सप्पह तथा प्रत्याह्वान (Referendum & Recall)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 49 तथा 142 में लोक निणय तथा प्रत्याह्वान की व्यवस्था की गई है। लोक निणय प्रेसीडियम द्वारा स्वतः ही अथवा किसी गणराज्य की माँग पर ही कराया जा सकता है। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार दिया गया है अर्थात् रूस में संविधान में प्रत्यक्ष व्यवस्थापन को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य (Fundamental Rights & Duties)

माशाल स्टालिन ने कहा था कि, "एक भूखे बेरोजगार व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति के समस्त शोषण, बेरोजगारी भ्रष्टाचार एवं कल के लिये चिन्ता की समस्या नहीं है।" अब संविधान में अधिकारों को समाहित करने की परम्परा का भी प्रचलन आरम्भ हो गया है किन्तु अब भी विश्व के कुछ संविधान ऐसे हैं जिनमें मौलिक अधिकारों का विवेचन नहीं किया गया है। रूसी संविधान में अधिकारों एवं आदर्शों के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अधिकारों को प्राकृतिक अथवा मौलिक सामाजिक दावों के रूप में नहीं देखा गया है। यहाँ पर अधिकारों के प्रयोग को रूस की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ समाजवादी आधार पर दृढ़ करने का साधन माना गया है। साम्यवादी नागरिक तथा समूह में किसी द्वाद की कल्पना नहीं करते। राज्य के विरुद्ध विद्रोह को स्टालिन पाप कहता था तथा उसे भयानक प्रकार का अपराध मानता था। पूँजीवादी संविधानों के मौलिक अधिकारों को साम्यवादी उपहासार्थक मानते हैं। रूस में अब अधिकारों को संविधान में समाहित करके सरकार की शक्तियों को सीमित करने की परम्परा का प्रचलन हो गया है। आयरलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, जापान तथा भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकारों को लिपिबद्ध किया गया है परन्तु कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के संविधानों में मौलिक अधिकारों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। रूस के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रयोग एक साधन के रूप में किया गया है। सम्भवतः सन् 1918 तथा 1924 के संविधानों में इन अधिकारों को इस भय से सम्मिलित नहीं किया गया कि कहीं प्रतिप्रियावादी शक्तियाँ इसका लाभ उठा कर क्रांति को विफल करने का प्रयास न करें। सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रशंसा करते हुए विलियम कापि सकी ने कहा है कि 'स्टालिन संविधान सोवियत नागरिकों को ऐसे अधिकार और ऐसी स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है जोकि किसी पूँजीवादी देश में न तो पायी

1. What can be the Personal Freedom of an unemployed person who goes hungry and finds no use for his toil
—Marshall Stalin

जाती हैं और न पायी हो जा सकती हैं।¹ सोवियत संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ (Salient Features of Soviet Civil Rights)

(1) समाजवादी स्वरूप (Socialistic Basis)—सोवियत रूस में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गये हैं, उनका आधार सामाजिक है। वे व्यक्तिवादी विचारधारा एवं स्वार्थ पर ही अवलम्बित नहीं हैं। अधिकारों का सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ को अज्ञित करना मात्र ही नहीं है। वे जनहित के साधन हैं। हर व्यक्ति समाज में मजदूर है, वह परजीवी रह कर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकेगा। अधिकारों का प्रयोग करके वह दूसरों को विविध सुख सम्पत्ति से विमुख नहीं कर सकेगा।

(2) उद्देश्य तथा साधनों का सामंजस्य (Coordination of Ends & Means)—साम्यवादी पश्चिमी देशों के अधिकारों को केवल कागजी महत्त्व का बताते हैं। उनमें केवल उद्देश्यों का बणन है किंतु उन साधनों का बणन नहीं है जिनके माध्यम से उन्हें उपाजित किया जा सकता है। किंतु सोवियत संविधान में अधिकारों का बणन केवल सउद्देश्य ही नहीं किया गया है अपितु इसके साथ ही उन साधनों का भी बणन किया गया है जिनके माध्यम से वे प्राप्त किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ—अवकाश प्राप्ति के अधिकार के साथ ही विधाम ग्रह एवं छविग्रह आदि का भी बणन किया गया है जिनके माध्यम से वे प्राप्त किये जा सकते हैं।

(3) अधिकारों के साथ कतब्यों का भी उल्लेख है (Duties follow the Rights)—सोवियत संविधान में केवल मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख नहीं है अपितु उसमें मौलिक कतब्यों का भी उल्लेख किया गया है। साम्यवादी संविधान में अधिकार तथा कतब्यों को अविभाज्य माना जाता है। यदि नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि उसे काम मिले तो इसके साथ ही उसका यह कतब्य भी है कि वह काम करे। रूस का संविधान ही वह विश्व का पहला संविधान है जिसमें अधिकारों के साथ साथ ही मौलिक कतब्यों का भी बणन किया गया है।

(4) न्यायपालिका के संरक्षण का अभाव (Lack of Judicial Protection)—भारत, अमेरिका तथा अन्य बहुत से देशों के सदृश मौलिक अधिकारों को "न्यायिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। वहाँ के न्यायालय मौलिक अधिकारों के ऊपर सरकारी आक्रमण की स्थिति में स्वयं को सरकार के समक्ष असहाय पाते हैं।

(5) सामान्य प्रतिबंध (General Restriction)—सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सबहारा वर्ग का हित माना गया है। संविधान ऐसे अधिकारों का मायता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है जो सबहारा वर्ग के हितों के विरुद्ध हैं। भाषण लेखन आदि नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग समाजवादी मायताओं के अनुरूप ही किया जा सकता है, अन्य सोवतन्त्रीय देशों में इस प्रकार के सामान्य प्रतिबंध अधिकारों के ऊपर नहीं लगाये गये हैं।

1 The stalin Constitution grants Soviet Citizens rights and liberties not and cannot exist in any of the capitalist countries

(6) आर्थिक आधार के अधिकार (Economic Basis of the Rights)—विश्व के अग्र लोकतन्त्रीय देशों में नागरिक स्वतन्त्रताओं को अधिक महत्वपूर्ण मानकर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, परन्तु रूस में यह मान्यता है कि बिना आर्थिक स्वतन्त्रता के राजनीतिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ व्यर्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक अधिकार महत्वहीन हैं।

(7) समव्यापकता (Comprehensiveness)—सोवियत संविधान में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है वे समव्यापक हैं। समव्यापकता में अभिप्राय यह है कि वहाँ स्त्री तथा पुरुष में राजनीतिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं माना गया है। सब को समान अधिकार प्राप्त हैं। स्विट्जरलैंड जैसे जनतन्त्रीय देश ने भी सन् 1971 में महिला मताधिकार की व्यवस्था की है। इंग्लैंड में रोमन कथोलिक पादरियों को राजनीति से निष्कासित कर दिया गया है। ग़ोरे लोगों ने अभी भी वे देशों में मताधिकार प्रदान नहीं किया है।

सोवियत संघ के संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। (Fundamental Rights of the Citizens) इनका उल्लेख संविधान की धारा 118 से 133 तक किया गया है—

(1) काम पाने का अधिकार (Right to Work)—विलियम कारपिन्स्की के शब्दों में 'काम करने का अधिकार रूस के लोगों की महान सफलता है। इस प्रकार का अधिकार न किसी पूँजीवादी देश में है और नहीं हो सकता है।'¹ सोवियत संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत काम प्राप्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस अधिकार की स्वीकृति के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों को रुचि एवं योग्यता के अनुसार काम प्रदान करना राज्य का उत्तरदायित्व है। सन् 1930 में इस साधन के द्वारा ही बेरोजगारी पर पूर्णतः काबू पालिया गया था। यद्यपि डॉ॰ हरमैन फाइन्टर ने वहाँ इस अधिकार की सत्यता की दासत्व की स्थिति कहा है, परन्तु यह सत्य है कि वहाँ पर मजदूरों की स्थिति में सतोपजनक सुधार हुआ है। केवल भरणपोषण मात्र के लिए ही पारिश्रमिक की बात मत्त्व नहीं मानी जा सकती।

(2) विराम तथा अवकाश प्राप्त करने का अधिकार (Right to Rest and Leisure)—संविधान के अनुच्छेद 119 के अनुसार नागरिकों को विराम एवं अवकाश प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। श्रमिकों को सामान्यतः प्रतिदिन 7 घण्टे काम करना पड़ता है परन्तु जहाँ पर श्रमिकों को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है वहाँ पर उन्हें केवल 6 घण्टे काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर काम का स्वरूप अधिक कठोर एवं दुःख है वहाँ पर उन्हें केवल 4 घण्टे ही काम करना पड़ता है। श्रमिकों के लिए मनोरंजन चिकित्सा सैनोटोरियम तथा मिठा आदि की समस्त सुविधाओं के साथ साथ ही पूर्ण अवकाश की भी व्यवस्था है।

1 The right to work is the greatest achievement of the Soviet people. No such right exists or can exist in the capitalist countries
—Karpinsky

(3) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Security)—सोवियत संविधान में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। वृद्धावस्था तथा बीमार हो जाने की स्थिति में राज्य द्वारा पोषण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक बीमा, चिकित्सा केन्द्रों तथा स्वास्थ्य लाभ शालाओं का देश में जाल-सा बिछा हुआ है। सन् 1965 से वृद्धावस्था में सेवा वृत्ति (Pension) प्राप्त करने का अधिकार कृषकों को भी दिया गया है। सोवियत सरकार प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक बजट का अधिकांश भाग नागरिक सुविधाओं पर व्यय करती है। यह व्यवस्था पूँजीवादी देशों में स्पष्ट रूप में नहीं पाई जाती है, परन्तु लोकहितकारी स्वरूप के कारण भी राज्य को सामाजिक सुरक्षा के कुछ कार्य तो करने ही पड़ते हैं।

(4) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)—रूस में क्रांति से पूर्व निरक्षरता भयानक रूप में विद्यमान थी, परन्तु अब इसे दूर कर दिया गया है। कामिन्स्की के इस कथन में पर्याप्त सत्यता दिखाई देती है कि “स्टालिन संविधान के वे शब्द जिनके द्वारा नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकारों की घोषणा की गई थी। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के गायन के रूप में पढ़े जाते हैं। “सोवियत संविधान की धारा 121 में नागरिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 8 वर्ष की अवधि की शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। प्रारम्भ से लेकर उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्र वृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। हापर तथा थोम्पसन के शब्दों में “सोवियत शासन की सर्वाधिक प्रभावी सेवा राज्य शिक्षा सेवा के क्षेत्र में हुई है।”¹

(5) स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकार (Equal Rights of Men and Women)—सोवियत संघ की धारा 122 के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक सभी क्षेत्रों में स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों को भी पुरुषों के सदृश ही वेतन तथा शिक्षा आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। स्त्रियों को प्रसूति के समय पूर्ण वेतन सहित अवकाश भी दिया जाता है। नारियों के लिए देश में अनेकों प्रसूतिका ग्रह, नर्सरिया (शिशुपालन ग्रह) आदि बनी हुई हैं। सोवियत रूस के उद्योगों में इन नारियों की सराया लगभग 48 प्रतिशत है। विभिन्न प्रशासकीय विभागों में भी 55 से लेकर 58 प्रतिशत स्त्रियाँ कार्य करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगभग 70% स्थानों पर नारियाँ अपना योगदान देती हैं। सबसे अधिक शिशु उत्पन्न करने वाली माता को राज्य की ओर से ‘हीरोइन मदर’ की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। नारियों का इतना व्यापक पमाने पर योगदान किसी भी पूँजीवादी लोकतन्त्रीय देश में नहीं है।

(6) समानता का अधिकार (Right to Equality)—सोवियत संविधान

1 The most effective state service of the Soviet Union has been in the field of education
—Harper & A

के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रीयता एवं प्रजातियता, आदि के भेद भाव के बिना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शासकीय क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इन अधिकारों पर लगाई गई रूकावट को कानून के द्वारा दण्डनीय समझा जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय जाति को अपनी भाषा तथा शिक्षा रखने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च सोवियत के वरिष्ठ सदन में प्रत्येक इकाई को प्रादेशिकता के आधार पर समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

(7) धार्मिक स्वतन्त्रता का आधार (Right to Freedom of Religion)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत नागरिकों का धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है परन्तु इसके साथ ही धर्म के विरुद्ध प्रचार करने का भी अधिकार दिया गया है जिसका साम्यवादियों ने खुलकर प्रयोग किया। धर्म को बच के अधीन नहीं रखा गया है। इसमें मार्क्सवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पर धर्मियों के लिए धर्म की तुलना अफीम से की गई है। रूस में अब बहुत कम ही लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं। यहाँ पर धर्म को व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु कहा गया है तथा धर्म के प्रचार करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है।

(8) स्वतन्त्रता का अधिकार (Rights to Freedom)—सोवियत रूस के अनुच्छेद 125 में सोवियत नागरिकों को भाषण, लेखन, सभा, सङ्गठन तथा जुलूस आदि की स्वतन्त्रता दी गई है। उन्हें प्रकाशन आदि के लिए राजकीय सुविधाओं का भी आश्वासन दिया गया है परन्तु इन पर यह प्रतिबन्ध भी है कि ये कार्य समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध न हों। इन स्वतन्त्रताओं का प्रयोग समाजवाद के प्रयोग के लिये ही किया जा सकता है। साम्यवादी दल का रेडियो तथा प्रेस पर पूर्ण अधिकार है। रूस में कृषि की कमियाँ तथा प्रशासन में सुधार करने हेतु सुझाव दिये जा सकते हैं—

(9) समुदाय बनाने का अधिकार (Right to form Associations)—अनुच्छेद 126 के अन्तर्गत नागरिकों को समुदाय बनाने का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को सहकारी समितियाँ, सांख्यिक सङ्गठन, धार्मिक सभों तथा अन्य सलूकों तकनीकी सङ्गठन बनाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके साथ-साथ ही संविधान में साम्यवादी दल का सहारा वर्ग के अप्रदूत (Vanguard) के रूप में मान्यता दी गई है जोकि अपने स्वयं की एक ही है। साम्यवादी दल को समस्त सङ्गठनों एवं समूहों का नेतृत्व करने वाला कहा गया है। अतएव साम्यवादी दल की सर्वोच्चता से इस अधिकार का महत्व कम हो जाता है।

(10) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा गृह सुरक्षा का अधिकार (The Right to Inviolability of Person & Home)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 127 तथा 128 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा गृह सुरक्षा का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को ग्यायालय अथवा प्रोसेक्यूटर (ग्यायालय से सम्बद्ध एक अधिकारी) की बिना अनुमति के दण्ड नहीं दिया जा सकता है। नागरिकों के घर अथवा घर की गोपनीयता तथा धर्म प्रवर्तन का अधिकार का उल्लंघन नहीं किया

जा सकता। परंतु यह अधिकार देशद्रोहियों एवं साम्यवादी नीतियों का खण्डन करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। साम्यवादी कानून तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घरों में भी प्रवेश किया जा सकता है।

(11) शरण प्राप्त करने का अधिकार (Right to Get Asylum)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 129 ने रूस को विश्व के महान क्रांतिकारियों का घर बना दिया है। संविधान के उक्त अनुच्छेद में कहा गया है कि उन विदेशियों को राजनैतिक शरण प्रदान की जायगी जो उनकी सरकारों द्वारा मजदूर आंदोलनों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तथा अन्य वंशानुगत गतिविधियों में भाग लेने के कारण दण्डित किए गये हों। इस अधिकार से राजनैतिक अपराधों को प्रोत्साहन मिला और अपराधी दूसरी सरकारों के चंगुल से बच निकलने के लिये रूस में प्रवेश पाते लगे।

(12) निजी सम्पत्ति का अधिकार (Right to Private Property)—सोवियत संविधान के अंतर्गत नागरिकों को निजी सम्पत्ति रखने का भी अधिकार दिया गया है। श्रम द्वारा कमाया हुआ धन, कपड़े, फर्नीचर एवं अन्य विलासोपकरण तथा मकान, घरेलू वस्तुओं आदि को निजी सम्पत्ति माना गया है। इसे उपार्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी इस सम्पत्ति को प्राप्त कर सकेंगे। कानून के द्वारा इस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है।

(13) निर्वाचन सम्बंधी अधिकार (Right to Election)—सोवियत संविधान के अंतर्गत उन सब नागरिकों को निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार दिया गया है जिन्होंने 19 वर्ष की अवस्था प्राप्त करली है। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक को राजकीय शक्ति के सर्वोच्च आगार सुप्रीम सोवियत के लिये निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार दिया गया है।

सोवियत संघ में नागरिकों के कर्तव्य (Duties of Citizens in U S S R)

सोवियत संविधान में अनुच्छेद 130 से लेकर 133 तक नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है जोकि निम्न प्रकार हैं —

1 संविधान तथा कानूनों का पालन (Obedience & Observance of the Constitution & Law)—इसके अंतर्गत संविधान के प्रति भक्ति कानूनों का पालन, श्रम अनुशासन को बनाये रखना, सांख्यिक कर्तव्यों तथा समाजवादी नियमों का पालन सम्मिलित है।

2 सांख्यिक सम्पत्ति की सुरक्षा (Protection of Public Socialist Property)—अनुच्छेद 131 में समाजवादी सम्पत्ति को राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि का स्रोत माना गया है। इसे श्रमिकों की सत्कृति तथा धन्य का स्रोत भी कहा गया है। इसके अनुसार समाजवादी सम्पत्ति का विरोध करने वाला जनता का शत्रु होगा। इस सम्पत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

3 सैनिक सेवा (Military Service)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 132 में सैनिक सेवा को सम्मानित कर्तव्य कहा गया है और जिसे विलियम कारपिस्की

ने सम्मानित अधिकारों की परम्परा में सर्वोत्तम मूल्य का कतव्य माना है और लिखा है कि "इससे बढ़कर अधिक सम्मानित और बौनसा कतव्य हो सकता है कि हम हाथ में शस्त्र लेकर अपने महान सोवियत देश की रक्षा करें। और यह मानवता द्वारा शोषण से मुक्ति पाने के लिए सघर्ष करने वालों की एक मात्र आशा है।"

4 स्वदेश की रक्षा (Defence of Motherland)—अनुच्छेद 133 में देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कतव्य बताया गया है। देशद्रोहिता, राष्ट्र की गुप्त बातों की सूचना देना, शत्रुओं से जाकर मिलना आदि कार्यों की निंदा की गई है, तथा इसे असम्य अपराध कहा गया है, अतएव इस अपराध के लिए अधिक से अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

5 काय करने का कतव्य (Duty to Work)—सोवियत संविधान में जहाँ एक ओर काम करने का अधिकार दिया गया है वहाँ दूसरी ओर काम करने को एक कतव्य भी माना गया है, क्योंकि रूस में यह सिद्धांत प्रचलित है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए भी काम नहीं करेगा उसे खाने की भी नहीं मिलेगा।

मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन (Fundamental Rights Evaluated)

मौलिक अधिकारों को संविधान में समाहित करने की रूसी परम्परा कोई नवीन नहीं है। रूस में पहले विश्व के कई अन्य संविधानों ने भी मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है। सबसे अधिक नवीन बात यह है कि सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों के अंकन के साथ-साथ ही उन साधनों का भी वर्णन किया गया है जिनके द्वारा उन्हें उपाजित किया जा सकता है। संविधानों में अधिकारों का उल्लेख ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उनका व्यावहारिक पक्ष भी दुर्बल होना चाहिए। सोवियत लेखक निकोलाई चरेनिस्वस्की ने कहा था कि "सभी को सोने की पाली में खाने का अधिकार हो सकता है, परंतु इस अधिकार के उपयोग के लिये सभी के पास सोन की पाली भी होनी चाहिए।" सोवियत रूस में आर्थिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वृद्धावस्था के समय राजकीय आर्थिक सहायता आराम तथा अवकाश की व्यवस्था रूस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सोवियत संविधान वस्तुतः पूँजीवादी राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। निरक्षरता की समस्या का समाधान करना रूस की बहुत बड़ी विजय है। राष्ट्रीय जातियों, भाषा तथा नस्ल आदि के लिए समानाधिकार की व्यवस्था की गई है। सोवियत संविधान ने काय के अधिकार (Right to Work) को स्वीकार करके विश्व में पूँजीवादी संविधानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

सोवियत संविधान में स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गये हैं। सोवियत जीवन में राजनितिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में महिलाओं का जितना अनुदाय है उतना अग्र हमें देखने को नहीं मिलता। अधिकारों की सीमित व्यवस्था होत हुए भी रूस ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित है। जिसमें आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक समानता का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों का कोई भी

स्वरूप क्यों न हो किन्तु यह तो मानना ही होगा कि रूस के पूँजीवादी आलोचक भी यह मानते हैं कि सोवियत देश ने विज्ञान तथा साहित्य के क्षेत्र में असाधारण उन्नति की है। जनसाधारण का स्तर ऊँचा हुआ है, वहाँ असह्य लोगों की महानत पर कुछ लोग जीवित नहीं रहते। वहाँ पर भूखे मरने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जो कि पूँजीवादों राष्ट्रों में गरीबों का एक कतव्य सा ही बन गया है, जूलियन टाउस्टर (Julian Towster) के शब्दों में “सोवियत सभ ने रचनात्मक स्वतंत्रताओं को स्थान देकर अग्र देशों का मागदश किया है।”

आलोचना (Criticism)

सोवियत सविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि वे किस सीमा तक उपलब्ध हैं और उनका व्यावहारिक स्वरूप क्या है। सोवियत सविधान में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उन पर तीव्र कटाक्ष करते हुए फाइनर ने कहा है “कि सोवियत नागरिकों के अधिकार जनता द्वारा छीने गये तथा जनता द्वारा घोषित अधिकार नहीं हैं जिन्हें जनता द्वारा सरकार पर सौंपा गया है। अपितु वे अधिनायकवादी सरकार द्वारा जनता को दास रूप में प्रदान किए गये हैं, वे तानाशाह की मेज से गिरे हुए रोटी के टुकड़े हैं जिसका उपयोग तानाशाह साधन के रूप में करता है।” मौलिक अधिकारों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है।

(1) ये केवल कागजी अधिकार हैं (They are Simply Paper Rights) पश्चिमी आलोचकों का यह कहना है कि सोवियत सविधान में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वे सिर्फ कागजी घोड़े हैं। उनका प्रयोग केवल समाजवादी व्यवस्था को बढ़ा करने की दृष्टि से ही किया गया है, क्योंकि नागरिक व्यावहारिक जीवन में उनका प्रयोग नहीं कर पाते। यदि किसी अधिकार से समाजवादी सिद्धांत का विरोध होता है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ—नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है परन्तु धर्म के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रूस में समानता का अधिकार दिया गया किन्तु वहाँ यहूदियों के साथ सद्व्यवहार नहीं किया गया। सविधान में जो स्वतंत्रताएँ दी गई हैं उनका प्रयोग समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रचार के लिये ही किया जा सकता है, उसके विरोध के लिए नहीं। सन् 1932 के एक आदेश के अनुसार देश में भ्रमण करने के लिए भी गृह पारपत्र (Home Passport) प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के 24 घंटे तक घर के बाहर रहता है तो उसकी सूचना प्रशासन को देनी पड़ती है। भाषण तथा विचारों की अभिव्यक्ति की बात उपहासात्मक है। यहाँ तक कि डा० जिवगो (Zivago) को नोबल पुरस्कार भी प्राप्त नहीं करने दिया गया तथा उसी दुविधा में उसकी मृत्यु भी हो गयी। वस्तुतः वहाँ नागरिकों का जीवन रूस की खुफिया पुलिस (Secret Police) के हाथों में है। यहाँ का गुप्तचर विभाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्वस्त कर सकता है।

(2) न्यायिक संरक्षण का अभाव (Absence of Judicial Protection)—सोवियत सविधान में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उन्हें सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है। अमेरिका तथा भारत के समान रूस में न्यायालय

के अधिकारों का संरक्षण नहीं करते। 'साधारण'ों को सविधान की व्याख्या करने तक का अधिकार नहीं है। इसी कारण मौलिक अधिकारों के भंग होने पर नागरिक 'साधारण' संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाते।

(3) अधिकार साम्यवादी दल के एकाधिकार की वस्तु है (Rights are Subjects of Communist Party's Monopoly)—समस्त मौलिक अधिकार सभी साधारण हो सकते हैं जबकि ये साम्यवादी दल की मायताओं के अनुकूल हों। साम्यवादी दल का अधिकारों के उपयोग पर पूर्ण अधिकार है। शिक्षा के माध्यम द्वारा भी साम्यवादी प्रचार कराया जाता है। स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोगों की वाणी पर सारा सारा रहता है।

(4) नागरिकों को काम पान का अधिकार तो है परन्तु वे अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते।

(5) जाति अथवा रंग का कोई भेद नहीं किया जाता है परन्तु फिर भी वहाँ पर अल्प संख्याओं का शोषण किया जाता रहा है।

(6) शरण प्रदान करने के अधिकार से अपराधियों की दुष्ट प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ही मिला है।

(7) वहाँ पर नागरिकों को निर्वाचन का अधिकार तो प्राप्त है, किन्तु वहाँ निर्वाचन केवल एक दिखावा मात्र हो होते हैं क्योंकि जिस समय तक अल्प राजनैतिक दलों का अस्तित्व ही नहीं हो उस समय तक निर्वाचन एक, दल के आदेश ही कहे जायेंगे।

(8) अनुच्छेद 126 के अन्तर्गत संसद का अधिकार दिया गया है परन्तु वह समाजवादी व्यवस्था तथा साम्यवादी दल के प्रतिवृत्त नहीं होना चाहिए।

(9) सोवियत रूस में विचार करना भी चेतना पर 'सोव' आचरण के समान ही है।

यह ठीक है कि पश्चिमी आलोचक रूस की प्रगति की उपेक्षा करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को बोलने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक सन्तुष्टि ही पर्याप्त नहीं होती। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि रूस में इतने प्रतिबन्धों के होते हुए भी विज्ञान तथा प्रावधिक ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अमूर्तपूर्व उन्नति किस प्रकार की है। कोई भी देश नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घोटकर वैज्ञानिक उन्नति के शिखर पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रतिभा भी कुण्ठित हो जाती है। परन्तु इसके विपरीत सोवियत रूस की प्रतिभा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सोवियत रूस के पश्चिमी आलोचक सत्यता की अपेक्षा शोर प्रचार अधिक करते हैं। यदि रूस में जन जीवन उन्नत एवं सुखी नहीं होता तो उसकी शक्ति की सफलताएँ कभी की इवस्त हो गई होतीं।

Select References

- Carter : *The Govt of U S S R*
 Towster : *Political Power of U S S R*
 Munro : *Govts of Europe*
 Finer : *Major Govts of Europe*
 Ogg & Zink : *Modern Foreign Govts*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 सोवियत संघ का संविधान कई बातों में संसार के अन्य संविधानों से अद्वितीय है। इस कथन की व्याख्या कीजिये।
(The constitution of U S S R is unique and makes a serious departure from other constitutions of the world) Discuss
- 2 सोवियत रूस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
- 3 सोवियत संघ में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि वे कहाँ तक वास्तविक हैं।

सोवियत सघात्मक व्यवस्था (Soviet Federalism)

"By the generally accepted western standards of Political Science, Soviet Federalism is as real as the Emperors new clothes in Hans Christian Anderson's famous tale"

—Neumann

Soviet Federalism remains only the federalism of accident'

—Finner H

परिचयात्मक

सोवियत सविधान के अनुच्छेद 13 में रूस की सघात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। रूसी राज्यक्रांति के जन्मदाता लेनिन ने सघ व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था कि 'सघात्मक व्यवस्था केवल पूर्ण एकता के पथ की ओर एक सन्क्रांतिकालीन अवस्था है।'¹ सोवियत नेताओं ने कभी भी सघात्मक व्यवस्था को स्थायी संस्था के रूप में नहीं देखा। लेनिन स्वयं अनुभवमूलक तथा राष्ट्रीय जातियों को लोकतंत्रीय एकात्मक सूत्र में श्रवसा बद्ध करने का प्रयत्न करता था। लेनिन ने अपने प्रवास काल में ही स्विटजरलैण्ड के स्वरूप के आधार पर सघ के निर्माण के विचार को काफी समय पूर्व ही अस्वीकृत कर दिया था। प्रत्येक सघ की उत्पत्ति का कोई मूल आधार अवश्य हुआ करना है। अमेरिकी सघ के निर्माण का आधार मौलिक रूप से आर्थिक एवं विकेंद्रित व्यवस्था की आकांक्षा था। भारतीय सघ में एकात्मकता का मूल कारण उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। रूसी सघ में एकात्मकता का कारण अनेकता की सदब के लिए सबहारा वग के अधिनायकत्व को समर्पित करना था। लेनिन ने सघात्मक पद्धति का मूलतापूर्ण सिद्धांत कहा था। वह आरम्भ से ही सघात्मक पद्धति को अनुपयुक्त प्रकार की पद्धति मानता था क्योंकि यह आर्थिक सम्बन्धों का कमजोर बनाती है। इसी कारण सोवियत नेताओं ने सघात्मक पद्धति को एक साधन के रूप में अपनाया है। स्वयं मानस ने इस व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था के लिये अनुपयुक्त बताया है। एजिल्स ने कहा था कि 'सबहारा वग केवल राज्य के एकात्मक तथा अविभाजित गणराज्य के रूप का ही प्रयोग कर सकता है।'²

सोवियत नेताओं ने सघात्मक पद्धति को बड़े घूट के रूप में ग्रहण किया।

1 Federalism is only a transitional form on the road to complete unity —Lenin

2 The proletariat can use only the form of one and indivisible republic —Engels

राजनैतिक एकता के बदले उन्हें दुबल सघात्मक एकता को स्वीकार करना पडा। इसके कारण निम्नलिखित हैं

1 सघात्मक व्यवस्था को अपनाना ही एकमात्र उपाय था। सोवियत नेता इस तथ्य से परिचित थे कि रूस बहु भाषाओं, जातियों एवं संस्कृतियों वाला देश है, उन सबको शक्ति के द्वारा एकात्मकता के सूत्र में नहीं बाँधा जा सकता। यदि शक्ति प्रदर्शन तथा बल प्रयोग से उन राष्ट्रीय जातियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध मिला भी लिया गया तो उसके परिणाम भी भयंकर ही होंगे। रूसीकरण की नीति से राष्ट्रीय जातियों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

2 सघात्मक व्यवस्था एक भाई चारे का समझौता होता है। सघात्मक पद्धति में यह भाई चारा तथा मंत्रीपुण व्यवहार हमें केवल तभी मिल सकता है जब कि इकाइयों के पक्के व्यक्तित्व की सुरक्षा की जाय। विलियम कारपिन्सकी ने सोवियत समाजवादी गणराज्य को सोवियत राष्ट्रो का भाई चारा कहा है। सहयोग के आधार पर इसे एक सघ राज्य के सूत्र में पिरोया गया है।

3 जिस समय सोवियत नेताओं ने सघ व्यवस्था को अंगीकार किया था उस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी। पूँजीवादी राष्ट्रो ने ममुक्त रूप से सोवियत भूमि में पक्कतावाद की चिनगारी सुलगा कर उसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया। अतएव उस समय सोवियत नेताओं के लिए राष्ट्रीय जातियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया। उसकी पूर्ति केवल सघात्मक व्यवस्था से ही सम्भव थी।

4 विध्वस्त अव्यवस्था के कारण भी सघात्मक प्रणाली को अपनाना आवश्यक था। उसका पुनर्निर्माण करना भी अत्यंत आवश्यक था जो कि सघात्मक व्यवस्था में ही सम्भव थी क्योंकि उसकी सफलता इकाइयों के सहयोग पर अवलम्बित थी।

सोवियत सघ में सघात्मक तत्व

(Elements of Federalism in Soviet Federation)

सोवियत संविधान क अनुच्छेद 13 में रूस को सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ का एक एक सघात्मक राज्य कहा गया है। यद्यपि प्रो० ऑंग ने रूस की व्यवस्था को सघात्मक स्वीकार नहीं किया है¹ तो भी उसमें सघात्मकता के तत्व पाये जाते हैं। यद्यपि उसकी प्रवृत्ति एकात्मक है। रूसी सघ में सघात्मकता के निम्न लिखित तत्व पाये जाते हैं।

1 सरकारों की द्वैध व्यवस्था (Dual Organization of Government)—सरकारों की द्वैध व्यवस्था सघात्मक पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। रूस में भी यह व्यवस्था पाई जाती है। रूस में माँस्को सरकार है जिसे हम केन्द्र अथवा सघ सरकार कहते हैं और दूसरी प्रत्येक सघीय इकाई की अपनी सरकार है। रूसी सघ में इस समय 15 गणराज्य (Union Republics) हैं। इन गणराज्यों को ही सघ की भूल इकाई माना गया है। प्रत्येक गणराज्य के अलग-अलग तीन अंग प्रकार की

1 The system is not federal in any ultimate sense at all

इकाइयाँ भी स्वतन्त्रता का उपयोग करती हैं। वे इस प्रकार हैं—स्वायत्त गणराज्य (Autonomous Republics), स्वायत्त क्षेत्र (Autonomous Regions) तथा राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas)। अमेरिका की भाँति प्रत्येक गणराज्य का अपना अपना संविधान है। सोवियत संविधान स्वायत्त गणराज्यों को भी पक्ष संविधान रखने का अधिकार प्रदान करता है परन्तु स्वायत्त क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों को यह अधिकार नहीं है। रूस में दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था है। सोवियत संघीय विधान मण्डल के द्वितीय सदन के लिये समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है—प्रत्येक गणराज्य को 15 प्रतिनिधि, स्वायत्त गणराज्य को 11 प्रतिनिधि तथा प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र को 5 तथा राष्ट्रीय क्षेत्र को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। संघ सरकार तथा गणराज्यों की सरकारें समस्तरीय हैं। गणराज्यों की सरकारों के क्षेत्र में बिना उनकी सहमति के परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

2 शक्तियों का वितरण (Division of Powers)—संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इस दिशा में रूसी संघ ने अमेरिकी पद्धति का अनुकरण किया है। केन्द्र सरकार को मुख्य-मुख्य विषय दिए गये हैं तथा अवशिष्ट शक्तियों को गणराज्यों की सरकारों में ही निहित माना गया है। केन्द्र सरकार के आधीन जो विषय रखे गये हैं उनमें कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—युद्ध तथा शांति, गणराज्यों का प्रवेश, गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण गणराज्यों के संविधानों की अनुकूलता पर नियंत्रण, विदेशी व्यापार, राज्यों की सुरक्षा का प्रबंध, राष्ट्रीय आर्थिक योजना, केन्द्रीय बजट, बैंक तथा कृषि का संघीय महत्त्व, परिवहन संचार, मुद्रा, राज्य बीमा का संगठन, भूमि, खनिज द्रव्य वन एवं स्वास्थ्य आदि के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण, श्रम कानून निर्धारण 'यायिक पद्धति एवं प्रक्रिया, विवाह एवं परिवार कानून, नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकार, संघीय क्षमादान आदि। संघीय गणराज्यों के संरक्षण का उत्तरदायित्व संघीय सरकार पर ही है तथा दो भागों में मतभेद हो जाने की स्थिति में भी केन्द्र की इच्छा को ही उच्चतर माना गया है।

3 संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)—सोवियत 'यायविद संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, संविधान समस्त शक्तियों का स्रोत है। साधारण कानून से वह उच्चतर है। उसमें परिवर्तन की व्यवस्था भी साधारण कानून से भिन्न है। संविधान लिखित है परन्तु उसे अनम्य संविधानों की श्रेणी में ही माना जाता है। सोवियत संघ की किसी भी इकाई का पृथक् संविधान अथवा उसमें संशोधन संघीय संविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता। संविधान का स्वरूप पूर्वनिर्धारित एवं निश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत रूस के संविधान में सर्वोच्चता के लक्षण सभी लक्षण पाये जाते हैं।

4 स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)—स्वतंत्र न्यायपालिका को संघ व्यवस्था की एक मूलभूत आवश्यकता माना गया है। केन्द्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उनके निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका एक बहुत बड़े विश्वास का काय करती है। वह संविधान का संरक्षण एवं उसकी

ध्याख्या करती है, अमेरिका में सविधान में गति एवं गरिमा बनाये रखने में उच्चतम 'यायालय का स्थान महत्वपूर्ण है। उच्चतम 'यायालय को 'यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का अधिकार है। स्विस सविधान अपने सघीय 'यायाधिकरण को यह अधिकार प्रदान नहीं करता। रूस में भी 'यायापानिका के पास यह अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से भी सोवियत सघ की सघात्मकता पर कुछ सदिग्धता आ सकती है। सोवियत रूस में 'यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रेसीडियम के हाथों में समर्पित किया गया है।

सोवियत सघ की विशिष्टताएँ (Special Features of Soviet Federation)

1 सोवियत रूस में सघात्मक व्यवस्था को एक साधन के रूप में अपनाया गया है, विभिन्न राष्ट्रीय जातियों की सृष्टि की दृष्टि से एकात्मकता को सघात्मकता के माग द्वारा खोजने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य कभी भी एकता तथा विकेंद्रीकरण का सम्बन्ध नहीं रहा।

2 सोवियत सघ विभिन्न राष्ट्रीय जातियों का सघ है। ये राष्ट्रीय जातियाँ ही सघ की इकाइयाँ हैं। सघ की प्रत्येक इकाई एक राष्ट्रीय जाति का प्रतिनिधित्व करती है।

3 सोवियत सघ की एक विशेषता यह है कि उसकी इकाइयों को सघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी प्राप्त है। सोवियत नेता इसी अधिकार पर गव करते हैं और अपने सविधान की धारा 17 को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे वे पूर्वाजादी सघ व्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती मानते हैं। सघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का आधार राष्ट्रीय आत्म नियंत्रण का सिद्धांत है। इसी अधिकार के कारण रूस को अमेरिका की भांति सतत सघ (Perpetual Federation) नहीं कहा जाता।

4 सोवियत सविधान में फरवरी 1944 में दो अनुच्छेद (18 A तथा 18 B) और भी सम्मिलित किए गए हैं। इन सशोधनों के द्वारा सोवियत सघ की इकाइयों को दो और महत्वपूर्ण अधिकार—विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार तथा सैनिक दृकडियों के संगठन का अधिकार—प्रदान किये गये। यद्यपि निश्चित सीमाओं में स्विस सविधान भी 'कैंटन' को ये अधिकार देता है परन्तु सोवियत सविधान तो अपने सघ की इकाइयों को विदेशी राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के अतिरिक्त उन्हें समुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बनने तक का अधिकार भी प्रदान करता है। उदाहरणार्थ—यूक्राइन तथा बेलोरसिया उसके सदस्य भी हैं।

5 सोवियत सघ व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि वहाँ पर सघ की इकाइयों में समानता नहीं है। केवल सघ गणराज्यों को ही सघ की मूल इकाई माना गया है और अन्य तीनों को गणराज्यों के आधीन स्वायत्तता प्रदान की गई है। सर्वोच्च सोवियत के वरिष्ठ सदन में तो प्रतिनिधित्व की समानता रखी गई है परन्तु निम्न सदन (सोवियत आफ दी यूनियनों) में प्रतिनिधित्व की समानता नहीं की गई है। सोवियत सघ में सोवियत समाजवादी गणराज्य (U S S R) को प्रधानता प्रदान की गई है।

6 सोवियत सभ में सविधान में सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार सभ की इकाइयों को नहीं है।¹ सोवियत सविधान में भारतीय सविधान की भाँति सभ की इकाइयों को सविधान में सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अमेरिकी तथा स्विस् सभों में यह अधिकार सभ की इकाइयों को प्राप्त है।

7 'यायिक सर्वोच्चता का अभाव (Absence of Judicial Supremacy)—अमेरिका तथा भारत की भाँति सोवियत सभ की यायपालिका को सविधान का संरक्षक एवं व्याख्याता नहीं माना गया है। वहाँ पर यायपालिका को सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए उन्हें यायिक पुनर्बीक्षण का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अतएव वहाँ की 'यायपालिका को वह स्तर तथा संवैधानिक स्तर प्राप्त नहीं है जोकि अमेरिकी तथा भारतीय उच्चतम न्यायालयों को प्राप्त है।

8 राजनैतिक स्वायत्तता के स्थान पर सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान की गई है (More Cultural Liberty than Political)—वैसे तो प्रत्येक सभ में इकाइयों को विविध प्रकार की सुविधाएँ एवं स्वतंत्रताएँ दी जाती हैं परन्तु रूस के सविधान में राजनैतिक स्वतंत्रताओं का तो गंवा ही छोड़ दिया गया है और सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं का बाहुल्य कर दिया गया है। प्रत्येक राष्ट्रीय जाति को अपनी भाषा, धरणा आदि रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह कहना उचित ही है कि सभवाद का आधार ही शक्तियों की विकेंद्रित व्यवस्था होती है परन्तु सोवियत सविधान ने जितनी छूट सांस्कृतिक क्षेत्र में इकाइयों को प्रदान की गई है वह अन्यत्र नहीं मिलती।

सोवियत सभवाद का मूल्यांकन (Soviet Federalism Evaluated)

फाइनर ने कहा है कि "सोवियत सभवाद केवल संयोग से ही सघातमक है।"² ऑग के अनुसार 'सोवियत पद्धति किसी भी रूप में सघातमक नहीं है।' काटर तथा हट्ज ने लिखा है कि "सोवियत सभवाद एक सुविधाजनक अपवाद की अपेक्षा अन्य अधिक कुछ नहीं है जोकि स्वायत्तता के विविध रूपों तथा शक्ति के पूर्ण विकेंद्रीकरण का समन्वय है।"³ सोवियत सभ की भी अपनी कई 'गूँतलाएँ' हैं।

(1) सिद्धान्त तथा व्यवहार में अंतर (Difference between Theory and Practice)—प्रत्यक्ष में तो ऐसा जान पड़ता है कि सोवियत सविधानवादियों ने सघातमकता का उच्चतम परिचय दिया है। संभवतः कोई भी शक्तिशाली सघातमक अपनी इकाइयों को सभ से सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार नहीं देता परन्तु सोवियत रूस में सैनिक टुकड़ियों तक को भी संगठन का अधिकार प्रदान किया गया है। सोवियत सविधानवादी अपने सविधान को सबसे अधिक सघातमक कहते हैं। प्रो० हैज़र्ड (Hazard) ने रूस की सघातमक व्यवस्था को शुद्ध सभ कहा है। परन्तु व्यवहार में सोवियत सभ का यह स्वरूप नहीं है। डॉ० व्हीयर (Wheare) ने उसे

1 Units are not granted right to initiate Amendment to the Constitution
2 Soviet Federalism remains only the federalism of accident —Flöer
3 "Soviet federalism is no more therefore than a convenient myth which makes it possible to combine the forms of autonomy with the facts of centralization —Carter & Hertz

अद्व सघ कहा है। उसमे पूण रूप से केन्द्रवाद की प्रवृत्ति है। सघात्मक व्यवस्था का सार विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति मे है। सिद्धात मे तो वहाँ इसकी बहुलता है परंतु व्यवहार में इसका अभाव ही है।

(2) सविधान की सर्वोच्चता सविघ्नतापूण है (Sovereignty of the Constitution is Doubtful)—सिद्धात मे तो सविधान की सर्वोच्चता प्रदान की गई है परंतु व्यवहार मे सवहारा वग को ही सावभौमिक माना गया है। सविधान का प्रयोग एक साधन के रूप मे किया गया है। सवहारा वग को अमर्यादित कहा गया है। वह सविधान के प्रावधानो से भी मर्यादित नहीं है। सोवियत सविधान मे सवहारा वग के अधिनायकत्व की अभिव्यक्ति है। उसी की इच्छा ने अनुसार सविधान का भी परिवर्तित होना आवश्यक है। साम्यवादी दल की नीतियो एव इच्छाओ के अनुकूल ही सविधान में परिवर्तन होते हैं। व्यवहार मे सविधान की अपेक्षा साम्यवादी दल की इच्छा को ही अधिक महत्व दिया गया है। विशिष्की के अनुसार "सवहारा अधिनायकत्व को विधियों द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता।"¹

(3) केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति (Spirit of Centralization)—सघात्मक सरकार की एक कसौटी स्वायत्तता की मात्रा भी होती है। हम भारतीय सघ की आलोचना करते हैं कि उसमे केन्द्रीकरण की मात्रा इतनी अधिक है कि इकाइयो का स्तर घट कर उपनिवेश जैसा ही रह गया है। उसी प्रकार सोवियत सघ मे भी चाहे सिद्धात मे सघ की इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त हो परंतु उनका स्तर उपनिवेश से अधिक नहीं माना जा सकता। सोवियत सघ मे भी केन्द्रीयकरण की इस प्रवृत्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हावर के कथनानुसार सोवियत सविधान मे भी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति मे और भी अधिक वृद्धि भयकर रूप मे हो रही है। सोवियत सविधान मे केन्द्रीकरण की यह प्रवृत्ति निम्नलिखित रूप मे दृष्टिगोचर होती है

1 सविधान की सवहारा वग के प्रति आधीनता (Subordination of Constitution to Proletarian Class)—सोवियत सविधान की सर्वोच्चता सविघ्नतापूण है, क्योंकि उसके लिए सवहारा वग के समक्ष समर्पण करना आवश्यक हो जाता है। सविधान के प्रारम्भ मे ही सविधान की भावना को अमेरिकी तथा भारतीय सविधानों की भांति व्यक्त नहीं किया गया है। उसे जन इच्छा पर अवलम्बित नहीं कहा गया है। सविधान का प्रयोग एक साधन के रूप मे किया गया है।

2 इकाइयो को सविधान में सशोधन का अधिकार प्राप्त नहीं है (Constituent Units have no Right to Propose Amendment in the Constitution)—सोवियत सविधान मे सशोधन की शक्ति एकमात्र सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त है। सघ की इकाइयो को सविधान मे सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं उनकी पुष्टि इकाइयो के द्वारा नहीं की जाती। इसके विपरीत अमेरिका तथा स्विटजरलैण्ड दोनों ही यह अधिकार अपनी अपनी इकाइयो को प्रदान करते हैं, यद्यपि यह अधिकार

1 The dictatorship of the Proletariat is authority unlimited by any statutes whatsoever

भारतीय संविधान भी अपने सघ की इकाइयों को नहीं देता है परन्तु फिर भी कुछ संशोधनों की पुष्टि आधे राज्यों से करना आवश्यक होता है।

3 एक दलीय नेतृत्व (One Party Rule)—रूस में शासन का स्वीकृत स्वरूप है। साम्यवादी दल ही वस्तुतः शासक है। उसकी नीतियों का अनुसरण ही सरकार के सब अंग करते हैं। साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण के कारण ही सघ तथा उसकी इकाइयों में पारस्परिक सघर्ष नहीं होते। साम्यवादी दल का संगठन स्वतः ही एकात्मक है। दलीय संगठन शासन के समानांतर चलता है।

4 इकाइयों को सम्बंध विच्छेद करने का अधिकार (Units have a Right of Secede)—यदि इस अधिकार का प्रयोग व्यवहार में भी सम्भव हो, तो यह अधिकार सघात्मकता का अतिशयोक्ति रूप है। यह अधिकार तो इकाइयों की एक बहुत बड़ी विजय है परन्तु व्यवहार में किसी भी गणराज्य के लिए सघ से पृथक होने का प्रस्ताव रखना तो असम्भव ही है, अपितु वह उसका स्वप्न भी नहीं देख सकता। चूँकि किसी भी इकाई का नागरिक स्वतंत्र होने का आभास भी प्रस्तुत करता है उसे तत्काल ही देशद्रोही का आरोप लगाकर कारावास में ही रखा जाता है।

5 विदेशी विषयों पर गणराज्यों द्वारा नियंत्रण का अधिकार केवल एक दिखावा मात्र ही है (Republics Independence in Foreign Affairs is Exhibitory)—आलोचकों का कथन है कि सघीय गणराज्यों को विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होना केवल एक दिखावा मात्र ही है। यह केवल एक ढोंग है। इस अधिकार के माध्यम से सोवियत नेता सरलतापूर्वक सब बात अनुभव अवश्य कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी इकाइयों को कितनी स्वायत्तता दे रखी है। सोवियत संविधान के इस प्रावधान का लाभ केवल यूक्राइन तथा बलोरोशिया को ही प्राप्त हुआ परन्तु वह भी वास्तविक नहीं है। साम्यवादी दल तथा नियोजन आयोग के कार्यों का अधिकार क्षेत्र भी इतना व्यापक है कि उसके समक्ष यह अधिकार महत्वहीन ही दिखायी पड़ता है। यह साम्यवादी शासन का केवल एक दिखावा मात्र ही है।

6 सघीय कानून की सर्वोच्चता (Supremacy of the Union Law)—सोवियत संविधान में सघीय कानून को प्राथमिकता प्रदान की गई है। गणराज्य तथा सघ के कानूनों के सघर्ष की स्थिति में भी सघीय कानून की इच्छा को ही प्राथमिकता दी जाती है। सघ किसी भी गणराज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून को रद्द कर सकता है। कानूनों को प्रयुक्त करने का उत्तरदायित्व केवल केन्द्र पर ही है।

7 केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता (Financial Dependence upon Centre)—गणराज्यों की वित्तीय निर्भरता इतनी अधिक है कि प्रत्येक समय उन्हें केन्द्रीय सहायता की ओर उन्मुख रहना पड़ता है। आय के प्रमुख स्रोत केन्द्र के ही अधिकार में हैं। गणराज्यों के विधान मण्डलों को वतमान कर में कटौती करने का अधिकार नहीं है। वे कोई भी नूतन कर केन्द्र की अनुमति बिना नहीं लगा सकते। सघ शासन ही यह निश्चित करता है कि कौन से करों को केन्द्र के अधीन रखा जाय और कौन से करों को सघाने का अधिकार गणराज्यों को प्रदान किया जाय।

8 आर्थिक नियोजन (Economic Planning)—इसमें सन्देह नहीं है कि नियोजित व्यवस्था के द्वारा रूस ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, परन्तु साथ में यह भी स्वीकार करना होगा कि आर्थिक नियोजन का प्रयोग सघीय गणराज्यों की सरकारों पर नियन्त्रण रखने के लिए भी किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक नियोजन आच्छादित है। इन स्वायत्त इकाइयों के भी अपने नियोजन आयोग हैं परन्तु उन्हें अपने नियोजनों की अंतिम स्वीकृति के द्रीय नियोजन आयोग से ही प्राप्त होती है। अतएव रूस में आर्थिक केन्द्रीयकरण है।

9 न्यायपालिका की विवशता (Helplessness of the Judiciary)—अमेरिका की अपेक्षा सोवियत उच्च न्यायालय का महत्व संविधान के संरक्षक एवं व्याख्याता के रूप में बहुत कम है। उच्चतम न्यायालय को सर्वहारा वर्ग के हितों के साक्षक के रूप में रखा गया है। वहाँ न्यायपालिका का सक्रिय साम्यवादी क्रांति को सुदृढ़ बनाना है। यथाथ में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये पहले से ही नाम साम्यवादी दल के प्रेसीडियम द्वारा तय कर लिए जाते हैं। न्यायालय के साथ एक प्रोड्यूरर की नियुक्ति को स्पष्ट रूप से न्यायिक क्षेत्र में प्रशासकीय हस्तक्षेप कहा जायगा।

10 गणराज्यों पर केन्द्र का कठोर नियन्त्रण (Rigid Control of the Centre on Republics)—सिद्धांत में चाहे कितनी ही स्वायत्तता क्यों न हो परन्तु व्यवहार में सघीय गणराज्यों पर केन्द्र का नियन्त्रण इतना कठोर है कि वे कुछ भी कर सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। आज तक इस कठोर नियन्त्रण के कारण ही अधिकार होते हुए भी किसी गणराज्य ने सघ से पथक होने का स्वप्न तक नहीं देखा। सघीय गणराज्यों पर केन्द्रीय नियन्त्रण इतना कठोर है कि उन्हें सैनिक टुकड़ियों तक को रखने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। रूस में मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं—सघीय सरकार के मंत्री तथा गणराज्यों के मंत्री। केन्द्रीय नियन्त्रण की इसी कठोरता के कारण ही प्रो० ऑग ने रूस की संघात्मकता को अस्वीकृत कर दिया है।

11 आदेश को निष्क्रिय करने की शक्ति (Power to Reject the Order)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रिपरिषद तथा प्रेसीडियम को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह गणराज्यीय सरकार के किसी भी ऐसे आदेश को निष्क्रिय कर सकती है जो कि सघीय कानून अथवा आदेशों से विरुद्ध हो।

12 शक्तियों का असन्तुलित वितरण (Unbalanced Distribution of Powers)—वेद तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इस प्रकार से किया गया है कि संविधान का स्वरूप संघात्मक के स्थान पर एकात्मक हो बन गया है। केन्द्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। फाइनर ने ठीक ही कहा है कि सोवियत संविधान यथाइच्छा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता।¹ स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि मास्को ही सत्ता है।²

13 एकात्मक न्यायपालिका (Unitary System of Judiciary)—सोवियत रूस में हमें न्यायपालिका का एकात्मक स्वरूप ही उपलब्ध होता है। वहाँ

1 The U S S R constitution leaves nothing to chance
2 Moscow is the authority

—Finer
—Finer



अमेरिका की भाँति दो प्रकार के 'यायालय नहीं हैं। सोवियत रूस में प्रोव्यूरेटर जनरल का निर्वाचन सुप्रीम सोवियत के द्वारा होता है। वह अथ 'यायालयों के प्रोव्यूरेटस की भी नियुक्ति करता है। प्रत्येक सीढ़ी पर साम्यवादी दल का ही नियंत्रण है। 'यायापालिका की समस्त व्यवस्था समाकलित (Integrated) है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संघ में किस प्रकार एकात्मक तत्वों का बाहुल्य है। न्यूमैन (Neumann) ने कहा है कि "वास्तव में रूस में सघात्मक तत्व कम है और एकात्मक तत्व अधिक है। आँग के शब्दों में, "सोवियत प्रणाली को किसी भी रूप में सघात्मक नहीं कहा जा सकता।" फाइनर ने भी ऐसे ही विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि 'सोवियत संघ यह दावा करता है कि वह संघ है पर तु वास्तव में वह एक अत्यंत एकात्मक राज्य है जिसकी प्रवृत्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की स्वतंत्र सरकार तथा अयव्यवस्था को समाप्त करने के उपरान्त उनकी राष्ट्रीय विशेषताओं को नष्ट करना है।"

सोवियत संघ की अमेरिकी संघ से तुलना (Soviet Federalism Compared with American Federalism)

रूस तथा अमेरिका दोनों ही सघात्मक राज्य हैं। एक पूँजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व करता है तो दूसरा साम्यवादी शिविर का। विश्व की राजनीति आज रूस तथा अमेरिका का ही अनुसरण करती है। एक का लक्ष्य साम्यवादी प्रसार को रोकना है तो दूसरे का लक्ष्य साम्यवादी प्रसार की अभिवृद्धि करना है। इसी कारण दोनों संघों की तुलना करना अत्यंत रोचक है।

समानताएँ

- (i) दोनों देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।
- (ii) दोनों देशों के संविधान कठोर हैं।
- (iii) दोनों देशों में केन्द्रीय संसद के अखंड सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- (iv) दोनों की सघात्मक व्यवस्थाओं में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं।
- (v) दोनों संघों में इकाइयों के अपने अपने संविधान हैं।

असमानताएँ

(i) सोवियत संघ की समस्त इकाइयों में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। गणराज्य स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त गणराज्य तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता नहीं पाई जाती। परन्तु अमेरिका में संघ की प्रत्येक इकाई को सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ii) सोवियत संविधान में ज्ञान वृद्ध कर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है जबकि अमेरिका में कभी भी केंद्र को शक्तिशाली रखने का उद्देश्य नहीं था, परन्तु अब वह शक्तिशाली बनता जा रहा है।

(iii) सोवियत संघ में संविधान को सर्वोच्च नहीं माना गया है और उसे सवहारा बग की इच्छाओं के समक्ष समर्पण करना ही होता है। वह समस्त राजकीय

शक्तियों का स्रोत नहीं है, परन्तु इसके विपरीत अमेरिकी संविधान को पूर्ण रूप से सर्वोच्च माना गया है।

(iv) अमेरिकी सघात्मक व्यवस्था में सोवियत सघ की भाँति न तो एक दलीय शासन ही है और न दल का साम्यवादी दल का सा नियंत्रण ही। अमेरिकी सघ में सोवियत सघ जैसी के द्वाद् की प्रवृत्ति नहीं है।

(v) सोवियत रूस में सघ की इकाइयों को संवैधानिक रूप में जितनी स्वायत्तता प्राप्त है उतनी अमेरिकी सघ की इकाइयों को प्राप्त नहीं है। वहाँ इकाइयों को सघ से सम्बन्ध विच्छेद करने, सैनिक टुकडियाँ रखने तथा विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार है परन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है।

(vi) व्यवहार में सोवियत सघ का सघ की इकाइयों पर जितना कठोर नियंत्रण है उतना अमेरिका में नहीं है। वहाँ केवल आपत्तिकालीन अवस्था में ही केन्द्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करता है।

(vii) अमेरिका में शक्तियों के पथकरण के कारण 'यायपालिका' को स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। उच्चतम 'यायालय' को संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याता कहा गया है। परन्तु सोवियत रूस में 'यायपालिका' का उद्देश्य साम्यवादी क्रांति को शक्तिशाली बनाना है। वह संविधान की संरक्षिका एवं व्याख्यात्री नहीं है। सोवियत यायपालिका को यायिक पुनर्निरीक्षण (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त नहीं है।

(viii) अमेरिकी सघ में सोवियत सघ जैसी प्रेसीडियम संस्था नहीं है।

(ix) सोवियत संविधान में आधिकारिक नियोजन में समस्त प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है जोकि अमेरिकी सघ में नहीं है।

(x) सोवियत सघ को राजनैतिक दृष्टि से पूर्ण एकात्मक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सघात्मक कहा जाता है परन्तु यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान में नहीं है।

(xi) अखिल भारतीय गणराज्यों का क्षेत्रीय समस्याओं पर जितना व्यापक नियंत्रण है उतना अमेरिकी सघ में भी नहीं है।

(xii) सोवियत सघ व्यवस्था में इकाइयों की वित्तीय सहायता के लिये धनका पडता है। परन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है।

(xiii) अमेरिका में संघीय राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है किन्तु सोवियत संविधान अपने गणराज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं देता।

सोवियत सघवाद तथा स्विस् सघवाद—तुलना

(Soviet Federalism Compared to Swiss Federalism)

समानतायें

(i) दोनों देशों के संविधान लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील हैं।

(ii) दोनों देशों की सघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ सघ की इकाइयों को प्रदान की गई हैं।

(iii) दोनों ही देशों की संसदों के वरिष्ठ सदन में सघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(iv) दोनों ही देशों में सघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य सन्नाधिकार सम्बन्धी सघष हो जाने की स्थिति में केन्द्र की इच्छा को ही उच्चतर माना गया है।

(v) दोनों ही देशों में सघीय इकाइयों के अपने अपने सविधान हैं और उन पर यह प्रतिबन्ध भी है कि उन्हें केन्द्रीय कानून का उत्सर्जन करने का अधिकार नहीं होगा।

(vi) दोनों ही देशों में 'यायिक पुनर्निरीक्षण' की व्यवस्था नहीं है।

असमानताएँ

(1) स्विस् सघ की पूरा कैंटन तथा अर्द्ध कैंटन जैसी व्यवस्था सोवियत सघ में नहीं है।

(ii) स्विस् सघ व्यवस्था में राजनसिक दलों का कोई महत्व नहीं है जबकि सोवियत सघ में साम्यवादी दल का प्रभुत्व है।

(iii) स्विस् सविधान में स्विटजरलैंड को परिसघ (Confederation) कहा गया है परन्तु सोवियत सविधान में उसे सोवियतों का एक सघ कहा गया है।

(iv) कैंटनों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कोई महत्व नहीं है किन्तु सोवियत सघ में उसके दो गणराज्य समुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य हैं।

(v) कैंटनों को सघ से पथक होने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु सोवियत सघ की इकाइयों को सैद्धांतिक दृष्टि से यह अधिकार प्राप्त है।

(vi) सोवियत सविधान में सशोधन की व्यवस्था स्विस् सविधान से बिलकुल भिन्न है। स्विटजरलैंड में अततोपत्ता जनता की सम्प्रभुता को प्राथमिकता दी गई है।

(vii) सोवियत सघ की सरकार जितनी शक्तिशाली है उतनी शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार स्विटजरलैंड में भी नहीं है।

(viii) स्विस् सघ में रूसी आदल की प्रेसीडियम जैसी सस्था नहीं है।

(ix) स्विटजरलैंड में कानूनी केन्द्रीकरण तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण है। इसके विपरीत सोवियत सविधान में शक्तियों के लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था है।

(x) स्विटजरलैंड को सघ की कसौटी पर कसकर सघ कहा जा सकता है परन्तु सोवियत सघ को अधिक से अधिक हम अर्द्ध सघ की सजा दे सकते हैं।

अतः हम देखते हैं कि स्विस् सघ में भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पनपती जा रही है। यदि केन्द्र किसी नियम अथवा अधिकार क्षेत्र का उत्सर्जन करता है तो कैंटनों के पास उसका कोई उपाय नहीं है। वहाँ पर भी सोवियत सघ की भाँति सघ की इकाइयों को केन्द्रीय अथ सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। वहाँ पर भी सोवियत सघ के सदृश इकाइयों के सविधानों तथा शासन पर कठोर नियन्त्रण रखा जाता है। सोवियत रूस में भी आज तक किसी इकाई ने सघ से अपनी सदस्यता वापस लेने की बात तक नहीं की।

Select References

Finer *Major Governments*

Towster *Political Power in U S S R*

Hertze & Carter *The Govt of the Soviet Union*

Ogg & Zink *Modern Foreign Govts*

Munro *Govts of Europe*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1 क्या सोवियत संघ को एक संघ कहना उचित होगा ?

(Would it be correct to describe U S S R as a Federation)

2 सोवियत संघ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

3 (द्विचर) के इस कथन की व्याख्या कीजिए कि "1936 का संविधान बड़ा संघीय है ।"

("The constitution of 1936 is at least Quasi Federal"—Wheare Comment)

3

संघीय सरकार

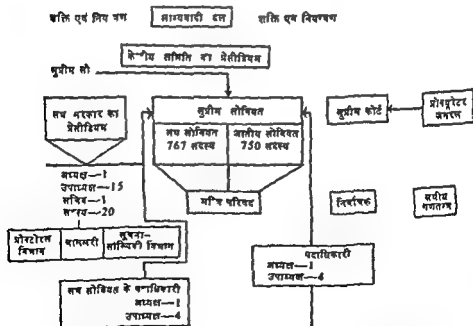
[Federal Government]

सर्वोच्च सोवियत, प्रेसोडियम, मन्त्रिपरिषद् तथा न्याय-व्यवस्था
(Supreme Soviet, Presidium, Council of Ministers, Judiciary)

"The Russian people will tolerate much and forgive their dictators even more, if the promise of abundance becomes performance" —Fier

"It (Supreme Soviet) has rather the status the Czar gave to the Russian Duma 1906 It is a strange commentary on popular Sovereignty" —Fier

सोवियत शासन व्यवस्था का रेखाचित्र



आयोग	सदस्य संख्या	आयोग	सदस्य संख्या
1 नियोजन एवं बजट समिति	51	1 नियोजन एवं बजट समिति	51
2 उद्योग, मातायास समिति	31	2 उद्योग एवं मातायास	31

3 कृषि समिति	41	3 भवन निर्माण समिति	31
4 सावजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति	31	4 कृषि समिति	41
5 सावजनिक शिक्षा समिति	31	5 जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा समिति	31
6 व्यापार तथा सावजनिक सुविधा समिति	31	6 सावजनिक समिति	31
7 विधि प्रस्ताव समिति	31	7 व्यापार तथा सावजनिक सुविधा समिति	31
8 विदेश समिति	31	8 वैधानिक प्रस्ताव समिति	31
9 प्रत्यय पत्र आयोग	31	9 विदेश समिति	31
10 भवन एवं पथ निर्माण समिति	31	10 प्रत्यय पत्र समिति	31

सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet)

सरचना (Composition)

सर्वोच्च सोवियत को संघ की सर्वोच्च सत्ता कहा गया है। स्टालिन संविधान में शक्तियों के पथक्कीकरण को अस्वीकृत करके शासन का स्वरूप संसदीय प्रणाली का रखने का प्रयत्न किया गया है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 30 से लेकर 47 तक सर्वोच्च सोवियत की संरचना एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पहले संविधानों में व्यवस्थापिका शक्ति किसी एक अंग में ही निहित नहीं थी। सर्वोच्च सोवियत के दो सदन हैं—संघ की सोवियत (Soviet of the Union) तथा राष्ट्रीयताओं की सोवियत (Soviet of the Nationalities)। इस प्रकार सोवियत रूस में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। सोवियत संविधानवादियों ने द्वितीय सदन की स्थापना एक प्रतिष्ठादी सदन के रूप में नहीं की। सर्वोच्च सोवियत का निम्न सदन जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय सदन की स्थापना केवल राष्ट्रीय जातियों को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से की गयी है। संघ की सोवियत में 767 तथा जातियों की सोवियत में 750 सदस्य हैं। दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताधिकार, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की पद्धति के माध्यम से होता है। 23 वर्ष की अवस्था का कोई भी नागरिक सर्वोच्च सोवियत का सदस्य बन सकता है। संघ की सोवियत के लिए प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीयताओं की सोवियत के लिए जनसंख्या का विचार नहीं किया जाता। विविध राष्ट्रीय हितों एवं समुदायों को इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जातियों की सोवियत में प्रतिनिधित्व का क्रम इस प्रकार है

प्रत्येक गणराज्य से 25 सदस्य, प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य से 11 सदस्य, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र से 5 सदस्य तथा राष्ट्रीय क्षेत्र से 1 सदस्य।

निर्वाचन में एक उम्मीदवार केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो सकता है। प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है। निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का मनोनयन श्रमिक संघों के द्वारा होता है। व्यवहार में योग्य उम्मीदवार

ही निर्वाचन में पड़े किये जाते हैं। निर्वाचन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्वाचन समितियाँ स्थापित की जाती हैं। सम्पूर्ण देश में निर्वाचन के लिए भी एक निर्वाचन समिति होती है। इस प्रकार की समितियाँ सभ की इकाइयों में उनके स्तर पर भी स्थापित की जाती हैं। उम्मीदवारों को चुनाव के लिए साउडस्पीकर, यातायात आदि की सुविधाएँ राज्य के द्वारा प्रदान की जाती हैं। निर्वाचन पर होने वाले व्यय को राज्य वहन करता है। साम्यवादी तथा असाम्यवादी दोनों ही सम्मिलित होकर चुनाव अभियान चलाते हैं। सर्वोच्च सोवियत के लिए निर्वाचन सम्पूर्ण देश में प्रायः रविवार को एक साथ ही होते हैं, वे प्रातः 6 बजे से प्रारम्भ होकर रात्रि को 10 बजे तक समाप्त हो जाते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है परन्तु साथ ही यह प्रतिबन्ध भी होता है कि जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित घोषित किया गया है वहाँ के कम से कम पचास प्रतिशत मतदाताओं ने निर्वाचन में भाग लिया हो। यदि किसी क्षेत्र में 50 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है और पुनः निर्वाचन होता है, परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम ही आते हैं क्योंकि सर्वोच्च सोवियत के लिए जनता में अगाध हृष एव उत्साह होता है। मतदान भारी सख्या में होता है।

अवधि (Tenure)

सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल 4 वर्ष है। परन्तु सोवियत संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत केवल ऐसी दशा में समयावधि से पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है जब कि किसी विषय पर उसके दोनों सदनों में मतभेद न हो सके। मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों से बराबर सदस्य लिए जाते हैं जिसके द्वारा संराधन समिति (Conciliation Committee) का गठन किया जाता है, यदि फिर भी मतभेद दूर नहीं हो पाते हैं तो सर्वोच्च सोवियत को प्रेसीडियम द्वारा भंग कर दिया जाता है और भंग करने की तिथि से 2 माह के अंदर नए निर्वाचन करवाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ द्वितीय सदन भी स्थायी नहीं है, जबकि वह अधिकांश देशों में स्थायी सदन है।

उन्मुक्तियाँ (Immunities)

(i) मंत्रियों से सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर उन्हें तीन दिन में मिलना आवश्यक है।

(ii) सदस्यों को प्रत्यालोचन में भाग लेने का अधिकार होता है।

(iii) अधिवेशन के समय सदन की कार्यकारी निकाय की अनुमति के बिना सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

(iv) कार्यकारी निकाय की अनुमति प्राप्त करके सदस्य प्रशासकीय विभागों का भी निरीक्षण कर सकते हैं।

(v) प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के सदस्यों की शिकायतों को उपयुक्त समूहों तक पहुँचाते हैं जिससे कि उन पर भीष्ट हो निर्णय हो सके।

(vi) प्रतिनिधियों को यातायात की सम्पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए भी पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। अधिवेशन (Session)

सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन अल्पकालीन होते हैं। अधिवेशन की अवधि 3 से 10 दिन तक की होती है। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ होता है। सामान्यतः वर्ष में दो अधिवेशन होते हैं। कभी-कभी वर्ष में बेचस एक ही अधिवेशन भी होता है। किसी गणराज्य की माँग पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च सोवियत के सत्रकालीन अधिवेशन भी प्रेसीडियम द्वारा आमन्त्रित किये जा सकते हैं। कभी-कभी आवश्यकता के समय अथवा कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए भी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित किया जाता है।

पदाधिकारी (Officials)

प्रत्येक सदन में एक अध्यक्ष तथा चार उपाध्यक्ष होते हैं जिनका निर्वाचन सदन के सदस्यों के द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अध्यक्ष का काम सदन की कार्यवाही का संचालन करना है। संविधान में तीन स्थायी आयोगों की भी चर्चा की गई है जिनका कार्य विधायी प्रक्रिया में सदन का सहयोग करना है। ये आयोग इस प्रकार हैं—विधेयक आयोग (Legislative Commission), बजट आयोग (Budget Commission) तथा परराष्ट्र समिति (Committee on Foreign Affairs)। इससे अतिरिक्त समय-समय पर विशेष आयोगों की स्थापना सदन द्वारा की जाती है। सदन एक प्रत्यय प्रमाणपत्र समिति (Credential Committee) को भी निर्वाचित करता है जो कि निर्वाचनों की वैधता का परीक्षण करती है। विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सामान्य महत्व प्राप्त होने पर ही वे स्वीकृत समझे जाते हैं। प्रस्तुति के पश्चात् विधेयकों को किसी आयोग के पास भेजा जाता है। दोनों सदनों को समानाधिकार प्राप्त हैं। घन विधेयकों की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी ही है। अन्तर-पेचल इतना ही है कि उसके कार्यों एवं आम ध्येय का निरीक्षण आयोग द्वारा किया जाता है।

वापस अथवा प्रत्याह्वान की पद्धति (System of Recall)

सोवियत रूस में सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदस्य को 1000 रूबल प्रतिमास वेतन मिलता है तथा इससे अतिरिक्त अधिवेशनों के दिनों में 150 रूबल प्रतिदिन प्राप्त होता है। किन्तु साथ में सदस्यों को वापस बुलाने की भी व्यवस्था है। यदि वे कार्यकुशल नहीं हैं, दुश्चरित्र हैं तथा अपने क्षेत्र के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में असफल रहते हैं अथवा अपने क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं और उदासीन हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनका निर्वाचन क्षेत्र के पचास प्रतिशत मतदाता उसे प्रस्ताव द्वारा वापस बुला सकते हैं। सर्वोच्च सोवियत की कार्यकारी समिति निर्वाचन की व्यवस्था करती है और प्रायः हाथ उठवाकर मतदाताओं के मत ज्ञात कर लेती है। सम्बन्धित सदस्य को अपने पक्ष में प्रचार करने की पूरी छूट होती है, किन्तु यह प्रणाली विधायकों एवं प्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से सावधान की स्थिति में रखती है। सर्वोच्च सोवियत की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ (Special Features)

सर्वोच्च सोवियत की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं जोकि अधिकांश पश्चिमी लोकतंत्रों में नहीं पाई जाती। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

1 सरकारी कमचारियों को निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है। यह अधिकार विश्व के बहुत ही कम देशों में है। सन् 1937 में 239 कमचारी तथा 65 सैनिक अधिकारी भी सर्वोच्च सोवियत के सदस्य थे।

2 सर्वोच्च सोवियत में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की प्रतिनिधित्व मिलता है। उत्तरोत्तर बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मजदूर एवं किसानों आदि सभी इसके सदस्य हैं।

3 विश्व के अन्य संसद सदस्यों की अपेक्षा यहाँ के संसद सदस्यों की आयु कम होती है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष रहती है।

4 विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा रूस के निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक रहती है। उदाहरणार्थ सन् 1954 के आम चुनावों में 99.8 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था।

5 अमेरिका तथा इंग्लैण्ड जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में सोवियत रूस की संसद में महिला सदस्यों की संख्या भी अधिक है। सन् 1950 में सर्वोच्च सोवियत में 20 प्रतिशत महिला सदस्य आएँ थीं।

6 निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने की स्वतंत्रता तो अवश्य है, किन्तु यह देखा जाता है कि सर्वोच्च सोवियत में 80 प्रतिशत सदस्य साम्यवादी दल के ही सदस्य हैं और वे साम्यवादी दल की नीतियों में ही आस्था रखते हैं। शेष 20 प्रतिशत सदस्य भी साम्यवादी दल के सदस्य तो नहीं हैं, परन्तु वे साम्यवादी व्यवस्था एवं नीतियों में ही विश्वास करते हैं।

सर्वोच्च सोवियत की शक्तियाँ (Powers of the Supreme Soviet)

1 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)—सोवियत संविधान के 14वें अनुच्छेद में जिन विषयों का वर्णन किया गया है उन पर सर्वोच्च सोवियत को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सोवियत संविधान में वीटो का अधिकार किसी भी अंग को नहीं दिया गया है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा निमित्त विधि को सर्वोच्च माना गया है। उस अवधि घोषित करने का अधिकार वहाँ के उच्चतम न्यायालय को भी नहीं है। परन्तु प्रेसिडियम अपने उपक्रम अथवा किसी गणराज्य की माँग पर किसी भी विधि पर लोक निर्णय (Referendum) करा सकती है परन्तु आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वीटो की आवश्यकता आज तक आवश्यक नहीं समझी गई है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर साम्यवादी दल प्रभावी रहा है।

2 संविधान में संशोधन का अधिकार (Right to Amend the Constitution)—सोवियत संविधान में संशोधन का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च सोवियत को है, संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल है कि कभी-कभी उसे अनन्य संविधान कहते में भी संदेह होने लगता है। संशोधन प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। भारत तथा अमेरिका की भाँति सच की इकाइयों के समर्थन का प्रावधान नहीं है। अतः रूस में सच की इकाइयों को संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत को गणराज्यों के संविधानों का भी

निरीक्षण करना पड़ता है कि कहीं उनमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर लिया जाय जोकि केन्द्रीय सरकार के प्रतिकूल हो।

3 इकाइयों का प्रवेश तथा सीमा निर्धारण (Admission and Change in the Units)—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सर्वोच्च सोवियत को नए राज्यों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने का भी अधिकार है। संघ की इकाइयों में परिवर्तन करने का अधिकार एकमात्र सर्वोच्च सोवियत को ही है। गणराज्यों के समान ही अन्य स्वायत्त प्रदेशों तथा क्षेत्रों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए भी सर्वोच्च सोवियत की अनुमति आवश्यक होती है।

4 आर्थिक कार्य (Economic Functions)—इस शीघ्र के अंतर्गत सर्वोच्च सोवियत सम्पूर्ण देश के आय व्यय का बजट तैयार करती है तथा संघ की इकाइयों के बजट पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण एवं उनका निष्पादन सर्वोच्च सोवियत के द्वारा सम्पन्न होता है। ऋण लेने तथा ऋण स्वीकृत करने का कार्य भी सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही सम्पन्न होता है। अधिकोपण, बीमा, कृषि एवं जन स्वास्थ्य आदि से सम्बंधित नियमों का निर्धारण भी इसी के द्वारा सम्पन्न होता है।

5 वदेशिक सम्बंध एवं सुरक्षा (Foreign Relations and Security)—अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में सर्वोच्च सोवियत ही सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करती है, अन्य वदेशिक राष्ट्रों के साथ संधि करना तथा संधियों की संपुष्टि करना, विदेशी राज्यों के साथ सम्बंधों के विषय में सामान्य नीति का निश्चय करना, संघीय नागरिकता के विषय में कानून बनाना तथा रूस में जो विदेशी निवास करते हैं उनके सम्बंध में कानूनों का निर्माण करना भी सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही होता है। संघ की सुरक्षा के विषय में कानूनों का निर्माण तथा युद्ध एवं शांति की समस्याओं का समाधान भी सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही होता है। अनुच्छेद 14 (7) के अंतर्गत यह रूस की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति को एकत्रित करती है तथा गणराज्यों की सैनिक शक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है।

■ निर्वाचन सम्बंधी अधिकार (Electoral Rights)—प्रेसीडियम, सोवियत मंत्रिपरिषद, प्रेसब्यूरेटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायालयों के सदस्य आदि सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं।

7 कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over Executive)—सोवियत रूस में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और सिद्धांततः कार्यपालिका की विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और राष्ट्रीय नीतियों का स्पष्टीकरण भी करा सकते हैं, परंतु यह नियंत्रण केवल एक दिखावा मात्र ही है, क्योंकि राजकीय सत्ता पर इन्हें गिने दो चार व्यक्तियों का ही नियंत्रण रहता है।

8 शासन का निर्देशन (Direction of Administration)—सोवियत संविधान में शक्ति प्रयत्नकरण के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया है सर्वोच्च सोवियत की शक्ति को न्यायपालिका एवं विधान मण्डल के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मंत्रिपरिषद प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है और वह सर्वोच्च सोवियत के अधीन है। सर्वोच्च सोवियत के चुनावकाय में जो अध्यादेश प्रेसीडियम के द्वारा

प्रसारित किये जाते हैं उनकी सम्पुष्टि इसी के द्वारा होती है। शासकीय नीतियों का निर्धारण सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है।

७ **अन्वेषण का अधिकार (Right of Investigation)**—सोवियत सविधान में सर्वोच्च सोवियत को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी भी विषय के सम्बन्ध में अन्वेषण आयोग की नियुक्ति कर सकता है। आय व्यय के लेखा परीक्षण के लिये भी आयोग की नियुक्ति कर सकती है। सरकार के समस्त विभाग इस आयोग को आवश्यक सूचनाएँ देने के लिए बाध्य हैं।

दोनों सदनों का सम्बन्ध (Relation of Both Houses)

सोवियत सदनों में बहुत सी पश्चिमी लोकतन्त्रीय व्यवस्थाओं के सदृश निम्नता तथा उच्चता की भावना नहीं है। दोनों सदन उद्देश्य, संगठन तथा शक्तियों की दृष्टि से समकक्ष हैं। विशिन्स्की (Vishinsky) के शब्दों में “सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों की वर्गीय प्रकृति तथा सार एक है। दोनों का निर्वाचन सोवियत सच के मजदूरों के द्वारा होता है। दोनों का उद्देश्य एक है—समाजवाद की दृढ़ता। सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के अधिकार समान हैं, यह समानता वास्तविक है। सोवियत पद्धति में उच्च तथा निम्न सदन नहीं हैं।” दोनों सदनों की समकक्षता निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध हो सकती है—

- 1 दोनों का उद्देश्य समाजवाद की दृढ़ता है।
- 2 दोनों मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 3, दोनों की सदस्य सख्या भी लगभग बराबर ही है।
- 4 दोनों सदनों का कार्यकाल 4 वर्ष का है।
- 5 दोनों सदनों के अधिवेशनों का आरम्भ तथा समाप्ति एक साथ होती है।
- 6 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोनों सदनों के अध्यक्ष बारी-बारी से करते हैं।

7 दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त समिति में दोनों सदनों में बराबर बराबर सदस्य लिये जाते हैं।

8 कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है और प्रत्येक विधेयक पर दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है।

सर्वोच्च सोवियत का मूल्यांकन—क्या सर्वोच्च सोवियत राजकीय सत्ता का सर्वोत्तम अंग है ?

(Evaluation of Supreme Soviet—Is Supreme Soviet the Highest Organ of State Power ?)

जिस प्रकार की शक्तियाँ सर्वोच्च सोवियत को सोवियत सविधान में प्रदान की गई हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह जन प्रतिनिधि के रूप में सबसे अधिक सम्पन्न अंग हो। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सर्वोच्च सोवियत को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं हो। प्रेसीडियम मंत्रिपरिषद् तथा न्यायपालिका के परिष्ठ अधिकारियों का निर्वाचन इसी के द्वारा होता है। सर्वोच्च सोवियत को जन-भाषना का प्रतीक एवं मंच कहा गया है। सर्वोच्च सोवियत को सविधान में समोपन करने तथा अन्य गणराज्यों के सविधानों पर नियन्त्रण करने का भी अधिकार

प्राप्त है। कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति इसके पास है। गृह एवं विदेश नीतियों का निर्धारण तथा सैन्य शक्ति का संगठन करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। संघियों की सम्पुष्टि तथा प्रेसीडियम द्वारा प्रसारित आज्ञप्तियों (Decrees) का यह अनुमोदन करता है।

सर्वोच्च सोवियत की वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। वास्तव में सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद द्वारा प्रसारित आज्ञप्तियों एवं निणयों का अनुमोदन करने वाली संस्था मात्र है। उसमें उपक्रम का अभाव एवं अनुमोदन का बाहुल्य है। साम्यवादी दल का नियंत्रण इतना कठोर है कि सर्वोच्च सोवियत उसके हाथों में बंधुपुतली सदृश जान पड़ती है। सम्भवतः इतना अशक्तशाली प्रथम सदन विश्व में अन्य कोई नहीं है। कोई ऐसा शक्तिशाली औचित्य नहीं है जिस पर उसके अस्तित्व को दायसंगत ठहराया जा सके। सर्वोच्च सोवियत के अस्तित्व में उपयोगिता कम तथा प्रदर्शन अधिक है। उसकी वास्तविक स्थिति को देखने के पश्चात् यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बिना इसके भी काम चल सकता है। आज तक कभी भी सर्वोच्च सोवियत ने मंत्रिमण्डल तथा प्रेसीडियम के निणयों को अस्वीकार नहीं किया है। सर्वोच्च सोवियत का प्रयोग केवल एक प्रचार संस्था के रूप में ही किया गया है। उसके सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में केवल उन्हीं बातों का प्रचार करते हैं जोकि उनके साम्यवादी स्वामियों द्वारा उनको बताई गई हैं। उसके सदस्य जनता को साम्यवादी निणयों एवं नीतियों के सम्बन्ध में अवगत कराते हैं। इसी कारण जूलियन टाउस्टर (Julian Towster) ने कहा है कि "इस समय तक तो सर्वोच्च सोवियत का एकमात्र कार्य यही रहा है कि वह पूर्वनिर्धारित नियमों का अनुसमयन करती रहे अथवा प्रचार का साधन मात्र बनी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि यह समय समय पर अवसर के अनुकूल शासन की नीति पर प्रतिनिधि निकाय के रूप में अनुमोदन और समयन प्राप्त करती रहे।" सर्वोच्च सोवियत की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए फाइनर ने बड़ा ही तीक्ष्ण कटाक्ष किया है "रूस की सर्वोच्च सोवियत को वही स्थान प्रदान किया गया है जोकि इंग्लैण्ड के राजाओं ने चार्ल्स प्रथम का विरोध करने वाली और चार्ल्स का सिर काटने वाली पार्लियामेंट के पूर्व पार्लियामेंट की दे दिया था। यह उसी नपुंसक स्थिति में है जो स्थिति फ्रांस के राजाओं द्वारा स्टेट जनरल (संसद) की की गई थी। इसकी भी लगभग वही स्थिति है जो जार ने सन् 1906 में ड्यूमा को प्रदान की थी। यह जनता की प्रभुसत्ता पर विचित्र टीका है।" वस्तुतः सर्वोच्च सोवियत राज्य शक्ति का सर्वोत्तम निकाय नहीं है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

1 सर्वोच्च सोवियत के अधिकांश सदस्य भयङ्कर वर्ग के होते हैं जो कानून के विशेषज्ञ नहीं होते। वे विधेयकों के बहुत ही कम उपयोगी सुझाव दे पाते हैं। सदस्यों के हाथों में ऐसी कोई शक्ति भी नहीं रह पाती जिसे हम प्रभावशाली कह सकें। सदस्यों की विचारधारा एवं आचरण ठीक वसा ही होता है जैसाकि उनके साम्यवादी नेता चाहते हैं। उनमें कोई नूतन दृष्टिकोण एवं उपक्रम नहीं होता।

2 सर्वोच्च सोवियत को बहुत से पदाधिकारियों को निर्वाचित करने का अधिकार है किन्तु यह अधिकार नाममात्र का ही है। पदाधिकारियों का निर्वाचन

साम्यवादी दल की पूव निश्चित योजना के अनुसार ही होता है। सर्वोच्च सोवियत तो केवल अनुमोदन मात्र ही करता है उसके द्वारा विरोध होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरणार्थ—दिनांक 19 मार्च 1946 को सर्वोच्च सोवियत की केवल सवा घण्टे की बैठक में लगभग 182 पदाधिकारियों को निर्वाचित किया गया।

3 सर्वोच्च सोवियत की बैठकें मुश्किल से ही वष में दो बार होती हैं, इसके अधिवेशन भी अति अल्पकालीन ही होते हैं। सम्भवत अब तक सबसे बड़ा अधिवेशन 12 दिन का हुआ है। इससे विपरीत पश्चिमी विधान मण्डलों के अधिवेशन वष में लगभग 200 दिन के होते हैं।

4 सर्वोच्च सोवियत नाममात्र को ही नीतियों का निर्धारण तथा प्रशासन का निर्देशन करती है। वास्तव में इस काय का सम्पादन साम्यवादी दल के कणधरों द्वारा ही होता है।

5 सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुमोदन का काय महत्वहीन है। प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद द्वारा जो आज्ञाप्तियाँ प्रसारित की जाती हैं, सर्वोच्च सोवियत द्वारा उनका अनुमोदन केवल नाममात्र का ही है। क्योंकि कभी भी इनका विरोध नहीं होता, यहाँ तक कि उसका कोई वैकल्पिक सुझाव भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

6 सर्वोच्च सोवियत की विधायी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा ही होता है।

7 राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यावहारिक रूप में साम्यवादी दल के द्वारा ही होता है।

8 संविधान में समोधन करने की शक्ति भी निरर्थक ही है क्योंकि समोधन पहले ही साम्यवादी दल के प्रेसीडियम द्वारा तय कर लिये जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च सोवियत राजकीय सत्ता का सर्वोत्तम अंग नहीं है अपितु उसकी स्थिति केवल रबर स्टाम्प मात्र ही है। 'न्यूमैन (Neumann)' ने ठीक ही कहा है कि 'वह सत्ता जोकि नीति निर्धारित नहीं करती और वास्तविक रूप में जिसका नीति निर्माण में कोई भाग नहीं होता। उसके सम्बन्ध में वास्तविक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सत्ताधारी है।' परन्तु इस कथन में (जैसा कि आँग तथा जिक ने कहा) हमें यह अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए कि यह सोवियत संघ के सावजनिक मामलों पर बिल्कुल ही—कम से कम उचित मात्रा में—प्रभाव नहीं डालती।¹ सर्वोच्च सोवियत में कभी भी वाद विवाद नहीं देखे गए हैं। विरोध एवं आलोचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ लोकतन्त्रीय ससदीय देशों की भाँति विरोधी दल नहीं होता। सर्वोच्च सोवियत एक आम सभा सी जान पड़ती है। निर्वाचन भी नाममात्र को ही होते हैं। यहाँ पर प्रतिद्वन्द्वी दृष्टिगोचर ही नहीं होते। साम्यवादी दल के उम्मीदवार के समथन अथवा अस्वीकृति के पक्ष में मत दाताओं को अपना मत व्यक्त करना पड़ता है।

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम (Presidium of the Supreme Soviet)

प्रेसीडियम का सोवियत रूस की मौलिक उत्पत्ति माना जा सकता है। यह

¹ But it should not be assumed that it does not exercise atleast a reasonable amount of influence in the public affairs of the Soviet Union

एक अनोखी सस्था है। पश्चिमी राष्ट्रों में इसका कोई अथ उदाहरण कठिनाता से ही देखने को मिलता है। डॉ० फाइनर ने इसे प्रेसीडियम कानून तथा यथाय रूप में शाश्वत सरकार ही कहा है।¹ विनिस्की ने प्रेसीडियम को सामूहिक राष्ट्रपति कहा है।² प्रेसीडियम एक ओर तो राष्ट्राध्यक्ष के पद की पूर्ति करती है तो दूसरी ओर सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के मध्यांतर में विधान मण्डल के कार्यों का सम्पादन करती है। माक्स स्टालिन 'एकल राष्ट्रपति' के पक्ष में नहीं थे। एकल राष्ट्रपति तानाशाह बनकर सर्वोच्च सोवियत की शक्ति को फीकी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने राष्ट्रपति का स्वरूप मण्डलात्मक रखा है। प्रेसीडियम के कार्यों का स्वरूप भी अथ राष्ट्रों के राष्ट्रपति के कार्यों के समान ही है। इसका स्वरूप कुछ कुछ श्वेत संघीय परिषद से मिलता जुलता है, क्योंकि वह भी राष्ट्रपति का सामूहिक रूप है। परंतु इसकी अनुरूपता उससे भी पूर्ण नहीं है क्योंकि संघीय परिषद मध्यांतर में विधान मण्डल के कार्यों का सम्पादन इसके सदस्य नहीं करती। प्रेसीडियम कुछ ब्रिटिश क्राउन का भी स्वरूप लिये हुए है, परंतु वह भी पूर्ण नहीं है। वास्तव में प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का स्थानापन्न (Substitute) है अथवा सर्वोच्च सोवियत का शाश्वत सक्षिप्त रूप है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह सर्वोच्च सोवियत का व्यावहारिक अंग है। हम इसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं कह सकते परंतु राष्ट्र के अलंकारपूर्ण कार्यों का सम्पादन इसी के द्वारा होता है।

संगठन तथा कार्यकाल (Composition & Tenure)

डॉ० फाइनर के विचारानुसार संस्था की दृष्टि में प्रेसीडियम स्वयं ही सर्वोच्च सोवियत का सक्षिप्त रूप है तथा वास्तविक प्रदत्त शक्तियों में उसका महत्व अंतरंग रूप से अधिक शक्तिशाली है।³ ब्रिटिश राजा की भांति प्रेसीडियम अनुष्ठानिक अवसरों की अध्यक्षता करती है। संविधान में संशोधित अनुच्छेद 48 के अनुसार इसकी सदस्य संख्या 37 है। इनमें से एक अध्यक्ष, पांद्रह उपाध्यक्ष, बीस सचिव तथा अथ सदस्य होते हैं। प्रत्येक संघीय गणराज्य में से एक उपाध्यक्ष होता है। पहले इसकी कुल सदस्य संख्या 32 हुआ करती थी। प्रेसीडियम के सदस्य सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल से कुछ माह अधिक भी अपने पद पर रह सकती है। जबकि सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल 4 वर्ष है तो स्वाभाविक रूप में प्रेसीडियम का कार्यकाल भी 4 वर्ष ही हुआ। सर्वोच्च सोवियत के विघटन के साथ ही प्रेसीडियम का कार्यकाल भी कम हो जाता है। यदि सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल में वृद्धि होती है तो प्रेसीडियम के कार्यकाल में भी स्वाभाविक रूप से ही वृद्धि हो जाती है। प्रथम प्रेसीडियम 1936 से लेकर 1946 तक रहा। इस संदर्भ में यह बात भी जानने योग्य है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के अध्यक्ष प्रेसीडियम के सदस्य नहीं बन सकते।

- 1 The Continuous Government of the Soviet Union in fact as well as in Law
Dr. Finer
- 2 The Presidium of the Supreme Soviet is a Collegial President —Vyshinsky
- 3 Presidium is the miniature of self of the Supreme Soviet in number and greater and inner self in actual delegated powers —Dr

अध्यक्ष (Chairman)—प्रेसीडियम के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष वे ही व्यक्ति निर्वाचित किये जाते हैं जोकि अपने अपने गणतंत्र की प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं। प्रेसीडियम का एक अध्यक्ष होता है जोकि व्यवहार में प्रेसीडियम की ओर से राष्ट्रपति के कार्यों का सम्पादन करता है। सोवियत संघ में एक राष्ट्रपति का स्थान पर सामूहिक राष्ट्रपति है। अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के द्वारा होता है। श्री पोटोमोर्नी सन् 1969 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष के पास अथवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ नहीं होती। उसका स्थान अथवा सदस्यों की अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं है। अध्यक्ष ही प्रेसीडियम की ओर से सर्वोच्च सोवियत द्वारा निमित्त विधेयकों पर तथा प्रेसीडियम एवं मंत्रिपरिषद की आज्ञातियों पर हस्ताक्षर करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, तथा विदेशी राजदूत अपने प्रत्यय पत्र अध्यक्ष को ही समर्पित करते हैं। परन्तु फिर भी गौरव तथा सम्मान की दृष्टि से उसकी तुलना अथवा राष्ट्रों के अध्यक्षों के समकक्ष नहीं की जाती है। उसकी स्थिति स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष के बहुत कुछ समान ही है जिसका राजनैतिक एवं वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। वैसे विदेशों में प्रेसीडियम के अध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सवत्र सम्मान एवं स्वागत होता है। जी एम कार्टर (Carter) ने प्रेसीडियम के अध्यक्ष की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि अथवा देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समान उसका सबसे प्रमुख कार्य सामान्य नागरिकों के प्रति उनकी भलाई के लिए सरकार ने पित्रतुल्य सम्बन्ध के जीवित मानवीय प्रतीक के रूप में मिलता है।" रूस में अध्यक्ष तथा इंग्लैण्ड के राजा में अंतर यह है कि रूसी प्रेसीडियम का अध्यक्ष साम्यवादी दल का प्रभावशाली सदस्य होता है। अध्यक्ष का कार्य वस्तुतः सांस्कृतिक स्वरूप जैसा ही है।

प्रेसीडियम की शक्तियाँ (Powers of the Presidium)

सोवियत संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रेसीडियम की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके कार्य मिश्रित प्रकार के हैं। प्रेसीडियम को वैधानिक, कार्यपालिका तथा "यायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ से सम्पन्न किया गया है। सुविधा की दृष्टि से प्रेसीडियम की शक्तियों का विवरण निम्नलिखित शीपकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

विधायी शक्तियाँ (Legislative Functions)

(i) प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन आमन्त्रित करता है।

(ii) सर्वोच्च सोवियत को भंग करके सर्वोच्च सोवियत के नवीन निर्वाचनों का आदेश देता है। किन्तु ऐसी स्थिति तभी आती है जबकि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने पर उसका निराकरण नहीं हो सके।

(iii) प्रेसीडियम को सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के मध्याह्नरो में अध्यादेश अथवा आज्ञातियाँ प्रसारित करने का अधिकार है जिनका वही मूल्य होता है जोकि संसद द्वारा बनाये गए कानून का। सर्वोच्च सोवियत द्वारा उनका समर्थन केवल एक औपचारिकता है।

(iv) संघ में प्रवेश हेतु प्रत्यासी गणराज्यों को, स्वीकृति प्रदान करती है।

(v) इनाइयों की सीमाओं में उनकी इच्छा से परिवर्तन करती है।

(vi) प्रेसीडियम को संविधान में सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत विधेयका पर निवेधाधिकार का अधिकार तो प्राप्त नहीं है परंतु किसी गणराज्य की मांग पर अथवा अपने उपक्रम पर वह उस पर लोक नियंत्रण कर सकती है।

(vii) यदि सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों की अनुपस्थिति में किसी विधायक (Deputy) को बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए प्रेसीडियम की स्वीकृति अनिवार्य है।

(viii) यह सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में समन्वय उत्पन्न करती है। अनिवार्य प्रलेखों को तैयार करती है तथा सर्वोच्च सोवियत के लिए आवश्यक सूचनाएँ तथा सामग्री प्रस्तुत करती है।

(ix) महत्वपूर्ण विधेयकों को उपयुक्त स्थायी समितियों के पास भेजती है। प्रेसीडियम की कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

(i) संविधान की धारा 49 (7) के अंतर्गत सोवियत मंत्रिपरिषद् सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों की अनुपस्थिति में प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है। सोवियत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसीडियम ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है।

(ii) विदेशी आक्रमण की स्थिति में अथवा किसी अन्य राष्ट्र के साथ की गई रक्षा-संधि के अंतर्गत यदि युद्ध घोषित करना आवश्यक हो तो प्रेसीडियम ही युद्ध की घोषणा करती है, जिसका समर्थन सर्वोच्च सोवियत करती है।

(iii) प्रेसीडियम अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए भी आदेश दे सकती है।

(iv) यदि मंत्रिपरिषद् अथवा गणराज्यों के मंत्रिपरिषदों के नियम संघीय कानून के अनुरूप नहीं हैं तो प्रेसीडियम उन्हें रद्द कर सकती है।

(v) सशस्त्र सेनाओं के उच्च कमान की नियुक्ति करती है तथा वह उसे पदच्युत भी कर सकती है।

(vi) शांति व्यवस्था, संघीय सुरक्षा अथवा व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से प्रेसीडियम सारे देश अथवा देश के किसी भाग में सैनिक शासन भी लागू कर सकती है तथा मार्शल कानून (Martial Law) लगा सकती है।

(vii) सोवियत संघ के कानून तथा संघीय कानून के द्वारा प्रेसीडियम अपना नियंत्रण रखती है।

(viii) प्रेसीडियम ही राजनतिक उपाधियाँ तथा अन्य सैनिक उपाधियों का नियंत्रण करती है।

(ix) सोवियत संघ की सम्मानसूचक उपाधियाँ तथा अनुष्ठानों की व्यवस्था करती है।

(x) सोवियत संघ के सामाजिक पद, पदक तथा सम्मान की उपाधियाँ प्रेसीडियम के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं।

(xi) विदेशी राजदूतों का स्वागत करती है तथा उनके प्रत्यय पत्रों को स्वीकार करती है।

(xii) अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकार कर सकती है अथवा उसे रद्द भी कर सकती है।

(xiii) यह विदेशों में सोवियत रूस के राजदूतों को नियुक्त करती है तथा आवश्यकतानुसार उनको स्थानान्तरित अथवा पदच्युत भी कर सकती है।

वैधानिक दृष्टि से प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु अवस्था है परन्तु व्यवहार में वह सर्वोच्च सोवियत से कहीं अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली है। इसने सेना, अस्त्रिक सेनायों, राष्ट्रीय नीतियां, निर्वाचन एवं नियुक्ति आदि अधिकारों के अतिरिक्त—लोक नियंत्रण तथा सर्वोच्च सोवियत को भंग करने के अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त—अपनी सभी अधिकारों का प्रयोग खुलकर किया है।

प्रेसीडियम द्वारा जो अध्यादेश एवं आज्ञापत्रियां प्रसारित की जाती हैं उनका क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिसने उसे सबसत्तात्मक बना दिया है। इन आज्ञापत्रियों ने प्रेसीडियम को एक अनवरत सरकार का स्वरूप प्रदान किया है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा सम्पुष्टि से केवल एक औपचारिकता मात्र है। आज तक कभी भी सर्वोच्च सोवियत ने प्रेसीडियम के कार्यों को अस्वीकार नहीं किया है। सन् 1946 में एक आज्ञापत्र द्वारा प्रेसीडियम ने सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की आयु 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। यह कार्य निर्वाचन से पूर्व किया गया। इन आज्ञापत्रियों के द्वारा प्रेसीडियम सही अर्थों में व्यवस्थापिका बन गई है और कार्यशील संस्था के रूप में निरंतर सफल रही है।

प्रेसीडियम में साम्यवादी दल के अनुभव प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ब्रजनेव ने कहा है कि "प्रेसीडियम का गठन उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो कि राष्ट्र के जीवन से भली भांति परिचित हैं और राष्ट्रहित की साधना अपना कर्तव्य समझते हैं।" उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा "वैयक्तिक सभी क्षेत्रों से सम्बंधित शक्तियां प्राप्त हैं।

प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्र का है। यह केवल एक दिखावा है। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम की जाननी होती हुए भी इसके अधीन ही है, उसी के नेतृत्व में कार्य करती है। किन्तु प्रेसीडियम भी पूर्णरूप से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष नहीं है। इसके ऊपर साम्यवादी दल का पूर्ण प्रभुत्व है। दलीय प्रेसीडियम का इसके ऊपर पूर्ण प्रभुत्व है और वह उनकी शक्तियों को भी भयानक रखती है। सर्वोच्च सोवियत तो साधारण व्यक्तियों की एक गोष्ठी सी ही प्रतीत होती है। साम्यवादी दल के प्रमुख नेता ही प्रेसीडियम के कणधार रहते हैं।

मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)

जूलियन टाउस्टर (Yowster) ने सोवियत मन्त्रिपरिषद् को सोवियत पद्धति का सर्वोत्तम नीति निर्देशक यंत्र कहा है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की राज्य शक्ति की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग कहा गया है। सन् 1946 से पूर्व इसे कौंसिल ऑफ पीपुल्स कमिस्सर्स (Council of Peoples Commissars) कहा जाता था। देश की कार्यपालिका शक्ति का समावेश मन्त्रिपरिषद् में ही निहित है।

1 The Presidium is composed of people who know the life of the nation and have a great duty to serve its interest
—Breznev

(xiv) विदेशों में जाने वाले रूसी शिष्ट मण्डलों के प्रतिवेदनों को सुनती है तथा तत्पश्चात् उन्हें सम्बंधित मंत्रालयों के पास भेजती है।

(xv) प्रशासनिक अभिकरणों तथा आयोगों की स्थापना कर सकती है।

(xvi) विदेशों में अंतर ससदीय सम्बंधों की स्थापना करती है।

(xvii) मंत्रालयों को भी स्थानांतरित करती है।

(xviii) सामाजिक आरोपों को सुनने का काम भी प्रेसीडियम द्वारा ही सम्पन्न होता है। प्रायः जनता के व्यक्ति प्रशासन को आरोपित करने के लिए प्रेसीडियम के स्वागत कक्ष में जाकर उसके सदस्यों से बात करते हैं तथा वर्तमान प्रशासन में संशोधन के लिए सुझाव भी देते हैं।

(xix) प्रेसीडियम द्वारा नागरिकता के प्रश्न पर भी निर्णय दिये जाते हैं।

(xx) प्रेसीडियम नवीन कानूनों का संग्रह करती है तथा अनुपयोगी कानूनों को रद्द करती है। समाजवादी कानून कठोरता के साथ लागू किये जाते हैं।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

(i) प्रेसीडियम को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह अधिकार अमेरिका तथा भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है।

(ii) प्रेसीडियम संघीय गणराज्यों के उन आदेशों को रद्द कर सकती है जो कि संघीय कानून के प्रतिकूल हों।

(iii) प्रेसीडियम सोवियत संघ के प्रचलित कानूनों की व्याख्या करती है।

(iv) प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है और इसी प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करती है।

(v) यह अपराधियों को क्षमादान दे सकती है। उदाहरणार्थ—दिनांक 24 जनवरी 1938 को लाल सेना दिवस पर मजदूरों तथा कुपकों को आम क्षमादान प्रदान किया गया था। दिनांक 7 जुलाई 1945 को भी जब जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की विजय हुई उस समय साप्ताहिक रूप से अपराधियों को क्षमादान प्रदान किया गया। इसी प्रकार दिनांक 7 नवम्बर 1957 को भी समाजवादी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी प्रेसीडियम के द्वारा क्षमादान प्रदान किया गया था।

प्रेसीडियम की वास्तविक स्थिति (Real Position of the Presidium)

प्रेसीडियम, वेद्रीभूत एकीकृत तथा अनवरत संस्था है। अपनी स्थिति एवं अपने स्वरूप के कारण ही यह सर्वोच्च सोवियत से अधिक शक्तिशाली बन गई है। जूलियन टाउटस्टर के अनुसार "प्रेसीडियम को संविधान में राज्य के सर्वोच्च अंगों की श्रेणी में रखा गया है। यह औपचारिक सोवियत पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है तथा सरकार के अनेक कार्यों का भी संचालन करती है।" प्रेसीडियम की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए ऑग तथा जिक ने कहा है कि "प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का केवल स्नायुविक केन्द्र ही नहीं है अपितु व्यवहारतः सर्वोच्च सोवियत का सर्वोच्च शासकीय अंग है।"¹

1 Presidium has taken a more active role in handling the work of government than its parent body the supreme council —Ogg & Zink

वैधानिक दृष्टि से प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु अवस्था है परंतु व्यवहार में वह सर्वोच्च सोवियत से कहीं अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली है। इसने सेना, असनिक सेवाएँ, राष्ट्रीय नीतियाँ, निर्वाचन एवं नियुक्ति आदि अधिकारों के अतिरिक्त—लोक नियंत्रण तथा सर्वोच्च सोवियत को भंग करने के अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त—अपने सभी अधिकारों का प्रयोग खुलकर किया है।

प्रेसीडियम द्वारा जो अध्यादेश एवं आपत्तियाँ प्रसारित की जाती हैं उनका क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिसने उसे सर्वसत्तात्मक बना दिया है। इन आपत्तियों ने प्रेसीडियम को एक अनवरत सरकार का स्वरूप प्रदान किया है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा सम्पुष्टि तो केवल एक औपचारिकता मात्र है। आज तक कभी भी सर्वोच्च सोवियत ने प्रेसीडियम के कार्यों को अस्वीकार नहीं किया है। सन् 1946 में एक आपत्ति द्वारा प्रेसीडियम ने सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की आयु 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। यह कार्य निर्वाचन से पूर्व किया गया। इन आपत्तियों के द्वारा प्रेसीडियम सही अर्थों में व्यवस्थापिका बन गई है और कार्यशील संस्था के रूप में निरंतर सफल रही है।

प्रेसीडियम में साम्यवादी दल के अनुभव प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ब्रेझनेव ने कहा है कि "प्रेसीडियम का गठन उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो कि राष्ट्र के जीवन से भारी भाँति परिचित हैं और राष्ट्रहित की साधना अपना कर्तव्य समझते हैं।" उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनतिक तथा "यायिक सभी क्षेत्रों से सम्बंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्र का है। यह केवल एक दिखावा है। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम की जननी होते हुए भी इसके अधीन ही है, उसी के नेतृत्व में कार्य करती है। किंतु प्रेसीडियम भी पूर्णरूप से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष नहीं है। इसके ऊपर साम्यवादी दल का पूर्ण प्रभुत्व है। दलीय प्रेसीडियम का इसके ऊपर पूर्ण प्रभुत्व है और वह उनकी शक्तियों को भी मर्यादित रखती है। सर्वोच्च सोवियत तो साधारण व्यक्तियों की एक गोष्ठी सी ही प्रतीत होती है। साम्यवादी दल के प्रमुख नेता ही प्रेसीडियम के कणधार रहते हैं।

मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)

जूलियन टाउस्टर (Yowster) ने सोवियत मन्त्रिपरिषद् को सोवियत पद्धति का सर्वोत्तम नीति निर्देशक यंत्र कहा है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की राज्य शक्ति की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग कहा गया है। सन् 1946 से पूर्व इसे कोंसिल ऑफ पीपुल्स कमिस्सर्स (Council of Peoples Commissars) कहा जाता था। देश की कार्यपालिका शक्ति का समावेश मन्त्रिपरिषद् में ही निहित है।

1 The Presidium is composed of people who know the life of the nation and have a great duty to serve its interest
—Breznev

(xiv) विदेशों में जाने वाले रूसी शिष्ट मण्डलों के प्रतिवेदनों को सुनती है तत्पश्चात् उन्हें सम्बंधित मंत्रालयों के पास भेजती है।

(xv) प्रशासनिक अधिकरणों तथा आयोगों की स्थापना कर सकती है।

(xvi) विदेशों में अन्तर सप्तदीय सम्बंधों की स्थापना करती है।

(xvii) मंत्रालयों को भी स्थानांतरित करती है।

(xviii) सावजनिक आरोपों को सुनने का कार्य भी प्रेसीडियम द्वारा ही सम्पन्न होता है। प्रायः जनता के व्यक्ति प्रशासन को आरोपित करने के लिए प्रेसीडियम के स्वागत कक्ष में जाकर उनके सदस्यों से बात करते हैं तथा वर्तमान प्रशासन में सशोधन के लिए सुझाव भी देते हैं।

(xix) प्रेसीडियम द्वारा नागरिकता के प्रश्न पर भी निर्णय दिये जाते हैं।

(xx) प्रेसीडियम नवीन कानूनों का संप्रह करती है तथा अनुपयोगी कानूनों को रद्द करती है। समाजवादी कानून कठोरता के साथ लागू किये जाते हैं।

यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

(i) प्रेसीडियम को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह अधिकार अमेरिका तथा भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है।

(ii) प्रेसीडियम सघीय गणराज्यों के उन आदेशों को रद्द कर सकती है जो कि सघीय कानून के प्रतिकूल हों।

(iii) प्रेसीडियम सोवियत संघ के प्रचलित कानूनों की व्याख्या करती है।

(iv) प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है और इसी प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करती है।

(v) यह अपराधियों को क्षमादान दे सकती है। उदाहरणार्थ—दिनांक 24 जनवरी 1938 को लाल सेना दिवस पर मजदूरों तथा कृषकों को आम क्षमादान प्रदान किया गया था। दिनांक 7 जुलाई 1945 को भी जब जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की विजय हुई उस समय सामूहिक रूप से अपराधियों को क्षमादान प्रदान किया गया। इसी प्रकार दिनांक 7 नवम्बर 1957 को भी समाजवादी क्रांति की 40वीं वषगाठ के अवसर पर भी प्रेसीडियम के द्वारा क्षमादान प्रदान किया गया था।

प्रेसीडियम की वास्तविक स्थिति (Real Position of the Presidium)

प्रेसीडियम, वे-ट्रीभूत एकीकृत तथा अनवरत संस्था है। अपनी स्थिति एवं अपने स्वरूप के कारण ही यह सर्वोच्च सोवियत से अधिक शक्तिशाली बन गई है। जूलियन टाउस्टर के अनुसार "प्रेसीडियम को संविधान में राज्य ने सर्वोच्च अंगों की श्रेणी में रखा गया है। यह औपचारिक सोवियत पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है तथा सरकार के अनेक कार्यों का भी संचालन करती है।" प्रेसीडियम की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए ऑग तथा जिंक ने कहा है कि "प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का केवल स्नायुविह्वल केन्द्र ही नहीं है अपितु व्यवहारतः सर्वोच्च सोवियत का सर्वोच्च शासकीय अंग है।"¹

¹ Presidium has taken a more active role in handling the work of government than its parent body the supreme council
—Ogg & Zink

वैधानिक दृष्टि से प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु अवस्था है परन्तु व्यवहार में वह सर्वोच्च सोवियत से कहीं अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली है। इसने सेना, अस्त्रिक सवायें, राष्ट्रीय नीतियाँ, निर्वाचन एवं नियुक्ति आदि अधिकारों के अतिरिक्त—लोक नियंत्रण तथा सर्वोच्च सोवियत को भंग करने के अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त—अब सभी अधिकारों का प्रयोग खुलकर किया है।

प्रेसीडियम द्वारा जो अध्यादेश एवं आज्ञाप्तियाँ प्रसारित की जाती हैं उनका क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिसने उसे सबसत्तात्मक बना दिया है। इन आज्ञाप्तियों ने प्रेसीडियम को एक अनवरत सरकार का स्वरूप प्रदान किया है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा सम्पुष्टि तो केवल एक औपचारिकता मात्र है। आज तक कभी भी सर्वोच्च सोवियत ने प्रेसीडियम के कार्यों को अस्वीकार नहीं किया है। सन् 1946 में एक आज्ञाप्ति द्वारा प्रेसीडियम ने सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की आयु 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। यह काम निर्वाचन से पूर्व किया गया। इन आज्ञाप्तियों के द्वारा प्रेसीडियम सही अर्थों में व्यवस्थापिका बन गई है और कार्यशील सत्ता के रूप में निरन्तर सफल रही है।

प्रेसीडियम में साम्यवादी दल के अनुभव प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ब्रेझनेव ने कहा है कि "प्रेसीडियम का गठन उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जोकि राष्ट्र के जीवन से भली भाँति परिचित हैं और राष्ट्रहित की साधना अपना कर्तव्य समझते हैं।" उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनतिक तथा वार्षिक सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्र का है। यह केवल एक दिखावा है। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम की जननी होते हुए भी इसके अधीन ही है, उसी के नेतृत्व में कार्य करती है। किन्तु प्रेसीडियम भी पूर्णरूप से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष नहीं है। इसके ऊपर साम्यवादी दल का पूर्ण प्रभुत्व है। दलीय प्रेसीडियम का इसके ऊपर पूर्ण प्रभुत्व है और वह उनकी शक्तियों को भी मर्यादित रखती है। सर्वोच्च सोवियत तो साधारण व्यक्तियों की एक गोष्ठी सी ही प्रतीत होती है। साम्यवादी दल के प्रमुख नेता ही प्रेसीडियम के कणधार रहते हैं।

मन्त्रिपरिषद (Council of Ministers)

जूलियन टाउस्टर (Towster) ने सोवियत मन्त्रिपरिषद को सोवियत पद्धति का सर्वोत्तम नीति निर्देशक यंत्र कहा है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 64 के अन्तर्गत सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की राज्य शक्ति की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग कहा गया है। सन् 1946 से पूर्व इसे कौंसिल ऑफ पीपुल्स कमिस्सर्स (Council of Peoples Commissars) कहा जाता था। देश की कार्यपालिका शक्ति का समावेश मन्त्रिपरिषद में ही निहित है।

1 The Presidium is Composed of people who know the life of the nation and have a great duty to serve its interest
—Breznev

यही रूस की वास्तविक सरकार है। प्रशासन के संचालन का उत्तरदायित्व इसी पर है। इसका उत्तरदायित्व प्रेसीडियम तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रति नाममात्र का ही है। वस्तुतः यह साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो का प्रशासकीय विभाग है। इसका अध्यक्ष पद सबदा ही उस व्यक्ति के हाथों में रहा है, जोकि साम्यवादी दल पर भी आच्छादित रहता है। सर्वप्रथम लेनिन ने इस पद को संभाला और उसके बाद क्रमशः राइखोव, स्टालिन, ह्यूश्चेव तथा कोसीगिन इस पद पर आसीन रहे हैं। विदेशों में मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष को प्रधानमन्त्री के नाम से जाना जाता है। सोवियत संविधानवादियों ने ऊपर से इसे सदसीय रूप दिया तो अवश्य है किन्तु व्यावहारिक रूप में वह लेशमात्र भी सदसीय नहीं है। सर्वोच्च सोवियत के प्रति उसका उत्तरदायित्व केवल औपचारिक है। वहाँ पर दल तथा सरकार में अंतर करना कठिन ही है, क्योंकि वहाँ नियम सब सम्मति से होते हैं। मन्त्रिमण्डल भी स्पष्ट रूप से दल का प्रभाव में रहता है।

मन्त्रिपरिषद् का गठन (Composition of Council of Ministers)

मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। इंग्लैण्ड तथा भारत आदि सदसीय देशों में मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के परामर्श पर होती है किन्तु सोवियत यूनियन में यह कार्य सिद्धांत रूप में सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही सम्पादित होता है। किन्तु व्यावहारिक रूप में मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष मन्त्रियों की सूची सदन के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को प्रत्येक मन्त्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक मन्त्री के नाम पर मतदान होता है। सर्वोच्च सोवियत के विरोध करने पर सन् 1938 में अध्यक्ष द्वारा रखी गई सूची में से तीन नाम पथक किये गये थे। परन्तु स्टालिन ने 1946 में अपनी सूची के समस्त नामों को सर्वोच्च सोवियत से स्वीकृत करा लिया था। सर्वोच्च सोवियत के संयुक्त अधिवेशन में सबसे प्रथम कार्य दल के अध्यक्ष के निर्वाचन का होता है। परन्तु रूस में एकदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की सूची साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति द्वारा पहले ही तैयार कर ली जाती है। सोवियत रूस के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के द्वारा होती है—

- (i) मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष।
- (ii) मन्त्रिपरिषद् का उपाध्यक्ष (प्रथम)।
- (iii) परिषद् का उपाध्यक्ष।
- (iv) संघीय मन्त्रिमण्डल तथा गणराज्यों की मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष।
- (v) सोवियत रूस की राज्य नियोजन समिति का अध्यक्ष।
- (vi) मन्त्रिपरिषद् की राजकीय समिति का अध्यक्ष।
- (vii) तकनीकी एवं समिति का अध्यक्ष।
- (viii) सोवियत रूस की लोकतन्त्रीय समिति का अध्यक्ष।
- (ix) सोवियत संघ की राजकीय, श्रम एवं मजदूरी समिति का अध्यक्ष।

- (x) ए. एस. ए. की राजकीय विज्ञान एवं तकनीकी समिति का अध्यक्ष ।
- (xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण की राजकीय समिति का अध्यक्ष ।
- (xiii) कृषि उत्पादन की राजकीय समिति का अध्यक्ष ।
- (xiii) राजकीय विदेशी आर्थिक समिति का अध्यक्ष ।
- (xiv) राजकीय समिति का अध्यक्ष ।
- (xv) राजकीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष ।
- (xvi) यू. एस. ए. के राजकीय बैंक प्रशासकीय मण्डल का अध्यक्ष ।
- (xvii) केन्द्रीय आकिकी बोर्ड का अध्यक्ष ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रिपरिषद एक विशाल निकाय है । वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 70 है । जिस समय प्रेसीडियम का अधिवेशन नहीं होता है उस समय मन्त्रिपरिषद के रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रेसीडियम के अध्यक्ष द्वारा होती है ।

मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष (Chairman of the Council of Minister)

जूलियन टाउस्टर के कथनानुसार "मन्त्रिपरिषद के अध्यक्ष का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा यह पद सोवियत शासन व्यवस्था में निर्णायक है ।"¹

मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष शासन का प्रमुख संचालक है । वहीं मन्त्रिपरिषद का प्रधानमंत्री है । साम्यवादी दल का सबसे अधिक प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इस पद को संभालता है । स्टालिन जीवन पथ पर इसका अध्यक्ष बना रहा । अब कोसीगिन मन्त्रिपरिषद के अध्यक्ष तथा रुस के प्रधानमंत्री हैं । प्रधानमंत्री वस्तुतः समस्त शासकीय व्यवस्था का केन्द्र है । प्रधानमंत्री साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो का प्रभावशाली सदस्य होने के कारण राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्धारक एवं निदेशक बन गया है । समस्त समाजवादी कार्यक्रमों पर उसका नियंत्रण रहता है । एक रूप में वह अधिनायक ही है । यह कहा जाता है कि रुस की समस्त शासकीय व्यवस्था माथल स्टालिन के संकेतों पर ही नाचती थी । प्रधानमंत्री का पद सोवियत संविधान का महत्वपूर्ण अंग है ।

मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के कारण वह उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके प्रस्ताव एवं निर्णयों पर हस्ताक्षर करता है । यदि वह व्यक्तिगत मंत्रियों के द्वारा प्रसारित आदेशों को अनुपयुक्त समझता है तो उन्हें निलम्बित भी कर सकता है । प्रधानमंत्री मन्त्रिपरिषद का प्रमुख संरक्षक एवं नेता होता है । प्रधानमंत्री के पद की अपेक्षा उसका प्रभाव साम्यवादी दल के नेता के रूप में अधिक होता है । वह इस स्थिति में भी होता है कि अपने विरोधियों को शांत कर सके, तथा उनके विरोध को कुचल भी सके । प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में उसका स्वयं का अनुदाय होता है । अब रुस में मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का शब्द सुनाई देने

1 The Office of the Chairman of the Council of Ministers is the most important position on the Council and the most crucial in the Soviet Policy as a whole
—Towster

लगा है। प्रधानमन्त्री अथवा ससदीय देशों के प्रधानमन्त्रियों की भाँति संसद का विघटन तथा अपने मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन नहीं कर सकता।

कायकाल (Tenure)—मन्त्रिपरिषद् का कायकाल सर्वोच्च सोवियत पर निर्भर करता है। नूतन सर्वोच्च सोवियत के साथ नवीन मन्त्रिमण्डल का गठन होता है, जब कि सर्वोच्च सोवियत का कायकाल 4 वर्ष है तो स्वाभाविक रूप से मन्त्रिपरिषद् का कायकाल भी 4 वर्ष ही हुआ। सर्वोच्च सोवियत के विघटन के साथ ही इसका भी विघटन हो जाता है। साम्यवादी दल की सत्ता सबत्र व्याप्त होने के कारण वास्तविक रूप से सर्वोच्च सोवियत और मन्त्रिपरिषद् का विघटन सम्भव नहीं है। सद्भाषितिक रूप से सर्वोच्च सोवियत मन्त्रिपरिषद् को भंग कर सकती है।

बैठकें (Meetings)—मन्त्रिपरिषद् की बैठकें प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में सप्ताह में कई बार होती हैं। उसकी कार्यवाहियाँ गुप्त रखी जाती हैं, वे प्रकाशित नहीं की जाती। इनमें निणय भी बहुमत से होते हैं। गणपूर्ति (Chorum) के लिए आधे सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

मन्त्रिपरिषद् की प्रमुख विशेषतायें (Characteristics of Council of Ministers)

1 मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रियों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी वहाँ कोई बात नहीं होती।

2 मन्त्रियों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। परन्तु साम्यवादी दल की सत्ता के रहते हुए यह सब व्यर्थ ही है।

3 मन्त्रिपरिषद् के गठन की प्रक्रिया में सबसे प्रथम अध्यक्ष अथवा प्रधान मन्त्री का निर्वाचन होता है, तत्पश्चात् अथवा मन्त्रियों की नियुक्ति निर्वाचन की पद्धति के द्वारा की जाती है।

4 मन्त्रिपरिषद् की सूची पर मतदान होता है, अथवा ससदीय प्रणाली वाले देशों में ऐसा नहीं होता है।

5 अथवा ससदीय प्रणालियों में राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का होता है तथा शासन का संचालन मन्त्रिपरिषद् के हाथों में होता है। सोवियत रूस में निर्णायक शक्ति मन्त्रिपरिषद् में नहीं है, वह साम्यवादी दल में है।

6 मन्त्रिपरिषद् के अधिकार औपचारिक हैं जबकि अथवा देशों में वे वास्तविक हैं।

7 प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष का स्तर ब्रिटिश अथवा भारत के प्रधानमन्त्री जैसा नहीं है। अध्यक्ष की शक्तियों का आधार प्रधान मन्त्रित्व की अपेक्षा दलीय मरुत्व के रूप में अधिक प्रभावशाली है।

8 सोवियत रूस के मन्त्रिपरिषद् में दो प्रकार के मन्त्री तथा दो ही प्रकार के मन्त्रालय होते हैं किन्तु ऐसी व्यवस्था अथवा किसी बड़े देश में नहीं पाई जाती।

मन्त्रालय (Ministries)

मन्त्रिपरिषद् में दो प्रकार के मन्त्री होते हैं—अखिल संघीय मन्त्री (All Union Ministers) तथा संघीय गणराज्य मन्त्री (Ministers for Union Republics)। इनसे सम्बन्धित मन्त्रालय भी दो ही प्रकार के होते हैं। अखिल संघीय

मंत्रालयों (All Union Ministries) के क्षेत्राधिकार में वे विषय आते हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का समझा जाता है। अखिल संघीय गणराज्यीय मंत्रालयों (Union Republican Ministries) के क्षेत्राधिकार में वे विषय आते हैं जिनका स्थानीय महत्व होता है और जो गणराज्यों की सरकारों के पास है। संघीय गणराज्यीय मंत्री संघीय गणराज्यों की मंत्रिपरिषदों की बैठकों में भाग लेते हैं तथा केन्द्रीय निर्देशानुसार आचरण भी करते हैं। इस सम्बन्ध में जी० एम० कार्टर ने लिखा है कि "इस अर्थ में, संघीय गणराज्यों के मंत्रालय केन्द्रीय सरकारों के उपकरणों के रूप में काम करते हैं, न कि अमेरिका के समान स्वायत्तशासी सरकारों के रूप में।"¹ यहाँ पर यह बताना भी अनुचित नहीं है कि मन्त्रिमण्डल की सहायता निश्चित नहीं है। हैरल्ड जिंक (Zink) ने इस पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वहाँ आज सहायता 55 अवश्य है परन्तु सदैव ही एक वर्ष पश्चात् लगभग 20 मंत्री पदच्युत कर दिये जाते हैं और सहायता वही 30 या 35 रह जाती है। अखिल संघीय मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लगभग 31 विषय हैं जिनका उल्लेख सोवियत संविधान के अनुच्छेद 78 के अन्तर्गत किया गया है।

अखिल संघीय मंत्रालयों की सूची

हवाई जहाज, मोटर ट्रक, वागज तथा काष्ठ उद्योग, विदेशी व्यापार, नौसेना, युद्ध सामग्री, भूगर्भ सर्वेक्षण, नगर निर्माण, खाद्य तथा पदार्थ, कृषि भण्डार, मशीन तथा यंत्र निर्माण उद्योग, समुद्री जहाजी व्यापार तेल तथा संचार यंत्र उद्योग रेल, जल परिवहनो संचार, कृषि मशीन उद्योग, मशीन दूध उद्योग, भवन तथा पथ निर्माण, जहाज निर्माण, परिवहन मशीनरी उद्योग, लोहा स्पात उद्योग, लेबर रिसर्च, भारी मशीन निर्माण, कोयला उद्योग, रासायनिक उद्योग, अलुमिना घातु उद्योग, विद्युत पावर स्टेशन, भारी उद्योग निर्माणों का निर्माण।

गणराज्य मंत्रालयों की सूची

गृह, सेना, उच्च शिक्षा राज्य नियंत्रण, राज्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, विदेशी सम्बन्ध, चल चित्र, प्रकाश उद्योग, वन विभाग, इमारती लकड़ी उद्योग, मींस तथा डेरी उद्योग, बाद्य उद्योग भवन निर्माण के सामान के उद्योग, मछली विभाग, कृषि राज्य फाम व्यापार, विल, कपास उद्योग एवं याय।

मंत्रिपरिषद की प्रेसीडियम (Presidium of the Council of Ministers)

इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सहायता भी पर्याप्त होती है। मंत्रिपरिषद प्रभावशाली रूप में काम नहीं कर सकती। इसीलिए एक अन्तरंग मन्त्रिमण्डल (Inner Cabinet) का भी गठन किया जाता है। इसी अन्तरंग मन्त्रिमण्डल को मंत्रिपरिषद की प्रेसीडियम कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य विभिन्न मंत्रालयों में ताल मेल उत्पन्न करना है। अन्तरंग मन्त्रिमण्डल में एक अध्यक्ष तथा पाँच उपाध्यक्ष होते हैं। इनका प्रमुख काम नीति निर्धारण तथा विविध विभागों के मध्य समायोजन उत्पन्न करना है।

1 In this sense the ministries of the Union Republics acts as agencies of central government rather than as autonomous governments comparable to those of American states
—Carter & Hertz

मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ

(Powers and Functions of the Council of Ministers)

सन् 1936 के स्टालिन संविधान में कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों को पृथक् किया गया है तथा मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। मंत्रिपरिषद सोवियत संघ का सर्वोच्च प्रशासकीय अंग है। परन्तु व्यावहारिक रूप में मंत्रिपरिषद सर्वोच्च विधायक भी बन गई है। मंत्रिपरिषद का प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप होता रहता है। अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद की शक्तियों का निम्नलिखित उल्लेख किया गया है

(i) मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण कार्य अखिल सघीय तथा सघीय गणराज्यों के मन्त्रालयों में सम-वय उत्पन्न करना है। प्रशासकीय विभागों के मध्य कार्य-नीति की एकरूपता स्थापित करना तथा विभिन्न मन्त्रालयों के आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक प्रकार के कार्यों में सम-वय उत्पन्न करना भी मंत्रिपरिषद का कार्य है।

(ii) मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक योजनाओं का निष्पादन करना भी है। बजट निर्माण, मुद्रा आदि इसके अन्तगत ही आते हैं।

(iii) मंत्रिपरिषद देश में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखती है। इस शीघ्र के अन्तगत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, बाह्य सुरक्षा तथा नागरिकों की सुरक्षा आदि विषय भी आते हैं। शस्त्रादि एवं सेनाओं का संगठन भी इसी में सम्मिलित है।

(iv) विदेशों से सम्पर्क बनाना तथा उनके साथ सम्बन्धों का स्वरूप निश्चित करना भी मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। नागरिकों के लिए आवश्यक सैनिक सेवा की व्यवस्था भी इसी के द्वारा होती है।

(v) आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सैनिक शक्ति के कुशल प्रशासन के लिए मंत्रिपरिषद आयोगों एवं समितियों की स्थापना कर सकती है।

(vi) मंत्रिपरिषद सघीय कानून के आधार पर आदेश दे सकती है तथा सघीय विधियों के निष्पादन (Execution) के लिये परीक्षण की व्यवस्था भी कर सकती है।

(vii) सघीय परिषद सघीय गणराज्यों के उन आदेशों को रद्द कर सकती है जो कि सघीय कानूनों के विपरीत हों।

(viii) जो विधेयक सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी तयारी करना भी मन्त्रिमण्डल का ही कार्य है।

(ix) सघीय गणराज्यों के उन आदेशों को जो कि अखिल सघीय विभागों के प्रशासन एवं अर्थ-व्यवस्था के विपरीत हों उन्हें भंग करने का अधिकार भी मंत्रिपरिषद को है।

मंत्रियों का उत्तरदायित्व (Ministerial Responsibility)

सोवियत संविधान में भी सद्भाषित रूप से मंत्रियों को सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अंतराल में उन्हें प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसका उत्तर उन्हें तीन दिन के अन्दर ही देना आवश्यक होता है। सर्वोच्च सोवियत

अथवा उसकी प्रेसीडियम के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है जिनको पयक भी किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा मंत्रियों के प्रस्तावों एवं उनके कार्यों की आलोचना भी की जाती है।

मन्त्रिपरिषद की वास्तविक स्थिति वह कहाँ तक संसदीय है ?

(Real Position of the Council of Ministers : How far is it Parliamentary ?)

मन्त्रिपरिषद की वास्तविक स्थिति के विषय में दो दृष्टिकोण हैं—संघातिक तथा व्यावहारिक, संघातिक दृष्टि से, मुनरा के अनुसार 'सोवियत रूस में भी ब्रिटेन तथा फ्रांस के सदृश संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। सोवियत मन्त्रिपरिषद में संघातिक दृष्टि से संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लक्षण पाये जाते हैं—

1 मन्त्रिपरिषद प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है।

2 प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सर्वोच्च सोवियत द्वारा मन्त्रिपरिषद के अथ सदस्य चुने जाते हैं।

3 मन्त्रिपरिषद सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अंतरकाल में प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है। वही मंत्रियों की नियुक्ति करती है तथा उन्हें पदच्युति भी करती है।

4 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मन्त्रिपरिषद के सदस्य कार्य करते हैं और उसी से निर्देश भी प्राप्त करते हैं।

5 सर्वोच्च सोवियत अथवा प्रेसीडियम मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकती है।

6 सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को तीन दिन के अंदर उनका उत्तर देना आवश्यक होता है।

7 मन्त्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा विधेयक सर्वोच्च सोवियत में प्रस्तुत किये जाते हैं।

8 मंत्री अपने विभागों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

9 सर्वोच्च सोवियत द्वारा मंत्रियों की आलोचना भी की जा सकती है।

इन लक्षणों के होते हुए भी हम सोवियत मन्त्रिपरिषद को संसदीय नहीं कह सकते, क्योंकि मन्त्रिपरिषद सबहारा वग की तानाशाही के सम्मुख आत्म समर्पण कर देती है। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का नियम भी साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो के द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रिपरिषद जिन नीतियों का निर्धारण करती है उनके विषय में भी नियम साम्यवादी दल के द्वारा ही किए जाते हैं। वास्तव में मन्त्रिपरिषद साम्यवादी दल के हाथों में एक यंत्र मात्र ही है। निम्नलिखित आधारों पर हम सरलतापूर्वक यह कह सकते हैं कि मन्त्रिपरिषद का स्वरूप किसी भी उचित माप से संसदीय नहीं कहा जा सकता।

1 प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद नीति निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है।

2 पश्चिमी संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं की भांति सोवियत मन्त्रिपरिषद को नीति निर्धारण अथवा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार भी नहीं है।

3 सन् 1964 में प्रधानमंत्री ख़ुश्चेव को इसी कारण अपदस्त होना पड़ा क्योंकि उनके नियम साम्यवादी नेताओं के विचारों के अनुरूप नहीं थे।

4 सोवियत रूस में सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ प्रेसीडियम तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से अधिक और सामूहिक रूप से यून मात्रा में ही है। सोवियत शब्दावली में पश्चिमी देशों की भाँति प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का त्याग पत्र नहीं होता है।

5 प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व नहीं करता है। पश्चिमी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद का नेतृत्व ही करता है अपितु वह सम्पूर्ण सदन का ही नेतृत्व करता है वह डूबते हुए मंत्रिमण्डल का अंतिम सहारा होता है। किसी मंत्री को वह पदच्युत नहीं होने देता। सम्पूर्ण मंत्री ही सम्मिलित रूप से सदन में मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णीत नीतियों का पक्ष लेते हैं। परंतु सोवियत रूस में ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक मंत्री अपनी-अपनी ठपकी बजाता है। एक मंत्री को पदच्युत करने से अन्य मंत्रियों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता।

6 सोवियत व्यवस्था में विरोधी दल के अभाव की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इंग्लैंड में तो विरोधी दल के नेता को शासकीय स्वीकृति दी जाती है और प्रधानमंत्री के समान ही उन्नत सी सुविधाएँ प्राप्त हैं। वहाँ आज का विरोधी दल का नेता आने वाले कल का भी विरोधी दल का नेता है। परंतु सोवियत रूस में साम्यवादी दल की तानाशाही है और विरोधी दलों को मत देने का भी अधिकार नहीं है। यद्यपि सोवियत संविधान में साम्यवादी दल को मान्यता दी गई है। सन् 1917 से लेकर आज तक वहाँ पर कोई भी विरोधी दल नहीं बन सका है। अतएव शासकीय दल की आलोचना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

7 सोवियत संघ में वास्तविक लोकतंत्र का अभाव है। वहाँ पर निर्वाचन भी एक उपराम मात्र ही है, यहाँ पर प्रतिद्वंद्वी भी बहुत कम ही होते हैं। प्रत्यासी भी साम्यवादी दल द्वारा ही खड़े किये जाते हैं। मतदाताओं को केवल उन्हें स्वीकार करने की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अतएव वहाँ पर संसदीय प्रणाली के लिए उपयुक्त वातावरण का ही अभाव है।

8 नागरिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व भी 'यायपालिका' को नहीं दिया गया है।

9 सोवियत रूस में प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद को भी सर्वोच्च सोवियत अथवा प्रेसीडियम को भंग करने का अधिकार नहीं है।

अतः यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि सोवियत मंत्रिपरिषद को किसी भी दृष्टिकोण में संसदीय नहीं कहा जा सकता। सोवियत संविधान मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का समुचित रूप में प्रावधान नहीं करता। इस प्रकार मन्त्रिमंडलों की अवस्था ही संसदीय परम्पराओं के अनुरूप प्रतीत नहीं होती। वस्तुतः मंत्रिपरिषद के सार्वभौमिक सोवियत द्वारा निर्वाचन नहीं होते, ये संघ काय साम्यवादी दल के द्वारा ही होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए

साम्यवादी दल के नेताओं की अनुकम्पा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऑंग तथा जिक के शब्दों में "निश्चय ही, औपचारिक अथ के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद को सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति कहना कठिन है। दलीय संगठन उस ऐसी शक्ति प्राप्त करने का अवसर ही नहीं देता।"¹ मंत्रिपरिषद अत्यन्त निबल निकाय है। यूमन के अनुसार मंत्रिपरिषद ने सदस्य प्रेसीडियम के अधीनस्थ प्रशासकीय कमचारी ही हैं। पुन ऑंग तथा जिक के शब्दों में "सोवियत संघ में मंत्रिमण्डल नाममात्र की कार्यपालिका है जिसका कार्य केवल साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो के निर्णयों पर स्वीकृति की मोहर लगाना है।" अतएव सोवियत मंत्रिपरिषद को किसी भी दृष्टि से ससदीय नहीं कहा जा सकता।

सोवियत न्याय व्यवस्था² (Soviet Judicial System)

अमेरिका, भारत, फ्रांस तथा इंग्लैण्ड आदि देशों में न्यायपालिका को संविधान का व्याख्याता तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। उसे जन भावना को समुचित सम्मान दिलाने वाला अधिकरण भी कहा जाता है। न्याय को पावन एवं पवित्र राजकीय कर्तव्य कहा गया है। समात्मक व्यवस्था में तो उसका अनुदाय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु न्याय एवं विधि (Law) के विषय में सोवियत दृष्टिकोण पूर्णतः भिन्न है। स्वतंत्र न्यायपालिका को पूँजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। सोवियत रूस में न्यायपालिका पूर्णतः सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अधीन है। वहाँ पर न्यायपालिका साध्य न होकर एक साधन मात्र ही है। न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व तथा उसकी निष्पक्षता के सिद्धान्त का खण्डन किया गया है। न्यायपालिका का प्रयोग समाजवादी क्रांति के विरोधी तत्त्वों को मूलोच्छेद करके उसे दब बनाना है। अतएव सोवियत रूस में न्यायपालिका को एक साधन के रूप में एक प्रशासकीय तंत्र के अधीन ही रखा गया है।

सोवियत रूस में न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। न्यायपालिका का कार्य एक विशिष्ट प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे की रक्षा करना मात्र ही है। साम्यवादी पूँजीपतिवादी देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवस्थिति को केवल एक ढकोसला मात्र ही मानते हैं। न्यायपालिका को राज्य शक्ति के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। साम्यवादी विचारधारा के प्रसार तथा संरक्षण में न्यायपालिका का महत्व कम नहीं है। न्यायपालिका का प्रयोग एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी किया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से सोवियत न्यायपालिका साम्यवादी दल की सेविका मात्र है। अतएव सोवियत रूस में न्याय की व्यवस्था वर्धमानिक न होकर राजनैतिक ही है।

1 Certainly it is hardly supreme executive authority in more than a formal sense the Party machine would leave it no room for such a role

2 The judiciary is an important and sharp weapon of the dictatorship of the Proletariat in cause of strengthening Socialist Construction

—Ogg & Zink

—Rychkov

सोवियत ग्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ (Important Features of Soviet Judiciary)

(1) शक्तियों के पृथक्करण का अभाव (Absence of Separation of Powers)—सोवियत रूस में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पर 'यायपालिका' को शासन के एक अंग के रूप में ही रखा गया है। वहाँ अ य मंत्रालयों के सदस्य 'याय मंत्रालय' हैं। प्रोव्यूरेटर जनरल 'याय व्यवस्था' का प्रभारी अध्यक्ष होता है।

(2) 'यायिक' एकरूपता (Judicial Uniformity)—सोवियत रूस में 'यायपालिका' का स्वरूप एकरूपीय है। 'यायपालिका' के संगठन में भी एकरूपीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत से योरोपीय देशों के समान शासकीय कमचारियों के लिए पृथक 'यायालय' भी हैं। परन्तु सोवियत रूस में कानून की समानता है, अतएव कानून के दो रूप नहीं हैं। वहाँ प्रशासकीय कानून तथा प्रशासकीय 'यायालय' की व्यवस्था नहीं रखी गई है। कानून के समझ लिए घम का भेद भाव भी नहीं किया गया है।

(3) उद्देश्य (Purpose)—अ य देशों में यायपालिका का प्रयोग राजनितिक दृष्टि से नहीं किया जाता है परन्तु रूस में उसका प्रयोग एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। अतः इसका प्रमुख लक्ष्य एक साधन के रूप में साम्यवाद के प्रसार तथा समाजवादी विचारधारा को शक्तिशाली बनाना ही है।

(4) स्थानीय भाषा का प्रयोग (Use of Local Dialects)—सोवियत संविधान की धारा 110 के अ तहत यह व्यवस्था की गई है कि सभी गणराज्य के यायालयों में स्थानीय भाषा का ही प्रयोग होगा, यदि वादी अथवा प्रतिवादी वहाँ की भाषा नहीं जानता हो तो उसके लिए राज्य की ओर से दुभाषिये की उपलब्धि करायी जाती है।

(5) सुनवाई की सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing of Cases)—सोवियत रूस में अधिकांश विवादों में सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाती है। अभियुक्त का अपने बचाव का पूरा पूरा अवसर दिया जाता है। वह अपने पक्ष में अपनी पक्ष का वकील भी नियुक्त कर सकता है।

(6) 'यायिक' प्रक्रिया की सरलता (Simplicity of Judicial Procedure)—सोवियत रूस की याय व्यवस्था अपनी सरलता एवं सस्ते रूप के लिए लोकप्रिय है। इसकी प्रक्रिया को अधिक से अधिक सरल एवं बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी 'यायिक' कार्यविधि को समझ सकता है। रूस में याय महंगा नहीं है। 'याय' को प्राप्त करने के लिए राज्य से समस्त सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर वकील भी निर्धारित शुल्क से अधिक की माँग नहीं कर सकता।

(7) जन निर्धारकों की व्यवस्था (Arrangements of Public Assessors)—सोवियत रूस में लगभग सभी विवादों के लिए जन निर्धारकों की व्यवस्था है। जन निर्धारकों का भी वही महत्व होता है जोकि 'यायाधीशों' का होता है। प्रत्येक विवाद में इनकी संख्या 2 होती है परन्तु अपील के विवादों में इनकी संख्या 3 हो जाती है।

इनका निर्वाचन भी 'यायाधीशों के समान ही होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को ही 'यायाधीश नियुक्त किया जाता है। निणय बहुमत के द्वारा ही होते हैं।

(8) निणयों में पूर्वोदहारणों का अभाव (Absence of Precedents)—अमेरिका भारत तथा इंग्लैण्ड की भाँति सोवियत रूस में निणय पूर्वोदहारण अथवा नज़ीरों पर अवलम्बित नहीं होते। वहाँ 'यायिक निणयों को विधि का स्रोत नहीं माना गया है। 'यायाधीशों को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है।

(9) राजनैतिक प्रकृति (Political Character)—पश्चिमी लोकतन्त्रीय देशों के 'यायालय सत्तारूढ़ राजनैतिक दल की विचारधारा से प्रभावित नहीं रहते। इनका उद्देश्य किसी राजनैतिक व्यवस्था का समर्थन करना नहीं होता। किंतु सोवियत रूस में पूँजीवादी अवशेषों के विनाश तथा समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ करने की दृष्टि से ही 'यायपालिका का प्रयोग किया गया है।

(10) निर्वाचित 'यायालय (Elected Judiciary)—पश्चिमी राष्ट्रों में 'यायपालिका को और अधिक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से 'यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किंतु सोवियत रूस में 'यायपालिका को अधिक से अधिक जनतन्त्रीय बनाया गया है। इसीलिए ही 'यायाधीशों के निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई है। इस व्यवस्था के समर्थन में रिचकोव (Rychkov) ने कहा था कि "यायालयों के निर्वाचनों से हमारे 'यायिक अंगों को अपरिमित शक्ति प्राप्त होगी और मजदूर वर्ग के हाथों में सोवियत 'यायपालिका अधिक शक्तिशाली शस्त्र होगी।"

(11) वकील मण्डल (Collegium of Lawyers)—यह सोवियत रूस की अपनी व्यवस्था है। पश्चिमी राष्ट्रों में अल्पतः इसका उदाहरण नहीं मिलता। प्रत्येक यायालय के लिए वकीलों का एक मण्डल होता है जिसके सदस्य कानून की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किए हुए होते हैं। किसी भी वकील को किसी भी विवाद की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वकील निश्चित वारिश्चमिक से अधिक नहीं ले सकता। माह के अंत में यह पैसा वकील मण्डल के पास जमा हो जाता है और बाद में योग्यता एवं कायकुशलता के आधार पर मण्डल के समस्त सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। यहाँ पर यह व्यवस्था इसीलिए प्रचलित है, क्योंकि यहाँ कानून राज्यनियंत्रित है।

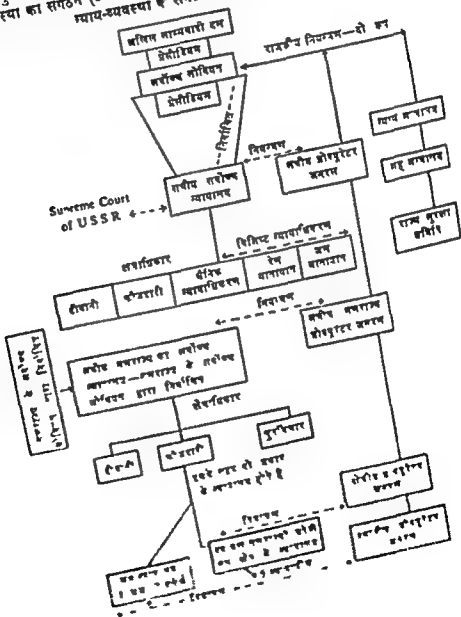
(12) सुधारवादी दृष्टिकोण (Reformative Outlook)—सोवियत रूस में दण्ड के सुधारवादी सिद्धांत को अपनाया जाता है। अपराधों को शिक्षा दी जाती है तथा उसमें अपराध के प्रति घणा का भाव उत्पन्न किया जाता है एवं ऐसा प्रयत्न किया जाता है जिससे कि भविष्य में अपराध की प्रवृत्ति को अवरुद्ध किया जा सके।

(13) 'यायपालिका की सर्वोच्चता का अभाव (Lack of Judicial Supremacy)—सोवियत रूस में 'यायिक सर्वोच्चता को स्थान नहीं दिया गया है। सर्वोच्च 'यायालय तब को भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। शक्तियों के केन्द्रीकरण की दृष्टि से यह अधिकार प्रेसीडियम को ही दिया गया है।

(14) प्रोक्यूरेटर के पद की व्यवस्था (Post of Procurator General)—

(15) प्रत्यावर्तन (Recall)—सोवियत रूस में 'यायासी' को वापस बुलाने की भी व्यवस्था है। जिस निर्वाचक मण्डल ने उन्हें निर्वाचित किया है वही उन्हें वापस भी बुला सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती।

(15) प्रत्येक न्यायाधीश की श्री व्यवस्था है। जिस न्यायाधीश की श्री व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था को न्याय-व्यवस्था का संगठन (Judicial Organization) कहा जाता है। न्याय-व्यवस्था के संगठन का रेखाचित्र



1 जन 'यायालय (Peoples Court)

सोवियत 'यायिक पद सोपान में जन 'यायालय सबसे निम्न स्तर के 'यायालय होते हैं। इन्हें जिला 'यायालय भी कहा जाता है। इनकी सख्या से सम्बंधित नियम गणराज्य की मंत्रिपरिषद करती है। नगरों में एक से अधिक जन 'यायालय होते हैं। प्रत्येक जन 'यायालय में एक न्यायाधीश तथा अभिनिर्धारक (Assessors) होते हैं, जिनका निर्वाचन 3 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इनके प्रत्यावर्तन (Recall) की भी व्यवस्था है। 'यायाधीश अध्यक्ष होता है। नियम बहुमत से होते हैं। इनमें फौजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार के विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। इसका क्षेत्राधिकार प्रारम्भिक ही है।

2 संघ गणराज्यों के उच्चतर 'यायालय (Higher Courts in Union Republics)

इस श्रेणी के अंतर्गत तीन प्रकार के 'यायालय आते हैं—

1 स्वायत्त गणराज्यों के सर्वोच्च 'यायालय

2 स्वायत्त प्रदेशों के 'यायालय

3 राष्ट्रीय क्षेत्रों के 'यायालय

इनमें से प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य में एक सर्वोच्च 'यायालय होता है। इसके 'यायाधीशों का निर्वाचन स्वायत्त गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा सम्पन्न होता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कई सदस्य तथा जन निर्धारक होते हैं। इनका प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है। 'यायाधीशों का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

स्वायत्त प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के 'यायालयों का निर्वाचन उसकी भौगोलिक इकाई के प्रतिनिधियों की सोवियतों के द्वारा किया जाता है। इनमें भी जननिर्धारकों की व्यवस्था का नहीं है। ये निम्नकोर्ट के 'यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी काम करते हैं। क्षेत्रीय 'यायालयों में भी फौजदारी तथा दीवानी तथा प्रारम्भिक न्यायालयों के विरुद्ध अपील के विवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जन 'यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

3 संघ गणराज्य का सर्वोच्च 'यायालय (Supreme Court of Union Republic)

प्रत्येक संघीय गणराज्य में एक सर्वोच्च 'यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके 'यायाधीशों का निर्वाचन उस गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक 'यायालय में एक अध्यक्ष होता है जोकि मुख्य 'यायाधीश कहलाता है। कई उपाध्यक्ष, कई सदस्य तथा अभिनिर्धारक (Assessors) भी होते हैं। इन सबका निर्वाचन 5 वर्ष के लिये होता है। इसका प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार है। इसके समक्ष दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। केवल विशेष महत्व के विवाद ही इसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च स्तर के सनिब अधिकारी भी इसके क्षेत्र में आते हैं। गणराज्य स्थित सभी गणराज्यों के निर्णयों को यह रद्द कर सकता है। स्वायत्त प्रदेश तथा गणराज्यों के 'यायालय इसके अन्तर्गत आते हैं। इसे उनके कार्यों का निरीक्षण करने का भी अधिकार है।

4 सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of U S S R)

सोवियत संविधान में सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इससे न्यायाधीशों का निर्वाचन भी स्विस न्यायाधिकरण की भांति ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन 5 वर्ष के लिये होता है। स्विस न्यायाधिकरण के न्यायाधीश 6 वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते हैं, परन्तु भारत में वे 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। परन्तु इससे विपरीत अमेरिका में यह पद लगभग जीवन भर के लिए होता है। वस्तुतः अमेरिका में आयु पर सदानार की सीमा है। सदाचार के रहते हुए न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। बहुत से अन्य देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनका निर्वाचन नहीं होता। यदि महान्यायवादी ने इनके विरुद्ध कायबाही कर रखी हो तो सोवियत रूस में न्यायाधीशों को पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। अमेरिका में न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की कायबाही की जाती है परन्तु सीनेट द्वारा एक न्यायालय के रूप में अपने 2/3 बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार करना आवश्यक है। भारत में भी संसद की प्रायना पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है।

यह भी आश्चर्य की ही बात है कि सोवियत संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। न्यायाधीशों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण भी संविधान में नहीं किया गया है। इस समय इसमें एक अध्यक्ष (Chairman) एक उपाध्यक्ष, 68 न्यायाधीश, 25 सहायक न्यायाधीश तथा अनेक जन निर्धारक होते हैं। कार्य की सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 भागों में विभाजित किया गया है—फौजदारी, दीवानी, सैनिक, रेल यात्रा एवं जल सम्बन्धी। प्रारम्भिक विवादों में एक न्यायाधीश तथा दो जन न्यायाधीश होते हैं परन्तु अपीलीय विवादों में न्यायाधीशों की संख्या 3 रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष अर्थात् मुख्य न्यायाधीश को किसी भी मण्डल की अध्यक्षता करने का अधिकार है। तटीय गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष गणराज्यीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विवाद को वहाँ ही हटाकर अपने समक्ष सुनवाई के लिए भेज सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं कर्तव्य (Powers & Functions of Supreme Court of U S S R)

सू० एस० एस० आर० के सर्वोच्च न्यायालय को दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं—प्रारम्भिक (Original) तथा अपीलीय (Appellate)। प्रारम्भिक क्षेत्र में बहुत ही गम्भीर प्रकार के फौजदारी तथा दीवानी के विवाद ही इसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा से किसी भी विषय पर पुनर्विचार कर सकता है। महान्यायवादी (Prosecutor General) अथवा मुख्य न्यायाधीश किसी भी निम्नस्तरीय न्यायालय के पास के विवादों में से अपने समक्ष किसी भी विवाद को विचाराय प्रस्तुत करा सकता है। यह विशेष न्यायालयों तथा अपने किसी मण्डल (Collegiate) के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुन सकता है। अपने कर्तव्य का

पालन करते हुए उच्च सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो अपराध किये जाते हैं उनकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संघ गणराज्यों के पारस्परिक अंतर्द्वंद्वों का भी निणय करता है। उच्च श्रेणी के सैनिक अधिकारियों के विवाद भी इससे अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उच्चतम न्यायालय की स्थिति (Position of the Supreme Court)

संघीय सर्वोच्च न्यायालय की विचित्र स्थिति का मूल कारण कानून तथा न्याय सम्बन्धी सोवियत दृष्टिकोण की विशेषता है। वहाँ न्याय व्यवस्था की शासन का ही एक अंग माना गया है। इसी कारण ही सोवियत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं दिया गया है।

संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय गणराज्यों के विधान मण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के सम्बन्ध में उनकी वैधानिकता पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। यदि मन्त्रिपरिषद् के आदेश संविधान की भावना के प्रतिकूल भी हों तो भी इसे उनकी रद्द करने का अधिकार नहीं है। अन्य देशों की न्यायपालिका में प्रोक्क्यूरेटर (महान्यायवादी) का पद नहीं पाया जाता। सोवियत संविधान में मन्त्रिपरिषद् को न्यायपालिका पर अपने न्याय विभाग द्वारा हस्तक्षेप करने तथा नियन्त्रण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी विवाद का निणय कर रहा हो तो उस समय न्याय मन्त्री उसमें भाग ले सकता है तथा हस्तक्षेप कर सकता है।

सोवियत रूस में व्यक्तिगत कानून (Private Law) तथा सावजनिक कानून (Public Law) में कोई अंतर नहीं है। सोवियत नेता राज्य तथा व्यक्ति में कोई अंतर नहीं करते। कानून की समस्त शाखाओं को प्रशासकीय क्षेत्र के अधीन माना गया है। पश्चिमी राष्ट्रों की भांति न्यायपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जूलियन टाउस्टर (Towster) ने कहा है कि "बहुत कुछ सम्भावना इसी बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निणयों द्वारा केवल दल स्वीकृत मन्त्रिपरिषद् के निणयों को ही वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक न होकर राजनतिक मात्र ही है। वह सरकार की पुष्टि करने वाला एक सत्य मात्र ही है। भारत तथा अमेरिका के उच्चतम न्यायालयों की तुलना में उसका महत्व नगण्य ही है। सोवियत रूस की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में एक हास्यास्पद बात यह है कि वहाँ पर न्यायाधीशों की योग्यता की अपेक्षा उनकी साम्यवाद के प्रति निष्ठा पर अधिक बल दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार किसी भी नागरिक को महान्यायवादी की अनुमति प्राप्त करके भिरपतार किया जा सकता है। टाउस्टर ने सोवियत न्यायपालिका को श्रमिक वर्ग की तानाशाही का महत्वपूर्ण अंग कहा है। दण्ड प्रदान करने में भी न्यायाधीशों को अपने विवेक को प्रयोग करने के बहुत से अवसर मिलते हैं। कार्टर (Carter) ने ठीक ही कहा है कि न्याय एक कानून की अस्पष्ट अवस्था की स्थिति में नागरिकों को बहुत कुछ मात्रा में न्यायालयों की इच्छा तथा कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कार्टर ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि जनता निम्नस्तरीय न्यायालयों के कार्यों में अधिक रुचि लेती है तथा न्याय एक

अपाय के अन्तर की भली प्रकार समझती है। सोवियत रूस में कानून के समक्ष साम्यवादी हित की अपेक्षा समानता का सिद्धांत पीना पड़ जाता है।

सोवियत संघ का प्रोक्यूरेटर जनरल (महा-यायवादी) (Procurator General of U S S R)

जार शासकीय काल में प्रोक्रैसी (Procracy) का जो पद था उसी के समकक्ष ही सोवियत रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है। यह पद इतना महत्वपूर्ण है कि 1930 में यह पद विशास्त्री ने ग्रहण किया था। उसी के शब्दों में "सोवियत महा-यायवादी समाजवादी कानूनी व्यवस्था का चौकीदार है। वह साम्यवादी दल की नीतियों का नेतृत्व करता है अतएव वह समाजवाद का प्रमुख व्यक्ति है।" पुनः जो एम काटर के शब्दों में "समस्त सोवियत संघ में विधायी नियमों की एकरूपता को आवश्यक बनाने के लिये प्रोक्यूरेटर जनरल का स्थान सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक महत्वपूर्ण है।" सोवियत संविधान के अनुच्छेद 113 में प्रोक्यूरेटर जनरल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। प्रो० रोडी (Rodee) के शब्दों में "यह अधिकारी सभी अभियोजनाओं का स्वामी होता है तथा गणराज्यीय एवं अन्य स्तर के अभियोजकों को निर्देश देता है तथा सोवियत संघ के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करता है।" इसके पद की तुलना अन्य देशों के महा-यायवादी से की जा सकती है।

प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के द्वारा सम्पन्न होता है। उसकी नियुक्ति 7 वर्ष के लिए की जाती है। वह अपने स्वतंत्र विभाग का अध्यक्ष होता है। अपने समस्त कार्यों के लिये वह सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है। सर्वोच्च सोवियत उसके दुराचरण के कारण इस अवधि से पूर्व भी उसे अपने पद से पदच्युत कर सकती है। सभी गणराज्यों, स्वतंत्र गणराज्यों के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति इसी पदाधिकारी के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। शस्त्र सेनाओं, जल यातायात तथा रेल यातायात के भी प्रोक्यूरेटर होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी प्रोक्यूरेटर जनरल के द्वारा ही होती है।

प्रोक्यूरेटर जनरल के काम (Functions of Procurator General)

1. **सावजनिक सम्पत्ति की रक्षा (Protection of Public Property)**—सोवियत संविधान में महा-यायवादी को सावजनिक सम्पत्ति का संरक्षक कहा गया है। सावजनिक सम्पत्ति की चोरी, लूट, अपहरण एवं उसके विनाश को रोकना महा-यायवादी का कर्तव्य है। वह सोवियत विरोधी विषयों की जांच-पड़ताल भी करता है।

2. **नागरिक अधिकारों की रक्षा (Protection of the Rights of Citizens)**—सोवियत संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को 'व्यक्तिगत अतिक्रमण' के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो वह अपनी शिकायत

1 The Soviet prosecuting officer is the watchman of Socialist legality the leader of the policy of the Communist party and of Soviet authority the champion of Socialism
—Vyshinsky

लिखित रूप में प्रोक्यूरेटर जनरल के पास भेज सकता है। प्रोक्यूरेटर उस सम्बन्ध में छानबीन करता है, तथा पदाधिकारी के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध आवश्यक कामवाही करता है।

3 फौजदारी मामलों की जांच पड़ताल (Investigation of Criminal Cases)—महा-यायवादी को फौजदारी मामलों में जांच पड़ताल करने का अधिकार है। वह उन परिस्थितियों का भी विश्लेषण करता है जिनके कारण अपराध किया गया है। वह लिखित एवं मौखिक साक्षियाँ भी एकत्रित करता है। वह अय्य अवैपणकारी सस्याओं के कार्यों का भी निरीक्षण करता है। महा-यायवादी यह भी देखता है कि सोवियत संघ के मन्त्रालय तथा उसके अधीन सस्याएँ उचित रूप से कार्य कर रही हैं अथवा नहीं।

(4) राज्य की ओर से अभियोग लगाना (To Prosecute in the Name of the State)—प्रोक्यूरेटर जनरल को राज्य की ओर से मुकद्दमा चलाने का अधिकार दिया गया है। 'यायालय नियम की घोषणा करने के पश्चात् अपने नियम प्रोक्यूरेटर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो इस बात का परीक्षण करता है कि नियम किस सीमा तक सही हुआ है। यदि वह नियम से सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह उसके विरुद्ध अपील करता है। यदि वह नियम को उचित समझता है तो वह उसे क्रियावित्त करता है। यायालयों का यह कर्तव्य है कि महा-यायवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर तुरन्त पुनर्विचार करें, वह राज्य की ओर से सजाये जाने वाले अपराधों में मुकद्दमे की पैरबी भी करता है।

पद का मूल्यांकन (Evaluation of the Office)

सोवियत संघ की प्रशासकीय व्यवस्था में प्रोक्यूरेटर जनरल का बहुत बड़ा महत्त्व है। उसके पद को अधिक से अधिक स्वतंत्र रखने की चेष्टा की गई है। उसका कार्यकाल प्रत्येक पदाधिकारी की अपेक्षा अधिक रखा गया है। प्रोक्यूरेटर मन्त्रिपरिषद् का सदस्य नहीं होता और न ही वह उसके द्वारा पदच्युत ही किया जा सकता है। वह केवल सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। किन्तु वह साम्यवादी दल के नियन्त्रण से मुक्त नहीं है। उस में जब से साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई है तभी से वहाँ यह पद चला आ रहा है। सन 1936 से पूर्व महा-यायवादी को मन्त्रिपरिषद् के अधीन रखा गया था किन्तु स्टालिन सविधान में उसे कार्यपालिका के नियन्त्रण से अधिकाधिक स्वतंत्र रखा गया है। प्रोक्यूरेटर जनरल का पद अत्यन्त केन्द्रित प्रकार का है। वह विधि अथवा 'याय मन्त्री के अधीन नहीं है। उसका प्रमुख कार्य यह देखना है कि कहीं अयाय तो नहीं हुआ। "सोवियत संघ का प्रोक्यूरेटर जनरल समाजवादी 'याय व्यवस्था का सरदार है। वह साम्यवादी दल तथा सत्ताधारी दल की नीतियों को निष्पादित करने वाला तथा समाजवाद के निमित्त योद्धा है।" गोर्नुस्की (Golunsky) ने सोवियत प्रोक्यूरेटर के पद का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि कोई भी पदसोपानीय विभागीय व्यवस्था में प्रोक्यूरेटर जनरल को उस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से नहीं रोक सकता जोकि उस समर्पित किए गए है।

1 Procurator is a guardian of Socialist legality a carrier of the policy of Communist and authority a fighter for the cause of Socialism.

Select References

भाग तथा जिक	आधुनिक विदेशी सरकारें
मुनरो	यूरोप की सरकारें
जूलियन टाउस्टर	यू एस एस आर में राजनैतिक सत्ता
काटर तथा हटज	सोवियत संघ की सरकार
फाइनर	यूरोप की प्रमुख सरकारें

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- सर्वोच्च सोवियत के संगठन रचना तथा कार्यों का विवरण दीजिए ।
(Describe the organization composition and functions of the Supreme Soviet of U S S R)
- "सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत वहाँ की राजसत्ता का उच्चतम अंग है"—
"स्पष्ट कीजिए ।
(The Supreme Soviet of the U S S R is the highest organ of the State authority of the U S S R , Explain)
- "आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि सोवियत रूस का प्रेसीडियम संसार में एक अनौखी संस्था है ।"
(How far do you agree with the Statement that the Soviet Presidium is the Unique institution in the world ?) (Vikram 62, 64)
- सोवियत संघ की प्रेसीडियम के संगठन तथा कृत्यों का वर्णन कीजिए और संघीय परिषद से उसका सम्बन्ध बताइए ।
(Describe the composition powers and functions of the Presidium and show its relation with the council of ministers in U S S R)
(P U 1957)
- "सोवियत रूस की संवैधानिक व्यवस्था में प्रेसीडियम का क्या महत्व है ? क्या यह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका बन गई है ?
(What is the position of the Presidium in the Constitutional set up of the U S S R ? How far if at all has it become the real legislature ?) (B U 1955 Agra 56)
- क्या सोवियत रूस में मंत्रिमण्डलात्मक पद्धति है ? यदि है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं ?
(Is there a Cabinet system in U S S R ? If so what are its peculiarities ?) (Raj Uni 1961 Agra)
- अमेरिकन तथा सोवियत मंत्रिपरिषदों की तुलना कीजिए ।
(Compare and Contrast the Cabinet in U S A with council of ministers in U S S R) (Raj U 1961)
- सोवियत संघ में कहाँ तक उत्तरदायी संसदात्मक सरकार है ? ब्रिटिश व्यवस्था के साथ इसकी तुलना कीजिए ।
(To What extent does the Soviet Union possesses a responsible parliamentary type of Government ? Compare and Contrast it with that in Britain)
- सोवियत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । क्या वह व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करती है ?

(Examine Critically the Composition and powers of the Supreme Court in the U S S R How far can it protect the Individual liberty)

- 10 सोवियत रूस तथा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की संगठन सम्बन्धी विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए ।

(Examine the differences in organization and powers of the Supreme Court of the U S A and the U S S R)

- 11 "रूस की न्यायपालिका एक नियमित प्रशासन का अंग है" (मुनरो) विवेचना कीजिए ।

(Russian Judiciary is a part of the regular administration ' (Munro) Discuss the importance of Soviet Judiciary in the light of the above Statement)

साम्यवादी दल तथा सोवियत रूस में लोकतन्त्र

[The Communist Party & Democracy in Soviet Union]

"The Communist party is the Sovereign ruler of the Soviet Union" —Finer

"Judged by the standards of British and the French Party Systems, the party structure of the Soviet Union is novel and perplexing" —Carter

"The Party is a thong it often cuts into my flesh but I can not live without it I need some one to give the orders I must feel another shoulder next to mine"

—A character in Russian Play Bread

परिचयार्थक

सोवियत संविधान में केवल साम्यवादी दल के अस्तित्व को ही स्वीकार किया गया है। संविधान में साम्यवादी दल को श्रमिकों का अग्रभाग कहा गया है। इसे श्रमजीवी लोगों के समस्त संगठनों का प्रमुख अंतरभाग कहा गया है।¹ सर्वहारा वर्ग के नाम से सोवियत रूस में राजनैतिक दल की तानाशाही है। दल ही राजनैतिक नीतिमा का निर्धारण करता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ दल द्वारा होती हैं। सोवियत रूस में एकदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण विरोधी स्वर सुनाई नहीं देता। सोवियत संविधान भी साम्यवादी दल के महत्व को स्वीकार करता है।

साम्यवादी दल रूस की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था पर इस प्रकार से आच्छादित है कि इसे अवश्य सरकार की सजा दी जा सकती है। देश की सम्पूर्ण व्यवस्था पर इसकी एकाधिपत्यपूर्ण स्थिति है। सिद्धांत में ही दल तथा सरकार में भिन्नता है परंतु व्यवहार में वे भिन्न नहीं हैं। भाष्य के विचारों को व्यावहारिक रूप साम्यवादी दल के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। श्रमिक, सर्वहारा तथा सांस्कृतिक एवं सावजनिक संगठनों को साम्यवादी दल नेतृत्व प्रदान करता है। राज्य के समस्त महत्वपूर्ण² साम्यवादियों के हाथों में हैं। प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति द्वारा नियंत्रित होती हैं।

सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी को एक आदेश तथा शिक्षक के रूप में देखा जाता है। समाजवाद को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए उसने क्रियात्मक काय किया है। मार्क्सवादी प्रचार करना दल का प्रमुख कार्य है। जनितकारी एवं

1 Communist party is the Vanguard of the working people the leading core of all organization of the working people

अभ्यासयुक्त व्यक्तियों का साम्यवादी दल एक प्रभावशाली संगठन है। लेनिन ने एक बार सबहारा क्रांति के परिवेप में दलीय सहयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा था कि "यदि दल का पथ कर दिया जाय तो रूस में सबहारा वग के अधिनायकत्व का अस्तित्व ही शेष नहीं रहेगा।"¹ साम्यवादी दल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से उच्च कोटि के नेता अपने कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। समस्त समाचार अभिकरण साम्यवादी दल के नियन्त्रण में ही कार्य करते हैं।

साम्यवादी दल सरकार का वास्तविक शासक है। वय दम्पति ने इसे सोवियत संघ के संवैधानिक ढाँचे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कहा है। स्टालिन के शब्दों में दल ही सरकार का पथ प्रदर्शक है। साम्यवादी दल के अधिनायकत्व (Dictatorship) की व्याख्या तीन प्रकार से की जाती है—

(i) सरकार के अधिकांश प्रभावशाली पदाधिकारी साम्यवादी दल के भी सदस्य होते हैं। वे अपने-से घनिष्ठ अंगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व कम तथा साम्यवादी दल के प्रति अपना उत्तरदायित्व अधिक समझते हैं। उसी के आदेशों का पालन करते हैं।

(ii) साम्यवादी दल कभी कभी सरकारी निकायों के निणयो के विषय में उनके स्थान पर घोषणा तक भी कर देता है। दल की कार्यकारिणी तथा मंत्रिपरिषद द्वारा संयुक्त नीतियों एवं निणयों की घोषणा तो एक साधारण बात है। इस साधन सम्पन्न सरकार के ऊपर दलीय प्रभाव की वृद्धि होती रहती है।

(iii) दलीय संगठन ही इस प्रकार का है कि दल के विभिन्न स्तरों के संगठन अपने समानांतर शासकीय संगठन के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करते हैं।

सोवियत शासन के विविध अंगों में कभी भी मतभेद नहीं देखा गया। इनमें निर्णय भी सबसम्मति से होते हैं। सरकार तथा दल मिल जुलकर कार्य करते हैं। दल ही इस बात का निश्चय करता है कि कौनसी बात कब, कैसे और क्यों करनी है। यदि व्यवहार की दृष्टि से देखा जाय तो सोवियत संघ का वास्तविक शासक साम्यवादी दल का महासचिव ही है। इस समय सोवियत रूस में कोसीगिन प्रधानमंत्री हैं तथा ब्रेझ्नेव उसके महामंत्री हैं। यह कहना गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री साम्यवादी दल के हाथ में केवल एक खिलौना मात्र ही है। स्टालिन तथा लेनिन अपने जीवन काल में इन दोनों पदों पर बने रहे। जो प्रधानमंत्री दल का महासचिव नहीं रहा उसे अंत में अपने पद से पृथक ही होना पड़ा। पश्चिमी लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में दल के महासचिव का इतना महत्व नहीं होता। साम्यवादी दल के अधिनायकत्व में जहाँ और तत्त्वों का महत्व है, वहाँ इसका भी महत्व है कि उसे आलोचनाओं एवं विरोधों का सामना नहीं करना पड़ता। फनशोड के शब्दों में 'दल सरकार के अंदर एक सरकार है और सोवियत संघ में शक्ति का वास्तविक केन्द्र है।'² सरकार यदि संयुक्त पूंजी कम्पनी है तो साम्यवादी दल की कार्यकारिणी

1 Where the party to be set aside there could in fact be no dictatorship of the Proletariat in Russia

2 The party in short is a government inside a government and the real of power is in the Soviet Union

प्रबल निदेशक है। सोवियत रूस में साम्यवादी दल को स्पष्ट प्लग कहा गया है। देश के जीवन पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। वह दल की चेतन्य अवस्था का सूचक है।

साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताएँ (Chief Characteristics of Communist Party)

सोवियत रूस में साम्यवादी दल की नींव 1868 में *Russian Social Democratic Labour Party* के रूप में पड़ी थी। आगे चलकर इस दल के दो बग हो गये—मैक्रोविक तथा बोलशेविक। सन् 1917 की क्रांति में इन दोनों ने संयुक्त रूप में सक्रिय सहयोग दिया था। सन् 1922 में इस दल का नाम बोलशेविकों का रूसी साम्यवादी दल से हटाकर 'सोवियत संघ का साम्यवादी दल' रखा गया। स्टालिन सविधान (1936) में साम्यवादी दल को संवैधानिक मायता प्रदान की गई। साम्यवादी दल को मार्क्सवादी दशन एवं आर्थिक कार्यक्रम को व्यवहार में रखने का महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। सोवियत रूस में दल तथा शासन में कोई अंतर नहीं है। साम्यवादी दल अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के लिए लोकप्रिय है।

1. एकदलीय व्यवस्था (One party Rule)—सोवियत रूस में केवल एक ही राजनैतिक दल को मायता दी गई है। अन्य राजनैतिक दलों की पनपने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। रूस में एकदलीय व्यवस्था राजनैतिक दलों के विषय में सोवियत दृष्टिकोण के बहुत कुछ अनुकूल है। साम्यवादी राजनैतिक दलों का सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से मानते हैं। इनमें से अधिकांश राजनैतिक बग व्यवस्था के प्रतीक हैं। समाज में जितने अधिक आर्थिक हित होंगे उसी अनुपात में राजनैतिक दल भी होंगे। रूस में बगविहीन समाज है, अतएव वहाँ एक से अधिक राजनैतिक दलों की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ एकदलीय शासन व्यवस्था है।

2. दलीय सर्वोच्चता (Supremacy of Party)—साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक है। सोवियत समाज की अन्य समस्त संस्थाएँ साम्यवादी दल के संरक्षण में संगठित हो सकती हैं और उसी से प्रेरणा लेती हैं तथा पथ प्रदर्शन प्राप्त करती हैं। समस्त प्रशासकीय व्यवस्था पर साम्यवादियों का नियंत्रण है। दल ही अंतिम निर्णय करता है। सर्वोच्च सोवियत तथा मंत्रिपरिषद साम्यवादी दल के निर्णयों को केवल त्रिगुणित करने के साधन मात्र हैं।

3. एकात्मिक स्वल्प (Monolithism)—मोनोलिथ का शाब्दिक अर्थ है एक ठोस परस्पर का बना हुआ घनमा। इसका अर्थ है साम्यवादी दल की अखण्डता। साम्यवादी दल में अनुशासन इतना बढोर है कि वह अस्वल्प फिरफार-परस्ती तथा गुटबन्दी के लिए कोई स्थान शेष नहीं छोड़ता। स्टालिन की मृत्यु पर दल के प्रति अपने उत्साह व्यक्त करते हुए मोलेस्कोव ने कहा था कि 'दल की एकाता हमारी आँखों का तारा है। मोनोलिथ दलीय संगठन की दृढ़ता तथा उसकी एकाता का प्रतीक है। दल में अंदर परस्परिक मध्य एक अनुचित प्रतियोगिता के लिए कोई स्थान नहीं है। स्टालिन ने स्वयं कहा था कि 'दल की दृढ़ता का अर्थ है दृढ़ता की एकाता। मोनोलिथ मन्त्र का आगम्य यह भी है कि महत्वपूर्ण निर्णयों का अधिकार दल के स्थायी समुदाय (प्रेसोवियम) को ही होना चाहिए जिसमें मन्त्रियों की संख्या बहुत

कम होती है। लेनिन तो यह मानता था कि दल की व्यापक नीतियों की आलोचना करने का अधिकार सदस्यों को ही होना चाहिए परन्तु स्टालिन के समय में यह दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया गया और उसके स्थान पर यह सिद्धान्त निश्चित किया गया कि नेता कभी कोई त्रुटि नहीं करता वह अमोघ है। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् ए. सुखोव तथा मेलनकोव के समय में एक नूतन दृष्टिकोण उद्भूत हुआ तथा दल के समस्त सदस्यों को नीतियों के विषय में प्रत्यालोचना का अधिकार दिया गया परन्तु साम्यवादी दल के मोनोतिथि स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि शीर्ष स्तरीय नियम का अधिकार चोटी के नेताओं के हाथों में ही केन्द्रित रहा।

4 सदस्यता (Membership)—साम्यवादी दल की सदस्यता प्राप्त करना कठिन कार्य है। उसके लिए सघन, वक्तव्यपरायणता, अनुशासन तथा त्याग का परिचय देना पड़ता है। तीन सदस्यों की सिफारिश तथा दल की प्रारम्भिक इकाई के कहने पर अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है तत्पश्चात् पूर्ण परीक्षण तथा साम्यवादी सिद्धान्तों की तपोभूमि पर कार्यरत रहने के पश्चात् दल की स्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है। दल से पृथक् होना आसान है किन्तु उसमें प्रवेश पाना कठिन है। दल के सदस्यों को दल के अन्दर ही आलोचना, मतदान, दोषारोपण के समय व्यक्तिगत सफाई तथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु उच्च श्रेणी के नेताओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। सदस्यों के वक्तव्यों पर अधिक बल दिया जाता है। साम्यवादी दल की सदस्यता में वृद्धि करने के लिए लोकतन्त्रीय देशों की भाँति चवनी छाप सदस्यों की भर्ती द्वारा दल की काल्पनिक शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते।

5 जनतांत्रिक केन्द्रवाद (Democratic Centralism)—साम्यवादी दल जनतांत्रिक केन्द्रवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। इसका अर्थ यह है कि दल के प्रत्येक उच्चतर संगठन का निर्वाचन निम्न स्तर के निकायों द्वारा होना चाहिए। दल का प्रत्येक निकाय अपने से उच्चतर निकाय के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी है। उसी के आदेशों का वह पालन करता है। उच्चतर निकाय की आलोचना करने का अधिकार निम्नतर निकाय को नहीं है। उत्तरदायित्व का सूत्र ऊपर को तथा आज्ञा का सूत्र नीचे की ओर चलता है। दलीय उपकरण अपने कार्यों का शीघ्रता समय समय पर समर्पित करते हैं। जनतांत्रिक केन्द्रवाद में अल्पमत की इच्छा के समक्ष बहुमत की इच्छा का समर्पण है। इस व्यवस्था में आवश्यक रूप से अनुशासन की सीमाओं में ही रहना पड़ता है।

6 उद्देश्य (Objectives)—साम्यवादी दल का सक्षम मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी विचारधारा को क्रियात्मक रूप प्रदान करना है। इसके अर्थ सत्य हैं—समाजवादी जनतन्त्र का विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर को उठाना, अन्तर्राष्ट्रवादी विचारधारा एवं दृष्टिकोण का विकास, साम्यवाद का प्रसार आदि।

इस प्रकार सोवियत प्रशासन की तानाशाही का आधार साम्यवादी दल की तानाशाही है। सोवियत रूस में एक ही दल की तानाशाही है। दल ही सरकार है। प्रत्येक सरकारी संस्था में साम्यवादी दल की समानांतर शाखा है। हार्पर (A) ने ठीक ही कहा है कि “दल तथा सरकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। साम्यवादी

मे इन दोनों को पृथक् नहीं किया जा सकता।" जॉन हेयड ने लिखा है कि "सोवियत राज्य की दलीय नीति का रबर स्टाम्प है।"

साम्यवादी दल का संगठन (Organization of Communist Party)

साम्यवादी दल के संगठन का स्वरूप एक पिरामिड के समान है। इसका आधार व्यापक एवं विस्तृत होता है जो कि शीर्ष की ओर संकुचित होता जाता है। साम्यवादी दल के संगठन का आधार जनतंत्रीय केन्द्रवाद है जिसमें उत्तरदायित्व की शृंखला नीचे से ऊपर की ओर और आना का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आँग तथा जिक ने कहा है "कि इस दल का संगठन इस समय सप्तर के किसी भी राजनैतिक दल की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।"¹ साम्यवादी दल के संगठन में सोवियत पद्धति का ही अनुकरण किया गया है। टाउटस्टर के अनुसार दल का संगठन क्षेत्रीय उत्पादन के आधार पर खड़े किए गये पिरामिड के समान है। साम्यवादी दल का संगठन समष्टि एवं सामूहिक भावना का प्रतीक है। दलीय संगठन की इकाइयाँ इस प्रकार हैं—

(1) प्रारम्भिक इकाइयाँ (Primary Units)—साम्यवादी दल के संगठन की इन प्रारम्भिक इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें कोशिकाएँ (Cells) कहा जाता है। ये संगठन की आधारभूत इकाइयाँ हैं। ये प्रत्येक कारखाने, दुकान, फक्ट्री, आफिस, श्रमिक काम, स्कूल तथा सैनिक टुकड़ियों में पाई जाती हैं। इनके आकार में भिन्न होता है। किन्तु प्रत्येक इकाई में कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्रत्येक कोशिका की एक कार्यकारिणी तथा सचिव होता है। सचिव के ही हाथों में वास्तविक शक्ति होती है और वह ही इस संगठन का अध्यक्ष होता है। इस समय इस प्रकार की इकाइयों की संख्या लगभग 25000 है। दल की इन प्रारम्भिक इकाइयों के कार्य इस प्रकार हैं—

1 दलीय निधियों को लागू करना एवं मजदूरों को संगठित करके आन्दोलन का संचालन करना।

2 नवीन सदस्यों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

3 उत्पादन योजना तथा समाजवादी प्रतियोगिता के लक्ष्य की पूर्ति करना।

4 फैक्ट्रियों तथा उद्योग धंधों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके उनमें कार्यकुशलता का विकास करना।

5 सदस्यों में आलोचना तथा प्रत्यालोचना की भावना भरना।

यदि प्राइमरी यूनिट की सदस्य संख्या 150 से अधिक है तो उसके लिये सचिव का पद वृत्तनिक भी हो सकता है। इन इकाइयों का प्रमुख कार्य सोवियत रूप के राजनैतिक जीवन में सक्रिय भाग लेना है।

(2) उच्चतर इकाइयाँ (Higher Units) प्रारम्भिक इकाइयों के ऊपर नगर तथा जिले के दल के सम्मेलन होते हैं। ये नगरीय तथा जिलों में पृथक् पृथक् कार्य करते हैं। इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रारम्भिक इकाइयों द्वारा होता है। नगर तथा जिला

¹ The organization of the communist party is probably more elaborate than that of any political group in the world at the present time — Ogg & Zloc

सम्मेलनों का अधिवेशन वष में कम से कम एक बार अवश्य होता है। प्रत्येक सम्मेलन के पास एक 'ब्यूरो' तथा तीन-तीन सचिव होते हैं। इन सम्मेलनों के सचिव प्रारम्भिक इकाइयों के साथ बराबर सम्पर्क बनाये रहते हैं। ब्यूरो सम्मेलन की कार्याकारी परिषद होती है। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं— यह प्रारम्भिक इकाइयों को निर्देश देती है, स्थानीय सभाचार पत्रों के सम्पादकों की नियुक्ति करती है, ट्रेड यूनियन तथा ओर्गैनेटिव युवक सगठन आदि दलीय सगठनों के कार्यों का निरीक्षण करती है।

(3) क्षेत्रों, प्रदेशों तथा सघीय गणराज्यों के स्तर के सगठन (Organization for Areas, Regions and Union Republics)—नगरो तथा जिलों के ऊपर क्षेत्रों, प्रदेशों तथा सघीय गणराज्यों के स्तर के साम्यवादी दलों का सगठन आता है। इनके सदस्य जिला तथा नगरो के सम्मेलनों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन सभी सगठनों में एक संस्था सामान्य रूप से होती है जिसे कॉन्फ्रेंस (Conference) कहा जाता है। सघीय गणराज्यों में इसे कांफ्रेंस कहा जाता है। प्रत्येक कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक कार्यकारिणी का निर्वाचन होता है जिसे 'ब्यूरो' कहा जाता है। यह पूरे वष कार्यरत रहती है। वास्तविक कार्य 4 या 5 मंत्रियों द्वारा सम्पादित होता है जिसके सदस्यों का निर्वाचन कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही होता है। यह सभाचार पत्र, ट्रेडयूनियनों, सहज साम्यवादी लीग रेडियो प्रसारण, शिक्षा संस्कृति तथा क्षेत्रीय एवं गणराज्यीय स्तर की सहकारी समितियों पर नियंत्रण स्थापित करती है। जीवन स्तर में वृद्धि करना औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आदि इसके लक्ष्य हैं। ये समितियाँ साम्यवादी व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाये रखती हैं।

(4) अखिल सघीय कांग्रेस (All Union Congress)—इन क्षेत्रीय समितियों के ऊपर अखिल यूनियन कांग्रेस का सगठन (All Union Congress) है जिसके सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों तथा सघीय गणराज्यीय स्तर की कांग्रेसों द्वारा होता है। सिद्धांततः दल की सर्वोच्च सत्ता इसमें निहित है। प्रत्येक 1000 सदस्यों पर इसके लिए एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। अखिल यूनियन कांग्रेस के कार्य इस प्रकार हैं—1 केन्द्रीय समिति के सदस्यों का निर्वाचन, 2 साम्यवादी दल की सामान्य नीतियों का निर्धारण, 3 पुरानी नीतियों में परिवर्तन, 4 गृह तथा वैदेशिक नीति पर विचार। अखिल सघीय कांग्रेस का अधिवेशन चार वष में एक बार होता आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/2 भाग ही उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अधिवेशन केन्द्रीय समिति द्वारा अथवा अपने सदस्यों के 1/3 बहुमत द्वारा आमंत्रित किये जा सकते हैं।

(5) साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति (Central Committee of the Communist Party)—केन्द्रीय समिति के सदस्यों का निर्वाचन अखिल सघीय कांग्रेस के द्वारा सम्पन्न होता है। यह अखिल सघीय कांग्रेस के अधिवेशनों के अंतराल में उसके कार्यों का सम्पादन करती है। सन् 1966 में इसमें 133 पूर्ण सदस्य तथा 122 वैकल्पिक सदस्य थे। छह मास में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। यह साम्यवादी दल के समस्त कार्यों का सम्पादन करती है। दल के अनेक सगठन स्थापित करती है। बड़ी संस्थाओं के दलीय अंगरंगों का सम्पादन करती है। दल की शक्तियों एवं

साधनों का विभाजन करती है। यह केन्द्रीय कोष की भी व्यवस्था करती है। यह सावियत सघ की अग्र दलीय इकाइयों को निर्देश देती है तथा उनके कार्यों का ब्योरा लेती है। यह दल तथा सरकार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह केन्द्रीय समिति के द्वारा साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम का निर्वाचन भी करती है। *Presidium of the Central Committee of the Communist party* में पोलिट ब्यूरो तथा ओरिग ब्यूरो दोनों को मिला दिया गया है।

(6) पोलिट ब्यूरो (Polit Bureau)—इसे साम्यवादी दल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। स्टालिन ने पोलिट ब्यूरो तथा ओरिग ब्यूरो दोनों को मिलाकर साम्यवादी दल के प्रेसीडियम की रचना की थी जिसमें 25 सदस्य थे। किंतु 1966 में साम्यवादी दल की तेइसवीं कांग्रेस ने प्रेसीडियम को समाप्त करके उसके स्थान पर पोलिट ब्यूरो की स्थापना की। इसके सदस्यों की संख्या 11 निश्चित की गई। ओरिग ब्यूरो को पुनः स्थापित नहीं किया गया। पोलिट ब्यूरो में साम्यवादी दल के चोटी के नेता होने हैं। सरकारी प्रेसीडियम, मंत्रिपरिषद, तथा उच्चतम न्यायालय में किन किन व्यक्तियों को रखा जाय इसका निश्चय पोलिट ब्यूरो करती है और सर्वोच्च सावियत उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा देती है। पोलिट ब्यूरो ही दलीय नीति का सर्वोक्षण एवं निश्चय करती है। सघ का प्रीस्यूटेर जनरल कौन व्यक्ति हो इसका नियम भी इसी के द्वारा होता है। माक्स स्टालिन ने इसे सत्ता सम्पन्न सत्ता कहा है। उन्हीं के शब्दों में 'यह राज्य का ही सर्वोच्च अंग नहीं अपितु दल का भी सर्वोच्च अंग है। यह राज्य की सबसे बड़ी भागदशक सत्ता है।' ¹ दल की वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में है। सरकार इसके द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुकरण करती है।

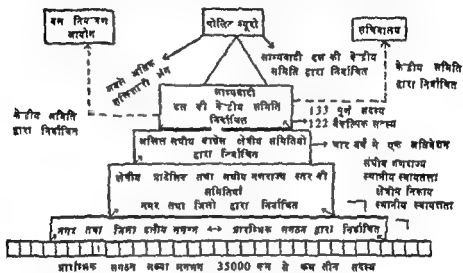
(7) सचिवालय (Secretariat)—इसमें एक महासचिव तथा अग्र चार सचिव होते हैं। यह दल का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसका प्रेसीडियम मंत्रिपरिषद तथा दल की पोलिट ब्यूरो पर विशेष प्रभाव होता है। इस समय ब्रिजनेव साम्यवादी दल के महासचिव हैं। सचिवालय के सदस्यों की संख्या 11 है। संख्या में कमी तथा अधिकता भी हो सकती है। सचिवालय साम्यवादी दल का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। महासचिव उन सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है जो दलीय अनुशासन को भंग करते हैं। स्टालिन प्रधानमंत्री तथा महासचिव दोनों पदों पर आसीन थे इसीलिए जीवनपथ तत्काली राजनीति पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सफल हुए थे। साम्यवादी दल में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं है।

(8) दल नियंत्रण आयोग (Party Control Commission)—केन्द्रीय समिति द्वारा निर्वाचित एक और भी निकाय दल नियंत्रण आयोग है। यह भी दल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य यह देखना है कि दल के सदस्य अनुशासन में रह कर उसकी नीतियों का गम्भीरतापूर्वक पालन करते हैं अथवा नहीं। दलीय

1 The Polit Bureau is the biggest organ not only of the state but of the party and party is the biggest directing force of the state

अनुशासन भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यह कठोर कार्यवाही करता है तथा उन्हें दण्ड देता है। यह दल के निम्न संगठनों द्वारा किए गये निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनता है। पहले इसका निर्वाचन अखिल सघीय कांग्रेस करती थी परन्तु अब इसका निर्वाचन साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के द्वारा किया जाता है। साम्यवादी दल के संगठन को निम्नांकित रेखाचित्र से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है—

साम्यवादी दल के संगठन का रेखाचित्र



साम्यवादी दल का स्थान (Position of the Communist Party)

साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता उसका मोनोलिथिक अथवा एकात्मिक स्वरूप है किन्तु यह सिद्धांत में ही सही है। यद्यपि स्टालिन ने एक बार कहा था कि "हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दल सत्ताधारी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पारस्परिक मनमुटाव देश में हमारे प्रभाव को कम कर सकते हैं और विदेशों में इसका क्या प्रभाव होगा उसके विषय में तो जो भी कहा जाय वह थोड़ा ही है।" परन्तु साम्यवादी दल की यह स्थिति उस समय तक ही रही जब तक कि स्टालिन जीवित रहा एवं वह प्रधानमन्त्री तथा साम्यवादी दल के महासचिव पद पर बसा रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत साम्यवादी दल में शक्ति के लिए छुश्चेव, बुलगानिन, मैलनकोव तथा बरिया आदि में संघर्ष हुआ। बरिया के प्रभाव को उखाड़ फेंका गया और उसे गोली मार दी गई। इसके पश्चात् छुश्चेव शक्ति में आया और उसने सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए यह मानना असत्य ही है कि साम्यवादी दल में परस्पर विरोध एवं द्वेष के लिए स्थान नहीं है। सन् 1929 के पश्चात् स्टालिन ने केवल ट्राट्स्की की शक्ति का ही मूलोच्छेदन नहीं किया अपितु उन समस्त बड़े नेताओं को समाप्त कर दिया जो उसके विरोधी हो सकते थे। परन्तु सोवियत रूस में केवल साम्यवादी दल को ही भाष्यता दी गई है और विरोधी दलों के पनपने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि साम्यवादी दल में अधिक राजनैतिक दलों को उग व्यवस्था का सूचक कहा गया है।

परन्तु फिर भी साम्यवादी दल का मूल्यांकन हम निम्नलिखित परिवेष्टियों में कर सकते हैं।

साम्यवादी दल रक्षक तथा सृजक के रूप में (As an Architect and Defender of Revolution)—साम्यवाद की प्रथम बार स्थापना सोवियत रूस में हुई। रूसी राज्यक्रांति (1917) का निर्माता लेनिन था जिसने दो मोर्चों पर जार शासन तथा विदेशी पूँजीवादी शक्तियों से—एक साथ लड़कर विजय प्राप्त की। बड़ी कठिनाइयों का सामना करके रूसी लाल सेना ने विदेशी सेनाओं को परास्त करके क्रान्ति विरोधी तत्वों को नष्ट किया। समय समय पर दल में जो अन्तर्विरोध उत्पन्न होते रहे उनका भी दृढ़तापूर्वक मुकाबिला किया गया। ट्राट्स्की जो स्टालिन ने पहले तो देश से बाहर निकाल दिया और बाद में उसकी हत्या ही करवा दी। द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसके बाद की परिस्थितियों का साम्यवादी दल ने दृढ़तापूर्वक मुकाबिला किया। आज सोवियत रूस विश्व की एक महान ताकत है। रूस ने विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उन्नति की है उसका एकमात्र श्रेय साम्यवादी दल को है। इतने कम समय में विश्व की महान शक्ति का स्तर प्राप्त करना कोई कम उपलब्धि नहीं है। साम्यवाद सोवियत रूस का राजनैतिक धर्म है, जिसकी उपेक्षा साम्यवादी दल वर्दाश नहीं कर सकता। साम्यवादी दल क्रान्ति का रक्षक तथा मार्क्सवादी विचारधारा का परम शिक्षक है।

दल एक शिक्षक तथा प्रेरणा स्रोत के रूप में (Party as an Educator and Source of Inspiration)—साम्यवादी दल ने जनता में त्याग तथा श्रम की भावना फूट फूट कर भरी। सोवियत साम्यवादी दल ने उत्तरदायित्व की भावना का एक महान परिचय भी दिया। सोवियत जनता को मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में प्रवीण किया। अपने आदर्श आचरण से जन समुदायों को प्रभावित किया। रचनात्मक कार्य को अपना उद्देश्य बनाया। कई युवक समूहों द्वारा साम्यवाद की शिक्षा दी गई। वैद दम्पति ने कहा है कि विभिन्न समुदायों के माध्यम से साम्यवादी दल ने जन मानस पर अच्छा प्रभाव डाला है। मविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत साम्यवादी दल को श्रमिकों का अग्रदूत कहा गया है। देश में वगबिहीन समाज की स्थापना से जनता में धार्मिक एवं सामाजिक शोषण करना बंद किया गया। रूस में जो प्रथम विश्व युद्ध के समय भूखमरी फैली हुई थी उसे एक संगठित अर्थव्यवस्था से दूर किया गया तथा एक नवजीवन की सृष्टि की गई। विश्व के श्रमिकों के लिये एक अलौकिक एकता का आदर्श प्रस्तुत किया गया।

साम्यवादी दल तथा सरकार (Communist Party & the Government)—साम्यवादी दल तथा सरकार के मध्य इतनी घनिष्ठता है कि हम दोनों को पृथक् नहीं कर सकते। दल सरकार है और सरकार ही दल है जिस प्रकार हम व्यावहारिक जीवन में राज्य तथा समाज के अन्तर की उपेक्षा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम राज्य तथा सरकार के अन्तर की चिन्ता नहीं करते। इसी घनिष्ठता पर दृष्टिपात करते हुए ऑग तथा जिक ने कहा है कि “सोवियत रूस में दल तथा सरकार में इतना अटूट सम्बन्ध है कि यह कहना असम्भव ही है कि दल का कार्य कहाँ से आरम्भ होता है। प्रायः एक व्यक्ति दल और सरकार के उच्च पदों पर आसीन

रहता है। अतएव यह ज्ञात करना ही असम्भव हो जाता है कि वे कब तो दल के नेता के रूप में कार्य करते हैं और कब दल के सरकारी अधिकारी के रूप में।

वैधानिक रूप से तो सोवियत रूस में ससदीय प्रणाली अपनाई गई है परंतु विरोधी दल की अनुपस्थिति में वह हास्यास्पद ही लगती है। सोवियत रूस में निर्वाचनों की व्यवस्था सोवतंत्र के मुख पर एक तमाचा है क्योंकि जनता की एक ही प्रत्याशी के पक्ष में ही या ना का नियम करना होता है। निर्वाचनों पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सरकार के ही समानांतर साम्यवादी दल के संगठनों का कार्य एक उनका स्वरूप रखा गया है। सरकारी निकायों में उनका निरंतर हस्तक्षेप बना रहता है। साम्यवादी दल इस प्रकार से सरकार पर आच्छादित है कि हम दोनों की पहचान नहीं कर पाते। सरकार के समस्त नियम साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो के द्वारा ही किये जाते हैं और सर्वोच्च सोवियत उस पर केवल अपनी रबर की मोहर मात्र लगाती है। साम्यवादी दल के प्रमुख सरकार का भी नेतृत्व करते हैं। हम इस बात से सोवतंत्र की मात्रा की कल्पना कर सकते हैं कि सवा घंटे की अवधि में लगभग 180 पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्पन्न हो गया। सर्वोच्च सोवियत के सदस्य विधायक कम तथा साम्यवादी विचारधारा के प्रचार अधिकारी एवं एजेंट अधिक होते हैं। प्रेसोडियम तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो के द्वारा रिया जाता है। सरकार तो साम्यवादी दल की शिष्यामात्र है, उसकी सेविका है अथवा उसका यंत्र मात्र है। सर्वोच्च सोवियत की बाहर दीवारी में विरोध जैसी कोई बात नहीं है। मंत्रियों की नियुक्त हो या निष्कासन सभी का नियम साम्यवादी दल के द्वारा ही होता है। प्रोव्यूरेटर जनरल की नियुक्त सर्वोच्च सोवियत द्वारा केवल एक औपचारिकता है। यह साम्यवादी दल का भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। सुप्रीम कोर्ट के 'यायाघीशा' के नामों का नियम भी साम्यवादी दल के द्वारा ही होता है। वहाँ 'यायपालिका' को साम्यवाद विरोधी तरफों को उखाड़ फेंकने का एक साधन मात्र ही माना गया है। अतएव सरकार साम्यवादी दल अथवा सबहारा वग की तानाशाही स्थापित करने का एक साधन मात्र ही है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। 'यायपालिका' को सरकार के एक अंग के रूप में रखा गया है। स्टालिन ने नवीन संविधान की आलोचना करने वालों को मुंहतोड़ उत्तर देने हुए कहा था कि 'मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि नया संविधान सोवियत रूस के साम्यवादी दल की प्रभुता को ज्यों का त्यों बना रहने देता है। यदि हमारे आलोचक इसे संविधान की एक कमी मानते हैं तो केवल यह खेदजनक है। इसीलिये फाइनर का यह कथन सही है कि "साम्यवादी दल सोवियत यूनियन का सावभौमिक शासक है।" ¹ सोवियत रूस में साम्यवादी दल की तानाशाही है। फाइनर के शब्दों में 'सोवियत यूनियन अब भी एक तानाशाही है परंतु वह थोड़ी सी विशेषिक अति-नायकतंत्र है।' ²

1 Communist party is sovereign ruler of the Soviet union

—Finer

2 The Soviet union is still a tyranny but a slightly qualified dictatorship

Major Government p 690

—Finer

क्या सोवियत संविधान जनतन्त्रात्मक है ?

(Is Soviet Constitution Democratic)

किसी भी देश के संविधान की वास्तविकता को केवल उसके लिखित रूप मात्र से ही नहीं जाना जा सकता। संविधान की वास्तविकता उसका व्यावहारिक स्वरूप एवं नीतियों का निष्पादन है। वस्तुतः सोवियत संविधान जनतांत्रिक है अथवा नहीं, इसका निश्चय करना कठिन कार्य ही है। यह कठिन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। लोकतंत्र स्वयं के विषय में पश्चिमी दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। किंतु यह एक विवादास्पद प्रश्न ही है कि सोवियत रूस में जनतंत्र है अथवा नहीं। सन् 1936 के सोवियत संविधान के प्रमुख निर्माता जोसफ स्टालिन ने हावड से कहा था कि 'मेरे विचार से हमारा नवीन संविधान विश्व में सबसे अधिक जनतंत्रीय संविधान होगा।'¹ इसके विपरीत आग तथा जिक ने कहा है कि "यदि सोवियत संघ में प्रजातंत्र है तो केवल साम्यवादी दल के सब शक्तिशाली होने में ही है।"² एक लेखक के अनुसार "यदि रूसी प्रजातंत्र को लोकतंत्र कहा जा सकता है तो बक के इस कथन में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि पूरा प्रजातंत्र संसार में सर्वाधिक लज्जाहीन वस्तु है।"³ बब वेम्पसि (Sydney Webb and Betric Webb) ने रूस को सर्वाधिक समाविष्ट तथा समानतापूर्ण प्रजातंत्र (The most inclusive and equalised democracy) कहा है। बहुत से रूसी विचारकों का निश्चित कथन है कि उनका प्रजातंत्र पूँजीवादी प्रजातंत्र से हजारों गुना उत्तम है। इसका मूल कारण यह है कि साम्यवादी आर्थिक लोकतंत्र को राजनैतिक लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानते हैं। कुछ राजनैतिक लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। रूसी जनक्रान्ति पर टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए अनातोले फ्रांस ने कहा था कि "यार्याप्रय लोगों को उस क्रान्ति के सामने सिर झुकाना चाहिए जिसने पहली बार जनता द्वारा और जनता के लिए शासन की स्थापना की है।" मुनरो (Munro) ने दूसरी ओर कहा है कि "स्टालिन संविधान ने बाह्य रूप से जनतंत्र का निर्माण किया है परंतु वास्तव में वहाँ जनतंत्र नहीं है।" इसलिए यह प्रश्न बड़ा ही विवादास्पद है कि रूस में जनतंत्र है अथवा नहीं।

इस विवाद का केवल एक ही हल है कि हम पहले लोकतंत्र की कसौटी निश्चित करें, तत्पश्चात् हम उस कसौटी पर सोवियत रूस की साम्यवादी व्यवस्था को कस कर देखें कि वह किस सीमा तक जनतांत्रिक है। लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत निम्नांकित हैं—

(i) राजनीतिक समानता।

(ii) स्वतंत्रता।

(iii) नीति निर्धारण करने वाली नीतियों पर जनता का नियंत्रण।

(iv) बहुमत का नियम।

- 1 In my opinion our new constitution will be the most democratic constitution in the world —Joseph Stalin
- 2 If this be democracy it is strictly within the Iron framework of the communist monopoly of power —Ogg & Zink
- 3 A perfect democracy is the most shameless thing on the earth —Burke

अतएव, राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में घासकीय सगठन लोकतन्त्रात्मक होना चाहिए। यद्यपि इन आधारों को भी अंतिम रूप से लोकतन्त्र के आधारभूत तत्व नहीं कह सकते परन्तु फिर भी हम इसे सोवियत संविधान की लोकतन्त्रात्मकता निश्चित करने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। विशिस्की ने सोवियत लोकतन्त्र के विषय में कहा है, “रूस में उच्च प्रकार का लोकतन्त्र है।” रूस के लोकतन्त्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

लोकतन्त्र के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Democracy)

(i) ससदीय प्रणाली (Parliamentary Government)—सोवियत संविधान में ससदीय प्रणाली को अपनाया गया है। केवल केन्द्र में ही नहीं अपितु सघीय गणराज्यों तथा स्वायत्त गणराज्यों आदि में भी ससदीय प्रणाली को अपनाया गया है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही निर्वाचित किये जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। कायपालिका का सिद्धांत रूप से विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होना भी ससदीय लोकतन्त्र का लक्षण है। यह जनतन्त्रीय तत्व है।

(ii) वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)—सोवियत रूस में एक बहुत बड़ी लोकतन्त्रीय पद्धति का अनुकरण किया गया है और वह है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। सोवियत रूस में प्रत्येक उस व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है जिसने 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करली है तथा 23 वर्ष का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च सोवियत के लिए निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। सघीय गणराज्यों में आयु की यह सीमा केवल 21 वर्ष रखी गई है। वयस्क मताधिकार लोकतन्त्र की बहुत बड़ी कसौटी है।

(iii) प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा गुप्त मतदान प्रणाली (Direct Election and Secret Ballot)—सोवियत रूस में प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यह जनतन्त्र के लिए आवश्यक है। मतदाता निर्वाचनों में विशेष रुचि लेते हैं। सामान्यतः वहां 90% मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो यह संख्या 97% तक पहुँच जाती है। पश्चिमी लोकतन्त्रीय देशों के निर्वाचनों में 50% से लेकर 80% तक मतदान होता है। इतना विशाल मतदान मतदाताओं की निर्वाचना में अभिरुचि का सूचक है। सोवियत रूस में तो यायाव्रीशों तक का निर्वाचन होता है।

(iv) द्वितीय सदन (Second Chamber)—बहुधा द्वितीय सदन का प्रयोग लोकतन्त्र में विशिष्ट हिता का प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका तथा भारत आदि देशों में द्वितीय सदन की व्यवस्था है। परन्तु सोवियत रूस में इसका प्रयोग किसी वग विशेष को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से नहीं किया गया है अपितु उसमें राष्ट्रीयताओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है। वैसे मेरी दृष्टि से वगविहीन समाज में द्वितीय सदन का कोई शक्तिशाली औचित्य नहीं है।

(v) मौलिक अधिकार तथा आर्थिक सुरक्षा (Fundamental Rights and Economic Security)—मौलिक अधिकारों का जितना व्यापक विवेचन सोवियत संविधान में किया गया है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसमें मौलिक अधिकारों

की लम्बी सूची दी गई है। मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कतव्यों का भी उल्लेख किया गया है। यदि अधिकारों के द्वारा नागरिकों में चेतना की उत्पत्ति हो सके, उन्हें व्यक्तित्व विकास की विविध सुविधाएँ भी मिल सकें तो यह लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है किंतु उन्हें प्रचार करने का अधिकार नहीं दिया गया है। नागरिकों को भेदभाव के बिना सम्पत्ति आदि का अधिकार भी दिया गया है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार भी दिया गया है। संविधान अनुच्छेद 125 में नागरिकों को भाषण, प्रसंगित होने तथा जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 128 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दी गई है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार (Right to Work) है जो हमें पूँजीवादी देशों में सुनने तक को नहीं मिलता है। इससे बढ़कर लोकतंत्र की कसौटी क्या होगी? सोवियत संविधान के अनुच्छेद 118 ने इस अधिकार को स्वीकार करके देश में बेरोजगारी की समस्या को सदैव के लिए नमस्कार कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद 119 के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो कि सोवियत नागरिकों को दिया गया है वह है आराम तथा अवकाश प्राप्त करने का अधिकार (Right to Leisure)। मजदूरों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को पूर्ण रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अमेरिका में मौलिक अधिकारों का आधार व्यक्तिवाद है और सोवियत रूस में उनका लक्ष्य समाजवाद की उपलब्धि है। सिडनी तथा बट्रिक बैंब ने लिखा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्वाचन यंत्र का पुनर्निर्माण ही नहीं अपितु मानव अधिकारों की नई सूची है।"

(vi) सामूहिक नेतृत्व (Collective Leadership) — सोवियत व्यवस्था के लोकतंत्रीय होने के पक्ष में एक तक यह दिया जाता है कि वहाँ स्टालिन के समय का आतंक समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का विकास हो रहा है। सामूहिक नेतृत्व जनतंत्रीय व्यवस्था का लक्षण है।

(vii) आर्थिक लोकतंत्र (Economic Democracy) — आर्थिक लोकतंत्र से अभिप्राय उस अव्यवस्था में है जहाँ मजदूरों को आने वाले कल की जीविका के विषय में चिंतित नहीं रहना पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयों एवं विषम जीवन से मुक्ति ही आर्थिक लोकतंत्र है। जो कि सोवियत रूस में उपलब्ध है। सोवियत भूमि में शोषण तो क्या उसके स्मृति चिह्नों को भी सदैव के लिए नष्ट कर दिया गया है। स्टालिन ने ठीक ही कहा था कि ऐसे समाज में जहाँ लोगों को रोटी, कपड़ा तथा आवास की चिंता से मुक्त कर दिया जाय तो वहाँ जनता को स्वतंत्रता कागजों पर नहीं अपितु वास्तव में ही प्राप्त होती है। सोवियत कणधारों की यह मायता आरम्भ से रही है कि जिस समय तक आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा उस समय तक राजनैतिक लोकतंत्र अवास्तविक तथा पूँजीवादी ही बना रहेगा। रूस में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना तो मिलता ही है जिससे मनुष्य मनुष्य ही रह सके, तत्परचात् प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पारिश्रमिक भी दिया जाता है। राष्ट्र की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति पर समाज का अधिकार है। वहाँ पूँजीपतिवादी देशों के

है। साम्यवादी दल का स्वरूप तब समाज का स्वरूप है। निर्वाचनों में मतदाताओं को वैकल्पिक उम्मीदवार नहीं मिलते। विरोधी विचार वहाँ कभी नहीं सुन जाते। विरोधी दलों की अनुपस्थिति लोकहित विरोधी है।

2 ससदीय सरकार केवल एक दिखावा मात्र है (Parliamentary System is Simply Exhibitory)—सोवियत रूस में साम्यवादी दल निगम लेता है और सरकार उन नियमों को कार्यान्वित करती है। वहाँ ससदीय प्रणाली केवल एक दिखावा मात्र ही है। वह केवल वागज पर ही है, यथार्थ में नहीं। मन्त्रिपरिषद् का निर्वाचन होता है। यह ससदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है। मन्त्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व भी उनके प्रति नाममात्र का है। वस्तुतः उसका उत्तरदायित्व साम्यवादी दल के प्रति ही है। सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन वष में केवल एक बार ही होता है और वह भी 15 या 20 दिन से अधिक की अवधि तक नहीं रहता। इस अवधि में ससद कितना काम कर सकती है, यह सरलतापूर्वक कल्पनीय है। व्यवहार में इसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रेसीडियम करती है।

(3) स्वतन्त्र न्यायपालिका का अभाव (Lack of Independent Judiciary) लोकतन्त्रीय देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को आवश्यक समझा जाता है। सोवियत रूस में न्यायपालिका के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। वहाँ न्यायपालिका को सरकार के एक अंग के रूप में साम्यवाद विरोधी तत्वों का दमन करने के लिये रखा गया है। वहाँ न्यायपालिका का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है।

(4) निर्वाचन पद्धति जनतन्त्रीय नहीं है। (Election System is not Democratic)—सोवियत रूस में निर्वाचन पद्धति अवास्तविक है। वहाँ सहकारी समितियों, ट्रेड यूनियनों तथा साम्यवादी दल को निर्वाचन में उम्मीदवार सँभल करने का अधिकार है। महकारी समितियों तथा ट्रेड यूनियनों पर भी साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है। वस्तुतः ये सब मिलकर एक ही उम्मीदवार खड़ा करती हैं। ऐसी स्थिति में लोकतन्त्र बस वास्तविक रह सकता है। वहाँ निर्वाचन साम्यवादी दल के आतंक से पीड़ित रहते हैं। सम्भवतः इतना व्यापक मतदान का प्रतिशत स्वेच्छा से कम तथा कम से अधिक रहता है। इतने विशाल पैमाने पर अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है।

(5) लोकतन्त्रीय केन्द्रवाद में लोकतन्त्र कम तथा केन्द्रवाद अधिक है (In Democratic Centralism there is more Centralism and less Democracy)—ग्रूमन ने अपनी पुस्तक *European and Comparative Governments* में लिखा है कि “सोवियत शासन प्रणाली एक पूर्ण नियन्त्रित राज्य का प्रयोग करती है जिसमें अत्यन्त कुछ व्यक्ति एक राजनैतिक विचारधारा के अनुसार ही यह निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य का सभी छोटे-बड़े अंगों तथा नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोवियत सामग्रीय व्यवस्था में केन्द्रवाद की मात्रा इतनी अधिक है कि वास्तव में उसमें उसकी जनतन्त्र भाषा कराह उठती है। आज तक किसी भी मदीय इकाई ने मध्य में सम्बन्ध विच्छेद करने की बात नहीं कही। अतः सोवियत रूस में केन्द्रवाद अधिक और लोकतन्त्र कम है।

(6) प्रचार द्वारा शासन (Government by Propaganda)—साम्यवाद में प्रचार पर अधिक बल दिया जाता है। प्रचार के द्वारा शासक वर्ग जनता के मस्तिष्क एवं विचारों पर नियंत्रण बनाये रखता है। देश के अन्दर नीति विषयक निर्णय करने का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रहता है। साम्यवादी दल का प्रचार इतना व्यापक एवं संगठित होता है कि जनता वास्तविकता को भूलकर उससे गुमराह हो जाती है। शासक वर्ग के विचार जनता के ऊपर लाद दिये जाते हैं। जनता के समक्ष विरोधी विचार नहीं रखे जाते। एक ही प्रकार के विचार जनता को स्वीकार करने पड़ते हैं। विचारों की स्वतन्त्रता के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता।

निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि रूसी लोकतन्त्र के विपक्ष में तक कम सबल नहीं हैं किन्तु उससे हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि वहाँ लोकतन्त्र का नामोनिशान ही नहीं है और वह एक दम अधिनायकवादी ही है। बनहम रूसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक मानता है परन्तु उस मैनेजेरियल राज्य कहता है। यह समझना भी कठिन है कि क्या पश्चिमी लोकतन्त्र को अंतिम आदर्श मानकर उसके आगे उस पर विचार ही न किया जाय। क्या हम रूसी लोकतन्त्र को इस आधार पर लोकतन्त्र स्वीकार नहीं करें क्योंकि वहाँ पर स्टालिन ने एक अधिनायक के रूप में दीर्घकाल तक शासन किया? किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् तो सामूहिक नेतृत्व का विकास होता जा रहा है जो जनतन्त्र के आदर्श के ही अनुकूल है। भारत की राजनीति पर भी श्री जवाहरलाल नेहरू का जीवनकाल प्रमुख रहा और आज भी श्रीमती गांधी की सूती बोलती है और उनका सिक्का चढ़ा हुआ है किन्तु फिर भी हम भारतीय व्यवस्था को तानाशाही नहीं कहते। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की स्थिति एक तानाशाह से कम नहीं है।

सोवियत लोकतन्त्र के विरुद्ध पश्चिमी आलोचकों को इस तक में भी खोखलापन है कि वहाँ व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ व्यक्तित्व विकास की सुविधाएँ नहीं हैं। परन्तु यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि इन असुविधाओं के होते हुए भी सोवियत रूस विज्ञान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विश्व के किसी राष्ट्र से पीछे नहीं रहा है। बिना स्वतन्त्रता प्रदान किए हुए शोध एवं अन्वेषण की कल्पना करना ही व्यर्थ है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र में सोवियत रूस सबसे आगे है। यदि आर्थिक लोकतन्त्र के लिए कुछ राजनैतिक लोकतन्त्र का परित्याग करना भी पड़े तो उसे सहन किया जा सकता है। यदि लोकतन्त्र से अभिप्राय भूल सदन तोड़ना तथा भ्रष्टाचार का प्रसार करना है तो रूस में लोकतन्त्र नहीं है। यदि मौलिक अधिकारों से अभिप्राय केवल कागजी कायवाही से है तो भी रूसी लोकतन्त्र, लोकतन्त्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वस्तुतः वहाँ पर एक नवीन प्रकार का ही लोकतन्त्र है। जॉन एडम्स ने कहा है कि 'पश्चात्य देशों में राजनैतिक लोकतन्त्र स्थापित किया गया है और वे कुछ मात्रा में समाजवाद को भी प्रयुक्त करते हैं परन्तु रूसियों ने वास्तविक समाजवाद स्थापित किया और कुछ लोकतन्त्र की भी स्थापना की है।'¹

1 The westerners have political democracy and practise some socialism the Russians have socialism and some form of Democracy —John Adames

Select References

- Munro *Govts of Europe*
 Towster : *Political Power in U S S R*
 Carter : *Govt of the Soviet Union*
 Neumann *European & Comparative Govts*
 Ogg & Zink : *Modern Foreign Govts*
 Finer *Major Govts of Europe*
 Vyshinsky *The Law of the Soviet State*
 Karpinsky *The Social and state structure of U S S R*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 'स्टालिन संविधान में दिखावे मात्र के लिए ही लोकतन्त्र स्थापित किया गया है यथार्थ में नहीं।' (मुनरो) विवेचना कीजिए।
 (The Stalin Constitution created a democracracy in form but not in fact [Munro]—Discuss)
- 2 इस विचार की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए कि सोवियत प्रजातन्त्र एक आविर्भूत अधिनायकतन्त्र है।
 (Discuss critically the view that democracy in the U S S R is avieled dictatorship)
- 3 'सोवियत रूस में प्रजातन्त्र नहीं है।' सोवियत संघ के संविधान तथा काम पालन को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में इसके इस कथन की समीक्षा कीजिये।
 ('There is no democracy in the Soviet Union' Examine this Statement in the light of the Constitution and its working in U S S R)
- 4 सोवियत साम्यवादी दल के महत्व पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
 [Write a critical note on the role of the Communist party in the Soviet Union]
 [B V 53 66 Agra 58 P U 55 Sagar 56 Bhag 63 Vikram 62]
- 5 सोवियत संघ के साम्यवादी दल के संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस दल का शासन पर कहा तक नियंत्रण है?
 [Briefly describe the organization of the Communist party of the Soviet Union How far can this party has social Control over the Government ? [Vikram (Part II) 64]

5

लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा सघीय इकाइयों का शासन

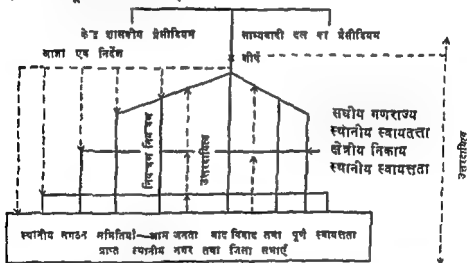
[Democratic Centralism & Administration of Federating Units]

"This term (democratic centralism) implies a combination between principles of mass participation at the bottom and the concentration of the leadership at the top"
—Neuman

परिचयात्मक— 'सोवियत संघ की शासन व्यवस्था जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद के आधार पर बनाई गई है। सोवियत रूस की जनतन्त्रात्मक केन्द्रवादी व्यवस्था पूँजीवादी राज्यों की नीकरशाही केन्द्रवादी व्यवस्था से भिन्न है।" जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद को अपनाने से पूर्व सोवियत सविधानवादियों के सामने दो सक्ष्य थे—शासन पर दल का अधिकाधिक नियंत्रण रखना जिससे क्रांतिविरोधी एवं पूँ्यकतावादी शक्तियाँ अपना सिर ऊँचा करके क्रांति को ही विफल न बना दें तथा सोवियत व्यवस्था में जनतन्त्र का समावेश इस प्रकार से किया जाय कि मौलिक स्वरूप भी नष्ट नहीं हो और वह पश्चिमी लोकतन्त्रों के लिये एक चुनौती भी सिद्ध हो सके। प्रथम सक्ष्य की पूर्ति सविधान में एकतन्त्रवाणी तत्त्वों को समाहित करके की गई तथा दूसरे सक्ष्य की पूर्ति लोकतन्त्र तत्त्वों को समाविष्ट करके की गई।

लोकतन्त्र तथा केन्द्रवाद दो विरोधी तत्त्व हैं। परन्तु सोवियत सविधान में इन दोनों को अदभुत प्रकार से एक साथ रखा गया है और वह रूस की विश्व को महत्वपूर्ण देन है। सोवियत शासकीय व्यवस्था में नागरिकों को भाग लेने तथा वाद विवाद करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। किसी भी विषय पर प्रत्यालोचन करने का यह अधिकार है। यह सोवियत सविधान का जनतन्त्रात्मक तत्त्व है। इससे अतिरिक्त शासकीय एवं दलीय संगठन में केन्द्रवाद तथा नियंत्रण की प्रवृत्ति को अपनाया गया है। जनतन्त्र से तात्पर्य जनता द्वारा शासन में भाग लेना है और केन्द्रवाद का सम्बन्ध नेतृत्व से है। लोकतन्त्र तत्त्व केन्द्रवाद में जनता की इच्छा पर सोवियत नेताओं का नियंत्रण है। शासकीय संगठन का स्वरूप एक पिरामिड के समान है। घरातल पर जनता है और उसके ऊपर सीडीनूमा अथवा संगठनात्मक इकाइयों का संगठन है। प्रत्येक उच्चतर इकाई के सदस्यों का निर्वाचन निम्नतर इकाइयों के सदस्यों द्वारा होता है। शीर्ष पर शासकीय या दलीय प्रेसीडियम है जो दल तथा शासन की नीतियों का निर्धारण करती है और अन्य निम्नतर इकाइयाँ उनका पालन करती हैं। आदेश

का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है। यही नियंत्रण सूत्र है। अनुपालन का सूत्र नीचे से ऊपर की ओर चलता है अर्थात् प्रत्येक इकाई अपने से उच्चतर इकाई से आदेश प्राप्त करके उसके अनुसार ही आचरण करती है तथा अपने आचरण के लिए उच्चतर इकाई के प्रति उत्तरदायी होती है। व तत् सत्ता शीर्ष के नेताओं के हाथों में रहती है। सोवियत रूस के इस जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद की व्याख्या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि संगठन के प्रत्येक सोपान पर तो लोकतन्त्र है परन्तु दो सोपानों अथवा संगठनों के मध्य केन्द्रवाद तथा नियंत्रण है। अतः जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद स्थानीय स्वायत्तता तथा मौलिक व्यापक प्रश्नों पर केन्द्रीय नियंत्रण का समन्वय है। लोकतन्त्रीय भूमि में यह केन्द्रवादी बीज है। अँग तथा जिक ने लिखा है कि स्थानीय इकाइयाँ अपनी मनमानी सभी कर सकती हैं जब तक कि उनके ऊपर स्थिति शासकीय अभिकृता उस पर आपत्ति नहीं करते।¹ निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से हम इसे सरलतापूर्वक समझ सकते हैं



लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा नौकरशाही केन्द्रवाद में अन्तर (Distinction between Democratic Centralism and Bureaucratic Centralism)

पश्चिमी प्रकार की नौकरशाही केन्द्रवादी परम्परा लोकतन्त्रीय केन्द्रवाद एकदम भिन्न है। नौकरशाही केन्द्रवाद में शासकीय पदाधिकारियों द्वारा जनता पर ऊपर की ओर से एकरूपता ला दी जाती है। इससे विपरीत लोकतन्त्रीय केन्द्रवाद में स्थानीय निकायों को विचार एवं क्रम की पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। स्थानीय सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में ही निहित रहती है। जनता के प्रति उन निकायों का उत्तरदायित्व होता है। नौकरशाही केन्द्रवाद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है।

1 The local units do exactly as they like as long as the agents of the government which are above do not object
—Ogg & Zink

व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद (Democratic Centralism in Practice)

सोवियत जनतन्त्रीय केन्द्रवाद के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार हैं, अतएव यह कह सकना कठिन हो जाता है कि वहाँ पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? रूसी लेखक लोकतन्त्रीय केन्द्रवाद की स्तुति करते हुए नहीं सकते और दूसरी ओर पश्चिमी आलोचक उसके पीछे इस तरीके से पड़े हैं कि वे उसका कचूर निकाल कर दम लेंगे। आँग तथा जिक ने कहा है कि 'यह विश्वास करना कठिन है कि लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद में भी लोकतन्त्र स्थापित हो सकता है। केन्द्रवाद के समान ही अब तक जितने तथ्य उपलब्ध हैं उनके अनुसार यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थानीय प्रबन्ध के विषय में किसी सीमा तक पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता अवश्य रहती है।' फैन्शॉड (Fainsbod) ने कहा है कि लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद में केन्द्रवाद को प्रधानता दी गई है। उसकी दृष्टि में यह सिद्धांत एक अच्छा खासा हास्य ही है। इसमें वास्तविकता कम तथा दिखावा अधिक है। यूर्मैन भी यही मानता है कि इसमें उत्तरदायित्व का अर्थ केवल सद्भावितक ही है, तथा वास्तविकता से उसका सम्बन्ध कम है। आलोचक निर्वाचन को भी हास्यास्पद ही मानते हैं क्योंकि वही व्यक्ति निर्वाचित होता है जिसको सोवियत नेता चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत व्यवस्था में केन्द्रीयकरण का तत्त्व अत्यन्त प्रमुख है एवं महत्वपूर्ण है। अब हमें यह देखना चाहिए कि सोवियत व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या रूप है।

सोवियत सघीय व्यवस्था में (In Soviet Federal System)

सोवियत सघीय व्यवस्था में कुछ आदर्श तो ऐसे रखे गये हैं जिन्हें देखकर पश्चिमी सघीय लोकतन्त्रीय व्यवस्था की दृष्टि भी शर्म से नीचे झुक जाय। ये आदर्श एवं प्रावधान अत्यधिक जनतन्त्रीय हैं, सम्भवतः कोई भी राष्ट्र उससे अधिक लोकतन्त्र का तत्त्व अपनी सघात्मक व्यवस्था में नहीं रख सकता। उदाहरणार्थ—

- 1 सघ की इकाइयों को केन्द्र से सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार है।
- 2 सघीय इकाइयों को सेना रखने का अधिकार है।
- 3 सघीय इकाइयाँ विदेशों से सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं।
- 4 प्रत्येक सघीय इकाई का आर्थिक नियोजन आयोग पृथक है।
- 5 प्रत्येक इकाई का अपना सविधान है।
- 6 प्रत्येक इकाई की अपनी 'याय व्यवस्था, भाषा तथा शण्डा पथक है।

उपयुक्त बातों को देखने से ऐसा लगता है कि हमसे आगे लोकतन्त्र की मजिल है ही नहीं। वास्तव में सघ की इकाइयों के पास इससे बड़ी स्वतन्त्रता होगी भी क्या ? किन्तु वास्तविकता का आभास हमें फाइनर के इन शब्दों में मिलता है कि 'सोवियत सघ एक अति केन्द्रीकृत राज्य है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतन्त्र सरकार तथा अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के पश्चात् उसका प्रमुख भुजाव उसकी राष्ट्रीय विशेषताओं को समाप्त करने की दिशा में है।' साम्यवादी वास्तविकता इस प्रकार है

1 साम्यवादी ऋतु का शासन के प्रत्येक सोपान पर प्रभुत्व है। आज तक किसी भी सघीय इकाई ने पृथक् होने की बात तो दूर रही इसकी वन्दना तक भी

नहीं की है। यदि कोई ऐसी कल्पना करता है तो उस पर देशद्रोहिता का आरोप लगाया जाता है।

2 सघीय इकाइयों को अपने सविधान में वे ही सशोधन करने की अनुमति है जिनसे केन्द्र की इच्छा का उत्सर्जन न होता हो। सविधान के द्वीय इच्छा के अनुकूल ही होना चाहिए।

3 सघीय गणराज्यों के पास केवल शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने मात्र के लिए ही सैनिक रहते हैं, विद्रोह करने के लिए नहीं।

4 आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रीय नियोजन वायोज ही वास्तविक सरकार है। प्रत्येक इकाई को इसके द्वारा अपनी योजनाओं की सम्पुष्टि कराना आवश्यक है। इसके निर्देशों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

5 केन्द्रीय प्रेसीडियम को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद् तथा सघीय गणराज्यों के प्रेसीडियमों के आदेशों को भी निलंबित कर सकती है।

6 अखिल सघ तथा सघीय गणराज्य के कानूनों में यदि मतभेद हो जाते हैं, तो केन्द्रीय कानून को ही उच्चतर एवं उपयुक्त माना जायगा।

7 यायपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसका प्रयोग सरकार के एक अंग के रूप में विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही किया जाता है।

साम्यवादी दल में लोकतन्त्रात्मक के द्रवाद (Democratic Centralism in the Communist Party)—साम्यवादी दल के संगठन का स्वरूप शासकीय संगठन के समान एक पिरामिड जसा ही है। साम्यवादी दल के संगठन में भी लोकतन्त्रात्मक के द्रवाद पाया जाता है, जिसके निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांत हैं—

1 दलीय संगठनात्मक व्यवस्था में निम्न से उच्च तक के समस्त निकायों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था।

2 दलीय निकायों का दलीय संगठन के प्रति उत्तरदायित्व।

3 कठोर दलीय अनुशासन तथा अल्पमत का बहुमत के समक्ष समर्पण।

4 उच्च निकायों के निणय निम्न निकायों पर बाध्यकारी होंगे।

ऊपर के प्रथम तीन सिद्धांतों में लोकतन्त्र प्रशंसित होता है परंतु चतुर्थ सिद्धांत उसके सारे मूलभूतों को उतार देता है। वस्तुतः साम्यवादी दल ही शासन करता है। अल्पमत के लिए बहुमत के आगे समर्पण करना हास्यास्पद ही है। समस्त दलीय निणय चोटी के नेताओं द्वारा ही लिये जाते हैं जोकि अल्पमत में ही होते हैं। किसी भी वरिष्ठ नेता की आलोचना असह्य है। शूश्वेव भी स्टालिन की तीव्र आलोचना उसकी मृत्यु के उपरांत ही कर सके। यदि आलोचना होती भी है तो उसकी अग्नि की सीमा सघीय गणराज्य तक है। केन्द्रीय नेताओं के आदेशों का सह्य पालन होता है। बाकी संगठन तो वस्तुतः ऊपर के आदेशों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फाइनर ने लिखा है कि 'साम्यवादी दल कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके मूल में जनतन्त्र ही यह स्वयं आप में तानाशाही ही है। इसका स्वरूप और इसके इरादे इसके नारे में छिपे हुए हैं।'¹

1 The Communist party is not an organization with democracy of work within its own operation. It is a dictatorship within itself —Finer

(3) सोवियतों में लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद—हमें लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद की प्रवृत्ति सोवियतों के संगठन में भी दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक सोवियत जनता द्वारा निर्वाचित है। वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता ही उनके प्रतिनिधि निर्वाचित करती है। प्रतिनिधियों को जन-उपेक्षा करने तथा अपने स्वत्वों का दुरुपयोग करने की स्थिति में प्रत्याह्वान अथवा वापिस बुलाने का अधिकार है। यह तो उसकी लोकतन्त्रीय पद्धति है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही नियुक्त होते हैं। सघीय गणराज्यों में भी उनकी नियुक्ति सोवियत द्वारा ही होती है। उसका यह भाग तो बहुत लोकतन्त्रीय है। परन्तु सोवियत व्यवस्था का द्वितीय भाग उतना ही अलोकतन्त्रीय है। केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत का नियन्त्रण सघीय इकाइयों की अत्यन्त समस्त सोवियतों पर है। केन्द्रिय प्रेसीडियम का नियन्त्रण एवं प्रभाव समस्त सोवियतों पर रहता है और इन सबके ऊपर साम्यवादी दल की पोलिट ब्यूरो अथवा प्रेसीडियम है जोकि समस्त सोवियतों का भागदशन करती है तथा उनको निर्देश देती है तथा आज्ञापितियाँ प्रसारित करती है। टाउस्टर ने कहा है कि “राजनैतिक बुद्धि, सुसाध तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है परन्तु कानूनों तथा आज्ञापितियों का अथवा आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है।”

अतः हम यही कहेंगे कि लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद रूसी ढंग का अद्भुत सम्मिश्रण है। समस्त शासन व्यवस्था पर केन्द्र का ही प्रभुत्व है। हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि स्थानीय मामलों तथा दैनिक कार्यों में नागरिकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है। परन्तु फिर भी केन्द्रीकरण की भावना अपनी चरम सीमा पर है। याम्पसन तथा हापर ने इसे दो मुख्य वाली व्यवस्था कहा है। मूरे ने इसे ‘पवित्र’ इच्छा कहा है।

सघीय इकाइयों का शासन

सोवियत रूस विविध संस्कृतियों एवं जातियों वाला देश है जिसमें विविध घन जातियाँ, सम्प्रदाय तथा वंश एवं परम्पराएँ पाई जाती हैं। इनमें से रूसी, जार्जियन तथा यूक्रेनियन जातियाँ रूसी राज्य की स्थापना में पूव भी राज्यों के रूप में संगठित थीं, परन्तु भारी तथा कौसी राष्ट्रीय जातियाँ इस प्रकार की हैं कि उनका विकास केवल रूसी राज्य का ही के पश्चात् ही सम्भव हो सका। हम यह अत्यन्त भी कह चुके हैं कि सोवियत रूस में सघात्मक व्यवस्था विविध प्रकार की सांस्कृतिक परिस्थितियों की विवशता है। यदि इन राष्ट्रीय जातियों को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई होती और उनके स्वरूप को बनाये हुए नहीं रखा गया होता तो सम्भवतः सोवियत सघ की स्थापना ही कठिन हो जाती। सोवियत रूस में 15 सघीय गणराज्य (Union Republics) 17 स्वायत्त गणराज्य (Autonomous Republics), 9 स्वायत्त क्षेत्र तथा 10 राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas) हैं।

सघीय गणराज्य की शासन व्यवस्था (Administrative System of Union Republic)

राजनैतिक दृष्टि से सघीय गणराज्य की ही सघ इकाई का स्तर प्राप्त है। सोवियत सघ में वे अपनी स्वेच्छा से ही सम्मिलित हुई हैं। प्रत्येक सघ गणराज्य की सेना, संविधान, नियोजन आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा केन्द्र से सम्बन्ध

विच्छेद करने सम्बन्धी आदि बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु इसके साथ ही कुछ प्रतिबन्ध भी हैं जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। सघीय गणराज्यों के आधीन स्वायत्त गणराज्य स्वायत्त क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, परन्तु स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप में इनको सघ का सदस्य स्वीकार नहीं किया गया है। सघ गणराज्य की शासकीय व्यवस्था पूणतः केन्द्र के समान ही है। सघ गणराज्यों के संविधान के द्वीय संविधान के प्रतिफल नहीं हैं—

सघ गणराज्य की शासन व्यवस्था

सघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत	सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम	सघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषद्	उच्चतर न्यायापालिका
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

(1) सघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत (Supreme Court of Union Republic)—केन्द्रीय ढाँचे का अनुकरण करके ही सघ गणराज्य में भी सर्वोच्च सोवियत की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी सर्वोच्च सोवियत को राजकीय सत्ता का सर्वोत्तम अंग स्वीकार किया गया है। यहाँ भी सर्वोच्च सोवियत का वयस्क मताधिकार के आधार पर ही निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है। परन्तु सर्वोच्च सोवियत एक सदनात्मक है। सर्वोच्च सोवियत अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेती है। सर्वोच्च सोवियत के निम्नलिखित काम हैं—

- 1 सविधान में 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन करना।
- 2 अपने आधीन स्वायत्त गणराज्यों की सीमाएँ निर्धारित करना।
- 3 बजट का निर्माण करना तथा आर्थिक योजनाओं का निश्चय करना।
- 4 क्षमादान करना।
- 5 विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- 6 सैनिक संगठन से सम्बन्धित नियमों का निर्माण करना।
- 7 गणराज्य की प्रेसीडियम एवं मन्त्रिपरिषद् का निर्वाचन करना।

(2) सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम (Presidium of the Supreme Soviet of a Federal Republic)—प्रेसीडियम का कार्यकाल 4 वर्ष है। यह सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के अंतराल में ही काम करती है। इसके सदस्य सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। प्रेसीडियम मन्त्रिपरिषद् के रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। यह सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन की अनुपस्थिति में भी उसके समस्त कार्यों का सम्पादन करती है। केन्द्रीय प्रेसीडियम भी एक प्रकार की सतत कार्यपालिका ही है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों पर जब तक प्रेसीडियम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हो जाते उस समय तक वह कानून नहीं बन सकता। इसमें एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं।

(3) सघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)—कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषद् में ही निहित है। इसकी नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही की जाती है। एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, मन्त्रिगण तथा राजकीय नियोजन

आयोग का अध्यक्ष आदि इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी सर्वोच्च सोवियत पर ही अवलम्बित है। केन्द्रीय शासन की भाँति यहाँ पर भी दो ही प्रकार के मन्त्री होते हैं—सघ गणराज्य के मन्त्री तथा गणराज्य के मन्त्री।

सर्वोच्च सोवियत की अनुपस्थिति में मन्त्रिपरिषद् ही प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है। सोवियत गणराज्य की मन्त्रिपरिषद् का प्रमुख काम विधियों का निष्पादित करना है। यह प्रेसीडियम द्वारा दिये गये आदेशों को कार्यान्वित करती है। स्वायत्त गणराज्यों का शासन (Administration of Autonomous Republic)

सोवियत यूनियन में 17 स्वायत्त गणराज्य हैं, जो सघ जिस राज्य में स्थित हैं, वह उसी का भाग हैं। प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य का अपना संविधान है। स्वायत्त गणराज्य के शासन का आकार भी केन्द्र जैसा ही है। वहाँ पर भी सर्वोच्च सोवियत, प्रेसीडियम तथा मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 91 में सर्वोच्च सोवियत का उल्लेख है। सर्वोच्च सोवियत को ही एकमात्र कानून बनाने वाली सत्ता कहा गया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के आधार पर ही होता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। बजट निर्माण, संविधान में संशोधन, प्रशासकीय इकाइयों की स्थापना तथा राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन आदि इसकी शक्तियाँ हैं।

सघ गणराज्य के आदेश पर ही स्वायत्त गणराज्य में भी सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की व्यवस्था है। यह सतत विधानपालिका है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही होता है। इसमें एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एवं सचिव तथा कुछ सदस्य होते हैं, प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के अंतराल में विधान मण्डल के कार्यों का सम्पादन करती है। मन्त्रिपरिषद् प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन आमन्त्रित करती है तथा मन्त्रिपरिषद् के रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है।

स्वायत्त गणराज्य में एक मन्त्रिपरिषद् की भी व्यवस्था की गई है। यह गणराज्य की कार्यपालिका है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य आदेश प्रसारित करना तथा निम्नतर इकाइयों के आदेशों को रद्द करना है।

स्वायत्त प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों का शासन (Administration of Autonomous Regions of National Areas)

सोवियत सघ में स्वायत्त प्रदेशों की संख्या 9 है और राष्ट्रीय क्षेत्रों की संख्या 10 है। प्रत्येक में यमजीवी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत है। इसका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए ही किया जाता है। सोवियत की वय में आठ बैठकें होती हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की कार्यकारिणी तथा प्रशासकीय शक्ति एक कार्यकारिणी सभा में निहित होती है। प्रदेश की सोवियत द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कार्यकारिणी परिषद् में एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं।

स्थानीय स्वशासन (Local Government)

रूस में स्थानीय शासन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इन्हें

सोवियत शासन का आधार कहा जाता है। प्रशासकीय, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में इन्हें महत्वपूर्ण अधिकार उपलब्ध हैं। ये कानून एवं शांति स्थापना में भी अपना पूर्ण सहयोग देती हैं। ये नागरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। स्थानीय स्वशासन की प्रमुख इकाइयाँ इस प्रकार हैं—प्रांत, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, नगर तथा ग्राम। इन सब इकाइयों में श्रमजीवियों की प्रतिनिधि एक सोवियत होती है। सोवियतों को अथ देशों में समिति (Council) कहा जाता है।

प्रांतों की सोवियतें—सम्पूर्ण संघ गणराज्य को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से प्रांतों तथा प्रांतों को जिलों में तथा जिलों को नगरों एवं ग्रामों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रांत की एक सोवियत होती है जिसके सदस्यों की संख्या प्रांत की जनसंख्या पर ही निर्भर होती है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 'याय, सुरक्षा, उत्पादन एवं वितरण, जनस्वास्थ्य, सावजनिक कल्याण तथा निम्न निकायों का निरीक्षण' इत्यादि इसके कार्य होते हैं। इसका भी वही स्थान है जोकि संघ गणराज्यों में सर्वोच्च सोवियत का है। प्रत्येक प्रांत में प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई है।

जिले का प्रशासन—सोवियत रूस में लगभग 3000 जिले हैं। 50,000 की जनसंख्या वाले नगरों को जिला प्रशासन में अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जिले को परगनों में विभाजित किया जाता है। एक जिले में 20 से लेकर 25 तक परगने होते हैं। प्रत्येक जिले की अपनी सोवियत होती है जिसमें 60 से अधिक सदस्य नहीं रह सकते। प्रत्येक 1000 की संख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। जिले की अपनी सोवियत, प्रेसीडियम तथा मंत्रिपरिषद भी होती है। प्रेसीडियम का अध्यक्ष जिले का राष्ट्रपति कहलाता है।

नगरों का शासन—नगरों के प्रबंध के लिए नगरपालिकाओं की स्थापना की गई है। इन नगरपालिकाओं को 'नगरपालिका सोवियत' कहा जाता है। इसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया जाता है। सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या पर ही निर्भर है। प्रत्येक नगर की भी प्रेसीडियम तथा कार्यकारिणी होती है। प्रेसीडियम के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण रूप से सम्मान होता है। सावजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय उद्योग तथा व्यापार आदि का प्रबंध करना नगर की कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व है।

ग्रामों की सोवियत—प्रत्येक ग्राम अथवा कुछ छोटे छोटे गाँवों के लिए एक सोवियत की व्यवस्था की गई है जिसे 'सेलो सोवियत' (Selo Soviet) कहते हैं।¹ 5 वर्ष में कई बार ग्रामीण प्रतिनिधि एकत्रित होकर स्थानीय स्वरूप की समस्याओं पर विचार करते हैं। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की भी व्यवस्था है। ग्राम सोवियतों का निर्वाचन जनता द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला तथा नगर सोवियतों की भांति अपने क्षेत्र में ग्राम सोवियतों को विविध अधिकार प्राप्त हैं। ग्राम सोवियत में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा आवश्यकतानुसार सदस्य होते हैं। शिक्षा, व्यापार, सावजनिक स्वास्थ्य स्थानीय उद्योगों आदि की व्यवस्था

¹ भारत में 5 वर्ष में इन्हें ग्राम सभा कहा जाता है।

करने का अधिकार ग्राम सोवियतों को प्राप्त है। रूस में लगभग ३ लाख गाँव हैं जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं।

क्षेत्र—सोवियत सघ में कुछ बेआबाद क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ नाममात्र की जनसंख्या है। वहाँ पर अब आर्थिक विकास किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों के लिए पृथक सोवियत का प्रबंध किया गया है।

सोवियत रूस में स्थानीय समस्याओं का बड़ा महत्व है। विशिस्को ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक सघ गणराज्य स्वयं में ही सम्प्रभु है परंतु यह सब असत्य ही है। सोवियत रूस में स्थानीय निकायों की स्वायत्ता इतनी व्यापक नहीं है जसी कि हमें दिखाई देती है। वहाँ पर वेंद्रोकरण की प्रवृत्ति के कारण ही स्थानीय समस्याओं का महत्व घटता रहा है। स्थानीय समस्याओं का महत्व इसलिए भी कम हुआ गया है क्योंकि वहाँ पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ साथ ही साम्यवादी दल का भी नियंत्रण है। वस्तुतः नियंत्रण को इस दुहरी व्यवस्था के कारण ही स्थानीय समस्याएँ नागरिक जीवन में वह अनुदाय प्रस्तुत नहीं कर पाती जितना कि वह प्रस्तुत कर सकती हैं।

Select References

- Adams *Foreign Governments and their Backgrounds*
 Karplosky *The Social and State Structure of U S S R*
 Vyshinsky *The Law of Soviet State*
 Harper *The Govt of Soviet Union*
 Sidney & Beatrice Webb *Soviet Communism—A new Civilization*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद से क्या आशय है? सोवियत रूस में इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
 (Define Democratic Centralism Discuss its working in U S S R)

चतुर्थ खण्ड
स्विटजरलैण्ड की शासन व्यवस्था

- स्विटजरलैण्ड के संविधान की सामान्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- संघीय कार्यपालिका
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र
- स्विस संघीय न्यायाधिकरण तथा राजनतिक बल
- संघीय विधानपालिका
- कानूनों की शासन व्यवस्था

|

स्विटजरलैण्ड के संविधान की सामान्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

[General & Historical Background of the Swiss Constitution]

“स्विटजरलैण्ड राजनीति के साहसी कार्यों की प्रयोगशाला है तथा उसकी सफलता से समस्त लोकतन्त्रीय देशों को सुरक्षा मिलती है।”

—बुक्स

“स्विटजरलैण्ड ही अधिनियम उपक्रम तथा लोक नियम का प्राचीनतम स्थान है।”

—मुनरो

परिचयामक

स्विटजरलैण्ड योरोप का एक छोटा सा देश है जो चारों ओर आल्पस पर्वत शृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह विश्व के मनोरम एवं आकर्षक क्रीड़ा स्थलों में से एक है। इसके उत्तर में जर्मनी, पूर्व में आस्ट्रिया, दक्षिण में इटली और पश्चिम में फ्रांस है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15,950 वर्गमील है जोकि भारत के केरल राज्य के बराबर है। इसके पास समुद्रतट नहीं है। इसकी जनसंख्या लगभग 55 लाख से अधिक ही है। इसकी भौगोलिक स्थिति की तुलना हैजलिट ने एक गोल्फ कोर्स से की है। यह अनेकों महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। इसका स्वरूप पहाड़ी एवं प्लेटोनुमा जैसा है तथा इसका 20% भाग घने जंगलों से घिरा हुआ है।

स्विटजरलैण्ड में विभिन्न भाषा भाषी तथा राष्ट्रीय जातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के 20 प्रतिशत निवासी फ्रांसीसी हैं जिनकी भाषा फ्रेंच है 5 प्रतिशत निवासी इटालियन भाषा भाषी हैं, 1 प्रतिशत निवासी रोमन भाषा बोलते हैं। स्विटजरलैण्ड में राजकीय कार्य तीनों ही भाषाओं में किया जाता है। यहाँ की 57 प्रतिशत जनसंख्या कथोलिक और 41 प्रतिशत प्रोटेस्टेंट है। स्विटजरलैण्ड में 20,000 के करीब यहूदी हैं। विभिन्न भाषा भाषी तथा राष्ट्रीय जातियों के होते हुए भी वहाँ के निवासियों में अनुपम एवं आश्चर्यजनक सहिष्णुता है। यहाँ सब लोगों में पारस्परिक भाई-चारे की अद्विभूत भावना पाई जाती है। यद्यपि जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया गया था परन्तु यहाँ पर वे पूर्ण सुरक्षित रहे। यहाँ की भूमि पर्वतीय होने के कारण केवल 22 प्रतिशत जनसंख्या का कृषि पर जीवित रखने में समर्थ है। यहाँ का विदेशी व्यापार अति उत्तम है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ विश्व के हर कोने से पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। यहाँ पर यातायात की भी

कठिनाई बनी रहती है। हैजलिट के शब्दों में “यातायात तथा निर्मात उनके जीवन का आधार है।” यहाँ जमन जाति के लोग सबसे अधिक हैं। वास्तव में औद्योगिक के द्र के साथ ही यह जाति के द्र भी है। इन धार्मिक विभिन्नताओं के होते हुए भी स्विटजरलैण्ड एक राष्ट्र है। उसकी राष्ट्रीयता का आधार हैं—स्वतंत्रता प्रेम, आर्थिक प्रजातंत्र, तटस्थता एवं गणतन्त्रात्मक लोकतंत्र। स्विटजरलैण्ड की विश्व को एक महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया है। अतएव जचर (Zurcher) ने कहा है कि “स्विस जनता ने राष्ट्रीय एकता तथा देश प्रेम की भावना योरोप के अ य देशों की जनता से अधिक दृढ़ है।” जॉन स्राउन मेसन का विचार है कि “धर्म और भाषा के आधार पर गम्भीर भेदों के होते हुए भी स्विटजरलैण्ड ने जिस प्रकार की राष्ट्रीय एकता स्थापित की है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विघेयज्ञ भी प्रभावित हुए हैं। इसमें उन्हें इस बात का प्रमाण मिलता है कि सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता की शक्तिशाली परम्परा के होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि की आशा और सम्भावना है।”

राजनैतिक विचार (Political Ideas)

स्विटजरलैण्ड के संविधान में उदारवादी विचारधारा का समावेश है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर बल दिया जाता है। स्विटजरलैण्ड के निवासी स्वभाव से ही पूणत जनतन्त्रवादी हैं। अंतिम राजनैतिक शक्ति जनता के हाथों में ही निहित है। लोकतंत्र को वे जीवन का श्रेष्ठतम अंग मानते हैं। वहाँ के जीवन में गणतन्त्रवाद का प्रमुख स्थान है। गणतन्त्रवाद तो वहाँ के संविधान का तृतीय स्तम्भ ही है। वहाँ पर कोई भी पद वशानुगत नहीं है। स्विटजरलैण्ड में 500 वर्ष पुराना गणतंत्र है। गणतंत्र की जड़ें वहाँ पर बहुत गहरी हैं। रैपड के शब्दों में ‘स्विटजरलैण्ड युगों से गणतंत्र रहा है।’ स्विटजरलैण्ड में सत्ता का पूणरूप से विकेंद्रीकरण है। वहाँ किसी शक्ति के निरकुश रूप को स्वीकार किया गया है। यद्यपि संविधान में स्विटजरलैण्ड को परिसद्व कहा गया है। परंतु उसमें सघात्मक सरकार के समस्त गुण विद्यमान हैं।

स्विस संविधान का संवैधानिक महत्त्व (Constitutional Importance of Swiss zerland)

स्विटजरलैण्ड विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ पर कभी राजतंत्र नहीं रहा। राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए स्विस संविधान का महत्त्व बहुत अधिक है। इसने सम्प्रभुता को व्यावहारिक रूप देने का एक महान् कार्य किया है। वास्तविक लोकतंत्र के दर्शन केवल स्विटजरलैण्ड में ही होते हैं। स्विटजरलैण्ड का राजनैतिक विकास लोकतंत्र का ही विकास है। स्विटजरलैण्ड ने कार्यपालिका के क्षेत्र में एक नूतन प्रयोग किया है जोकि बहुत ही सफल रहा है। कार्यपालिका (Plural Executive) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का यहाँ पर सफल प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमें लोकप्रिय संप्रभुता का सजनात्मक रूप देखने को मिलता है। द्रुबस के

शब्दों में "स्विटजरलैण्ड साहसी कार्यों की प्रयोगशाला है तथा उसकी सफलता से समस्त जनतन्त्रीय देशों को शिक्षा मिलती है।"¹

स्विटजरलैण्ड की शासकीय व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत सी राष्ट्रीय जातियाँ भी एक साथ मिलकर रह सकती हैं। विविध धर्म एवं भाषाओं के होते हुए भी स्विस जनता राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत है। वहाँ विविधता में ही एकता है। आज के विश्व के लिए यह उसका अनूठा उदाहरण है। योरोप ने अथ किसी भी देश के निवासियों में इतनी एकता तथा राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती जितनी कि स्विटजरलैण्ड के निवासियों में विद्यमान है। धर्म ने वहाँ भाषायों विवाद को जन्म नहीं दिया है। वहाँ पर एक ही कैंटन में विविध भाषा भाषी एवं धर्म के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। कैंटनों की सीमाएँ भाषा अथवा धर्म के आधार पर निर्मित नहीं की गई हैं। स्विस सविधान पूर्ण रूप से सिद्धांत एवं व्यवहार में धर्म निरपेक्ष है। सन् 1928 से वहाँ 'रोमांश' को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।

स्विटजरलैण्ड ने तटस्थता (Neutrality) का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। जर्मनी तथा इटली जैसे बड़े राष्ट्रों से घिरे रहने पर भी उसने तटस्थ रहने का सफल प्रयत्न किया है। उसने अपने इतने लम्बे इतिहास में तटस्थता के आदर्श को कभी नहीं गिरने दिया। सन् 1815 के वियना सम्मेलन के समय से लेकर सन् 1920 तक प्रत्येक सम्मेलन में स्विटजरलैण्ड ने अपनी तटस्थता को स्थिर रखने का पूर्ण प्रयत्न किया है, इसमें उसे सफलता भी मिली है। वह राष्ट्र सभ का भी सदस्य बना था और अब संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता भी उसने इसी शत पर स्वीकार की है कि प्रत्येक मूल्य पर उसकी तटस्थता की रक्षा की जायगी। इसी तटस्थता के कारण ही वहाँ स्थायी सेना नहीं रखी जाती है, यद्यपि वहाँ के व्यक्ति सबसे अधिक अच्छे लड़ाकू माने जाते हैं। जॉन ब्राउन मैसन ने स्विटजरलैण्ड को "अशांति के समुद्र में बसने वाला सुखी द्वीप कहा है।"² विश्व के बड़े बड़े सम्मेलन वहाँ पर होते रहते हैं। जेनेवा सम्मेलन इसके लिए बहुत लोकप्रिय है। वहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन ही इसकी तटस्थता को प्रमाणित करता है। स्विटजरलैण्ड के निवासी खनिज पदार्थों के अभाव में भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। यहाँ पर स्वतन्त्रता तथा खुशहाली एक दूसरे की सहचरी है। वहाँ पर हाय हुल्ड नहीं है और न ही अशान्ति। स्विटजरलैण्ड ने एक आदर्श उदाहरण यह भी प्रस्तुत किया है कि लोकतन्त्र कठोर राजनैतिक दलों की अनुपस्थिति में भी चल सकता है तथा सघीय व्यवस्था के लिए सर्वोच्च प्रकार की यायपालिका का होना भी आवश्यक नहीं है। सविधान के पाठकों के लिए यह और भी अधिक रुचिकर है कि वहाँ पर अर्ध कैंटनों (Half Cantons) जैसी व्यवस्था है जोकि सम्भवतः बहुत ही कम सविधानों में पाई जाती है। पाठक की रुचि में उस समय और भी अधिक वृद्धि हो जाती है जबकि हम स्विस सविधान को जनतन्त्र का प्रत्यक्ष घर कहते हैं। अंत बुयेल (Buell) ने

1 It is a laboratory of adventurous experiments and her success contributes to the instruction of all republican people
—Brooks.

2 A happy land in the sea of unrest

—Brown Mason

ठीक ही कहा है कि 'स्विटजरलैण्ड' उन लोगों में निकटतम सहयोग की भावना प्रदर्शित कर चुका है जोकि किसी समय राजनैतिक रूप में एक दूसरे से स्वतंत्र थे और भाषा एवं धर्म के अनुसार एक दूसरे से बहुत अलग हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

स्विटजरलैण्ड का संविधान एक लम्बे विकास का परिणाम है। यहाँ का इतिहास एकीकरण तथा वृद्धिकरण का इतिहास है। यहाँ के प्रारम्भिक इतिहास को हम आवागमन का इतिहास भी कह सकते हैं। 13वीं शताब्दी में स्विटजरलैण्ड में भी सामन्तवाद से मुक्ति पाने के लिए संघ प्रारम्भ हुआ। सन् 1291 में स्विट्स परिसंघ की स्थापना हुई। परिसंघ की स्थापना का उद्देश्य विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना था। स्विट्स राष्ट्रीयता का जन्म यही से प्रारम्भ हुआ। सन् 1315 में इस संघ ने आस्ट्रिया को पराजित करके अपनी उपयोगिता प्रमाणित की। सन् 1353 में इसमें आठ राज्य सम्मिलित हो चुके थे। इन्हें कैंटन कहा जाता था। कैंटनों की पारस्परिक फूट के कारण ही सन् 1442 से 1450 तक गृह युद्ध चलता रहा। सन् 1481 तक गृह युद्ध की विभीषिका स्विट्सवासियों को पीड़ित करती रही। इसी वर्ष स्टैज नामक स्थान पर इन कैंटनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें यह निश्चय किया गया कि किसी भी कैंटन में अशांति की स्थिति में परिसंघ को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। सन् 1513 तक बेजूल, शाफहाउस तथा अर्जेस नामक तीन कैंटनों के परिसंघ में सम्मिलित हो जाने पर परिसंघ के सदस्यों की संख्या 13 हो गई थी। कुछ कैंटन ऐसे थे जिनको परिसंघ द्वारा पराजित होने के पश्चात् इसमें सम्मिलित कर लिया गया और कुछ कैंटन ऐसे भी थे जोकि युद्ध के समय परिसंघ की सहायता करने को उद्यत रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 16वीं शताब्दी तक स्विटजरलैण्ड के विविध भागों में एकीकरण की गहरी भावना स्थापित हो चुकी थी।

सन् 1531 में पुनः स्विटजरलैण्ड की धार्मिक कारणों से गृह युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त होना पड़ा। सुधारवादी नेता ज्विगली के नेतृत्व में यूरेरिच तथा बर्न के कैंटनों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। कैथोलिक धर्म के अवलम्बियों से उनका संघर्ष हुआ। तदुपरांत धर्म सुधार आन्दोलन का कार्यक्रम जॉन कालविन के नेतृत्व में चलता रहा। स्विटजरलैण्ड में धर्म का संघर्ष दो शताब्दियों तक चलता रहा। सन् 1648 में वेस्टफेलिया की संधि (Treaty of Westphalia) हुई तथा यूरोप में धार्मिक युद्धों का अन्त हुआ। आन्तरिक अशांति के होते हुए भी वेस्टफेलिया की संधि में स्विटजरलैण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई और उसे जर्मन शासन से मुक्त कराकर एक संप्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। परिसंघ की दुर्बलता यह थी कि उसमें केन्द्रीय कार्यपालिका का अभाव था। ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता था जोकि सभी सदस्य कैंटनों को मान्य हो। क्रमर (Cramer) का कथन है कि "अपने बड़े पड़ोसी देशों की तुलना में स्विट्स इतिहास हिंसा, रक्तपात, और धार्मिक मदाघता से कहीं अधिक भरा हुआ है। इस

कारण वहाँ लोकतन्त्रात्मक संघवाद सामाजिक शांतिप्रियता और धार्मिक सहनशीलता की अंतिम विजय विशेष रूप से उल्लेखनीय है।'

फ्रांसीसी राज्य क्रांति का प्रभाव (Impact of French Revolution)

सन् 1789 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति ने कुलीन वर्ग के समस्त विशेषाधिकारों को एक झटके में समाप्त कर दिया। स्विस राज्यमण्डल की पराजय हुई और उसके स्थान पर हेल्वेटिक गणराज्य (Helvetic Republic) की स्थापना हुई। इस गणराज्य पर क्रांतिकारियों का आधिपत्य था। नूतन संविधान की रचना करके एकात्मकता शासन में प्रविष्ट हुई। कुलीनतन्त्र के अन्त्य का अन्त हुआ और उसके स्थान पर क्रांतिकारी लोकतन्त्र स्थापित हुआ। इस नूतन शासकीय व्यवस्था के सिद्धान्त के द्वािकरण राष्ट्रीय नागरिकता, निर्वाचित विधानमण्डल तथा उत्तरदायी कार्यपालिका आदि थे। क्रांति का आधार राष्ट्रीय विप्लव नहीं था। उसका आधार था विदेशी हस्तक्षेप। इसी कारण ही ये सिद्धान्त लोकप्रिय नहीं बन सके। आस्ट्रिया तथा फ्रांस में संघर्ष छिड़ा, परन्तु स्विटजरलैण्ड से फ्रांसीसी आधिपत्य नहीं छिग सका। स्विस भूमि संघर्ष की रणस्थली बनी रही। नैपोलियन ने राजनैतिक अव्यवस्था को रोकने के लिए स्विटजरलैण्ड की प्रशासकीय व्यवस्था में कई संशोधन किये परन्तु फ्रांसीसी आधिपत्य भी सन् 1813 के पश्चात् नहीं चल सका तथा सन् 1815 में नैपोलियन के पतन के साथ ही यह भी घराशाही हो गया।

आधुनिक स्विटजरलैण्ड का जन्म (Birth of Modern Switzerland)

सन् 1815 का वर्ग तथा विना सम्मेलन स्विटजरलैण्ड के लिए बरदान सिद्ध हुए। स्विस परिषद (Confederation) में तीन और नये कंटनों के सम्मिलित हो जाने से उसकी सदस्य संख्या 22 हो गई। ये तीन कंटन फ्रव भाषा भापी थे। यहाँ से ही आधुनिक स्विटजरलैण्ड का जन्म हुआ परन्तु स्विस सीमाएँ परिषीत नहीं हुईं। अनेक कंटनों में कुलीन वर्ग का आधिपत्य अब भी बना रहा। डाइट (Diet) में प्रत्येक कंटन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। यह डाइट विधानमण्डल के रूप में पहले से ही कार्य करती रही थी। डाइट की शक्तियों का निणय आंतरिक अशांति को रोकने के लिए ही किया गया था। परिषद प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथों में रहा। कार्यपालिका के अभाव तथा विकेंद्रित व्यवस्था न एक बार पुन स्विटजरलैण्ड को खतरे क मोठ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस समय आस्ट्रिया के प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रति सन् 1830 में अविश्वास की भावना जनता के खुले विद्रोह के रूप में पुन भडक उठी। डाइट विद्रोह रोकने में असफल रही जिसके फलस्वरूप मध्यम वर्ग शासन पर सत्ताखंड रहा। कुलीन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्विटजरलैण्ड का इतिहास उसकी भूमि के सदृश भारी उतार चढ़ाव का इतिहास है। सन् 1847 में पुन गृह युद्ध की ज्वाला भडक उठी। उसका स्वरूप तो धार्मिक ही था—कैथोलिक तथा प्रोटेस्टंटों में संघर्ष हुआ और प्रोटेस्टंटों का विजय हुई।

सन् 1848 का संघीय संविधान (Federal Constitution of 1848)

सन् 1848 में स्विटजरलैण्ड के लिए जिस संविधान की रचना की गई उसे

आदर्श संविधान की सजा दी गई है। लोकतंत्र के आधार पर नवीन संविधान की रचना की गई है। प्रथम बार स्विस राजनीतिज्ञ ने एक शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता का अनुभव किया। योरोपीय अशांति के कारण आक्रमण का खतरा बढ़ता गया और उसी अनुपात में शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी। संविधान का प्रारूप लोकनिर्णय (Referendum) द्वारा स्वीकार कर लिया गया। औपचारिक रूप से इसे परिषद ही कहा गया। सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा डाक व्यवस्था आदि सामान्य हित के विषय संघीय सरकार के अधिकार में ही रखे गये। इस पर अमेरिकी संघीय व्यवस्था का विशेष प्रभाव पड़ा, द्वितीय सदन का नाम सीनेट रखा गया और उसमें समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया। निम्न सदन के संगठन का आधार सामान्य जनसंख्या को रखा गया। कार्यपालिका का स्वरूप न तो संसदीय ही रखा गया है और न ही अध्यक्षतात्मक। कार्यपालिका शक्ति को एक परिषद के ही हाथों में रहने दिया गया। आगे चलकर इसी पद्धति को उठोने संघीय कार्यपालिका का आधार बनाया। अमेरिका की भाँति कार्यपालिका को सर्वोच्च रूप नहीं दिया गया है। जनता की इच्छा को संविधान के रूप में सर्वोच्च माना गया है। सम्प्रभुता का निवास जनता में ही स्वीकार किया गया है।

सन् 1874 का संविधान (Constitution of 1874)

उग्रवादी वग (Radicalists) इस संविधान से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि शक्तिशाली संघ की स्थापना में और अधिक वृद्धि की जाय। कथोलिक हस्तक्षेप में कमी करने का प्रयत्न किया गया। सन् 1874 में नूतन संविधान एक पूर्ण संशोधन के रूप में लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया। संविधान के इस संशोधित रूप को स्वीकार कर लिया गया। कठनों की स्वतंत्रता में पहले से कुछ कमी की गई। कार्यपालिका को और अधिक स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया। सन् 1874 के पश्चात् भी संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं परन्तु उसकी मूल प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् 1971 तक वहाँ महिला मताधिकार की अनुपस्थिति में लोकतंत्र का रूप अधूरा ही था परन्तु यह वष इसकी भी पूर्ति हो गई। संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं उनसे केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है अपितु उसका विकास ही हुआ है।

स्विटजरलैण्ड के संविधान की विशेषताएँ

(Characteristics of the Swiss Constitution)

प्रत्येक संविधान की अपनी अनूठी विशेषताएँ हुआ करती हैं। स्विस संविधान उदारवाद के आवरण में विभुद्ध जनतंत्र है। यह अपने ढंग का संविधान है जिसकी धमनियों में लोक निर्णय तथा प्रारम्भिक का रक्त बहाव हो रहा है। यह एक स्विस परीक्षण है। यह अध्यक्षतात्मक तथा संसदात्मक प्रणालियों का मध्य भाग है। इसकी संघीय व्यवस्था अमेरिकी तथा भारतीय संघ व्यवस्थाओं के मध्य की है। बहुत कार्यपालिका का आविष्कार इसकी राजनीति विज्ञान की मौलिक देन नहीं आ सकती है। यदि इंग्लैंड की संसदीय पद्धति का सूत्रधार और अमेरिका की अध्यक्षतात्मक प्रणाली का आदर्श कहा जा सकता है तो स्विटजरलैण्ड का भी प्रत्यक्ष जनतंत्र का घर कहा जा सकता है। इसकी मौलिक विशेषताएँ अप्रतिष्ठित हैं—

1. लिखित एवं अनम्य संविधान (Written & Rigid Constitution)

प्रत्येक संघीय संविधान के द्र तथा उसकी इकाइयों के बीच समझौता होता है। लिखित रूप में के द्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। स्विस संविधान को भी लिखित संविधानों की श्रेणी में ही रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर भी इंगलैण्ड की भाँति न तो संवैधानिक परम्पराएँ ही हैं और न ही उनका वहाँ महत्व है। स्विस संविधान निर्मित संविधान है, इसी कारण वह लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया से उसका निर्माण हुआ है। उसके निर्माण का समय भी निश्चित है। इसमें संवैधानिक निषेधों को भी महत्व नहीं दिया गया है। अमेरिका, भारत, कनाडा तथा रूस आदि की भाँति यहाँ का संविधान भी लिखित संविधान है। उसमें मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र नहीं है परंतु कहीं कहीं महत्वपूर्ण अधिकारों का वर्णन अवश्य किया गया है।

स्विस संविधान को अनम्य संविधानों की श्रेणी में रखना अधिक उपयुक्त होगा यद्यपि वह इतना कठोर एवं दुष्परिवर्तनशील नहीं है जितना कि अमेरिका का संविधान अटल एवं कठोर है। वहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल तथा अमेरिका की अपेक्षा अधिक लोकतंत्रीय है। वहाँ संशोधन की विशेष क्रिया द्वारा कानूनों में परिवर्तन हो सकते हैं। अब तक इसमें लगभग वहाँ 55 संशोधन हो चुके हैं। सन् 1874 में तो पूरा संविधान ही बदल दिया गया। यदि हम संविधान के संशोधन सम्बन्धी अनुच्छेदों का अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का बदलना बहुत कठिन है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। यह बात अवश्य है कि साधारण कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक परिवर्तन करना कठिन है। स्विटजरलैण्ड में संघीय कार्यपालिका संशोधनों के प्रारूप तैयार करती है और वे ही दोनों सदनों के समक्ष उन्हें प्रस्तुत भी करते हैं। संघीय कार्यपालिका में विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य होते हैं। इसीलिए संघीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। फाइनर के शब्दों में 'स्विस संविधान का वर्गीकरण अनम्य संविधानों में ही किया जायेगा क्योंकि वहाँ पर साधारण कानून के निर्माण की विधि की तुलना में संवैधानिक संशोधन करना अधिक कठिन है।' संशोधन के लिए जनता की साधारण सी शक्ति ही पर्याप्त होती है। इसके विपरीत अमेरिका में संवैधानिक संशोधन 3/4 राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही होना चाहिए।

2. लम्बा प्रलेख (A Long Document)

स्विस संविधान अमेरिकी संविधान से दुगुना तथा भारतीय संविधान का आठवाँ भाग है। इसमें केवल 123 धाराएँ हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 धाराएँ हैं परंतु इसके विपरीत भारतीय संविधान में 395 धाराएँ हैं। सम्भवतः स्विस संविधान के कुछ विस्तृत होने का मूल कारण यह है कि संविधान निर्माता के द्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट एवं व्यापक रूप से करना चाहते थे जिससे कि सदिग्धता के लिए कोई स्थान ही शेष न रह जाय।

3. गणतन्त्रात्मक संविधान (Republican Constitution)

वास्तव में स्विटजरलैण्ड कभी भी राजतन्त्र नहीं रहा परंतु वह सदैव स ही स्वतन्त्र होने की कामना करता रहा है। संविधान का स्वरूप गणतन्त्रात्मक है। यहाँ

साधारण कमचारी से लेकर सचीय कायपालिका के अध्यक्ष तक का कोई भी राजकीय पद वशानुगत नहीं है। सचीय कायपालिका का सामूहिक राष्ट्रपति (Collective President) अत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है।

4 उदारतावाद का प्रभाव (Impact of Liberalism)

स्विस संविधान के निर्माता उदारतावादी विचारधारा से पूर्णरूप से प्रभावित थे। उन विचारों को उन्होंने संविधान में स्थान दिया, यद्यपि रूस भारत तथा अमेरिका के संविधानों के समान उनका स्वरूप अधिकार पत्र का नहीं है। स्वतन्त्रता की रक्षा सम्बन्धी कई अनुच्छेद स्विस संविधान में उपलब्ध हैं। नागरिकों को भाषण, आवागमन, विचार आदि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। यहाँ पर धार्मिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की गई है। संविधान निर्माता नागरिकों को प्रतारणा तथा विविध अनुश्रुतियों से मुक्त रखना चाहते थे। विधि के समक्ष समानता रखी गई है। निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यद्यपि उदारतावाद के आर्थिक पहलू को पूँजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, परन्तु संविधान निर्माताओं ने राज्य के स्वरूप को लोक हितकारी राज्य का रूप ही दिया है।

5 परिषदात्मक कायपालिका (Collegial Executive)

स्विस संविधान निर्माताओं ने अपनी कायपालिका का स्वरूप परिषदात्मक रखा है। कायपालिका शक्ति किसी विशेष व्यक्ति में निहित न होकर एक परिषद में ही निहित है। परिषद में सात सदस्य होते हैं जो समान स्तर के होते हैं और जिनकी शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्वों में कोई अन्तर नहीं होता। परिषद का अध्यक्ष औपचारिक रूप से स्विस संघ का अध्यक्ष होता है, जोकि अन्य ससदीय देशों में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सम्पादित कार्यों का ही सम्पादन करता है किन्तु उसकी स्थिति अन्य सदस्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं होती। वह अन्य सदस्यों के ही सवश कार्य करता है। कायपालिका का अध्यक्ष पद बारी बारी से उसके सदस्यों को प्राप्त होता है।

6 द्विसदनात्मक विधान मण्डल (Bicameral Legislature)

प्रो० स्ट्रॉम ने कहा है कि परिषदात्मक कायपालिका के समान स्विस विधान मण्डल भी अनूठा ही है। यहाँ पर व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद (National Council) तथा वरिष्ठ सदन को राज्य सभा (Council of the States) कहा जाता है। निम्न सदन का प्रयोग जन साधारण के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए किया गया है और वरिष्ठ सदन का प्रयोग वैदनों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए किया गया है। सन् 1971 तक वहाँ पर महिला मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों का कार्य साज सज्जा तथा गृह कार्यों तक ही सीमित था। आर्थिक कार्यों में वे अग्रणी थीं परन्तु उनमें राजनैतिक चेतना देर से जागृत हुई। सन् 1971 के पश्चात् ही स्विस लोकतन्त्र को पूर्णता प्राप्त हुई है।

7 प्रशासनिक कानून पर अवलम्बित न्यायपालिका (Judiciary based on Administrative Law)

स्विटजरलैण्ड की न्याय व्यवस्था का आधार है प्रशासकीय कानून। जन

साधारण तथा प्रशासकीय कमचारियों के लिए पृथक पृथक 'यायालय' होते हैं। डाइसी प्रशासकीय 'याय' व्यवस्था को नागरिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात समझता है। परंतु यदि 'यायपालिका' स्वतंत्र रह सके और 'यायाधीश' निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की 'याय' व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। यह सत्य है कि वहाँ पर भी 'यायपालिका' भारत तथा अमेरिका की भाँति ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। परंतु वहाँ के सर्वोच्च 'यायालय' अर्थात् संघीय 'यायालय' (Federal Tribunal) को वह स्तर प्राप्त नहीं है जोकि अमेरिका के सर्वोच्च 'यायालय' को प्राप्त है। यहाँ पर संघीय 'यायालय' वहाँ की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका पर कोई नियंत्रण नहीं रखता तथा उसके द्वारा बनाये गये किसी नियम को अवैध घोषित नहीं कर सकता परंतु उसे इस प्रकार का अधिकार कैंटनों की व्यवस्थापिकाओं के सम्मुख भी अवश्य ही प्राप्त है। इससे संविधान में केन्द्रीयकरण की ओर अधिक पुष्टि होती है।

(8) राजनैतिक दलों की स्थिति (Position of Political Parties)

स्विटजरलैण्ड राजनैतिक दल प्रणाली की दृष्टितत्वाओं से मुक्त है। राजनैतिक समस्याओं पर दलीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता। वहाँ पर दलों का स्वभाव ही समझौतावादी है। संघीय कार्यपालिका का गठन दलीय अनुपात पर किया जाता है। वहाँ विधान मंडल में एंग्लो सक्शन (इंग्लैंड) राज्य के समान विरोधी दल नहीं होते तो वहाँ के प्रमुख राजनैतिक दलों में सत्ता के लिये विषय सघर्ष भी नहीं होता है।

(9) गतिशील संविधान है (It is a Dynamic Constitution)

गतिशील संविधान उसे कहा जाता है जोकि अपनी आत्मा की अवहेलना किए बिना भी समयानुकूल परिवर्तन कर लेता है। यह गुण स्विस संविधान में पाया जाता है। समय की माँग को दृष्टिगत रखते हुए उसने उदारतावादी आत्मा की अवहेलना किए बिना समय समय पर संविधान में जो संशोधन कर लिये हैं उनसे उसका पूँजीवादी रंग कुछ फीका पड़ गया है। सन् 1877 से लेकर 1920 तक कई अधिनियमों के द्वारा औद्योगिक शोषण की मात्रा को भी बहुत कम कर दिया गया है। सन् 1913 में कई नियमों का निर्माण करके जनस्वास्थ्य की रक्षार्थ बीमारियों से सघर्ष करने की संधारियों की गइ। व्यक्ति की सामाजिक रक्षार्थ सन् 1820 में जूरा विरोध कानून बनाया गया। यहाँ पर स्वतंत्रता को कम करने वाले अधिनियमों का जाता है सबदा ही विरोध किया है।

(10) संघात्मक संविधान (It is a Federal Constitution)

यद्यपि संविधान में स्विटजरलैण्ड को परिसंघ कहा गया है परंतु उसमें संघात्मकता के समस्त गुण पाये जाते हैं संविधान की सर्वोच्चता है निश्चित एवं अनन्य संविधान है तथा केन्द्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। कैंटनों ने स्वाधीनता को त्यागकर स्वायत्तता का वरण किया है।

(11) भिन्नता में एकता (Unity in Diversity)

स्विटजरलैण्ड विविध भाषाओं, धर्मों एवं जातियाँ वाला देश है। यहाँ ५७ प्रतिशत जर्मन, 21 प्रतिशत फ्रेंच, 4 प्रतिशत इटालियन तथा 1०

लटिन भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। समस्त कानून एवं राजकीय आदेशों का प्रकाशन प्रथम तीन भाषाओं में होता है। वहाँ धार्मिक भिन्नता भी है। कुल जनसंख्या के 41 प्रतिशत निवासी रोमन कथोलिक हैं 54 प्रतिशत प्रोटस्टेंट धर्मावलम्बी हैं तथा 1 प्रतिशत निवासी यहूदी हैं। इस प्रकार वहाँ भाषागत एवं धार्मिक विभिन्नताओं ने होते हुए भी एकीकरण की भावना है जोकि उनको एक राष्ट्र के रूप में परिणत करती है।

(12) अधिकार पत्र का अभाव (Absence of the Bill of Rights)

अधिकतर सत्तात्मक संविधानों में अधिकार पत्र को सम्मिलित किया जाता है और उनकी सुरक्षा के साधनों का भी वर्णन होता है किन्तु स्विस संविधान में इस प्रकार के अधिकार पत्र का अभाव है। नागरिकों के अधिकारों को संविधान के किसी भी भाग में समर्पित रूप में नहीं रखा गया है। ये संविधान में यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने देती। जिस समय तक जनता में मैत्रीभाव है उस समय तक नागरिक अधिकारों की सुरक्षा चिन्ता का विषय नहीं है। साइमन ने स्विस संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा है, 'स्विटजरलैण्ड का संविधान प्राथमिक लोकतन्त्र जैसी संस्थाएँ प्रदान करता है जोकि एक स्थिर समाज में ही पनप सकती हैं।'

स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया (Amending Process of Swiss Constitution)

स्विटजरलैण्ड का संविधान अनम्य है जिसमें संशोधन के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। स्विटजरलैण्ड में अनुच्छेद 118 से लेकर 123 तक संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। स्विटजरलैण्ड में संशोधन करना इतना कठिन नहीं है जितना कि अमेरिका में। इसमें दो मत गहरी हैं कि स्विस संविधान की दुष्परिवर्तनशीलता संविधान की गतिशीलता में कभी भी बाधक सिद्ध नहीं हुई। स्विस संविधान में संशोधन की दो प्रक्रियाएँ रखी गई हैं और दोनों में ही अतित लोकप्रिय सप्रभुता का प्रतीक लोक निर्णय ही निर्णायक है।

पूर्ण संशोधन अथवा पूर्ण पुनर्विचार (Complete Modification)

संविधान को पूर्णतः संशोधित करने के लिये राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है तथा इस आशय का प्रस्ताव दोनों सदनों से एक साथ भी आ सकता है। यदि दोनों सदन उस पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो तत्पश्चात् वह प्रस्ताव लोक निर्णय की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय की स्वीकृति ही पूर्ण संशोधन के लिये पर्याप्त नहीं होती। इसके साथ साथ उस संशोधन प्रस्ताव को कैंटनों का बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक पूर्ण कटन का एक मत होता है और प्रत्येक अर्द्ध कटन का आधा मत माना जाता है। परन्तु यह भी सम्भव है कि व्यवस्थापिका के दोनों सदन एकमत नहीं हो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है—

1. सवप्रथम लोक निर्णय के द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि पूर्ण संशोधन किया जाय अथवा नहीं।

2 यदि लोक निर्णय द्वारा संशोधन की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को भंग कर दिया जाता है और उसके लिये नवीन निर्वाचन कराये जाते हैं। इस समय कैंटनों के मतों को ध्यान में नहीं रखा जाता।

3 नवनिर्मित व्यवस्थापिका संशोधन का कार्य करती है एवं उसके प्रारूप तथा कलेवर का निर्माण करती है।

4 दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात् उसे पुनः लोक निर्णय के लिये रखा जाता है। जनमत द्वारा स्वीकृति होने पर उस पर कंटनों के बहुमत की स्वीकृति भी अपेक्षित है। इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में पूर्ण संशोधन करना सम्भव है। स्विटजरलैण्ड में पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया अधिक लोकप्रिय नहीं है। वास्तव में सन् 1874 का संविधान ही इसका अपवाद है। यहाँ पर आंशिक संशोधन ही अधिक लोकप्रिय है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि संविधान में पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव को व्यवस्थापिका द्वारा ही रखा जाना आवश्यक नहीं है। इस उद्देश्य का प्रस्ताव वहाँ के 50 000 नागरिकों द्वारा भी रखा जा सकता है। इस स्थिति में लोक निर्णय ही यह निर्णय करता है कि संशोधन अपेक्षित है अथवा नहीं।

2 आंशिक संशोधन (Partial Amendment)

इस रूप में संशोधन व्यवस्थापिका की ओर से भी प्रस्तुत किया जा सकता है और जनता की ओर से भी। जब संविधान में आंशिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव जनता की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो वह उपक्रम (Initiative) कहलाता है और उसे 50 000 नागरिक व्यवस्थापिका के सम्मुख निमित्त तथा अनिमित्त (Formulated and Unformulated) दोनों रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव अनिमित्त रूप में है तो व्यवस्थापिका उसका प्रारूप तैयार करके लोकनिर्णय (Referendum) के लिये प्रस्तुत करती है। और यह जानने की चेष्टा करती है कि इस आशय का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। यदि नागरिकों ने संशोधन प्रस्ताव निमित्त रूप में रखा है तो वह प्रस्ताव व्यवस्थापिका में तुरन्त ही लोक निर्णय द्वारा स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु यदि व्यवस्थापिका चाहे तो वह अपनी ओर से भी संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके बकल्पिक रूप में प्रस्तुत कर सकती है और वह भी साथ ही साथ लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका इस प्रकार का पग उसी समय उठाती है जब वह प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं हो पाती। यदि लोक निर्णय संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता है तो व्यवस्थापिका प्रस्ताव में लिये हुए निर्देशों के अनुसार ही संशोधन विधेयक निर्मित करती है। पुनः एक बार वह प्रस्ताव जनता द्वारा स्वीकृति के लिये रखा जाता है। उस प्रस्ताव को कंटनों के बहुमत द्वारा भी स्वीकृत होना चाहिए।

इस प्रकार स्विस संविधान में संशोधन की जिन दो प्रक्रियाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि संशोधन के रूप एवं वांछनीयता का अंतिम निर्णय लोक निर्णय के हाथों में ही है। जनता की शक्ति को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

सशोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन (Estimate of Amending Process)

जसा कि पहल भी कहा जा चुका है स्विटजरलैण्ड में पूर्ण सशोधन, लोकप्रिय नहीं है। सन् 1880 में पचास हजार नागरिकों द्वारा रखा गया आंशिक सशोधन का प्रस्ताव लोक निर्णय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आज के वैज्ञानिक एवं यांत्रिक युग में सविधान में पूर्ण सशोधन करना सम्भव नहीं होता। ऐसा करने के लिए तो पृथक निर्वाचित सविधान निर्मात्री सभा का होना ही आवश्यक है। स्विस् सविधान में सन् 1960 तक लगभग 51 सशोधन हो चुके हैं। अमेरिका के इतने दीर्घकालीन इतिहास में भी इतने सशोधन सुलभ नहीं हो सके। स्विटजरलैण्ड में 'न्यायिक पुनर्विलोकन' (Judicial Review) की व्यवस्था नहीं है और इसी लिए सविधान को गतिशील बनाए रखने का कार्य संवैधानिक सशोधनों ने किया है। सन् 1939 में जनता ने इस आशय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था कि 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संघीय न्यायपालिका को दी जाय'। रपार्ड (Rappard) ने इस ओर संकेत किया है कि स्विस् जनता के लिए राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के विद्रोहात्मक स्वरूप के समक्ष अपने देश के मूल कानून में परिवर्तन करना साधारण नियमों एवं विधियों की अपेक्षा अधिक सरल है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विटजरलैण्ड की सशोधन व्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण तिकाय एक साथ ही भाग लेते हैं—कार्यकारिणी परिषद, व्यवस्थापिका, जनता तथा कैंटन एवं लोक निर्णय की व्यवस्था प्रत्येक परिस्थिति में होती आवश्यक है। अमेरिका, रूस तथा भारत में यह व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जनता संवैधानिक सशोधनों में भाग नहीं लेती। स्विस् सविधान में जो सशोधन प्रक्रिया है उसकी अपनी कुछ कमियाँ हैं जो कि निम्न प्रकार हैं।

1 सविधान में सशोधन की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है वह इंगलैण्ड अपवाद रूस की भाँति सरल नहीं है, अपितु यहाँ पर समस्याएँ पारस्परिक रूप से एक-दूसरे के साथ उलझी हुई हैं।

2 सशोधन प्रक्रिया बहुत अप्रत्यक्षी है।

3 सशोधनों के पुष्टीकरण की व्यवस्था भी समय एवं धन का दुरुपयोग ही है। जनता में इतने विवेक का होना निवे संवैधानिक सशोधनों पर कोई निर्णय कर सके, आवश्यकजनक ही है। कानून विशेष योग्यता का विषय है और वह जनता में उपलब्ध नहीं होती। यह भी कम हास्यास्पद नहीं है कि विधायकों के निर्णय अज्ञानी व्यक्तियों के हाथों में समर्पित किए जाएँ।

4 सशोधन की प्रक्रिया राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में अविश्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है।

5 महिला भूतधिकार जैसे प्रगतिशील सशोधन भी सशोधन प्रक्रिया की जटिलता के कारण ही कानून का रूप धारण नहीं कर सके।

6 उपक्रम के द्वारा जब 50,000 नागरिक निर्मित रूप में आंशिक सशोधन सम्बंधी प्रस्ताव विधानपालिका के पास भेजते हैं और उस समय व्यवस्थापिका यदि अपनी असहमति प्रकट करती है तो उसे वैकल्पिक रूप में लोकनिर्णय के समक्ष

प्रस्ताव रखने का अधिकार है। इस प्रावधान से अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा द्वेष को बल मिलता है।

7 राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सदैव ही पराजित आत्म समर्पण की स्थिति में रहना पड़ता है।

स्विस संशोधन प्रक्रिया की अमेरिकी संशोधन प्रक्रिया से तुलना
(Swiss & American Procedures Compared)

(i) स्विटजरलैण्ड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिकी संशोधन प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक सरल एवं जनतन्त्र प्रीय है।

(ii) स्विटजरलैण्ड में जनता को उपक्रम के आधार पर ही संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है। यह अधिकार अमेरिका में जनता को प्राप्त नहीं है।

(iii) अमेरिका में स्विटजरलैण्ड के समान संशोधन के दो रूप—पूण एवं आंशिक नहीं हैं।

(iv) अमेरिका में संघ की इकाइयों को भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है। परंतु यह अधिकार स्विटजरलैण्ड में इकाइयों को प्राप्त नहीं है।

(v) अमेरिका में संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव 3/4 राज्यों से भी स्वीकार होना चाहिये परंतु यह व्यवस्था स्विटजरलैण्ड में नहीं है।

(vi) अमेरिका में यदि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर दोनों सदन सहमत हो तो वह प्रस्ताव लोकनिर्णय के द्वारा निर्णित नहीं किया जाता, परंतु यह प्रावधान स्विटजरलैण्ड में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका भंग कर दी जाती है और नवीन निर्वाचन होते हैं।

(vii) अमेरिका में 13 राज्य एक मत से संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन करने से रोक सकते हैं परंतु स्विटजरलैण्ड में यह सम्भव नहीं है क्योंकि वहाँ पर 11½ कंटन अपना मत तो अवश्य देते हैं परंतु वे भी प्रगति को नहीं रोक सकते।

(viii) अमेरिका में यह निश्चित नहीं है कि कितने समय में राज्य संशोधन के सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त करें। उदाहरणार्थ—एक संशोधन पर ओहियो राज्य ने अपनी सहमति 80 वर्ष पश्चात् प्रदान की थी। इसके विपरीत स्विटजरलैण्ड में लोकनिर्णय की व्यवस्था इतनी शक्तिशाली है कि प्रक्रिया एवं स्वीकृति में देर का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ix) अमेरिका में संवैधानिक संशोधनों को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है और इसके समक्ष व्यवस्थापिका भी स्वयं अपने आप को असमर्थ पाती है परंतु स्विटजरलैण्ड में यह सम्भव नहीं होता, वहाँ पर संघीय न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।

स्विटजरलैण्ड की संघ व्यवस्था
(Swiss Federal System)

संघात्मक व्यवस्था आज के युग की सबसे अधिक उपयोगी व्यवस्था समझी

जाती है। सघ राज्य समझौतावादी होते हैं। यह के द्वािकरण तथा विकेन्द्रीकरण का सामजस्य है। हम इसे सामांय एव प्रादेशिक शासको के मध्य सामजस्य कह सकते हैं। फाइनर के अनुसार 'सघ राज्य वह है जिसमे अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों मे ही निहित होता है और दूसरा भाग एक के द्वािक सस्था मे।' भारत, रूस, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों मे सघात्मक व्यवस्था ही पाई जाती है। स्विटजरलैण्ड ने भी सघात्मक व्यवस्था को अपनाया है।

कभी कभी स्विटजरलैण्ड की सघात्मकता के विषय मे सका प्रकट की जाती है कि वह एक सघ है अथवा नहीं। कुछ लेखक स्विटजरलैण्ड को सघ मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार स्विटजरलैण्ड सघात्मकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उसे वे परिसघ (Confederation) कहना अधिक उचित समझते हैं क्योंकि वे इसे कैंटनो का शिथिल समूह मानते हैं। सविधान मे भी स्विटजरलैण्ड को परिसघ ही कहा गया है जोकि उचित नहीं है। वस्तुतः यह तो निश्चित ही है कि वह अरब गणराज्य जैसा परिसघ नहीं है। स्विस सविधान का अनुच्छेद 3 ही यह भ्रम उत्पन्न करता है क्योंकि उसके अंतगत उन विषयों क सम्बध में जो केन्द्र को नहीं दिये गये हैं कैंटनो की सरकारों को सप्रभु कहा गया है। परंतु स्विस सवैधानिक विकास की उन्मुखता केन्द्रवाद की ओर अधिक रही है। कैंटनों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है और उसका वे प्रयोग भी करते हैं। कैंटनो के अपन अपने सविधान हैं और अनुच्छेद 6 के अनुसार उन पर केवल एक ही प्रतिबंध है कि सविधान का स्वरूप गणतन्त्रात्मक होगा और सविधान का कोई भी अंग सघीय सविधान के विपरीत नहीं होगा। सघ शासन हम उसे कहते हैं जिसमे द्वैध शासन व्यवस्था (Dual Polity), शक्तियों का वितरण, सविधान की सर्वोच्चता एव स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि विद्यमान हो। यदि हम स्विस सविधान को सघात्मकता की इस कसौटी पर बस बर देखें तो हम यह अनुभव करेंगे कि वह वास्तव मे एक सघ ही है। स्विस सविधान मे सघात्मकता के तत्त्व (Federal Elements in Swiss Constitution)

स्विस सविधान मे परिसघ शब्द का प्रयोग केवल एक औपचारिकता माना ही है। स्विटजरलैण्ड का सवैधानिक इतिहास केन्द्रीकरण की ओर झुका हुआ है। वहाँ के निवासियों ने सदैव ही केन्द्रीय शासन को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। स्विस परिसघ के विघटन की कोई संभावना नहीं है। वह शिथिलता के बगार पर खड़ा हुआ नहीं है। अमेरिका की भांति स्विम कैंटन भी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये किसी भी सीमा तक अपनी सप्रभुता का परित्याग करने को तत्पर थे। स्विस सघ की अटूटता तथा उसके स्थायित्व को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। स्विस सघ को शाश्वत कैंटनों का शाश्वत सघ बना दिया है। स्विस सघ मे 19 पूरा कैंटन हैं तथा 6 अर्धकैंटन हैं। स्विस सविधान की प्रमुख इकाइयाँ हैं—बेर्न उपरिषद, बौद उरी, जुग औरगो बस, जेनेवा रिसनो आदि। स्विम सविधान में सघात्मकता के निम्नलिखित तत्त्व विद्यमान हैं—

(1) सरकारों के दो समूह (Two Sets of the Government)—
स्विम सघात्मक व्यवस्था में सरकारों के दो समूह हैं—राष्ट्रीय सरकार तथा कैंटन

की सरकारें। केन्द्र तथा कैंटनों की सरकारें एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। परन्तु वे एक दूसरे को नष्ट भी नहीं कर सकती। संघ की इकाइयों को स्वेच्छा से पथक होने का अधिकार नहीं है। केन्द्र तथा कैंटनों की सरकारों के अपने अपने क्षेत्र निश्चित हैं जिनमें वे स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक कैंटन का पथक संविधान है। उन्हें नागरिकता के अपने अपने नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी यायपालिका भी रखी गई है। अमेरिकी सीनेट की भाँति कैंटनों की केन्द्रीय व्यवस्थापिका के वरिष्ठ सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रत्येक पूर्ण कैंटन दो सदस्य तथा अर्द्धकैंटन एक सदस्य प्रेषित करता है। इससे हमें यह संकेत भी मिलता है कि केन्द्र संघ की इकाइयों पर अवलम्बित है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की भाँति सम्मेलन प्रक्रिया द्वारा स्विस् संघ का भी निर्माण हुआ है। 3 कैंटनों से प्रारम्भ होकर यह 19 पूर्ण तथा 6 अर्द्ध कैंटनों तक पहुँच गया है।

(2) शक्तियों का वितरण (Distribution of Powers)—स्विस् संघ में भी शक्तियों एवं अधिकारों का वितरण केन्द्रीय तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघीय अनुसूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गये हैं। इसमें वे विषय हैं जिनको कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय महत्व का समझा है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध की घोषणा, मुद्रा, उच्च शिक्षा, डाक एवं तार, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य विशेषकर छूतवाली बीमारियाँ एवं भूखली पकड़ना आदि। इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का एक मात्र अधिकार केन्द्र को है।

समस्तानि अनुसूची का अन्तर्गत स्विस् संविधान में किया गया है। इसमें उन विषयों को रखा गया जिनके सम्बन्ध में केन्द्र तथा कैंटनों दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। ये विषय हैं—प्रेस, उद्योग, बैंक व्यवसाय, आप्रवासन (Immigration) आदि। यदि इन विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र तथा कैंटनों की सरकारों में विरोध हो जाता है तो संघीय सरकार के निर्णय को प्राथमिकता मिलती है।

स्विस् संविधान में कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन्हें विभक्त अधिकारों की सजा दी गई है। विदेशों से संधियाँ करने का अधिकार, सेना की व्यवस्था, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा अलगाव आदि ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में कैंटनों को अधिकार तो दिये गये हैं परन्तु केन्द्र को उनके संचालन के सम्बन्ध में निरीक्षण करने का अधिकार है। निरीक्षण का उद्देश्य यह होता है कि कैंटन अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर रहे हैं अथवा नहीं। कैंटनों को सीमित क्षेत्र में ही अपने निकटवर्ती देशों से संधियाँ करने का अधिकार है।

इस प्रकार शक्तियों का विभाजन केन्द्र तथा इकाइयों के मध्य किया गया है। अमेरिकी आदर्श पर अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) कैंटनों को दी गई हैं जो कि अस्पष्ट एवं प्रारम्भिक हैं तथा जिनका स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। केन्द्र की शक्तियाँ स्पष्ट, प्रदत्त एवं अविविक्त हैं। बनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं और विशिष्ट शक्तियाँ संघ की इकाइयों को प्रदान की गई हैं।

(3) **सविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)**—सविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। विवादों का निणय सविधान के उपबन्धों के अनुसार ही होता है। सविधान की सर्वोच्चता से आशय सविधान की कठोरता से भी है जोकि वहाँ पर विद्यमान है। स्विस सघीय न्यायालय को सविधान के उपबन्धों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है, सविधान के समस्त अंग अपनी शक्ति सविधान से ही प्राप्त करते हैं। कैंटनो की सरकारों के पास जो स्वायत्तता है वह केन्द्र द्वारा प्रवृत्त नहीं है अपितु सविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं। केन्द्र तथा कैंटन दोनों ही सविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। सघीय न्यायापालिका को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है।

(4) **न्यायपालिका की सर्वोच्चता (Supremacy of the Judiciary)**—इस कसौटी पर स्विस सविधान खरा नहीं उतरता। सविधान की रक्षा करने में सघीय न्यायपालिका अपने को असमय पाती है। न्यायपालिका किसी भी कानून के सविधान का अतिक्रमण करके उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। न्यायपालिका की शक्ति को केवल इस दृष्टि से ही सीमा रखा गया कि स्विस जनता, जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में विश्वास करती है। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती थीं।

अतः यह स्पष्ट है कि अंतिम विशेषता को छोड़कर स्विटजरलैण्ड के सविधान में सघात्मकता के समस्त गुण पाये जाते हैं। यदि स्विस सविधान परिस्रष्ट होता तो वह कभी का बिखर गया होता। स्विस सविधान का विकास भी अथवा सघीय सविधानों के सदृश ही केंद्रीयकरण की ओर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्विटजरलैण्ड केवल तटस्थता की नीति का ही अनुसरण कर सकता है।

स्विस सविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति (Tendency for Centralization)

स्विस सविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 'सघीय सविधान की सीमाओं में कैंटनो को प्रभुसत्ता सम्पन्न कहा गया है।' सघीय सीमा तथा प्रभुसत्ता सम्पन्नता दोनों एक साथ सम्भव नहीं हैं। इसके साथ ही साथ यह व्यवस्था भी है कि कैंटनों के नियम सघीय नियमों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इससे कैंटन केन्द्रीय इच्छा के अधीन हो जाते हैं। सप्रभुता सूचक समस्त शक्तियाँ केन्द्र में एकत्रित कर दी गई हैं। यदि कैंटन सघीय विधि तथा अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं तो सघ के पास कायबाही एवं हस्तक्षेप करने के अनर्को साधन हैं परन्तु इसके विपरीत यदि सघ कैंटनों के स्वतंत्रता का हनन करता है तो उसके पास केन्द्र से प्रतिशास्य लेने का कोई साधन नहीं है। कैंटनो के पास केवल स्थानीय महत्त्व की शक्तियाँ ही हैं, सघीय सरकार को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वे इतने व्यापक हैं कि सघ प्रत्येक समय कैंटनों की सरकारों पर आच्छादित रहता है। कैंटनों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल भी कोई अस्तित्व नहीं है।

इसके अतिरिक्त कैंटनों के पारस्परिक विवादों में केन्द्र का निणय अंतिम है। कैंटनो को यह अधिकार नहीं है कि वे सघ से पृथक् हो सके अथवा पारस्परिक रूप में किसी प्रकार के समझौते कर सकें। कैंटनों की आर्थिक दृष्टि से भी केन्द्र की वित्तीय सहायता पर ही निर्भर रहना होता है। अशांति की स्थिति में भी उन्हें केन्द्र से ही सहायता की माँग करनी होगी। कैंटनों की सर्वोच्च न्यायालय का

संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। स्विस संघीय न्यायालय को संघीय कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। परंतु कैंटनों के सम्बंध में अवश्य ही निषेधात्मक अधिकार प्राप्त है।

कैंटनों को संविधान में संशोधन करने के लिए केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती है और वह स्वीकृति भी इस आवश्यक प्रतिबन्ध के साथ ही प्रदान की जाती है कि संशोधन संघीय नियमों के अनुकूल ही होना चाहिये। संविधान द्वारा कैंटनों को जो स्थिति प्रदान की गई है वह भी कुछेक अपवादों के अतिरिक्त भारतीय संघ के राज्यों जैसी ही है। डूपरीज ने इस सम्बंध में तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए कहा है कि "स्विस संविधान में परिषद को ऐसा रूप प्रदान किया गया है, मानो वह कैंटनों का मिश्रक तथा निरोधक हो।" स्विस संविधान की केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति का सार रूप में हम इस प्रकार भी रख सकते हैं —

- (i) आवश्यकता एवं अग्रांति की स्थिति में कैंटन का प्रशासन संघ सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है।
- (ii) कैंटनों पर संघ का प्रभुत्व है अतएव वे सकुचित रूप में भी प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं हैं।
- (iii) कैंटनल कानून संघीय कानून का विरोधी नहीं हो सकता।
- (iv) कैंटनों के पास केवल स्थानीय महत्व की शक्तियाँ ही उपलब्ध हैं।
- (v) उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है।
- (vi) कैंटनों को संघ के विरुद्ध सर्वोच्च यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- (vii) कैंटनों के परस्पर विवादों में भी संघ सरकार का निणय ही अंतिम है।
- (viii) कैंटनों को संविधान में संशोधन के लिए संघ की स्वीकृति लेनी पड़ती है।
- (ix) संघीय न्यायालय कैंटनों के कानूनों को अवैध घोषित करने का भी अधिकार रखता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—

इसमें सन्देह नहीं है कि स्विस संविधान में आर्थिक आवश्यकताएँ, सुरक्षाएँ, औद्योगिक माँग तथा समाजवादी प्रभाव के कारण केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है, और यह राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप हेतु अधिकाधिक हस्तक्षेप की अपेक्षा भी करता है, परंतु इससे हमें यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि संघ की इकाइयाँ केवल सर्वप्राणिक शून्य मात्र हैं। स्विस संघ में कैंटनों का कोई स्थान नहीं है। विज्ञान की प्रगति, यांत्रिक शक्ति तथा यातायात के सम्पन्न साधनों ने ही केन्द्रीकरण की स्थिति को बढ़ावा दिया है परंतु फिर भी उसमें कैंटनों का महत्व कम नहीं हुआ है। ब्रूक्स (Brooks) ने अनुसार कैंटन अब भी सक्रिय राजनैतिक जीवन के केन्द्र हैं। कैंटनों का अपना राजनैतिक जीवन एवं महत्व है। केन्द्रीय हस्तक्षेप तथा उद्दण्ड व्यवहार के विरुद्ध कैंटनों के पास अब भी प्रारम्भिक तथा लोक निणय की शक्ति है जो संघ को मर्यादाओं में रखने के लिए पर्याप्त है। नागरिकों के जीवन में संघीय शासन की अपेक्षा कैंटनों का महत्व अधिक है।

जनता नागरिक स्वतंत्रता एवं कैंटनो की स्वायत्तता पर कुठाराघात को कभी भी सहन नहीं करेगी। स्वतंत्रता की रक्षा केवल नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों से नहीं हुआ करती अपितु वह जागृति तथा चेतना से ही हुआ करती है जोकि स्विस नागरिका में अपने अधिकारों के प्रति विद्यमान है। वहाँ के नागरिक इस सत्य को भली भाँति समझते हैं कि राष्ट्र में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रगति तभी हो सकती है जब तक कि कैंटनो की स्वतंत्रता की रक्षा होती रहेगी। कैंटनो को राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के बरिष्ठ सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है जोकि उनकी शकाओं के समाधान के लिये पर्याप्त है। कैंटनो को बारी बारी से संघीय परिषद में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद प्राप्त करने का अधिकार है। समवर्ती अनुसूची के विषयों के सम्बन्ध में भी कैंटनो की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त संघीय सरकार कैंटनो की जनता पर प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं लगा सकती है। यह प्रावधान कैंटनो को सघ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त है। कैंटनों को नागरिकता के सम्बन्ध में भी अपने अपने नियम बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कैंटनों को सेनाएँ रखने का अधिकार भी है। अतः में हम यही कहेंगे कि स्विटजरलैण्ड में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है परन्तु कैंटन लोकतन्त्र की प्रयोगशालाएँ हैं। बिना उनके सहयोग के केन्द्र का अस्तित्व ही क्या है। इसमें दो मत नहीं कि हमें एंड्रे (Andre) की चेतावनी के प्रति भी सजग रहना चाहिए कि "इस विकासमान केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में यह भय निहित है कि जैसे जैसे केन्द्रीय शक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में बढ़ि करेगी वैसे-वैसे ही कैंटनों की प्रभुता नष्ट होनी जायगी और अतः में उनका स्वरूप माध्यम प्रशासन के जिले मात्र का ही रह जायगा अर्थात् केन्द्रीय शासन की प्रत्येक आज्ञा को कार्यान्वित करना ही उनका काम रह जायगा।" परन्तु हमें इस सम्बन्ध में आज के युग की माँग को नहीं भूलना चाहिए। स्विटजरलैण्ड तटस्थता की नीति का कितना भी अनुयायी क्यों न हो उसके निकट जर्मनी, फ्रांस तथा इटली जैसे सशक्त राष्ट्र भी रहते हैं। उदाहरणार्थ—हिटलर ने बेल्जियम की तटस्थता की घञ्जियाँ बिखेर दी थीं। बोर्नोर्न न उचित ही कहा है कि "कैंटन एवं छोटे छोटे राष्ट्र अपने राजनैतिक संगठन को पूर्ण बनाने के लिये और लोकतन्त्र की संस्थाओं का विकास करने के लिये व्याकुल हैं।"¹

अमेरिकी तथा स्विम संघ व्यवस्था की तुलना (American & Swiss Federal Systems Compared)

स्विटजरलैण्ड की शासकीय एवं वैधानिक रचना पर हमें कहीं कहीं अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दोनों ही देशों में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के बरिष्ठ सदन का प्रयोग संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये किया गया है। संविधान लिखित एवं कठोर है। दोनों ही देशों में संवैधानिक विकास का क्रम संघात्मकता की ओर रहा है। दोनों ही संघों में इकाइयों की संख्या में वृद्धि घटती जा रही है। दोनों ही

1 Cantons are small nations animated by a ceaseless desire to perfect their political organization and to develop their democratic institutions

संविधानों में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं। दोनों में ही सघातमकता के गुण भी पाये जाते हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में संविधान का आधार मौलिक रूप में शक्तियों का पृथक्करण है जोकि स्विटजरलैण्ड में नहीं है। दोनों की संशोधन व्यवस्थाओं में भी भिन्नता है। इसी प्रकार दोनों देशों की संघ प्रणालियों में भी अंतर है।

(i) अमेरिकी संविधान में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग संघ सरकार के लिये निषिद्ध है और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग राज्य नहीं कर सकते परंतु इस प्रकार का कोई प्रावधान स्विस संविधान में नहीं है।

(ii) अमेरिका में यदि शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस सम्बन्ध में न्यायाधिकार का निर्णय अंतिम माना जाता है। परंतु स्विस संघ व्यवस्था में संघीय अतिक्रमण के विरुद्ध कंट्रोल को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

(iii) यदि अमेरिकी संघ की इकाइयों में कोई परस्पर विवाद होता है तो उसके निराकरण का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है परंतु स्विटजरलैण्ड में इस प्रकार के विवादों में अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार का ही होता है।

(iv) अमेरिका में संघीय कानूनों को अवश्य घोषित करने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है परंतु स्विटजरलैण्ड में यह अधिकार संघीय न्यायपालिका को कंट्रोल की सरकारों के सम्बन्ध में ही प्राप्त है परंतु संघीय कानून के विरुद्ध यह विवश है।

(v) स्विटजरलैण्ड में संघीय न्यायालय इतने स्वतंत्र नहीं है जितने कि अमेरिका में क्योंकि वहाँ संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा होता है।

(vi) अमेरिका में संवैधानिक संशोधनों पर पुष्टि संघ की इकाइयों के विधान मण्डलों द्वारा होती है और स्विटजरलैण्ड में कंट्रोल की जनता द्वारा।

(vii) स्विटजरलैण्ड की भांति अमेरिकी संघ में राज्यों को अपने संविधानों में संशोधन करने के लिए संघ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(viii) अमेरिका के संविधान में अमेरिका को राज्यों का समुक्त रूप कहा गया जबकि स्विटजरलैण्ड में उसे केवल परिसंघ (Confederation) कहा गया है।

(ix) स्विटजरलैण्ड में संघ की इकाइयों को अपने यहाँ सेना रखने का अधिकार है परंतु इस प्रकार का कोई अधिकार अमेरिका में राज्यों को प्राप्त नहीं है।

(x) स्विटजरलैण्ड में कंट्रोल की निकटवर्ती राज्यों से संघीय निरीक्षण में वाणिज्य समझौते करने का अधिकार है परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है।

(xi) अमेरिका में संविधान में संशोधन करने के लिए आरम्भिक तथा लोक निर्णय (Initiative & Referendum) आदि की व्यवस्था है परंतु स्विटजरलैण्ड में ऐसा नहीं है।

(xii) स्विटजरलैण्ड में पूर्ण तथा अर्द्ध कंट्रोल की व्यवस्था है परंतु इस प्रकार का कोई वर्गीकरण अमेरिकी संघ की इकाइयों में नहीं है।

(xiii) अमेरिकी संघ में कर लगाने की शक्ति जितनी व्यापक है उतनी व्यापक स्विटजरलैंड में नहीं है। वहाँ कर कटनो के माध्यम से ही कर लगाये जाते हैं।

(xiv) स्विटजरलैंड में केन्द्रशासन जितनी स्वच्छदता के साथ कटनो के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है उतनी स्वच्छदता के साथ अमेरिका में सम्भव नहीं है।

Select References

- Brooks : *Govt of Switzerland*
 Hands Huber : *How Switzerland is Governed*
 Reppard : *Govt of Switzerland*
 Munro : *Govts of Europe*
 Bryce : *Modern Democracies Vol 1*
 Huner : *Theory & Practice of Modern Govts*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 स्विस् संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
 Describe the basic features of Swiss Constitution
- 2 स्विटजरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा उसकी तुलना अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रणाली से कीजिए।
 Discuss the process of Amending the Swiss Constitution and compare it with the process of Amending the American constitution
- 3 स्विटजरलैंड की संघ व्यवस्था का उल्लेख कीजिए तथा उसकी तुलना अमेरिकी अथवा रूस की संघ व्यवस्था से कीजिए।
 Discuss the Swiss Federalism and compare it either with American or Soviet Federalism

2

संघीय कार्यपालिका

[Swiss Federal Executive]

"The Federal Council (Bundesrath) is one of the institutions of Switzerland that deserves study"

—Bryce

"संघीय परिषद राष्ट्रीय सरकार का मुख्य स्रोत है और वह निश्चय ही उसका सतुलन चक्र है"

—सर्विल

परिचयात्मक

जी० ए० कौडिंग के शब्दों में "इस अनोखे छोटे देश की अनोखी संस्था जिस देह संघीय परिषद अर्थात् स्विस् संघीय कार्यपालिका है। स्विटजरलैण्ड की कार्यपालिका शक्ति एक परिषद में निहित है जिसका स्वरूप न तो संसदात्मक ही है और न ही अध्यक्षतात्मक। हम इसे दोनों प्रणालियों का समुक्त रूप भी नहीं कह सकते। यह अपने ढंग की एक अनोखी ही संस्था है जोकि वहाँ के लिए कोई नई वस्तु नहीं थी। संविधान निर्माता इससे पहले ही परिचित थे। वहाँ की जनता का ऐसा विश्वास था कि कार्यपालिका शक्ति को एक व्यक्ति के हाथों में समर्पित करने की अपेक्षा एक संस्था के हाथों में समर्पित करना ही अधिक श्रेयस्कर है। वे इस व्यवस्था को अधिक जनतन्त्रीय समझते थे। कुलीनतन्त्र में शासन सत्ता कुलीनों की परिषद को ही समर्पित की जाती है क्योंकि इस व्यवस्था को ही उन्होंने संघीय स्तर पर कार्यान्वित किया है। इस परिषद की कुछ बातें मौलिक हैं। प्रो० वे० के० मिश्रा के अनुसार "वास्तव में यह विदेशी कलम नहीं अपितु स्वदेशी पौधा है।" स्विस् संघीय कार्यपालिका बहुत कुछ स्विस् निवासियों के स्वभाव के ही अनुकूल है। वहाँ पर राजनतिक विवाद उपग्रह रूप में उत्पन्न नहीं होते। वे इसके स्थान पर संसदीय प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षतात्मक राष्ट्रपति (जिनका बमजोर होना अवसर की बात है) रक्षना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझते थे।

स्विटजरलैण्ड एक तटस्थ देश है। वह चारों ओर फौलादी राष्ट्रों से घिरा हुआ है परन्तु फिर भी वह पैर फटकार सोता है। न किसी के उत्तरुप से उसे प्रसन्नता होती है और न ही किसी के पतन में गम के आँसु फूटते हैं। वह तो विश्व राजनीति का निष्पक्ष दणक है। वह भावनाओं से ऊपर गुटों के चक्कर में आकर पाकिस्तान जैसी आँखमिचीनी नहीं खेसता। उस हाइड्रोजन बम का डर भी नहीं है और न ही रॉकेट की चिंता एवं उसे प्रक्षेपास्त्रों की मार का भी खतरा नहीं है। वहाँ पूँजीवा-

अवश्य है परंतु वर्गीय एकाधिकार नहीं है। यहाँ पर वय सघष का ताण्डव नृत्य देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर न तो सकट ही है और न ही युद्ध, न सघष और न संयोजरण। इसी कारण स्विसवागियो ने बहुल कायपालिका को अपनाया है।

सघीय परिषद का सगठन

(Organization of the Federal Council)

सदस्यता—स्विस सविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार सघीय कायपालिका के सदस्यों की संख्या 7 रखी गई है। कायपालिका शक्तियाँ सामूहिक रूप से इन्हीं के हाथों में समर्पित की गई हैं। आधुनिक राज्य के काय भार को दृष्टिगत रखते हुए यह संख्या कम ही समझी जायगी। संख्या में वृद्धि करने हेतु 1900 तथा 1942 में दो बार प्रयत्न भी किये गये परंतु दोनों बार ही संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। स्विस जनता ने बहुल कायपालिका के स्वरूप को इसीलिए अंगीकृत किया है क्योंकि वे यह समझते थे कि एकल कायपालिका राजतंत्र का गभस्थ शिष्टु है। सघीय परिषद को व्यापक बनाने की दृष्टि से ही यह व्यवस्था रखी गई है कि एक ही कैन्टन से दो सदस्य नहीं लिए जा सकते। अतएव किसी भी कैन्टन का इस व्यवस्था से एकल रूप में प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सकता। परम्परा एवं रूढ़ि के रूप में स्विस राष्ट्र के विभिन्न धर्मों, भाषा तथा राजनैतिक दलों को यायोजित रूप में प्रतिनिधित्व अवश्य ही दिया जाता है। बड़े बड़े कैन्टनों को आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने की परम्परा अनिवार्य ही बन गई है। सामान्य रूप से सघीय परिषद में 4 सदस्य जर्मन भाषी 2 फ्रेंच भाषी तथा 1 इटालियन भाषी होता है। परिषद में धार्मिक दृष्टि से 4 प्रोटेस्टेंट तथा 3 कथोलिक सदस्य होते हैं। इसी कारण से परिषद को राजनीतिज्ञों का बेमेल एवं विजातीय समुदाय कहा जाता है। सन् 1929 के पश्चात् बहुधा उदारवादी, कथोलिक, अनुदारवादी क्लक दल तथा साम्यवादी दल को निर्वाचन रूप से सघीय परिषद में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। सदैव से ही ज्यूरिच, बर्न तथा बीद के कैन्टनों का एक एक प्रतिनिधि परम्परानुसार इसका सदस्य रहता है।

योग्यताएँ एवं कायकाल (Qualifications & Tenure)

स्विस सविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार वे समस्त व्यक्ति इसके सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं जोकि राष्ट्रीय परिषद (Federal Legislature) की सदस्यता की योग्यता रखते ह। धर्माधिकारी (Clergy) इसमें सदस्य नहीं बन सकते। सघीय परिषद में ऐसे दो सदस्य नहीं रह सकते जोकि एक दूसरे से रक्त संबंध रखते ह। सघीय परिषद का सदस्य बन जाने के पश्चात् उसका कोई भी सदस्य कैन्टनों के किसी भी लाभकारी पद पर पदारूढ़ नहीं रह सकता और न ही उन्हें राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य बने रहने की अनुमति होती है। उन्हें व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। परंतु वे व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की कायवाहिया में भाग लेते हैं किंतु मतदान नहीं करते। निर्वाचन के समय सदस्यों की प्रशासकीय योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनुभव की अधिकार दिया जाता है। और यही कारण है कि लोग बहुत सम्ये समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। उदाहरणार्थ—श्री मोट्टा 30 वय तक इसके सदस्य बने रहे एवं श्री बीफ 27 वय तथा बेंस्टी भी 25 वय तक इसके सदस्य रहे।

संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के प्रतिनिधियों में से किया जाता है। यद्यपि संघीय परिषद के सदस्य 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं परंतु जैसाकि ऊपर कहा गया है, वे अपने अनुभव, प्रशासकीय योग्यता एवं मधुर व्यवहार के कारण सम्बन्धी अवधि तक भी बार-बार उसी सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। सन् 1931 से पूर्व संघीय परिषद का कार्यकाल केवल 3 वर्ष था। सामान्यतः इसके सदस्य 10 वर्ष के लिए रहते हैं। निर्वाचन में प्रशासकीय अनुभव एवं बौद्धिक योग्यता के अतिरिक्त सीम्प स्वभाव का विशेष प्रभाव होता है। कोडिंग के अनुसार भी सदस्यों को लोकप्रिय बनने के लिए विनम्रता की अति आवश्यकता होती है। संघीय परिषद के गठन में भौगोलिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है।

वेतन एवं उन्मुक्तियाँ (Emoluments & Immunities)

संघीय कार्यपालिका के सदस्यों को 80 000 फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है और परिषद के अध्यक्ष को 90,000 फ्रैंक मिलते हैं। यह वेतन अधिक नहीं है। परिषद के सदस्य बड़ी ही सादगी से रहते हैं। जो सदस्य 55 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और जो सदस्य कम से कम 10 वर्ष तक संघीय परिषद के सदस्य रह चुके हों उनके लिए निवृत्ति वेतन (Pension) भी मिलता है। इसके अतिरिक्त संघीय परिषद को निम्नलिखित उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हैं—

1 सेवा काल में संघीय परिषद के सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त हैं।

2 संघीय परिषद के सदस्यों पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु यदि स्वेच्छा से परिषद इस प्रतिबन्ध को हटावे तो मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यदि संघीय परिषद इस प्रतिबन्ध को न हटावे तो उस प्रश्न को संघीय सभा में ले जाया जा सकता है। यदि संघीय व्यवस्थापिका इस विशेषाधिकार को समाप्त कर देती है तो मुकदमा संघीय न्यायाधिकरण में चलाया जा सकता है। संघीय परिषद के सदस्यों के नागरिक अधिकार उनके सम्बन्धित कानूनों में सुरक्षित रहते हैं।

अधिवेशन (Sessions)

संघीय परिषद की बैठकें कम से कम सप्ताह में दो बार होती हैं। गणपूर्ति के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित होती है। इसमें निर्णय बहुमत के द्वारा होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसका स्वरूप ससदारमक नहीं है। परिषद की बैठकें स्विटजरलैंड की राजधानी बर्न में होती हैं। परिषद के अध्यक्ष की निष्ठात्मक मत देने का अधिकार होता है। परिषद का अध्यक्ष ही स्विटजरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है और उपराष्ट्रपति उसका उपाध्यक्ष होता है।

संघीय परिषद के पदाधिकारी (Officers of the Federal Executive)

1 अध्यक्ष (President) — संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही स्विटजरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। उसका निर्वाचन संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है। संविधान की धारा 98 के द्वारा उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह दूसरे वर्ष उसी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता। उसी लिए संघीय परिषद का सदस्य होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस पद के

लिए अथ किसी प्रकार की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। वह एक से अधिक बार अध्यक्ष तो रह सकता है परन्तु निरन्तर नहीं। उदाहरणार्थ—हर मूलर सन् 1899, 1907 तथा 1913 में अध्यक्ष रहा, डॉ० फिलिप्स एटर 1939, 1942, 1947 तथा 1953 में अध्यक्ष रहे। गुसिप मोट्टा लगभग पाँच बार सघीय कायपालिका के अध्यक्ष रहे। परन्तु वहाँ यह परम्परा पड़ गई है कि बहुधा आगामी वष में उपाध्यक्ष को ही परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन द्वारा पदोन्नत कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन अधिक रोचक होता है क्योंकि उसका आगामी वष में अध्यक्ष बनना लगभग पूर्व निश्चित होता है। अध्यक्ष दूसरे वष उपाध्यक्ष भी नहीं रह सकता है। ये दोनों पद सघीय परिषद के सदस्यों में बारी बारी से घूमते रहते हैं। उपराष्ट्रपति के पास कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहता। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद ग्रहण करता है। दुक्स के शब्दों में राजनैतिक क्षेत्रों में यह जानने की उत्सुकता रहती है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा परन्तु जब से बरिष्ठता के सिद्धांत को प्राथमिकता मिलने लगी है यह उत्सुकता अब उतनी अधिक मात्रा में नहीं रह गई है। अमेरिका तथा भारत के सदृश स्विट्जरलैण्ड का उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के बरिष्ठ सदन का पदेन सभापति नहीं होता।

कार्य (Functions)—सघीय परिषद के अध्यक्ष के निम्नलिखित काम होते हैं

- 1 परिषद की बैठकों का सभापतित्व करना।
- 2 किसी एक प्रशासकीय विभाग का संचालन करना।
- 3 वह प्रशासन पर सामान्य निरीक्षण करता है।
- 4 वह औपचारिक नियुक्तियाँ करता है।
- 5 वह राष्ट्रीय उत्सवों की अध्यक्षता करता है।
- 6 वह विदेशी राजदूतों को स्वीकार करता है।
- 7 वह अधिकृत रूप से स्विस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- 8 वह विभागों के विवादों को निपटा कर समावय्य स्थापित करता है।
- 9 वह सकट काल में सघीय परिषद के कार्यों का सम्पादन करता है।

स्थिति (Position)—स्विस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की स्थिति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अथ पापदो से उसकी स्थिति उच्च होती है। उसका स्थान प्रशासकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने अथ साधियों के सदृश वह भी एक विभाग का अध्यक्ष होता है। मुनरो ने उसकी स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि 'वह सघ का केवल नाम धारी प्रमुख है। वह किसी भी रूप में प्रधानमन्त्री नहीं है।'¹

सकटकाल में वह अपने प्रारम्भिक पर उचित कार्यवाही कर सकता है परन्तु बाद में उसे अपने अथ साधियों से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी नहीं है क्योंकि वह प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और उसे विधेयक पर निषेधाधिकार (Veto) के प्रयोग करने का भी अधिकार नहीं है। उसे

1 He is merely titular head of the confederation. He is in no sense a Prime Minister. —Munro

ब्रिटिश सम्राट जैसा गौरव भी प्राप्त नहीं है। उसकी स्थिति की तुलना हम प्रधान-मंत्री से भी नहीं कर सकते क्योंकि वह परिषद के सदस्यो में प्रथम नहीं है। प्रधान-मंत्री की भांति वह परिषद की धुरी और उसका जीवन नहीं है। वह अपने साधियों को विमुख करके कोई भी निणय नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री उसके समान राष्ट्र का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है। परंतु स्विस संघीय परिषद का अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सदृश सदन का नेतृत्व नहीं करता और न ही उसे प्रधानमंत्री की भांति सदन का विघटन कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र मां त्रमण्डल का त्यागपत्र होता है परंतु स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष का त्यागपत्र परिषद का त्यागपत्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री की भांति वह अपने साधियों को न तो नियुक्त ही करता है और न ही पदच्युत करता है। हम अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि उसकी स्थिति सम्राट तथा प्रधानमंत्री के बीच की है और वह भी क्षीण रूप में। लॉवेल (Lowell) ने तो उसकी स्थिति आँते हुए यह कहा है कि एक औपचारिक अध्यक्ष के रूप में स्विस राष्ट्रपति यह जानने का इच्छुक अवश्य रहता है कि उसके साथी क्या करने और क्या कराते हैं अर्थात् उनका आचरण नियमों के अनुकूल हो रहा है अथवा नहीं। संघीय परिषद की स्थिति के विषय में रपड ने लिखा है कि राष्ट्रपति के पद का कोई महत्त्व नहीं है। यह पद उसे कोई पुष्क विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता और न ही उसके प्रभाव में कोई विशेष वृद्धि ही करता है।¹ हंस ह्यूबर (Hans Huber) के अनुसार 'स्विस संघीय परिषद का कोई प्रधान नहीं होता और कैबिनेटों का कोई गवनर नहीं होता।' किंतु दुबस इसे उसकी स्थिति का बड़ा ही दुर्बल मूल्यांकन कहता है। उसके शब्दों में, 'जन सेवा के दीप जीवन के पश्चात् इस पद की सर्वोच्च पारितोषिक के रूप में कामना की जाती है। समस्त स्विस जनता के द्वारा यह पद सम्मानपूर्ण रूप से देखा जाता है।'²

(2) संघीय चांसलर (Federal Chancellor)—स्विस संविधान की धारा 105 में संघीय शासन से सम्बंधित एक अग्र कमचारी का उल्लेख किया गया है जोकि संघीय सचिव (Federal Chancellor) कहलाता है। वह संघीय सचिवालय का अध्यक्ष होता है। संघीय सचिवालय संघीय परिषद से सलग्न होता है। चांसलर की नियुक्ति संघीय सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है। उसकी सहायता के लिए उप चांसलर भी होता है। सन् 1958 में चांसलर के नीचे 20 कमचारी थे। उप चांसलर की नियुक्ति भी संघीय सभा के द्वारा की जाती है। चांसलर परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह संघीय परिषद के कार्यों का विवरण रखता है। वह अपने हस्ताक्षर द्वारा विधेयकों को प्रमाणित करता है, उसे परिषद की बैठकों में उपस्थित रहना पड़ता है। निर्वाचनों तथा लोकनिर्णय के लिए मतदान की व्यवस्था भी उसी को करनी पड़ती है। संघीय

1 Its office has no true national importance It confers no special privileges nor even particular influence —Rappard

2 A such It is sought after as the crowning reward of a long career of public service as such also it commands high measure of the respect of the Swiss People as a whole

सभा के अधिवेशनों में भी उसकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है। राजनैतिक दृष्टि से इस पद का महत्व चाहे कम हो परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से यह पद महत्वपूर्ण है क्योंकि असैनिक सेवाओं के कमचारियों से उसका सम्पर्क रहता है और परिषद के नियम जानने के लिए वे चांसलर से सम्पर्क स्थापित करते हैं। वास्तव में वह समस्त असैनिक सेवा के कमचारियों का प्रधान है। निर्वाचन की व्यवस्था करना भी उसका कर्तव्य है। सभ की चारों भाषाओं में कानूनों का अनुवाद भी वही करता है। चांसलर पद की स्थापना सन् 1931 में हुई है। योग्यता के अनुसार एक ही व्यक्ति ब्रिटिश स्पीकर की भाँति दीर्घकाल तक इस पद पर आसीन रह सकता है।

प्रशासकीय विभाग (Administrative Departments)

हमें सघीय परिषद का कोई सामूहिक रूप दृष्टिगत नहीं होता। उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी नहीं होती है। प्रायः यह कहा जाता है कि स्विटजरलैण्ड में सात कार्याकारिणों सदस्य तो अवश्य हैं परन्तु कोई कार्याकारिणी परिषद नहीं है। सात सदस्यों के पास सात पृथक्-पृथक् विभाग होते हैं। एक विभाग का प्रधान दूसरे विभाग का उपाध्यक्ष होता है। सब सदस्य परस्पर बैठकर विभागों का वितरण करते हैं। बहुधा विभागों में परिवर्तन बहुत कम ही होता है। अनुभव का लाभ उठाने के लिए यथासम्भव विभागों को पुनर्व्यवस्था की रहने दिया जाता है। यद्यपि नियम सामूहिक रूप से ही होते हैं किन्तु कोई भी विभागाध्यक्ष अपने प्रारम्भिक पर अपने विभाग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भी नियम कर सकता है और बाद में परिषद से उसका अनुमोदन प्राप्त कर लेता है। प्रमुख प्रशासकीय विभाग इस प्रकार हैं—

- 1 राजनैतिक विभाग (Political Deptt.)
- 2 गृह विभाग (Department of Interior)
- 3 न्याय तथा आरक्षी विभाग (Justice & Police)
- 4 सेना विभाग (Military Department)
- 5 वित्त एवं सीमा शुल्क विभाग (Finance & Custom)
- 6 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विभाग (Deptt. of Public Economy)
- 7 यातायात एवं संचार विभाग (Transport & Communication)

इनमें से समस्त विभागों का महत्व एक समान नहीं होता है। इन सब विभागों में महत्वपूर्ण विभाग राजनैतिक विभाग है जो विदेश नीति, सीमा विवादों, निर्वाचनों तथा लोक नियम की व्यवस्था आदि से सम्बन्ध रखता है। सेना विभाग स्विटजरलैण्ड में महत्वपूर्ण नहीं है। न्याय विभाग का अध्यक्ष कोई विधि विशेषज्ञ ही होता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश परम्परा के विपरीत है क्योंकि यहाँ पर न्यायियों को अपने विभागों का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है।

सघीय परिषद के कार्य (Functions of Federal Executive)

स्विस संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत सघीय परिषद की शक्तियाँ

एक कार्यों की एक सम्बन्धी सूची दी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 95 में संघीय परिषद को स्वयं परिषद में सर्वोच्च निर्देशिका एवं कार्यपालिका शक्ति के रूप में देखा गया है। प्रमुख रूप से संघीय परिषद के कार्य प्रशासकीय हैं। परिषद के अंतर्गत प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना का पूर्ण उत्तरदायित्व संघीय परिषद पर ही है। संघीय कानूनों को क्रियान्वित करना तथा परिषद के सदस्यों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करने का काम भी संघीय परिषद का है। यायाधिकरणों की शक्ति ही संघीय कार्यपालिका है। संघीय शासकीय तंत्र भी इसी के आदेशानुसार ही आचरण करता है। संघीय परिषद के पास प्रशासकीय शक्तियों के अतिरिक्त विधायी एवं वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। परंतु हम सबसे प्रथम उसकी प्रशासकीय शक्तियों का ही उल्लेख करेंगे।

(1) प्रशासकीय शक्तियाँ (Administrative Powers)

(1) संघ में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा स्विटजरलैंड की तटस्थता बनाए रखने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी का ही है।

(2) संघीय सेना का अधीक्षण संघीय परिषद का कार्य है। इसके सम्बन्ध में कुछ प्रतिबंध भी हैं। यदि संघीय सभा का अधिवेशन न हो रहा हो और परिषद को सेना का प्रयोग 3 सप्ताह से अधिक के लिए करना हो अथवा 2000 सैनिकों से अधिक के प्रयोग करने का प्रश्न हो तो तुरंत ही महासभा की आपातकालीन बैठक आमंत्रित करनी पड़ती है।

(3) यह कौंटो की परस्पर संधियों या विदेशों से की हुई संधियों का निरीक्षण एवं पुष्टीकरण करती है।

(4) यह संघीय सभा के समक्ष प्रत्येक वर्ष आंतरिक एवं विदेश विभागों के विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। सावजनिक कल्याण के उपायों पर भी विचार करती है। किसी भी सदन की भाँग पर अतिरिक्त विवरण भी प्रस्तुत करती है।

(5) आय तथा व्यय के वार्षिक बजट को तैयार करना परिषद का कार्य है।

(6) परिषद को यह बात भी देखनी पड़ती है कि आवश्यक प्रत्याभूतियों के अनुसार ही कौंटो में संधोधन किये जा रहे हैं अथवा नहीं।

(7) शिक्षा एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी परिषद ही करती है।

(8) कार्यकारिणी को किसी एक अथवा दोनों सदनों को सदेश देने का भी अधिकार है।

(9) विधि निर्माण में भी संघीय परिषद का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है।

(10) संघीय परिषद ऐसी नियुक्तियाँ भी करती है जिनका अधिकार संघीय सभा अथवा संघीय यायाधिकरण को नहीं है।

(11) संघीय कानून तथा अध्यादेशों के अनुसार ही संघीय काम-काज का संचालन करती है।

(12) स्वयं हितों की विदेशों में रक्षा करना इसका कर्तव्य है।

(13) यह प्रशासकीय कमचारियों का निर्देश देती है तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करती है।

(2) विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

संघीय परिषद की शक्तियाँ केवल प्रशासकीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं। विधायी क्षेत्र में भी उसका महत्व कम नहीं है। संघीय परिषद वस्तुतः विधायी गतिविधियों का भण्डार है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं

(i) सांख्यिक प्रकृति के महत्वपूर्ण विधेयक परिषद के द्वारा ही निर्मित किये जाते हैं।

(ii) ये विधेयक संघीय सभा की प्राथम्यता अथवा प्रस्तावों पर ही निर्मित किए जाते हैं।

(iii) संघीय परिषद को कानूनों को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न प्रकार के नियम बनाने का भी अधिकार है। परम्परानुसार संघीय सभा का आदेश मिलने पर अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। आपत्तिकाल में मौलिक अधिकारों के प्रयोग को कुछ सीमा तक सीमित किया जा सकता है। अध्यादेश साधारण नियमों की कार्यान्वित करने की दृष्टि से भी जारी किये जाते हैं।

(iv) संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। परंतु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।

(v) संघीय विधान मण्डल तथा कौटो के विधान मण्डल संघीय परिषद के सशोधनो अथवा अन्य विधायी प्रश्नों पर परामर्श कर सकते हैं परंतु उनके लिए उस परामर्श के अनुसार आचरण करना आवश्यक नहीं है।

(vi) संघीय परिषद संघीय सभा में विधेयक प्रस्तुत करती है और उस विधेयक का एक संरक्षक भी नियुक्त करती है जो उसे कार्यान्वित करता है और सदस्यों को उसके उद्देश्यों को समझाता है एवं उनकी शिकायतों का समाधान करता है। जैसाकि रैपड ने कहा है कि वह संरक्षक है तथा विधेयक की विधायक रूपी भेदियों से एक गहरिये की भाँति रक्षा भी करता है।¹

(vii) संघीय सभा की समितियों के निर्माण में संघीय परिषद के सदस्यों का अग्रतम रूप से बहुत बड़ा हाथ होता है। समितियाँ संघीय परिषद के विशेषज्ञों की राय से ही अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित कर पाती हैं। इसी महत्व के कारण रैपड ने कहा है कि 'यह मानना ही पड़ेगा कि सर्वाधिक उत्तरदायी तथा प्रभावपूर्ण कार्य विधान मण्डल का नहीं अपितु कार्यपालिका का है।'

(3) न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

पहले संघीय परिषद को पर्याप्त न्यायिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे, परंतु सन् 1914 के पश्चात् उनमें अत्यधिक कमी कर दी गई है। संघीय परिषद की न्यायिक शक्तियाँ घट कर बहुत कम रह गई हैं।

(i) संघीय विभाग विविध प्रकार के निणय करते हैं। उसे उन निर्णयों के विरुद्ध दलीय (Private) व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अपील सुनने का भी अधिकार है।

(ii) संघीय रेलवे प्रशासन द्वारा किये गए निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार संघीय परिषद को है।

(iii) यदि कैंटनो की सरकारें धार्मिक आधार पर भेदभाव करती हैं तो इसे उनके निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार है।

(iv) उसे कैंटनो के विविध प्रकार के वाणिज्य समझौते एवं संधियाँ करने का भी अधिकार है और उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी संघीय परिषद को दिया गया है।

किंतु संघीय परिषद को अन्य देशों की कायपालिकाओं की भांति क्षमादान करने का अधिकार नहीं है।

(4) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

(i) संघीय बजट संघीय परिषद द्वारा तैयार किया जाता है।

(ii) यह परिषद के वित्तीय प्रशासन का संचालन करती है।

(iii) यह संघीय सभा के समक्ष आय एवं व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

(iv) यह संघीय सभा की अनुमति से राजस्व तथा आय करो को एकत्रित करती है।

(v) संघीय सभा की पूर्वानुमति से सघ के समस्त वित्तीय प्रशासन का निरीक्षण एवं निर्देशन करती है।

उपयुक्त जिन शक्तियों का उल्लेख मूल रूप में किया गया है। इनके अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers) भी संघीय परिषद को दी जाती रही हैं। इन्हें हम शक्तियों का प्रदत्त स्वरूप कह सकते हैं। स्विस संवैधानिकता की रक्षा तथा उसके आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिये—उदाहरणार्थ—1914-1930 तथा 1939 में उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हुईं यहाँ तक कि उसे कुछ सीमाओं में मौलिक अधिकारों को निलम्बित करने तक का भी अधिकार प्राप्त हुआ। संकटकालीन परिस्थितियों के कारण परिषद की शक्तियों का पर्याप्त प्रसार हुआ है। उसके इसी रूप पर टिप्पणी करते हुए लॉबेल ने कहा है, 'संघीय परिषद को मुख्य शक्ति ओत कहा जा सकता है और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय सरकार का सत्तुलन चक्र है।' ¹

संघीय परिषद तथा विधान मण्डल (Federal Council and Federal Assembly)

संघीय परिषद तथा विधान मण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन हम दो दृष्टिकोण से कर सकते हैं—संवैधानिक तथा वास्तविक। पहले हम स्विस संघीय परिषद पर संवैधानिक दृष्टि से विचार करेंगे—

(1) संवैधानिक दृष्टिकोण (Constitutional Point of View)

इस दृष्टि से संघीय परिषद का स्वरूप वास्तव में एक सेविका जसा है जो

¹ The Federal council may almost be regarded as the main spring and is certainly the balance wheel of the national Government



कि सदस्य रामभक्त हनुमान के समान राष्ट्रीय विधान मण्डल की भक्ति में करबद्ध प्रस्तुत रहती है। सघीय सभा ही उसकी निर्देशिका एवं निरोधक है। सघीय सभा द्वारा उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। राष्ट्रीय सभा का भग होने के साथ ही यह भी भग हो जाती है। संवैधानिक दृष्टि से इसकी अधीनता की स्थिति को हम निम्नलिखित रूप में प्रमाणित कर सकते हैं

1 सघीय परिषद सघीय सभा का विघटन नहीं कर सकती।

2 इसे अपने कार्यों का वायिब्य प्रतिवेदन सघीय सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है।

3 इसे सघीय सभा के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। उनकी सरकारी नीति सम्बन्धी विविध शिकायतों का समाधान करना पड़ता है।

4 अध्यादेश तथा सैनिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये उसे विधानपालिका से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है।

5 सघीय कार्यपालिका को अन्य देशों की कार्यपालिकाओं के सदस्य उसे विधेयकों पर विधेयाधिकार (Veto) का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

6 विधानपालिका सघीय परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, नियमों तथा विधेयकों को अस्वीकार कर सकती है पर तु इसके फलस्वरूप सघीय परिषद पद त्याग नहीं करती, यहाँ तक कि प्रस्ताव का प्रस्तावक भी व्यक्तिगत रूप में त्यागपत्र नहीं देता। एक बार लोक नियम के समय हर बैटरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उसने सघीय परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कि तु यहाँ भी 'यायवेस्ताओ' ने उसने इस कार्य को असंवैधानिक बताया। उस समय के पश्चात् ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लॉरेल के शब्दों में "सघीय परिषद के सदस्यों की स्थिति एक कबील या शिल्पकार की भाँति है, पापद अपने परामर्श के अस्वीकार होने पर भी स्वयं पद त्याग करना आवश्यक नहीं समझते।"

कहने का तात्पर्य यह है कि संवैधानिक दृष्टि से सघीय परिषद उन्ही नीतियों का अनुकरण करती है जो सघीय सभा द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। डाइसी (Dicey) ने तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए कहा है कि "परिषद सदन के आदेशों का पालन उसी प्रकार करती है जिम प्रकार कि किसी दुकान के मालिक से अपने मालिक की आज्ञाओं का ही पालन करने की आज्ञा की जाती है।" डाइसी तो यह मानता है कि "सघीय परिषद की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह तो एक ऐसा निर्देशक मण्डल है जो सघीय सभा की इच्छानुसार परिषद के कार्यों का प्रबंध करता है।"¹

(2) वास्तविक स्थिति (Actual Position)

सघीय परिषद की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए रैपड ने कहा है कि संवैधानिक विशेषाधिकारों के विद्यमान होते हुए भी अब नवतृत्व सघीय सभा के हाथों से निकलकर सघीय परिषद को प्राप्त हो गया है।"²

1 A Board of Directors appointed to manage the Concern of the Confederation in accordance to the wishes of the Assembly
—Dicey

2 Today inspite of all constitutional prerogatives the lead has clearly passed into the hands of Federal Council
—Rappard

वर्तमान युग कायपालिका की शक्तियों के पक्ष में है। यही स्थिति विश्व के लगभग प्रत्येक देश में है। स्विटजरलैण्ड ही इसका कोई अपवाद नहीं है। संघीय कायपालिका के सदस्य अनुभवी एवं विविध विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, संघीय परिषद या कायकाल लगभग निश्चित ही होता है। जब तक संघीय सभा का विघटन न हो उस समय तक संघीय परिषद के विघटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। संघीय सभा के अविश्वास का संघीय परिषद की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता। विधेयकों के प्रारूप की तयारी तथा उनकी प्रस्तुति संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा ही होती है और बिना उनके परिश्रम के विधेयकों का पारित होना दुष्कर हो जाता है। वे स्वयं मतदान नहीं करते परंतु उनके व्यक्तित्व एवं दूरदर्शिता की छाप विधेयकों पर लगे बिना नहीं रहती। संघीय परिषद संघीय व्यवस्थापिका का विधायकी प्रारूप निमित्त करने वाला प्रतिष्ठित विभाग (*Glorified Legislative Drafting Bureau*) बन गयी है। व्यवहार में संघीय परिषद स्वेच्छा से कार्य करती है। व्यवहार में वह सदन का नेतृत्व, प्रशासन का निर्देशन तथा नियंत्रण भी करती है। रफ ने तो इस सत्य को यहाँ तक स्वीकार किया है कि संघीय परिषद का प्रभाव संघीय सभा पर, लोकसभा पर ब्रिटेन में मंत्रिमण्डल की अपेक्षा भी अधिक है। ह्यूज ने उसे सदन की कायपालिका की अपेक्षा राष्ट्र की कायपालिका कहना अधिक उचित समझा है। यह सत्य है कि उपक्रम द्वारा प्रस्तुत होने पर भी विधेयक बिना संघीय परिषद के सहयोग के सफल नहीं हो पाते। कभी कभी संघीय परिषद द्वारा रखे गये प्रस्ताव लोक नियम अथवा संघीय सभा द्वारा अस्वीकार भी कर दिये जाते हैं परंतु उसका प्रभाव परिषद के सदस्यों की स्थिति पर नहीं होता।¹

संघीय परिषद की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए रोबर्ट ब्राइट ने कहा है कि वास्तव में यह वैधानिक दृष्टि से विधान मण्डल के अधीन होते हुए भी ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के समकक्ष और कुछ क्वच मंत्रिमण्डलों से अधिक शक्ति का प्रयोग करती है। इन कानूनों के निर्माण तथा उन पर सुझाव देने में पथ प्रदर्शक तथा एक साधन के रूप में कार्य करती है।¹

संघीय परिषद के प्रभावी होने के कारण (*Causes of Its being Effective*)

(i) सचिवसंघ समिति है (*All Party Council*)—सभी दलों के प्रमुख नेता इसके सदस्य होते हैं। यह दलबन्दी की भावना से ऊपर रहकर कार्य करती है। अतएव इसे सभी दलों का सहयोग प्राप्त होता है। दल इसकी आलोचना नहीं करते। दल के नेता अपने सहयोगियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं।

(ii) मनोवृत्ति की पहिचान (*Psychological Familiarity*)—संघीय परिषद के अधिकतर सदस्य वे व्यक्ति बनते हैं जो कि पहले विधायक रह चुके होते हैं। वे अपने नये पुराने सहयोगियों की मनोवृत्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं।

¹ Legally the servant of the Legislature it exerts in practice almost all much authority as do English and more than do some French Cabinets. It is a guide as well as an instrument and often suggests as well as drafts measures.

(iii) विभिन्नता में एकता का भाव (Spirit of Unity in Diversity)—संघीय परिषद में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल जैसे दृष्टिकोण का तो अभाव है परंतु विवादास्पद प्रश्नों तथा महत्वपूर्ण विधेयकों पर वे सब एकमत होते देखे जाते हैं। वे सब मिलजुलकर एक समान दृष्टिकोण को उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। जिससे संघीय परिषद की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

(iv) दूरदर्शिता (Farsightedness)—संघीय परिषद के सदस्य बड़ी ही दूरदर्शिता से कार्य करते हैं। वे जो प्रस्ताव अथवा विधेयक प्रस्तुत करते हैं उसके सम्बन्ध में संघीय सभा के प्रभावशाली व्यक्तियों से पहले ही बातचीत करके उन्हें विश्वास में ले लेते हैं। डाइसी के विचारानुसार संघीय परिषद के सदस्य "निर्देशकों का एक प्रमण्डल है जिनकी नियुक्ति संघीय सभा की इच्छाओं के अनुसार संघ के व्यवसाय का प्रबंध करती है।" जिस विषय में उन्हें सभासदों का समर्थन प्राप्त करने में सदिग्धता होती है, ऐसे कार्य वे नहीं करते हैं।

(v) आपातकालीन स्थितियाँ (Emergencies)—संकटकालीन परिस्थितियों के कारण भी संघीय परिषद को समय समय पर बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती रही हैं, जिनके द्वारा उसके स्तर में पर्याप्त अंतर हुआ है, उसका प्रभाव अत्र व्यापक बना है। दोनों विश्वयुद्धों तथा विश्वव्यापी आर्थिक संकट के समय भी संघीय परिषद की शक्तियों में पर्याप्त रूप में विकास हुआ है।

(vi) राष्ट्रीय चरित्र के अनुरूप है (It concides with the Swiss National Character)—संघीय परिषद की लोकप्रियता एवं उसके प्रभावी होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसका स्वरूप बहुत कुछ सीमा तक वहाँ के निवासियों के चरित्र एवं गुणों के अनुकूल ही है। स्विसवासी बहुत ही सहनशील तथा सुसंस्कृत होते हैं। वे भावनाओं से पराजित होकर भी तर्क का त्याग नहीं करते। संघीय परिषद विश्व सरकार के लिए एक आदर्श कार्यपालिका भी सिद्ध हो सकती है।

संघीय कार्यपालिका की प्रकृति (Nature of the Federal Executive)

हम यह अर्थ भी कह चुके हैं कि स्विस संघीय परिषद अपने ढंग की एक ही है जिसमें अनुभव एवं दूरदर्शिता का अद्भुत सम्मेलन है। ऐतिहासिक अनुभव ने ही स्विस संविधान निर्माताओं को शक्तिशाली राष्ट्रपति के प्रस्ताव को ठुकराने में सहयोग प्रदान किया और इसी अनुभव के आधार पर वे ऐसी कार्यपालिका भी नहीं चाहते थे जिसका कार्यकाल अनिश्चित हो और जिससे दलीय भावना को बल मिले। अतएव उन्होंने ऐसी कार्यपालिका का आविष्कार किया जो कि संसदीय तथा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों के अवगुणों से तो मुक्त हो परंतु उसमें इन दोनों शासन पद्धतियों के गुणों का सम्मेलन अवश्य हो। इसीलिये हम स्विस संघीय परिषद को दोनों का मध्यभागी तथा राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में स्विस आविष्कारक कह सकते हैं। प्रो० स्ट्राय के शब्दों में विश्व की कोई भी कार्यपालिका स्विटजरलैंड के अनुरूप नहीं है क्योंकि स्विस संविधान निर्माता एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में सफल हुए हैं जबकि इससे पहले की व्यवस्थाओं ने समस्त राजनीतियों को परेशान कर

रता था। यह व्यवस्था संसदीय तथा अर्ध-संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका के गुणों से युक्त है परन्तु उनके दोषों से मुक्त है।”

1 यह समव्यवस्था नहीं है (It is not Parliamentary)

ऊपर से दृष्टिपात करने से स्विस संघीय परिषद का स्वरूप संसदीय सा जान पड़ता है परन्तु उसमें कुछ विशेषण हैं ऐसी हैं जोकि किसी की भी धारणा में आसक्त होती हैं। संसदीय प्रणाली का सार विधानमण्डल के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, विधेयकों का प्राख्य निमित्त करने हैं और उन्हें संघीय सभा से पारित कराते हैं। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्यों के उत्तरदायक हैं और उनसे निर्देश प्राप्त करते हैं। उनमें विभागों का वितरण भी होता है। संघीय परिषद प्रशासन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। किन्तु निम्नलिखित कारणों से हम उसे संसदीय नहीं कह सकते

(i) स्विस कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा चार वर्ष के लिए होता है और संघीय सभा के विघटन के साथ ही उसका भी विघटन होता है। यह मन्त्रिमण्डलीय पद्धति में नहीं होगा। वहाँ मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता वे अनिवार्य रूप से सदन के सदस्य होते हैं। उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं और मनवान भी करते हैं।

(ii) दूसरा अंतर यह है कि जो एकरूपता अथवा सजातीयता मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था में पाई जाती है वह स्विस संघीय कार्यपालिका में नहीं पाई जाती। वे एकमत होकर कार्य नहीं करते हैं। प्रत्येक पाद अपने विभाग के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें नियम भी बहुमत द्वारा ही होते हैं परन्तु संसदीय पद्धति के समान उनका जन्म और मृत्यु एक साथ नहीं होती है। उसमें विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है।

(iii) संसदीय प्रणाली में यदि लोक सदन मन्त्रिमण्डल के प्रति किसी भी रूप में अविश्वास उत्पन्न करता है तो मन्त्रिमण्डल के पास दो विकल्प होते हैं—राष्ट्राध्यक्ष से लोकसभा का विघटन कराना अथवा स्वयं त्यागपत्र दे देना, परन्तु स्विटजरलैण्ड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर संघीय परिषद के सदस्य न तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र ही देते हैं और न ही उन्हें संघीय सभा की विघटित कराने का अधिकार है। वे अपने अपमान को उसी प्रकार अपनी जेब में रख लेते हैं जैसे सभ्य अनुप्य रूमात में नाक सिककर जेब में रख लेते हैं।

(iv) स्विस कार्यपालिका के अध्यक्ष की स्थिति प्रधानमन्त्री जैसी नहीं है। वह किसी भी रूप में राष्ट्रीय सरकार की धुरी नहीं है। वह मन्त्रिमण्डल तथा सदन का नेतृत्व नहीं करता। उसे प्रधानमन्त्री की भाँति अपने साधियों की नियुक्ति तथा उनकी निवृत्ति करने का भी अधिकार नहीं होता। स्विस संघीय परिषद का अध्यक्ष रिक्त परिषद का भी राष्ट्रपति होता है और उससे समस्त औपचारिक कार्यों का सम्पादन करता है।

(2) यह अध्यक्षीयक भी नहीं है (It is also not Presidential)

स्विटजरलैण्ड की संघीय परिषद में हमें कुछ महान् अध्यक्षीयक

भी देखने को मिलते हैं। कायपालिका का निश्चित कार्यकाल उनमें से एक है। परन्तु हम निम्नलिखित कारणों से उसे अध्यक्षात्मक नहीं मान सकते

(1) अमेरिकी शासन पद्धति का आधार शक्ति पृथक्करण है जो कि स्विस विधान का नहीं है।

(2) अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से पृथक् किया जा सकता है परन्तु सघीय परिषद को हटाने के लिए महाभियोग की पद्धति का प्रयोग स्विटजरलैण्ड में नहीं किया जाता।

(3) अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कायपालिका के सदस्य विधानपालिका के सदस्य नहीं होते और न ही उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं परन्तु स्विटजरलैण्ड में सघीय कायपालिका के सदस्य विधानमण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं तथा विधेयक प्रस्तुत एवं पारित कराते हैं परन्तु मतदान नहीं करते।

(4) अमेरिका में राष्ट्रपति को विधेयकों के सम्बन्ध में नियेच्छाधिकार प्राप्त है परन्तु स्विस कायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

(5) अमेरिका में कायपालिका का स्वरूप एकल है परन्तु स्विटजरलैण्ड में उसका स्वरूप बहुल है।

(6) अमेरिका में कायपालिका का स्वरूप विधानमण्डल से पूर्णतः स्वतन्त्र है। वहाँ विधानमण्डल राष्ट्रपति के निर्वाचन में तभी हस्तक्षेप करता है जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। स्विटजरलैण्ड में तो सम्पूर्ण कायपालिका का निर्वाचन सघीय सभा के द्वारा ही सम्पन्न होता है।

(7) सघीय परिषद का अध्यक्ष न तो अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति राष्ट्राध्यक्ष ही है और न कायपालिकाध्यक्ष ही।

(8) अमेरिका में राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल के सदस्य उसके सहयोगी नहीं होते अपितु उसके परामर्शदाता एवं अनुचर होते हैं परन्तु यह स्थिति स्विटजरलैण्ड में सघीय परिषद के अन्य सदस्यों की नहीं होती है।

(3) यह प्रेसीडियम भी नहीं है (It is not like Presidium)

कभी कभी स्विस सघीय परिषद की तुलना उसके बहुल रूप के कारण सोवियत प्रेसीडियम से की जाती है। दोनों में कई बातों की अनुरूपता भी है। दोनों का ही निर्वाचन अपने अपने देशों की विधानपालिकाओं के द्वारा ही होता है। दोनों के अध्यक्ष अपने-अपने राष्ट्रों के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष हैं और समस्त औपचारिक कार्यों का सम्पादन करते हैं। दोनों के अध्यक्षों की स्थिति अन्य सदस्यों के समक्ष है। परन्तु दोनों में कई अंतर भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं

1 सघीय परिषद में केवल 7 सदस्य होते हैं और प्रेसीडियम में 33।

2 प्रेसीडियम सामूहिक राष्ट्रपति है जोकि स्विस कायपालिका नहीं है।

3 जबकि सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय प्रेसीडियम विधानपालिका के कार्यों का सम्पादन भी करती है परन्तु यह काय स्विस कायपालिका द्वारा नहीं किया जाता।

4 प्रेसीडियम एक दलीय संस्था है और स्विस सघीय परिषद बहुदलीय संस्था है।

5 प्रेसीडियम मूल रूप में विधायिनी संस्था है जबकि स्विस् मधीय कायपालिका प्रशासकीय है।

(4) तब यह क्या है (Then what it is ?)

स्विस् मधीय परिषद का स्वरूप न तो सदस्यतात्मक ही है और न ही अध्यक्षतात्मक, इसमें दोनों की अच्छाइयों को समाहित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें उत्तरदायित्व एवं निश्चितता का अद्भुत मिश्रण है। इसमें न तो सदस्यीय प्रणाली जैसी अनिश्चितता ही है और न ही अध्यक्षतात्मक प्रणाली जैसी कायपालिका एवं व्यवस्थापिका में प्रतिस्पर्धा। मधीय परिषद अपने ढंग की अनोखी ही है। वह अध्यक्षतात्मक प्रणाली के स्थायित्व का गुण तो अपनाती है परंतु पृथक्ता के गुण को अंगीकार नहीं करती। वह एक निरदलीय संस्था है जिसके सदस्य दीर्घकाल तक उसके सदस्य बने रहते हैं। उसमें न दलीय कोलाहल ही है और न ही निरकुशता का भाव। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिकी पद्धतियों का मध्य भाग कहना ही अधिक उचित होगा। बाइसी ने इसकी तुलना निदेशक मण्डल से की है, जोकि उचित ही है। बाइस के शब्दों में "अब किसी गणतंत्र में एक व्यक्ति के स्थान पर एक परिषद को शासनाधिकार समर्पित नहीं किये जाते हैं। किसी भी स्वतंत्र देश की कायपालिका इतनी कम राजनैतिक उलझनों में नहीं रहती।" इसमें दोनों प्रणालियों (सदस्यीय एवं अध्यक्षतात्मक) के लक्षण विद्यमान हैं। वह दल की दल दल से अलग है। यद्यपि वह दलीय काम करने के लिए निश्चित नहीं होती है, परंतु फिर भी वह दलीय प्रभाव से अछूती नहीं है।"

मधीय कायपालिका की विशेषताएँ

(Unique Features of Federal Executive)

स्विटजरलैण्ड की कायपालिका अपने ढंग की एक ही संस्था है। बाइस ने इसे अब स्विस् संस्थाओं में से निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा है

(i) बहुलस्वरूप (Plural Executive)—स्विस् कायपालिका का स्वरूप मण्डलात्मक है। कायपालिका शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं की गई है। जनस्वभाव तथा अनुभव के आधार पर कायपालिका शक्ति एक 7 सदस्यीय परिषद को समर्पित की गई है जिनमें से क्रमानुसार एक अध्यक्ष तथा दूसरा उपाध्यक्ष केवल एक वर्ष के लिए ही निर्वाचित होते हैं। उत्तरदायित्व का स्वरूप सामूहिक ही है अर्थात् कायपालिका शक्तियाँ एक परिषद में ही निहित हैं। उनमें विविध दलों के सदस्य होते हैं, स्विस् कायपालिका का स्वरूप ब्रिटिश मंत्रिमण्डल जैसा नहीं है।

(ii) विधानपालिका के प्रति उत्तरदायित्व (Subordination to Legislature)—स्विस् कायपालिका विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। विधानपालिका के सदस्यों का निर्वाचन मधीय सभा के द्वारा होता है और मधीय परिषद उसी के निर्देश एवं नियंत्रण में कार्य करती है। परिषद को अपनी गति विधियाँ का वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है और यदि परिषद की बात न मानी जाय तो वे पदत्याग नहीं करते।

(iii) स्थायित्व (Permanence)—स्विस् कायपालिका का स्वरूप स्थायी है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित है। मधीय सभा के विघटन होने से पूर्व उसके

विघटन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कायपालिका के सदस्यों की दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त होता है। साधारणतः, सदस्य 10 वर्ष तक इसके सदस्य रहते हैं। सघीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में दलीय भावना से काय नहीं किया जाता, इसीलिए सघीय परिषद में स्थायित्व का भाव पाया जाता है।

(iv) निवृत्तीय स्वरूप (Non partisan Character)—स्विस सघीय कायपालिका दलीय भावना से ऊपर रहती है। उसमें विविध दलों का तो प्रतिनिधित्व मिलता ही है, साथ में धार्मिक एवं भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। सघीय परिषद का सौम्य स्वरूप केवल इसी कारण रह पाता है क्योंकि उसके सदस्यों के निर्वाचन में दलीय भावना काय नहीं करती और न ही वह राजनैतिक विवादों का शिकार बनती है। इसका स्वरूप सदैव मिला जुला होता है जोकि अन्य देशों की कायपालिकाओं में सफल नहीं समझा जाता।

(v) सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव (Lack of Collective Responsibility)—स्विस सघीय परिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है। उसमें ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का गुण नहीं पाया जाता। किसी सदस्य के कार्यों की भरसका होना पर सम्पूर्ण परिषद पद त्याग नहीं करती। यह भी आवश्यक नहीं है कि सघीय मन्त्रालय में सदस्य एक-दूसरे की रक्षा करें। यहाँ विचारों की भिन्नता की अभिव्यक्ति खुलकर की जा सकती है। ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का यह सूत्र कि मरने तो एक साथ तथा जीवने तो एक साथ, स्विटजरलैंड में प्रयुक्त नहीं होता है।

(vi) नेतृत्व का अभाव (Lack of Leadership)—सघीय परिषद में नेतृत्व का अभाव है उसके अध्यक्ष को हम उसका नेता नहीं मान सकते। यह भी आवश्यक नहीं है कि अन्य सदस्य उसकी आज्ञाओं का अनुपालन करें। वह अपने सचिवों को आदेश भी नहीं देता है और न ही उनके कार्यों का निरीक्षण ही करता है। सघीय परिषद एक विजातीय समुदाय है। वह भानुमती का कुनबा है। इसी कारण उसे गौरवमय महोदय तैयार करने वाला निकाय (A Glorified Drafting Bureau) मात्र ही कहा गया है।

Select References

- Lowell *Govt. & Politics of Continental Europe*
 Rappard *Switzerland in the Govt. of Continental Europe*
 Brooks *Govt. of Switzerland*
 Harns Huber *How Switzerland is Governed*
 Munro *Governments & Politics of Switzerland*
 Bryce *Modern Democracies*
 Buell *The Govt. of Switzerland*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 स्विस सघीय कायपालिका का वर्णन करें।
 [Discuss the working of the Federal Executive in Switzerland]
- 2 स्विस सघीय कायपालिका की विलक्षणताओं की विवेचना कीजिए। यह स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व का किस प्रकार सम्बन्ध करती है?
 [Discuss the unique character of the Swiss Federal Executive
 How far does it combine stability with responsibility?]

- 3 बहुल कार्यपालिका का क्या अर्थ है ? यह कहाँ तक स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व का समन्वय करती है ? स्विटजरलैण्ड से उदाहरण दीजिए ।
[What is meant by a Plural Executive ? How far does it combine stability with responsibility ? Discuss with illustration from Switzerland]
- 4 स्विस् संघीय कार्यपालिका न तो ससदात्मक है न अध्यक्षतात्मक ।" विवेचना करें ।
["The Swiss Federal Executive is neither Parliamentary nor Presidential" Discuss]
- 5 सोवियत संघ की प्रेसीडियम की शक्तियों तथा कृत्यों की तुलना स्विस् कार्यपालिका से कीजिए ।
[Compare the powers and functions of the Presidium in the U S S R with those of the Swiss Executive]
- 6 ब्रिटिश मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था की तुलना स्विस् बहुल कार्यपालिका से कीजिए ।
[Compare and contrast the British Cabinet system with the Plural Executive in Switzerland] (Vikram, Univ B A (Part II, 64)
- 7 'स्विटजरलैण्ड की बहुल कार्यपालिका आधुनिक प्रजातन्त्र की एक अदभुत सृष्टि है ।' इस कथन की विवेचना करें ।
['The Collegial Executive of Switzerland is one of the most striking political institutions in modern democracy' Discuss]
- 8 'स्विस् संघीय परिषद एक अनोखी सृष्टि है ।' इस कथन की समीक्षा करें ।
['The Federal Council is the most unique institution in Switzerland' Comment]
- 9 स्विस् संघीय परिषद अन्य सर्वोच्च कार्यपालिका से कैसे भिन्न है ? समझाकर लिखें ।
[How is the Federal Council of Switzerland unlike any other supreme executive ? Describe and comment]
- 10 Describe the composition and powers of the Swiss Federal Council
[Ravishanker Univ II A (Previous) 64, Vikram Univ II A]
- 11 स्विटजरलैण्ड की संघीय परिषद की विशेषताओं का वर्णन कीजिये तथा उसका विधायिका से सम्बन्ध बतलाइये ।
[Describe the specific features of the Swiss Federal Council and trace its relationship with the legislature]

3

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

"Swiss democracy is more truly than the democracy in any other country in the world" —Bryce

'प्रजातन्त्र के विद्यार्थी के लिए स्विस शासन-व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र से बढ़कर शिक्षा देने वाली अन्य कोई संस्था नहीं है क्योंकि यह जनता की आत्मा में प्रवेश द्वार खोल देती है।'

परिचयात्मक

शाटवेल ने स्विस प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को एक विचारधारा का सबसे अधिक साहसपूर्ण तथा सफल प्रयोग कहा है। हमें सबसे अधिक ध्यान प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था में होता है। प्रत्यक्ष जनतन्त्र ने स्वित्जरलैंड को आधुनिक एथेंस (Athens) बना दिया है। स्वित्जरलैंड ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की माध्यम से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवस्था के मध्य अनीखा समन्वय उत्पन्न किया है। ब्राइस के शब्दों में "लोकतन्त्र के विद्यार्थी के लिए स्वित्जरलैंड की प्रणाली में इससे अधिक बढ़कर अन्य कोई वस्तु शिक्षाप्रद नहीं है क्योंकि इससे जनता को मानव ज्ञान प्राप्त होता है।"

प्रत्यक्ष व्यवस्थापन (Direct Legislation)

प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का सिद्धांत रूसो द्वारा प्रतिपादित लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धांत के निकट है। आज हम जिस प्रकार की जनतन्त्रीय व्यवस्था के अभ्यस्त हो गये हैं वह प्रतिनिध्यात्मक अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतन्त्रीय पद्धति है। आज के भीतिक्वादी युग में जहाँ जनसंख्या की वृद्धि दिन दूनी तथा रात चौगुनी हो रही है जहाँ सरकारें परिवार नियोजन के माध्यम से इस बाढ़ को रोकना चाहती हैं वहीं प्रकृति ने एक बच्चे के स्थान पर पाँच पाँच एक साथ भेजना सम्भवतः आरम्भ कर दिया है। वहीं प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जैसी बात की कल्पना करना ही व्यर्थ है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में ही प्रत्यक्ष व्यवस्थापन सम्भव हो सकता है। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन एक प्राचीन आदर्श है। ग्रीस के नगर राज्यों में यह प्रथा विद्यमान थी। नगर राज्यों के नागरिक राज्य व्यवस्था में सक्रिय भाग लेते थे और विधि निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे। बिना आज के भीड़ तन्त्रीय दलों में यह सम्भव नहीं है।

कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ समस्त व्यक्तियों को एकत्रित करके उन्हें प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के लिए आमन्त्रित किया जा सके। अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन की ही व्यवस्था है। विधि निर्माण में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही भाग लेती है। किंतु स्विटजरलैंड में आज भी जनता को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भाग लेने की सुविधाएँ दी जाती हैं। वहाँ पर लण्डसजीमेडी नामक सस्थाएँ पाई जाती हैं जिनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापन में भाग लेती है। स्विटजरलैंड में आज भी विधि सम्बन्धी अंतिम निणय जनता के हाथों में ही है। जनमत संग्रह द्वारा जनता को अंतिम निणय लेने का अधिकार दिया जाता है। कानून का प्रारम्भ तथा अन्त दोनों ही जनता के हाथों में हैं।

भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका आदि सभी बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र है। साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की तानाशाही है। मिस्र, स्पेन, टर्की तथा पाकिस्तान आदि देशों में सैनिक अधिकारियों ने शक्ति हथिया कर अपनी शक्ति को वधानिक रूप प्रदान किया है। इन सब देशों में भी अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र ही है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सबसे बड़ी बाधा यह है कि पाँच वर्ष के बाद ही जनता को अपनी सम्प्रभुता का आभास होता है। उसी समय उसे कृष्ण लीला दिखाई जाती है और फिर उसे मोरफिया का इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में व्यवस्थापन शक्ति वस्तुतः राजनैतिक दलों के हाथ में आ जाती है। सत्ताधारी दल अपनी बहुमत की शक्ति का अनुचित लाभ उठा कर ऐसे विधेयकों को पारित कराने का यत्न करता है जो सम्भवतः जनता द्वारा लोकादेश के समय पसन्द नहीं किया जाय। जनता विधेयकों की धारिकियों में जाने की अभ्यस्त नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में राजनैतिक दल स्वायत्त तथा भ्रष्टाचार से भर जाते हैं। एक बार जनता को बेबकूफ बनाकर अर्थात् भूठे आश्वासन देकर एक बड़ी बड़ी बातें बगाकर, निर्वाचन में विजयी हो जाते हैं और फिर निश्चित हो पैर पसार कर सोते हैं। अपनी विधायिका तथा अपने वायदों को सभी भूल जाते हैं। जनता धिक्का हो किकत्तव्यविमूढ़ होकर यह सब निहारती रहती है। जिन देशों में जन शिक्षा का अभाव है वहाँ तो दशा और भी अधिक खस्ता है। अभी हाल ही में भारत में ही राज्य भाषा समीक्षण विधेयक पर कितना हंगामा हुआ, रैलें तोड़ी गई, पोस्ट ऑफिस जलाये गये अश्रुगैस छोड़ी गई तथा गोलियाँ खली। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कुछ तो हुआ किन्तु फिर भी इन भावनाओं के विषय में द्वितीय उपविस्त मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाडिया के शब्दों में 'हिन्दी के बिना राष्ट्र में एकता स्थापित नहीं हो सकती। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो एकता की बड़ी का काम कर सकती है। मोठे से लोग हैं जो अपना हित साधन के लिए हिन्दी का विरोध करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन अंग्रेजी जानने वाला के हाथों में है, जिनकी सम्झना बहुत थोड़ी है।' अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र का यह भयकर अवगुण है। जिन देशों में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र है वहाँ दूरदर्शी कुशल व्यक्तियों ने बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक यह सोचना प्रारम्भ कर दिया है कि किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये जो लोकतन्त्र को बहुत से विकारों से मुक्त कर स्वास्थ्य का अद्भुत टॉनिक सिद्ध होगा।

स्विटजरलैण्ड को प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का घर माना गया है, इसके तीन माध्यम हैं—लोकमत सग्रह (Referendum), उपक्रम (Initiative), वापस बुलाना (Recall) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की सबसे अधिक आवृण की जो सस्या है, वह है लैंडसर्जेमेंटो (Landsgemeinde)। यह प्रत्यक्ष नैटन (स्विस सघ की इकाई) में नही पाई जाती। यह नगर सभा का काय करती है। यहाँ प्रत्यक्ष वयस्क ध्यति सर कार का धयन करने के लिये उपस्थित होता है। किंतु अधिकांश कैंटनों में लोकमत सग्रह तथा उपक्रम की प्रणालियों का ही प्रयोग होता है। लोकमत सग्रह की प्रणाली केवल स्विटजरलैण्ड में ही प्रयुक्त होती हो, ऐसी बात नही है। यह प्रणाली अमेरिका रूस आदि घोरोगीय देशों में भी प्रयोग में लाई जाती है। रूस में लोकमत सग्रह की प्रणाली को सिद्धांत रूप में तो स्वीकार किया गया है किंतु उसे व्यवहार में अभी तक कभी परिणित नहीं किया गया है।

लोकमत सग्रह का अर्थ (What Referendum Means)—इसके शाब्दिक अर्थ हैं, प्रस्तुत करना। जब विधान मण्डल द्वारा साधारण तथा सवधानिक जनता द्वारा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं, तब उसे लोकमत सग्रह कहा जाता है। किसी भी कानून का अंतिम निणय जनता करती है। कोई कानून अपेक्षित है अथवा नहीं, इसका निणय जनता करती है। जनता को इस माध्यम से निपेधा अधिकार प्राप्त है। दूसरे के अनुसार 'निम्नतम सीमा पर, लोकमत वह साधन है जिसके द्वारा निर्वाचक गण विधानपालिका द्वारा स्वीकार किये गये कानूनों का निपेध कर सकें।' डा० मुनरो ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये कानूनों को क्रियावित होने से उस समय तक के लिये रोका जा सके जिस समय तक कि वह जनता के समक्ष प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से स्वीकार न कर लिया जाय। लोकमत सग्रह दो प्रकार का होता है—अनिवाय तथा वकल्पिक (Compulsory and Facultative or Optional) जब कि विशिष्ट प्रकार के विषयों के लिये लोकमत सग्रह करना विधानमण्डल के लिए अनिवाय हो जाता है तब हम उसे आवश्यक प्रकार का लोकमत सग्रह कहते हैं। कभी कभी कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में लोकमत सग्रह करना विधान मण्डल के लिए अनिवाय नहीं होता किंतु जब निश्चित सस्या में मतदाता यह माँग करें कि इसे विषय विशेष को लोकमत सग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाय तो वह वकल्पिक प्रकार का लोकमत सग्रह कहलाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि या तो विधानमण्डल स्वतः ही किसी विधायक को महत्वपूर्ण मानकर उसे लोक निणय के लिए प्रस्तुत कर देता है, अथवा वकल्पिक लोक निणय को 30 000 नागरिकों अथवा 8 कैंटनों की माँग पर 90 दिन की अवधि में, आवश्यक लोक निणय में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि इस 90 दिन की अवधि में जनता अथवा कैंटनों द्वारा माँग नहीं की जाती है तो उसे स्वीकृत समझा जाता है।

अधिकांश कैंटनों में सघ की ही तरह लोक निणयों का प्रयोग किया जाता है। कैंटनों में सर्वधानिक सगोधनों के लिए लोक निणय अनिवाय है। सघ स्तर पर यदि राज्य परिषद द्वारा किसी भी विधेयक को 'अत्यावश्यक' घोषित कर दिया

जाता है तो उस पर 1 वष तक लोक नियम की भाँति नहीं की जा सकती और उस कानून को बिना लोक नियम के ही कार्यान्वित किया जायगा। सन् 1949 के पश्चात् यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि अध्यादेश 1 वष की अवधि में लोक नियम द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते जो स्वतः ही समाप्त भमझे जायेंगे।

लोकमत सग्रह के गुण (Merits of Referendum)

(1) राजनैतिक शिक्षण की उपलब्धि—बै और के शब्दों में 'लोकमत सग्रह' निश्चय ही व्यक्तिगत निर्वाचकों की शिक्षा में वृद्धि करता है और उपक्रम के साथ सलामत देने से जाति व विरुद्ध वास्तविक सुरक्षा प्रदान करता है।¹ लोकमत सग्रह के माध्यम से जनता में गति एवं चेतना बनी रहती है। जनता को बार-बार राजनैतिक प्रश्नों के विविध पहलुओं पर विचार करने को मिलता है। राजनैतिक दल भी प्रस्तुत प्रश्नों के विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनसे जनमानस व्यापक होकर समृद्धिशाली बनता है।

(2) लोकप्रिय सम्प्रभुता के सन्निकट—बै और ने ठीक ही कहा है कि लोकमत सग्रह राजनैतिक वातावरण का सर्वश्रेष्ठ मापक यंत्र है। इसने सवप्रथम सामान्य इच्छा तथा लोकप्रिय सम्प्रभुता का विचार दिया था। लोकमत सग्रह उस विचार के बहुत कुछ सन्निकट है। जन इच्छा एवं व्यक्तिगत भावनाओं की सम्यक अभिव्यक्ति के लिए यह सवसुगम माध्यम माना है। दलों को अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रसारण, समाचार पत्रों एवं सावजनिक मंचों का सहारा लेना नहीं पड़ता। लोकमत एवं सावजनिक सम्पत्ति का परीक्षण करने के लिए यह सर्वोचित साधन है।

(3) राजनैतिक दलों को हतोत्साहित करता है—लोकमत सग्रह की पद्धति के कुछ समालोचकों का ऐसा विचार है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजनैतिक दलों का महत्व कम हो जाता है और जनता उनके कुप्रभावों से मुक्त हो जाती है। जनता के हाथों में निपटाराधिकार की शक्ति आ जाने से राजनैतिक दलों का स्वाभाविक रूप से हतोत्साहित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। राजनैतिक दल भी यह जान लेते हैं कि अन्तिम नियम उनके हाथों में नहीं है। राजनैतिक दलों का प्रभाव कम हो जाता तो प्रशासन में से पक्षपात एवं झण्टाचार का कम हो जाना स्वाभाविक सी बात है।

(4) बहुसंख्यकों की तानाशाही के विरुद्ध सुरक्षा—लोकमत में एक बहुत बड़ा अवयुग यह पाया जाता है कि उसके अन्तर्गत बहुमत पक्ष अल्पसंख्यकों की भावनाओं एवं उनकी अभिव्यक्तियों की उपेक्षा करके उन पर अपनी तानाशाही लादने की चेष्टा करता है। किन्तु लोकमत सग्रह की प्रणाली में बहुमत दल अपनी तानाशाही स्थापित करने में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाता। अल्पसंख्यकों को भी अवसर मिलता है कि वे भी अपने विचार अपने दृष्टिकोण सबके समक्ष रख सकें और बहुमत को अपनी माँगों के प्रति उदार बनाने में सफल हो सकें।

(5) कानूनों की सृष्टि नैतिक शक्ति का बाहुल्य—ब्राइस का यह कहना

1 It certainly stimulates the political education of the individual electors taken in conjunction with initiative. It affords a real safe guard revolution.

सत्य है कि जन स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति एवं सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात् वे अपना यह कतव्य समझते हैं कि कानूनों का पालन किया तथा करवाया जाय। इससे सदेह नहीं कि जिन कानूनों का निर्माण लोकमत सग्रह के माध्यम से होता है वे उन कानूनों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे होते हैं जो कि विधानमण्डल द्वारा बनाये जाते हैं। विधान मण्डल जन अंतरण को समझने में असफल रह सकते हैं।

(6) शारयत सम्पर्क—अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें एक बहुत बड़ा अभाव महसूस पड़ता है कि सामान्य निर्वाचन के उपरान्त विधायक अपनी विधायकाओं को लगभग भूल से ही जाते हैं। जनता तथा सरकार के मध्य शाश्वत सम्पर्क नहीं रह पाता, किंतु इस प्रणाली में ऐसा सम्भव नहीं है। यहाँ पर विधानमण्डल को प्रत्येक कदम नाप कर रखना पड़ता है और साथ ही जनता को भी साथ लेकर चलना पड़ता है।

(7) अप्रिय कानूनों के प्रति सुरक्षा—सभीय प्रणाली अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से जनता के लिए यह बठिन हो जाता है कि वह प्रत्येक कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करे और अपने को सुरक्षित रखे। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की इस पद्धति में जनता पूर्ण रूप से अप्रिय कानूनों के प्रति सजग रह कर अपने स्वायत्तों को सुरक्षित रख सकती है। जो कानून लोकप्रिय नहीं होते अथवा लोक इच्छा के प्रतिकूल होते हैं उन्हें असफल बनाया जा सकता है।

(8) सरकार के किसी भी अंग का एकाधिकार नहीं रह पाता—प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की इस प्रणाली का एक गुण यह भी है कि सरकार के किसी भी अंग को अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रायः यह दोष देखने में आता है कि सरकार का एक अंग अनुचित रूप से शक्तिशाली बन कर अन्य अंगों के व्यक्तित्व को आच्छादित कर लेता है। अमेरिका में कभी-कभी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध यह बात कही जाती है कि वह वहाँ के प्रशासकीय ढाँचे का एकमात्र अधिकारी बन गया है किंतु इस प्रणाली में इतना भी सम्भव नहीं है।

(9) पारस्परिक झगड़ों का निपटारा—प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के पक्ष में एक बात यह भी कही जाती है कि लोकमत सग्रह की इस पद्धति में विधान मण्डल के दोनों सदनों में पारस्परिक सम्बन्ध मधुर रहने जाते हैं। विधान मण्डल के दोनों सदनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखते दोनों ही यह जानते हैं कि एक दूसरे का विरोध करना व्यर्थ है क्योंकि अंतिम निर्णय जनता के द्वारा ही सम्पन्न होगा।

प्रोफेसर सी०एफ० स्ट्रॉंग ने इस प्रणाली के तीन प्रमुख लाभ बताये हैं—प्रथमतः लोकमत सग्रह विधान मण्डल की उन त्रुटियों को दूर करता है जब वह भ्रष्ट होकर अथवा लोगों के आदेशों के विरुद्ध रह कर कार्य करता है। द्वितीय यह निर्वाचित एवं निर्वाचकों के मध्य एक लाभदायक तथा स्वस्थ सम्पर्क बनाता है। तृतीय यह इस बात की रक्षा करता है कि लोक भावना के विरुद्ध कोई भी कानून पास न किये जाए।

लोकमत सग्रह के अवगुण
(Demerits of Referendum)

(1) विधानमण्डल की प्रतिष्ठा कम हो जाती है—जनमत सग्रह के विरुद्ध

सबसे शक्तिशाली तक यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके द्वारा विधान मण्डल की मान प्रतिष्ठा को वास्तव में आघात पहुँचता है। सदन के सदस्य जब यह जान लेते हैं कि उनके प्रयासों एवं विशेष योग्यता का कोई मूल्य नहीं है और उनमें रुकावट डालने पर भी काय नहीं रुक सकेगा, तब व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हतोत्साहित और अनुत्तर दायी बन जाते हैं। व्यवस्थापन में उनकी रुचि कम हो जाती है। विधान मण्डल के अनुभवी एष प्रोफ़ेसर विशेषज्ञों को स्वाभाविक रूप से यह बात अनुचित लगती है कि उनके द्वारा पारित विधेयक सवप्रिय मत द्वारा पराजित कर दिये जायें। ड्यूब्स (Dubbbs) ने इस बात पर बल देते हुये कहा है कि यदि आप लोकमत सग्रह की व्यवस्था कर दें तो सदन परामश समिति बनकर रह जायगी। डॉ० इलियास अहमद के शब्दों में "यदि इस प्रकार बनाये गये कानून जनता द्वारा स्वीकार कर दिये जायें तो उसका अर्थ यह होगा कि अनुभव, शिक्षा एवं विशेषज्ञों के परामश की अयोग्यता तथा द्वेष भाव एवं निम्न हितों की पूर्ति के लिये अवहेलना की जा रही है। इस तरह विधान मण्डल के सदस्यों की प्रतिष्ठा घट जाती है और विधान मण्डलों को अपयश प्राप्त होता है।

(2) अनावश्यक देरी—प्रो० स्ट्रॉज़ का यह कथन सही है कि 'यदि किसी विशाल राज्य में इस प्रयोग में लाया जाय तो यह सम्भवतः कानून निर्माण में इतनी देर कर देगा कि समाज उस लाभ से वंचित हो जाय, जिसके लिये यह बनाया गया था अथवा उन बुराइयों को निरन्तर फलाये रखेगा, जिनको दूर करने की इच्छा व्यक्त की गई थी।' वास्तविकता भी यही है कि कानूनों के बनने में बहुत देरी लगती है। आज के औद्योगिक विकास की प्रगति का देखते हुये यह सोचना भी कठिन है कि सरकारें लोकमत सग्रह की प्रतीक्षा करें और हाथ पर हाथ रखे फ्राइस्ट के चित्र के समक्ष बैठी रहे। इसीलिए सकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये सरकार लोकमत सग्रह पर निर्भर नहीं रह सकती। सम्भवतः समय की आवश्यकता तथा इस पद्धति की रुढ़िवादिता में सामंजस्य उत्पन्न करने की दृष्टि से अब स्विटजरलैण्ड की कामपालिका को डीकरीज व अद्यादेशों का सहारा लेना पड़ता है जिनके सम्बन्ध में लोकमत सग्रह प्रयुक्त नहीं होता।

(3) दुर्गम प्रणाली—लोकमत सग्रह की पद्धति बहुत ही कठिन एवं उलझी हुई है। जन साधारण को प्रत्यक्ष रूप में हम इतना योग्य नहीं पाते कि वे कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट कर सकें। कानूनों के निर्माण में तो अच्छ-अच्छे विशेषज्ञों के सिर चक्कर खाने लगते हैं, अतः एक अग्रिम साधारण मानसिक स्तर के व्यक्ति से यह आशा करना कि वह कानूनों पर अपना मत साधिकार व्यक्त कर सकता है, कितना हास्यास्पद है। यह सिद्धांत हमें विवेक से अविवेक की ओर, तथा प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने वाला है। इसमें अज्ञानता शासक होगी तथा उत्तरदायित्व के प्रति अनुत्तरदायित्व प्रधानमंत्री। यह तो ऐसा ही है कि "अंधे के आगे रोवें और अपने नयना खोलें।" एक अस्तबल में घोड़ों की मालिश करने वाले व्यक्ति का व्यवस्थापन पर मत देते देख क्षोभ होता है। ब्राइस के शब्दों में "जूरा की निजन घाटी में रहने वाला सालथोमर का एक किसान वित्त बिल की योग्यता

विषय में अपना मत कैसे बना सकता है ? क्या यह प्रस्तावित धन देने के योग्य है ?”

(4) मतों की अल्पसङ्ख्या—लोकमत सग्रह में कितने मताधिकारी भाग लेते हैं इससे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में एक देश के निवासियों की अभिरुचि मापी जा सकती है। स्विट्जरलैण्ड में यह अनुमान लगाया गया है कि बहुत ही थोड़ी सङ्ख्या में लोग मत डालने आते हैं। कभी कभी तो प्रस्ताव के समयको भी सङ्ख्या कम रह जाती है और विपक्षी भारी सङ्ख्या में मतदान करके प्रस्ताव को विफल बना देते हैं। इस अरुचि के सम्भवतः दो कारण हो सकते हैं—या तो मतदाता लोकमत सग्रह में रुचि नहीं रखते या वे इतने योग्य ही नहीं हैं जो सविधान एवं उसकी जटिलताओं को समझ सकें। किन्तु वास्तविकता यह है कि जनता में निर्वाचन सम्बन्धी धकान बढ़ जाती है, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, अरुचि। लोग बार बार मतदान के द्रो पर जाते जात परेशान हो जाते हैं। उनकी विचारधारा इस प्रकार की हो जाती है कि निर्वाचन तो आये दिन होते ही रहते हैं, कहीं तक उनका भाव दिया जाय।

(5) जनता के मन की वास्तविक अभिरुचि नहीं होती—ब्राइत के मतानुसार “लोकप्रिय निर्वाचन के परिणाम सदैव जन इच्छा की अभिरुचि नहीं करते क्योंकि जनता मुहावरों द्वारा आकर्षित हो जाती है। जन इच्छा का लोकमत सग्रह वास्तविक प्रतिबिम्ब नहीं है। जनता के समक्ष बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। तथ्य छिपाये जाते हैं। अतः मतदाता प्रचार के शिकार हो जाते हैं। मतदाता वास्तव में क्या अनुभव करते हैं और क्या चाहते हैं, यह लोकमत सग्रह से नहीं जाना जा सकता। राजनैतिक दल जोशीले भाषणों से जनता को भुमराह करते हैं।

(6) जनता का नकारात्मक अनुदाय—लोकमत सग्रह के आलोचकों का यह कहना कि यह पद्धति व्यक्तियों को केवल नकारात्मक अधिकार ही प्रदान करती है। लोकमत सग्रह के लिये प्रस्तुत विधेयकों के सम्बन्ध में मतदाताओं को केवल एक ही विकल्प दिया जाता है कि या तो वे विधेयक के पक्ष में हाँ करें अथवा नाँ करें। यह सम्भव हो सकता है कि एक मतदाता सम्पूर्ण विधेयक के पक्ष में न होकर उसकी कुछ धाराओं का समर्थन करता हो। परन्तु उस मताधिकारी के पास केवल एक ही विकल्प है कि या तो वह सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करदे। इस नकारात्मक अधिकार के देने में लोकतन्त्र का महत्व बहुत कम हो जाता है।

(7) बड़े क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली अनुपयुक्त है—लोकमत सग्रह की प्रणाली के विरुद्ध एक तक यह दिया जाता है कि यह बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रणाली के अपनाने से कई संवैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। बड़े देशों में भिन्न भिन्न कानूनों की आवश्यकता हो सकती है और इसीलिये यह प्रणाली इससे दूर रहती है।

(8) खर्चीली—लोकमत सग्रह की प्रणाली के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया जाता है कि यह प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली है। धन का दुरुपयोग होता है। निर्वाचन बार-बार होते हैं और हर बार मत पत्रों मतदान के द्रो तथा मतदान अधिकारियों को एकत्रित करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र का बहुत सा धन प्रचार आदि पर व्यय होता है। इन सबका सामूहिक परिणाम यह निश्चलता है कि

राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिये नये कर लगाने पड़ते हैं अतः यह प्रणाली बहुत खर्चीली है।

(9) राष्ट्रीय उत्पत्ति में बाधक—ग्राइस के अनुसार “लोकमत सग्रह के विरुद्ध अत्यंत विस्तृत एक ही दृष्टि विचार यह है कि यह राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पत्ति में बाधा डालता है। फाइनर के अनुसार बुद्धिहीन एवं अशिक्षित व्यक्तियों ने प्रगतिवादी व्यवस्थापन को प्रायः नष्ट कर दिया है। साधारण व्यक्ति स्वभाव से ही दक्षिणपंथी तथा सकीर्ण विचार वाले होते हैं। वे प्रगतिशील विचारों का स्वागत नहीं करते। लोकमत सग्रह के लिये प्रस्तुत प्रगतिशील विधेयकों के प्रति वे उदासीनता का भाव प्रकट करते हैं इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। हैनरी मेन ने भी इसी बात पर बल देते हुये कहा है कि जहाँ कहीं भी लोकमत सग्रह की पद्धति का प्रयोग किया गया है वहाँ पर राष्ट्रीय प्रगति अनिवार्यतः रुकी है।

(10) दल प्रणाली के दोषों में वृद्धि—लोकमत सग्रह के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि इसने द्वारा दल प्रणाली के दोषों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। राजनैतिक दल घुमाधार प्रचार करते हैं। और निर्वाचनों में निंद्यता से घन व्यय करते हैं। राजनैतिक दल अपने समर्थन में कुछ ऐसे व्यक्तियों को रख लेते हैं जो कि चुनावों में उनके एजेंट का काम करते हैं। वे कुछ ऐसे किराये के टट्टू भी रखते हैं जिन्हें वे अवसर आने पर विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में खड़ा कर देते हैं। बार बार निर्वाचन होने से राजनैतिक दलों का अष्ट हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

उपक्रम (Initiative)

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की और अधिक प्रभावशाली बनाने वाला यह दूसरा साधन है। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के समर्थक केवल अपने को लोकमत सग्रह तक ही सीमित रखना नहीं चाहते। वे विधान मण्डल द्वारा पारित संवैधानिक संशोधनों पर अपना निगम देकर ही संतुष्ट नहीं जान पड़ते। वे चाहते हैं कि वे स्वयं भी अपनी ओर आगे आकर विधान मण्डल को आदेश दे सकें कि अमुक विषय के सम्बन्ध में वे व्यवस्थापन चाहते हैं। जब साधारण अथवा संवैधानिक कानूनों के सम्बन्ध में पहल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा न होकर स्वयं जनता द्वारा की जाती है तो हम उसे उपक्रम की संज्ञा देते हैं। किंतु उपक्रम प्राथनापत्र नहीं है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है।

(1) उपक्रम आज्ञासूचक होता है, जिसे अस्वीकार करना विधान मण्डल के लिये कठिन होता है।

(2) उपक्रम का आदेश प्रभुसत्ता सम्पन्न जनता के द्वारा दिया जाता है। यह श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को आदेश है जिसको स्वीकार करना उसका कर्तव्य है।

(3) उपक्रम संवैधानिक विषयों से सम्बन्धित होता है जबकि प्राथनापत्र किसी भी विषय पर दिया जा सकता है।

(4) उपक्रम को विधान मण्डल स्वीकार करने तथा उसमें अंकित बिंदुओं के अनुसार आचरण करने के लिये बाध्य है किंतु प्रायनापत्रों के सम्बन्ध में विधान मण्डल स्वेच्छानुसूल आचरण करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र है।

उपक्रम के दो रूप होते हैं—सूत्रबद्धात्मक तथा सामान्य (Formulative and Unformulative)। यदि जनता विधान मण्डल से निश्चित एवं व्यापक आदेशों सहित विशिष्ट संबंधानिक सशोधन सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहे तो उसे सूत्र बद्धात्मक उपक्रम कहते हैं। इससे अतन्त्र जनतादेश स्वीकार करने तथा उसके अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त विधान मण्डल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। इससे विपरीत सामान्य तापक्रम में जनता अपनी इच्छा को सूत्रबद्ध नहीं करती और न उसे कोई व्यापक रूप ही प्रदान करती है। जनता की ओर से विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में विधान मण्डल से विधेयक प्रस्तावित करने को कहा जाता है। शेष बातों की पूर्ति विधेयक वा श्रेणीबद्ध सगठन व्यक्ति की इच्छानुसूल विधान मंडल ही करता है। स्विटजरलैंड में उपक्रम का प्रयोग केन्द्र तथा कैंटन दोनों में होता है। केन्द्र में इसका प्रयोग संविधान में पूर्ण परिचलन करने के लिए किया जाता है। सामान्य नियमों के लिये उपक्रम का प्रयोग नहीं होता। कैंटनों में यह इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है। उपक्रम की माँग जनता के पचास हजार मतदाताओं के द्वारा रखी जा सकती है। यदि विधान मण्डल उसे अस्वीकार कर देता है तो उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करके यह जानना होता है कि अमुक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। यदि जनता उसका समर्थन करती है तो अस्वीकार करने वाले उस विधान मण्डल को भग कर दिया जाता है और नये चुनाव होते हैं। नया विधान मण्डल उपक्रमानुसार विधेयक की रचना करता है। स्विटजरलैंड के कैंटनों में माँग करने वाले मतदाताओं की संख्या कम से कम तीस हजार होनी चाहिये।

उपक्रम के गुण (Merits of Initiative)

(1) लोक प्रभुसत्ता की सुरक्षा—लोकतंत्र को वास्तविक रूप वस्तुतः उपक्रम द्वारा ही प्राप्त होता है। जब जनता को लोकमत संग्रह के लिये संबंधानिक सशोधनों के सम्बन्ध में योग्य समझा जाता है तो उपक्रम के लिये उन्हें अयोग्य समझा जाता है। उपक्रम द्वारा जनता को स्वयं कानून निर्माण करने तथा नीति निर्धारण करने के बल्लुत से अवसर प्राप्त होते हैं। जनता अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्रतिनिधियों द्वारा न कराके स्वयं करती है। इससे लोक प्रभुसत्ता दृढ़ एवं प्रभावशाली बनती है।

(2) विधान मण्डल अधिक उत्तरदायी बन जाता है—उपक्रम की व्यवस्था में यह देखा गया है कि विधान मण्डल बहुत ही उत्तरदायी ढंग से कार्य करता है। विधान मण्डल इस बात से भयभीत रहता है कि कहीं उस पर ये आरोप न लगा दिये जाएँ की वह अयोग्य है और जन इच्छा की अवहेलना करना चाहता है। यही स्थायी भय उसे सतक एवं उत्तरदायी रखता है।

(3) भ्रमों का सशोधन करता है—प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनैतिक शिक्षण के कितने ही अवसर क्यों न मिलते हो परंतु फिर भी हम यह आशा नहीं करते कि मतदाता और उनके अन्य प्रतिनिधि विधि निर्माण में पूर्ण विशेषज्ञ हैं। उनसे बहुत सी त्रुटियाँ रह जाने की सम्भावना रहती है। विधान मण्डल की उदासीनता तो दर

होती ही है किन्तु उपक्रम विधान मण्डल द्वारा की जाने वाली श्रुतियों में सुधार करने का एक अच्छा साधन है। उपक्रम द्वारा लाभदायक व्यवस्थापन के निर्माण की सम्भावनाएँ रहती हैं। विधान मण्डल जिन आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहता है उनकी पूर्ति उपक्रम द्वारा जनता करा सकती है। क्रांतियों का भय दूर हो जाता है। ऐसा माना गया है कि हर व्यक्ति अपने हित को पहचानता है और जो प्रस्ताव जनता द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं उनकी वकालत भी अच्छी तरह से होती है। इन परिस्थितियों में जब लोगों को आत्म निणय का अधिकार हो तो विद्रोह इत्यादि की सम्भावना नहीं रहती, जन असतोष नहीं पनपता।

(4) धर्मवाद समाप्त हो जाता है—जब लोग स्वयं कानून बनाते हैं तो वग विभाजन की भावना निरुत्साहित हो जाती है। लोग दलीय हित को विमुख करके राष्ट्रीय हित की अधिक अपेक्षा करते हैं। लोकमत सग्रह में तो फिर भी विधानमण्डल ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकता है जो किसी वग विरोध के हित में हों किन्तु उपक्रम में यह सम्भव नहीं है।

(5) विधान व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं होगा—इस पद्धति के प्रवर्तकों का कहना है कि इसके अंतर्गत विधान मण्डल के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थों से अभिभूतित होकर पदयत्न नहीं कर पाते। इसमें दो राय नहीं हैं कि राजनैतिक दल एवं व्यक्तिगत हित विधान मण्डल के सदस्यों के दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। उपक्रम द्वारा विधियों का जो निर्माण होता है उसमें व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित पारस्परिक पदयत्न करके सावजनिक हितों की उपेक्षा नहीं कर पाते।

उपक्रम के अवगुण (Demerits of Initiative)

(1) विधान मण्डल महत्वहीन बन जाता है—प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की दोनों ही पद्धतियाँ विधान मण्डल की स्थिति एवं उसके महत्व को क्षीण बना देती हैं। लोकमत सग्रह का प्रहार ही विधानमण्डल के लिये पर्याप्त भयानक होता है परन्तु उपक्रम तो उससे भी कुछ आगे है। यह तो उसके महत्व को नष्ट करके उसकी जड़ों को खोखला बना देने वाला है। इन दोनों पद्धतियों को देख कर तो ऐसा लगता है कि यदि विधानमण्डल न हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

(2) कठोर सविधान निरर्थक बन जाते हैं—कठोर सविधान की विश्वास का प्रतीक कहा जाता है जो कि राजनैतिक दलों की अदूरदर्शिता और स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखता है। उसके सन्शोधन की क्रिया भी कुछ दुर्गम और विशिष्ट प्रकार की होती है। सघातमक प्रणाली में उसका एक विशय महत्व है किन्तु प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की पद्धति सविधान की दुष्परिवर्तनशीलता को इस सीमा तक विवश एवं निरर्थक बना देती है कि स्वयं सविधान उपहासात्मक सा जान पड़ता है। सविधान की कठोरता परिवर्तनशीलता में परिवर्तित हो जाती है और उसकी उपयोगिता भलीभाँति पड़ जाती है।

(3) व्यावहारिक उपयोगिता का अभाव—उपक्रम के कुछ आलोचकों का यह मत है कि इसका व्यावहारिक स्वरूप आशावान नहीं है। जहाँ जहाँ भी इसको व्यावहारिक स्वरूप दिया गया है वहाँ पर इसकी सफलता सदिग्धतापूर्ण है। स्वयं स्विट्जरलैंड में भी यह अधिक सफल नहीं रहा है। स्वयं कानूनों के निर्माण में भी

इसका अनुदाय महत्वहीन रहा है। प्रगतिशील व्यवस्थापन में भी इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

(4) शोषण के अवसर प्रदान करता है—उपक्रम के सम्बन्ध में आलोचकों का ऐसा अनुमान है कि इसके द्वारा समाज में उन तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है जो सामाजिक पक्षों की रचना करते हैं। उत्तेजनात्मक बातों के द्वारा जनता को गुमराह करते हैं। जनता के मानसिक सन्तुलन को राजनैतिक दल इतना दुबल बना देते हैं कि जनता आवेश में यह नहीं पहचान पाती कि कौन सी बात उसके हित में है और कौन सी नहीं। आकर्षण भाषणाएँ एवं प्रभावशाली, ओजस्वी शली एवं सामग्री के द्वारा जनता को ये नेता लोग शब्द जाल में फँसा लेते हैं और फिर काम निकालने पर अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। उपक्रम में जनता की अप्रामाण्यता विश्वास एवं स्वाभाविक स्वायत्तता के माध्यम से उत्तेजना फैलाने का पूर्ण अवसर मिलता है। ब्राइस के अनुसार उपक्रम एक उत्तमक वगैरह अवस्था असंदिग्ध नेता का वेगपूर्ण परिवर्तन की ऐसी योजना बनाने का प्रलोभन देता है जिससे कि वह एक वगैरह के लोगों को इतने आकर्षक लाभों की आशा दिलाता है कि वह कानून को ऊँची आवाज से पारित होने में सहयोग देता है।

(5) बुरे कानूनों के लिये उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता—उपक्रम के आलोचकों को उसके विरुद्ध एक अवसर इस आधार भी पर उपलब्ध होता है कि इसके अंतर्गत यह निश्चित करना इतना कठिन है कि बुरे कानूनों के निर्माण के लिये उत्तरदायित्व किसका है। लोकमत सग्रह में तो फिर भी हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिकता विधानमण्डल करता है कि तु उपक्रम में तो हम अपने को इस स्थिति में भी नहीं पाते क्योंकि वहाँ विधानमण्डल कहीं पर भी बीच में नहीं आता। समस्त जनता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुमत को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हम उन परिस्थितियों का सही एवं निश्चित मूल्यांकन करने में सफल नहीं हो पाते जिन्हें मध्य भावावेश में आकर अमुक विधेयक पर वे अपना मत प्रकट करते हैं।

(6) अनुचित व्यवस्थापन का आरम्भ—फाइनेर (Finer) के अनुसार उपक्रम किसी भी चीज में सुधार नहीं करता, न कानूनों में और न लोगों में। यह समाधान किये बिना ही विघ्न डालता रहता है। उपक्रम के विरुद्ध एक आरोप यह भी है कि जनता द्वारा रखे गये प्रस्ताव प्रायः अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। उनमें निपुणता का अभाव होता है और भाषा सम्बन्धी त्रुटियाँ भी कभी-कभी गम्भीर प्रकृति की होती हैं। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि अस्पष्ट एवं अनुचित कानूनों को सशोधित करने अथवा उनमें सामयिक परिवर्तन करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। ऐसे व्यवस्थापन के परिणाम अनिश्चित तथा दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होंगे। ऐसे कानून जिन पुस्तकों में भी बद्ध किये जायेंगे वे बुरे शब्दों के सग्रह मात्र ही होंगे।

प्रत्याह्वान
(Recall)

लीकॉक (Leacock) के मतानुसार “पद ग्रहण करने वाले सब व्यक्तियों को तभी तक पद ग्रहण करना चाहिए जब तक कि लोग उनकी पदावधि की स्वीकृति

दें। जिस समय भी मतदाताओं का बहुमत अधिकारी को इसके पद से हटाना चाहे तो हटाया जा सकता है।" प्रत्याह्वान की पद्धति का प्रमुख लक्ष्य विधायकों पर निर्वाचकों का नियन्त्रण रखना है। इस प्रणाली के तत्त्वविधान में विधायिका के मतदाताओं को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि यदि वे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि की गतिविधियों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे उसे हटा सकें और उसके स्थान पर नये प्रतिनिधि को निर्वाचित करके भेज सकें। प्रायः यह देखने में आता है कि जिन देशों में इस प्रणाली का अनुकरण नहीं किया जाता और वहाँ की जनता यदि जन जागरूकता के गुण से वंचित है तो वहाँ विधायक पैर फँसा कर सुख की नींद सोते हैं। वे अपने क्षेत्र के विषय में चिंतित नहीं रहते और निर्वाचनोपरांत यह जाकर भी नहीं देखते कि उनकी विधायिका में क्या होता है। पाँच वर्ष के लिये वे निश्चित हो जाते हैं और अपने क्षेत्र का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इस प्रकार के विधायकों का प्रत्याह्वान करना जनता का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। क्षेत्र की एक निश्चित जनसंख्या इस अधिकार का प्रयोग करके विधायक को हटा सकती है। अधिकारियों के प्रत्याह्वान का अधिकार भी जनता को प्राप्त रहता है। लावेल के अनुसार इस विधि का मूल उद्देश्य केवल अधिकारियों तथा "यायाधीशों को हटाना ही नहीं है वरन् प्रतिनिधियों को निर्वाचकों के नियन्त्रण में रखना भी है।

अमेरिका के कुछ पश्चिमी राज्यों में अधिकारियों का प्रत्याह्वान करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। ये राज्य हैं एलीजोना, मीनोटाना, किकहोमा लूइसियाना, कनसास, वाशिंगटन कलीफोर्निया अकन सासा कालोरडो उत्तरी डकाटा नेबडा तथा ओरिगन। ओरिगन राज्य में तो "यायाधीशों" तक को वापस बुलाया जा सकता है। वाशिंगटन में "यायाधीश" इस प्रणाली से नहीं हटाये जा सकते। अपने देश में भी कभी कभी यह चर्चा चल पड़ती है कि यह अधिकार यहाँ की जनता को भी प्राप्त होना चाहिये। प्रोफसर लास्की ने इस अधिकार के सीमित प्रयोग पर बल दिया है। सीमित प्रयोग के सम्बन्ध में उनके परामर्श इस प्रकार हैं

(1) इस अधिकार का प्रयोग निर्वाचन के पश्चात् एक वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिये।

(2) विधान मण्डल के कार्य काल के अन्तिम वर्ष में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

(3) जब तक आधे निर्वाचक न चाहें तब तक पदाधिकारियों को न हटाया जाय इसका निश्चय भी उस निर्वाचन के द्वारा होना चाहिये।

(4) यदि दो तिहाई बहुमत चाहे तभी इस पद्धति का प्रयोग किया जाय। ग्राइस ने भी इस पद्धति का समर्थन किया है। "यायाधीशों के सम्बन्ध में अमेरिका के जिन ६ राज्यों में इसका प्रयोग किया गया वह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस पद्धति के गुण और दोष इस प्रकार हैं

प्रत्याह्वान के गुण (Merits)

(1) लोक प्रभुसत्ता को वास्तविक उपलब्धि सुलभ हो सकती है।

(2) अधिकारियों को नियन्त्रित रखने तथा उन्हें शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिये प्रभावशाली यंत्र है।

(3) अधिकारी प्रलोभन आदि से मुक्त रहते हैं क्योंकि यह डेमोनीज की तलवार की भाँति उनके सिर पर सटकी रहती है।

(4) राजनतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उत्तम यत्र है।
अवगुण (Demerits)

(1) इसका परिणाम लयाय हो सकता है क्योंकि किसी सत्यनिष्ठ कमचारी ने कतव्य निर्वाह करते समय निर्वाचको को रुष्ट कर लिया हो और उनके सम्पूर्ण आक्रोश का भोजन बन जाय।

(2) प्रशासन को क्षति पहुँच सकती है क्योंकि योग्य व्यक्ति दुजनों के पदग्रों से भयभीत रहते हैं।

(3) अधिकारी बग स्वतन्त्र नहीं रह पाता।

(4) 'यायाघीशों' को इस पद्धति से हटाने पर दुष्ट व्यक्तियों का शासन होगा और 'याय खतरे में पड़ जायगा।

(5) लोकहित की अवहेलना होगी।

(6) प्रतिनिधि वास्तव में प्रतिनिधि नहीं रहते बरन विशिष्ट हितों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण और दोष

गुण (Merits)

(1) प्रजातन्त्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और जनता को प्रशासन से साक्षात्कार स्थापित करने के लिए एक के बाद एक अवसर मिलते रहते हैं। जनता को अपनी स्थिति एवं शक्तियों के महत्व का अनुभव होता है।

(2) जनता पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं थोपा जा सकता। यह इस सत्य को प्रमाणित करता है कि कानून जन इच्छा की ही अभिव्यक्ति है।

(3) जब कानूनों का निर्माण जनता के द्वारा होता है तो उनका पालन भी उतनी ही श्रद्धा एवं सम्मान के साथ स्वाभाविक रूप से किया जाता है।

(4) जनता के प्रशासनिक ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ ही राजनतिक शिक्षण भी उपलब्ध होता है। जनता को राजनतिक विषयों पर मनन करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं।

(5) लोक मत सग्रह की व्यवस्था राजनतिक दलों के कुछ प्रभावों को घटाती है।

(6) व्यवस्थापिका अपरिपक्व एवं अदूरदर्शी प्रस्तावों को स्वीकार करने से घबराती है और उसे जन आकांक्षा के प्रति सतक रहना पड़ता है।

(7) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन जनता में इस चेतना को जन्म देता है कि वह विधि का निर्माता है। इस अवस्था में न तो बहुमत को निरकुशता प्राप्त होती है और न ही अल्पसंख्यक वर्ग को निराशा।

(8) प्रत्याह्वान की पद्धति प्रतिनिधियों को सतक रखती है और उन्हें जन सम्पर्क बनाये रखने के लिए विवश करती है।

(9) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि पूजीपति अथवा व्यापारिक वर्ग शासन पर अपना अधिकार नहीं जमा पाता।

दोष (Demerits)

(1) सब साधारण को विधि निर्माण काय के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय की शक्ति देना राष्ट्रीय हित के लिये निःसन्देह घातक सिद्ध हो सकता है।

(2) व्यवस्थापिका का महत्व कम हो जाता है। सदस्यों में काय के प्रति रुचि नहीं रहती जिसके फलस्वरूप वे अनुत्तरदायी ढंग से व्यवहार करने लगते हैं।

(3) लोकमत सभ्य को जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। मतदान में जितने लोग भाग लेते हैं वह संख्या निःसन्देह निराशाजनक ही कही जायेगी।

(4) जनसाधारण के पास समय का अभाव रहता है। विधि निर्माण का काय योग्यता और समय चाहता है। इनमें से दोनों ही चीजें जनसाधारण के पास कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी यकान मतदाताओं में बढ़ जाती है। बस्ती का यह कहना सही है कि जनता व्यावसायिक कानून बनाने वाले का स्थान नहीं ले सकती। शासन कार्यों की जटिलता को देख कर नागरिकों से उपयुक्त निर्णय की आशा करना रेत में से तेल निकालना है।

(5) जनता के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों के सम्बन्ध में जनता को पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्हें 'हाँ' अथवा 'ना' करने का ही अवसर प्रदान किया जाता है। अतः उनके समक्ष विकल्प का स्वरूप बहुत ही संकुचित होता है।

(6) राष्ट्रीय आर्थिक नीति से सम्बन्धित कानूनों पर नागरिक स्वायत्त होने के कारण कोई निष्पक्ष निर्णय देने में समर्थ नहीं हो पाते। "ऐसी दशा में सलाहों की पेटी का परिणाम आदर्शों या विचारों की लड़ाई का फल न होकर निहित हितों के संपर्क का प्रतिबिम्ब होता है।"

(7) जनता के सदस्य प्रायः रुढ़िवादी होते हैं जो प्रगतिशील विधेयकों का स्वागत नहीं करते। इसी कारण प्रत्यक्ष व्यवस्थापन प्रगतिशील कानून देने में असफल रहा है।

(8) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की पद्धति अत्यन्त खर्चीली है। इसमें बार-बार निर्वाचन होते हैं, जिनकी व्यवस्था पर काफी धन लगाना पड़ता है।

(9) बड़े देशों में प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की पद्धति को लागू नहीं किया जा सकता।

(10) प्रायः यह देखने में आता है कि विधेयक उस समय जनता द्वारा स्वीकृत होकर आते हैं जबकि उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो चुकती है। विधेयकों की स्वीकृति में अनावश्यक रूप से देरी लगती है। सक्रमणकालीन समस्याओं का सामना कठिनाता से सम्भव हो सकेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की प्रणाली में बहुत से दोष हैं परन्तु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि इनमें से कुछ को दूर किया जा सकता है। स्विटजरलैण्ड में यह प्रणाली काफी सफल हुई है। वहाँ पर इसके विरुद्ध कोई विशेष यातावरण नहीं है। "प्रजातंत्र की प्रणाली स्विस राजनैतिक संगठन का एक आवश्यक और स्वतंत्र रूप से काम करने वाला अंग बन गई है।" अन्य देशों में इसके परीक्षण

आशावादी सिद्ध नहीं हुए हैं। रपट का स्विस प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के विषय में यह पर्यवेक्षण सही है कि यदि कोई स्विटजरलैण्ड में एक गली से गुजरने वाले मनुष्य से पूछे कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के अनुभवों के परिणाम से पूर्णतः सन्तुष्ट है, उत्तर अवश्य ही स्वीकारात्मक रूप में दिया जायगा।

स्थानीय सभाएँ (Landsgemeinde)

उरी, ग्लेरियस के पूरा कंटोन तथा अण्डरवालडेन, जुग, श्वेज तथा अपेजिस के अर्द्धकंटनों में स्थानीय सभाएँ आज भी सफलतापूर्वक कार्य करती हैं। इन सभाओं का मुक्त वायुमण्डल का लोकतन्त्र कहा गया है। विधायी शक्ति जनता में निहित है, ये इस सत्य को पूर्णरूप से प्रमाणित करती हैं। इन जन सभाओं को लैण्डसजीम-हाई कहा जाता है।

स्थानीय सभाओं में उस क्षेत्र के समस्त वयस्क व्यक्ति भाग लेते हैं। इसे हम नागरिकों की राजनतिक सभा भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का यह व्येष्टतम स्वरूप है। ये प्राचीन यूनान के नगर राज्यों का स्मरण कराती हैं जहाँ पर कि विधि निर्माण हेतु नगर के समस्त वयस्क व्यक्ति भाग लेते थे। समस्त वयस्क व्यक्तियों से इन सभाओं में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। कहीं कहीं तो अनुपस्थित रहने वाले व्यक्तियों पर दण्ड शुल्क (Fines) की व्यवस्था भी पाई जाती है। स्थानीय सभाएँ कानून बनाती हैं और उन कानूनों की पुष्टि भी करती हैं जोकि उनके द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका ने बनाये हैं। स्थानीय सभाओं के कुछ प्रमुख कार्य निम्न लिखित हैं।

- 1 सविधान में संशोधन पर विचार करना।
- 2 सामान्य विधियों का निर्माण करना।
- 3 करारोपण एवं ऋण की व्यवस्था करना।
- 4 सावजनिक सम्पत्ति का निपटारा करना।
- 5 मताधिकार तथा नवीन पदों की सृष्टि से सम्बन्धित प्रश्नों एवं समस्याओं पर विचार करना।
- 6 स्थानीय कार्यपालिका के अधिकारियों का निर्वाचन करना।
- 7 अनुदानों की स्वीकृति, वेतनभ्रम का निर्धारण।
- 8 कार्यकारिणी का निर्वाचन।

कुछ विद्वानों ने तो इन स्थानीय सभाओं की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। रपट के शब्दों में, “यह विश्वास करना कठिन है कि लोक सभाएँ अनिश्चित काल तक बनी रह सकती हैं। ये प्रारम्भिक लोकतन्त्र के प्रदर्शनात्मक नमूनों अथवा बीते हुए दिनों की स्मृति चिह्नों के रूप में ही रह सकती हैं।”

स्विटजरलैण्ड में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की सफलता के कारण (Causes of Success of Direct Democracy in Switzerland)

मुनरो ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की जनता द्वारा सीधी कार्यवाही का एक साधन कहा है। (A channel of direct action by the people) मुनरो के ही शब्दों में ‘लोकतन्त्र का अध्ययन करने वाले के लिए स्विटजरलैण्ड में इससे अधिक अथ

कोई वस्तु शिक्षाप्रद नहीं है।¹ के० सी० ह्यूये ने कहा है कि स्विस संविधान अवश्य ही दुष्परिवर्तनशील है, परन्तु जनता में गतिशीलता है। स्विस शासन प्रणाली का केन्द्र बिन्दु अब भी लोकमत सग्रह है। जॉन वि सेंट (Vincent) ने इस सत्य पर प्रकाश डाला है कि 'स्विटजरलैण्ड में 1848 से लेकर शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना तक जो संवैधानिक प्रगति हुई है वह केवल वकीलों तथा राजनीतिज्ञों के प्रयत्नों से ही नहीं हुई अपितु लोकमत सग्रह में 'युक्त जनता की स्पष्ट सम्मति के द्वारा हुई है।' बैजूर (Banjour) ने लोकमत सग्रह को राजनैतिक वातावरण का बैरोमीटर कहा है। स्विटजरलैण्ड की पुरुष प्रधान राजनीति ने 1971 में स्विस लोकतन्त्र के एक बहुत बड़े कलक को स्त्री सत्ताधिकार को देने के प्रयत्न में समर्पित कर दिया। लॉर्ड ब्राइस ने प्रत्यक्ष जनतन्त्र की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य पर बल दिया है कि "कुछ ऐसी सच्चाएँ हैं जो पौधों के समान एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में ही विकसित होती हैं।"² स्विटजरलैण्ड अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक परम्पराओं तथा राजनैतिक अपेक्षाओं के कारण प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जैसी सस्था को सफल बनाने में समर्थ हो सच है। वातावरण एवं सांस्कृतिक मायताओं का प्रभाव सस्थाओं की सफलता अथवा असफलता में निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण है। स्विस लोकतन्त्र की सफलता में जिन तत्वों का सहयोग रहा है वे इस प्रकार हैं

(1) भौगोलिक स्थिति (Geographical Conditions)—स्विटजरलैण्ड प्रकृति की गोद में पला हुआ, नदी, घाटियों घने जंगलों तथा पर्वतमालाओं लुपी वस्त्रों को धारण करने वाला सुकोमल नहा सा सुकुमार है। स्विटजरलैण्ड एक कृषि प्रधान देश है। सकल परीक्षणों की अभूत्य कमस्वली है। भौगोलिक परिस्थितियों ने पर्वतीय प्रदेशों की दुर्गमता को व्यापक जन सम्पर्क तथा सौहार्द में परिवर्तित कर दिया है। स्विस निवासियों में परम्पराओं के प्रति मोह तथा स्थानीय स्वतन्त्रताओं के प्रति अनुराग विचित्र भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। स्विस जनजीवन पर वहाँ के प्राकृतिक सौ दम की अमिट छाप है, उगते तथा डूबते हुए सूर्य की आभा राजनैतिक जीवन को भी अनुप्राणित करती है। यदि स्विटजरलैण्ड एक विशाल राष्ट्र होता तो उसे भी अमेरिका तथा भारत की भाँति अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अपनाना पड़ता।

(2) नागरिकों का चरित्र (Character of the People)—ड्यूब्स (Dubbes) के इस कथन में बड़ा सत्य छिपा हुआ है कि 'विश्व के देशों पर दृष्टि पात कीजिए। यद्यपि आपको अल्प स्थानों पर अधिक बड़ी राजनैतिक सफलताएँ मिल सकती हैं परन्तु आपको स्वतन्त्र, राष्ट्रीय एवं व्यावहारिक विचार करने वाले इतने अच्छे नागरिक अल्प किमी दश में नहीं मिलेंगे, और न ही कहीं पर इससे अधिक ऐसे जन सेवक मिलेंगे जो दोत्रों में अपने कामों को सम्मान एवं बुद्धिमत्ता के साथ करने

1 Nothing in the Swiss Political System is more instructive to the student of modern democracy
—Munro

2 There are institutions which like plants flourish only on their own hill side under their own sunshine
—Bryce

मे सफल हो सकें।" राष्ट्र की उन्नति, उसका गौरव एवं राजनैतिक समस्याओं की सफलता का सम्बन्ध वहाँ के निवासियों के चरित्र से है। राष्ट्र तथा समस्याएँ केवल कानून से नहीं पनपती। उसके लिए श्रेष्ठ एवं आदर्श चरित्र रामबाण औपधि है। ईमानदारी कसब्यपरायणता एवं कायनिष्ठा आदि नैतिक गुण वहाँ के नागरिकों के जीवन में समाहित हैं। स्विस नागरिक भावावेप से मुक्त विवेक से कार्य करते हैं। समस्याओं को तक की कसीटी पर कसते हैं और अनुभव एवं ईमानदारी को प्रभुता देते हैं। वे अस्थायी सवेगों के दास नहीं हैं। स्वभाव से स्विस नागरिक मध्यमार्गी हैं और उन्होंने यही रूप अपने जनतन्त्र को भी दिया है। लोगों के चरित्र में राजनैतिक जागरूकता, उदारता, निष्पक्षता तथा सहृदयता विद्यमान है। वे न तो रुढ़िवादी ही हैं और न ही अत्यधिक आधुनिकता के पुजारी। इन सब गुणों का सामूहिक प्रभाव स्विस राजनैतिक समस्याओं पर भी हुआ है।

(3) तटस्थता की नीति (Policy of Neutrality)—स्विटजरलैण्ड की लोकतन्त्रीय व्यवस्था की सफलता का एक कारण उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता की नीति है। वह सदैव से ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ रहा है, जिसके फलस्वरूप वह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों से भी मुक्त रहकर आन्तरिक समस्याओं के प्रति अधिक सजग रह सका है। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में ऐसे पक्षों का विचार है जिसका सिध्द भावनाओं के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सैनिक तैयारियों की आवश्यकता भी कभी अनुभव नहीं हुई है, अतः उसका समस्त ध्यान लोकतन्त्रीय उपकरणों को सफल बनाने में ही लगा रहा।

(4) सामाजिक एवं आर्थिक समानता (Social & Economic Equality)—स्विस सामाजिक जीवन आर्थिक द्वेष, प्रतिस्पर्धा तथा वैमनस्य से मुक्त है। वह अमेरिका की भाँति न तो घनाढ्य ही है और न ही भारतवर्ष की भाँति तिथन। वहाँ पर आर्थिक जीवन भी स्वाभाविक रूप से ही सन्तुलित है, अतिवादी नहीं। यहाँ पर धन का सग्रह कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में नहीं है। राज्य का स्वरूप लोकहितकारी राज्य का स्वरूप है। बड़े बड़े उद्योग धंधों पर राज्य का नियन्त्रण है। इस सन्तुलित आर्थिक जीवन का प्रभाव स्विस लोकतन्त्र की सफलता में सहयोगी तत्व के रूप में पड़ा है।

(5) व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव (Absence of Professional Politicians)—स्विस राजनैतिक जीवन व्यावसायिक राजनीतिज्ञों से मुक्त है। यहाँ पर राजनीति पर पनपने वाले ऐसे गिढ़ नहो हैं जोकि निमग्नता तथा छल से लोगों का मुडन करते हैं। जोकि राजनीति के कुशल खिलाडी हैं तथा जोड़ तोड़ बैठाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। कोठियों के निर्माण तथा सम्पत्ति उपाजन में ही लगे रहते हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के ये पोषक अत्यधिक सख्या में पाये जाते हैं। परन्तु स्विटजरलैण्ड ऐसी आत्माओं से मुक्त है। ऐसी मानव वृत्ति वहाँ के जीवन में कीटाणु बनकर प्रवेश नहीं कर सकी है। इसीलिए वहाँ पर न तो राजनैतिक लूट खसोट ही है और न ही राजनीति के प्रति लोगों में इतना अनुराग। इसीलिए ही दलीय अनुशासन जैसी बातें भी वहाँ पर कम पाई जाती हैं।

(6) स्थानीय स्वशासन में प्रेम (Affection for Local Government)—

स्विस प्रजातन्त्र का मूल सिद्धांत है—कम्यून, कैण्टन तथा तत्पश्चात् परिसर। सदैव से ही स्थानीय स्वशासन के प्रति लोगों का अनुराग रहा है। इस स्वतन्त्रता को वे किसी भी मूल्य पर त्यागने को तयार नहीं हैं। वहाँ पर स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं को राजनैतिक शिक्षण एवं अनुभव की प्रयोगशाला समझा जाता है। राजनैतिक शिक्षण तथा स्थानीय स्वशासन की परम्पराओं का लोकतन्त्र की सफलता में विशेष अनुदाय रहा है।

(7) राष्ट्रीय एकता (National Unity)—स्विटजरलैंड विविध भाषाओं तथा घमों वाला देश है परन्तु फिर भी वहाँ पर विविधता में ही एकता है। यहाँ पर निम्न कोटि के धार्मिक एवं भाषागत विवाद नहीं हैं। यहाँ का जीवन स्वतन्त्रता तथा सहिष्णुता की भावनाओं से पूर्ण है। यहाँ के लोगों में उदारवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ है तथा उनमें एक अनोखी एकता उपलब्ध है। उनमें पृथक्तावादी मनोवृत्ति नहीं है जोकि कहीं के भी लोकतन्त्रीय एवं राष्ट्रीय जीवन को नष्ट कर सकती है।

(8) प्रेस (Press)—प्रेस लोकतन्त्र में सबसे बड़ा उद्योग है। स्वस्थ प्रेस स्वस्थ जनमत का पोषक तथा सफल लोकतन्त्र का एक मात्र आधार है। प्रेस जितना निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र होगा लोकतन्त्र भी उतना ही सफल होगा। स्विटजरलैंड में प्रेस पर्याप्त रूप में शक्तिशाली तथा निर्भीक है, जो किसी बग विशेष के हितों का ही पोषण मात्र नहीं करते तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण ही जनसमुदाय को समझ प्रस्तुत करते हैं।

(9) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सफल उपकरण (Tools of Direct Democracy)—किसी भी पद्धति की सफलता केवल उसके साध्यों एवं उद्देश्यों पर ही अवलम्बित नहीं होती है। उसकी सफलता बहुत कुछ उसके साधनों एवं उपकरणों पर भी निर्भर होती है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उपकरण—लोक निर्णय तथा उपक्रमो—ने ही निश्चयात्मक तथा निपेक्षतात्मक दोनों ही रूपों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की सेवा की है। इन्होंने नागरिकों को जागरूक तथा हीन कुण्डाओं से ऊपर तो रखा ही है साथ ही विधान मण्डलों की राजतन्त्रीय मनोवृत्ति पर भी अकुश लगाया है। सफल उपकरण किसी भी पद्धति को सफल बना सकते हैं। अतएव स्विस जनतन्त्र की सफलता में लोक निर्णय तथा उपक्रम का विशेष हाथ है। इन्होंने जन सप्रभुता को सफल प्रमाणित कर दिखाया है।

Select Reference

- Finer *Major Governments of Europe*
 Bryce *Modern Democracies*
 Rappard *Govt & Politics of Switzerland*
 Lowell *Govt & Politics of Continental Europe*
 Brooks *The Govt of Switzerland*
 Hans Huber *How Switzerland is Governed*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र से आप क्या समझते हैं? स्विटजरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की क्रियावित पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिए।

(What do you understand by Direct Democracy ? Write a short essay on its working in Switzerland)

- 2 'प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधन के लाभ वास्तविकता से अधिक दिखावा हैं।' स्विटजरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की क्रियाविति के प्रसंग में इसकी व्याख्या कीजिए।

("Advantages of direct democratic devices are more apparent than real" Discuss with reference to the working of democracy in Switzerland)

- 3 स्विटजरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की क्रियाविति की व्याख्या कीजिए। यह कहाँ तक सफल हुआ है ?

(Describe the working of Direct Democracy in Switzerland How far is it success ?

- 4 स्विटजरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक अवरोधों की समीक्षा कीजिए। यह कहाँ तक सफल हुआ है ?

(Examine the working of Direct Democratic checks in Switzerland How far are they successful ?)

- 5 स्विटजरलैंड में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की सफल कार्यवाही का कारण बताइये।

(Account of the successful working of democratic institutions in Switzerland)

- 6 स्विटजरलैंड में जनमत संग्रह एवं आरम्भण के प्रभाव एवं कार्यकरण का वर्णन करें।

(Describe the working and assess the influence of Referendum and Initiative in Switzerland)

- 7 स्विटजरलैंड में प्रचलित जनमत संग्रह और आरम्भण प्रणाली का विवेचन करें।

(Describe the system of the initiative and the referendum in Switzerland)

- 8 "स्विटजरलैंड का प्रजातन्त्र ससार के अन्य देशों के प्रजातन्त्रों से अधिक सही ज्यों में प्रजातन्त्रात्मक है। लार्ड ब्राइस के इस कथन के औचित्य को स्विटजरलैंड के प्रजातन्त्र की विशेषताओं के आधार पर सिद्ध कीजिए।

(Swiss democracy is more truly democratic than the democracy in any other country in the world Justify this statement of Lord Bryce on the basis of the distinguishing features of the democracy in Switzerland)

- 9 प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की परिभाषा कीजिए। यह स्विटजरलैंड में किस प्रकार कार्यान्वित होता है ?

(Define 'Direct Democracy' How is it being worked out in Switzerland ?)

- 10 "प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधनों के लाभ वास्तविक की अपेक्षा दिखावटी अधिक हैं।" उक्त कथन के सन्दर्भ में स्विटजरलैंड के प्रजातन्त्र की क्रियाविति की विवेचना कीजिए।

(The advantages of direct democratic devices are more apparent than real ' Discuss this statement with reference to the working of democracy in Switzerland)

स्विस सघीय न्यायाधिकरण तथा राजनैतिक दल [Swiss Federal Tribunal & Political Parties]

परिचयार्थक

सन् 1848 के संविधान में सघीय न्यायाधिकरण की शक्ति बहुत ही अल्प एवं सीमित थी। उसे केन्द्र तथा कंट्रॉन् के पारस्परिक विवादों के निणय करने का अधिकार नहीं था। सघीय न्यायालय केवल उन्ही विषयों पर विचार करता था जो कि उसके पास सघीय परिषद द्वारा भेजे जाते थे। सघीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के विषय में सन् 1874 के संविधान में कुछ परिवर्तन किये गये थे परन्तु वे भी अधिक क्रान्तिकारी एवं महत्वपूर्ण नहीं थे। सघीय न्यायाधिकरण को वह स्तर प्राप्त नहीं हुआ है जो कि अमेरिका तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है उसकी शक्तियों में जो कुछ भी विकास हुआ है तथा इतना उच्च स्तर प्राप्त करने में भी काफी समय लगा है। विधियों के एकीकरण तथा अनाधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में भी सघीय न्यायाधिकरण का अनुदाय महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलण्ड के सम्पूर्ण सघीय क्षेत्र के लिये संविधान की धारा 107 के अन्तर्गत एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसे ही देश का सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त है। इसे ही संविधान के अनुच्छेद 106 के अन्तर्गत सघीय न्यायाधिकरण (Federal Tribunal) का नाम दिया गया है। इसका सन् 1907 के सिविल कोड तथा 1937 के सिविल फौजदारी कोड के अन्तर्गत और अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

सघीय न्यायाधिकरण की रचना (Composition of the Federal Court)

सघीय न्यायाधिकरण में 26 से 28 तक न्यायाधीश होते हैं। संविधान न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं करता। सन् 1875 में न्यायाधीशों की संख्या केवल 9 थी। सन् 1943 में इस संख्या को एक विधि के द्वारा पुनः स्थापित किया गया और इसकी सन्त्य संख्या में वृद्धि हुई जो कि 28 तक पहुँच गई। इन न्यायाधीशों के अतिरिक्त वैकल्पिक न्यायाधीश (Alternative Judges) की नियुक्ति करने की व्यवस्था भी पाई जाती है। वैकल्पिक न्यायाधीशों की संख्या 11 से 13 तक हो सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सघीय सभा द्वारा 9 वर्ष के लिए होती है। सघीय सभा ही इन न्यायाधीशों में से एक को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। परम्परानुसार न्यायाधीशों का पुनर्निर्वाचन होता रहता है जिससे उन पदों में स्थायित्व का भाव आ जाता है। केवल अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते। बार बार निर्वाचन होने से न्यायाधीशों में अनुभव की

गरिमा बनी रहती है। सविधान में 'यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का भी उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु वहाँ परम्परा से ऐसा प्रतीत होता है कि वे 70 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। परम्परानुसार इस अवस्था को प्राप्त करने के उपरान्त यायाधीश स्वतः ही त्यागपत्र प्रस्तुत कर देते हैं। यह कहना भी उचित ही है कि यायाधीशों को बार-बार की नियुक्ति से 'यायाधिकरण को सघीय परिषद के नियन्त्रण से पर्याप्त मात्रा में मुक्ति मिली है।

अर्हताएँ (Qualifications)—स्विस सविधान में 'यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि 'यायाधीश केवल वे ही व्यक्ति बन सकेंगे जोकि सघीय सभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। इस प्रतिबंध की एक उपसिद्धि यह भी है कि पादरी तथा अन्य धर्माधिकारी 'यायाधीश का पदग्रहण कर सकेंगे। 'यायाधीशों का निर्वाचन करते समय अनुभव बौद्धिक योग्यता एवं कानून की विशेष योग्यता आदि को दृष्टिगत रखा जाता है। स्विटजरलैण्ड की विभिन्न भाषाओं धर्मों तथा प्रमुख राजनैतिक दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसीलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वहाँ पर राजनैतिक जीवन दलीय पद्धति की दुर्गन्धता से मुक्त है। एक ही कैबिनेट के दो यायाधीश नहीं हो सकते ऐसे लोग भी 'यायाधीश नहीं हो सकते जो निकट के सम्बन्धी है अथवा सघीय तथा कैन्टोनल सरकारों के आधीन कोई लाभ का पद ग्रहण किये हुए हों। परन्तु यह भी सदेहास्पद ही है कि स्विस जीवन तथा 'यायाधीशों का निर्वाचन राजनैतिक दलबन्दी से मुक्त है।

वेतन, सचिवालय तथा विभाग आदि (Salaries, Secretariat & Departments)

सघीय यायालय के प्रत्येक 'यायाधीश को 53 हजार फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है। सघीय यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्रमशः अन्य यायाधीशों की अपेक्षा 3600 तथा 2400 फ्रैंक अधिक वेतन मिलता है। बैंकल्पिक 'यायाधीशों को वेतन नहीं मिलता अपितु उन्हें भत्ता दिया जाता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है सेवा अवधि के आधार पर वेतन का 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में दिया जाता है।

'यायाधिकरण का मुख्य कार्यालय लासेन नगर में स्थित है। यायाधीशों को वही रहना पड़ता है परन्तु उन्हें नागरिक अधिकार उनसे सम्बन्धित कैबिनेटों में भी प्राप्त होते हैं। वे इस पद पर आसीन रहते हुए कोई अन्य नौकरी तथा व्यवसाय नहीं कर सकते। सघीय यायालय का अपना एक सचिवालय भी होता है जिसे चांसलरी कहा जाता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी स्वयं यायाधिकरण द्वारा ही की जाती है।

काय की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सघीय यायालय को निम्नलिखित चार विभागों में विभाजित किया गया है

(1) संवैधानिक अथवा प्रशासकीय 'यायालय (Constitutional and Administrative Law Courts) इसमें 3 से लेकर 9 तक 'यायाधीश रहते हैं।

(2) फौजदारी अपील न्यायालय (Criminal Appellate Court) इसमें भी इतने ही न्यायाधीश होते हैं।

(3) ऋण तथा दिवालियापन का चैम्बर (Chamber of Debts and Bankruptcy)।

(4) दोषारोपण चैम्बर (Chamber of Complaints) इनमें लगभग 3 न्यायाधीश होते हैं।

न्यायालयों में जूरी व्यवस्था का प्रयोग होता है। प्रत्येक न्यायिक विभाग का एक अध्यक्ष होता है। इसमें नियम बहुमत से किए जाते हैं। बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष को नियमात्मक मत देने का अधिकार होता है। न्यायाधिकरण की कार्यवाही जनता के लिए खुली रहती है। कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही को गुप्त भी रखना पड़ता है। संवैधानिक न्यायालय में गणपूर्ति की संख्या 7 निश्चित की गई है परन्तु अन्य सभी न्यायालयों में गणपूर्ति की संख्या 5 है।

सघीय न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

सघीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

इसमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें सघीय न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के दीवानी विवाद भी प्रस्तुत किये जाते हैं

- (i) सघ सरकार तथा कंटनों के मध्य सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद।
- (ii) राज्य सघ तथा किसी निगम अथवा निजी व्यक्ति के मध्य विवाद जिसका मूल्य 8000 फ्रैंक से कम न हो।
- (iii) कंटनों के मध्य होने वाले विवाद।
- (iv) राष्ट्रीयता के खीये जाने के विषय में विवाद।
- (v) कंटनों की कम्प्यूनों में नागरिकता विषयक विवाद।
- (vi) यदि दोनों पक्ष विवाद को सघीय न्यायाधिकरण को सौंपने हेतु प्रस्तुत

हों और उसका मूल्य 10,000 फ्रैंक से कम नहीं हो तो सघीय न्यायाधिकरण ऐसे मामलों को नियम के लिए स्वीकार कर सकता है।

फौजदारी विवाद (Criminal Cases)—(i) राज्य मण्डल के विरुद्ध विद्रोह सघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह तथा हिंसा आदि के विवाद।

- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध विवाद।
- (iii) राजनैतिक अशांति के ऐसे विवाद जिनमें सघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
- (iv) फर्जी मुद्रण के सम्बन्ध में विवाद।
- (v) कंटनों की सरकारों द्वारा सघ सरकार ने पास प्रेषित विवाद।
- (vi) सघीय कमचारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कमचारियों पर लगाये गये आरोपों के विषय में विवाद।

फौजदारी विवादों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण स्विटजरलैण्ड को 5 जिलों में विभाजित किया गया है। विवादों की सुनवाई एक जूरी के द्वारा होती है जिसमें 12 सदस्य होते हैं। प्रत्येक विवाद में निणय करने के लिए जूरी की 6 सस्या की स्वीकृति आवश्यक है।

(2) अपीलक्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

ऐसे विवाद जिनका मूल्य 4000 फ्रैंक अथवा इससे अधिक आँका गया है और जिनका निणय भी कैंटनों के 'यायालयों' द्वारा ही किया गया हो, उनके निणयों के विरुद्ध अपील सघीय 'यायाधिकरण' में की जा सकती है।

(3) प्रशासकीय क्षेत्राधिकार (Administrative Jurisdiction)

सन् 1925 से पूर्व प्रशासकीय विवादों का निणय सघीय परिषद करती थी परन्तु इसके पश्चात् सघीय सभा द्वारा पृथक् प्रशासकीय 'यायालय' की स्थापना न करके ये अधिकार सघीय 'यायाधिकरण' को ही समर्पित कर दिये गये। अतएव प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित प्रकार के विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं—

(i) ऐसे विवाद जिनका सम्बन्ध सरकारी कर्मचारियों की योग्यता तथा क्षमता आदि से है।

(ii) ऐसे विवाद जिनका सम्बन्ध सघीय रेलवे शक्ति से है।

(iii) कराधान सम्बन्धी प्रशासकीय विवाद।

(iv) राज्य कर्मचारियों तथा नागरिकों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निणय भी सघीय 'यायाधिकरण' ही करता है।

(4) संवैधानिक क्षेत्राधिकार (Constitutional Jurisdiction)

(i) सघीय तथा कैंटनों के कर्मचारियों के मध्य विवाद।

(ii) कैंटनों के ऐसे विवादों की सुनवाई सघीय 'यायाधिकरण' करता है जो कि सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं।

(iii) नागरिकों की ऐसी शिकायतें जिनका सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौतों से है।

(iv) नागरिकों को जो अधिकार कैंटनों के संविधानों ने तथा सघीय संविधान ने प्रदान किये हैं उनके विरुद्ध किये गये कार्यों की अपील सघीय 'यायालय' सुनता है।

स्थिति (Position)

स्विस 'यायाधिकरण' की स्थिति अमेरिकी उच्चतम 'यायालय' जसी शक्तिशाली नहीं है। इसका मूल कारण है 'यायिक पुनर्विलोकन' की शक्ति का अभाव। सघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों को अवैध घोषित करने का अधिकार केवल जनता को ही है सघीय 'यायाधिकरण' को नहीं। सघीय 'यायाधिकरण' को अपने अस्तित्व के लिए सघीय सभा की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके 'यायाधीशों' का प्रायः पुनर्निर्वाचन होता है जिसके कारण उन्हें विधान मण्डल की कृपा पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है। स्विस संविधान निर्माता 'यायिक पुनर्विलोकन' (Judicial Review) को जनप्रभुता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं मानते थे। उनका विचार था कि 'यायिक पुनर्विलोकन' 'यायपालिका' को अनुत्तरदायी बनाती है और 'यायालय' अपने मौलिक कृत्यों की

अपेक्षा करके राजनीति में सलग्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्विसवासी यह मानते थे कि 'यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है। इस पद्धति से परिष्कृति विधि का निरूपण हो सक्ता है। परंतु यह इतनी मंद गति से होता है कि हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम लॉरेल के इस अभिमत से सहमत नहीं हैं कि 'जहाँ जहाँ हमारा संविधान चूटिपूण है, वहाँ-वहाँ पर स्विटजरलैण्ड का संविधान दृढ़ है और जहाँ जहाँ हमारा संविधान दृढ़ है वहाँ वहाँ स्विस संविधान चूटिपूण है।' डाइसी ने यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था के अभाव को स्विस संविधान निर्माताओं की भयंकर भूल कहा है क्योंकि वे यायपालिका को कायपालिका से पृथक् नहीं कर सके।¹ परंतु ये दोनों ही मत उपयुक्त नहीं कहे जा सकते क्योंकि यायिक पुनर्विलोकन के अभाव में स्विस लोकतंत्र की गति अवरोध नहीं हुई है।

स्विस न्यायाधिकरण तथा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना (American & Swiss Federal Tribunals Comparison)

(i) स्विटजरलैण्ड में सघीय यायाधिकरण के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य सघीय 'यायालय नहीं है, परंतु अमेरिका में उच्चतम यायालय की अधीनता में सघीय 'यायालयों की एक शृंखला सी है।

(ii) स्विस 'यायाधिकरण में 'यायाधीशों की संख्या अमेरिकी उच्चतम 'यायालय की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(iii) स्विस यायाधिकरण के 'यायाधीश 6 वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं परंतु उच्चतम 'यायालय के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की संपुष्टि पर ही नियुक्त होते हैं।

(iv) स्विटजरलैण्ड में 'यायाधीश प्रायः पुनः निर्वाचित होते रहते हैं जबकि अमेरिका में सम्भव नहीं है।

(v) अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के कारण 'यायपालिका का एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है परंतु स्विटजरलैण्ड में यह सम्भव नहीं हो सका है।

(vi) अमेरिकी उच्चतम 'यायालय के सदस्य स्विस सघीय 'यायाधिकरण की 'यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी शक्ति के आधार पर तो अमेरिकी उच्चतम 'यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। स्विस सघीय 'यायाधिकरण को यह सम्मान प्राप्त नहीं है।

(vii) स्विस 'यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार अमेरिकी क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। स्विस में दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार सघीय 'यायाधिकरण के अधिकार में है जबकि वह अमेरिका में राज्य सरकारों के अधीन है। अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालय को स्विस उच्चतम यायालय की भांति प्रशासकीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है।

¹ Swiss Statesmanship failed as distinctly as American Statesmanship has succeeded in keeping the judicial apart from the Government —Dicey

फौजदारी विवादों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण स्विटजरलैण्ड को 5 जिलों में विभाजित किया गया है। विवादों की सुनवाई एक जूरी के द्वारा होती है जिसमें 12 सदस्य होते हैं। प्रत्येक विवाद में निणय करने के लिए जूरी की 5/6 सख्या की स्वीकृति आवश्यक है।

(2) अपील्य क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

ऐसे विवाद जिनका मूल्य 4000 फ्रैंक अथवा इससे अधिक आँका गया है और जिनका निणय भी कैंटनों के यायालयों द्वारा ही किया गया हो, उनके निणयों के विरुद्ध अपील सघीय यायाधिकरण में की जा सकती है।

(3) प्रशासकीय क्षेत्राधिकार (Administrative Jurisdiction)

सन् 1925 से पूर्व प्रशासकीय विवादों का निणय सघीय परिषद करती थी परन्तु इसके पश्चात् सघीय सभा द्वारा पृथक् प्रशासकीय यायालय की स्थापना न करके ये अधिकार सघीय यायाधिकरण को ही समर्पित कर दिये गये। अतएव प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित प्रकार के विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं—

(i) ऐसे विवाद जिनका सम्बन्ध सरकारी कर्मचारियों की योग्यता तथा क्षमता आदि से है।

(ii) ऐसे विवाद जिनका सम्बन्ध सघीय रेलवे शक्ति से है।

(iii) कराधान सम्बन्धी प्रशासकीय विवाद।

(iv) राज्य कर्मचारियों तथा नागरिकों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निणय भी सघीय यायाधिकरण ही करता है।

(4) संवैधानिक क्षेत्राधिकार (Constitutional Jurisdiction)

(i) सघीय तथा कंटनों के कर्मचारियों के मध्य विवाद।

(ii) कैंटनों के ऐसे विवादों की सुनवाई सघीय यायाधिकरण करता है जो कि सावजनिक कानून के अंतर्गत आते हों।

(iii) नागरिकों की ऐसी शिकायतें जिनका सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौतों से है।

(iv) नागरिकों को जो अधिकार कंटनों के संविधानों ने तथा सघीय संविधान ने प्रदान किये हैं उनके विरुद्ध किये गये कार्यों की अपील सघीय यायालय सुनता है।

स्थिति (Position)

स्विस यायाधिकरण की स्थिति अमेरिकी उच्चतम यायालय जैसी शक्तिशाली नहीं है। इसका मूल कारण है यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अभाव। सघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों को अवध घोषित करने का अधिकार केवल जनता को ही है सघीय यायाधिकरण को नहीं। सघीय यायाधिकरण को अपने अस्तित्व के लिए सघीय सभा की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके यायाधीशों का प्रायः पुनर्निर्वाचन होता है जिसके कारण उन्हें विधान मण्डल की कृपा पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है। स्विस संविधान निर्माता यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) को जनप्रभुता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं मानते थे। उनका विचार था कि यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका को अनुत्तरदायी बनाती है और यायालय अपने मौलिक वस्तुओं की

उपेक्षा करके राजनीति में सलग्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्विसवासी यह मानते थे कि 'यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है। इस पद्धति से परिष्कृति विधि का निसृण हो सकता है। परन्तु वह इतनी मन्द गति से होता है कि हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम लॉरेल के इस अभिमत से सहमत नहीं हैं कि 'जहाँ जहाँ हमारा संविधान श्रुतिपूर्ण है, वहाँ-वहाँ पर स्विटजरलैण्ड का संविधान दृढ़ है और जहाँ जहाँ हमारा संविधान दृढ़ है वहाँ वहाँ स्विस संविधान श्रुतिपूर्ण है।' डाइसी ने 'यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था के अभाव को स्विस संविधान निर्माताओं की भयकर भूल कहा है क्योंकि वे यायपालिका को कार्यपालिका से पथक नहीं कर सके।¹ परन्तु ये दोनों ही मत उपयुक्त नहीं कहे जा सकते क्योंकि यायिक पुनर्विलोकन के अभाव में स्विस लोकतन्त्र की गति अवरोध नहीं हुई है।

स्विस न्यायाधिकरण तथा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना (American & Swiss Federal Tribunals Comparison)

(i) स्विटजरलैण्ड में सघीय यायाधिकरण के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य सघीय 'यायालय नहीं है, परन्तु अमेरिका में उच्चतम यायालय की अधीनता में सघीय 'यायालयों की एक शृंखला सी है।

(ii) स्विस 'यायाधिकरण में 'यायाधीशों की संख्या अमेरिकी उच्चतम 'यायालय की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(iii) स्विस 'यायाधिकरण के 'यायाधीश 6 वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं परन्तु उच्चतम यायालय के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, सीनेट की सपुष्टि पर ही नियुक्त होते हैं।

(iv) स्विटजरलैण्ड में 'यायाधीश प्रायः पुनः निर्वाचित होते रहते हैं जोकि अमेरिका में सम्भव नहीं है।

(v) अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के कारण 'यायपालिका को एक स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान किया गया है परन्तु स्विटजरलैण्ड में यह सम्भव नहीं हो सका है।

(vi) अमेरिकी उच्चतम 'यायालय के सदस्य स्विस सघीय 'यायाधिकरण को 'यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी शक्ति के आधार पर तो अमेरिकी उच्चतम 'यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। स्विस सघीय 'यायाधिकरण को यह सम्मान प्राप्त नहीं है।

(vii) स्विस 'यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार अमेरिकी क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। स्विस में दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार मघीय 'यायाधिकरण के अधिकार में है जबकि वह अमेरिका में राज्य सरकारों के अधीन है। अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालय को स्विस उच्चतम यायालय की भाँति प्रशासकीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है।

¹ Swiss Statesmanship failed as distinctly as American Statesmanship has succeeded in keeping the judicial apart from the Government —Dicey

(viii) स्विस जूरी पद्धति तथा सघीय 'यायाधिकरण' का विभागों में वितरण अपने ही ढंग का है।

स्विटजरलैण्ड में दल पद्धति (Party System in Switzerland)

परिचयात्मक—स्विटजरलैण्ड में बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था है परन्तु वहाँ का जनतंत्रीय जीवन कभी भी उससे विचलित नहीं हुआ। स्विटजरलैण्ड में कई दल तथा भाषाएँ हैं अतएव राजनैतिक दल उसकी इन कमजोरियों का लाभ उठा सकते थे। परन्तु वहाँ की स्वस्थ परम्पराओं एवं प्रबुद्ध जनमत ने इन राजनैतिक तत्त्वों को अनुचित रूप में उभारने नहीं दिया। निर्वाचन की अनुपाती प्रणाली प्रत्येक राजनैतिक दल को सात्वना देती रही है, राजनैतिक दलों को मोक्ष त्र की घुरी कहा जाता है। परन्तु विनाशकारी तत्वों का समावेश भी उनमें ही है। स्विस राजनैतिक जीवन राजनैतिक दलों की गतिविधियों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं रहा है, राजनैतिक दलों का प्रभाव केवल कैबिनेट तक ही सीमित है। स्विटजरलैण्ड प्रजातंत्र का वह उदाहरण है जो कि धर्मांधता, विद्वेष और परम्परागत अंधविश्वास से दूर है। यद्यपि वहाँ पर भी राजनैतिक भ्रष्टाचार कुछ कैबिनेटों में विद्यमान है। परन्तु ऐसा बहुत कम मात्रा में ही है। इसका मूल कारण यह है कि आर्थिक जीवन में समतुलन की अधिक मात्रा एवं दलबन्दी रूपी लहरें स्विस लोकतंत्र रूपी पोत को डगमगा नहीं सकी हैं। अर्थात् वह उसे गमराह करके उसका विनाश नहीं कर सकी हैं। नवीन राजनैतिक दलों की उत्पत्ति के लिये जितना खुला वातावरण वहाँ पर विद्यमान है ऐसा अन्यत्र नहीं है। परन्तु फिर भी राजनैतिक दलों का प्रभाव कम है। स्विस राजनैतिक दलों की अपनी विशेषताएँ हैं, चाहे वहाँ के राजनैतिक जीवन में उनका महत्व कितना ही कम क्यों न हो।

स्विस राजनैतिक दलों की विशेषताएँ (Characteristics of Swiss Party System)

1 **बहुदलीय व्यवस्था (Multiple Party System)**—इंग्लैण्ड में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था कायपालिका को अस्थायी बनाती है। परन्तु स्विस कायपालिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। यहाँ पर लगभग 8 राजनैतिक दल हैं। बहुदलीय व्यवस्था के कारण ही फ्रांस में सरकार स्थायी नहीं रह सकी।

2 **विरोधी दलों का अभाव (Absence of Opposition)**—स्विटजरलैण्ड में विरोधी दल का अभाव रहता है। फ्रांस, भारत, इंग्लैण्ड तथा आस्ट्रेलिया आदि में विरोधी दल पाये जाते हैं परन्तु स्विटजरलैण्ड में ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण यहाँ पर विद्यमान निर्वाचन की अनुपाती प्रणाली है। प्रत्येक दल को सघीय परिषद में उनके दलों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। किसी भी दल को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता। यहाँ के राजनीतिज्ञों में प्रतिस्पर्धा का भाव भी अल्प मात्रा में ही विद्यमान है।

3 **वर्गीय संगठन का अभाव (Absence of Organized Political Party)**—स्विटजरलैण्ड में राजनैतिक दलों का संगठन कठोर एवं राष्ट्रव्यापी नहीं है। दलों के पास धन का अभाव रहता है। दलीय सदस्यता के नियम भी कठोर नहीं हैं। यहाँ पर दलीय संगठन भारत, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका जसा नहीं है।

4 **सैद्धांतिक मतभेदों का अभाव (Absence of Ideological Differences)**—अमेरिका के राजनैतिक दलों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। उन सब के सिद्धांत लगभग एक से हैं क्योंकि यहाँ पर पूजोपतियों तथा अधिक निधनता की स्थिति नहीं है। यहाँ पर मध्यम वर्ग का ही आधिक्य है जिनकी आर्थिक समस्याएँ लगभग समान ही हैं एवं घम निरपेक्षता तथा तटस्थता के मौलिक तत्व सब में ही पाये जाते हैं।

5 **घम का राजनैतिक दलों पर प्रभाव नहीं है (No Effect of Religion on Politics)**—स्विटजरलैण्ड में राजनैतिक दलों पर घम का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर घम निरपेक्ष व्यवस्था है। किसी भी दल के संगठन का आधार घम नहीं है। भारतवर्ष में पहले हिंदू महासभा तथा मुसलिम लीग के संगठनों का आधार घम ही था। परंतु यहाँ के राजनैतिक जीवन पर घम की प्रतिच्छाया नहीं है।

6 **व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव (Absence of Professional Politicians)**—स्विस निवासियों ने राजनीति को कभी भी व्यवसाय के रूप में ग्रहण नहीं किया। वे ऐसी भावना से ही घणा करते हैं। राजनीति को वे रोटी रोजी का साधन नहीं मानते। यहाँ राजनैतिक दलों का कोई व्यवस्थित संगठन भी नहीं पाया जाता है। यहाँ निर्वाचन में उम्मीदवारों के नेतृत्व का मूल्यांकन भावुकता से अभिभूतित होकर नहीं किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर प्रयाशी के अनुभव एवं उसकी योग्यताओं का अवलोकन सूक्ष्म दृष्टि से किया जाता है।

प्रमुख राजनैतिक दल (Main Political Parties)

(1) **कैथोलिक अनुदारवादी दल (Catholic Conservative Party)**—सन् 1847 से ही यह दल कैथोलिक चर्च तथा कैटनों के अधिकारों का समर्थक रहा है। इसने केन्द्र को अधिक शक्तियाँ देने का विरोध किया है। यह कृषि व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता का पक्षपाती है। यह ट्रेड यूनियनों का समर्थन करते हुए भी अनुदारवादी ही है।

(2) **क्रांतिकारी दल (Radical Party)**—सन् 1832 में इस दल की स्थापना हुई। यह दल नाम से ही क्रांतिकारी है। यह समाजवादी तथा कैथोलिक दलों का मध्यमार्गी है। समाजवादी दल के अभ्युदय के कारण ही इसका महत्व कम होता जा रहा है। यह इन बातों का समर्थक है—वैधानिक उपक्रम तथा घमनिरपेक्षता। यह कैथोलिकों की प्रभुता का खण्डन करता है। राष्ट्रवाद तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी यह समर्थन करता है।

(3) **समाजवादी लोकतंत्रीय दल (Social Democratic Party)**—इस दल की स्थापना 1860 में हुई। यह पहले माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित एवं अतिवादी था परंतु अब यह विकासवादी समाजवाद का पोषक है। यह दल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के लिए अधिक वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बेकारी में सहायता, सभी को काम देने, सघीय परिषद के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था तथा महिला मतधिकार का पक्षपाती है।

(4) **उदारवादी दल (Liberal Party)**—सन् 1848 में संविधान इस दल की प्रमुख देन है। सन् 1890 तक स्विटजरलैण्ड की राजनैतिक व्यवस्था पर

इस दल का प्रभुत्व बना रहा। अब इसका प्रभाव नहीं के बराबर ही है। यह दल व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र के रामभरोसे सिद्धांत (Laissez faire) का समर्थक है। यह दल समाजवादी व्यवस्था तथा सघ द्वारा प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था का विरोधी रहा है। इसके सदस्य प्रोटेस्टेंट धार्मिक वर्ग के लोग हैं।

(5) साम्यवादी दल (Communist Party)—स्विटजरलैंड में यह दल कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा। यह मार्क्सवादी दशन के आधार पर साम्यवाद लाने के पक्ष में है। प्रतिबन्ध लगे रहने के कारण इस दल ने अपना नाम बदलकर कृषक दल रख दिया है।

(6) स्वतंत्र दल (Independent Party)—इस दल की स्थापना सन् 1935 में हुई। यह उद्योगों में राजकीय हस्तक्षेप का विरोध करता है। देश की राजनीति में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

(7) कृषक, मजदूर तथा मध्य वर्गीय दल (Farmers, Labour and Middle Class Party)—इस दल की स्थापना सन् 1918 में हुई। यह कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, वैद्वाद का समर्थन, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रगतिशील राष्ट्रीयता एवं कृषि उत्पादन के महत्व आदि को प्रोत्साहन देता है इस दल के अधिकांश सदस्य मध्यमवर्गीय हैं।

स्विटजरलैंड में इन बड़े दलों के अतिरिक्त उदारवादी दल, समाजवादी दल, लोकतन्त्रात्मक दल तथा प्रोटेस्टेंट दल, नेशनल फ्रंट, नवयुवक अनुदार दल तथा राष्ट्रीय लीग आदि छोटे छोटे दल भी हैं। परन्तु इनका महत्व नहीं के बराबर ही है। आज के चार प्रमुख दल इस प्रकार हैं—क्रांतिकारी दल (Radical Party), कथोलिक अनुदारवादी दल (Catholic Conservative Party), समाजवादी लोकतन्त्रीय दल (Social Democratic Party), कृषक दल (Farmer Party)।

स्विटजरलैंड में राजनैतिक दलों का संगठन अत्यंत शिथिल है। राजनैतिक दलों के तीन अंग हैं—डाइट (Diet), केन्द्रीय समिति (Central Committee), तथा कार्यपालिका समिति (Executive Committee)। डाइट दल का सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है, जिसमें दल की वार्षिक रिपोर्ट, आय व्यय तथा समयाकालीन समस्याओं पर विचार किया जाता है। केन्द्रीय समिति के सदस्य भी प्रत्येक वर्ष डाइट के द्वारा ही निर्वाचित किये जाते हैं। यह दल की कार्यपालिका होती है यह अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं जोकि दल की कार्यकारिणी समिति का गठन करते हैं। स्विटजरलैंड में दल व्यवस्था की दुबसता के कारण (Causes of the Weaknesses of Swiss Party System)

अब देना की अपेक्षा स्विटजरलैंड की दल पद्धति को दुबस माना गया है। इसके कई कारण हैं जिनका उल्लेख ब्राइस ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक लोकतन्त्र' में किया है, जोकि इस प्रकार हैं

1. शासन के स्वरूप के सम्बन्ध में जनता में कोई मतभेद नहीं है। सभी वर्ग लोकतन्त्रात्मक संघीय संविधान के समर्थक हैं।

2 सघीय परिषद में एकदलीय प्रभुत्व के स्थान पर बहुदलीय सरकार बनती है। सभी दलों को प्रतिनिधित्व उपलब्ध हो जाता है।

3 स्विटजरलैण्ड में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में ही निहित है।

4 अमेरिका की भांति स्विटजरलैण्ड में किसी राजनैतिक दल के पास सरक्षण शक्ति नहीं है। वे अपने समयको एवं अनुयायियों की सेवा नहीं कर पाते। राजनैतिक दल अपनी इच्छा से शासकीय पदों का वितरण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं।

5 आर्थिक दशाओं से जनता मतुष्ट है।

6 सामाजिक सामंजस्यता का बाहुल्य तथा साम्प्रदायिकता एवं पृथक्तावादी प्रवृत्तियों का अभाव है।

7 राष्ट्रप्रेम की भावना का बाहुल्य तथा स्थानीय व्यक्तिगत दृष्टिकोण की भावना में कमी है।

8 व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है।

9 स्विस नागरिकों में वस्तुनिष्ठ अधिक मिलती है एवं पारितोषिक तथा उपाधियों के प्रति जनता में उदासीनता का भाव मिलता है। इसी कारण दलबन्दी उस रूप धारण नहीं कर पाती।

10 स्विटजरलैण्ड की तटस्थता की नीति।

11 राष्ट्रीय समस्याओं की अपेक्षा कानूनों की समस्याओं में जनता की अधिक रुचि है।

12 स्विटजरलैण्ड में महत्वपूर्ण समस्याओं की अनुपस्थिति।

वास्तविकता यह है कि स्विटजरलैण्ड में फ्रांस, इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा भारतवर्ष के समान व्यावसायिक रूप से राजनीतिज्ञ नहीं पाये जाते हैं। स्विटजरलैण्ड में भी हित समूह (Interested Groups) पाये जाते हैं। वस्तुतः स्विटजरलैण्ड में हित समूह वहाँ की राजनैतिक प्रक्रिया का अंतरण भाग बन गये हैं। देश में बहुत से राजनैतिक दल हैं, इसी कारण हित समूहों पर किसी न किसी राजनैतिक दल का बरदहस्त रहता है। राजनीतिज्ञों के वेतन इतने कम हैं कि वे राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में नहीं अपना सकते हैं। राजनीतिज्ञों का स्थान वेतनभोगी औद्योगिक संघों के पदाधिकारी ले लेते हैं। सघीय परिषद कानूनों का निर्माण करते समय इन हित समूहों से भी परामर्श करती है। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन ने भी इन हित समूहों को प्रोत्साहन दिया है। यदि व्यवस्थापन हित समूहों के विरुद्ध होता है तो वे ऐसे व्यवस्थापन को लोक निणय में पराजित कर देते हैं। उपक्रम की पद्धति से वे सघ सरकार को ऐसे प्रस्ताव अथवा विधि निर्माण करने को कहते हैं जो उनके हित में हों। स्विटजरलैण्ड में निम्नांकित चार हित समूह अधिक लोकप्रिय हैं —

(1) The Swiss Union of Commerce and Industry (2) The Swiss Peasants Unions (3) Swiss Federation of Trade Unions, (4) The Swiss Association of Arts & Crafts

Select References

Brooks *Govt of Switzerland*
 Rappard *The Govt of Switzerland*
 Lowell *Govt & Politics of Continental Europe*
 Finer *Major Govts of Europe*
 Bryce *Modern Democracies*
 Hans Hubner *How Switzerland is Governed*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 स्विटजरलैण्ड में दल पद्धति का महत्व बताइए। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका की अपेक्षा उनका महत्व वहाँ पर कम क्या है ?
- 2 स्विस् दल पद्धति की विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 3 स्विस् राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। उनकी दुर्बलताओं के क्या कारण हैं ?
- 4 स्विटजरलैण्ड के राजनीतिक दलों का वहाँ के जनसंघ में क्या स्थान है ? ब्रिटेन तथा अमेरिका में पाई जाने वाली स्थिति से यह किस प्रकार भिन्न है ?
 (What is the position of Political Parties in Swiss Democracy ? How does it differ from the position found in Britain & U S A)
- 5 स्विस् संघीय न्यायालय तथा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मध्य अंतर बताइए।
 (Compare and contrast the Swiss Federal Tribunal and the American Supreme Court)
- 6 स्विस् संघीय न्यायालय के संगठन तथा कृत्यों का वर्णन कीजिए।
 (Describe the composition and functions of the Federal Tribunal of Switzerland)

(Agra, 1942, Alld 1950 P U 1858 Vikram 1963)

संघीय विधानपालिका [विशेष विवेचनो [संवेदन];

"Sovereignty is paramount to the maintenance of the rights of the States. It is the right of the States to determine their own political destiny. All States are equal in the eyes of the law. The political rights of the States are the basis of the work of the League of Nations." — *League of Nations*

परिचयात्मक

संघीय परम्परा के अनुरूप रिपब्लिकन संसद ने भी विधानपालिका के विमर्श से द्विदनात्मक व्यवस्था को अपनाया है। प्रथम सदन जन प्रतिनिधित्व का प्रतीक है और द्वितीय सदन सैनिकों अथवा सभा की पार्लियामेन्टरी सभा का प्रतिनिधित्व करता है। स्विस् विधानमण्डल स्वरूप एक संविधान को प्रति से इंग्लैण्ड के लोक सदन से मिलता जुलता है परन्तु स्विस् विधानमण्डल की स्थिति इंग्लैण्ड की संसद के समकक्ष नहीं है क्योंकि उसकी यह सम्प्रभुत्वसंपन्नता नहीं है जोकि विधि सभा से विद्यमान है। लोक निर्णय की सर्वसाधारण परिपाटी में संघीय विधानमण्डल की स्थिति को कुछ निर्भर बना दिया है। परन्तु इसमें दो मत नहीं हैं कि स्विस् विधानमण्डल के प्रथम सदन का महत्व निश्चय ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से बड़ी अधिक शक्तिशाली एवं सम्प्रभु है। अमेरिका में विधानपालिका का संवैधानिक समान अधिकार सम्पन्नता विधानमण्डल जब इसे कुदृष्टि से देखने लगता है तो कांग्रेस का राज भावता ही प्रतीत होता है, परन्तु इस प्रकार की कोई समस्या स्विस् संघीय विधानपालिका में समझा उत्पन्न नहीं होती। वहाँ संघीय मायालय विधानमण्डल का ही मिश्रण है और ऐसा परमभक्त है कि मत भूलकर भी उद्वेगता करने का साहस नहीं कर सकता। अमता के अतिरिक्त कोई अन्य इसके द्वारा निर्मित विधियों पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकता। संघीय सभा का कटोरी की सरकारों पर भी सर्वोच्च अधिकार है।

स्विस् संसद में दो सदन हैं—राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषद। विधानपालिका व्यवस्था के अपनाने का मूल आधार ऐतिहासिक भवनाओं द्वारा प्राप्त अनुभव है। वास्तव में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है अर्थात् विधानपालिका शक्तियों के अखाड़े में बराबर रहें। इसी को धृष्टिगत रखते हुए, मी० २३ यह विचार व्यक्त किया है कि "स्विस् संघीय सभा नहीं की संघीय एक और दृष्टिकोण से भी अजीबी है, क्योंकि इसके बीना सदन में

समान ही हैं। अर्थात् निचले सदन की शक्तियाँ किसी दृष्टि से उच्च सदन से पृथक् अथवा कम नहीं हैं।'

राष्ट्रीय परिषद (National Council)

1 सगठन (Composition)

यह संघीय विधानमण्डल का निम्न सदन है। वस्तुतः लोक सप्रभुता का प्रति निधित्व इसी सदन के द्वारा होता है। इसके सगठन का आधार व टन की जनसंख्या है। सामान्यतः 24000 की संख्या पर एक प्रतिनिधि का अनुपात रखा गया है। संविधान में 12000 से अधिक जनसंख्या पर भी एक प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है, किंतु स्विस् संविधान की धारा 72 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक कंटन को चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही हो—एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 1951 तक 196 थी परंतु एक संवैधानिक समीक्षण के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रतिनिधित्व की सीमा के मध्य समन्वय स्थापित करके सदन की सदस्य संख्या 200 निश्चित कर दी गई है।

2 निर्वाचन पद्धति (Election System)

बीस वय की अवस्था प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदाधिकार दिया गया है। पादरी, शासकीय कर्मचारी तथा सशस्त्र परिषद तथा राज्य परिषद के सदस्य इसके निर्वाचन में खड़े नहीं हो सकते। निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। सन् 1918 से पूर्व निर्वाचन का आधार प्रादेशिक प्रतिनिधित्व था परंतु इसके पश्चात् अब निर्वाचन प्रणाली का आधार अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation) है। अनुपाती प्रणाली में सूची पद्धति (List System) का प्रयोग किया जाता है। मतदाता व्यक्ति की अपेक्षा राजनैतिक दल को मत देते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से सम्पूर्ण कंटन को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। कंटन प्रत्येक राजनैतिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करता है। ह्यूज ने स्विस् निर्वाचन प्रणाली की कुछ कमियों की ओर संकेत किया है कि मतदाता तथा प्रतिनिधियों के मध्य सम्पर्क उत्तरोत्तर कम होता जाता है। शासकीय नीतियों में एकरूपता नहीं आ पाती है। इस एकरूपता के अभाव में वे प्रभावशाली भी नहीं बन पाती। एकरूपता नहीं आने का मुख्य कारण है—किसी भी राजनैतिक दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत का अभाव स्विस् निर्वाचन पद्धति का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न विचारधाराओं में समझौता करना पड़ता है। विधानमण्डल इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता कि वह किसी शाश्वत नीति का अनुसरण कर सके। प्रत्येक दल को लगभग बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अतएव उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। संघीय परिषद में भी राजनैतिक एकरूपता का अभाव रहता है जिसके फलस्वरूप वह अत्यधिक प्रभावशाली नहीं बन पाती। अभी हाल के ही वर्षों में स्त्रियों को भी मतदाधिकार प्रदान किया गया है। अनुपाती प्रणाली के अवशुण अपने निम्नतम विकारों को वहाँ के राजनैतिक जीवन को पूर्णरूप से दूषित करने में सफल नहीं हो पाए हैं।

3 कायकाल (Tenure)

राष्ट्रीय परिषद का कायकाल सन् 1931 तक केवल तीन का वर्ष ही था। परन्तु संवैधानिक संशोधन के फलस्वरूप अब यह 4 वर्ष है। यह अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से अधिक तथा ब्रिटिश तथा भारतीय लोक सभाओं से कम है। आस्ट्रेलिया में यह 3 वर्ष ही है। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि एक अधिवेशन का अवशिष्ट कार्य दूसरे अधिवेशन द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि एक ही सदस्य कई कई बार निर्वाचित हो जाता है जिससे राष्ट्रीय परिषद में पर्याप्त रूप से स्थिरता आ जाती है। हमारे देश तथा ब्रिटिश संविधान की परम्पराओं के सदृश कायपालिका की सलाह पर स्विस राष्ट्रीय विधान मण्डल के विघटन की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यहाँ पर राष्ट्रीय विधानमण्डल का विघटन केवल उसी स्थिति में होता है जबकि संशोधन सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतभेद नहीं होता और लोक विधायक उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर में होते हैं। इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि अब देशों की भाँति विधानमण्डल की बैठकें बुलाने का काम कायपालिका का नहीं है। अधिवेशन राष्ट्रीय सभा स्वेच्छा से आमन्त्रित करती है। राष्ट्रीय सभा के असाधारण अधिवेशन 1/4 सदस्यों की माँग करने पर बुलाये जा सकते हैं। राष्ट्रीय सभा के लिए गणपूर्ति की संख्या 101 रखी गई है।

(4) पदाधिकारी (Officials of House)

राष्ट्रीय परिषद का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, ये दोनों एक वर्ष के लिए सदन के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किये जाते हैं, एक ही व्यक्ति दूसरे वर्ष उसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं रह सकता। परम्परानुसार आगामी वर्ष के लिए उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित कर लिया जाता है। सदन के अध्यक्ष का सम्मान एवं कार्यों की सीमा तथा स्वरूप भी ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष नहीं है। इसका मूल कारण पदावधि का अल्प स्वरूप है। विशेषाधिकार न होते हुए भी राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है

- 1 सदन के गौरव एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।
- 2 सदन में अनुशासन बनाये रखता है।
- 3 उसे बराबर मत आन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है।
- 4 समितियों तथा आयोगों के गठन के समय अध्यक्ष एक साधारण सदस्य के रूप में मतदान करता है।

राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष का पद निष्पक्षता का ही पद होता है। वह सदन की कार्यवाही में एक निष्पक्ष दशक के रूप में कार्य करता है परन्तु वह अमेरिका के स्पीकर की भाँति शक्तिशाली नहीं होता। वह सदन में निर्वाचन के समय भी एक साधारण सदस्य के रूप में मतदान करता है। बुक्स के शब्दों में "उसका पद सदन के नेताओं द्वारा एक पुरस्कार के रूप में समझा जाता है। जिन लोगों को

इस पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें अपने सहयोगियों से एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।¹

राज्य परिषद (Council of the States)

1 संगठन (Organization)

यह राष्ट्रीय सभा का वरिष्ठ अथवा द्वितीय सदन है जोकि निम्न सदन के समकक्ष शक्तियों से सम्पन्न है। यह अल्पसंख्यक व्यवस्थाओं की भाँति प्रथम सदन के अधीन नहीं है। कुछ दृष्टियों से यह अमेरिकी सीनेट से भी उच्च है, क्योंकि वार्षिक आय-व्यय का बजट वैकल्पिक रूप में इस सदन में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके संगठन का आधार लगभग अमेरिकी सीनेट जैसा ही है। प्रत्येक कैबिनेट प्रति निधिया के रूप में दो सदस्य इस सदन को प्रेषित करता है चाहे उसका स्वरूप एवं जनसंख्या कितनी ही क्यों न हो। प्रत्येक अल्प कैबिनेट एक सदस्य भेजता है। इस प्रकार 38 सदस्य तो 19 पूर्ण कैबिनेटों के होते हैं और 6 सदस्य छ अल्प कैबिनेटों द्वारा भेजे जाते हैं। कुल सदस्य संख्या 44 है। भारतीय राज्य सभा के विषय में इस परिपाटी का अनुसरण नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा निर्वाचन की पद्धति आदि का प्रश्न कैबिनेटों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसी कारण सदस्यों की कार्यावधि एवं वेतन आदि में हमें व्यवधान देखने को मिलता है। सभ के 17 कैबिनेटों में राज्य परिषद के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रत्यक्ष व्यवस्था है। 4 कैबिनेटों में उनका निर्वाचन कैबिनेटों की जनसभाभा (Landsgemeinde) के द्वारा सम्पन्न होता है। चार कैबिनेटों में राज्य परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधानपालिकाओं द्वारा ही सम्पन्न होता है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि 31 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, 5 नागरिक सभाओं द्वारा तथा 8 अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इन सदस्यों के कार्यकाल में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसमें 35 सदस्य लगभग 4 वर्ष के लिए हैं। 5 सदस्य 3 वर्ष के लिए तथा 4 सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। कैबोलिक पादरियों के लिए इस सदन की सदस्यता खुली हुई है। अमेरिकी सीनेट की भाँति राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी व्यवहार में दीर्घकालीन होता है क्योंकि सदस्य अपनी लोकप्रियता के कारण ही बार बार निर्वाचित होते रहते हैं।

विशेषाधिकार एवं उ मुक्तियाँ (Privileges & Immunities)

1 सदस्यों को भाषणों तथा सदन के अल्प समस्त वाद विवादों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।

2 सदस्यों को केवल सदन के प्रति ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

¹ His office is considered to be a great prize by parliamentary leaders and those men who have so fortunate as to attain it enjoy special prestige among their party associates
—Brooks

3 विधानमण्डल जिन विधियों को पारित करता है उनके लिये वे उत्तरदायी नहीं होते ।

4 गम्भीर अपराध की स्थिति में भी सदन के सदस्यों को सदन की अनुमति से ही बर्दी बनाया जा सकता है ।

राज्य परिषद के सदस्य संघीय 'यायपालिका' के सदस्य नहीं बन सकते । संघीय कायपालिका तथा राष्ट्रीय सभा के सदस्य राज्य परिषद के सदस्य नहीं रह सकते । संविधान की धारा 91 के अंतर्गत राज्य परिषद के सदस्य अपनी कैबिनेटों के अनुदेशों के बिना ही कार्य करते हैं । अतः वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं सकीण से दृष्टिकोण नहीं । कुछ कैबिनेट अपने प्रशासकीय पदाधिकारियों को निर्वाचनों में खड़े होने को आजा भी दे सकते हैं । केवल वौड (Vaud) तथा यूचेटल के कैबिनेटों के अतिरिक्त अब किसी कैबिनेट को अपने सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

अधिवेशन, गणपूर्ति तथा वेतन (Sessions, Quorum & Salary)

राज्य परिषद के सदस्यों को वेतन कैबिनेटों के राजकोषों से ही प्राप्त होता है परंतु इसके विषय में भी एकरूपता नहीं है । सब सदस्यों के वेतन एक समान नहीं हैं । इसके अधिवेशन मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में होते हैं । अधिवेशनों की अवधि सामान्यतः 10 या 12 सप्ताह होती है । राष्ट्रीय परिषद के 1/4 सदस्य अथवा चौथाई कैबिनेट राष्ट्रीय सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की भी मांग कर सकते हैं । किसी भी विषय को कार्यावधि करने के लिए राज्य परिषद के लिये 44 में से 23 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है । सदन की कार्यवाही बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होती है । अनुशासन स्थापित करने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती ।

राज्य परिषद के सदस्यों में से 1 वर्ष के लिये एक सदस्य अध्यक्ष तथा दूसरा सदस्य उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है । वे दोनों एक ही कैबिनेट के नहीं हो सकते । भारत तथा अमेरिका की भांति स्विट्जरलैण्ड का उपराष्ट्रपति खरिष्ठ सदन का पदेन अध्यक्ष नहीं रहता ।

संघीय सभा की शक्तियाँ (Powers of Federal Assembly)

स्विस संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत स्विस राष्ट्रीय सभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है । इसमें स्विस विधान मण्डल को परिषद की सर्वोच्च शक्ति कहा गया है । उक्त अनुच्छेद में राष्ट्रीय सभा को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जोकि उसने अधिकार क्षेत्र में दिये गये हैं । धारा 71 के अंतर्गत उसकी शक्तियों पर तीन प्रकार के प्रतिबंध हैं—

स्विस जनता के अधिकार, स्विस कैबिनेटों के अधिकार तथा अन्य प्राधिकरणों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, राष्ट्रीय सभा की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) विधायी शक्तियाँ (Legislature Powers)—(i) यह संघीय सूची के समस्त विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

(ii) संघीय क्षेत्र में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेश प्रकाशित करने का अधिकार भी संघीय सभा को ही है ।

(iii) यह सघीय अधिकारियों के निर्वाचन एवं सभ्य सभ्य घी कानून का निर्माण करती है ।

(iv) कमचारियों के वेतन तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

(v) सघीय शासन के अतगत स्थायी पदों का निर्माण करती है ।

(vi) संविधान में संशोधन करने में इसका प्रमुख हाथ होता है ।

(vii) सघीय उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए कानून का निर्माण करती है ।

(viii) राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा के लिए कानून का निर्माण करती है ।

(ix) कैंटन की सीमाओं की सुरक्षा करती है ।

2 कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)—(i) सघीय कार्यपालिका के सदस्यों तथा चांसलर का निर्वाचन करना ।

(ii) यह सघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है ।

(iii) यह सघीय शासन का सामान्य निरीक्षण करती है ।

(iv) यह सघीय सेनापति का निर्वाचन करती है ।

(v) इसे युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार है ।

(vi) यह विदेशों के साथ सघीय परिषद द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन करती है ।

(vii) कैंटनों द्वारा विदेशों से की गई संधियों का अनुमोदन करना ।

(viii) कैंटनों द्वारा जो पारस्परिक संधियाँ की जाती हैं यदि उनके विषय में कोई आपत्ति हो तो उस पर विचार करना ।

(ix) यदि कोई कैंटन सर्वसामानिक उपबन्धों अथवा किसी सघीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सघीय सभा को है ।

(x) कार्यपालिका पर सघीय सभा का पूर्ण नियंत्रण है । सघीय सभा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सघीय परिषद के सदस्यों से नीतियों का स्पष्टीकरण भी करा सकते हैं ।

(xi) यह सघीय न्यायालय तथा नागरिक सेवाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है ।

(3) न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)—सन् 1874 से पूर्व राष्ट्रीय सभा को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी परन्तु इस नवीन संविधान द्वारा उसकी न्यायिक शक्तियों में कुछ कमियाँ कर दी गई हैं । अब उसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं

(1) न्याय शासन के निरीक्षण का राष्ट्रीय सभा को अधिकार प्राप्त है ।

(2) अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने तथा उन्हें सामूहिक रूप में भी क्षमादान प्रदान करने का अधिकार है । यह अधिकार अब देशों में प्रायः कार्यपालिका को ही दिया करता है ।

(3) यदि प्रशासकीय अधिकारियों के मध्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद हो जाय तो उसका निपटारा सघीय सभा करती है ।

(4) यह सघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है ।

(5) जनता द्वारा प्रस्तुत न्यायिकाओं पर नियंत्रण देती है ।

(6) इसे संविधान की धारा 113 के अंतर्गत प्रशासकीय विवादों पर संघीय परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार है।

(4) वित्तीय अधिकार (Financial Powers)—(1) संघीय सरकार के वजह को स्वीकृति करना।

(ii) यह संघीय सरकार के आय तथा व्यय का निरीक्षण करती है।

(iii) यह संघीय सरकार को ऋण देने का अधिकार के द्रीय सरकार से प्राप्त कर सकती है।

संघीय सभा की स्थिति (Position of the Federal Assembly)

यद्यपि जचर (Zacher) ने यह कहा है कि "संघीय सभा का निर्माण करते समय स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्तियों के प्रयत्नकरण के सिद्धांत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इसको प्रत्येक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं।" परंतु यह उसकी शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं है। वर्तमान शताब्दी में कार्यपालिका का प्रभुत्व है। विधानपालिकाओं का स्तर निरंतर प्रगतिशीलता में चला जा रहा है। इंग्लैंड में भी संसदीय सावधानीमयता मंत्रिमण्डल के अधिनायकत्व के समक्ष केवल एक किताबी बात ही रह गई है।

जिस प्रकार की शक्तियाँ संघीय सभा को प्रदान की गई हैं और जिस रूप में वे संविधान में अंकित की गई हैं उन्हें देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्विस संघीय सभा वास्तव में प्रभुत्व संपन्न है और ब्रिटिश संसद का स्वरूप उसके समक्ष फीका पड़ने लगता है। ब्रिटिश संसद की स्थिति को मंत्रिमण्डल की स्थिति ने काफी कमजोर बना दिया है। आज हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय सावधानीमयता केवल एक साहित्यिक अपवाद ही है। लोक सदन का कार्य अब नियंत्रण करना नहीं, अपितु आलोचना करना मात्र ही रह गया है। ब्रिटिश लोक सदन कार्य नहीं करता, केवल मंत्रिमण्डल द्वारा रखे गये प्रस्तावों का अनुमोदन मात्र ही करता है। परंतु स्विस संघीय सभा की स्थिति इस प्रकार की नहीं है। संघीय परिषद पर उसका पूर्ण नियंत्रण है तथा राष्ट्र की नीतियों पर भी उसका अक्रुश प्रभावशाली है। उसे संविधान में भी परिसम की सर्वोच्च सत्ता कहा गया है। जिस प्रकार कि स्विस में सर्वोच्च सोवियत को राज्य सत्ता का सर्वोत्तम निकाय कहा जाता है।

अमेरिकी कांग्रेस की स्थिति भी स्विस संघीय सभा की शक्तियों के समक्ष फीकी पड़ जाती है। कांग्रेस की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली प्रथम शक्ति तो राष्ट्रपति ही है और दूसरी शक्ति उन सबका पितामह उच्चतम न्यायालय है जिसे उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की शक्ति के कारण कांग्रेस के तृतीय सदन की सजा दी जाती है। स्विटजरलैंड के संघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है वह संघीय सभा द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता वह पूर्ण रूप से निरस तथा विधानपालिका का कान पकड़ा शिष्य है। केवल न्यायपालिका ही क्या बेंचों की सरकारों पर या संघीय सभा का नियंत्रण कम बजनी नहीं है। उनके द्वारा की गई सधियों का अनुमोदन भी संघीय सभा द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय कर्मचारियों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों का

निराकरण भी सघीय सभा के द्वारा ही किया जाता है। स्विस प्रधान सेनापति की नियुक्ति भी इसके द्वारा ही होती है।

उपर्युक्त जिन शक्तियों का विवरण दिया गया है वे यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं कि स्विस सघीय सभा एक सप्रभुसत्ता सम्पन्न निकाय है। किन्तु यह समीक्षा पूर्ण रूप से सही नहीं कही जा सकती। वह सर्वोच्च नहीं है। स्विस शासकीय प्रणाली में ससदीय सावभौमिकता (Parliamentary Sovereignty) के स्थान पर लोकप्रिय सप्रभुता (Popular Sovereignty) को उच्चतर स्थान दिया गया है। लोकनिर्णय (Referendum) तथा उपक्रम (Initiative) की जन शक्तियों के द्वारा सघीय सभा की सविधान सशोधन तथा विधायी शक्तियाँ भी पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकारों के कारण भी सघीय सभा की शक्तियाँ सीमित हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त आजकल व्यवहार में कायपालिका का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। अधिकांश कार्यों का सम्पादन उसी के द्वारा ही होता है। अधिशायी कार्यों का ज्ञान तथा कानून की विशेष योग्यता की जितनी मात्रा सघीय परिषद के पास होती है उतनी सघीय सभा के पास नहीं है। सघीय सभा में अनुपाती प्रणाली के कारण किसी भी राजनैतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, अतएव वहाँ पर सदन का विभाजन भी बहुमत तथा अल्पमत में नहीं हो पाता। वहाँ पर राजनैतिक गतिविधियों का रूप प्रायः समझौतावादी ही होता है। अतः स्विस सघीय सभा का जो स्तर तथा उसकी जो स्थिति हमें सिद्धांत रूप में दृष्टिगोचर होती है वास्तव में वह वैसी नहीं है। फिर भी वह ब्रिटिश संसद तथा अमेरिकी कांग्रेस से कम प्रभावी भी नहीं है। विदेश नीति, वित्त, याव, विधि, सेना आदि सभी पर तो उसका नियन्त्रण है। वस्तुतः सघीय परिषद की तो वह निर्देशिका है। सघीय कायपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों का प्रभाव उसकी शक्तियों को उत्तरोत्तर कम करता जा रहा है।

यूएस के अनुसार "जनता के निवेद्याधिकार के भय" विधान मण्डल के सदस्य निर्भीक होने के स्थान पर डरपोक बन जाते हैं। इस स्थिति में उपक्रम ही उन्हें गतिशील बनाने में सहायक होता है। फ्रांस, भारत तथा इंग्लैंड में लोकसदनों के विघटन की व्यवस्था है परन्तु स्विटजरलैंड में यह सम्भव नहीं है। स्विटजरलैंड में विघटन लोकनिर्णय के पश्चात् अथवा दोनों सदनों में संवैधानिक सशोधनों के सम्बन्ध में मतभेद होने की स्थिति में होता है। कायपालिका के परामर्श पर नहीं। स्विस संसद अन्य लोकतन्त्रीय देशों की भाँति राजनीति का अखाड़ा नहीं बनती है।

सघीय सभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया (Process of Law Making)

स्विटजरलैंड में कानून के दो रूप होते हैं — कानून तथा आज्ञा (Decrees)। सन् 1949 से पूर्व महत्वपूर्ण कानूनों को लोकनिर्णय से बचाने के लिये आज्ञाप्तियों का रूप दे दिया जाता था। परन्तु अब आज्ञाप्तियों को केवल एक वर्ष की ही छुट्टी दी गई है जिसके अनन्तर अब जनता आज्ञाप्तियों पर भी लोकनिर्णय की माँग

कर सकती है। स्विस विधि निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है। यहाँ पर कानून निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है

(1) विधेयक का प्रस्तुतिकरण (Introduction of the Bill)—विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिकांश विधेयक संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। एक विधेयक एक ही समय में दोनों सदनों में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदन एक साथ ही उस पर विचार भी कर सकते हैं। संघीय सभा कानून निर्माण के लिये संघीय परिषद से भी अनुरोध कर सकती है। उस स्थिति में संघीय परिषद सदन द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार ही विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है। उपक्रम द्वारा भी जनता अमुक प्रकार के कानून निर्माण की माँग कर सकती है। उस स्थिति में संघीय परिषद अपनी समयता अथवा असमयता का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, संघीय सभा में कोई भी सदस्य कानून निर्माण का प्रस्ताव रख सकता है जिसे अभिधारणा (Postulate) कहा जाता है। विधेयकों का प्रारूप तैयार करने में संघीय परिषद विशेषज्ञों की सेवाएँ अर्जित करती है। विधेयक पहले किस सदन में प्रस्तावित किया जाय, इसका निर्णय दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर करते हैं। यदि उनमें सहमति नहीं होती है तो निर्णय लॉटरी के द्वारा किया जाता है। घन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु परम्परानुसार घन विधेयक पहले निम्न सदन में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। संघीय परिषद के सदस्य दोनों सदनों में विधेयक के सम्बन्ध में अभिभाषण करते हैं परन्तु मतदान में भाग नहीं लेते। यदि संघीय परिषद किसी विधेयक को अत्यावश्यक घोषित कर देती है तो दोनों सदनों को उस पर स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है।

(2) समिति अवस्था (Committee Stage)—प्रत्येक सदन में विधेयकों पर विचाराय समितियों की स्थापना उपलब्ध रहती है। ये समितियाँ अपनी बैठकें उस समय करती हैं जबकि सदन का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है। समितियाँ विधेयक के मौलिक उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं करती हैं परन्तु विधेयक में अत्यावश्यक संशोधन कर देती हैं। समिति अपनी रिपोर्ट अपने प्रसूचक (Reporter) के द्वारा सदन के पास भेज देती है। यदि समिति में मतभेद होता है तो बहुमत दल तथा अल्पमत दल के एक-एक प्रसूचक सदन में अपनी रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं। सदन अपनी सहमति संशोधन के पक्ष अथवा विपक्ष दोनों में ही दे सकता है। परन्तु विधेयकों पर दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है।

(3) सदन में विधेयकों पर स्वीकृति (Passage of the Bill in the House)—विधेयकों को दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सदन में समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने के उपरान्त धारावार विचार किया जाता है। इसी समय विधेयकों के सम्बन्ध में संशोधन भी प्रस्तावित किये जाते हैं। एक सदन जब विधेयक को स्वीकार कर लेता है तो दूसरे सदन में विधेयक के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया काम में लाई जाती है। यदि दोनों सदनों में विधेयकों के सम्बन्ध में सहमति नहीं होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) की व्यवस्था की जाती है। अथवा दोनों सदनों में छे बराबर-बराबर सदस्य लेकर एक संयुक्त

(Joint Committee) की स्थापना की जाती है। यदि इस प्रकार से भी विधेयको के सम्बन्ध में विवाद समाप्त नहीं होता तो विधेयक समाप्त समझा जाता है।

जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे सघीय परिषद के अध्यक्ष के पास अन्तिम हस्ताक्षरों के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति केवल एक औपचारिकता मात्र है। इसी के साथ विधेयक का प्रकाशन किया जाता है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। विधेयक पर स्वीकृति की तिथि से पाँच दिन के अंदर लोक नियम की माँग की जा सकती है। सदन की प्रमुख समितियाँ इस प्रकार हैं—(1) समाधान समिति, (2) रेलवे रियायत समिति, (3) सघीय रेलवे समिति, (4) सोमा शुल्क समिति, (5) वित्त समिति (6) याचिका समिति, (7) विदेश समिति। इन समितियों का कार्य विधेयको के विषय में समस्त आवश्यक तत्त्व एकत्रित करना होता है।

दोनों सदनों के मध्य सम्बन्ध (Relations Between the Two Houses of Federal Assembly)

स्विस विधानपालिका के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों पर दृष्टिपात करते हुए प्रो० स्ट्रॉंग ने कहा है कि 'स्विस सघीय परिषद के सदस्य स्विस विधान पालिका भी अद्वितीय है। विषय में यही विधानपालिका है जिसके उच्च तथा निम्न सदन में कोई अंतर नहीं है।' दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं।

(i) दोनों सदनों की स्थिति समान है। केवल अमेरिका के अतिरिक्त अन्य सब देशों में बरिष्ठ सदन की स्थिति द्वितीय अथवा समपण की है। परन्तु स्विटजरलैंड में वह समकक्ष है।

(ii) कोई भी विधेयक चाहे वह छन विधेयक ही क्यों न हो किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। वार्षिक आय-व्यय का बजट वार्षिक रूप से प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् एक वर्ष वह एक सदन में तो द्वितीय वर्ष दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) विधेयको पर दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। मतभेद की स्थिति में गतिरोध को एक समुक्त समिति के द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और यदि यह भी सम्भव न हो सके तो विधेयक समाप्त हो जाता है। समुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या समान होती है। गतिरोध के अवसर नहीं के बराबर ही आते हैं। दोनों सदन बड़ी समझदारीपूर्वक सद्भावना के वातावरण में कार्य करते हैं। वे भावावेश में नहीं आते और राष्ट्रीय हित के समक्ष दलीय हित का ध्यान कम रखते हैं।

(iv) सघीय परिषद के सदस्य दोनों सदनों के अधिवेशनों में भाग लेते हैं। अन्य देशों में कार्यपालिका पर सीक सदन का प्रभुत्व रहता है। स्विटजरलैंड में दोनों

1 Swiss legislature like the Swiss executive is unique it is the only legislature in the world the function whose upper house are in no way differentiated from those of the lower —Prof Strong

सदनो की शक्ति इस क्षेत्र में भी समान ही है। अमेरिका में सीनेट निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।

(v) संघीय न्यायालय, प्रधान सेनापति, चांसलर आदि की नियुक्ति में दोनों सदनों का योगदान समान ही रहता है।

(vi) संशोधनों में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं।

(viii) राष्ट्रीय सभा द्वारा कानूनों के ऊपर जो विविध प्रकार के नियंत्रण होते हैं उसमें भी दोनों सदनों की स्थिति समान ही होती है।

परंतु वर्तमान समय में व्यावहारिक रूप से राज्य परिषद का प्रभाव उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है जिसके कारण इस प्रकार हैं

1 राज्य परिषद के कुछ सदस्यों का कार्यकाल बहुत कम है।

2 उनके निर्वाचन में भी एकरूपता का अभाव है।

3 वे कानूनों के कोष से वेतन पाते हैं और उनके वेतनों में भी एकरूपता का अभाव है।

4 राष्ट्रीय परिषद जन संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके कारण उसका शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही है।

5 प्रतिभाशाली व्यक्ति राज्य परिषद की अपेक्षा राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता की अधिक श्रेष्ठकर समझते हैं। परंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड की लॉर्ड सभा तथा भारत की राज्य सभा से राज्य परिषद की स्थिति श्रेष्ठतर और अधिक सुदृढ़ है।

स्विस राज्य परिषद की अमेरिकी सीनेट

तथा इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से तुलना

(Swiss Council of States Compared with American Senate and British House of the Lords)

1 स्विस राज्य परिषद तथा अमेरिकी सीनेट (Council of States & Senate)

(i) ह्यूज (Hughes) के अनुसार "स्विस राज्य परिषद की गिरती हुई प्रतिष्ठा का एक कारण यह है कि उसके पास काम का अभाव रहता है परंतु अमेरिकी सीनेट के पास काम का आधिक्य रहता है।"

(ii) अमेरिकी सीनेट के पास खोज करने की शक्ति है। वह राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा अन्य शासनाधिकारियों के सम्बंध में भी खोज कर सकती है। अतएव लोग उससे भयभीत रहते हैं, परंतु स्विटजरलैंड में ऐसा नहीं है।

(iii) स्विस राज्य परिषद के सदस्यों में वेतन, कार्यकाल तथा निर्वाचन पद्धति में कई अंतर हैं परंतु अमेरिकी सीनेट में ऐसा नहीं है।

(iv) अमेरिका में सीनेट के सदस्य बनने के लिए सोम प्रयत्नशील रहते हैं परंतु स्विटजरलैंड में दूरदर्शी तथा अनुभवी व्यक्ति ही राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता की प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

(v) राज्य परिषद में घन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है परंतु अमेरिका में घन विधेयक सदैव ही प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है।

(vi) अमेरिकी सीनेट का कभी विघटन नहीं होता, जबकि स्विस राज्य परिषद् का विघटन सम्भव है।

(vii) अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है परन्तु स्विस राज्य परिषद में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अध्यक्ष केवल 1 वर्ष के लिए ही निर्वाचित किया जाता है।

(viii) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का सीनेट समायोजन करती है परन्तु स्विस राज्य परिषद इस प्रकार का काम नहीं करती।

(ix) सीनेट को घनिको एवं पूजोपतियों का घर कहा जाता है। परन्तु इसके विपरीत मुनरो के शब्दों में "स्विस राज्य परिषद् को कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रियावाद का गढ़ अथवा प्रगति के पक्ष को रोकने वाली संस्था नहीं कहता।"

(x) स्विस राज्य परिषद कई पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है परन्तु सीनेट उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में केवल उस समय भाग लेती है जबकि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो।

(xi) राष्ट्रपति अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भी सीनेट एक न्यायालय का रूप धारण करती है, परन्तु स्विस काय पालिका के विषय में यह बात प्रयुक्त नहीं होती।

स्विस राज्य परिषद तथा लॉर्ड सभा (Council of States & House of Lords)

स्विस राज्य परिषद तथा लॉर्ड सभा में तुलना का महत्व भी अनोखा ही है। दोनों ही वरिष्ठ सदन हैं। पहले लॉर्ड सभा पर्याप्त शक्तिशाली सदन था, परन्तु सन् 1911 का बिल उसके लिये अभिशाप सिद्ध हुआ और उसकी शक्तियाँ पर भयंकर कुठाराघात हुआ। इसी प्रकार सन् 1874 के नवीन संविधान में राज्य परिषद की शक्तियों में भी कुछ न कुछ कमी हुई है। दोनों सदनों की स्थिति की तुलना इस प्रकार की जा सकती है।

(1) लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या स्विस राज्य परिषद से कहीं अधिक है।

(2) लॉर्ड सभा एक ऐतिहासिक सदन है जबकि स्विस राज्य परिषद एक निर्मित सदन है।

(3) लॉर्ड सभा पूर्णरूप से एक स्थायी सदन है परन्तु स्विस राज्य परिषद एक स्थायी सदन नहीं है।

(4) लॉर्ड सभा दीर्घकाल से एक प्रतिक्रियावादी सदन रही है। परन्तु राज्य परिषद के विषय में मुनरो ने कहा है कि "स्विस राज्य परिषद प्रतिक्रियावाद का गढ़ नहीं रही और न अभी उसने प्रगति को ही अवरोध किया है।"¹ लॉर्ड सभा ने तो सदैव ही प्रगतिशील विधेयकों का विरोध किया है।

(5) लॉर्ड सभा में घन विधेयक प्रस्तुत नहीं होते परन्तु वे स्विस राज्य परिषद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

(6) लॉर्ड सभा में कई प्रकार के सदस्य मिलते हैं और उनमें अधिकारशत

1 No one ever speaks of the swiss council of States as a citadel of reaction or brake upon the wheels of progress —Munro

आनुवंशिक पीयस ही होते हैं परंतु स्विस् राज्य परिषद में इस प्रकार के सदस्यों के कई वग नहीं मिलते।

(7) लॉर्ड सभा लोक सदन द्वारा स्वीकृत विधेयकों को एक वष से अधिक नहीं रोक सकती, परंतु स्विस् राज्य परिषद चाहे तो पूर्णरूप से विधेयको को असफल करा सकती है। धन विधेयको के विषय में भी उसकी शक्ति बराबर है।

(8) लॉर्ड सभा का ब्रिटिश मंत्रिमण्डल पर कोई नियंत्रण नहीं है परंतु इसके विपरीत स्विस् राज्य परिषद का संघीय कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण है। यह उसके निर्वाचन में भी भाग लेती है।

(9) लॉर्ड सभा के अधिवेशन अल्पकालीन होते हैं और उसकी गणपूर्ति की सख्या भी बहुत अल्प है, परंतु यह स्थिति स्विस् कार्यपालिका के सम्बन्ध में नहीं है। वहाँ पर 44 में से 23 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। लॉर्ड सभा की कार्यवाहियों में उसके सदस्य काम में रूचि भी लेते हैं।

(10) लॉर्ड सभा केवल एक विधेयकों का पुनर्वाचन करने वाला निकाय मात्र हो रह गया है परंतु राज्य परिषद का स्तर ऐसा नहीं है। वहाँ पर महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किये जाते हैं।

(11) लॉर्ड सभा कार्यपालिका द्वारा की गई सधियों का समर्थन एवं पुष्टि नहीं करती परंतु राज्य परिषद इस प्रकार की पुष्टि में सक्रिय भाग लेती है।

यद्यपि दोनों ही बरिष्ठ सदन हैं और आधुनिक युग में राज्य परिषद की शक्तियों में भारी कमी भी हुई है परंतु फिर भी उसका स्तर घटकर लॉर्ड सभा की भाँति द्वितीय श्रेणी का ही रह गया है। लॉर्ड सभा अनुदारवादी दल का गढ़ है परंतु राज्य परिषद पर किसी दल का एकाधिकार नहीं है।

Select References

- Rappard *The Govt of Switzerland*
 Munro *Govts of Europe*
 Zurcher *Govts of Continental Europe*
 Hans Huber *How Switzerland is Governed*
 Finer *Theory & Practice of Modern Govts*
 R C Ghosh *The Govt of Switzerland*
 Bryce *Modern Democracies (i)*
 Strong *Modern Political Constitution*
 John Brown Mason *Federal Govt in Switzerland*

परिक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 स्विस् संघीय सभा के दोनों सदनों के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।
 (Describe the composition and functions of both the Houses of the Federal Assembly of Switzerland)
- 2 स्विस् संघीय विधानमण्डल की कार्य प्रणाली पर एक निबन्ध लिखिये।
 (Write a critical essay on the working of the Swiss Federal Legislature)
- 3 "स्विस् संविधान के निर्माताओं ने संघीय सभा को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की—विधायी, प्रशासकीय और न्यायिक भी।" इस कथन की समीक्षा कीजिए।

(The makers of the Swiss constitution conferred on the federal Assembly all kinds of authority, legislature, executive and even Judicial " Comment)

- 4 अमेरिका से भी अधिक मात्रा में स्विटजरलैंड में संघीय सभा के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय सभा और राज्य परिषद के बीच सम्बन्ध बतलाइये।

(In greater that in America, the two houses of the federal Assembly have equal powers in Switzerland Examine the relation between the national Assembly and the Council of states)

- 5 संघीय सभा की सर्वोच्चता पर कौन कौन प्रतिबंध हैं ? स्विस संघीय सभा की शक्ति और स्थिति की तुलना ब्रिटिश संसद से कीजिए।

(What limitations have been imposed on the Supremacy of the federal Assembly ? Compare and contrast the powers and position of the Swiss federal Assembly with that of the British parliament)

- 6 ' स्विटजरलैंड में परिषदों और विधानमण्डल का सम्बन्ध अन्य देशों से भिन्न है।' इस सम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए और स्विस विधानमण्डल तथा कार्यपालिका की अनोखी प्रवृत्ति को बतलाइये।

("The relation between the Swiss ministers to the legislative body is different from that which exists in any other country Explain this relation fully and point out the unique nature of the Swiss Legislature and Executive)

- 7 स्विस विधान मण्डल के संघटन तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए तथा उन सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए जिनके द्वारा इनके सम्बन्ध स्विस संघ कार्यपालिका से नियमित होते हैं।

(Give an account of the Composition and powers of the Swiss federal Legislature ? What are the principles which regulate its relations with the Federal Executive) (Gwalior U 1965)

कैन्टनो की शासन व्यवस्था

[The Govt of Cantons]

‘नागरिक की दृष्टि में कैन्टन एक जीवित वास्तविकता है तथा सच तो उनके लिये एक प्रशासकीय मशीनरी से अधिक कुछ नहीं है।’
—Andre Siegfried

स्विस सच की इकाइयों को कैन्टन कहा जाता है। सच के आधार कैन्टन हैं और कैन्टनो की आधारशिला कम्पून हैं। स्वित्जरलण्ड के नागरिकों का अपने कैन्टनों से अधिक लगाव है। केन्द्र सरकार के प्रति उनमें इतनी आसीनता नहीं है। स्वित्जरलण्ड की प्रकृति मछपि केन्द्रीकरण की ओर है परन्तु फिर भी वहाँ के नागरिक जीवन में कैन्टनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कैन्टन सघीय शक्ति के स्रोत हैं। प्रत्येक कैन्टन की अपनी सरकार है तथा उसका संविधान है। प्रत्येक कैन्टन की जनता को अपने संविधान को अपनी इच्छानुकूल निमित्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है परन्तु उसमें निम्नांकित तीन प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक है

- (i) कैन्टनों के संविधान सघीय शासन के विरुद्ध नहीं होने चाहिए।
- (ii) जनता को राजनैतिक अधिकारों के प्रयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
- (iii) संविधान कैन्टन की जनता द्वारा स्वीकृत होना चाहिए तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार भी जनता का ही होना चाहिए।

स्वित्जरलण्ड में आज भी कैन्टनों का सम्मान है और वे राजनैतिक जीवन के केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। स्वित्जरलण्ड में 25 कैन्टन हैं, जिसमें 19 पूर्ण कैन्टन हैं, तथा 6 अर्द्ध कैन्टन। स्वित्जरलण्ड में कैन्टनों में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं—पहली व्यवस्था के अन्तर्गत जनता स्वयं व्यवस्थापन में भाग लेती है। इस व्यवस्था को लैण्डसजीमैन्डार्ड (Landsgemeinde) कहते हैं। यह व्यवस्था एक पूर्ण कैन्टन में तथा चार अर्द्ध कैन्टनों में विद्यमान है। अन्य कैन्टनों में दूसरी व्यवस्था विद्यमान है जिसके अन्तर्गत जनता प्रशासन एवं व्यवस्थापन में अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेती है। कैन्टनों को केवल सच की राजनैतिक इकाई मान नहीं सम्मनना चाहिए। वे वस्तुतः सघीय राज्य के अन्तर्गत विवसित राजनैतिक समुदाय हैं। कैन्टनों के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन का नियन्त्रण होता है। 5 कैन्टनों के अतिरिक्त सगसय अन्य सभी में समान व्यवस्था पाई जाती है। लैण्डसजीमैन्डार्ड का उल्लेख हम प्रत्यक्ष लोकतन्त्र वाले अध्याय में कर चुके हैं।

कैन्टनो का राजनैतिक ढाँचा (Political Structure of the Canton)

कैन्टनों की व्यवस्थापिकाएँ (Cantonal Legislatures)

स्विटजरलैण्ड के 19 कैन्टनों में प्रतिनिधि प्रकार का लोकतन्त्र है। ऐसे प्रत्येक कैन्टन में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। ऐसे कैन्टनों में महानगर परिषदों (Great Councils) की व्यवस्था है। यह एक ससदीय प्रकार की व्यवस्थापिका है। महापरिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कुछ कैन्टनों में इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता और वहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन बहुमत पद्धति के आधार पर हो होता है। समस्त कैन्टनों में महापरिषद के कार्यकाल में भी समानता नहीं है। महापरिषद के सदस्य विभिन्न कैन्टनों में 1 से लेकर 5 वर्षों तक के लिए निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों की बैठक नहीं मिलती अपितु उन्हें परिषद की बैठक में भाग लेने पर भत्ता मिलता है। महापरिषद के निम्नलिखित कार्य हैं

- 1 बजट को पारित करना।
- 2 कैन्टन की कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करना।
- 3 मायाघीशों तथा अन्य सावजनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
- 4 विधियों का निर्माण करना।

महापरिषद में सदस्यों की संख्या 32 से लेकर 228 तक होती है। कैन्टनों की जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या अत्यधिक है परन्तु बेतम व्यवस्था नहीं होने के कारण कैन्टन के कोय पर इसका कोई विशेष अत्यधिक भार नहीं पड़ता है।

स्विटजरलैण्ड के कुछ कैन्टन ऐसे भी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष जनतन्त्र का मूल रूप देखा जा सकता है। इनमें प्रतिनिधित्व प्रकार की विधान पालिकाएँ नहीं हैं। इनमें प्रत्यक्ष जनतन्त्र है तथा जनता के सभी वयस्क सदस्य विधि निर्माण कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार के लोकतन्त्र को खुले वातावरण का प्रजातन्त्र (Open air type Democracy) कहा जाता है जो सभा विधि निर्माण के कार्यों का सम्पादन करती है उस लण्डसजीमेंडी (Landsgemeinde) कहते हैं। जनता के समस्त वयस्क नागरिक एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर प्रत्यक्ष मतदान (हाथ उठाकर) द्वारा विधियों का निर्माण करते हैं एवं कार्यपालिका के सदस्यों का चयन करते हैं तथा राज्य परिषद के लिए भी सदस्यों का चयन करते हैं। इसी सभा को कैन्टनो के सविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। जो वयस्क मताधिकारी अकारण ही इसकी बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं उन पर जुर्माना किया जाता है इससे सदस्य सामूहिक भावना से गर्भित रहते हैं तथा इसी रूप में प्रायना करते हैं तथा आसन ग्रहण करते हैं। यही सभा कैन्टन के अध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। समिति में वाद विवादों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, अतः इसके लिए एक छोटी सी सलाहकार समिति (Advisory Committee) की रचना की जाती है। कैन्टन सरकार के अध्यक्ष को लण्ड्समैन (Landsman) कहा जाता है। इसका कार्य विधि निर्माण, वार्षिक बजट तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करना है। रैपड का यह कथन उचित ही है कि यह विश्वास करना कठिन है कि एक अजायबघर की वस्तु के रूप में तथा आदिम लोकतन्त्र की पुण्य स्मृति के रूप में यह सभा कैसे जीवित रह सकी है। कैन्टनों की कार्यपालिका (Cantonal Executive)

स्विटजरलैण्ड के प्रत्येक कैन्टन में एक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है।

इस कायपालिका का फ्रेंच भाषा भाषी कंटनों में 'सरकारी परिषद' (Government Council) कहा जाता है तथा जर्मन भाषा भाषी कंटनों में इसे राज्य परिषद कहा जाता है। इसका स्वरूप भी बहुत है। प्रत्येक कंटन की कायपालिका में 5 से लेकर 11 तक सदस्य होते हैं। कंटोनल कायपालिका के सदस्यों का निर्वाचन कंटनों के विधान मण्डलों द्वारा होता है। जुग तथा टिसीनो कंटनों में कायपालिका का निर्वाचन अनुपाती प्रणाली के द्वारा सम्पन्न होता है। प्रत्येक कायपालिका का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। इसके कार्य केन्द्र में सघीय कायपालिका के समान ही हैं। कंटोनल कायपालिका के सदस्य दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकारिणी के अध्यक्ष को 'लैण्ड्समैन (Landsman)' कहा जाता है। कंटन की कायपालिका के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

(i) विधेयकों को व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ii) जिन विधेयकों को व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें कायपालिका कार्यान्वित करती है।

(iii) व्यवस्थापिका के समक्ष प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन कंटन की कायपालिका प्रस्तुत करती है। सिद्धांत में तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यवहार में वह उसका मागदर्शन करती है।

कंटनों की न्यायपालिका (Cantonal Judiciary)

प्रत्येक कंटन की अपनी 'याय व्यवस्था' है क्योंकि वहाँ सघीय 'यायालय' की शाखाएँ नहीं हैं। कंटन में सबसे छोटे न्यायालय को शक्ति यायालय कहा जाता है। ये यायालय दीवानी प्रकार के विवाद सुनते हैं। इन यायालयों का पहला कर्तव्य दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न होता है और जब समझौता नहीं हो पाता तब ये कानून के अनुसार दण्ड की व्यवस्था करते हैं, इनके ऊपर जिला यायालय (District Courts) होते हैं। प्रत्येक जिला यायालय में 5 से लेकर 7 तक यायाधीश होते हैं। कंटनों में फौजदारी तथा दीवानी प्रकार के विवाद सुनने के लिए पथक पथक यायालय होते हैं। फौजदारी प्रकार के विवादों के लिए जूरी (Jury) की भी व्यवस्था है। प्रत्येक कंटन में एक उच्च यायालय की भी व्यवस्था है जिसके सदस्य कंटन की व्यवस्थापिका द्वारा 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते हैं। कंटनों में यायाधीशों को बार बार निर्वाचित करने की परम्परा है। उच्च यायालय के द्वारा दोनों प्रकार के विवादों का सुनवाई की जाती है। फौजदारी विवादों की सुनवाई एक जूरी की सहायता से होती है जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस यायालय को भी यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है।

प्रदेशों तथा कम्यूनो का शासन

(Administration of Regions & Communes)

स्विटजरलैण्ड में बड़े तथा छोटे दोनों ही प्रकार के कंटन हैं। बड़े-बड़े कंटनों को प्रदेशों में विभाजित किया गया है। छोटे छोटे कंटनों में केवल कम्यून की व्यवस्था है। बड़े-बड़े कंटनों को प्रदेशों तथा प्रदेशों को कम्यूनो में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रदेश के प्रशासन का एक मुखिया होता है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है। मुखिया ही अभ्यादेशों एवं कानूनों को कार्यान्वित करता है। यही मुखिया न्यायालय के निष्पक्षों को भी कार्यान्वित करता है।

कम्यून (Commune) कंटन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। स्विटजरलैण्ड में लगभग 3164 कम्यून हैं। ये वहाँ के राजनैतिक जीवन की आधार

मिलाएँ हैं। इसी कारण है सट्टर ने कहा 'है कि' स्विटजरलैण्ड कम्प्यूनों का देश है।¹ कम्प्यून जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं।² 5 कम्प्यूनों की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। लगभग 20 कम्प्यूनों की जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच में है। स्विटजरलैण्ड के सबसे छोटे कम्प्यून की जनसंख्या 14 है। स्विटजरलैण्ड में कम्प्यून भी दो प्रकार के हैं—शहरी कम्प्यून तथा ग्रामीण कम्प्यून। लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या शहरी कम्प्यूनों में तथा शेष 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण कम्प्यूनों में निवास करती है।

प्रत्येक कम्प्यून में जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था है। प्रत्येक कम्प्यून में एक व्यवस्थापिका होती है जिसे 'सामान्य परिषद' (General Council) कहा जाता है। नागरिकों द्वारा ही इसका निर्वाचन सम्पन्न होता है। कम्प्यून की सीमा के समस्त व्यस्क पुरुष नागरिक इसके सदस्य होते हैं। कुछ बड़े बड़े कम्प्यूनों में जहाँ पर समस्त नागरिकों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना सम्भव नहीं होता वहाँ प्रतिनिधि प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। सभी कम्प्यूनों में कानूनी की भाँति लोक निर्माण तथा उपक्रम की व्यवस्था की गई है।³ हैस हूबर के शब्दों में "स्विस कम्प्यून बहुत सी बातों में इंगलैण्ड के पैरिश जिले तथा काउन्टियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र तथा सगठन में अधिक लोकतन्त्रीय है।"⁴ स्विटजरलैण्ड के नागरिकों को तीन स्तरों पर नागरिकता प्राप्त होती है—राष्ट्रीय, कैंटोनल तथा कम्प्यून। वास्तव में स्विटजरलैण्ड कम्प्यूनों का अदभुत देश है। स्विस नागरिकों के जीवन में कम्प्यूनों का विशिष्ट महत्व है।

कम्प्यून की प्रशंसा करते हुए साइ ब्राइस ने कहा है कि कम्प्यून स्विटजरलैण्ड के न केवल प्रशासकीय भवन का आधार है बरन वह एक प्रशिक्षण है जिसे लोगो ने अभ्यास के रूप में प्राप्त किया है जिससे वे लोकतन्त्रीय समस्याओं को चलाने में सफल हुए हैं। कम्प्यून व्यवस्था की सफलता हम इससे भी माप सकते हैं कि आज तक केन्द्र सरकार की उनका कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। प्रत्येक कम्प्यून में एक कार्यकारिणी होती है जिसे कम्प्यून परिषद (Commune Council) कहा जाता है। इसका भी स्वरूप बहुलवादी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जल वितरण, विद्युत आदि की व्यवस्था करना कार्यकारिणी का ही कार्य है।

Select References

- Hans Huber *How Switzerland is Governed*
 Rappard *The Govt & Politics of Switzerland*
 Bryce *Modern Democracies*

परीक्षोपयोगी प्रश्न

- 1 स्विस कैंटनों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
 (Describe Cantonal Administration of Switzerland)
- 2 स्विस प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय व्यवस्था में कम्प्यून का महत्व बताइए।
 (Assess the importance of Commune in the Direct Democracy of Switzerland)

1 Switzerland is a characteristic country of Communes —Hans Huber
 2 The swiss communes are more independent and in many respects democratic in their organization than the English Parishes, rural districts and counties —Hans Huber

